



सत्यमेव जयते

विदेश मंत्रालय



वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

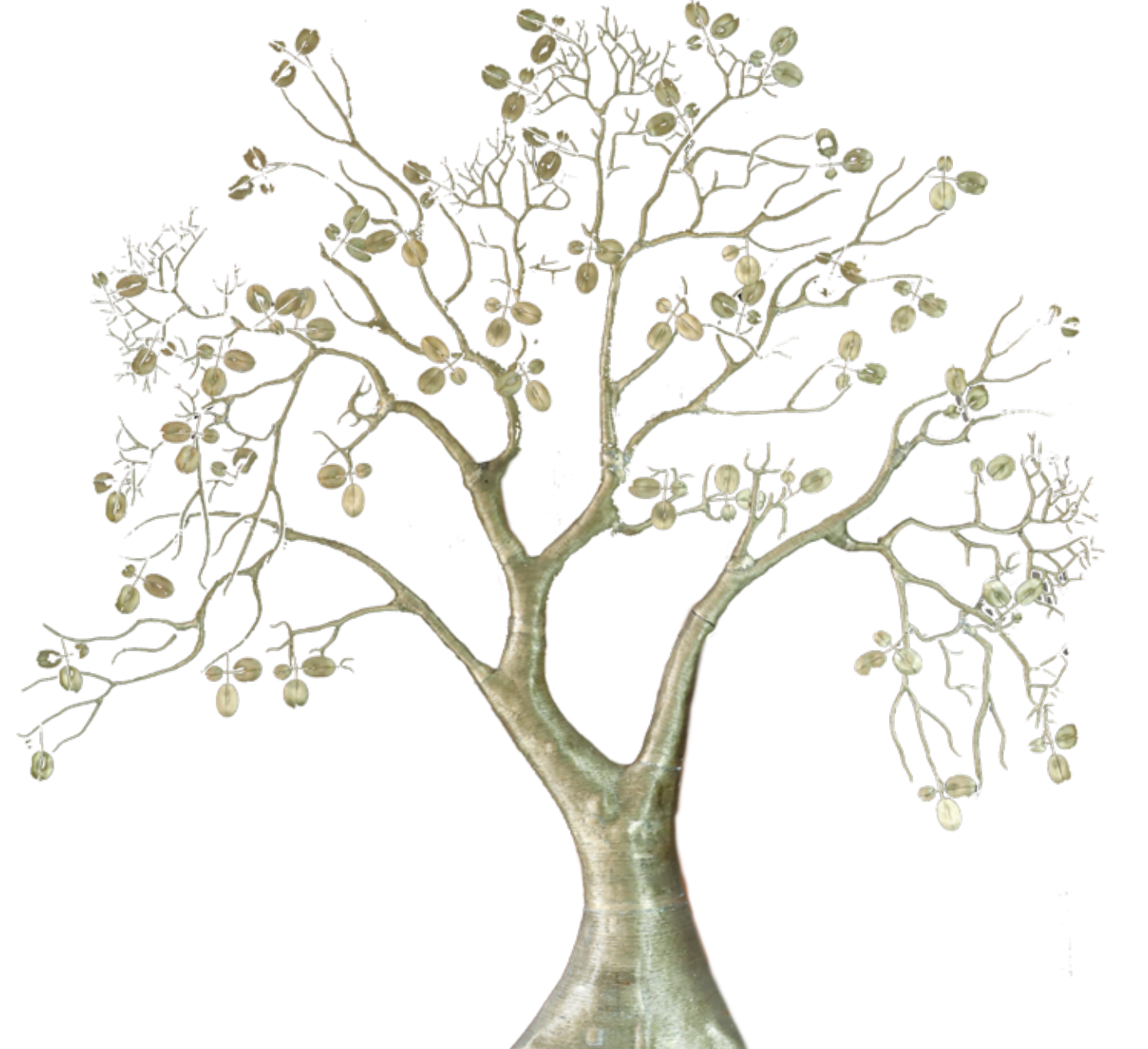


कृपया स्कैन करें

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21



विषय सूची

प्रस्तावना एवं सारांश	4
1. भारत के पड़ोसी	25
2. हिंद महासागर क्षेत्र	41
3. दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया	45
4. पूर्व एशिया	56
5. यूरोशिया	61
6. खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका	69
7. अफ्रीका	83
8. यूरोप और यूरोपीय संघ	101
9. अमेरिका	123
10. बिम्स्टेक, सार्क एवं नालंदा	139
11. भारत-प्रशांत	142
12. संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठन	147
13. बहुपक्षीय आर्थिक संबंध	154
14. विकास सहकार्यता	158
15. आर्थिक राजनय	166
16. स्टेट प्रभाग	174
17. निरस्त्रीकरण एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मामले	177
18. विधि एवं संधि प्रभाग	182
19. नीति, नियोजन और अनुसंधान प्रभाग	186
20. आतंकवाद - रोध	190
21. साइबर, राजनय, ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी	192
22. कौसुली, पासपोर्ट एवं वीजा सेवाएं	195
23. प्रवासी भारतीय मामले	203
24. नई उभरती हुई एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकी	208
25. प्रोटोकॉल	210
26. विदेश प्रचार एवं लोक राजनय प्रभाग	213
27. प्रशासन, स्थापना और सूचना का अधिकार	218
28. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	220
29. वित्त और बजट	221
30. संसद और समन्वय प्रभाग	227
31. सम्मेलन प्रभाग	230
32. अभिलेखागार	232
33. सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान	233
34. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद परिशिष्ट	237

प्रस्तावना और सार-संक्षेप

कोविड -19 महामारी ने 2020-21 में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक बड़ा आघात दिया। पूरे समाज को और पूरी दुनिया की सरकारों को इस अभूतपूर्व व्यवधान का सामना करने के लिए जूझना पड़ा। फैलते हुए वायरस के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन लगाना पड़ा और आवाजाही पर प्रतिबंध लग गए। इसके कारण आजीविका के नुकसान और कई दशकों में उत्पादन में सर्वाधिक कमी आने के साथ अन्य गंभीर आर्थिक नुकसान भी हुए। महामारी के कारण मानव जीवन की भारी क्षति हुई। 2 मिलियन से अधिक लोगों की जान चली गई। पूरी जीवन शैली पर खतरा उत्पन्न हो गया।

इस कठिन समय के दौरान, विदेश मंत्रालय ने महामारी के दुष्परिणामों का मुकाबला करने और इससे बचाव के लिए प्रतिक्रिया देने में अग्रणी रहने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह प्रतिक्रिया कई स्तरों पर थी और कई दिशाओं में एक साथ प्रयास किया गया। तुरंत एक कोविड -19 प्रकोष्ठ बनाया गया और कोविड से संबंधित दायित्वों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया। विदेशों में फंसे हुए भारतीयों के आपातकालीन अनुरोधों पर कार्रवाई करने के

लिए और सूचनाओं के प्रसार के लिए एक 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। इसे 110,000 से अधिक ई-मेल और 33,000 टेलीफोन कॉल प्राप्त हुए। मंत्रालय ने महामारी से निपटने के लिए चिकित्सा प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत करने हेतु खरीद अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परीक्षण किट, वेंटिलेटर, पीपीई और मास्क तथा उपयुक्त तकनीकों को भी दुनिया भर से प्राप्त किया गया।

भारत के विभिन्न हिस्सों से 110,000 से अधिक विदेशी नागरिकों को 123 देशों में भेजने की सुविधा प्रदान की गई। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केंद्रों तथा भारत में सभी संबंधित संगठनों के सहयोग से बहुत बड़े पैमाने पर एक समन्वित प्रयास, वंदे भारत मिशन, शुरू किया गया। इस मिशन के तहत 30 लाख से अधिक भारतीय भारत लौट आए हैं। उनकी वापसी हवाई, समुद्री और भूमार्ग से हुई।

भारत ने 154 से अधिक देशों को कोविड से संबंधित चिकित्सा आपूर्ति प्रदान

करके संकट के दौरान एक जिम्मेदार अंतरराष्ट्रीय नागरिक के रूप में भी काम किया। इनमें हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और पेरासिटामोल जैसी दवाएं शामिल थीं। इन दवाइयों को लॉकडाउन और लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद भी पहुंचाया गया। भारतीय रैपिड रिस्पांस टीमों को महामारी से मुकाबला करने में सहायता के लिए कोमोरोस, कुवैत, मालदीव और मॉरीशस में भी तैनात किया गया था।

भारत में कोविड टीके के विकास और उत्पादन और उनके निर्यात ने वैश्विक स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक जिम्मेदार और विश्वसनीय हितधारक के रूप में और एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में भारत की स्थिति को उजागर किया। इससे भारत के जैव-फार्मास्युटिकल क्षेत्र की क्षमताओं पर भी ध्यान केंद्रित हुआ। 2021 में, भारत ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मॉरीशस, सेशेल्स, श्रीलंका, यूएई, ब्राजील, मोरक्को, बहरीन, ओमान, मिस्र, अल्जीरिया, कुवैत और दक्षिण अफ्रीका को वैक्सीन प्रदान की। यह आपूर्ति अनुदान सहायता के साथ-साथ वाणिज्यिक आधार पर की गई।

मंत्रालय ने याला में आई रुकावटों के कारण कूटनीतिक संप्रेषण और बातचीत के समक्ष आई चुनौतियों के सामने स्वयं को तेजी से एवं बड़े पैमाने पर अनुकूलित किया। वर्चुअल उपकरणों का उपयोग करते हुए कोरोना-युग की कूटनीति तेजी से सक्रिय की गई। वर्चुअल प्लेटफॉर्म और वॉयस कम्युनिकेशन का उपयोग कर सभी स्तरों पर बहुपक्षीय, अनेकपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकें की गईं। प्रधान मंत्री ने जी 20, सार्क, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, वैक्सीन शिखर सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन और आसियान-भारत शिखर सम्मेलन सहित कई वर्चुअल बहुपक्षीय और अनेकपक्षीय शिखर बैठकों में भाग लिया।

प्रधान मंत्री ने दुनिया भर के नेताओं के साथ कम से कम 70 टेली-वार्तालाप और वर्चुअल बैठकें की। वर्चुअल शिखर बैठकें भी शुरू की गईं और प्रधान मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, डेनमार्क, यूरोपीय संघ, इटली, लक्जमबर्ग, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान और वियतनाम के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

विदेश मंत्री ने दुनिया भर के अपने समकक्ष नेताओं और अन्य नेताओं के साथ कम से कम 113 टेली-वार्तालाप और बैठकें की। विदेश मंत्री ने 27 देशों के साथ वर्चुअल संयुक्त आयोग की बैठकें की। उन्होंने कई बहुपक्षीय / अनेकपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठकों में भी भाग लिया। इनमें ब्रिक्स, एससीओ, आरआईसी, जी 20, अफगानिस्तान शांति वार्ता और अफगानिस्तान प्रतिज्ञा सम्मेलन, आईबीएसए, जी 4, सार्क, बहुपक्षवाद के लिए गठबंधन, भारत-मध्य एशिया संवाद, सीआईसीए, भारत-जीसीसी संवाद, भारत-नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन शामिल हैं।

विदेश मंत्री ने महामारी के पश्चात पहली याला के रूप में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए रूस की याला की। इसके बाद, विदेश मंत्री ने बहरीन, जापान, कतर, सेशेल्स, श्रीलंका और संयुक्त अरब और अमीरात की याला की।

राज्य मंत्री ने ओमान और यूएई की याला की। राज्य मंत्री ने सूरीनाम के साथ एक संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता भी की।

विदेश सचिव ने महामारी के पश्चात पहली विदेश राजनयिक याला के रूप में अगस्त 2020 में बांग्लादेश की याला की। इसके बाद उन्होंने फ्रांस, जर्मनी,

म्यांमार, मालदीव, नेपाल और ब्रिटेन की आधिकारिक याला की।

इस अवधि के दौरान विदेशों से आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की यालाएं होती रहीं। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और रक्षा सचिव ने 26-27 अक्टूबर 2020 तक 2 + 2 की बैठक के लिए भारत की याला की। अन्य देशों के गणमान्य व्यक्तियों की यालाओं में 14-17 दिसंबर, 2020 तक यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 14-16 जनवरी, 2021 तक नेपाल के विदेश मंत्री की याला शामिल है।

जैसे ही भारत ने अनलॉक करना शुरू किया, 24 देशों के साथ एयर बबल समझौतों पर बातचीत हुई, जिससे भारत और इन गंतव्य देशों के बीच आवाजाही बहाल हो गई।

इस अवधि के दौरान पड़ोस प्रथम की नीति भारतीय कूटनीति के मूलभूत स्तंभों में से एक रही है। हमारे विदेशी कोविड सहायता कार्यक्रमों में हमारे पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी गई। भारत के 10 मिलियन अमरीकी डॉलर को योगदान से सार्क कोविड -19 इमरजेंसी फंड बनाया गया।

कई संयुक्त क्षमता निर्माण कार्यक्रम जैसे भारत-भूटान मैत्री छालवृत्ति, ई-आईटीईसी कार्यक्रम शुरू किए गए। भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड से संबंधित आवश्यक दवाओं की खेप समुद्र के रास्ते मालदीव भेजी और और 6.2 टन दवाइयां वायुयान द्वारा भेजी। भारत ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को कोविड से संबंधित दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को वायुयान द्वारा भेजा।

प्रधानमंत्री ने 15 मार्च 2020 को महामारी के प्रसार को कम करने के लिए प्रत्येक देश के लिए सहकारिता के उपायों की पहचान करने के लिए सार्क नेताओं की एक बैठक बुलाई। भारत एवं बांग्लादेश एवं भारत और श्रीलंका के बीच वर्चुअल शिखर बैठकें हुई हैं। प्रधान मंत्री ने 1 जनवरी 2020, 10 अप्रैल और 15 अगस्त 2020 को नेपाल के प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने श्रीलंका की याला की और विदेश सचिव ने बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और मालदीव की याला की। इस अवधि के दौरान मंत्रिस्तरीय और वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर वर्चुअल मंचों का उपयोग करते हुए नियमित बातचीत जारी रही।

पड़ोस में कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विकास साझेदारी परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ा। जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें बांग्लादेश के साथ चिल्हाटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक और भूटान के साथ रूपे कार्ड के चरण-II का शुभारंभ शामिल हैं। नई अखौरा-अगरतला क्रॉस-बॉर्डर रेलवे लिंक, भारत-म्यांमार-थाईलैंड लिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, भूटान के साथ जल विद्युत परियोजनाएं, कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट सहित कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम जारी है।

व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में, प्रधान मंत्री के सागर- क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास- के व्यापक दृष्टिकोण के तहत रक्षा और सुरक्षा, विकास साझेदारी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत किया गया है। उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखे गए थे। 30 जुलाई, 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधान मंत्री और मॉरीशस के प्रधानमंत्री, प्रवीण जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरीशस में नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया।

हिंद महासागर क्षेत्र को कोविड सहायता में प्राथमिकता दी गई। मिशन सागर के माध्यम से एचएडीआर सहायता और कोविड राहत पहुंचाई गई जिसमें भारतीय नौसेना के जहाजों ने मॉरीशस, सेशेल्स, कोमोरोस और मेडागास्कर तक सहायता पहुंचाई। सेशेल्स और मॉरीशस को टीकों की आपूर्ति की गई।

भारत की एक्ट ईस्ट नीति पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ अपने संबंधों पर केंद्रित है। उच्च-स्तरीय संपर्कों को बनाए रखा गया और इनमें बढ़ोतरी हुई। प्रधान मंत्री ने इस क्षेत्र के 9 देशों के साथ टेलीफोन पर बातचीत और वर्चुअल बैठकें की। वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के साथ शिखर सम्मेलन स्तर की बैठकें हुईं। विदेश मंत्री ने मंगोलिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और वियतनाम में अपने समकक्षों के साथ बैठकें की। उन्होंने 06 अक्टूबर, 2020 को टोक्यो में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

भारत ने आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया-यूरोप बैठक (एएसईएम), मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी), अय्यवाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (एसीएमईसीएस), और भारत-प्रशांत महासागरीय पहल (आईपीओआई) सहित विभिन्न भारत-प्रशांत कार्यद्वारों के साथ अपने संबंधों की प्रगाढ़ता बनाए रखी।

मध्य पूर्व और खाड़ी क्षेत्र में भारत के भागीदारों से संपर्क भी बनाए रखा गया। प्रधान मंत्री ने मिस्र, इजरायल, जॉर्डन, कुवैत फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब और यूएई के साथ वर्चुअल बैठकें कीं। विदेश मंत्री ने यूएई और ओमान के समकक्षों के साथ वर्चुअल बातचीत की और संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक संयुक्त आयोग की बैठक की। महामारी के दौरान विदेश में विदेश मंत्री की पहली यात्रा का पहला पड़ाव पत्तन सितंबर, 2020 में तेहरान था। इसके बाद, उन्होंने नवंबर 2020 में यूएई एवं बहरीन और दिसंबर 2020 में कतर की यात्रा की। राज्य मंत्री ने दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में क्रमशः ओमान और यूएई की यात्रा की।

इस क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी संख्या है। यह बात इस क्षेत्र में वंदे भारत मिशनों तथा मिशनों और केंद्रों द्वारा सामुदायिक कल्याण गतिविधियों के लिए प्रमुखता से ध्यान में रखी गई। भारतीय प्रवासी की क्षमताओं और उनके कल्याण के मुद्दे पर इस क्षेत्र की सरकारों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा गया था। इस क्षेत्र में लोगों के लाने-ले जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई के साथ4 एयर बबल व्यवस्थाएं की गईं।

अफ्रीका में भागीदारों के साथ संपर्क बनाए रखा गया। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया, मोजांबिक, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और युगांडा में अपने समकक्षों के साथ वर्चुअल बैठकें की। विदेश मंत्री ने नाइजीरिया के साथ एक वर्चुअल कॉल और अंगोला के साथ एक संयुक्त आयोग की बैठक की। भारत ने अफ्रीका में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति का विस्तार किया और साओ तोम प्रिंसिपे, सियरा लियोन और टोगो में नए निवासी मिशन खोलने को मंजूरी दी गई।

विकास साझेदारी संबंधी क्रियाकलाप जारी रहे। 2020 में विभिन्न देशों को लगभग 1.36 बिलियन अमरीकी डालर की 13ऋण सहायताएं प्रदान की गईं

और 2020-21 में 6 ऋण सहायता परियोजनाएँ पूरी हुईं। भारत वर्तमान में 308 ऋण सहायताओं में 31.6 बिलियन अमरीकी डालर का व्यय कर रहा है। विकास साझेदारी प्रशासन ने महामारी के दौरान भारत के एचएडीआर और कोविड राहत कार्यों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवधि के दौरान लोगों की व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ आईटीईसी पाठ्यक्रम काफी हद तक निलंबित रहे। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल सुपुर्दगी और कोविड -19 प्रबंधन रणनीतियों पर ऑनलाइन ई-आईटीईसी पाठ्यक्रमों के माध्यम से कई आईटीईसी कार्यक्रम जारी रखे गए।

भारत विभिन्न साझेदार देशों में सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण परियोजनाओं में शामिल रहा है। वियतनाम में माई सन मंदिर परिसर, कंबोडिया में ता प्रोम और प्रिय विहार मंदिर और लाओ पीडीआर में वात फॉओ मंदिर का पुनरुद्धार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को इस अवधि के दौरान उच्चतम स्तरों पर नियमित संपर्कों द्वारा सुदृढ़ किया गया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 24 फरवरी 2020 को भारत का दौरा किया और अहमदाबाद, गुजरात में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में भाग लिया। इसके बाद, प्रधान मंत्री ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से कई अवसरों पर और आगामी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन से बात की। अक्टूबर 2020 में वार्षिक 2 + 2 बैठकों के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल आर पॉम्पियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क टी एस्पर ने भारत की यात्रा की। रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाया गया। अमेरिका की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा भारत में कई बड़े निवेश करके व्यापार संबंधों को और मजबूत किया गया। लोगों के आपसी संपर्क जारी रहे। एयर बबल की स्थापना की गई और इसका संचालन शुरू किया गया।

भारत ने रूस के साथ अपनी विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखा। राजनीतिक समझ, मजबूत रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष साझेदारी और ऊर्जा संबंध जैसे क्षेत्र रूस के साथ हमारे संबंधों के प्रमुख आधार हैं।

यूरोप और यूरोपीय संघ प्रमुख भागीदार हैं। भारत और यूरोपीय संघ, भारत और डेनमार्क, भारत और इटली तथा भारत और लक्जमबर्ग के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन द्वारा संबंधों को नए आयाम दिए गए। भारत और डेनमार्क ने 28 सितंबर 2020 को अपने शिखर सम्मेलन के बाद ग्रीन स्ट्रैटेजिक भागीदारी की।

चीन के साथ भारत के संबंध जटिल हैं। दोनों पक्ष अपने मतभेदों को दूर करने और किसी भी मुद्दे पर मतभेदों को विवाद नहीं बनने देने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा, दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि सीमा संधि विवाद का लंबित अंतिम समाधान, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन बनाए रखना द्विपक्षीय संबंध के समग्र विकास के लिए एक आवश्यक आधार है। हालाँकि, अप्रैल-मई 2020 के बाद से चीनी पक्ष ने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ एकतरफा रूप से यथास्थिति में बदलाव के कई प्रयास किए, जिसने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ अमन और शांति व्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान हुआ और इससे संबंधों के विकास में बाधा पहुंची। हालांकि, भारतीय सशस्त्र बलों ने इस तरह के प्रयासों का उचित जवाब दिया, दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से मुद्दों के समाधान के लिए सहमति

व्यक्त की। नतीजतन, संघर्ष के सभी क्षेत्रों से सेनाओं को हटाने के लिए और शीघ्र ही भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में अमन और शांति की पूर्ण बहाली के लिए चीनी पक्ष के साथ चर्चा जारी है।

इस वर्ष में भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी और मजबूत हुई। जापान एकमात्र देश है जिसके साथ भारत की वार्षिक शिखर बैठकें और 2 + 2 मंत्रिस्तरीय बैठकें हुईं। दोनों पक्षों ने कोविड -19 संबंधित व्यवधानों के बावजूद वर्चुअल बैठकों और फोन कॉल के माध्यम से अपने संबंधों की प्रगाढ़ता बनाए रखी। विदेश मंत्री ने 7 अक्टूबर, 2020 को 13 वीं भारत-जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के लिए टोक्यो की यात्रा की।

भारत इस अवधि के दौरान बहुपक्षीय पहलों में सक्रिय रूप से शामिल रहा। इसने शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की अध्यक्षता की और 10 नवंबर, 2020 को एक एससीओ वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। प्रधान मंत्री ने 17 नवंबर, 2020 को एक वर्चुअल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और विदेश मंत्री ने 04 सितंबर, 2020 को ब्रिक्स वर्चुअल विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्री 10 सितंबर, 2020 को रूस-भारत-चीन (आरआईसी) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मास्को की यात्रा की।

भारत 1 जनवरी, 2021 को एक गैर-स्थायी कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद-निरोध समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। भारत सुधारित बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध है जो मानव-केंद्रित वैश्वीकरण और वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है।

भारत की आगामी महत्वपूर्ण बहुपक्षीय व्यस्तताएं हैं। भारत वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष और डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष है। यह 2023 में जी-20 की अध्यक्षता भी करेगा। इन जिम्मेदारियों का प्रबंधन करने के लिए संचालन व्यवस्था संबंधी और ठोस तैयारियां चल रही हैं।

भारत के पड़ोसी

अफगानिस्तान

भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौती के बावजूद 2020-21 में और अधिक मजबूत हुई। राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, कनेक्टिविटी, विकास साझेदारी, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग, शिक्षा और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय संपर्क जारी रहे।

विदेश मंत्री ने 12 सितंबर 2020 को दोहा में वर्चुअल रूप से अंतर-अफगान वार्ता के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्री ने बाद में 24 नवंबर 2020 को जिनेवा में आयोजित 2020 अफगानिस्तान सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

भारत और अफगानिस्तान ने शत्रुता बांध बनाने के लिए एक करार किया है, जो काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी महासभा, अक्टूबर 2020 में एक अनुकूलित वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुई, जिसमें 53 सदस्य देशों ने भाग लिया। आपदा निवारण अवसरचना संबंधी गठबंधन की शासी परिषद की पहली बैठक और कार्यकारी समिति की पहली बैठक क्रमशः मार्च और जून 2020 में हुई थी।

संचार और संपर्क के पारंपरिक माध्यमों और सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए विदेशी मीडिया और इनफ्ल्यूएंसर्स और पूरे विश्व के लोगों के लिए रणनीतिक पहुंच को बनाए रखा गया। लोक राजनय के क्षेत्र में प्रबुद्ध मंडलों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क व्यवस्था में गति लाई गई। मंत्रालय के प्रमुख सम्मेलनों, रायसीना डायलॉग, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट और एशियन इकोनॉमिक डायलॉग ने वर्चुअल पद्धति को अपनाकर नई वास्तविकता के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है।

मंत्रालय ई-सनद और मदद प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक और कौसुली सेवाओं की सुपुर्दगी में लगातार सुधार कर रहा है। दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों से जुड़ने के लिए 30 दिसंबर, 2020 को मंत्रालय ने वैश्विक प्रवासी अनुसंधान पोर्टल और ऐप भी लॉन्च किया।

9 जनवरी, 2021 को 16 वां प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) वर्चुअल पद्धति से आयोजित किया गया।

डिजिटल प्लेटफार्मों को भी मंत्रालय के कामकाज के साथ एकीकृत किया जा रहा है। मंत्रालय वर्चुअल कूटनीति के बढ़ते हुए कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को ढालने में सक्षम रहा। मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग ने 16 दिसंबर, 2020 को एक वेबसाइट www.indbiz.gov.in शुरू की।

निम्नलिखित पृष्ठ 2020-21 के दौरान भारत के विदेश संबंधों के प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं।

इससे पहले भारत ने काबुल शहर को बिजली प्रदान करने वाली 202 किमी पुल-ए-खुमरी हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया था। भारत ने अफगानिस्तान में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के चरण-IV को भी शुरू किया है, जिसमें 80 मिलियन अमरीकी डालर के 100 से अधिक प्रोजेक्ट शामिल हैं।

भारत और अफगानिस्तान के बीच 2020-21 में द्विपक्षीय व्यापार 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया है।

भारत ने अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए चाबहार के माध्यम से 20 मीट्रिक टन से अधिक जीवन रक्षक दवाओं और 75,000 मीट्रिक टन गेहूं की मानवीय सहायता सहित कोविड -19 से संबंधित सहायता प्रदान की। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट (एसआईआई) द्वारा निर्मित कोविशिल्ड वैक्सीन की 500,000 खुराक फरवरी 2021 में अनुदान सहायता के रूप में अफगानिस्तान भेजी गई थी।

भारत-बांग्लादेश

भारत ने अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों (एएनडीएसएफ) के सदस्यों के लिए 2020 में क्षमता-निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए।

बांग्लादेश

भारत-बांग्लादेश के बीच उच्चतम स्तर पर संपर्क बनाए रखते हुए 2020-21 में दोनों देशों के संबंधों में आगे प्रगति हुई। प्रधान मंत्री और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना ने 17 दिसंबर, 2020 को भारत-बांग्लादेश वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया।

इस शिखर सम्मेलन के दौरान, चिल्हाटी-हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया और कृषि, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, और विकास साझेदारी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आठ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर महात्मा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान की विरासत पर बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया।

विदेश मंत्री स्तर की संयुक्त सलाहकार आयोग (जेसीसी) की बैठक वर्चुअल रूप से 29 सितंबर, 2020 को हुई। विदेश सचिव ने मार्च और अगस्त 2020 में ढाका की दो यात्राएं कीं।

वर्ष 2021 बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50 वीं वर्षगांठ और भारत एवं बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों का स्थापना वर्ष है।

बांग्लादेश अब दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत, बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत की कुल विकास भागीदारी का 30% के करीब बांग्लादेश के लिए होता है। भारत ने लगभग 10 बिलियन अमरीकी डालर रियायती ऋण बांग्लादेश को प्रदान किया है। ये इसकी तीन सबसे बड़ी द्विपक्षीय ऋण व्यवस्थाओं में शामिल है।

भारत ने बांग्लादेश को कोविड से संबंधित सहायता की तीन खेप प्रदान की हैं। जनवरी 2021 में बांग्लादेश को कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन से अधिक खुराक अनुदान सहायता के रूप में भेजी गई थी।

भूटान

वर्ष 2020-21 के दौरान भारत और भूटान के बीच बहुआयामी संबंध और मजबूत हुए। परंपरागत के साथ-साथ जल विद्युत, आईसीटी, स्वास्थ्य, संस्कृति, कृषि, अंतरिक्ष, तृतीयक शिक्षा एवं डिजिटल और वित्तीय कनेक्टिविटी सहित सहयोग के नए क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हुई है।

16 अप्रैल 2020 को प्रधान मंत्री ने भूटान के प्रधान मंत्री लोतेय त्शोरिंग के साथ बात की। दोनों राजनेताओं ने इससे पहले मार्च 2020 में कोविड -19 पर सार्क नेताओं के सम्मेलन के दौरान वर्चुअल रूप से बातचीत की थी। भारत और भूटान के प्रधानमंत्रियों ने 20 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल समारोह के दौरान रूपए कार्ड के चरण -2 का शुभारंभ किया।

600 मेगावाट की खोलोंगछु (संयुक्त उद्यम) जल विद्युत परियोजना के लिए रियायत समझौते पर 29 जून 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों सरकारें चल रही दो अन्य परियोजनाओं 1200 मेगावाट की पुनतासंगछू-I और 1020 मेगावाट की पुनतासंगछू-II के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए घनिष्ठ

समन्वय बनाए रखना चाहती हैं।

भारत, भूटान (2018-23) की 12 वीं पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) के लिए 4500 करोड़ रुपये का वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है,जिसमें परियोजना संबंधी सहायता के लिए 2800 करोड़ रुपये,उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपये और 850 करोड़ रुपए कार्यक्रम अनुदान के लिए हैं। भारत-भूटान की 12 वीं पंचवर्षीय योजना (एफवाईपी) के लिए 400 करोड़ रुपए की ‘ट्रांज़िशनल ट्रेड सपोर्ट फैसिलिटी’ देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। दोनों पक्षों ने बुनियादी ढांचा विकास, सड़कों और पुलों, उद्योगों, कृषि, ई-गवर्नेंस, सामुदायिक विकास परियोजनाओं जैसे सिंचाई चैनलों, खेत सड़कों, ब्लॉक कनेक्टिविटी सड़कों, बुनियादी स्वास्थ्य इकाइयों, आदि के क्षेत्रों में लगभग 600 बड़ी और छोटी परियोजनाओं की पहचान की है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

जनवरी 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की 150,000 खुराक अनुदान सहायता के रूप में भूटान को भेजी गई थी।

मालदीव

कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत और मालदीव के बीच मजबूत सहयोग बनाए रखा गया। विदेश सचिव ने 8-10 नवंबर 2020 के दौरान मालदीव का दौरा किया। यह महामारी के बाद मालदीव की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। उनकी यात्रा के दौरान, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा के दौरान तीन अन्य समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

मालदीव को भारत की बहु-आयामी और समय पर सहायता ने इसकी कोविड -19 के स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक प्रभावों का सामना करने में मदद की। भारतीय वायु सेना ने अप्रैल 2020 में ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से विभिन्न भारतीय शहरों से 6.2 टन दवाईयां एयर-लिफ्ट की। मई 2020 में, भारतीय नौसेना के आईएनएस केसरी ने मिशन सागर के तहत 580 टन खाद्य सहायता प्रदान की। जनवरी 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की 100,000 खुराक अनुदान सहायता के रूप में मालदीव को भेजी गई थी।

दोनों देशों ने विभिन्न मौजूदा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर ऋण व्यवस्था और अनुदान के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है। नए ऐवन्यू को शामिल करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार किया गया। उच्च प्रभाव वाली 9 सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। राष्ट्रपति सोलीह ने जनवरी 2021 में एमवीआर 8 मिलियन भारतीय अनुदान से वित्त पोषित एकुवेनी सिंथेटिक ट्रैक परियोजना का उद्घाटन किया। भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को एक डोर्नियर विमान प्रदान किया, जिसे मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों द्वारा संचालित किया जाएगा।

भारत ने अगस्त 2020 में मालदीव के साथ दक्षिण एशिया का पहला हवाई यात्रा बबबल बनाया। भारत महामारी ग्रस्त वर्ष 2020 में मालदीव में पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत बन गया। सितंबर 2020 में दोनों देशों के बीच सीधी नौ सेवा शुरू की गई। भारत की ‘नेबरहुड फ़र्स्ट’ पॉलिसी और मालदीव की ‘इंडिया फ़र्स्ट’ पॉलिसी ने परस्पर लाभ के लिए मिलकर काम किया।

म्यांमार

म्यांमार, आसियान के लिए भारत का जमीनी प्रवेश द्वार है और भारत के ‘नेबरहुड फ़र्स्ट’ और “एक्ट ईस्ट “ नीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक है।

उच्च स्तरीय यात्राओं की एक श्रृंखला द्वारा द्विपक्षीय संबंधों में गति बनाए रखने में मदद मिली है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने 26-29 फरवरी 2020 के दौरान भारत का दौरा किया। विदेश सचिव और थल सेनाध्यक्ष ने 4-5 अक्टूबर 2020 को म्यांमार का दौरा किया। दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श अक्टूबर 2020 में वर्चुअल मंच के माध्यम से हुआ।

म्यांमार को भारत की विकास सहायता 1.8 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गई है जिसमें अनुग्रह अनुदान सबसे बड़ा घटक है। अब तक सीमावर्ती क्षे्ल विकास कार्यक्रम के तहत, 100 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। राखीन राज्य में जापान द्वारा निर्मित स्कूलों के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करने के लिए भारत जापान के साथ त्रिपक्षीय स्तर पर काम कर रहा है। भारत ने म्यांमार में कौशल विकास और क्षमता निर्माण पहलों में भी निवेश किया है।

भारत ने म्यांमार को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित कोविड से संबंधित सहायता प्रदान की है। जनवरी 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक अनुदान सहायता के रूप में म्यांमार भेजी गई थी।

सागर - इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के हमारे विजन के अनुसार भारत ने अक्टूबर 2020 में म्यांमार की नौसेना को एक किलो-क्लास पनडुब्बी, आईएनएस सिंधुवीर सौंपी। यह म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी है। दिसंबर 2020 में दोनों देशों के बीच हाइड्रोग्राफी संबंधी एक कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए गए।

नेपाल

भारत की ‘नेबरहुड फ़र्स्ट पॉलिसी ’के अनुरूप, नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों में गतिशीलता कायम रही है जिसमें सतत कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने 15 मार्च 2020 को आयोजित सार्क राजनेताओं के वीडियो-सम्मेलन में और 10 अप्रैल 2020 को टेलीफोन पर अपनी बातचीत के दौरान कोविड -19 महामारी का संयुक्त रूप से मुकाबला करने पर विचार साझा किए।

भारत और नेपाल के बीच संबंध उच्च स्तरीय यात्राओं और विभिन्न द्विपक्षीय तंत्र की वर्चुअल बैठकों द्वारा और मजबूत हुए। विदेश मंत्री और नेपाली के विदेश मंत्री ने 20 मार्च 2020 को टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश सचिव ने 26 से 27 नवंबर, 2020 तक नेपाल का दौरा किया और सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवने ने 4 से 6 नवंबर, 2020 तक नेपाल का दौरा किया। वाणिज्य, रेलवे, बिजली, तेल और गैस क्षेत्र पर भारत-नेपाल संयुक्त कार्य समूह ने भी संबंधित क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए वर्चुअल रूप से मुलाकात की।

भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की 6 वीं बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री और नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा की गई। दोनों पक्षों ने जनकपुर होते हुए जयनगर से कुर्था की भारत और नेपाल के बीच पहली यात्री रेलवे लाइन का

प्रस्तावना और सार-संक्षेप

कार्य पूरा होने का स्वागत किया।

2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार को 7 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक करने के साथ भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना रहा। नेपाल में भारत द्वारा सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं ने सड़क और रेल कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचा, मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2020-21 के दौरान बड़ी प्रगति हासिल की। भारतीय सहायता के साथ, नेपालगंज में एक नए एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण पर नवंबर में कार्य शुरू हुआ। पिछले वर्ष भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण की कई परियोजनायें और उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनायें भी पूरी हुई।

कोविड -19 महामारी को रोकने के प्रयासों में नेपाल की सहायता करने के लिए भारत ने इसे लगभग 25 टन दवाईयां, चिकित्सा उपकरण और अन्य चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की। भारत ने सीमा पार व्यापार और आपूर्ति के निर्बाध प्रवाह को भी सुकर बनाया। दोनों पक्षों ने फंसे हुए नागरिकों की वापसी के प्रबंधन के लिए मिलकर काम किया। जनवरी 2021 में, भारत ने नेपाल को अनुदान सहायता के रूप में कोविशिल्ड वैक्सीन की 1 मिलियन खुराक भेजी।

पाकिस्तान

नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अमन और शांति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को 2003 के युद्धविराम का पालन करने के लिए बार-बार याद दिलाने के बावजूद पाकिस्तानी बलों ने युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने के साथ साथ लगातार गोलीबारी और संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में छद्म युद्ध की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीके शुरू किए, जिसमें सीमा पार आतंकवाद और हथियार एवं नशीले पदार्थों की तस्करी में सहायता और बढ़ावा देने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के साथ सुरंगों और झ्रनों का उपयोग शामिल है।

कोविड की शुरुआत से ही भारत ने पाकिस्तान से भारत में 1400 से अधिक भारतीय नागरिकों और दीर्घकालिक वीजा धारकों (एनओआरआई वीज़ा) और कोविड -19 के कारण लागू सीमा प्रतिबंधों की वजह से भारत में फंसे 1250 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों की स्वदेश वापसी सुकर बनाई है।

भारत बूढ़ी रावी चैनल के पार करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।सरकार,कोविड -19 प्रतिबंधों के बावजूद भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक तीर्थस्थलों की यात्रा के संबंध में 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के अनुसार तीर्थयात्रियों की यात्रा लगातार सुकर बना रही है।

श्रीलंका

In2020-21 में, भारत की “नेबरहुड फ़र्स्ट” और सागर (सिक्वोरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) नीतियों के अनुरूप इसके श्रीलंका के साथ संबंध और अधिक मजबूत हुए।

26 सितंबर 2020 को भारत के प्रधान मंत्री और श्रीलंका के प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच आयोजित एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन द्वारा द्विपक्षीय संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं पर प्रगति की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय

सुरक्षा सलाहकार ने 27-28 नवंबर को कोलंबो में समुद्री सुरक्षा के संबंध में एनएसए लिपक्षीय बैठक के लिए श्रीलंका का दौरा किया। विदेश मंत्री ने 5-7 जनवरी 2021 के दौरान कोलंबो का दौरा किया और राष्ट्रपति गोताबया राजपक्षे, प्रधान मंत्री महिंदा राजपक्षे और विदेश मंत्री दिनेश गनवार्दन से मुलाकात की।

भारत ने श्रीलंका की आवश्यकताओं के अनुसार, कोविड -19 रिस्पांस, व्यापार और निवेश, रक्षा, विकास सहयोग और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में श्रीलंका के लिए अपनी सहायता जारी रखी। भारत ने श्रीलंका को कुल 25

हिंद महासागर क्षेत्र

कोविड महामारी के बावजूद हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंध 2020-21 में निर्बाध जारी रहे।

कोमोरोस

भारत-कोमोरोस द्विपक्षीय संबंधों में और तेजी आई। कोविड आपदा के दौरान कोमोरोस सरकार और वहां के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए विदेश मंत्री ने 25 अप्रैल 2020 को कोमोरोस के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कोमोरियाई पक्ष से चिकित्सा सहायता के लिए अनुरोध के जवाब में, एक 14-सदस्यीय भारतीय चिकित्सा सहायता दल ने 1-18 जून 2020 को कोमोरोस का दौरा किया। भारत द्वारा दवाओं की एक खेप जिसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) भी शामिल थी, कोमोरोस को दान दी गई।

मेडागास्कर

2020-21 में भारत मेडागास्कर संबंध और प्रगाढ़ हुए। कोविड -19 महामारी से निपटने में सहायता के अनुरोधों पर भारत ने मेडागास्कर को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान की, जिसमें एचसीक्यू की 1,00,000 गोलियों की आपूर्ति और एज़िथ्रोमाइसिन की 44,000 गोलियां शामिल हैं।

इससे पहले, बाढ़ के बाद भारत ने मेडागास्कर को मानवीय और आपदा राहत सहायता (एचएडीआर) प्रदान की थी। आईएनएस ऐरावत ने ‘ऑपरेशन वेनिला’ के तहत अंटिशिराना बंदरगाह का दौरा किया और 1 फरवरी 2020 को मेडागास्कर के बाढ़ प्रभावित उत्तरी क्षेत्र के लिए राहत सामग्री पहुंचाई। आईएनएस शार्दुल ने 10-14 मार्च 2020 के दौरान 600 टन चावल पहुंचाने के लिए अंटिशिराना बंदरगाह का भी दौरा किया।

प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नत्से द्वारा दूतावास भवन में 8 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन के साथ महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई गई।

मॉरीशस

2020-21 में मॉरीशस के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए। कोविड आपदा के दौरान भारत पहला रेस्पॉन्डर था, जिसने लगभग 14 टन कोविड संबंधित आवश्यक दवाइयां प्रदान की थी, जिसमें एचसीक्यू की 500,000 गोलियाँ और आयुर्वेदिक दवाओं की एक विशेष खेप शामिल थी। मिशन सागर के

टन से अधिक वजन वाली आवश्यक दवाओं और अन्य वस्तुओं की चार खेपें भेंट कीं। भारत और श्रीलंका दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र से अपने फंसे हुए नागरिकों की सुचारू रूप से स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने में भी निकटता से समन्वय किया। वंदे भारत मिशन की ग्यारह उड़ानों के तहत, समुद्री जहाज, आईएनएस जलाश्व, और अनेक चार्टर्ड उड़ानों द्वारा लगभग 3500 फंसे हुए भारतीयों की श्रीलंका से स्वदेश वापसी करवाई।

जनवरी 2021 में, भारत ने श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में कोविशिल्ड वैक्सीन की 500,000 खुराकें भेजीं।

भाग के रूप में, कोविड आपातकाल से निपटने में मदद करने के लिए मॉरीशस में चिकित्सा सहायता दल तैनात किए गए थे। प्रधान मंत्री ने 23 मई 2020 को प्रधान मंत्री प्रवीण जुगनाथ के साथ टेलीफोन पर बातचीत की जिसमें प्रधानमंत्री जुगनाथ ने कोविड महामारी के दौरान भारत की सहायता के लिए धन्यवाद दिया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने 30 जुलाई 2020 को एक वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त रूप से मॉरीशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। भारत द्वारा मॉरीशस को दिए गए 353 मिलियन अमरीकी डालर के ‘विशेष आर्थिक पैकेज’ की भारतीय अनुदान सहायता के तहत यह ऐतिहासिक परियोजना पूरी की गई है।

भारत ने 25 जुलाई 2020 को मॉरीशस तट के पास एमवी वाकाशियो नामक जहाज में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता के लिए मॉरीशस के अनुरोध का तुरंत जवाब दिया। भारत ने तेल फैलाव से निपटने के लिए 30 टन के विशेष तकनीकी उपकरण और 10 सदस्यीय तटरक्षक तकनीकी रिस्पांस दल भेजे।

जनवरी 2021 में कोविशिल्ड वैक्सीन की 100,000 खुराकें मॉरीशस को अनुदान सहायता के रूप में भेजी गई थीं।

सेशेल्स

2020 में सेशेल्स के साथ भारत के संबंधों में और तेजी आई। सेशेल्स, भारतीय कोविड -19 संबंधी सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य था और जीवन रक्षक दवाओं को प्राप्त करने वाले पहले कुछ देशों में से एक था। 15 अप्रैल 2020 को एयर इंडिया की एक चार्टर्ड उड़ान के माध्यम से 4 टन दवाओं की पहली खेप भेजी गई थी। दूसरी खेप 7 जून 2020 को आईएनएस केसरी के माध्यम से मिशन सागर के एक भाग के रूप में दी गई। जनवरी 2021 में कोविशिल्ड वैक्सीन की 50,000 खुराकें सेशेल्स को अनुदान सहायता के रूप में भेजी गई थीं।

विकासत्मक सहयोग भारत के सेशेल्स के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। उच्च प्रभाववाली सामुदायिक विकास परियोजना के तहत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सेशेल्स, सितंबर 2020

में भारतीय अनुदान सहायता से संचालित ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती (टेलीमेडिसिन और टेली-एजुकेशन) परियोजना में औपचारिक रूप से

दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और ओशिनिया के साथ भारत के संबंध अधिनियम पूर्व नीति ढांचे के तहत आते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रमुख तत्व 2020-21 में भी गतिशील रहे जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तर पर निरंतर संपर्कों के माध्यम से इस क्षेत्र के देशों के साथ बढ़ते आर्थिक सहयोग,सांस्कृतिक संबंधों और रणनीतिक संबंधों में विकास जारी रहा।

ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम के साथ भारत के संबंध साझे लोकतांत्रिक लोकाचार, बढ़ते भू-स्थानिक वैचारिक संपर्क, सभी की भलाई के लिए साझी आकांक्षाओं, लोगों-से-लोगों के बीच मजबूत संबंध और कम्प्लीमेंटरी अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित हैं।

4 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्तर का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था। 2020 में, प्रधान मंत्री ने इंडोनेशिया और फिलीपींस के राष्ट्रपतियों और ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने 21 दिसंबर 2020 को व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों पर एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में वियतनामी प्रधान मंत्री गुयेन जुआनफुच के साथ विचार साझा किये।

5 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड-टेबल 2020 के दौरान ऑस्ट्रेलियाई अधिवर्षिता निधि की भागीदारी हुई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2020 को वर्चुअल रूप से बेंगलुरु टेक समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया जिसका उद्घाटन भारत के

भारत- प्रशान्त

2020-21 के दौरान इस महामारी द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के बावजूद, भारत ने विभिन्न इंडो-पैसिफिक ढांचे के साथ अपने संपर्क जारी रखे। इनमें एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशंस (आसियान), ईस्ट एशिया समिट (ईएएस), इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया-यूरोप मीटिंग (एएसईएम), मेकांग गंगा कोऑपरेशन (एमजीसी), अयेयावाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (ए सी एम इ सी एस), और इंडो-पैसिफिक ओसियन इनिशिएटिव पहल (आईपीओआई) शामिल हैं।

वर्ष 2020 के अंत में 37 वां आसियान, 15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), और वियतनाम द्वारा आयोजित 11-15 नवंबर 2020 को 17वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने वियतनामी प्रधान मंत्री गुयेन जुआनफुच के साथ 17 वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन ने आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। विदेश मंत्री ने 15 वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिया।

शामिल हो गया।

प्रधानमंत्री ने किया था।

प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री की रूप में फिर से चुनी गई। सुश्री प्रियांका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनीं और उन्हें समुदाय, युवा और स्वैच्छिक क्षेत्र के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। मंत्री राधाकृष्णन ने 8 जनवरी 2021 को 5 वें युवा प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया।

वियतनाम के उपराष्ट्रपति ने फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया। थाईलैंड के राजा की दोनों बहनों ने राजकुमारी महाचक्रशिखरिन्दरहॉर्न और राजकुमारी चुलाभोरन ने फरवरी 2020 में भारत का दौरा किया। विदेश मंत्री ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों के साथ टेली-बातचीत की जबकि राज्य मंत्री ने अक्टूबर 2020 में एक वियतनामी थिंकटैंक (विआईआईएसएएस) को मुख्य भाषण दिया। 2020 में विदेश मंत्री स्तर पर संरचित तंत्र की बैठकें वियतनाम (संयुक्त आयोग की बैठक; 25 अगस्त 2020) और फिलीपींस [द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग (जे सी बी सी)]; 6 नवंबर 2020] के साथ आयोजित की गईं।

घोषणाओं को अपनाने और “व्यापक रणनीतिक साझेदारी” सहित 9 लैंडमार्क दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के साथ 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण विकास हुआ। ये संबंधों और प्रगाढ़ करने के लिए ठोस आधार प्रदान करेंगे।

वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 4.3% से बढ़कर 148.8 बिलियन अमरीकी डॉलर पहुंच गया। वर्ष 2020 में अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 26.55 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ। वित्त वर्ष 2020 में अमेरिका को व्यापार का कुल निर्यात 201.295 बिलियन अमरीकी डॉलर और आयात 261.468 बिलियन अमरीकी डॉलर का रहा। वर्ष के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में निर्यात 130.37 बिलियन अमरीकी डॉलर और आयात 74.68 बिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ।

वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण परामर्श आयोजित किए गए जिनमें भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक, भारत-अमेरिका सीईओ मंच, भारत-अमेरिका आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह, भारत-अमेरिका साइबर सुरक्षा वार्ता, भारत-अमेरिका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्य समूह बैठक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर परामर्श शामिल हैं। भारतीय सुरक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ-आईडीईएक्स) और अमरीकी रक्षा नवाचार यूनिट सहित भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी तथा व्यापार पहल

के बीच उद्घाटन बैठक 2020 में आयोजित की गई थी।

भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी की उन्नति के लिए प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए अनुकरणीय योगदान को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने 21 दिसंबर, 2020 को प्रधान मंत्री को अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ उपाधि, द लिजियन ऑफ मेरिट, प्रमुख सेनाध्यक्ष की पदवी से सम्मानित किया।

पूर्व एशिया

चीन

पिछले तीन दशकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति ने अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए संबंधों को मूल आधार प्रदान किया था। जबकि वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ के अवसर पर, इस वर्ष भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में काफी तनाव भी देखा गया है।

अप्रैल-मई 2020 से, चीनी पक्ष पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों और वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों और युद्ध सामग्री का जमावड़ा कर रहा था। मई के मध्य से चीनी पक्ष ने भारतीय-चीन सीमावर्ती क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र के कई हिस्सों में वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करने के कई प्रयास किए। भारतीय सशस्त्र बलों से इन प्रयासों का यथोचित उत्तर देते हुए इनका सामना किया।

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ते हुए संघर्ष को देखते हुए, दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों ने 6 जून 2020 को एक बैठक में पारस्परिक कार्रवाई सहित सैन्यबल पीछे हटाने पर सहमति जताई थी। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने और उसका पालन करने और यथास्थिति में बदलाव के लिए कोई गतिविधि नहीं करने पर सहमति व्यक्त की। हालाँकि इसका उल्लंघन करते हुए चीनी पक्ष ने 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हिंसक झड़प की। हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और चीनी पक्ष को भारी नुकसान पहुंचाते हुए उनके कई सैनिकों को मौत के घाट उतरा दिया। भारत के विदेश मंत्री ने 17 जून 2020 को चीन के स्टेट कॉउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से टेलीफोन पर बातचीत की और भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताई। भारत के विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि चीनी पक्ष को इस मामले पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि एलएसी में अमन और शांति बहाल की जा सके।

सीमा के प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों ने 5 जुलाई 2020 को टेलीफोन पर भी बातचीत की है। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई है कि दोनों पक्षों को भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में यथाशीघ्र पूर्ण रूप से सैनाएं पीछे हटाने पर काम करना चाहिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण अमन और शांति बहाल की जा सके। नेतृत्व स्तर के संपर्कों के दौरान दोनों पक्ष एलएसी पर परिस्थित के शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर घनिष्ठ संप्रेषण बनाए रखने पर सहमत हुए।

विदेश मंत्री ने 10 सितंबर 2020 को मास्को में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रही घटनाओं

17 नवंबर, 2020 को प्रधान मंत्री और तात्कालीन निर्वाचित-राष्ट्रपति जोसफ बाइडन ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए एक जुट होकर कार्य करने पर सहमत हुए। उन्होंने, प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें कोविड-19 महामारी, सस्ते टीकों को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन से निपटना और भारत-प्रशान्त में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

पर स्पष्ट और रचनात्मक चर्चा की और वे एलएसी में चल रही समस्याओं का समाधान करने, संघर्ष के सभी क्षेत्रों से अपनी सेनाएं पीछे हटाने तथा अमन और शांति बहाल करने को सुनिश्चित करने के लिए पांच बिन्दुओं पर सहमत हो गए।

भारत-चीन सीमा मामलों (डब्ल्यूएमसीसी) पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 15वीं, 16वीं, 17 वीं, 18 वीं, 19 वीं और 20 वीं बैठक क्रमशः 24 जून 2020, 10 जुलाई 2020, 24 जुलाई 2020, 20 अगस्त 2020, 30 सितंबर 2020 और 18 दिसंबर 2020 को वीडियो-कानफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थीं। वरिष्ठ कमांडरों के बीच नौ दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं।

आज की तारीख तक, वर्तमान परिस्थिति का सामना करने और पूर्ण रूप से अमन और शांति बहाल करने के लिए सैन्य और राजनयिक प्रयास जारी हैं।

जापान

कोविड महामारी के कारण व्यवधान उत्पन्न होने पर, दोनों पक्षों ने 2020-21 में वर्चुअल बैठकों और फोन कॉल के माध्यम से अपने संबंधों की प्रगाढ़ता को बनाए रखा है। संवाद वार्ता का 6 वां संस्करण दिनांक 21 दिसंबर 2020 को टोक्यो में हाइब्रिड रूप से आयोजित किया गया था। प्रधान मंत्री ने एक वीडियो संदेश दिया जबकि प्रधान मंत्री सुगा ने व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी दी। विदेश मंत्री ने 7 अक्टूबर 2020 को जापानी विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतिगि के साथ 13 वें भारत-जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के लिए टोक्यो का दौरा किया।

दोनों देशों ने 9 सितंबर 2020 को एक्यूजिशन और क्रॉस-सर्विसिंग एग्रीमेंट या एसीएसए पर हस्ताक्षर किए। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जेआईएमईएक्स के चौथे संस्करण के पूरा होने पर 2020 में संयुक्त युद्ध अभ्यास कार्यक्रम जारी हैं। जापान और भारत ने अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में आयोजित चरण -1 मालाबार -20 में भी भाग लिया।

13 वंदे भारत उड़ानों द्वारा लगभग 2665 भारतीयों को लाया गया और 10 चार्टर उड़ानों द्वारा जापान से भारत लगभग 436 भारतीयों को लाया गया। 13 वंदे भारत उड़ानों द्वारा 1286 भारतीयों को भारत से जापान ले जाया गया।

कोरिया गणराज्य

जबकि कोविड महामारी ने बाधाएं उत्पन्न की है, सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से द्विपक्षीय आदान-प्रदान किया गया। 20 अगस्त 2020

को निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार पर भारत-कोरिया गणराज्य के बीच वर्चुअल विचार-विमर्श किया गया। वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में, 242 भारतीयों को भारत वापस लाया गया और 234 भारतीयों को यात्रा सुविधा प्रदान की गई। इसके अलावा, लगभग 1350 भारतीयों ने चार्टर उड़ानों द्वारा भारत और कोरिया गणराज्य के बीच यात्रा की।

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य

भारत सरकार ने एंटी-ट्यूबरकुलोसिस दवाओं के रूप में डीपीआर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमरीकी डालर की चिकित्सा सहायता प्रदान की।

खाड़ी देश और पश्चिमी एशिया

खाड़ी देश

भारत की 'थिंक वेस्ट नीति' के अनुरूप कोविड-19 महामारी के दौरान खाड़ी देशों और भारत के बीच मजबूत संबंध है। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में सउदी अरब की अध्यक्षता में 15वीं जी-20 शिखर सम्मलेन में वर्चुअल रूप से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने 2020-21 के दौरान क्षेत्र में अपने समकक्ष के साथ टेलीफोन वार्ता भी की।

विदेश मंत्री ने नवंबर 2020 में यूएई और बहरीन तथा दिसंबर 2020 में कतर का दौरा किया। नवंबर 2020 में भारत-जीसीसी वार्षिक राजनीतिक वार्ता वर्चुअल रूप से आयोजित की गई, जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया। राज्य मंत्री ने दिसंबर 2020 में ओमान और जनवरी 2021 में यूएई का आधिकारिक दौरा किया। भारत ने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के फैसले का स्वागत किया।

खाड़ी देशों ने अपने-अपने देशों में भारतीयों की असाधारण देखभाल की और भारतीय नागरिकों की व्यवस्थित वापसी को सुकर बनाया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि भारत में लॉकडाउन के बावजूद इन देशों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला बाधित न हो। इसी प्रकार, भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारतीय डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी महामारी से लड़ने में सहायता करने के लिए खाड़ी देशों की यात्रा कर सकें।

वंदे भारत मिशन के तहत, 230,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को खाड़ी देशों से भारत के विभिन्न राज्यों में वापस लाया गया। इसके अतिरिक्त, बहरीन, कुवैत, यूएई और कतर के साथ 4 एयर बबल व्यवस्थाओं पर सहमति हुई।

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

महामारी के कारण प्रतिबंध के बावजूद, वर्ष 2020-21 में पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (वाना) के देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गति को बनाए रखने के लिए उच्च स्तर की बातचीत जारी रही। वर्ष के दौरान, सभी वाना देशों के साथ संबंधों को टेलीफोन कॉल और वर्चुअल बैठकों के माध्यम

मंगोलिया

वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 65 वीं वर्षगांठ मनाई गई। नियमित द्विपक्षीय आदान-प्रदान से मौजूदा संबंधों में मजबूती आई है। 30 अगस्त 2020 को, भारत के चुनाव आयोग और मंगोलिया के आम चुनाव आयोग ने चुनाव के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञान और सहयोग पर हस्ताक्षर किए।

भारत-मंगोलिया सहयोग संयुक्त समिति की 7 वीं बैठक दिनांक 3 दिसंबर 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री और मंगोलिया के मुख्यमंत्री और मंत्रीमंडल सचिव, एल ओयुन-एर्डिन ने संयुक्त रूप से की।

ईरान

वर्ष 2020 में भारत और ईरान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ मनाई गई।

विदेश मंत्री ने 9 सितंबर 2020 को ईरान का दौरा किया और द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित अन्य मुद्दों पर विदेश मंत्री जवाद जरीफ़ के साथ व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की। इससे पहले, विदेश मंत्री और विदेश मंत्री जरीफ़ ने भी 13 अप्रैल 2020 को टेलीफोन पर बातचीत की और क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

ईरान की मजलिस ने सितंबर 2020 में द्विपक्षीय दोहरे कराधान को रोकने संबंधी समझौते (डीटीएए) की पुष्टि की जो द्विपक्षीय वाणिज्यिक और व्यापार संबंधों को मजबूत करेगा। चाबहार के माध्यम से पहले पोतांतरण के साथ, बंदरगाह में वर्ष 2020-21 में थोक और सामान्य नौभार यातायात में लगातार वृद्धि हुई और कोविड महामारी के दौरान मानवीय सहायता देने के लिए इस क्षेत्र के लिए “संपर्क बिंदु” के रूप में उभरा।

इसके निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद, भारत ने ईरान को 3 मिलियन अमरीकी डालर के सर्जिकल मास्कों की आपूर्ति की। 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को क्रमशः वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के हिस्से के रूप में हवाई और समुद्री मार्गों के माध्यम से ईरान से वापस लाया गया था। भारत ने टिड्डियों के नियंत्रण में ईरान की मदद करने के लिए 45 मीट्रिक टन मैलाथियान (95 फीसदी यूएलवी) की भी आपूर्ति की।

अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने 22 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 15 वें सीआईआई-एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।

एम्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2020 में इरिट्रिया के मेडिकल डॉक्टरों की क्षमता निर्माण में भागीदारी की संभावनाएं तलाशने के लिए इरिट्रिया का दौरा किया। जुलाई 2020 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय और मोरक्को की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति परिषद के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

राज्य मंत्री ने दिनांक 23 जून 2020 को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (युएनआरडब्ल्यूए) हेतु विशेष मंत्रिस्तरीय

अफ्रीका

प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री ने वर्ष 2020-21 में इस क्षेत्र में अपने समकक्षों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखा। भारत-अंगोला संयुक्त आयोग की पहली बैठक सितंबर 2020 में आयोजित की गई, जिसकी सहअध्यक्षता विदेश मंत्री और अंगोला के समकक्ष द्वारा की गई। इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य, राजनयिकों के प्रशिक्षण और वीजा सुविधा पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य मंत्री ने जनवरी 2020 में मोजाम्बिक और जनवरी 2021 में घाना का आधिकारिक दौरा किया। सितंबर 2020 में 15 वें सीआईआई-एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव में विभिन्न अफ्रीकी नेताओं ने भाग लिया।

वर्ष 2020 में साओ टोम प्रिंसिपे, सिएरा लियोन और टोगो में तीन और मिशनों के उद्घाटन के साथ अफ्रीका में हमारी राजनयिक उपस्थिति बढ़ी। मॉरिटानिया, लाइबेरिया, गिनी बिसाऊ और काबो वर्डे में जल्द ही राजनयिक मिशन खोले जाने की संभावना है। चाड ने वर्ष 2020 के शुरुआत में नई दिल्ली में अपना आवासीय दूतावास खोला और भारत वर्ष 2021 में यहां मिशन खोलने की

यूरेशिया

2020-21 के दौरान भारत के विस्तारित पड़ोस के भाग के रूप में यूरेशियन क्षेत्र के देशों विशेष रूप से रूस के साथ भारत के पारंपरिक करीबी संबंधों को और मजबूती मिली। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के कार्यवाह के तहत संभावित मुक्त व्यापार समझौते, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) और सहयोग पर भारत-मध्य एशिया वार्ता, भारत-यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईईयू) जैसे तंत्रों के माध्यम से संबंधों को और अधिक रणनीतिक महत्व मिला।

कोविड -19 महामारी के दौरान भी रूस के साथ भारत के संबंध और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन के बीच व्यक्तिगत संबंध का महत्व वर्चुअल संपर्कों की संख्या से स्पष्ट था। विभिन्न अवसरों पर दोनों नेताओं के बीच 3 टेलीफोनिक वार्ता हुई। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने मार्च-सितंबर 2020 के बीच रूस, एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार का एकमात्र मंत्री स्तरीय दौरा किया। द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75 वीं वर्षगांठ की याद में मास्को में सैन्य परेड में पहली बार भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भाग लिया।

वर्चुअल वचन सम्मेलन के दौरान फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन में घोषणा की कि भारत आने वाले दो वर्षों में 10 मिलियन अमरीकी डालर का और योगदान करेगा।

भारत ने मिस्र, लेबनान, फिलिस्तीन और सीरिया में कोविड से संबंधित चिकित्सा सहायता भेजी और जॉर्डन, इज़रायल और मिस्र को भारतीय दवा कंपनियों द्वारा निर्मित दवाओं के निर्यात की सुविधा प्रदान की। भारत ने अगस्त 2020 के बेरूत विस्फोट और सितंबर 2020 में सूडान और दक्षिण सूडान में विनाशकारी बाढ़ के बाद लेबनान और सूडान को खाद्य सहायता और राहत सामग्री भेजी।

संभावना है।

17 अफ्रीकी देशों ने भारत की प्रमुख परियोजना के तहत अफ्रीका के लिए टेली-एजुकेशन और टेलीमेडिसिन में ई-विद्याभारती और आरोग्यभारती नेटवर्क परियोजना नामक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत ने लगभग 3 बिलियन अमरीकी डालर की विभिन्न ऋण सहायता की घोषणा करके अफ्रीका के साथ अपनी विकास साझेदारी संधि को जारी रखा। भारत ने कोविड -19 महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में 35 अफ्रीकी देशों को अनुदान के आधार पर लगभग 1.8 मिलियन अमरीकी डालर की कोविड दवाएँ प्रदान करके चिकित्सा सहायता प्रदान की है। आईटीईसी कार्यक्रम के तहत कम से कम 16 अफ्रीकी देशों को भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए। 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत में वापस लाया गया। भारत ने इथियोपिया, केन्या, रवांडा और तंजानिया के साथ एयर बबल की व्यवस्था की।

वर्ष के दौरान रूस का 1.8 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात और 3.8 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया।

कोविड महामारी के निरंतर प्रभावों के बावजूद भी यूरेशिया क्षेत्र में अन्य देशों के साथ संबंध उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़े। इस अवधि के दौरान कजाखस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ उच्च स्तरीय बातचीत जारी रही। प्रधान मंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव ने 11 दिसंबर 2020 को भारत-उज्बेकिस्तान वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर विचारों का गहन आदान-प्रदान किया और भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी की पुनः पुष्टि की।

भारत ने कोविड-19 के खिलाफ उनकी लड़ाई में अर्मेनिया, कज़ाखस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, ताजिकिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान को मानवीय चिकित्सा सहायता प्रदान की। भारत और यूरेशियाई देशों ने अपने फंसे हुए

नागरिकों को उनके अपने देश लौटने में सक्षम बनाने में सक्रिय रूप से एक-दूसरे की सहायता की।

प्रधानमंत्री ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की अध्यक्षता में “यूनाइटेड अगैस्ट कोविड -19 महामारी” नामक विषय पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) संपर्क समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

विदेश मंत्री ने 24 सितंबर, 2020 को कजाखस्तान के विदेश मंत्री की अध्यक्षता में कॉन्फ्रेंस आन इंटरएक्शन एंड कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया (सीआईसीए) पर सम्मलेन के सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग पर क्रमशः कजाख और ताजिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श आयोजित

यूरोप और यूरोपीय संघ

यूरोपीय संघ

वर्ष 2020 भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। दोनों पक्ष वैश्विक महामारी और लगातार विकसित हो रहे भूराजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रेक्सिट के बाद के यूरोप के बदलते संरचनात्मक संदर्भों के बीच भारत ने यूरोपीय संघ को उच्च राजनयिक प्राथमिकता देनी जारी रखी। कई वर्षों से, शीर्ष स्तर पर शिखर सम्मेलन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक बहु-स्तरीय संस्थागत कार्यवाह के को स्थापित किया गया। पहला भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन लिस्बन में वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था, जो संबंधों को आगे बढ़ाने में ऐतिहासिक साबित हुआ। तब से अब तक, भारत और यूरोपीय संघ के बीच 15 वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुए हैं। वर्ष 2004 में हेग में आयोजित पांचवें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान इस संबंध को एक ‘रणनीतिक साझेदारी’ में स्तरोन्नत किया गया।

प्रधान मंत्री ने 15 जुलाई 2020 को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीन के साथ, 15 वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश तथा समुद्री सुरक्षा पर नए संवाद तंत्रों को स्थापित करने सहित संबंधों को व्यापक रूप आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 तक एक नई रणनीतिक कार्ययोजना प्रदान की गई।

यूरोपीय संघ भारत के शीर्ष व्यापार और निवेश भागीदारों में से एक है। जनवरी से जुलाई 2020 तक माल में भारत-यूरोपीय संघ-27 कुल द्विपक्षीय व्यापार 40.09 बिलियन अमरीकी डालर था और सेवाओं में यह व्यापार 33.15 बिलियन अमरीकी डालर था। कुल एफडीआई का 17.31% भारत में आता है (470 बिलियन अमरीकी डालर) यूरोपीय संघ एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक ईयू-27 से कुल 81.35 बिलियन अमरीकी डालर का एफडीआई हुआ।

की गई।

इस वर्ष द्विपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भारत और उज्बेकिस्तान की संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समितियों की पहली संयुक्त बैठक भी हुई जिसकी सह-अध्यक्षता अगस्त 2020 में राज्य मंत्री और उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सरदोर उमुरज़कोव ने की थी।

अक्टूबर 2020 में भारत-मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक आयोजित की गई और इसे हर वर्ष आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जो भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच सहयोग का एक वैकल्पिक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। यह वार्ता भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए एक अरब अमरीकी डालर की ऋण सहायता की घोषणा के संदर्भ में महत्वपूर्ण थी।

मध्य यूरोप

राजनीतिक रूप से, मध्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंध किसी भी प्रमुख द्विपक्षीय बाधाओं से मुक्त हैं। कई मध्य यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध सांस्कृतिक संबंधों में निहित हैं। कई देश अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंच पर भारत का समर्थन करते हैं, जिसमें भारत की यूएनएससी की स्थायी सदस्यता भी शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और दृढ़ता से बढ़ती आर्थिक रूपरेखा ने भारत के साथ संबंधों को गहरा करने और सहयोग के नए अवसरों को खोलने का मार्ग प्रशस्त किया है। यूरोपीय संघ, मध्य यूरोपीय देशों में एक मजबूत धारणा है और विसैग्रड समूह (चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया) जैसे समूह हैं जो यूरोपीय संघ की एक मजबूत ताकत है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, मध्य यूरोपीय देशों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय गतिविधियां सक्रिय रही हैं। प्रधान मंत्री और डेनमार्क के प्रधान मंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने 28 सितंबर 2020 को प्रथम भारत-डेनमार्क वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। भारत और डेनमार्क, जलवायु परिवर्तन में द्विपक्षीय और वैश्विक चुनौतियों के समाधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अपनी तरह के पहले, एक ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाने पर सहमत हुए।

वर्ष 2020-21 के दौरान, प्रधान मंत्री ने ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, पोलैंड, स्वीडन, स्लोवेनिया, रोमानिया, ग्रीस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया और लिथुआनिया के अपने समकक्षों के साथ वर्चुअल परामर्श और टेलीफोन पर बातचीत की और आपसी हित के मुद्दों पर गहन चर्चा की।

मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 5 नवंबर 2020 को संयुक्त रूप से पहले भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। उद्घाटन सत्र में विदेश मंत्री मुख्य वक्ता थे जिसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड और लातविया से मंत्री स्तर की भागीदारी भी देखी गई।

भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा सहायता की आपूर्ति और विदेशी नागरिकों की निकासी के संबंध में मध्य यूरोपीय देशों को सहायता प्रदान की, जिसकी इन देशों के नेताओं ने सराहना की।

पश्चिमी यूरोप

वर्ष 2020-21 में, कोविड की सीमाओं के बावजूद पश्चिम यूरोपीय देशों और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों में उच्चतम स्तर पर निरंतर बातचीत चलती रही। भारत-यूरोपीय संघ वर्चुअल शिखर सम्मेलनों के अलावा, प्रधानमंत्री ने इटली और लक्ज़मबर्ग के साथ कोविड महामारी के दौरान वर्चुअल शिखर सम्मेलनों में भी भाग लिया।

कोविड और कोविड के बाद रिकवरी, टीकों पर रणनीति, आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और नए उभरते क्षेत्रों जैसे हरित प्रौद्योगिकी, एआई, डिजिटल डोमेन और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर अनेक राजनीतिक और आधिकारिक स्तरों पर बातचीत भी की गई। भारत ने लोगों की कानूनी आवाजाही को सुकर बनाने के लिए कई देशों के साथ प्रवासन गतिशीलता

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका

फरवरी 2020 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी केस्तर तक विकास हुआ।

दिनांक 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे वार्षिक 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद ने सामरिक दृष्टिकोण से द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा को समर्थ बनाया और इन्हें आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक दिशा प्रदान की। इस अवसर पर बुनियादी आदान-प्रदान और सहयोग समझौते सहित 5 समझौता ज्ञापनों / समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

कोविड -19 महामारी का सामना करते हुए भारत और अमेरिका ने विशेष रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा विज्ञान और टीका विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाया।

पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि देखी गई है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (माल और सेवाओं में संयुक्त रूप से) है।

वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 4.3% से बढ़कर 148.8 बिलियन अमरीकी डॉलर पहुंच गया। वर्ष 2020 में अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 26.55 बिलियन अमरीकी डॉलर हुआ।

वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण परामर्श आयोजित किए गए जिनमें भारत-अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी मंत्री स्तरीय बैठक, भारत-अमेरिका सीईओ मंच, भारत-अमेरिका आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह, भारत-अमेरिका साइबर सुरक्षा वार्ता, भारत-अमेरिका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कार्य समूह बैठक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर परामर्श शामिल हैं। भारतीय सुरक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ-आईडीईएक्स) और अमरीकी रक्षा नवाचार यूनिट सहित भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी तथा व्यापार पहल के बीच उद्घाटन बैठक 2020 में आयोजित की गई थी।

भागीदारी समझौते (एमएमपीए) की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें इंग्लैंड, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी और बेनेलक्स समूह शामिल हैं। फ्रांस के साथ प्रवासन गतिशीलता भागीदारी समझौता (एमएमपीए) में फ्रांसिसी अनुसमर्थन प्रतीक्षित है।

इंग्लैंड के प्रधान मंत्री श्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर, प्रधान मंत्री ने 12 दिसंबर 2020 को इंग्लैंड द्वारा सह-आयोजित क्लाइमेट एम्बिशन समिट में भाग लिया।

इंग्लैंड डोमिनिक राब के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के सेक्रेट्री ऑफ स्टेट ने 14-17 दिसंबर 2020 को भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया।

भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी की उन्नति के लिए प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए अनुकरणीय योगदान को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने 21 दिसंबर, 2020 को प्रधान मंत्री को अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ उपाधि, द लिजियन ऑफ मेरिट, प्रमुख सेनाध्यक्ष की पदवी से सम्मानित किया।

17 नवंबर, 2020 को प्रधान मंत्री और तात्कालीन निर्वाचित-राष्ट्रपति जोसफ बाइडन ने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक सहभागिता को आगे बढ़ाने के लिए एक जुट होकर कार्य करने पर सहमत हुए। उन्होंने, प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें कोविड-19 महामारी, सस्ते टीकों को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन से निपटना और भारत-प्रशान्त में सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

कनाडा

प्रधान मंत्री ने 2020 में कनाडा के प्रधान मंत्री श्री जस्टिन टूडो से टेलिफोन पर दो बार बातचीत की।

8 अक्टूबर 2020 को, प्रधान मंत्री ने फेयर/कैक्स फाइनेशियल होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा आयोजित वर्चुअल इन्वेस्ट इण्डिया 2020 सम्मलेन में उद्घाटन भाषण दिया।

विदेश मंत्री ने 3नवम्बर, 2020 को कनाडा के विदेश मंत्री द्वारा कोविड-19 प्रतिक्रिया (कोविड-19 पर मंत्रीस्तरीय समन्वय समूह) पर आयोजित बैठक में विदेश मंत्रियों के अनौपचारिक समूह में भाग लिया।

आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह ने 26 अगस्त, 2020 को भारत-कनाडा आतंकवाद-रोधी कार्य योजना पर चर्चा की। भारत और कनाडा ने अपने व्यापार और वाणिज्य संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर कार्य किया है। 01 अप्रैल से 31 अगस्त, 2020 तक द्विपक्षीय व्यापार 2.17 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। वर्ष के दौरान कनाडा को भारतीय निर्यात 2.09 बिलियन अमरीकी डॉलर और आयात 2.10 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। कनाडियन पेंशन निधि ने भारत में 50 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का निवेश करने का वचन दिया है। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी

समझौता (सीईपीए) और द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण समझौता (बीआईपीपीए) पर चर्चा कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच सीईपीए और बीआईपीपीए पर एक वर्चुअल बैठक 22 जून 2020 और 27 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की गई थी।

वाणिज्य और व्यापार मंत्री ने कई मौकों पर कनाडियन मंत्री से छोटे व्यवसाय, निर्यात संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मैरी एनजी पर बातचीत की और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव, दवा उत्पादों की उपलब्धता, जी-20 सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

लैटिन अमेरिका और कैरेबियन

भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुए व्यवधानों के बावजूद वर्ष 2020-21 में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों के सभी 33 देशों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा है। यह क्षेत्र हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बिन्दु रहा है, विशेष रूप से द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि के साथ, पिछले पांच वर्षों में पांच गुना बढ़कर लगभग 38 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। वर्ष के दौरान महामारी के परिणामस्वरूप वैश्विक प्रतिबंधों को संपर्कता बढ़ाने के अवसर के रूप में प्रयोग में लाया गया और जो इस क्षेत्र के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में अपने अत्यधिक सफल दौर के दो माह के पश्चात ही ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो और प्रधान मंत्री के बीच अप्रैल, 2020 में कोविड-19 महामारी की वैश्विक स्थिति पर टेलीफोन पर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने क्षेत्र में अपने 23 समकक्षों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री की अध्यक्षता में भारत और चिली के बीच प्रथम संयुक्त आयोग की बैठक 16 अक्टूबर, 2020 को अपने समकक्ष के साथ की गई थी।

बिम्सटेक, सार्क और नालंदा

भारत ने सार्क के संबंध में सक्रिय संबंधों के माध्यम से कोविड महामारी से मुकाबला करने में

अग्रणी भूमिका निभाई है। प्रधान मंत्री की पहल पर, 15 मार्च, 2020 को दक्षिण एशियाई नेताओं का एक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित किया गया था। भारत ने सार्क कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष में 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का स्वैच्छिक योगदान का वचन दिया। भारत ने 26 मार्च, 2020 को सभी सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों की एक वीडियो कांफ्रेंस की मेजबानी की। अप्रैल में, भारत ने अंतर-क्षेत्रीय व्यापार पर कोविड-19 की अड़चनों पर चर्चा करने के लिए सार्क देशों के व्यापार अधिकारियों की एक वीडियो कांफ्रेंस की मेजबानी की। इसके अतिरिक्त, भारत ने मई, 2020 में कोविड-19 सूचना विनियम मंच 'सीओआईएनईएक्स' की शुरुआत की। भारत ने सार्क भागीदारों-मालदीव (150 मिलियन अमरीकी डॉलर) और भूटान (200 मिलियन अमरीकी डॉलर) को विदेशी मुद्रा विनियम सहायता भी प्रदान की।

भारत शिक्षा के क्षेत्र में कनाडा के साथ संपर्क को बढ़ा रहा है। कनाडा में अध्ययन कर रहे 2,30,000 भारतीय छात्रों सहित भारत अब विदेशी छात्रों का शीर्ष स्त्रोत बन गया है। शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना के तहत शामिल 28 देशों में से कनाडा एक है, जो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान पारितंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक पहल है। शिक्षा और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना के तहत 19 परियोजनाओं और 'शिक्षा नेटवर्क की वैश्विक पहल' के तहत 106 परियोजनाओं को अब तक कनाडाई शिक्षा संकायों को सौंपा गया है।

एलएसी देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें अर्जेंटीना के साथ लिथियम की खोज एवं उसके दोहन के क्षेत्र में सहयोग और मैक्सिको के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना शामिल है।

एकजुटता के प्रतीक के रूप में और “फॉर्मसी ऑफ द वर्ल्ड” के रूप में हमारी भूमिका के अनुरूप, भारत ने एलएसी क्षेत्र के 27 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की गोलियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों से युक्त चिकित्सा सहायता पैकेज भेजे हैं।

इस क्षेत्र में फंसे 3,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। भारतीय मिशन ने स्थानीय अधिकारियों,अन्य राजदूतावासों और विमानन कंपनियों के साथ मिलकर कड़े यात्रा प्रतिबंधों के तहत भारतीयों को बाहर निकलने के लिए विभिन्न उड़ान मार्गों का पता लगाया। एलएसी देशों के नागरिकों को उनके घर वापस भेजने में भी मदद की गई थी और मंत्रालय ने अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और कोलोम्बिया सहित एलएसी देशों को निकासी उड़ाने की सुविधा प्रदान की।

2020 में परिवहन कनेक्टिविटी पर तीसरी बिम्सटेक कार्य समूह बैठक में परिवहन कनेक्टिविटी पर बिम्सटेक मास्टर योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया, जिसकी अध्यक्षता भारत ने 8 दिसंबर, 2020 को वर्चुअल प्रारूप में की।

नालंदा विश्वविद्यालय ने वास्तविक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ शैक्षणिक कार्यक्रमों दोनों के मामले में लगातार प्रगति की है। विश्वविद्यालय को नेट जीरो एनर्जी कैम्पस के लिए 9अक्टूबर, 2020 को जीआरआईएचए परिषद द्वारा एकीकृत आंतरिक मूल्यांकन, बड़े विकास (जीआरआईएचए एलडी- 5 स्टार) के लिए 5 स्टार रेटिंग दिया गया है। विश्वविद्यालय ने अपनी नवीन शैक्षणिक वास्तुकला के लिए शिक्षा में उत्कृष्टता में सीएसआर पुरस्कार भी प्राप्त किया है।

आतंकवाद-रोध

वर्ष के दौरान सभी स्तरों पर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में आतंकरोधी मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। ऐसी सभी परिचर्चाओं के दौरान, भारत ने अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा की तथा क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी द्वारा लागू सीमितताओं के बावजूद, भारत ने यूरोपीय संघ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके

और फ्रांस जैसे साझेदार देशों के साथ आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी-सीटी) के तंत्र के माध्यम से वर्चुअल रूप में व्यवस्थित परामर्श आयोजित करना जारी रखा है। इसके अतिरिक्त, भारत ने ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी कार्य समूह और उप-समूह बैठकों में भाग लिया। भारत ने आतंकवाद से निपटने संबंधी मुद्दों पर एफएटीएफ, जीसीटीएफ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य विभिन्न दूसरे क्षेत्रों और बहुपक्षीय संगठनों की बैठकों में भी भाग लिया।

नीति नियोजन एवं अनुसंधान

नीति नियोजन एवं अनुसंधान प्रभाग रणनीतिक और शैक्षणिक समुदाय के साथ नीति नियोजन एवं लोक राजनय के लिए मंत्रालय का एक नोडल प्रभाग है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय नीति वार्ता भी आयोजित करता है।

ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, इजरायल, पोलैण्ड, तुर्की, वियतनाम, युनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और ब्रिक्स के साथ वर्चुअल संवाद किया गया। यह प्रभाग कई मुद्दों पर नीति विश्लेषण और रिपोर्ट प्रदान करना जारी रखे हुए है। कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ कई ट्रेक

1.5/2 संवादों को सुविधा प्रदान की गई थी।

थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ नियमित और व्यवस्थित परिचर्चाएं आयोजित की गईं। विश्वविद्यालयों और अनुसंधान निकायों के साथ अनेक संयुक्त गतिविधियां आयोजित की गईं। मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख सम्मेलन वर्चुअल एवं हाइब्रिड मंचों को अपनाकर कोविड के बाद की वास्तविकताओं के अनुसार आयोजित की गई थी। रायसीना वार्ता, एशियन आर्थिक वार्ता और हिन्द महासागर सम्मेलन वर्ष 2021 में आयोजित होने का कार्यक्रम है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्लूए)

आईसीडब्लूए एशिया, अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत-प्रशांत क्षेत्र और व्यापक वैश्विक भू-स्थानिक वातावरण में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा प्रगतियों के अनुसंधान और अध्ययन को उच्च प्राथमिकता देना जारी रखा है। इसके निष्कर्ष सार, दृष्टिकोण और विशेष रिपोर्ट के रूप में प्रसारित किए गए थे। जिसे आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त, आईसीडब्ल्यूए अपने शैक्षणिक परिणामों का हिंदी में

अनुवाद कराने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए है, जिसे नियमित रूप से वेबसाइट पर डाला जाता है। इसके अलावा, परिषद अप्रैल 2020 से पुस्तकों और सप्पु हाउस पेपरों का प्रकाशन कर रहा है। आईसीडब्ल्यूए अपने अधिदेश के अनुरूप बड़ी संख्या में कार्यक्रमों, लेक्चरों, सम्मेलनों और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन करता है।

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस)

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली एक स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में विशेषज्ञता रखता है। यह वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के मध्य प्रभावपूर्ण नीतिगत वार्ता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों के साथ दक्षिण-दक्षिण सहभागिता और सहयोग को बढ़ावा देना है। थिंक टैंक के अपने गहन नेटवर्क के माध्यम से आरआईएस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकासपूर्ण भागीदारी केनवस पर नीतिगत समबद्धता को मजबूत करता है।

नीति वार्ताएं आयोजित की। जिनमें अन्वयों के अलावा (क) भारत-वियतनाम एसएण्डटी सहयोग पर संभावनाएं और परिप्रेक्ष्य; (ख) कोविड के बाद के समय में बिस्स्टेक; (ग) इंडोनेशिया का कोविड-19 एक्जिट प्लान और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग पर क्षमता; (घ) अन्वोन्याश्रित विश्व में दक्षिण-दक्षिण सहभागिता का विस्तार; (ङ.) भारत और कोट डी वार के बीच सहभागिता की पहलों को मजबूत करना, (च) एसटीआई और एकडीजी; (छ) दक्षिण एशिया से कोविड-19 पर बहुपक्षीय प्रतिक्रिय-कोविड-19 से त्वरित रिकवरी के लिए दक्षिण एशियाई सहयोग की आवश्यकता शामिल हैं। नीति थिंक टैंक के बिस्स्टेक नेटवर्क की 5 वीं बैठक (बीएनपीटीटी, बिस्स्टेक देशों के थिंक टैंक को एकजुट करना) भी आयोजित की गई थी।

2020-21 में आरआईएस ने कोविड-19 महामारी पर फोकस की गई कई

नई, उभरती हुई और रणनीतिक प्रौद्योगिकियां

नई उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकी (एनईएसटी) प्रभाग की स्थापना जनवरी, 2020 में हुई थी, जो नई प्रौद्योगिक कूटनीति पर ध्यान देता है और वैश्विक मंचों में इस तरह की चर्चाओं की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहलुओं के कार्य भी देखता है। एनईएसटी प्रभाग संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित बहुपक्षीय संदर्भ में प्रौद्योगिकी शासन नियमों, मानकों और वस्तुकला के बारे में बातचीत में भारत द्वारा अपनाए गए रूख का एक

समन्वय बिन्दु है। यह प्रभाग इस संबंध में प्रमुख सहभागी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। यह संबंध मंत्रालयों के सहयोग से भारत में नई उभरती और सामरिक प्रौद्योगिकियों की मांग आधारित आवश्यकताओं का आकलन कर रहा है और सिनैप्सिस के समान सुविधा प्रदान कर रहा है, उनके लिए अधिग्रहण करने के लिए इंटरलैक्चर/पार्टनर इंटेफेस के रूप में कार्य कर रहा है और इस प्रक्रिया से भारतीय मिशनो की भूमिका को सुदृढ़ कर रहा है।

साइबर राजनय, ई-गवर्नेंस और आई टी

भारत ने साइबर और साइबर-समर्थ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में एक मुक्त, स्वतंत्र, सुरक्षित और संरक्षित इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजना व दोनों देशों के बीच समृद्धि लाने के लिए एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध करावने पर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। फ्रेमवर्क के तहत पंचवर्षीय कार्य योजना लागू की जा रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें आईसीटी और साइबर सुरक्षा पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीएस) का गठन, डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवोन्मोषिता पर केन्द्रीत अनुसंधान को प्राथमिकता देने के लिए “ऑस्ट्रेलिया इण्डिया रणनीतिक अनुसंधान राजकोष”, मजबूत साइबर फोरेंसिक और जांच क्षमताओं को बढ़ावा देना और क्रांटम कम्प्यूटिंग, कृत्रिम जांच इत्यादि के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में अनुसंधान पर सहयोग करना शामिल हैं। भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जापान के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और जर्मनी, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साइबर वार्ताओं का आयोजन किया।

साइबर-संबंधी मुद्दों पर भाग लेता रहा है और विचार-विमर्श भी करता रहा है, जिसमें साइबरक्राइम पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की वर्चुअल बैठक के लिए यूएनडीओसी का छठा सत्र, साइबर संबंधी मुद्दों पर आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक, साइबर सुरक्षा पर 5वीं आसियान मंत्रीस्तरीय सम्मेलन, सुरक्षा पर ब्रिक्स कार्य समूह की छठी बैठक और अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर शंघाई सहयोग संगठन विशेषज्ञ समूह की बैठक शामिल हैं।

मंत्रालय के लिए एक परफार्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तैयार किया गया था। जिसका ध्यान इस पांच क्षेत्रों: प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क, विकासपूर्ण भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, व्यापार और वाणिज्य एवं नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम एवं पहलों के सभी लक्षित क्षेत्रों पर केन्द्रीत है।

वर्दे भारत मिशन पोर्टल की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने की सुविधा हेतु मई, 2020 में की गई थी।

भारत ने अन्वयों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों और बहुपक्षीय संरचनाओं में

संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन

Iभारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व व्यवस्था में निर्भाई जा रही केन्द्रीय भूमिका के अनुसार यून के साथ अपने उच्च-स्तरीय संपर्क बनाए रखे हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है।

राष्ट्र आतंकवाद-रोधी समिति, तालिबान प्रतिबंध समिति और लिबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा।

21 सितंबर, 2020 को भारत के प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर महासभा की उच्च-स्तरीय बैठक को संबोधित किया था। 26 सितंबर, 2020 को आम चर्चा के दौरान वर्चुअल रूप से महासभा को संबोधित करते हुए, प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार करने और इसकी निर्णय लेने वाली संरचना में भारत की आवाज को शामिल करने का आह्वान किया।

प्रधान मंत्री ने नीदरलैण्ड सरकार और वैश्विक अनुकूलन आयोग (जीसीए) द्वारा 25 जनवरी, 2021 को आयोजित वातावरण अनुकूलन शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लिया था। भारत जीसीए के सह-संयोजकों में से एक है।

भारत ने कोविड-19 महामारी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष सत्र में भाग लिया, जिसका आयोजन 3-4 दिसंबर, 2020 को किया गया था।

अंतर-संसदीय संघ के शासकीय परिषद का 206वां संस 1-4 नवंबर, 2020 वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। सितंबर में हुए चुनावों में महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग के सदस्य के रूप में भारत का चयन किया गया था। भारत, अफगानिस्तान और चीन ने एशिया-प्रशांत समूह में दो सीटों के लिए चुनाव लड़ा जिसमें भारत और अफगानिस्तान विजेता के रूप में उभरे। भारत को कार्यक्रम और समन्वय समिति(सीपीसी) तथा जनसंख्या और विकास संबंधी आयोग की समिति के लिए भी चुना गया था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य संबंधी चुनाव में, भारत ने डाले गए 192 मतों में से 184 मत हासिल किए हैं। भारत ने 1 जनवरी, 2021 को सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्य की सीट ग्रहण की। भारत संयुक्त

भारत ने दिसंबर, 2020 में महामारी से संबंधित तैयारी और रिसपाउंस के लिए

गठित नए स्वतंत्र पैनल पर डब्ल्यूएचओ में सुधारों के संबंध में एपरोच पेपर प्रस्तुत किया।

भारत, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में कुल मिलाकर सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है, जिसने 1950 से अब तक लगभग 2,53,000 सैनिक भेजे हैं। 31 अक्टूबर,

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

बहुपक्षीय मंचों पर भारत ने इस बात को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की पुनः पुष्टि की है कि कोविड-19 महामारी पर वैश्विक प्रतिक्रिया मानव केन्द्रित,समावेशी,और स्थायी हो। प्रधान मंत्री ने 15वें जी-20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से और जी-20 नेताओं के विशिष्ट वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विदेश मंत्री ने जी-20 विदेश मंत्रियों की एक विशिष्ट बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्होंने जांच और क्वारंटीन प्रक्रियाओं तथा ‘संचलन एवं पारगमन’ प्रोटोकॉल के मानकीकरण सहित ‘लोगों की सीमा-पार समन्वित आवाजाही के लिए जी-20 सिद्धांतों’ को स्वेच्छिक रूप से विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

प्रधान मंत्री ने रूस द्वारा संचालित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी वर्चुअल

आर्थिक राजनय

आर्थिक राजनय प्रभाग, ने देश की विदेश नीति के आर्थिक राजनय आयामों को एक केंद्रित दिशा देने के प्रयास के रूप में कई पहल शुरू की।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी महासभा अनुकूलित वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से 14 अक्टूबर,2020 को आयोजित की गई थी। आपदा प्रतिरोधी संरचना गठबंधन (सीडीआरआई) की प्रथम शासी परिषद बैठक नई दिल्ली में 20 मार्च, 2020 को आयोजित की गई थी। वर्तमान में 22 सदस्य जिनमें 18 राष्ट्रीय सरकारें और 4 बहुपक्षीय संगठन शामिल हैं, सीडीआरआई से जुड़ गए हैं।

भारत ने सितंबर,2020 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) और इसके अंतर-सत्र कार्य समूह के 53वें सत्र में भाग लिया था।

भारत ने अब तक कुल 19 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करार पर हस्ताक्षर किए व उनका अनुसमर्थन किया।

भारत ने अभी तक 24 देशों अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, नाइजीरिया, जापान, केनिया, यूक्रेन, ओमान, इराक, फ्रांस, जर्मनी, तंजानिया, रवांडा, नीदरलैण्ड, संयुक्त राज्य अमरीका, युनाइटेड किंगडम, इथियोपिया, कुवैत, नेपाल और कतर के साथ एयर बबल व्यवस्था की है। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रूस, इजराइल, न्यूजीलैण्ड, फिलीपिंस, सऊदी अरब, कज़ाखस्तान, मलेशिया, और थाईलैण्ड के साथ एयर बबल व्यवस्था के बारे में बातचीत की जा रही है।

भारत अपनी वर्षों पुरानी निवेश संधियों को समाप्त कर रहा है और 2015 के नई मॉडल संधि पर आधारित द्विपक्षीय निवेश संधियों पर विचार-विमर्श करते

2020 तक, भारत 8 शांति मिशनों मे 5,353 सैनिकों को भेजने के बाद इन मिशनों में पाचवां सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। भारत ने गोमा(डीआरसी) और जूबा (दक्षिण सूडान) में चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की।

रूप से भाग लिया। ब्रिक्स की वर्चुअल रूप से आयोजित की गई विदेश मंत्रियों की बैठक में, विदेश मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने महामारी को देखते हुए कई कदम उठाए जिनमें आरोग्य सेतु नागरिक ऐप, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज और लगभग 85 देशों को भारत द्वारा दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की आपूर्ति शामिल है।

विदेश मंत्री ने सितंबर, 2020 में आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ के एक साझा प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए आईबीएसए संयुक्त मंत्रीस्तरीय वक्तव्य को अंगीकार एवं जारी किया।

हुए 30 से अधिक देशों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क बनाए हुए है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, मेजबान देश के समझौते के दायरे में रहते हुए पीसीए-भारत सम्मेलन एवं कार्यशालाएँ आयोजित कर रहा है।

भारतीय उद्योगों और व्यापार की बढ़ती मांग के अनुसार प्रभावी कार्रवाई करने हेतु विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों को सक्षम बनाने के लिए आर्थिक राजनय पर एक वेबसाइट लांच की गई है। वेबसाइट का एक खण्ड संसाधन मंच के लिए समर्पित है जो विश्व संसाधन व्यवस्थाओं एवं अवसर के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएगा। कृषि संबंधी निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक विशेष प्रयास किया जा रहा है।

कई औद्योगिक पहुंच और निवेश प्रोत्साहन एवं प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनमें भारत-कनाडा कृषि-प्रौद्योगिकी वर्चुअल शिखर सम्मेलन; वर्चुअल प्लेटफॉर्म रूप से भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी संबंधी 15वीं सीआईआई एक्जिम बैंक डिजिटल सभा; वर्चुअल रूप से विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन; भारत-म्यांमार वर्चुअल व्यापार सम्मेलन2020; फार्मा और स्वास्थ्य कल्याण, ऑटो व ऑटो पुरजों पर भारत-थाइलैण्ड डिजिटल सम्मेलन और वर्चुअल व्यापार सम्मेलन; बांग्लादेश के साथ व्यापार करने संबंधी डिजिटल सम्मेलन; प्रथम भारत-आसियान ओसियानिक व्यापार शिखर सम्मेलन एवं एक्सपो; वैश्विक आयुर्वेदा शिखर सम्मेलन 2020; भारत-फिलीपिन्स द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध पर एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन; वर्चुअल ग्लोबल इंवेस्टर राउंडटेबल शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत पहल के एक भाग के रूप में, मंत्रालय अन्य देशों में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार करने हेतु मिशनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

राज्य प्रभाग

इस मंत्रालय ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों तथा भारत में शाखा सचिवालयों/क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से राज्य के बाहरी आर्थिक सहभागिता की सुविधा प्रदान की है। राज्यों के राजनयिक प्रसार को सुविधाजनक बनाने और राज्य सुविधा एवं ज्ञान सहायता निधि का उपयोग करते हुए राज्य स्तर पर आर्थिक राजनयिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए, 16 नवंबर 2020 को डेक्कन संवाद के तीसरे संस्करण जैसे कई कार्यक्रम आयोजन किए गए।

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले

निरस्त्रीकरण, अप्रसार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर एक विकसित वैश्विक परिदृश्य के बीच, भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और पारंपरिक रूप से मूल्यवान भूमिका के आधार प्रासंगिक बहुपक्षीय मंचों पर और भागीदार देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था।

वर्ष 2020 में, “आतंकवादियों को सामूहिक विनाश वाले हथियारों को प्राप्त करने से रोकने के उपाय”, नामक भारत के पारंपरिक संकल्प को फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति द्वारा बिना वोट के अपनाया गया था। इस संकल्प में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से आतंकवादियों को सामूहिक विनाश वाले हथियार प्राप्त करने से रोकने और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने के उद्देश्य से उपाय करने का आह्वान किया गया है।

शिखर सम्मेलन और सम्मेलन प्रभाग

सम्मेलन प्रभाग मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को भारत, विदेश में प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रियों की अंतर्राष्ट्रीय एवं बहुपक्षीय भागीदारी सहित बैठकों, कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों के आयोजन के लिए सभी संभार व्यवस्था प्रदान करता है। प्रोटोकॉल, प्रतिनिधियों की सुरक्षा और विशिष्ट प्रकृति वाले आयोजन

विकास सहयोग

‘वसुधैवकुटुम्बकम्’ की भावना से प्रेरित होकर, इस वर्ष के दौरान भारत के अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग में अपनी भौगोलिक पहुंच के साथ-साथ सहयोग के क्षेत्रों में विस्तार जारी रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के विकास सहायता का एक प्रमुख पहलू अन्य विकासशील देशों के लिए ऋण सहायता (एलओसी) प्रदान करना रहा है। विभिन्न देशों को लगभग 1.9 बिलियन अमरीकी डालर की 13 नई ऋण सहायता प्रदान की गई थी और 6 ऋण सहायता परियोजनाएं 2020-21 में पूरी की गई थी।

मेजबान सरकारों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई प्रमुख

एक प्रमुख पहलू में, अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव के तौर-तरीकों पर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए पहली बार एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया। इस वर्ष एक नया उत्तर पूर्व संवाद आरंभ करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया। राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के रेजिडेंट कमिश्नरों के साथ नियमित बातचीत के माध्यम से उनसे संपर्क बनाए रखना जारी है। इस प्रभाग द्वारा राज्य सरकारों एवं शहरों के बीच उनके विदेशी समकक्षों के साथ सिस्टर-स्टेट और शहर साझेदारी स्थापित करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों को सुगम बनाया गया था।

“अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका” पर एक और भारत-प्रायोजित संकल्प सर्वसम्मति से अपनाया गया था। यह संकल्प विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मौजूदा प्रगतियों पर बहुपक्षीय संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं निरस्त्रीकरण प्रयासों पर उनके संभावित प्रभाव को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आउटरीच कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करता है।

2020-21 में, भारत ने सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण, सामान्य निरस्त्रीकरण और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विचार-विमर्श में योगदान देना जारी रखा।

पूर्ण सटिकता वाले, के लिए सम्मेलन प्रभाग ने 8 कार्यक्रम प्रबंधन कंपनियों (ईएमसी) को पैनल पर रखा है। आयोजन के लिए ईएमसी का चयन मंत्रालय के संबंधित प्रभाग की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

विकासोत्सुक परियोजनाएं वर्तमान में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव में कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें अवसंवरचना, पनबिजली, बिजली पारेषण, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुरातात्विक संरक्षण आदि में परियोजनाएँ शामिल हैं। पड़ोस के अतिरिक्त, दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिनिया, मध्य एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका में द्विपक्षीय परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

भारत ने कोविड -19 महामारी के प्रकोप के दौरान दवाइयों, कोविड संरक्षण गियर, फार्मास्युटिकल उत्पादों और चिकित्सा विशेषज्ञता के रूप में चिकित्सा सहायता के जरिए हमारे विकासशील भागीदार देशों की सहायता की। वर्ष के दौरान, भारत ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के 82 देशों में कोविड

से संबंधित चिकित्सा सहायता जैसे दवाइयाँ, जांच किट और कोविड संरक्षण गियर प्रदान किए। यह उल्लेखनीय है कि यह पूरी सहायता वैश्विक लॉकडाउन के दौरान उस समय प्रदान की गई जब आपूर्ति और रसद श्रृंखला गंभीर रूप से बाधित थी।

2020-21 के दौरान, कोविड -19 महामारी के वैश्विक प्रकोप और इसके बाद लॉकडाउन के कारण व्यक्तिगत रूप से आईटीईसी पाठ्यक्रम काफी हद तक निलंबित रहे। मंत्रालय ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लागू करने के समय भारत के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में फंसे लगभग 1200 आईटीईसी प्रशिक्षुओं का सफल प्रत्यावर्तन किया। तत्पश्चात, आईटीईसी कार्यक्रम को ऑनलाइन ई-आईटीईसी पाठ्यक्रम के माध्यम से जारी रखा गया, जो

विधिक एवं संधि प्रभाग

विधिक एवं संधि प्रभाग मंत्रालय से संबंधित सभी विधिक एवं संधि-संबंधी कार्यों को देखता है। 2020-21 के दौरान, भारत ने 52 देशों एवं संगठनों के साथ 97 करारों पर हस्ताक्षर किए; 15 करारों का अनुसमर्थन किया और 10 उपक्रमों के लिए पूर्ण शक्तियों को संसाधित किया। (देखें अनुबंध- I)

कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाएँ

2017 में ई-सनद के आरंभ होने के बाद से 373,732 से अधिक दस्तावेजों को इसके माध्यम से सफलतापूर्वक संसाधित किया गया है। सितंबर 2020 तक 5439 दस्तावेजों को ऑनलाइन सत्यापित/एपोस्टिल किया गया तथा 337,224 सत्यापन और 330,750 एपोस्टिल सेवाओं को ऑफ़लाइन मोड में प्रदान किया गया। मदद पोर्टल पर अक्टूबर 2020 तक 69,000 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 61,000 शिकायतों का निपटारा किया गया है। इस वर्ष के दौरान, ग्रेनाडा और मार्शल द्वीप समूह के साथ राजनयिक और/अथवा

प्रवासी भारतीय मामले

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ़) कोविड -19 महामारी के चलते विदेशों में फंसे एवं संकटग्रस्त भारतीयों को सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। 31 दिसंबर 2020 तक, 1,56,000 से अधिक भारतीयों को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 33.5 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था।

प्रवासी कामगारों के लिए प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत स्थापित मौजूदा 23 केंद्रों के अलावा 5 नए प्रस्थान-पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण केंद्र अक्टूबर 2020 में भुवनेश्वर, कोलकाता, लिवेंद्रम, अमृतसर और जालंधर में स्थापित किए गए थे।

जनवरी 2021 में जापान के “स्पेशलाइज्ड स्किल्ड वर्कर” वीजा श्रेणी की योजना के तहत भारतीय कुशल श्रमिकों की आवाजाही को सुविधाजनक

व्यापक रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और कोविड -19 प्रबंधन रणनीतियों पर केंद्रित था। इस अवधि के दौरान ऐसे कुल 20 ई-आईटीईसी पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

एक सभ्यतागत और सांस्कृतिक महाशक्ति के रूप में भारत की पहचान को देखते हुए, मंत्रालय ने धरोहर संरक्षण के लिए समर्पित जनवरी 2020 में विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए) नामक प्रभाग बनाया। वियतनाम में माई सन मंदिर परिसर, कंबोडिया में ता प्रोम और प्रीहवीयर मंदिर और लाओ पीडीआर में वात फोउ मंदिर की पुनर्स्थापना इस प्रभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख परियोजनाएँ हैं।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (कानूनी), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के तहत गठित कार्य समूह, एनरिका लेक्सी मामला (इटली और भारत), पेरेंटेज/सरोगेसी परियोजना पर विशेषज्ञों के समूह की सातवीं बैठक और विभिन्न संधि वार्ताओं में भाग लिया।

सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं में छूट संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजनयिक और/अथवा सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं में छूट संबंधी करार को कोस्टा रिका, इक्वेटोरियल गिनी, ओमान और मार्शल द्वीप के साथ लागू किया गया। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक, भारत को प्रत्यर्पण के 17 अनुरोध प्राप्त हुए और विभिन्न देशों को प्रत्यर्पण संबंधी 18 अनुरोध भेजे हैं। 2020 में, दो भगोड़े अपराधियों को अन्य देशों द्वारा भारत में प्रत्यर्पित किया गया था।

बनाने के लिए जापान के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष के दौरान, प्रवासन अनुसंधान पर मंत्रालय के आंतरिक थिंक-टैंक, भारतीय प्रवासन केंद्र ने भारत से हुए अंतरराष्ट्रीय प्रवास पर और लौटने वाले प्रवासियों की संख्या पर कोविड -19 के प्रभाव पर दो विशेष रिपोर्ट तैयार की। भारतीय प्रवासन केंद्र ने भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और भारतीय महिला श्रमिक पर दो पुस्तिकाएँ भी तैयार की है।

16वें प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन का आयोजन 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से किया गया था। प्रधान मंत्री ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय “आत्मनिर्भर भारत के लिए योगदान” था।

विदेश प्रचार

विदेश प्रचार और लोक राजनय प्रभाग अपने अधिदेश के अनुसार प्रमुख विदेश नीति के मुद्दों पर भारत की स्थिति को प्रभावी रूप से व्यक्त करने का प्रयास करता है। इसके साथ ही, ‘इंडिया स्टोरी’ और देश की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है। हालांकि कोविड -19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों की अपनी अलग चुनौतियाँ थी, परंतु वर्चुअल प्लेटफार्मों के रचनात्मक उपयोग के साथ, मंत्रालय इस वर्ष के दौरान अपने कार्यक्रमों की गति को बनाए रखने में सक्षम रहा। जनवरी 2021 तक प्रधान मंत्री स्तर के 13 से अधिक वर्चुअल शिखर सम्मेलन, विदेश मंत्री स्तर की 34 से अधिक मंत्रिस्तरीय बैठकों और विदेश मंत्री द्वारा की गई 7 यात्राओं का प्रैस कवरेज किया गया था। अक्टूबर 2020 में सोशल मीडिया पर सभी मिशनों और केन्द्रों के प्रमुखों के लिए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन किया गया था।

मंत्रालय का वेब पोर्टल www.mea.gov.in जो नियमित रूप से भारत की विदेश नीति की स्थिति को बताता है, पर 2012 में इसके आरंभ होने के बाद से 55 मिलियन से अधिक हिट सहित जनवरी 2020 से अब तक 4.8 मिलियन से अधिक हिट देखे गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंत्रालय की डिजिटल

प्रोटोकॉल

प्रोटोकॉल प्रभाग में कुल सात अनुभाग हैं प्रोटोकॉल- I, प्रोटोकॉल- II, प्रोटोकॉल- III, प्रोटोकॉल (हैदराबाद हाउस), प्रोटोकॉल विशेष, प्रोटोकॉल (आतिथ्य और लेखा) और सरकारी आतिथ्य संगठन (जीएचओ)। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक कोविड -19 अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री के स्तर के 33 वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त,

प्रशासन, स्थापना और सूचना का अधिकार

अप्रैल 2020 में, प्रभाग ने ‘विदेशों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियाँ’ के 9वें संस्करण को प्रकाशित किया, जिसे रेड बुक भी कहा जाता है।

प्रशासन ने नए विकास और कार्यात्मक प्राथमिकताओं के लिए प्रभागों और उनके कार्यों के पुनर्गठन का कार्य किया है, जैसे कि - ओशिनिया प्रभाग का सृजन, डीपीए-IV के तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) खरीद सेल की स्थापना, आर्थिक राजनय एवं स्टेट प्रभाग का दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजन।

अफ्रीका में 18 नए मिशन खोलने के संबंध में मार्च 2018में मंत्रिमंडल के

स्थापना प्रभाग

कोविड -19 महामारी के दौरान, स्थापना प्रभाग ने कार्यालय भवनों के साथ-साथ आवासीय परिसरों के स्वच्छता पर कार्य किया। कोविड के प्रसार को रोकने

आउटरीच में तेजी से वृद्धि देखी गई है। ट्विटर पर @MEAIndia पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स और @IndianDiplomacy पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर कुल 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो पिछले साल से लगभग 200,000 फॉलोअर्स की बढ़ोतरी है। @MEAIndia अब विश्व भर के सभी विदेशी कार्यालयों के बीच तीसरा सबसे अधिक फॉलो किया जाने वाला हैंडल है। मंत्रालय के दोनों YouTube चैनलों पर संयुक्त रूप से 27 मिलियन से अधिक व्यू काउंट है जो पिछले वर्ष की तुलना में 27% से अधिक की वृद्धि है। पिछले साल की तुलना में 31% की वृद्धि के साथ, मंत्रालय को फॉलो करने वालों की संख्या अब लगभग 523,000 है। युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि इसकी सामग्री विशेष रूप से इसी वर्ग के लोगों के लिए तैयार की गई है।

महामारी के दौरान डिजिटल राजनय की शक्ति का लाभ उठाते हुए, मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भारतीय समुदाय के साथ संपर्क, हमारे वार्ताकारों के साथ संपर्क और भारत के सॉफ्ट पवार का प्रचार निर्बाध रूप से जारी है।

इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री/उप विदेश मंत्री स्तर की आने वाली 6 यात्राओं और 103 आतिथ्य-सत्कार कार्यक्रमों को संभाला गया। एयरपोर्ट पास, लाउंज (औपचारिक और आरक्षित) के लिए 513 अनुरोध और तलाशी से छूट की सुविधा प्रदान की गई।

अनुमोदन के अनुरूप मार्च 2018 से मई 2019 के बीच पहले चरण में रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, बुर्किना फासो और गिनी में 6 मिशन और दूसरे चरण में इस्वातिनी, इरिट्रिया और कैमरून में 3 मिशन खोले गए।

जून 2019 और सितंबर 2020 के बीच, तीसरे चरण में 6 मिशन और खोले गए जिनमें सियरा लियोन, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, लाइबेरिया, टोगो गणराज्य, चाड गणराज्य और मॉरिटानिया शामिल हैं। केप वर्डे, गिनी बिसाऊ और सोमालिया में शेष 3 मिशनों को स्थापित करने के लिए प्रारंभिक प्रशासनिक और स्थापना संबंधी उपाय शुरू किए गए हैं।

के लिए निवारक उपायों को सभी कार्यस्थलों में अपनाया गया था। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए, बैठकें आयोजित करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की

मांग बढ़ गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सुचारु रूप से चलाने के लिए अवसंरचना के उन्नयन हेतु कदम उठाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने कार्यों को जारी रखने के लिए, मंत्रालय ने भारत में अपने सभी विभिन्न

कार्यालयों और विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में श्रमदान के साथ-साथ “स्वच्छता पखवाड़ा” भी आयोजित किया।

सूचना का अधिकार

अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना हेतु कुल 1570 आरटीआई आवेदन और 183 प्रथम अपील प्राप्त हुई हैं और उनका संतोषजनक रूप से निपटारा किया गया है। महामारी के दौरान, स्वतः संज्ञान लेकर प्रकटीकरण करने संबंधी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक डोमेन पर आरटीआई

आवेदन/अपील/प्रतिउत्तर और मासिक आरटीआई आंकड़ों को अपलोड किया गया है। ‘सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान’ के सहयोग से, सीआईसी के निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय के सभी सीपीआईओ द्वारा एक निर्धारित समय-सीमा में स्वतः संज्ञान लेकर ऑनलाइन प्रकटीकरण (पारदर्शिता ऑडिट) किया गया है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन और विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

मंत्रालय की भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए विदेशों में हिंदी के प्रचार और प्रसार हेतु एक व्यापक योजना है। विश्व हिंदी सम्मेलन और क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मंत्रालय ने विशिष्ट भाषांतरकारों (द्विभाषियों) का एक पूल बनाने के

उद्देश्य से भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए अटल भाषांतर योजना (एबीवाई) आरंभ की है। मंत्रालय में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था जिसमें कोविड-19 की मौजूदा स्थितियों के बावजूद पर्याप्त भागीदारी देखी गई थी।

सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान

पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज के सम्मान में 14 फरवरी 2020 को उनकी जयंती पर विदेशी सेवा संस्थान (एफएसआई) का नाम बदलकर सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआईएफएस) कर दिया गया। 2020-21 में, कोविड -19 महामारी के दौरान, संस्थान ने ऑनलाइन और ऑन-कैम्पस सत्र दोनों प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए शिक्षण का एक मिश्रित तरीका आरंभ किया है। वास्तविक एवं डिजिटल प्रशिक्षण की हाइब्रिड पद्धति 2019 बैच के भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारी प्रशिक्षुओं (ओटी) के लिए लाभप्रद साबित हुई है और एसएसआईएफएस द्वारा 2019 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए

निर्धारित अधिदेश के अनुसार मूल्यांकन की एक नई प्रणाली शुरू की गई है।

सितंबर 2020 में पहली बार, सूरीनाम के राजनयिकों के लिए एक पूरी तरह से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अक्टूबर-नवंबर 2020 में, हाल में नए आए निवासी विदेशी राजनयिकों के लिए ‘इंट्रोडक्शन टू इंडिया’ पर प्रथम सुषमा स्वराज व्याख्यान आयोजित किया गया। पहली बार, सूरीनाम के राजनयिकों के लिए सितंबर में प्रोटोकॉल पर और दिसंबर 2020 में वाणिज्यिक और आर्थिक राजनय पर दो पूरी तरह से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद

महामारी के दौरान, आईसीसीआर ने 900 से अधिक नव प्रवेशित छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों और संस्थानों के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएँ आयोजित कराईं, ताकि उनके शैक्षणिक वर्ष का नुकसान न हो। 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान, पूरे विश्व में आईसीसीआर की 57 पीठें कार्यरत थीं। इसने 114 भारतीय मिशनों और 39 केन्द्रों के माध्यम से 147 देशों में 6ठें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2020 का आयोजन किया। कोविड-19 के

दौरान, आईसीसीआर भारत ग्लोबल वीक - लंदन, द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल (टीजीआईएफ) - ओटावा, सारंग 2020 - कोरिया गणराज्य में भारत का 6ठां वार्षिक महोत्सव और प्रायोजित सितार समूह “इंडिया पुन कॉन्सेटो” त्यौहार – स्पेन जैसे विदेशी उत्सवों में रिकॉर्ड की गई प्रस्तुतियों की स्ट्रीमिंग करके उन्हें ऑनलाइन/ वर्चुअल रूप से प्रस्तुत करने की पहल की।

संसद एवं समन्वय प्रभाग

संसद और समन्वय प्रभाग की जिम्मेदारी व्यापक रूप से संसदीय कार्य; मंत्रालय के भीतर और बाहर समन्वय; भारतीय शिक्षण संस्थानों में विदेशी छात्रों का प्रवेश और अन्य देशों के साथ भारत संघ द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की

निगरानी के साथ-साथ उनकी समीक्षा करना है। जनवरी-दिसंबर 2020 के दौरान, कोविड महामारी के चलते समन्वय प्रभाग ने वर्चुअल सम्मेलनों संबंधी अनापत्ति को सरल बनाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए।

1

भारत के पड़ोसी

अफगानिस्तान

भारत और अफगानिस्तान सदियों से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों से जुड़े हुए हैं। अक्टूबर 2011 में हस्ताक्षरित सामरिक भागीदारी समझौता (एसपीए) भारत-अफगानिस्तान संबंधों की मार्गदर्शक भावना है।

एसपीए अफगानिस्तान के बुनियादी ढांचे और संस्थानों के पुनर्निर्माण, विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी अफगान क्षमता के पुनर्निर्माण हेतु, भारत से शिक्षा और तकनीकी सहायता प्रदान करता है; इसके अलावा, यह अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश को प्रोत्साहित करना; अफगानिस्तान के निर्यात के लिए भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुँच प्रदान करना; अफगान के नेतृत्व वाली, अफगान के स्वामित्व वाली, अफगान नियंत्रित और शांति और सुलह की समावेशी प्रक्रिया के लिए राजनीतिक समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अफगानिस्तान के लिए एक निरंतर और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता की वकालत करता है।

नियमित उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान भारत-अफगानिस्तान संबंध की विशेषता है। हमारे नेताओं ने द्विपक्षीय यात्राओं के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के दौरान एक-दूसरे से भेंट की। भारत के विदेश मंत्री ने अप्रैल और अगस्त 2020 में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अटमार के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में अफगान राष्ट्रीय दिवस समारोह में

भाग लिया। विदेश सचिव ने 28-29 फरवरी 2020 को अफगानिस्तान का दौरा किया, जो पदभार संभालने के बाद विदेश में उनकी पहली यात्रा थी। अफगानिस्तान से, राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद के अध्यक्ष, अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2020 में भारत का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान, डॉ. अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से भेंट की। अफगानिस्तान के अन्य उच्च स्तरीय आगंतुकों में हमदुल्ला मोहिब, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (जनवरी 2020); हमिद करज़ई, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति (जनवरी 2020); फील्ड मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम (सितंबर 2020); अत्ता मोहम्मद नूर, जमीयत-ए-इस्लामी के मुख्य कार्यकारी (अक्टूबर 2020)। अफगानिस्तान के सुलह के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि राजदूत ज़ल्माय खलीलज़ाद ने दो बार (मई और सितंबर 2020) भारत का दौरा किया।

विदेश मंत्री ने 12 सितंबर 2020 को दोहा में अंतर-अफगान वार्ता के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत का एक प्रतिनिधिमंडल दोहा गया। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में एक स्थायी और व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। विदेश मंत्री ने सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक परियोजनाओं के साथ अफगानिस्तान के एक प्रमुख विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला।



राष्ट्रीय सुलह के लिए उच्च परिषद, अफगानिस्तान के अध्यक्ष डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से भेंट की, नई दिल्ली, 08 अक्टूबर 2020

विदेश मंत्री ने 12 सितंबर 2020 को दोहा में अंतर-अफगान वार्ता के उद्घाटन सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत का एक प्रतिनिधिमंडल दोहा गया। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में एक स्थायी और व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। विदेश मंत्री ने सभी 34 प्रांतों में 400 से अधिक परियोजनाओं के साथ अफगानिस्तान के एक प्रमुख विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला।

विकास सहयोग

भारत, एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में, एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, संप्रभु, लोकतांत्रिक और एकजुट अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान और विश्व समुदाय के लोगों के साथ काम कर रहा है। भारत के पास अफगानिस्तान के लिए 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का विकास सहयोग पोर्टफोलियो है। यह पांच स्तंभों: (क) बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं; (ख) मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण; (ग) मानवीय सहायता; (घ) उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाएं; तथा (ङ) हवाई और भूमि संपर्क के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर पर केंद्रित है।

विदेश मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 23-24 नवंबर 2020 को जिनेवा में आयोजित 2020 अफगानिस्तान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के साथ शतूट बांध के निर्माण के लिए एक समझौते की घोषणा की, जो काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा। भारत ने पहले काबुल शहर को बिजली प्रदान करने वाली 202 किलोमीटर की फुल-ए-खुमरी ट्रांसमिशन लाइन बनाई थी। विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान में उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के चौथे चरण को लॉन्च करने की भी घोषणा की, जिसमें 80 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की 100 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री ने अपने बयान में, एक पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के रूप में अफगानिस्तान के विकास के लिए भारत की दीर्घकालिक

प्रतिबद्धता पर बल दिया।

भारत ने अफगानिस्तान को 20 मीट्रिक टन से अधिक की जीवन रक्षक दवाओं सहित कोविड-19 से संबंधित सहायता का विस्तार किया। भारत ने कोविड-19 महामारी के समय अफगानिस्तान की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चाबहार पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान को 75,000 मीट्रिक टन गेहूं की मानवीय सहायता दी।

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग 2020-21 में जारी रहा। भारत ने अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों (एएनडीएसएफ) के सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए।

अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना और ऑनलाइन अल्पकालिक क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम सहित विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी 2020-21 में जारी रहे।

आर्थिक सहयोग और संपर्क

भारत और अफगानिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2019-20 में 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के पार पहुँच गया। अफगानिस्तान में भारत का निर्यात लगभग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर (997.58 मिलियन अमरीकी डॉलर) तक पहुँचा और अफगानिस्तान से भारत का आयात 530 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा। पिछले पांच वर्षों में व्यापार मूल्य की वृद्धि में लगातार सुधार हुआ है। अफगानिस्तान में भारतीय निर्यात में 2015-16 और 2019-20 के बीच 89% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। इसी प्रकार, भारत का आयात भी इसी अवधि के दौरान 72% बढ़ा। मूल्य के संदर्भ में, 2018-19 की तुलना में निर्यात में 2019-20 में, 39% की और आयात में 21% से अधिक की वृद्धि हुई।

अप्रैल 2020 में, कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रसार ने सामान्य व्यापार और व्यापारिक परिवहन को बाधित कर दिया। अप्रैल-सितंबर 2020 (अप्रैल-

सितंबर 2019 की तुलना में) में अफगानिस्तान में भारतीय निर्यात कुल मिलाकर 12% से पिछड़ गया। हालांकि, अर्थव्यवस्था और बाजारों के सामान्यीकरण की शुरुआत के साथ, व्यापार के आंकड़ों में सुधार शुरू हो गया है। सितंबर 2020 में भारत में अफगान से निर्यात में 27% वृद्धि (सितंबर 2019 की तुलना में) दर्ज की गई।

अपने उद्घाटन के बाद से, भारत को अफगान से निर्यात की सुविधा प्रदान की है। जनवरी-अक्टूबर 2020 के दौरान, 157 कार्गो उड़ानों ने 3505 मीट्रिक

टन सूखे मेवे, ताजे फल, औषधीय जड़ी-बूटियाँ, केसर, हींग और मसालों को 85 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का कारोबार किया। केसर और हींग उच्च मूल्य वाले उत्पाद हैं और इन्हें मुख्य रूप से एयर-कॉरिडोर के माध्यम से रूट किया जाता है। इसी तरह, चाबहार बंदरगाह से 4500 मीट्रिक टन अफगान उत्पादों की शिपिंग देखी गई, जिसमें भारत में भेजे जाने वाले सूखे मेवे और ताजे फल शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 11 मिलियन अमरीकी डॉलर है।

बांग्लादेश

बांग्लादेश भारत के सबसे करीबी सहयोगियों और महत्वपूर्ण पड़ोसियों में से एक है। दोनों देशों में बहुआयामी संबंध हैं। दशकों में, ये संबंधों रणनीतिक साझेदारी में बदल गये हैं।

वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50वीं वर्षगांठ और भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना को चिह्नित करता है। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के साथ भारत का घनिष्ठ संबंध इन द्विपक्षीय संबंधों को अद्वितीय बनाता है।

राजनीतिक संबंध

दोनों देश उच्चतम स्तर सहित परस्पर निकट संपर्क बनाए रखते हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने पिछले 5 वर्षों में 8 बार भेंट की है, जिसमें 4 द्विपक्षीय दौर और 4 अंतरराष्ट्रीय बैठकों के मौके पर 4 बैठकें शामिल थीं। अप्रैल 2020 से, दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक-दूसरे से दो बार फोन पर (29 अप्रैल और 25 मई) बात की है। प्रधानमंत्री हसीना के अनुरोध पर, भारत के प्रधानमंत्री ने 17 मार्च, 2020 को "मुजीब वर्षों" के अवसर पर एक वीडियो संदेश दिया था।



भारत-बांग्लादेश आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री, 17 दिसंबर 2020

दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच हालिया उच्च स्तरीय बातचीत 17 दिसंबर 2020 को हुई भारत-बांग्लादेश आभासी सम्मेलन था। मार्च 2021 में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की स्वर्ण जयंती और बांग्लादेश के मुजीब वर्षों समारोह की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री के ढाका का दौरा करने की उम्मीद है।

दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच भी नियमित रूप से बातचीत होती है। 2020-21 में विदेश मंत्री-स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री आयोग (जेसीसी) की 6 दौर की बैठक हुई है। पिछले दौर को लगभग 29 सितंबर 2020 को

आयोजित किया गया था। विदेश सचिव ने मार्च और अगस्त 2020 में ढाका की दो यात्राएं कीं। इसके अलावा, दोनों तरफ के विभिन्न मंत्रालयों के बीच वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर नियमित बातचीत और दौरें जारी रहे।

दोनों पक्षों ने 2020-21 के दौरान 8 द्विपक्षीय सहयोग दस्तावेजों को पूरा किया गया। 17 दिसंबर 2020 के भारत-बांग्लादेश आभासी सम्मेलन के दौरान, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर एक रूपरेखा; स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य संस्थानों के माध्यम से उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के

बारे में समझौता ज्ञापन; सीमापार हाथी संरक्षण पर प्रोटोकॉल; बरिशाल सिटी कॉरपोरेशन के लिए लमचोरी क्षेत्र में कचरे/ठोस अपशिष्ट निपटान मैदान के लिए सामानों की आपूर्ति और सुधार के लिए समझौता ज्ञापन; कृषि के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल संग्रहालय, ढाका, बांग्लादेश और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, भारत के बीच समझौता ज्ञापन और भारत-बांग्लादेश सीईओ के फोरम के संदर्भ की शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, मई 2020 में अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के द्वितीय परिशिष्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे।

संपर्क

दोनों पक्ष बांग्लादेश के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ परस्पर परिवहन और संपर्क बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। रेलवे, सड़क, तटीय और साथ ही नदी संपर्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

वर्तमान में, 1965 के पूर्व के छह में से पांच रेल लिंक बहाल किए गए हैं, जिनके नाम पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल)-बेनापोल (बांग्लादेश), गेदे (पश्चिम बंगाल)-दर्शना (बांग्लादेश), राधिकापुर (पश्चिम बंगाल) -बिराल (बांग्लादेश) और सिंहबाद (पश्चिम बंगाल)-रोहनपुर (बांग्लादेश) और सबसे नवीनतम लिंक - चिल्हाटी (बांग्लादेश) - हल्दीबाड़ी (पश्चिम बंगाल) लिंक हैं। शाहबाजपुर (बांग्लादेश)- महिषासन (असम) लिंक पर काम चल रहा है। इसके अलावा, जब कोविड के कारण जमीन के रास्ते से व्यापार में गिरावट आई, तो आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जुलाई 2020 में पार्सल और कंटेनर ट्रेन सेवाएं शुरू की गईं। अखौरा (बांग्लादेश) -अगरतला (त्रिपुरा) सीमा पार की नई रेलवे लिंक पर काम चल रहा है।

कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच की हालिया पहलों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

(I) अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार के प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर मई 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने नदी मार्गों की संख्या को कुल 10 तक बढ़ा दिया है और त्रिपुरा को भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ा है। सितंबर 2020 में नए मार्ग (सोनमुरा-दाउदकंडी) पर ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जहां त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने इसे प्राप्त किया। अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा में यह पहला निर्यात था।

(II) विदेश मंत्री, रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने जुलाई 2020 में अपने बांग्लादेशी समकक्षों को 10 ब्रॉड गेज इंजन दिए। ये लोकोमोटिव गेज भारत के साथ रेल संपर्क बढ़ाने में मदद करने के साथ-साथ बांग्लादेश को भारत से कार्गो प्राप्त करने और बांग्लादेश के भीतर यात्री और मालगाड़ियों की आवाजाही की क्षमता बढ़ाने में भी मदद करेंगे।

(III) दोनों पक्षों ने जुलाई 2020 में चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश से भारत में माल ले जाने के लिए ट्रायल रन किया। अभी पारगमन शुल्क को अंतिम रूप देने के बारे में चर्चा चल रही है।

(IV) अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग कर भारत से बांग्लादेश के लिए मालवाहक कंटेनर कार्गो द्वारा निर्यात जुलाई 2020 में ढाका के पनगांव अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल तक पहुँच गया।

भारत और बांग्लादेश के बीच चार स्वीकृत बस सेवाएँ हैं, हालांकि कोविड की स्थिति के कारण उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। ये बस सेवाएँ कोलकाता-खुलना, ढाका-कोलकाता, ढाका-अगरतला और ढाका-शिलांग-गुवाहाटी मार्ग पर चलती हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रति सप्ताह 100 से अधिक उड़ानों के संचालन की मंजूरी दी गई है।कोविड महामारी के कारण बाधित होने वाले उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने की सुविधा के लिए, अक्टूबर 2020 में दोनों पक्षों के बीच एक हवाई यात्रा बुलबुला स्थापित किया गया था। यह दोनों पक्षों के बीच प्रति सप्ताह 56 उड़ानों की अनुमति देता है।

आर्थिक और वाणिज्यिक

पिछले दशक में द्विपक्षीय व्यापार 10 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का हो गया है।बांग्लादेश अब दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 9.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि 2018-19 में यह 10.25 बिलियन अमरीकी डॉलर था (अप्रैल-अक्टूबर 2020 के आंकड़े 4.72 बिलियन अमरीकी डॉलर)। दोनों पक्ष बांग्लादेश में भारतीय निवेश को बढ़ावा देने और प्रत्यक्ष हवाई सेवाओं, रेलवे, तटीय शिपिंग सेवाओं और अंतर्देशीय जलमार्ग सेवाओं के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। दोनों पक्ष वर्तमान में एक द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के विभिन्न पहलुओं पर एक संयुक्त अध्ययन कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने भारत-बांग्लादेश सीईओ फोरम के लिए संदर्भ की शर्तों को भी अंतिम रूप दिया है, इन शर्तों में व्यापार और निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत स्तर के इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच आदान-प्रदान की परिकल्पना की गई है।

कोविड महामारी के दौरान, भूमि मार्ग से व्यापार बाधित हो जाने पर बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए भारत की सुगठित रेल प्रणाली का उपयोग किया गया था। लॉकडाउन की अवधि में, भारत और बांग्लादेश के बीच चार मौजूदा रेल मार्गों से 800 से अधिक रैक (कुल 1.65 मिलियन एमटी) पहुँचाये गये, जिनमें प्याज, लाल मिर्च, अदरक, धान के बीज आदि जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

दोनों पक्षों ने दिसंबर 2020 में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर एक रूपरेखा का को अंतिम रूप दिया। इसके अलावा, इंडियन ऑयल ने जुलाई 2020 में बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवी) की स्थापना करने और बांग्लादेश और अन्य देशों में व्यापार के अन्य अवसरों की खोज के लिए बांग्लादेश के बेमेस्को ग्रुप के साथ सहयोग किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी बेक्सिमको समूह के मोंगला में एलपीजी आयात टर्मिनल और बॉटलिंग प्लांट से जुड़े मौजूदा एलपीजी बुनियादी ढांचे के संचालन को संभालेगी और इंडियन ऑयल के अनुभव के साथ कारोबार को बढ़ाएगी। भविष्य की योजनाओं में एक गहरे पानी के बंदरगाह (मटरबारी या मीरसराय में) में एक बड़े एलपीजी टर्मिनल में निवेश करना शामिल है जो बड़े प्रशीतित कार्गो की अनुमति देगा और आयात की लागत को काफी कम कर देगा।

विकासात्मक भागीदारी

भारत अपनी कुल वैश्विक विकास सहायता का लगभग 30% बांग्लादेश को देता है। भारत ने 10 बिलियन अमरीकी डॉलर का कुल रियायती ऋण दिया है, जिसमें बांग्लादेश को तीन लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) शामिल हैं, जो किसी भी देश को दिए जाने वाले कुल रियायती ऋण में सबसे बड़ी है। भारतीय एलओसी के अंतर्गत कुल 46 परियोजनाओं में से 14 पूरी हो चुकी हैं, 17 परियोजनाएँ चल रही हैं या टेंडर के चरण में हैं और शेष 15 विस्तृत परियोजनाएँ रिपोर्ट तैयार करने के चरण में हैं। इन एलओसी द्वारा समर्थित क्षेत्रों में बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन, रेल और सड़क परिवहन और आर्थिक क्षेत्रों सहित बुनियादी ढाँचा विकास शामिल हैं।

भारत सरकार ‘बांग्लादेश को सहायता’ के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को अनुदान सहायता भी प्रदान करती है। प्रमुख अवसंरचना और सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं में 12 किलोमीटर लंबा अगरतला-अखौरा रेल लिंक, अंतर्देशीय जलमार्ग का ड्रेजिंग और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन (सिलीगुड़ी से परबतीपुर तक उच्च गति डीजल की आपूर्ति के लिए) शामिल हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, संस्कृति, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन और सामुदायिक कल्याण आदि के क्षेत्रों में कई उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (एचआईसीडीपी) भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें स्कूल/कॉलेज भवन, प्रयोगशालाएँ, औषधालय, गहरे नलकूप, सामुदायिक केंद्र, ऐतिहासिक स्मारकों/भवनों के नवीनीकरण आदि जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं। कुल मिलाकर, 81 एचआईसीडीपी की गई हैं, जिनमें से 63 पूरी हो चुकी हैं। दिसंबर 2020 में हुए आभासी सम्मेलन में, दोनों पक्षों ने एचआईसीडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं के दायरे और मात्रा का विस्तार करने का निर्णय लिया।

रक्षा सहयोग

भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ा है। वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन, सेवा प्रमुखों के स्तर पर उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और वार्षिक सेवा विशिष्ट स्टाफ वार्ता के आयोजन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के उल्लेखनीय सुधार में योगदान दिया है। सातवीं नौसेना स्टाफ वार्ता (अक्टूबर 2020), चौथी कोस्ट गार्ड स्टाफ वार्ता (अक्टूबर 2020) और तीसरा वार्षिक रक्षा संवाद (नवंबर 2020) आयोजित किया गया। भारत ने दिसंबर 2020 में बांग्लादेश सशस्त्र बलों को 120 मिमी मोर्टार का एक रेजिमेंट भी उपहार में दिया है।

बांग्लादेश सशस्त्र बलों के साथ प्रशिक्षण सहयोग में लगातार वृद्धि हुई है, हालांकि 2020-21 के लिए प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम में कोविड महामारी के कारण कुछ व्यवधान रहे हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले यात्रा प्रतिबंधों के बीच, भारत में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज पाठ्यक्रम और उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संशोधित कार्यक्रम के साथ आयोजित किए गए थे। नेशनल डिफेंस कॉलेज की तीसरी रिक्ति के बदले उच्चतर रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम में एक अतिरिक्त रिक्ति और 2020-21 के लिए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में दो अतिरिक्त रिक्तियां आवंटित की गई थीं। भारतीय सेना और मुक्तिबाहिनी दोनों के द्वारा साथ लड़े गए, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की 50 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए, बांग्लादेश सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने भारत के 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया था।

सुरक्षा और सीमा प्रबंधन

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी)के बीच महानिदेशक-स्तरीय वार्ता (डीजीएलटी) का 51वां दौर दिसंबर 2020 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, जबकि डीजीएलटी का 50 वां दौर सितंबर 2020 में ढाका में हुआ था। दोनों पक्षों ने कोविड महामारी के दौरान अस्थायी व्यवधानों को देखते हुए वार्ता के बाद समन्वित गश्त तेज कर दी है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बांग्लादेश के साथ भारत के विकास सहयोग का एक सक्रिय स्तंभ है। भारत सरकार आईटीईसी, टीसीएस, आईसीसीआर, सार्क और अन्य योजनाओं के अंतर्गत बांग्लादेश के अधिकारियों के लिए भारत में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रायोजित करती है। 2014 से, बांग्लादेश के लगभग 1500 न्यायिक अधिकारियों और 5600 सिविल सेवकों को प्रशासन, पुलिस, सीमा शुल्क, नशीले पदार्थों का पता लगाने, परमाणु विज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों को आवृत्त करने वाले भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षित किया गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) कर्मियों के बच्चों को भारत में अध्ययन करने के लिए हर साल 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अब तक लगभग 52 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के परस्पर संबंध

ढाका में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (आईजीसीसी) के माध्यम से भारतीय कला और सांस्कृतिक रूपों को बढ़ावा दिया जाता है। योग, कथक, मणिपुरी, हिंदी, हिंदुस्तानी संगीत आदि में कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। 2014 और 2019 के बीच एक वर्ष में जारी किए गए वीजा की कुल संख्या 500,000 से 1.6 मिलियन हो गई है, जिससे बांग्लादेश भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा वीजा परिचालन बन गया है। दोनों पक्षों के बीच क्रूज सेवाओं को भी मंजूरी दी गई है।

कोविड सहयोग

भारत सरकार ने बांग्लादेश को 3 भागों में चिकित्सा सहायता प्रदान की है। पहली खेप के रूप में 30,000 सर्जिकल मास्क और 15000 हेड कवर दिए गए, दूसरी और तीसरी खेप में क्रमशः जबकि 50,000 दस्ताने और 100,000 एचसीक्यू टैबलेट, और 30,000 आरटी-पीसीआर परीक्षण किट दिए गए थे। 6 ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें से एक को विशेष रूप से बांग्ला भाषा में आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर, इन पाठ्यक्रमों में बांग्लादेश के 352 पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है।

जनवरी 2021 में बांग्लादेश को अनुदान सहायता के रूप में कोविड वैक्सीन की 2 मिलियन से अधिक खुराक भेजी गई थी।

दोनों देश कोविड-19 वैक्सीन के क्षेत्र में सहयोग के बारे में सक्रिय चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चरण-III परीक्षण, टीका वितरण, सह-उत्पादन और बांग्लादेश में टीकों का वितरण शामिल हैं। भारत सरकार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान भारत से 5500 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान की।

भूटान

भारत और भूटान में, आपसी समझ और सम्मान पर आधारित एक विशेष साझेदारी है, एक साझा सांस्कृतिक विरासत और लोगों से लोगों के बीच मजबूत संबंधों ने इसे और सुदृढ़ किया है। वर्ष के दौरान जलविद्युत, आईसीटी,

स्वास्थ्य, संस्कृति, कृषि, अंतरिक्ष, तृतीयक शिक्षा और डिजिटल और वित्तीय कनेक्टिविटी सहित पारंपरिक और साथ ही सहयोग के नए क्षेत्रों में निरंतर विकास के साथ, दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध और गहरे हुए हैं।



प्रधानमंत्री मोदी, भूटान के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से भूटान में रुपेकार्ड फेज -2 की शुरुआत की

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और संवाद

दोनों देशों के बीच विशेष संबंध है और नियमित रूप से उच्च स्तरीय आदान-प्रदान और बातचीत की परंपरा कायम है। 16 अप्रैल 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री लोटे त्सरिंग के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर क्षेत्रीय स्थिति पर चर्चा की और दोनों नेताओं ने सार्क देशों के नेताओं के बीच सहमत विशेष व्यवस्था को लागू करने में हुई प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले, दोनों नेताओं ने मार्च 2020 में कोविड-19 पर सार्क नेताओं के सम्मेलन के दौरान आभासी बातचीत की थी।

17 सितंबर 2020 को, प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक से बात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की और बहुपक्षीय भारत-भूटान संबंधों को और मजबूत करने और इनका विस्तार करने के लिए रास्ते तलाशने पर भी बात की।

प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्सरिंग ने 20 नवंबर 2020 को एक आभासी समारोह के दौरान रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जो दोनों देशों में रुपे कार्ड कार्ड की अंतर-क्षमता को पूरा करेगा। इस आयोजन के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने तकनीकी सहयोग के अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से, अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल की पहलों का स्वागत किया और 'बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग' के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। दोनों नेताओं ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच अनूठे संबंध न केवल अमूल्य हैं, बल्कि ये दुनिया के लिए अद्वितीय उदाहरण भी हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में

सहयोग के लिए, भूटान के लिए एक छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास पर काम करने के लिए चार भूटानी अंतरिक्ष इंजीनियरों ने दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक इसरो में प्रशिक्षण लिया।

भारत के विदेश मंत्री और भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी की आभासी उपस्थिति में, 29 जून 2020 को भूटान की रॉयल सरकार और खोलचेन हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच 600 मेगावाट की खोलोंगचु (संयुक्त उद्यम) हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर, भूटान एर भारत के विदेश मंत्रियों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में जलविद्युत विकास के महत्व पर जोर दिया।

विकासत्मक सहयोग

भूटान के साथ भारत की व्यापक विकास भागीदारी लोक-केंद्रित और भूटान सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और जरूरतों पर आधारित है। भारत सरकार ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना (वित्तीय वर्ष 2018-23) के लिए 4500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें परियोजना से जुड़ी सहायता के लिए 2800 करोड़ रुपए, उच्च प्रभाव सामुदायिक सामुदायिक परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपए और 850 करोड़ रुपए का कार्यक्रम अनुदान है। भारत सरकार ने 400 करोड़ रुपए की 'संक्रमणकालीन व्यापार सहायता सुविधा' भी प्रदान की है, जो भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदान की जाएगी। भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500

करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए प्रतिबद्धता की है और भारत सरकार से 501 करोड़ रुपए की शुरुआती रिलीज़ भी प्रदान की, ताकि कोविड-19 के प्रभाव को कम करने में भूटान के प्रयासों का समर्थन किया जा सके।

भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अप्रैल और अक्टूबर 2020 में चिह्नित, विभिन्न नए क्षेत्रों में 298 करोड़ रुपए लागत की 180 नई उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाएं, जैसे कि सिंचाई चैनल, फार्म रोड, बुनियादी स्वास्थ्य इकाई इत्यादि की पहचान की गई है। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

भारत भूटान में एक मल्टी-डिसिप्लिनरी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (एमडीएसएसएच) की योजना के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। एचएससीसी लिमिटेड के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ टीम ने मार्च 2020 में भूटान का दौरा किया और परियोजना की डीपीआर तैयार करने के लिए भूटान की रॉयल सरकार के साथ चर्चा जारी रखी।

जल विद्युत सहयोग

पारस्परिक रूप से लाभकारी जलविद्युत सहयोग 29 जून 2020 को 600 मेगावाट खोलोंगचु जलविद्युत परियोजना के लिए रियायती समझौते पर हस्ताक्षर कर एक और उपलब्धि प्राप्त की। दोनों सरकारों ने दो बड़ी परियोजनाओं-1200 मेगावाट की पुनात्संग्लु-आई हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना और 1020 मेगावाट डब्ल्यू पुनात्संगु-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए निकट समन्वय बनाए रखा। भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की प्रतिबद्ध राशि 'मंगदेछु टैरिफ के समायोजन' के रूप में भी जारी की है, जिसका भूटान में राजस्व-सृजन गतिविधियों के पूरक के लिए उपयोग किया जा रहा है। संयुक्त रूप से निर्मित 720 मेगावाट की मंगदेछु जलविद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा 'सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए' ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया।

शिक्षा और क्षमता निर्माण

भारत सरकार ने भूटानी छात्रों के लिए तीन नई भारत-भूटान मैत्री छात्रवृत्तियाँ स्थापित की हैं, जिनके लिए आईआईटी कानपुर में प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राजदूत छात्रवृत्ति, नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति, परियोजना बंधी सहायता के अंतर्गत स्नातक छात्रवृत्ति, नालंदा विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, आईसीसीआर छात्रवृत्ति, भूटानी छात्रों को सार्क छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करती है, भूटान के छात्रों द्वारा आयुष छात्रवृत्ति का भी लाभ उठाया जा सकता है। भूटान के शाही सरकार के सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण में, न भूटान का मुख्य भागीदार है। आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, भूटान को लगभग 325 प्रशिक्षण स्लॉट सौंपे गए हैं, 2019-2020

मालदीव

भारत ने एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध मालदीव को देखने की पारस्परिक इच्छा के अंतर्गत मालदीव सरकार और मालदीव के लोगों के साथ अपने करीबी जुड़ाव को उन्नत किया। स्वास्थ्य और यात्रा प्रतिबंधों के कारण उच्च-स्तरीय बैठकें आभासी मंचों पर चली गईं। इस अवधि ने भारत को 'प्रथम और

में इनमें से 279 स्लॉटों का उपयोग किया गया था। अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के दौरान, 86 भूटानी नागरिकों ने ई-आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण के अवसरों का लाभ उठाया है। सेबी नीतियों और सुरक्षा बाजार नियमों के साथ-साथ भूटान के न्यायिक अधिकारियों के क्षेत्रों में भूटानी वित्त क्षेत्र के पेशेवरों के लिए अनुकूलित ई-आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा, भूटान के कई सरकारी अधिकारियों को एलबीएसएनएए, एसएसएफएसआई, एनएसीईएन और एसवीपी-एनपीए सहित प्रमुख सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा। 2019 में, द्विपक्षीय व्यापार लगभग 9647 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। दोनों सरकारें व्यापार और आपसी निवेश को सुविधाजनक बनाने के उपाय करने में जुटी रहीं। टॉर्सा टी गार्डन (भारत) और अहले (भूटान) के माध्यम से एक नया व्यापार मार्ग खोला गया था। नगरकाटा, अगरतला और पांडु और जोगीगोपा नदी के बंदरगाहों पर नए व्यापार बिंदु भी जल्द ही काम करने लगेंगे।

अक्टूबर 2020 में, भूटानी कृषि उत्पादों (सेब, एस्का नट, अदरक, मैडरिन, आलू) के भारत में निर्यात के लिए औपचारिक बाजार पहुँच दी गई। इसी तरह, भारतीय कृषि उत्पादों (ओकरा, प्याज, टमाटर) को भूटान में औपचारिक रूप से बाजार पहुँच दी गई। भूटान से कृषि उत्पादों के भारत में निर्यात की सुविधा के लिए भारत-भूटान सीमा पर पहला प्लांट क्वारंटाइन कार्यालय भारत के जयगांव में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन में खोला गया था।

कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग

भारत-भूटान के अनूठे और विशेष संबंधों के अनुरूप, भारत सरकार ने कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के बावजूद भूटान को व्यापार और आवश्यक वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की। भारत सरकार ने अब तक भूटान की शाही सरकार को पेरसितामोल, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन, पीपीई, एन 95 मास्क, एक्स-रे मशीन और टेस्ट किट आदि आवश्यक दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की हैं। भारत ने भूटान के साथ 'हवाई यात्रा व्यवस्था' या 'ट्रांसपोर्ट बबल' में भूटान के साथ क्रमिक तरीके से उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए समझौता किया है। कोविड-19 महामारी के कारण उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। भारत कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवारों के तीसरे चरणके नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिए भूटान के साथ भी सहयोग कर रहा है।

जनवरी 2021 में कोविशिल्ड वैक्सीन की 150,000 खुराक अनुदान सहायता के रूप में भूटान को भेजी गई थी।

विदेश सचिव ने 8-10 नवंबर 2020 तक मालदीव का दौरा किया। महामारी की शुरुआत के बाद से यह मालदीव की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी। उनकी यात्रा के दौरान, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर अनुदान सहायता और युवा मामलों और खेल में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दो उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) - हनीमाधू में कृषि प्रयोगशाला और अडू में ड्रग डिटॉक्स सुविधा के समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव ने पूरे द्वीप में स्थापित करने के लिए 67 बच्चों के पार्क (एक भारतीय अनुदान द्वारा वित्त पोषित) भी सौंपे।

कोविड-19 सहायता

महामारी ने मालदीव की अर्थव्यवस्था (पर्यटन राजस्व पर निर्भरता के कारण दक्षिण एशिया में सबसे बुरी तरह प्रभावित) और इसके स्वास्थ्य क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया। मालदीव पर पड़े कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए भारत के बहुआयामी और समय पर सहायता के तत्वों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) कोरोनोवायरस प्रकोप के दौरान फरवरी 2020 में वुहान से सभी 9 मालदीव वासियों की निकासी।
- (ख) अप्रैल 2020 में 5.5 टन आवश्यक दवाओं का दान।
- (ग) अप्रैल 2020 में ऑपरेशन संजीवनी के माध्यम से विभिन्न भारतीय शहरों से भारतीय वायुसेना द्वारा 6.2 टन दवाएँ पहुँचाना।
- (घ). आरबीआई और एमएमए के बीच मुद्रा स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत 150 मिलियन अमरीकी डॉलर।

(ङ) कोविड-19 निवारक विधियों में सहायता के लिए त्वरित प्रतिक्रिया मेडिकल टीम की तैनाती।

(च) मई 2020 में आईएनएस केसरी द्वारा मिशन सागर के अंतर्गत 580 टन खाद्य सहायता की आपूर्ति।

(छ) बजट समर्थन के लिए टी-बाँड्स की एसबीआई सदस्यता के माध्यम से 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता।

(ज) अक्टूबर/नवंबर 2020 में मालदीव के स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए नैदानिक अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना।

(झ) मालदीव के मरीजों को तत्काल इलाज के लिए भारत की यात्रा के लिए अनुमति देना।

मालदीव सरकार के अनुरोध पर, भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को एसबीआई द्वारा मालदीव के टी-बाँड्स में निवेश के माध्यम से 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है। यह सहायता मालदीव में सरकारी वित्त को उस समय सहारा देगी जब पर्यटन उद्योग के पतन के कारण राजस्व में 50% की कमी आई है। यह अब तक किसी भी राष्ट्र या संस्था द्वारा महामारी के दौरान मालदीव को दी गई सबसे बड़ी वित्तीय सहायता है।

जनवरी 2021 में कोविशिल्ड वैक्सीन की 100,000 खुराक अनुदान सहायता के रूप में मालदीव भेजी गई थी। मालदीव मेड-इन-इंडिया वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश था



मालदीव में टीकाकरण अभियान। मालदीव वैक्सीन मैली के अंतर्गत मेड-इन-इंडिया वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश था।

आर्थिक संबंध

शिपिंग राज्य मंत्री द्वारा 21 सितंबर 2020 को मालदीव के अपने समकक्ष अइसथ नाहुला के साथ संयुक्त रूप से एक मालवाहक नौका सेवा शुरू की गई थी। यह कार्गो सेवा कोचीन और तूतीकोरिन के साथ माले और कुलधुफुशी को जोड़ती है।

मालदीव सरकार के अनुरोध पर, दोनों देशों के बीच अगस्त 2020 के अंत में मालदीव में भारत से पर्यटन प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए हवाई यात्रा बुलबुला शुरू किया गया था। Iयह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पहला हवाई यात्रा बुलबुला था। 2020 में फैली महामारी के कारण, भारत मालदीव में आने वाले पर्यटकों

के लिए सबसे बड़ा स्रोत बाजार बन गया। 62,905 पर्यटकों के साथ, भारत शीर्ष स्थान पर रहा जिसके बाद रूस और इटली का स्थान है, मार्च 2020 के बाद एक वर्ष में मालदीव में कोई चीनी पर्यटक नहीं आया।

भारत ने मालदीव को खाद्यान्न, प्याज और निर्माण सामग्री सहित 11 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के समझौते को आगे बढ़ाया। इस वर्ष इन वस्तुओं के निर्यात का कोटा पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है।

मालदीवियन एयरलाइंस ने प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद गुजरात में साबरमती और केवडिया के बीच सीप्लेन सेवा की पहली उड़ान के लिए सीप्लेन (और चालक दल) प्रदान किया।

समुद्री खाने के क्षेत्र में दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को मापने के लिए 15 जनवरी 2021 को फिक्की द्वारा आयोजित क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की गई थी। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार को देखते हुए मालदीव के पर्यटन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट सेक्टर पर 2021 की पहली तिमाही में नये तौर पर ध्यान केंद्रित रहने की आशा है।

विकास सहयोग

मालदीव में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही जन-केंद्रित अनुदान परियोजनाओं को पूरा किया गया और आभासी समारोहों के माध्यम से इनका उद्घाटन किया गया। इनमें माले सिटी काउंसिल को वाहनों का उपहार, कोल्हूफी में स्ट्रीट लाइट की स्थापना, 61 द्वीपों को जिम उपकरण का दान, मालदीव पुलिस सेवाओं के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन आदि शामिल हैं। चल रही नौ उच्च प्रभावी सामुदायिक विकास परियोजनाएँ (एपआईसीडीपी) - 3 फिश प्रोसेसिंग प्लांट, 5 इको-टूरिज्म जोन और 1 वाटर बॉटलिंग प्लांट पर काम शुरू हुआ।

एक्विज्म बैंक ऑफ इंडिया के 1.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के रियायती ऋण द्वारा वित्तपोषित 9 मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति हुई थी। 2021 की पहली तिमाही में छह बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं – अडू में सड़कें और पुनर्निर्माण, गुलहिफलहु बंदरगाह, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, हनीमाधू में हवाई अड्डा विस्तार, हल्हुमले में क्रिकेट स्टेडियम, 34 द्वीपों में जल और सीवरेज नेटवर्क के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाएँगी। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इन परियोजनाओं में से कम से कम 4 के सौंपे जाने की आशा है।

राष्ट्रपति सोलीह ने जनवरी 2021 में एमवीआर 8 मिलियन भारतीय अनुदान से वित्त पोषित एकुवेनी सिंथेटिक ट्रैक परियोजना का उद्घाटन किया। 2021 की पहली

तिमाही में कई भारतीय अनुदान परियोजनाओं का उद्घाटन होने की संभावना है।

मानव संसाधन विकास

मालदीव के अधिकारियों ने चुनाव, स्वास्थ्य, महामारी शमन, लिंग आदि क्षेत्रों में ई-आईटीईसी पाठ्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया।

अक्टूबर 2020 से, 125 से अधिक मालदीव के शिक्षकों के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 मॉड्यूल) आयोजित किए गए थे।

वर्ष 2021 की पहली तिमाही में ऑडिट अधिकारियों, कस्टम अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवा प्रशासकों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है।

रक्षा सहयोग

महामारी के बावजूद- मालदीव में 33 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारत की सबसे बड़ी एकल अनुदान परियोजना -नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट पर कार्य प्रगति पर है। मार्च 2021 में परियोजना का उद्घाटन होने की संभावना है।

मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों (एमएनडीएफ), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के निर्माण और तटीय निगरानी रडार प्रणाली (सीएसआरएस) के निर्माण के लिए समग्र प्रशिक्षण केंद्र (सीटीसी) के शेष कार्यों पर भी काम जारी रहा।

भारत ने सितंबर 2020 में मालदीव को एक डोर्नियर विमान प्रदान किया, जिसे एमएनडीएफ द्वारा संचालित किया जाएगा। यह विमान एमएनडीएफ के नियंत्रण और कमान के अंतर्गत ईईजेड निगरानी, मानवीय और खोज और बचाव अभियान चलाने में मदद करेगा।

रक्षा मंत्री मरिया दीदी, रक्षा बलों के प्रमुख और मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने 3-7 फरवरी 2021 तक एयरो इंडिया में भाग लिया।

राजनयिक / बहुपक्षीय

मालदीव ने धारा 370 के हटाए जाने, सीएए, और अन्य मुद्दों पर यूएन, ओआईसी, आदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करना जारी रखा। विदेश सचिव ने नवंबर 2020 में मालदीव की अपनी यात्रा के दौरान 2021 में यूएनजीए के अध्यक्ष के रूप में विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद की उम्मीदवारी के लिए भारत के समर्थन की घोषणा की।

म्यांमार

म्यांमार आसियान के साथ भारत के संपर्क की जमीनी कड़ी और भारत के “पड़ोसी पहले” और “एक्ट ईस्ट” नीतियों का एक महत्वपूर्ण घटक है। म्यांमार के प्रति भारत का दृष्टिकोण म्यांमार द्वारा निर्देशित एक महत्वपूर्ण भूमि और समुद्री पड़ोसी का है जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक, सभ्यतागत, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और जातीय संबंध हैं। उच्च स्तरीय यात्राओं की एक श्रृंखला ने द्विपक्षीय संबंधों की गति को बनाए रखने में मदद की है, जिसमें कनेक्टिविटी परियोजनाएँ, ऊर्जा सहयोग, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

राजनीतिक

म्यांमार के राष्ट्रपति 26-29 फरवरी 2020 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। नौसेना प्रमुख ने 17-20 फरवरी 2020 के बीच म्यांमार का दौरा किया। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जनवरी 2020 में म्यांमार का दौरा किया। जून 2020 में, अपनी माँस्को यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री ने म्यांमार सुरक्षा बल के कमांडर-इन-चीफ से भेंट की। भारत-म्यांमार विदेश कार्यालय परामर्श 01 अक्टूबर 2020 को आभासी रूप से आयोजित किया गया था,

जिसके बाद 04-05 अक्टूबर 2020 को विदेश सचिव और थल सेना प्रमुख ने म्यांमार का दौरा किया गया था। प्रतिनिधिमंडल ने स्टेट काउंसलर दाऊ आंग सान सू की और कमांडर-इन-चीफ सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाङ्ग से भेंट की। याला के दौरान, मीचकीइना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग का आभासी उद्घाटन किया गया और भारत ने चिन राज्य

में एक पुल के निर्माण के लिए 2 मिलियन अमरीकी डॉलर देने की घोषणा की। यह पुल मिज़ोरम राज्य और म्यांमार के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाएगा। 24 नवंबर 2020 को दोनों देशों के बीच सातवीं मंत्रिस्तरीय संयुक्त व्यापार समिति की आभासी बैठक आयोजित की गई थी।



1 अक्टूबर, 2020 को भारत-म्यांमार विदेश कार्यालय परामर्श में विदेश सचिव।

वर्तमान सत्तारूढ़ दल, नेशनल काउंसिल फॉर डेमोक्रेसी, स्टेट काउंसलर, डॉ. आंग सान सू की के नेतृत्व में 664 सदस्यीय संसद में 396 सीटें हासिल करके 8 नवंबर 2020 को म्यांमार में हुए आम चुनावों में विजेता रहा।

कोविड सहयोग

अप्रैल 2020 में, प्रधानमंत्री ने घरेलू और क्षेत्रीय संदर्भों में विकसित कोविड-19 परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए म्यांमार के स्टेट काउंसलर दाऊ आंग सान सू की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक-दूसरे को जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए म्यांमार को हर संभव सहायता प्रदान करने की भारत की तत्परता से भी अवगत कराया।

अपनी “पड़ोसी पहले” नीति के अनुरूप, भारत ने म्यांमार को, दो चरणों में कोविड से संबंधित सहायता दी है। मई 2020 में, दवाओं की पहली खेप भेजी गई, जिसमें 8.526 करोड़ रुपए (1 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक) के चिकित्सा उपकरण शामिल थे। अक्टूबर, 2020 में म्यांमार के विदेश सचिव और थल सेनाध्यक्ष की याला के दौरान रेमेड्सविर की 3024 शीशियों से युक्त दूसरी खेप प्रदान की गई थी। आज तक म्यांमार को कोविड से संबंधित सहायता देने के लिए 9.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

भारत और म्यांमार संदे भारत की उड़ानों के माध्यम से नागरिकों के प्रत्यावर्तन में भी सहयोग कर रहे हैं। आज तक, एयर इंडिया की 5 उड़ानों का संचालन किया है और म्यांमार के 800 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है।

जी-20 ऋण सेवा निलंबन पहल के अंतर्गत, भारत ने म्यांमार को 31 दिसंबर 2020 तक ऋण सेवा राहत प्रदान की। इसके अतिरिक्त, भारत ने म्यांमार से

उड़द और तुअर दाल के आयात के लिए कुछ प्रतिबंधों और कोटा सीमाओं को भी कम कर दिया।

जनवरी 2021 में कोविशिल्ड वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक अनुदान सहायता के रूप में म्यांमार भेजी गई थी।

विकास सहयोग

म्यांमार को भारत से 1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की विकास सहायता दी गई है, जिसमें अधिकांश परियोजनाएँ अनुदान सहायता के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं।

संपर्क की पहलें

भारत कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी प्रमुख संपर्क और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू कर रहा है। एक बार संचालित होने पर ये पहल, द्विपक्षीय संपर्क और व्यापार को बढ़ाएंगी और दोनों पक्षों के स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाएंगी।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)

दोनों पक्षों ने 2012 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अंतर्गत भारत ने चिन राज्य और नागा स्व-प्रशासित क्षेत्र में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और शिक्षा से संबंधित परियोजनाओं के लिए पाँच वर्ष की अवधि में प्रति वर्ष 5 मिलियन अमरीकी डॉलर (कुल 25 मिलियन अमरीकी डॉलर) की अनुदान सहायता प्रदान की है। अब तक 100 से अधिक परियोजनाओं को लागू किया गया है। बीएडीपी के चौथे चरण के अंतर्गत 29 परियोजनाएँ पूरी होने वाली हैं और पाँचवें चरण के अंतर्गत लागू होने वाली 24 परियोजनाओं

पर काम जल्द ही शुरू होने की आशा है।

राखीन राज्य विकास कार्यक्रम (आरएसडीपी)

भारत और म्यांमार ने आरएसडीपी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत भारत म्यांमार को पाँच वर्षों की अवधि में 25 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले चरण के अंतर्गत, जुलाई 2019 में 250 पूर्वनिर्मित घरों को पूरा किया गया और उन्हें म्यांमार को सौंप दिया गया है। राखीन राज्य में 11 परियोजनाओं का दूसरा चरण पूरा किया जा रहा है, जिसमें सौर परियोजनाएँ, सड़कों का निर्माण और जल आपूर्ति का प्रावधान शामिल हैं। दोनों पक्ष इसके तीसरे चरण के अंतर्गत एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जापान के साथ त्रिपक्षीय सहयोग के अंतर्गत, भारत राखीन राज्य में जापान द्वारा बनाए जा रहे स्कूलों के लिए नरम बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहा है। भारत और म्यांमार ने आरएसडीपी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत भारत म्यांमार को पाँच वर्षों की अवधि में 25 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले चरण के अंतर्गत, जुलाई 2019 में 250 पूर्वनिर्मित घरों को पूरा किया गया और उन्हें म्यांमार को सौंप दिया गया है। राखीन राज्य में 11 परियोजनाओं का दूसरा चरण पूरा किया जा रहा है, जिसमें सौर परियोजनाएँ, सड़कों का निर्माण और जल आपूर्ति का प्रावधान शामिल हैं। दोनों पक्ष इसके तीसरे चरण के अंतर्गत एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जापान के साथ त्रिपक्षीय सहयोग के अंतर्गत, भारत राखीन राज्य में जापान द्वारा बनाए जा रहे स्कूलों के लिए नरम बुनियादी ढांचा प्रदान कर रहा है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

रक्षा सहयोग पर 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रक्षा संबंधों को और मजबूत किया है। भारत से म्यांमार में उच्च स्तरीय यालाओं, प्रशिक्षण सहयोग, क्षमता निर्माण और रक्षा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

म्यांमार भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति संवेदनशील है और उसने मई 2020 में भारतीय विद्रोही समूहों के 22 कैडरों को भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया है।

समुद्री क्षेत्र में सहयोग म्यांमार के साथ भारत की बढ़ी हुई भागीदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दोनों पक्षों के बीच व्हाइट शिपिंग के आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन हुआ है।

हमारे सागर – पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण के अनुसार अक्टूबर 2020 में, भारत ने म्यांमार की नौसेना को, एक किलो-क्लास पनडुब्बी-आईएनएस सिंधुवीर, सौंपी, जो म्यांमार नौसेना की पहली पनडुब्बी है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, नौसेना से संबंधित क्षेत्रों और मौसम विज्ञान स्कूडन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में म्यांमार के रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना जारी रखा है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, भारत और ड्रग एब्यूज़ कंट्रोल के लिए केंद्रीय समिति, म्यांमार के बीच महानिदेशक स्तर की पाँचवीं द्विपक्षीय वार्ता की बैठक 10 दिसंबर 2020 को हुई थी।

व्यापार

भारत म्यांमार का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2019-20 के

दौरान म्यांमार को भारत का निर्यात 973.89 मिलियन अमरीकी डॉलर और म्यांमार से आयात 547.25 मिलियन अमरीकी डॉलर था। म्यांमार से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ सेम और दालें, लकड़ियाँ, धातु आदि हैं। भारत से म्यांमार को औषधीय वस्तुएँ, कृषि वस्तुएँ, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी आदि का निर्यात किया जाता है।

म्यांमार के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि और तमू-मोरेह में एकीकृत चेक पोस्ट को उन्नत करने और रिवाखदार-ज़ोख्तर में बुनियादी ढांचा, तटीय नौवहन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वार्ता, सिटवे पोर्ट के विकास आदि पर कई पहले कार्यान्वयन के चरण हैं। स्थानीय समुदायों को दोनों तरफ से लाभान्वित करने के लिए बॉर्डर हाट स्थापित करने के प्रयास भी जारी हैं।

“रचनात्मक विकास के लिए पुल निर्माण” पर छठवाँ भारत-सीएलएमवी (कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम) बिजनेस कॉन्क्लेव 3-4 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था।

ऊर्जा

इस वर्ष ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर कोऑपरेशन, ट्रेड एंड शिपिंग पर संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की आभासी बैठकें हुईं। ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर के सचिव स्तर के परामर्श भी आयोजित किए गए। विदेश कार्यालय परामर्श का अंतिम दौर अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच सातवीं मंत्री स्तरीय संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) 24 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी।

2020 में द्विपक्षीय बैठकें

इस वर्ष ऑयल एंड गैस, पावर सेक्टर कोऑपरेशन, ट्रेड एंड शिपिंग पर संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की आभासी बैठकें हुईं। ऑयल एंड गैस और पावर सेक्टर के सचिव स्तर के परामर्श भी आयोजित किए गए। विदेश कार्यालय परामर्श का अंतिम दौर अक्टूबर 2020 में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच सातवीं मंत्री स्तरीय संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) 24 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

एक विकास भागीदार के रूप में, भारत म्यांमार में कौशल विकास और क्षमता निर्माण की पहल की श्रृंखला में कृषि अनुसंधान, औद्योगिक प्रशिक्षण, ई-लर्निंग प्रौद्योगिकी, उद्यमिता विकास, अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण और आईटी कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में निवेश कर रहा है।

एम्स, पीजीआई, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, लिवर और पैतृक विज्ञान संस्थान आदि विभिन्न संस्थानों द्वारा 01 अप्रैल - 30 अक्टूबर 2020 तक, बारह ई-आईटीईसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित किए गए, इनमें म्यांमार सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी देखी गई।

एफएटीएफ दायित्वों के अनुपालन में म्यांमार की सहायता करने के लिए, भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई ने अक्टूबर 2020 में आईटी और वित्त के क्षेत्रों में म्यांमार वित्तीय खुफिया इकाई के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया। म्यांमार के छात्रों को भारत के विभिन्न आआटी में अध्ययन करने के लिए आसियान छात्रों को 5 वर्ष की

एकीकृत पीएचडी फैलोशिप के अंतर्गत छात्रवृत्ति का प्रस्ताव किया गया है।

आईसीसीआर और केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा द्वारा म्यांमार के छात्रों के लिए हिंदी भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रस्ताव किया गया है।

दिसंबर 2020 में दोनों देशों के बीच हाइड्रोग्राफी पर एक कार्यान्वयन व्यवस्था (आईए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

संस्कृति

कोविड महामारी के कारण, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस, हिंदी दिवस, आयुर्वेद दिवस आदि जैसे कई कार्यक्रमों को आभासी रूप से संपन्न किया गया। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक

केंद्र, यंगून ने लोकमान्य तिलक (1908-1914 से मंडला में कैद की गई) की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर डिजिटल प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया। विश्व संस्कृति दिवस, विश्व संगीत दिवस और शिक्षक दिवस आदि अन्य कार्यक्रम भी आभासी तौर मनाए गए।

हमारे सभ्यतागत संबंधों के अनुरूप, भारत द्वारा भारत-म्यांमार मैत्री परियोजना के अंतर्गत 2016 में आए भूकंप से क्षतिग्रस्त हुए पैगोडा/मंदिरों की मरम्मत और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले 2018 में, म्यांमार के शासकों, किंग माइंडन और किंग बायगीडों द्वारा बोधगया में निर्मित दो ऐतिहासिक मंदिरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुनर्स्थापित और पुनर्निर्मित किया गया था।

नेपाल

नेपाल के साथ भारत के पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध विशेष जन केंद्रित साझेदारी और बहुमुखी विकास सहयोग पर आधारित हैं। नियमित

उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान, व्यापक व्यापार और आर्थिक संबंध, एक दूरदेशी विकास एजेंडा और लोगों से लोगों के संपर्क इन द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता है।



विदेश मंत्री और उनके नेपाली समकक्ष ने 15 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में छठी भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की

उच्च स्तरीय आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ संयुक्त रूप से, 15 मार्च 2020 को आयोजित सार्क नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोविड-19 वैश्विक महामारी का मुकाबला करने पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 10 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री के साथ एक टेलीफोन वार्ता में नेपाल को आवश्यक दवाओं और आपूर्ति के लिए भारत को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री को किए गए एक विशेष टेलीफोन कॉल में, 74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार और भारत के लोगों को बधाई दी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में भारत के हालिया चुनाव के लिए भी बधाई दी।

विदेश मंत्री और नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने 20 मार्च 2020 को टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 महामारी के संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने 24 सितंबर 2020 को नेपाल की अध्यक्षता में सार्क विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक आभासी बैठक के दौरान विचारों का आदान-प्रदान किया। विदेश सचिव ने 26 - 27 नवंबर, 2020 को नेपाल का दौरा किया। नेपाल के विदेश सचिव के साथ विचार-विमर्श करने के अलावा, उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी भेंट की।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत और नेपाल के बीच रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से व्यापक रूप

से लाभप्रद सहयोग बना रहा है। रक्षा उपकरणों की आपूर्ति और दोनों पक्षों के सैन्य नेताओं द्वारा यात्राओं के नियमित आदान-प्रदान के अलावा, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की एक नियमित विशेषता रही है।

थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने ने 4-6 नवंबर 2020 को नेपाल का दौरा किया। एक अनूठी परंपरा को जारी रखते हुए उन्हें नेपाल की राष्ट्रपति श्रीमती बिद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाल सेना के जनरल ऑफ ऑनररी रैंक से सम्मानित किया गया, जो दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंधों को दर्शाता है। यात्रा के दौरान, जनरल नरवाने ने नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके नेपाली समकक्ष जनरल पूर्ण चंद्र थापा से भेंट की। भारत ने नेपाल सेना को उपहार में आईसीयू वेंटिलेटर जैसे कई चिकित्सा उपकरण, एम्बुलेंस और फील्ड अस्पताल उपकरण भी दिए।

भारत का क्षमता निर्माण और नेपाल सेना को प्रशिक्षण देने में नेपाल के साथ व्यापक सहयोग है, जिसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज (एनडीसी) और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) के पाठ्यक्रम शामिल हैं।

दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बल अर्थात् सशस्त्र सीमा बल और नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल ने निकट समन्वय बनाए रखा और दोनों पक्षों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित आभासी और भौतिक बैठकें हुईं

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और प्रमुख निवेशक बना हुआ है। भारत नेपाल के तीसरे देशों के अधिकांश व्यापार के लिए पारगमन की सुविधा भी देता है। कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी के बावजूद, 2019-2020 में द्विपक्षीय व्यापार 7.87 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का रहा। भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण आईकठिनाइयों के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार और आपूर्ति का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया।

भारत और नेपाल के वाणिज्य सचिवों ने 7 दिसंबर 2020 को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार, पारगमन और सहयोग पर अंतर-सरकारी समिति (आईजीसी) की बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक मुद्दों की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने निवेश संवर्धन, संयुक्त व्यापार मंच के गठन, मानकों के सामंजस्य के साथ-साथ व्यापार बुनियादी ढांचे के समन्वित विकास पर भी चर्चा की। आईजीसी की बैठक की तैयारी के लिए, 3-4 दिसंबर 2020 को संयुक्त सचिवों के स्तर पर अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने के लिए व्यापार, पारगमन और सहयोग पर अंतर-सरकारी उप-समिति (आईजीएससी) की बैठक हुई।

भारत और नेपाल के विद्युत/ऊर्जा सचिवों की सह-अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त संचालन समिति (जेएससी) की आठवीं बैठक 11 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक की तैयारी में, 10 दिसंबर 2020 को संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने बिजली, ऊर्जा बैंकिंग, सीमा पार उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के साथ-साथ 900 मेगावाट अरुण-तृतीय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त नियमों और दिशानिर्देशों के विकास पर चर्चा की।

तेल और गैस सहयोग पर भारत-नेपाल संयुक्त कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 13 अगस्त 2020 को आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइनें बनाने की संभावनाएं भी शामिल हैं।

विकास भागीदारी

भारत सरकार ने द्विपक्षीय कनेक्टिविटी, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना विकास की चल रही परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया। कोविड प्रतिबंधों के बावजूद, चल रही कनेक्टिविटी और विकासामक परियोजनाओं पर काम जारी रखा और इनमें काफी प्रगति हुई। भारत में नेपाल के राजदूत और नेपाल के विदेश सचिव की सह-अध्यक्षता में 17 अगस्त 2020 को भारत-नेपाल प्रवासी तंत्र की आठवीं बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में समग्र प्रगति की समीक्षा की गई।

रेलवे सहयोग पर भारत-नेपाल संयुक्त कार्यकारी समूह की चौथी बैठक 19 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने नेपाल में जनकपुर से होकर जयनगर से कुर्था के बीच पहली यात्री रेलवे लाइन के संचालन पर सहमति व्यक्त की थी। इस संबंध में, भारत में बने दो अत्याधुनिक 1600 एचपी डेमू ट्रेन सेटों को, नेपाल में निर्यात के आधार पर इस सेक्शन में यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन के लिए वितरित किया गया था। दोनों पक्षों द्वारा लाइन के अंतिम स्थान का सर्वेक्षण करने पर सहमति व्यक्त करने पर रक्सौल-काठमांडू ब्रॉडगेज विद्युतीकृत रेलवे लाइन पर काम भी आगे बढ़ा।

भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित सीमा-पार अवसंरचना परियोजनाओं में पर्याप्त प्रगति हुई है। भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित तराई सड़क परियोजना ने 14 में से 8 सड़क पैकेजों को पूरा करने के साथ प्रगति हासिल की। 8 मार्च 2020 को काठमांडू में हुई संयुक्त परियोजना निगरानी समिति की बैठक के दौरान परियोजना की प्रगति की निगरानी की गई। बीरगंज और बिराटनगर में दो एकीकृत चेक पोस्टों के पूरा होने के बाद, नेपालगंज और भैरहवा में दो नए आईसीपी पर काम चल रहा है। 12 नवंबर 2020 को, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नेपाल के शहरी विकास मंत्री, गोपाल कृष्ण श्रेष्ठ ने संयुक्त रूप से नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण के लिए आधारशिला समारोह को देखा।

भारत ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति विरासत क्षेत्रों में भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के लिए अपनी दीर्घकालिक सहायता के रूप में 1 बिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान किया था। नेपाल के गोरखा और नुवाकोट जिलों में कुल 50,000 घरों में से 46,000 घरों का निर्माण पूरा किया गया। भारत नेपाल के विभिन्न जिलों में 70 स्कूलों, 02 पुस्तकालयों और 147 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भूकंपरोधी भवनों के निर्माण में भी सहायता कर रहा है। भारत आधुनिक संरक्षण तकनीकों के साथ 28 संस्कृति विरासत स्थलों की बहाली में भी नेपाल की सहायता कर रहा है।

कई अन्य बड़े और मध्यम स्तर की विकास परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं। इनमें हेटुडा में नेपाल-भारत मैत्री पॉलिटेक्निक संस्थान और पनौटी में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी परियोजना शामिल हैं। 2020 में शिक्षा, स्वास्थ्य, संपर्क, स्वच्छता और पेयजल आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 11 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं पूरी की गईं और इनका उद्घाटन किया गया।

सांस्कृतिक और लोगों का लोगों से जुड़ाव

क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच मजबूत सहयोग है। भारत हर वर्ष नेपाली छात्रों को लगभग 3000 छात्रवृत्ति प्रदान करता है और नेपाल और भारत में अध्ययन के अवसर प्रदान करता है। आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रतिवर्ष नेपाल के लगभग 250 अधिकारियों को भारत के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाता है। कोविड-19 स्थिति के कारण, 2020 में नेपाल में 100 से अधिक उम्मीदवारों की भागीदारी के साथ ई-आईटीईसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

कोविड-19 सहायता

भारत ने नेपाल को लगभग 25 टन चिकित्सा सहायता प्रदान की है जिसमें पेरासिटामोल, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और रेमिडीसिर जैसी आवश्यक दवाएं शामिल हैं। भारत ने कोविड-19 महामारी को रोकने के प्रयासों में नेपाल की सहायता के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किट, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक चिकित्सा उपकरण भी प्रदान किए। महामारी के कारण कठिनाइयों के बावजूद, भारत ने नेपाल को द्विपक्षीय व्यापार और आपूर्ति का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित किया।

जनवरी 2021 में, भारत ने, भारत के सीरम संस्थान द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन की एक मिलियन खुराक अनुदान सहायता के रूप में नेपाल भेजी।



भारत - श्रीलंका आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, 26 सितंबर 2020

पाकिस्तान

पाकिस्तानी बलों द्वारा 2020 में किए गए 5000 से अधिक अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन में 22 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं और 71 निर्दोष नागरिक घायल हुए हैं। यह पाकिस्तान की ओर से 2003 से जारी संघर्ष विराम उल्लंघन के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा युद्धविराम उल्लंघन हैं, जो जम्मू-कश्मीर में सीमा पार आतंकवादी घुसपैठ का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए असफल प्रयासों का संकेत देते हैं। जम्मू और कश्मीर से परे अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास सुरंगों के जरिए घुसपैठ की गई और हथियारों को पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग कर सीमा पार आतंकवाद, हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी का पता चला है।

परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के अंतर्गत, भारत और पाकिस्तान ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से 01 जनवरी 2021 को शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और इकाइयों की सूची का आदान-प्रदान किया। दोनों देशों के बीच इस तरह की सूची का यह लगातार तीसवां आदान-प्रदान था।

धार्मिक तीर्थयात्रा

कोविड-19 प्रतिबंधों के बावजूद, सरकार ने गुरु नानक देव जी की 551 वीं जयंती के अवसर पर, नवंबर-दिसंबर 2020 में गुरुद्वारा जनम अस्थान, ननकाना साहिब में सीमित संख्या में सिक्ख जत्थों की यात्रा की सुविधा प्रदान की। दिसंबर 2020 में शादानी दरबार द्वारा हिंदू तीर्थयात्रियों के पाकिस्तान जाने की व्यवस्था की गई।

श्री लंका

भारत की “पड़ोसी पहले” नीति और एसएजीएआर (पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा और विकास) सिद्धांत ने एक प्रमुख समुद्री साझेदार और करीबी पड़ोसी श्रीलंका के साथ भारत के संबंधों को और अधिक मजबूत किया है। कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को आभासी बातचीत सहित नवीन समाधानों से दूर किया गया। 26 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बीच आयोजित एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों

कैदियों और मछुआरों के मानवीय मुद्दे

सरकार पाकिस्तान की हिरासत में बंद कैदियों के मुद्दे को उच्च महत्व देती है और उनकी जल्द रिहाई और भारत प्रत्यावर्तन के मामले को लगातार उठाती रहती है। राजनयिक पहुंच पर 2008 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत के अनुसार, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को एक दूसरे की हिरासत में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया गया। 01 जनवरी 2021 को आदान-प्रदान की गई सूचियों के अनुसार, पाकिस्तान के 263 नागरिक कैदी और 77 मछुआरे भारत की हिरासत में हैं। पाकिस्तान ने 49 नागरिक कैदियों और 270 मछुआरों के अपनी हिरासत में होने की बात स्वीकारी है, जो भारतीय हैं या भारतीय समझे जाते हैं।

लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत 2014 से पाकिस्तान की हिरासत से मछुआरों सहित 2144 से अधिक भारतीयों की रिहाई और प्रत्यावर्तन कराने में सफल रहा है। इसमें 2019 में लौटे 364 भारतीय और 2020 में लौटे 30 भारतीय शामिल हैं। भारत ने शीघ्र राजनयिक पहुंच और पाकिस्तान की हिरासत में शेष भारतीय नागरिकों की रिहाई और प्रत्यावर्तन की मांग की है।

सरकार ने कोविड-19 प्रेरित सीमा प्रतिबंधों के कारण सीमा के दोनों ओर फँसे पाकिस्तानी और भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा भी दी। मार्च 2020 से, 1400 से अधिक भारतीय नागरिकों और पाकिस्तान से दीर्घकालिक वीजा धारकों (एनओआरआई वीजा) को भारत में वापस लाया गया है और भारत में फँसे 1250 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान वापस भेजा गया।

के सभी प्रमुख पहलुओं में प्रगति की समीक्षा की गई। भारत ने श्रीलंका की आवश्यकताओं के अनुसार, कोविड-19 पर प्रतिक्रिया, व्यापार और निवेश, रक्षा, विकास सहयोग और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में श्रीलंका को अपनी सहायता जारी रखी। श्रीलंका में अगस्त 2020 के संसदीय चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री ने, कोविड-19 महामारी के बीच 26 सितंबर 2020 को, चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री, महिंदा राजपक्षे के साथ एक

आभासी द्विपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मामलों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की और सामान्य चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों के संबंधों के लिए साझा दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए मिलवा मग्गा (दोस्ती का पथ) नामक एक संयुक्त वक्तव्य, इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के अनुदान की घोषणा की।

अन्य उच्च-स्तरीय बातचीत में मई, 2020 में राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से प्रधानमंत्री मोदी की टेलीफोन वार्ता, अगस्त 2020 में विदेश मंत्री की उनके श्रीलंकाई समकक्ष दिनेश गुणावर्धने से टेलीफोन वार्ता और 17 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएँ देने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का टेलीफोन कॉल शामिल हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने 27-28 नवंबर को कोलंबो में समुद्री सुरक्षा एनएसए द्विपक्षीय बैठक के लिए श्रीलंका का दौरा किया।

विदेश मंत्री ने, वर्ष की अपनी पहली विदेश यात्रा में, अपने श्रीलंकाई समकक्ष दिनेश गुणावर्धने के निमंत्रण पर 5-7 जनवरी 2021 तक कोलंबो का दौरा किया। यात्रा के समय, विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और विपक्ष के नेता सजीथ प्रेमदासा और पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे सहित कई अन्य गणमान्य लोगों से भेंट की। उन्होंने यात्रा के दौरान श्रीलंका के औद्योगिक नेताओं के साथ व्यापारिक बातचीत भी की।

विदेश मंत्री ने यह संदेश दोहराया कि भारत एक विश्वसनीय मित्र और भरोसेमंद साझेदार था, जो आपसी विश्वास, आपसी हित, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भी उत्सुक है। उन्होंने श्रीलंका में भारत सरकार की विकास परियोजनाओं के सकारात्मक प्रभाव और इस संबंध को आगे ले जाने की भारत की इच्छा पर भी प्रकाश डाला। इस तनाव से सुलह के मुद्दे पर भारत की अच्छी तरह से ज्ञात और सुसंगत स्थिति को रेखांकित किया गया था कि एक एकजुट श्रीलंका में तमिल लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना उनके अपने हित में था। इस संदर्भ में, सभी पक्षों के साथ व्यापक बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और तेरहवें संशोधन के कार्यान्वयन सहित शक्तियों के एक सार्थक विचलन के लिए अपनी पूर्व प्रतिबद्धताओं पर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

प्रांतीय परिषदों की प्रणाली को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया। इसके अलावा, अपने श्रीलंकाई समकक्ष के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी में भी बिम्स्टेक में श्रीलंका की नेतृत्वकारी भूमिका की सराहना की गई।

मत्स्य पालन पर सचिव स्तर के भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक आभासी मोड के माध्यम से 30 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। भारतीय पक्ष का नेतृत्व मत्स्य विभाग के सचिव द्वारा किया गया था और श्रीलंकाई पक्ष का नेतृत्व उनके समकक्ष आर.एम.आई. रथनायके ने किया। बैठक में तमिलनाडु और पुडुचेरी की सरकारों, भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक सहित दोनों पक्षों के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। बैठक में उन सभी मुद्दों को शामिल किया गया जो वर्षों से द्विपक्षीय एजेंडे पर हैं। भारतीय पक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि मछुआरों और उनकी आजीविका से संबंधित मुद्दों से पिछली समझ के साथ मानवीय तरीके से निपटा जाना चाहिए था।

कोविड सहयोग

भारत और श्रीलंका ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से लड़ने के लिए परस्पर हाथ मिलाया। भारत ने श्रीलंका को कुल आवश्यक 25 टन से अधिक आवश्यक दवाओं/चिकित्सा दस्ताने और अन्य वस्तुओं की चार खेपें उपहार में दीं। राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने भारत द्वारा 15 मार्च 2020 को आयोजित कोविड-19 का मुकाबला करने पर सार्क नेताओं के वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सार्क कोविड इमरजेंसी फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया था, श्रीलंका ने इसमें 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का वादा किया था। भारत और श्रीलंका दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र से अपने फँसे हुए नागरिकों का सुचारू रूप से प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करने में भी निकटता से समन्वय किया। वंदे भारत मिशन 11 उड़ानों के अंतर्गत, एक जहाज (आईएनएस जलाश्व) और कई चार्टर्ड उड़ानों से श्रीलंका में फँसे हुए लगभग 3500 भारतीयों को भारत वापस लाया गया है। भारतीय अधिकारियों द्वारा विभिन्न भारतीय शहरों में फँसे कई सौ नागरिकों के श्रीलंका प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की गई थी।

जनवरी 2021 में, भारत ने श्रीलंका को अनुदान सहायता के रूप में कोविशिल्ड वैक्सीन की 500,000 खुराकें भेजीं।



विदेश मंत्री ने 06 जनवरी 2021 को, कोलंबो में अपने समकक्ष श्रीलंका के विदेश मंत्री, दिनेश गुणवर्धने से भेंट की

विकास सहयोग

विकास सहयोग भारत-श्रीलंका संबंध के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना किसी भी देश में भारत की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है, जिसमें भारत ने श्रीलंका में 60,000 से अधिक घरों का निर्माण किया है। इस प्रतिबद्धता में से, लगभग 49,112 घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा, भारत ने श्रीलंका में कई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (एचआईसीडीपी) शुरू कीं। जाफना सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण पूरा हो गया है। पल्लेकेले में कांडियन नृत्य संकाय के लिए इमारतों का निर्माण, पुसलेवा में सरस्वती सेंट्रल कॉलेज का उन्नयन, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हस्टन में उपकरण और वाहनों का निर्माण/आपूर्ति और वितरण, दंबुल्ला में 5000 मीट्रिक टन तापमान नियंत्रित गोदाम का निर्माण, उत्तरी प्रांत के 27 स्कूलों का नवीनीकरण और ग्राम शक्ति हाउसिंग प्रोजेक्ट आदि के अंतर्गत 2400 घरों का निर्माण कार्य जैसी कई अन्य परियोजनाएं प्रगति पर हैं। भारत और श्रीलंका ने 2020 - 25 की अवधि के लिए एचआईसीडीपी के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन को भी अंतिम रूप दिया।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश लगातार बढ़ता रहा है। भारत 2019 में द्विपक्षीय व्यापार में श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसकी कुल राशि 4.59 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जिसमें भारत से श्रीलंका को होने वाला निर्यात 3.83 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि भारत में आयात 0.76 बिलियन अमरीकी डॉलर का था। भारत 2019 में 1.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के संचयी निवेश के साथ श्रीलंका में प्रमुख विदेशी निवेशकों में से एक है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 07 मई 2020 को श्रीलंका में भारतीय आईटी फर्म एचसीएल के पहले विकास केंद्र का उद्घाटन किया। वर्ष 2019 में 3,55,000 से अधिक भारतीय पर्यटकों के साथ भारत, श्रीलंका में पर्यटकों की आमद का शीर्ष स्रोत रहा। कोविड-19 आर्थिक सुधार और विकास के बाद दोनों देशों के व्यापार मंडलों के बीच कई ऑनलाइन चर्चाएं आयोजित की गई थीं।

रक्षा सहयोग

रक्षा सहयोग के अंतर्गत, भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लीनेक्स का आठवां संस्करण 19-21 अक्टूबर 2020 से आयोजित किया गया था। 27 अगस्त 2020 को कोविड-19 प्रबंधन पर भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना के बीच एक आभासी विशेषज्ञ स्तर की बातचीत का आयोजन किया गया था। सितंबर 2020 में श्रीलंका के तट से जहाज एमटी न्यू डायमंड पर जहाज में आग लगने और संभावित तेल रिसाव को रोकने में अपने श्रीलंकाई समकक्षों की सहायता के लिए ऑपरेशन सागर अरक्षा के अंतर्गत भारतीय नौसेना और तट रक्षक रवाना हुए।

संस्कृति के क्षेत्र में, श्रीलंका के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शैलेन्द्र सिल्वा के नेतृत्व में सेना मुख्यालय में छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त पालन के अंतर्गत आयोजित इस समारोह में कई सेना इकाइयों की ऑनलाइन भागीदारी भी देखी गई। श्रीलंका में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती और रवींद्रनाथ टैगोर की 159 वीं जयंती मनाई गई।

आभासी द्विपक्षीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा श्रीलंका को घोषित 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से बौद्ध धर्म के क्षेत्र में निर्माण/नवीकरण के माध्यम से दोनों देशों के लोगों को जोड़ने, क्षमता विकास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पुरातात्विक सहयोग, बुद्ध के अवशेष, बौद्ध विद्वानों और पुजारियों की संबद्धता को मजबूत करने से लोगों के का पारस्परिक संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने में की आशा है।

स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी), कोलंबो ने बौद्ध धर्म में श्रद्धेय माने जाने वाले "पोया" (पूर्णिमा) के दिनों को चिह्नित करने के लिए कई आयोजन किए, जिसमें "वैश्विक कल्याण के लिए धम्म" विषय पर श्रीलंका और भारत के बौद्ध विद्वानों का एक वेबिनार (जुलाई 2020) और एक ऑनलाइन कार्यशाला "बौद्ध विरासत प्रबंधन और संरक्षण: पहाड़ से महासागर तक" (अगस्त 2020) भी शामिल है।

इस अवधि में ई-भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ईएलटीईसी) कार्यक्रम के अंतर्गत 28 श्रीलंकाइयों ने क्षमता निर्माण का लाभ उठाया।

2

हिंद महासागर क्षेत्र

कोमोरोस

भारत और कोमोरोस के बीच मैत्री और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। अक्टूबर 2019 में भारत के उपराष्ट्रपति की कोमोरोस यात्रा से इस संबंध को एक मजबूत गति मिली, इस यात्रा के समय दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2020 में, भारत-कोमोरोस द्विपक्षीय संबंधों में और तेजी आई। 25 अप्रैल 2020 को विदेश मंत्री ने कोमोरोस के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बात की थी जिसमें कोविड संकट के खिलाफ कोमोरोस की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी। टेलीफोन वार्ता के दौरान कोमोरियन पक्ष से किए गए चिकित्सा सहायता के अनुरोध के जवाब में, कोमोरोस में डेंगू के प्रसार के खिलाफ उसकी लड़ाई में भारत के समर्थन के रूप में 14-सदस्यीय भारतीय

चिकित्सा सहायता दल ने 1 से 18 जून, 2020 तक कोमोरोस का दौरा किया। चिकित्सा दल ने इस यात्रा के दौरान कोमोरोस अंजुआन, मोहेली और ग्रैंड कोमोर के तीन द्वीपों का दौरा किया और कोमोरियन स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ डेंगू और कोविड-19 रोगियों के निदान और उपचार के लिए शिविरों का आयोजन किया। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई के समर्थन में भारत द्वारा कोमोरोस को दवाओं की एक खेप दान में दी गई थी जिसमें अन्य दवाओं के साथ हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन भी शामिल था। इस वर्ष, कोविड-19 महामारी के कारण 21 जून, 2020 को मोरोनी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन मंच के माध्यम से मनाया गया।

मेडागास्कर

भारत और मेडागास्कर सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का आनंद लेते हैं। मार्च 2018 में राष्ट्रपति की मेडागास्कर की यात्रा के दौरान, रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे वर्ष 2020-21 में द्विपक्षीय संबंधों को और गति मिली।

कोविड-19 महामारी से निपटने में सहायता के अनुरोधों का जवाब देते हुए, भारत सरकार ने मेडागास्कर को मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान की। इसमें एचसीक्यू की 100,000 गोलियों और एज़िथ्रोमाइसिन की 43,950 गोलियों की आपूर्ति शामिल थी।



आईएनएस ऐरावत ने ऑपरेशन वेनिला के अंतर्गत एंटिसिरनाना बंदरगाह का दौरा किया

आईएनएस ऐरावत ने 'ऑपरेशन वेनिला' के अंतर्गत एंटिसिरनाना बंदरगाह का दौरा किया और 01 फरवरी 2020 को मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए भारत से राहत सामग्री पहुंचाई। आईएनएस शार्दुल ने 10-14 मार्च 2020 तक एंटिसिरनाना बंदरगाह का दौरा किया, जिसने मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में भारी बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए मेडागास्कर को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) के रूप में 600 टन चावल पहुंचाया। आईएनएस केसरी ने 26-28 मई 2020 तक एंटिसिरनाना बंदरगाह का दौरा किया, जिसके द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए मालागासी की ओर से प्राप्त अनुरोध के अनुसार दवाइयों की खपत पहुंचाई गई।

मिशन द्वारा 21 जून 2020 को छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

मॉरीशस

भारत और मॉरीशस का एक अनूठा संबंध साझा करते हैं जो एक ओर रणनीतिक, विश्वसनीय और समय-परीक्षित है, और दूसरी ओर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रिश्तेदारी के संबंधों पर आधारित है। नेतृत्व और लोगों के बीच मजबूत संबंधों और घनिष्ठ जुड़ाव से यह रिश्ता और मजबूत हुआ है। मॉरीशस के साथ भारत के जुड़ाव के प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लोक उन्मुख विकास साझेदारी सहयोग, रक्षा और समुद्री सहयोग, व्यापार और वाणिज्यिक संबंध, छात्रवृत्ति और आईटीईसी कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण आदि शामिल हैं, जिनसे बहुआयामी संबंध विकसित हुए हैं।

मॉरीशस के साथ भारत के संबंध 2020 में और मजबूत हुए हैं। भारत मॉरीशस के लिए पहले प्रतिक्रिया देने वाले देशों में से एक था, जिसमें मॉरीशस के लिए 14 टन कोविड से संबंधित आवश्यक दवाएं उपलब्ध थीं, जिसमें एचसीक्यू की 500,000 गोलिएं और आयुर्वेदिक दवाओं की एक विशेष खपत भेजना शामिल था। मिशन सागर के हिस्से के रूप में, मॉरीशस में चिकित्सा सहायता टीमों को तैनात किया गया था, जो कोविड की आपात स्थितियों से निपटने में

अंतानानारिवो में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अलावा मालागासी समुदाय का भागीदारी में सराहनीय वृद्धि हुई। मालागासी प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नत्से द्वारा दूतावास भवन में 8 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन के साथ महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाई गई।

फरवरी 2020 में भारत से मेडागास्कर में नवीकरणीय ऊर्जा के आयात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा लिसे जीन जोसेफ रेबेरिवलो के हाई स्कूल के छात्रों को 150 सौर लैंप दान किए गए थे। मेडागास्कर सरकार को अनुदान के रूप में दी गई 100,000 एनसीईआरटी पुस्तकें 2019 में मेडागास्कर पहुंची और 14 जनवरी 2020 को सरकारी अधिकारियों को सौंप दी गईं।

वहाँ की सरकार की मदद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने 23 मई को मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ के साथ टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री जुगनाथ ने 'ऑपरेशन सागर' के हिस्से के रूप में मॉरीशस को भारतीय नौसेना जहाज 'केसरी' भेजने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने मॉरीशस द्वारा आरंभ की गई प्रभावी कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए अपनी सराहना व्यक्त की।

कोविड-19 संकट के दौरान, मॉरीशस और भारत की सरकारों ने एक-दूसरे के देशों से अपने नागरिकों के प्रत्यावर्तन में सहायता प्रदान करने में एक-दूसरे का सहयोग किया। दोनों सरकारों ने वंदे-भारत मिशन के हिस्से के रूप में अपने राष्ट्रीय वायुयान संचालकों को सभी तरह की सहायता दी

मॉरीशस में स्थित भारत के उच्चायोग ने मॉरीशस के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को चिह्नित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री



प्रधानमंत्री मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने 30 जुलाई 2020 को संयुक्त रूप से मॉरीशस के नए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया

ने उच्चायुक्त के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के संदर्भ में, 22 जून 2020 को गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को, मॉरीशस सरकार के 4 मंत्री: स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री, कैलाश कुमार सिंह जगपाल; तत्कालीन पर्यटन मंत्री, जॉर्जस पियरे लेसोंगार्ड; युवा सशक्तिकरण, खेल और मनोरंजन मंत्रालय, जीन क्रिस्टोफ़ स्टीफ़न टूसेंट; और कला और संस्कृति मंत्री, अविनाश तेलेक ने विशेष वीडियो संदेश साझा किये जिसमें योग के लाभों के बारे में बात की गई थी।

25 जुलाई 2020 को मॉरीशस के दक्षिण-पूर्व में जापानी थोक वाहक जहाज, एमवी वाकाशियो से समुद्र में तेल फैलने के बाद, भारत संकट के दौरान पहले उत्तरदाताओं में से एक था। तेल रिसाव के कारण पर्यावरण संकट से निपटने में सहायता के लिए मॉरीशस सरकार के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने 30 टन के विशेष तकनीकी उपकरण और 10-सदस्यीय तकनीकी प्रतिक्रिया दल भेजा, जिसमें तेल फैलने पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के जवान शामिल थे। भारत सरकार ने मॉरीशस के लिए दो चरणों में : 24-30 अगस्त 2020 तक; और 4-6 सितंबर 2020 तक एक गोताखोरी सहायता पोत 'आईएनएस निरक्षक' तैनात किया। जहाज में पानी के नीचे सहायता के लिए 30 से अधिक गोताखोरी के विशेषज्ञ थे।

सेशेल्स

भारत और सेशेल्स ने पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। सेशेल्स अपने विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकता के लक्ष्यों को पूरा करने में भारत को वरीयता के भागीदार के रूप में देखता है। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में विकासवात्मक साझेदारी, रक्षा सहयोग, छात्रवृत्ति और आईटीईसी कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता निर्माण, सांस्कृतिक सहयोग आदि शामिल हैं। भारत ने सेशेल्स की राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में उसकी मदद करने में सहयोग करके सेशेल्स में अपनी विकास सहायता के दायरे और प्रसार का विस्तार किया है।

मॉरीशस में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ ने मॉरीशस और भारत के उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। उस दिन, मॉरीशस के उप प्रधानमंत्री, लीला देवी लुचूमन डुकुन और कला और संस्कृति मंत्री, अविनाश तेलेक ने मॉरीशस में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाई। इससे पहले, गांधीजी के 150 वर्ष के समारोहों के एक भाग के रूप में, 12 सितंबर 2020 को उच्चायोग के सहयोग से युवा सशक्तिकरण, खेल और मनोरंजन मंत्रालय मॉरीशस द्वारा एक साइक्लिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। युवा सशक्तिकरण, खेल और मनोरंजन मंत्री, जीन क्रिस्टोफ़ स्टीफ़न टूसेंट और सार्वजनिक सेवा, प्रशासनिक और संस्थागत सुधार के मंत्री, श्री तीरथराज हर्डिल ने लगभग 400 स्थानीय साइकिल चालकों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया।

मॉरीशस और भारत सरकार के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में मौजूदा समझौता ज्ञापन को 24 अक्टूबर 2020 को आपसी समझौते से पाँच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।

विदेशमंत्री ने 27 और 28 नवंबर 2020 को सेशेल्स का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने राष्ट्रपति वेवल रामकलावन से भेंट की। विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष सेशेल्स के विदेश मामलों और पर्यटन मंत्री, सिल्वेस्ट्र राडेगोंडे से भी बात की।

सेशेल्स के साथ भारत के संबंधों ने 2020 में, लोग उन्मुख और मांग संचालित परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से और गति प्राप्त की। सेशेल्स भारत की कोविड-19 सहायता का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी बन गया और

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जीवन रक्षक दवाएं प्राप्त करने वाले पहले कुछ देशों में से एक था। 15 अप्रैल 2020 को, नई दिल्ली से एयर इंडिया की एक चार्टर्ड उड़ान से 4 टन जीवन रक्षक दवा की पहली खेप पहुंची। ऐसी ही दूसरी खेप 07 जून 2020 को मिशन सागर के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज केसरी से पहुंची थी। कोविड-19 संकट के दौरान, सेशेल्स

और भारत की सरकारों ने एक-दूसरे के देशों से अपने नागरिकों के प्रत्यावर्तन में सहायता प्रदान करने में एक-दूसरे का सहयोग किया।

जनवरी 2021 में कोविशिल्ड वैक्सीन की 50,000 खुराकें सेशेल्स को अनुदान सहायता के रूप में भेजी गई थीं।



विदेश मंत्री 27 नवंबर 2020 को विकटोरिया में सेशेल्स के विदेश मंत्री से मिले

विकासात्मक सहयोग

सेशेल्स के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक रहा है। इस अवधि में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के अंतर्गत 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। सात और परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और उन्हें औपचारिक रूप से सौंपने का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा 07 सितंबर 2020 को अन्य 5 परियोजनाएं के लिए अनुबंध हस्ताक्षर किए गए थे। 02 सितंबर 2020 को मंत्रालय से अनुदान सहायता के साथ सेशेल्स औपचारिक रूप से ई-विद्या भारती और ई-अरोग्य भारती (टेलीमेडिसिन और टेली-शिक्षा) परियोजना में शामिल हो गए।

उच्चायोग में उच्चस्तरीय सहभागिता के साथ 20 जून को छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जून के महीने में राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल एसबीसी पर विभिन्न प्रकार के योगों पर छह भाग की श्रृंखला का प्रसारण किया गया। सेशेल्स नेशनल पार्क अथॉरिटी के साथ साझेदारी में उच्चायोग ने 05 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस को चिह्नित करने के लिए स्थानिक पॉम 'नेप्रोस्पेर्मा वनहॉटेना' लगाया। महात्मा गांधी की 151 वीं जयंती को सेशेल्स विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में एक फोटो प्रदर्शनी, एक पेंटिंग, एक निबंध प्रतियोगिता और महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों पर एक संगोष्ठी का आयोजन करके मनाया गया।

3

दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया

एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब हमारे भारत-प्रशांत (आईपी) दृष्टिकोण और इसके तार्किक बहिर्वेशन में एक केंद्रीय तत्व है। भारत, भारत-प्रशांत के साथ मजबूत सह, समुद्री और हवाई संपर्क, डिजिटल-लिंक के माध्यम से हमारी साझेदारी को मजबूत करने के लिए अध्ययन, अनुसंधान, व्यापार और पर्यटन के लिए लोगों की अधिक आवाजाही को, कृषि, विज्ञान, अनुसंधान, आईसीटी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और भागीदारी के माध्यम से प्रोत्साहित करता है।

भारतीय व्यापार संवर्धन निकायों ने एक महामारी की स्थिति में नए अवसरों का पता लगाने के लिए आभासी सम्मेलनों और व्यापार-से-व्यापार बैठकों की एक श्रृंखला के आयोजन में अपने आसियान देशों के समकक्षों के साथ भागीदारी की। भारत ने महत्वपूर्ण स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और विविधता लाने के लिए बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय तंत्र का इस्तेमाल किया, जबकि कोविड-19 दवाओं और भारत-प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए सुरक्षात्मक उपकरण/सामग्री की आपूर्ति करके 'विश्व की फार्मसी' का नाम कमाया।

हमारा प्रयास दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की साझेदारियों और भारतीय संस्कृति की आधुनिक अभिव्यक्तियों के साथ भारत के साझेदारों को इस क्षेत्र में विरासती सांस्कृतिक स्थलों की पुनर्स्थापना और जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के माध्यम से (कंबोडिया में ता प्रोम मंदिर, लाओस में वात फो

मंदिर और वियतनाम में माई सन स्मारक) इनसे परिचित कराना है। जकार्ता स्थित चिंतक संस्था "आसियान और पूर्वी एशिया के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान (ईआरआईए)" को मार्च 2019 में भारत-म्यांमार-थाईलैंड लिपक्षीय राजमार्ग और लाओ पीडीआरआर, कंबोडिया, वियतनाम तक इसके संभावित पूर्वी विस्तार: चुनौतियां और अवसर' पर अध्ययन का कार्य सौंपा गया। ईआरआईए ने जुलाई 2020 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रक्षा सहयोग

नियमित उच्च-स्तरीय यात्राओं, कर्मचारियों की वार्ता, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर और वियतनामी सशस्त्र बलों के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर के रियायती ऋण के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। 2020 में पापुआ न्यू गिनी में भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग (एफआईपीआईसी) का तीसरा फोरम आयोजित करने के भारत के प्रयास कोविड-19 के कारण सफल नहीं हो सके। भारत ने सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा व अन्य बातों के साथ जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए 'भारत-यूएनडीपी फंड के अंतर्गत विकास सहायता और कोविड-19 सहायता' प्रदान करने का प्रयास किया। दक्षिणी और ओशिनिया डिवीजनों के अंतर्गत भारत के सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध नीचे चर्चा की गई है।

ऑस्ट्रेलिया

वर्ष 2020-21 द्विपक्षीय संबंधों में एक निर्णायक वर्ष था, क्योंकि दोनों देश रक्षा, समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, जल संसाधन, स्वच्छ ऊर्जा, आरएंडडी, कौशल और शासन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा बनाने के लिए सहमत हुए। 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की भारत की निर्धारित यात्रा दो बार- पहली बार जनवरी 2020 में ऑस्ट्रेलिया में अभूतपूर्व रूप से लगी जंगल की आग के कारण और फिर मई 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 4 जून 2020 को

द्विपक्षीय आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि दोनों राष्ट्र 2009 में सामरिक भागीदारी को लागू करने के 11 वर्ष बाद, अपने रिश्ते को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी (सीएसपी) के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हुए। सीएसपी को आगे बढ़ाने के लिए, दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने कम से कम हर दो वर्ष में रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए '2+2' प्रारूप में मिलने पर सहमति व्यक्त की। ऑस्ट्रेलिया के साथ, पहले से ही भारत के 2 + 2 विदेशी और रक्षा सचिव संवाद स्थापित हैं।



भारत- ऑस्ट्रेलिया आभासी शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया गया

प्रधानमंत्री-स्तरीय शिखर सम्मेलन ने “व्यापक सामरिक साझेदारी” और “भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण पर संयुक्त घोषणा” पर ऐतिहासिक संयुक्त वक्तव्य के अलावा, ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करने के लिए सात महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों/समझौतों को पूरा किया। इसमें (i) सहमत लॉजिस्टिक्स सपोर्ट से संबंधित व्यवस्था (एमएलएसए); (ii) साइबर और साइबर-सक्षम क्रिटिकल प्रौद्योगिकी सहयोग पर ढांचा व्यवस्था, (iii) महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनन और प्रसंस्करण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; (iv) रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन के लिए रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) में सहयोग के संबंध में व्यवस्था लागू करना; (v) लोक प्रशासन और शासन सुधार में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; (vi) व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन; और (vii) जल संसाधन प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन शामिल है।

कोविड-19 के कारण आई बाधाओं के बावजूद, उच्च-स्तरीय संबंध पूरे वर्ष जारी रहे। कोविड-19 के कारण बाधाओं के बावजूद, उच्च-स्तरीय सगाई पूरे वर्ष जारी रही। 6 अप्रैल 2020 को, प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने चल रही महामारी और अपने संबंधित सरकारों द्वारा अपनाई गई घरेलू प्रतिक्रिया की रणनीतियों पर चर्चा

की। 8 अप्रैल 2020 को, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिज पायने का भारत के विदेश मंत्री के साथ एक टेलीकॉन्फ्रेंस हुआ था। दोनों विदेश मंत्रियों ने 06-07 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया-भारत-जापान-अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भेंट की। दोनों मंत्रियों ने क्लाइ बैठक के मौके पर द्विपक्षीय वार्ता भी की। कोविड-19 से पहले, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने ने जनवरी 2020 में रायसीना वार्ता में भाग लिया और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा बैठक भी की।

द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव का बढ़ना जारी रहा। भारतीय नौसेना ने 23 और 24 सितंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ एक मार्ग अभ्यास (पासेक्स) का आयोजन किया। अक्टूबर 2020 में भारत के निमंत्रण पर, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने विशाखापत्तनम से दूर बंगाल की खाड़ी में 3-6 नवंबर 2020 तक मालाबार एक्सरसाइज-2020 के प्रथम चरण में भाग लिया। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए 26 मई 2020 को एक टेलीकॉन्फ्रेंस आयोजित की। दोनों देशों ने 10 सितंबर 2020 को आभासी प्रारूपके माध्यम से वरिष्ठ आधिकारिक स्तर की रक्षा नीति वार्ता भी आयोजित की।



06 अक्टूबर 2020 को टोक्यो में अन्य क्लाइ विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्री

आतंकवाद निरोध पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की बारहवीं बैठक 17 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कृषि में सहयोग पर पाँचवीं जेडब्ल्यूजी बैठक 03 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी।

व्यापारिक संबंधों में वृद्धि को देखते हुए, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर फिर से जुड़ने का फैसला किया। 30 जुलाई 2020 को, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने सीईसीए और व्यापार से संबंधित अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंघम के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की। दोनों पक्ष सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने फैसला किया कि दोनों देशों के प्रमुख उद्योगों को दूसरे देश के एसएमई/एमएसएमई को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में विविधता आए। 01 सितंबर 2020 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री साइमन बर्मिंघम और जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री, काजीयामा हिरोशी के साथ एक आपूर्ति श्रृंखला लचीला पहल (एससीआरआई) के शुभारंभ पर चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय मंत्रीस्तरीय वार्ता आयोजित की। 11 सितंबर 2020 को, केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री, खान मंत्री और कोयला मंत्री ने कीथ पिट, संसाधन मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आभासी बैठक की।

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, 05 नवंबर 2020 को आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड-टेबल 2020 में ऑस्ट्रेलियाई सुपरनेचुरल फंड्स स्कॉट मॉरिसन ने भागीदारी की, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2020 को बेंगलुरु टेक समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया गया था।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनेरल्स के खनन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक 26 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने भारत सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम, खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिज सुविधा कार्यालय (सीएमएफओ) के

बीच सहयोग के लिए अंतर तंत्र और रोडमैप पर सहमति व्यक्त की थी। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 26 नवंबर 2020 को आयोजित की गई थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 18 दिसंबर 2020 को सीआईआई ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति का शुभारंभ किया। आभासी बैठक को ऑस्ट्रेलियाई व्यापार मंत्री साइमन बर्मिंघम ने भी संबोधित किया। रिपोर्ट में 2018 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी भारत आर्थिक रणनीति 2035 में भारतीय उद्योग की प्रतिक्रिया को शामिल किया गया कर लिया। यह रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में व्यापार के माहौल, बाजार के अवसरों और निवेश क्षमता का अवलोकन प्रदान करती है और विभिन्न कार्यान्वयन रणनीतियों और कार्रवाई बिंदुओं के रूप में भविष्य के सहयोग के लिए एक टेम्पलेट भी देती है।

ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया। इसने 2021-22 के कार्यकाल के लिए एक अस्थायी यूएनएससी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के लिए अपना ‘मजबूत समर्थन’ भी दोहराया है। बहुपक्षीय मंचों में सहकारी रूप से काम करने के लिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेशी कार्यालयों ने 17 अगस्त 2020 को आभासी प्रारूप के माध्यम से बहुपक्षीय मुद्दों पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर के परामर्श की शुरुआत की।

भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय, चतुर्पक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूपों में भी संलग्न है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ एक नए वार्षिक द्विपक्षीय तंत्र की स्थापना हुई। एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम-आधारित भारत-प्रशांत सुनिश्चित करने के लिए अपनी-अपनी शक्तियों के समन्वय के लिए विदेश सचिव स्तर के भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय वार्ता का उद्घाटन सत्र 09 सितंबर 2020 को आभासी रूप से आयोजित किया गया था। मौजूदा भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया द्विपक्षीय वार्ता के स्तर को आधिकारिक से मंत्री स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। विदेश सचिव ने 20 मार्च 2020 और



15 मई 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, वियतनाम और अमेरिका के अपने समकक्षों के साथ कोविड-19 पर नियमित साप्ताहिक इंडो-पैसिफिक समन्वय वार्ता आयोजित की। 11 मई 2020 को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजरायल और कोरिया के विदेश मंत्रियों के बीच एक वीडियो-सम्मेलन हुआ, जिसमें कोविड-19 का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्व और इसके कारणों को संबोधित करने पर चर्चा हुई।

ऑस्ट्रेलिया भारत द्वारा समर्थित भारत-प्रशांत महासागरीय पहल के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, साथ ही आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोध पर गठबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) जैसे विभिन्न बहुपक्षीय ढांचों में भी शामिल है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय की लगभग 7 लाख की आबादी (कुल जनसंख्या का 2.8%) के साथ आकार और महत्व में वृद्धि जारी है। ऑस्ट्रेलिया

ब्रुनेई दारुस्सलाम

द्विपक्षीय संबंध सौहार्द और मैत्रीपूर्ण बने रहे। ब्रुनेई कच्चे तेल के लगभग 22% निर्यात के साथ ब्रुनेई भारत की ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है; आसियान की इसकी सदस्यता; भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (एईपी) और भारत-प्रशांत (आईपी) अवधारणा में इसकी भागीदारी और ब्रुनेई में लगभग 10,000 भारतीय नागरिकों की उपस्थिति का बहुत महत्व है। ब्रुनेई आमतौर पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा है। ब्रुनेई ने यूएनएससी में अस्थायी सीट और हाल ही में यूएनजीए की पाँचवीं समिति में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों (एसीएबीक्यू) की सलाहकार समिति में हमारी उम्मीदवारी का समर्थन किया था। अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी) के ट्रैकिंग का समर्थन करने के लिए टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड टेलकमांड (टीटीसी) स्टेशन (इसरो द्वारा ब्रुनेई में 1998 से

कंबोडिया

भारत और कंबोडिया के बीच के द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण रहने के साथ मजबूत होते रहे। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और आसियान के संदर्भ में, कंबोडिया एक महत्वपूर्ण वार्ताकार और एक सकारात्मक और आगामी साझेदार है। 10 जून 2020 को प्रधानमंत्री और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच हुए टेलीकांफ्रेंस द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री हुन सेन ने भारत की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भूमिका और मानवीय संकेतों के साथ-साथ दुनिया के 130 देशों में दवाओं का उत्पादन और आपूर्ति करने की भारत की क्षमता के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (आईसीसी) की सह-अध्यक्षता और परेह विहार मंदिर की बहाली और विकास के लिए भारत पर विश्वास रखने के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की।

राज्य मंत्री/राज्य सचिव के स्तर पर आयोजित की जाने वाली संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) को 2020 में विदेश मंत्रियों के स्तर तक बढ़ाया गया है। रक्षा सहयोग में, डेमिंग उपकरण की खरीद के लिए रॉयल कंबोडियन



में भारतीय प्रवासी समुदाय अब सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रवासी समुदाय है। भारत 2019-20 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के शीर्ष स्रोत के रूप में उभरा। भारत ऑस्ट्रेलिया के कुशल प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत भी है। ऑस्ट्रेलिया में फँसे हुए 21,000 से अधिक भारतीयों को 47 वंदे भारत मिशन (वीबीएम) उड़ानों और 51 चार्टर्ड उड़ानों (31 अक्टूबर 2020 तक) के माध्यम से भारत वापस लाया गय

कोविड-19 संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को ऑस्ट्रेलिया-भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष (एआईएसआरएफ) के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए मंजूरी दी गई थी। विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए 1 दिसंबर 2020 को एक टेलीकांफ्रेंस की। नीति आयोग और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन ने मिलकर सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर एक हैकथॉन शुरू किया, जिसका समापन फरवरी 2021 में हुआ।



स्थापित) के उन्नयन और स्थानांतरण के प्रयास जारी हैं। इसरो की 3 सदस्यीय टीम इस समय ब्रुनेई में है। यह टीम 8 नवंबर 2021 को इसरो उपग्रह के प्रक्षेपण का समर्थन करने के लिए ब्रुनेई पहुंची थी। इसरो के टीटीसी स्टेशन के स्थानांतरण के लिए, इसरो की टीम, ब्रुनेई दारुस्सलाम सरकार द्वारा तेलेई में प्रस्तावित नई साइट की उपयुक्तता का भी आकलन करेगी।

क्षमता निर्माण में ब्रुनेई की सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता के अंतर्गत, 14 ब्रुनेई अधिकारियों ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत मानव अवस्थान प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई) द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया। साइबर सुरक्षा पर एक अन्य पाठ्यक्रम में ब्रुनेई के आंतरिक सुरक्षा विभाग के 2 ब्रुनेई अधिकारियों ने भाग लिया।



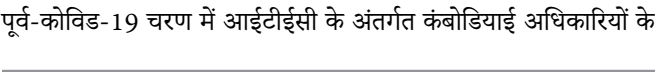
सशस्त्र बलों (आरसीएएफ) को 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता देने के समझौते पर 10 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय सेना के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा शांति कायम रखने, डीमाइनिंग मॉड्यूल में आरसीएएफ के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैम्पूल के संचालन के साथ रक्षा सहयोग जारी रहा। आरसीएएफ ने आईटीईसी के अंतर्गत भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षण प्राप्त करना जारी रखा। विकास सहयोग, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण गतिविधियां द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहीं। भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित पेयजल, मंदिरों के संरक्षण और क्षमता निर्माण के लिए कंबोडिया को अपनी सहायता जारी रखी।

कंबोडिया में ग्रामीण जल आपूर्ति के संवर्द्धन के लिए 1,500 अफ्रिडेव हैंड पंपों की आपूर्ति और स्थापना के लिएकी परियोजना, जो कि 2017 में कम्पोंग चाम और सीमावर्ती बंतेई मीनची प्रांतों में लक्षित समुदायों में सुरक्षित पेयजल प्रदान



करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी, अगस्त 2020 में डब्ल्यूएपीसीओएस द्वारा पूरा की गई। भारत सरकार द्वारा 12 मिलियन अमरीकी डॉलर की आर्थिक सहायता के साथ निष्पादित की गई इस परियोजना की दोनों प्रांतों में लाभार्थियों ने व्यापक सराहना की। 2015 में मेकांग गंगा सहयोग पहल के अंतर्गत शुरू की गई त्वरित प्रभाव परियोजना (क्यूआईपी) योजना, कंबोडिया में अच्छी तरह से आगे बढ़ी। अब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण और कौशल विकास आदि के क्षेत्रों में 19 क्यूआईपी परियोजनाएं लागू की गई हैं और 15 और परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

कोविड-19 के बावजूद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने योजना के अनुसार कार्य जारी रखा, अंगकोर वाट पार्क में ता प्रोहम मंदिर में बहाली और संरक्षण कार्य का तीसरा चरण नवंबर 2016 में शुरू हुआ था। अगस्त 2018 में, भारत के भगवान शिव के एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, प्रीह विएर के पुनरुद्धार के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, भारत, जो प्री विहेर (आईसीसी) की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति का सह-अध्यक्ष है, 5.55 मिलियन अमरीकी डॉलर की कुल लागत से, एएसआई के माध्यम से जल्द ही प्रीह विहेर मंदिर में संरक्षण और पुनरुद्धार का काम शुरू कर रहा है।



इंडोनेशिया

कोविड-19 महामारी ने इंडोनेशिया के साथ 2020-21 में समग्र सहयोग की गति को धीमा नहीं किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मार्सुडी ने 01 अप्रैल 2020 को विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सक्रिय फार्मा सामग्री (एपीआई) का आयात करना और इंडोनेशिया से भारत के लिए कार्गो का निर्बाध प्रवाह शामिल है। भारत ने क्लोरोक्वीन फॉस्फेट और ओसेल्टामिविर के एपीआई के स्थानीय विनिर्माण के लिए इंडोनेशिया को 2425 किलोग्राम एपीआई का निर्यात किया।

प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल 2020 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के साथ फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति को आश्वासन दिया कि भारत दोनों देशों के बीच बिक्री किए गए चिकित्सा उत्पादों या अन्य वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। वीबीएम के अंतर्गत, मई 2020 में, 2500 से अधिक भारतीयों को इंडोनेशिया से भारत के विभिन्न शहरों में भेजा गया था। कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से 900 से अधिक इंडोनेशियाई नागरिकों को इंडोनेशिया में वापस लाया गया था।

रक्षा सहयोग में, भारत और इंडोनेशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के साथ भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (सीओआरपीएटी) 15-16 जून 2020 को आयोजित किया गया था, पिछले 18 वर्षों में इन सीओआरपीएटी को मजबूती से निष्पादित करने के साथ मजबूत आपसी सहयोग पर निर्माण करने की मांग की गई। दोनों देश 6 जुलाई 2020 को भारतीय तटरक्षक बल और इसके इन्डोनेशियाई समकक्ष बीएकेएमएलए के बीच समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा



लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान सुचारू रूप से आगे बढ़ा। कंबोडिया में 1981 में, आईटीईसी शुरू होने के बाद से अब तक 1750 कंबोडिया वासी आईटीईसी कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए हैं। कंबोडिया द्वारा कंबोडिया सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम के आईटीईसी स्लॉट के उपयोग से गुणात्मक परिवर्तन आए। कोविड-19 के समय भी, कंबोडियाई अधिकारियों ने 2020 में आईटीईसी के अंतर्गत आयोजित कुछ ई-पाठ्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा, कंबोडियाई छात्रों के लिए हर वर्ष भारत में यूजी/पीजी और उच्च अध्ययन के लिए 25 छात्रवृत्तियाँ एमजीसी (10), जीसीएसएस (13) और सीईपी (2) के अंतर्गत उपलब्ध हैं। 2020-21 के दौरान, कम्बोडियन छात्रों द्वारा अब तक 7 स्लॉट स्वीकार किए गए हैं। राज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ने 5 अगस्त 2020 को आभासी प्रारूप में सीआईआई द्वारा आयोजित पहले इंडो-आसियान ओशनिक बिजनेस समिट एंड एक्सपो में भाग लिया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साझेदारी में, 3 -4 दिसंबर, 2020 को छठवें भारत-सीएलएमवी बिज़नेस कॉन्क्लेव: कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार और वियतनाम के साथ आभासी प्रारूप में रचनात्मक विकास के लिए पुल का निर्माण आयोजन किया।राज्य मंत्री ने आयोजन में भाग लिया औरवाणिज्य मंत्रालय के सचिव ने कॉन्क्लेव में कंबोडिया का प्रतिनिधित्व किया।



सहयोग

सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) प्रबोवो सुबियांतो ने 26-27 जुलाई 2020 को भारत का दौरा किया और रक्षा सहयोग के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने भारतीय समकक्ष रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भेंट की। वे किसी भी देश के पहले मंत्री थे जो कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में आए थे।

वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 19 बिलियन अपनीकी डॉलर था, जिसने इंडोनेशिया को आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाया। आर्थिक भागीदारी को आगे मजबूत आगे बढ़ाते हुए, 29 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीसरे भारत-इंडोनेशिया द्विवार्षिक व्यापार मंत्रियों के फोरम का आयोजन किया गया था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री और इंडोनेशियाई पक्ष का नेतृत्व व्यापार मंत्री अगुस सुपरमैन्टो ने किया था। दोनों मंत्रियों ने 2025 तक 50 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की।

एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) और बीएनएन (इंडोनेशिया नेशनल नारकोटिक्स एजेंसी) के बीच डीजी स्तर के संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 17 दिसंबर 2020 को आभासी मोड में हुई, बैठक के दौरान एनसीबी और बीएनएन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भारत और इंडोनेशिया के बीच स्वास्थ्य सहयोग पर दूसरा संयुक्त कार्य समूह लगभग 31 मार्च 2021 की अवधि तक होने वाला है, इसमें स्वास्थ्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

लाओ पीडीआर

प्रधानमंत्री ने 12 जून 2020 को, लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री थोंगलोजन सिसोउलिथ से फोन पर बात की। भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लाओ पीडीआर की लड़ाई का समर्थन करने के लिए दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति भी भेंट की। बाँकोव सिहावॉन्ग, लाओ स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र में भारत को धन्यवाद दिया। आईटीईसी के अंतर्गत, लाओस चिकित्सा सैन्य विभाग के 7 अधिकारियों ने 6-9 जुलाई 2020 से आयोजित कोविड-19 पर पहले सीएलएमवी ई-आईटीईसी रक्षा चिकित्सा पाठ्यक्रम में भाग लिया। 2020 में, भारतीय सेना प्रशिक्षण टीम ने लाओ पीडीआर में अपने 25 वर्ष पूरे किए।

लाओ-इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग

मलेशिया

भारत और मलेशिया में लोगों के आपसी संबंधों, साझा इतिहास और अच्छी तरह से स्थापित व्यापारिक संबंधों के आधार पर सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। अप्रैल-अगस्त 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण सीमाओं पर व्यापार को प्रभावित करने के बावजूद, मलेशिया 4.75 बिलियन अमरीकी डॉलर (निर्यात - अमरीकी डॉलर 2.54 बिलियन: आयात 2.21 बिलियन अमरीकी डॉलर) के कुल व्यापार के साथ भारत के लिए 12वें सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा। 2019-20 में मलेशिया भारत का 13 वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत ने 2019-20 में 3.42 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापार घाटे की तुलना में अब तक 332 मिलियन अमरीकी डॉलर (अप्रैल-अगस्त 2020) का अधिशेष व्यापार संतुलन दर्ज किया है।

विदेश मंत्री ने 13 अप्रैल 2020 को मलेशिया के विदेश मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन से टेलीफोन पर बात की। अप्रैल 2020 में, भारत ने मलेशिया के हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन सल्फेट (एसचीक्यूएस) के 1.2 मिलियन टैबलेट और 24 टन पेरासिटामोल के निर्यात के लिए मलेशिया के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। भारत ने क्लोरहेक्सिडाइन (हैंड सेनिटाइज़र) की 400,000 बोतलें, केटामाइन एचसीआई 10मिग्रा/मिली के 6000 पैक और 3-प्लाई

न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स और व्यापार और निर्यात विकास मंत्री डेविड पार्कर की एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ फरवरी 2020 के अंत में की गई यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की तीव्र इच्छा को परिलक्षित किया था। न्यूजीलैंड यात्रा की पूर्व संध्या पर, न्यूजीलैंड ने अगले पाँच वर्षों में भारत के साथ एक अधिक “स्थायी रणनीतिक संबंध” की कल्पना करते हुए एक रणनीति पत्र “भारत-न्यूजीलैंड 2025 - रिश्ते में निवेश” जारी किया। यात्रा के दौरान, उप प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री से भेंट की और द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा आयोजित ‘द इंडो पैसिफिक: प्रिंसिपल्स टू पार्टनर्स’ शीर्षक से एक मुख्य संबोधन दिया, जिसमें भारत-प्रशांत महासागर की पहल (आईपीओआई) पर भारत के नेतृत्व के

(सीईएसडीटी) वियनतियाने ने, 2019-20 में सरकारी अधिकारियों सहित लाओस के 11 विभिन्न संगठनों के 4 अलग-अलग पाठ्यक्रमों में 90 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। लाओस में त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए भारतीय अनुदान सहायता (क्यूआईपी) पर छत्र समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। उर्वरक विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए एक क्यूआईपी परियोजना पूरी की गई। प्राचीन शिव मंदिर, वात फु में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार का दूसरा चरण का दूसरा सत्र जुलाई 2020 में पूरा हुआ; जीर्णोद्धार कार्य के तीसरे सत्र के जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

डिस्पोजेबल फेस मास्क के 370,785 टुकड़ों के मलेशिया को निर्यात की अनुमति दी।

मई 2020 से, कोविड-19 और वीबीएम उड़ानों को संचालित करने के भारत के निर्णय के कारण यात्रा प्रतिबंधों के बाद, मलेशिया से अब तक 15,223 भारतीयों को प्रत्यावर्तित करते हुए 89 वीबीएम उड़ानों का संचालन किया गया है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और मलेशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने 4 दिसंबर 2020 को म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद अक्टूबर 2020 में इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 3 दिसंबर 2020 को मलेशिया द्वारा आयोजित सातवें आईईएफ-आईजीयू (इंटरनेशनल एनर्जी फोरम-इंटरनेशनल गैस यूनियन) मिनिस्ट्रियल गैस फोरम के वर्चुअल मिनिस्ट्रियल राउंडटेबल में भाग लिया।

लिए समर्थन व्यक्त किया गया। उन्होंने मजबूत समुद्री सहयोग का आह्वान किया और न्यूजीलैंड की आईएसए में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने 26 फरवरी 2020 को आईआईटी, दिल्ली में ‘न्यूजीलैंड केंद्र’ का उद्घाटन भी किया, जो न्यूजीलैंड के सभी 8 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग के नोडल बिंदु के रूप में काम करेगा। व्यापार मंत्री पार्कर ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री और अन्य से भेंट की। उन्होंने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा आयोजित भारत-न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में भी भाग लिया।

भारत और न्यूजीलैंड ने एफएस स्तर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम सहित 7 देशों के समूह के हिस्से के रूप में कोविड-19

स्थिति पर नियमित रूप से टेलीफोन पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के फँसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए बहुत निकटता से सहयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप न्यूजीलैंड के 3000 से अधिक नागरिकों और वीबीएम के अंतर्गत न्यूजीलैंड से लगभग 3700 भारत के निवासियों का प्रत्यावर्तन हुआ। 16 अप्रैल 2020 को टेलीफोन पर एक बातचीत में, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने न्यूजीलैंड के नागरिकों के प्रत्यावर्तन में सहयोग और आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति करने के आश्वासन के लिए विदेश मंत्री को धन्यवाद दिया।

अक्टूबर, 2020 में होने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री जैकिंडा अर्डन ने भारी बहुमत से अपनी लेबर पार्टी के लिए दूसरा कार्यकाल जीता। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन ने न्यूजीलैंड की सरकार में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक ट्रीट और एक औपचारिक संदेश के माध्यम से बधाई दी। सुखी टर्नर 1995 में मेयर के पद पर काबिज होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे।

6 दिसंबर, 2020 को वाटेकेरे इंडियन एसोसिएशन और भारतीय उच्चायोग ने ‘न्यूजीलैंड के भारतीयों के आर्थिक योगदान’ शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित

फिलीपींस

अक्टूबर 2019 में फिलीपींस के राष्ट्रपति के राजकीय दौरे से उत्पन्न गति को बढ़ाते हुए, 9 जून 2020 को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डुटर्टे के बीच टेलीफोन पर बातचीत के साथ नेतृत्व स्तर का आदान-प्रदान जारी रहा। राष्ट्रपति डुटर्टे ने फिलीपींस के लिए आवश्यक दवा उत्पादों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की। द्विपक्षीय सहयोग पर भारत-फिलीपींस संयुक्त आयोग की चौथी बैठक, विदेश मंत्री और फिलीपींस गणराज्य के विदेश मामलों के विभाग के सचिव टेओदोरो लोकोसीन जूनियर की सह-अध्यक्षता में 06 नवंबर 2020 को आभासी तौर पर आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने भारत-फिलीपींस द्विपक्षीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, आईसीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापार और निवेश और रक्षा क्षेत्र के सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी व्यापक संबद्धता के भविष्य के प्रक्षेपवक्र पर चर्चा की।

व्यापार और निवेश पर संयुक्त कार्य समूह की तेरहवीं बैठक 17 सितंबर 2020

सिंगापुर

संकट के मद्देनजर चुनौतियों का सामना करने के लिए कोविड-19 के दौरान भारत और सिंगापुर एक साथ खड़े रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ली हसियन लुंग के बीच 23 अप्रैल 2020 को एक टेलीकॉन का आयोजन हुआ था, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के लिए चिकित्सा उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का वादा किया था। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में भारतीय नागरिकों को दिए गए समर्थन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने 11 जुलाई को, सिंगापुर में आम चुनाव के सफल समापन पर, प्रधानमंत्री ली को बधाई दी।

की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल के लोग अब न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का योगदान करते हैं। भारतीय मूल के लगभग 2,50,000 लोग न्यूजीलैंड की आबादी का लगभग 5% योगदान करते हैं। वे मुख्य रूप से खुदरा, होटल, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, बिजनेस सपोर्ट, फाइनेंस, आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे सेक्टर में लगे हुए हैं।

कोविड-19 ने माल और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। जनवरी से जून 2020 के दौरान, भारत में न्यूजीलैंड का निर्यात 741 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर था, जबकि भारत से आयात 486 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर था। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के समारोह का समापन 02 अक्टूबर 2020 को वेलिंगटन रेलवे स्टेशन के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर वित्त मंत्री राबर्टसन, न्यूजीलैंड आनंद सत्यानंद पूर्व गवर्नर जनरल और वेलिंगटन एंडी फोस्टर के मेयर सहित गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी के साथ हुआ थी।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आभासी विदेश कार्यालय परामर्श 16 फरवरी 2021 को हुआ।

को आयोजित की गई थी। बैठक में टीका विकास में सहयोग; पीपीई और दवा उद्योग; वस्त्र; इलेक्ट्रॉनिक्स; आईसीटी और आईटी-बीपीएम; नवीकरणीय ऊर्जा; आधारिक संरचना; कृषि; पारंपरिक औषधि; ऑटोमोबाइल; सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और आपसी सहायता पर समझौता; तरजीही व्यापार डेटा आदि का साझाकरण तंत्र पर चर्चा की गई। संयुक्त रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स समिति (जेडीआईएलसी) की दूसरी बैठक 17 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। बैठक में क्षमता बढ़ाने, उन्नत प्रणालियों के हस्तांतरण और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन सहित सहयोग को मजबूत करने के लिए क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। पर्यटन सहयोग पर भारत-फिलीपींस संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 08 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी। दोनों देशों ने अक्टूबर 2020 में द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर पहले दौर की वार्ता भी की। द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के नेतृत्व के साथ, यह विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों के गहन और विविधीकरण के लिए एक रणनीतिक चरण है।

भारत ने कोविड-19 को संभालने के लिए सिंगापुर को 2.5 मिलियन एचसीक्यू गोलियों; 4.8 मिलियन सर्जिकल मास्क; 1.4 मिलियन बोटल हैंड सैनिटाइज़र; 39,750 किलोग्राम मेल्ट-ब्लोन पॉलीप्रोपाइलीन सामग्री; 25,000 किलोग्राम एसएसएमएमएस कपड़ा के निर्यात को मंजूरी दी। कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को लगाए जाने के बाद से 30 अक्टूबर 2020 तक, 209 उड़ानों में कुल 33,099 यात्रियों को वापस लाया गया। सिंगापुर के 5000 से अधिक नागरिकों और स्थायी निवासियों को भी भारत से सिंगापुर में वापस लाया गया था।

वर्ष 2020-21 (अगस्त 2020 तक) में, द्विपक्षीय व्यापार 7.2 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इसी अवधि के लिए सिंगापुर को निर्यात 3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था, इसमें 24.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि आयात 3.6 बिलियन अमरीकी डॉलर था और इसमें 45.0% की गिरावट आई। सिंगापुर में जावक भारतीय एफडीआई वित्तीय वर्ष 2020-21 में अगस्त 2020 तक 0.84 बिलियन अमरीकी डॉलर था जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह 4.39 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

थाईलैंड

आसियान, मेकांग गंगा सहयोग (एमजीसी) और बिस्स्टेक के ढांचे के भीतर सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंध 2020 में बढ़ते रहे। भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी के लिए समन्वयक देश के रूप में, थाईलैंड सक्रिय रूप से वियतनाम की अध्यक्षता में 12-15 नवंबर 2020 से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित सत्रहवें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और संबंधित बैठकों के आयोजन में लगा हुआ था। प्रधानमंत्री ने 01 मई 2020 को थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान-ओ-चा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और चिकित्सा विज्ञान और टीका विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में सहयोग के लिए सहमति व्यक्त की।

विदेश मंत्री और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, डॉन प्रमुदविनई ने 12 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की, जिसमें आसियान-भारत योजना (2021-25) को अपनाया गया था। बाइसवां आसियान-भारत एसओएम 16 जुलाई 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सचिव (पूर्व) और बुसाया मैटिलिन, थाईलैंड एमएफए के स्थायी सचिव ने की थी। आसियान-भारत नेटवर्क थिंक टैंकों (एआईएनटीटी) की छठवीं गोल मेज “आसियान-भारत: पोस्ट-कोविड-19 युग में रणनीतिक साझेदारी” का उद्घाटन 20 अगस्त 2020 को विदेश मंत्री और उप-मुख्यमंत्री डॉन प्रमुदविनई ने संयुक्त रूप से किया

इंडो-थाई कॉर्पोट का तीसवां चक्र 18-20 नवंबर 2020 तक 'केवल समुद्र में संपर्क रहित' के रूप में आयोजित किया गया था। सिंगापुर द्वारा आयोजित

तिमोर लेस्ते

संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न निकायों के चुनावों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की उनकी अभिव्यक्ति सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत के साथ टीएल के

भारत-सिंगापुर डिफेंस वर्किंग ग्रुप की तेरहवीं बैठक लगभग 30 जून 2020 को हुई। बारहवीं आईएएफ-आरएएसएफ वायु सेना स्टाफ वार्ता (एएसटी) 3 जुलाई 2020 को वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई थी। रक्षा नीति वार्ता (अगस्त 2020) और रक्षा उद्योग कार्य समूह की बैठक (अक्टूबर 2020) आयोजित की गई थी।

सेना और वायु सेना के लिए 2020 में वार्षिक अभ्यास आयोजित नहीं किए जा सके, सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (सिमबेक्स) के 27 वें संस्करण को नवंबर 2020 के लिए नो-कॉन्टैक्ट प्रारूप में आयोजित किया गया था। इसी तरह, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड (सिटमेक्स) के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का दूसरा संस्करण भी नवंबर 2020 में आयोजित किया गया था। सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री हेंग स्वे केट द्वारा द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर के माध्यम से मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर), रक्षा सहयोग को बढ़ाया गया था। मंत्री एस. ईश्वरन 03 अक्टूबर 2020 को लिटिल इंडिया में दीपावली प्रकाश समारोह में शामिल हुए थे

सिंगापुर-भारत-थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमेक्स-2020, 21-22 नवंबर 2020 से अंडमान सागर में 'केवल समुद्र में संपर्क रहित'के रूप में आयोजित किया गया था। एक्स कोबरा गोल्ड का पहला चरण फरवरी से 05 मार्च 2021 तक होना निर्धारित है। भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों को प्रेक्षक प्लस श्रेणी के अभ्यास में भाग लेना निर्धारित किया गया है। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और रॉयल थाई वायु सेना के बीच वार्षिक स्टाफ वार्ता 21 अगस्त 2020 को वीसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। भारत और थाईलैंड के बीच 17 फरवरी 2021 को कानूनी और न्यायिक सहयोग और समुद्री सहयोग पर संयुक्त कार्य बल की चौथी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित करने का प्रस्ताव है।

भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बारहवीं बैठक 4 दिसंबर 2020 को भारत के वाणिज्य मंत्रालय और थाईलैंड के संयुक्त सचिव स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। सीआईआई द्वारा 4-6 अगस्त 2020 तक इंडो-आसियान ओशनिक बिजनेस समिट और एक्सपो का आयोजन तक किया गया था। आईसीसीआर और सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय के बीच एक वर्ष के लिए आईसीसीआर के अध्यक्ष के रूप में सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 29 मई 2020 को हस्ताक्षर किए गए। अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान, थाईलैंड में फँसे कुल 3275 भारतीय नागरिक और ओसीआई कार्ड धारक 18 वीबीएम उड़ानों से भारत लौटे।

सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। अप्रैल 2019 में आरंभ किया गया तिमोर-लेस्ते के ओइ-कसे क्षेत्र में आईटी इनोवेशन लैब प्रोजेक्ट उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है

और जल्द ही इसका काम पूरा होने की संभावना है। इस परियोजना का उद्देश्य स्कूलों में आईटी साक्षरता को बढ़ाना है, जिसमें 12 विद्यालयों की कवरेज के

वियतनाम

भारत ने कोविड-19 के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी की गति को बनाए रखने और वियतनाम के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहने की रणनीतियों की फिर से खोज की। व्यापार और वाणिज्य, रक्षा और सुरक्षा, विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग जारी रहा। प्रधानमंत्री ने वियतनाम के प्रधान मंत्री, गुयेन जुआन फुक के साथ 21 दिसंबर 2020 को व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों पर एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में विचारों का आदान-प्रदान किया और भारत-वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी भविष्य के विकास को निर्देशित करने के लिए 'शांति, समृद्धि एवं लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण' जारी किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी सहित आम वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। भारत के भारत-प्रशांत महासागरों की पहल और भारत-प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण के आधार पर इस क्षेत्र में सभी के लिए साझा सुरक्षा, समृद्धि और वृद्धि हासिल करने के लिए समुद्री क्षेत्र में नए और व्यावहारिक सहयोग को साझा करने पर भी सहमति हुई।

प्रधानमंत्री ने 13 अप्रैल 2020 को कोविड-19 महामारी से उभरने वाली वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री न्गुयेन जुआन फुक के साथ एक टेलीकॉन आयोजित किया था।

विदेश मंत्री और वियतनाम के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री फाम बिन्ह मिन्ह द्वारा संयुक्त आयोग की सत्रहवीं बैठक (आभासी) 25 अगस्त 2020 की सह-अध्यक्षता की गई थी। वे आर्थिक और रक्षा सहयोग में नई गति लाने और असेैनिक परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान और नई प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाने के लिए सहमत हुए। विदेश मंत्री ने एक चुनौतीपूर्ण वर्ष में आसियान को नेतृत्वकारी भूमिका प्रदान करने और 2020-2021 के लिए यूएनएससी अस्थायी सदस्य के रूप में जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वियतनाम की सराहना की।

इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यू) और वियतनाम इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एंड साउथवेस्ट एशियन स्टडीज (वीआईआईएसएस) द्वारा 07 अक्टूबर 2020 को आयोजित 'भारत-वियतनाम संबंधों में नए क्षितिज' नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य मंत्री ने मुख्य भाषण दिया।मंत्रालय के पीपीआर डिवीजन और वियतनाम के विदेश मंत्रालय के पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन के बीच पहली विदेश नीति वार्ता 15 सितंबर 2020 को जेएस/डीजी-स्तर पर ऑनलाइन आयोजित की गई थी।

भारत के सभी महत्वपूर्ण आसियान कार्यक्रमों में भारत की सक्रिय भागीदारी के साथ बहुपक्षीय क्षेत्र में भारत-वियतनाम संबंधों को और मजबूत किया गया, जिसमें भारत-आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) 2020 की आभासी मंत्रिस्तरीय बैठकें और यूएनएससी में भारत और वियतनाम की समवर्ती अस्थायी सदस्यता की तैयारी में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मामलों पर परामर्श शामिल हैं।

साथ, आईटी इनोवेशन लैब और मोबाइल आईटी इनोवेशन वैन दोनों शामिल हैं। .

वियतनाम के साथ नियमित आदान-प्रदान के साथ रक्षा, समुद्री सुरक्षा में सहयोग जारी रहा। रक्षा मंत्री ने 27 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल न्गो जुआन लिच के साथ ऑनलाइन वार्ता की। हाइड्रोग्राफी सहयोग के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा सचिव ने 29 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वियतनाम के उप रक्षा मंत्री सीनियर जनरल गुयेन ची विन्ह के साथ भारत-वियतनाम वार्षिक सुरक्षा वार्ता का 13 वां दौर आयोजित किया। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस किलतान ने मध्य वियतनाम में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए वियतनाम को बाढ़ राहत सामग्री पहुँचाने के लिए दिसंबर 2020 में वियतनाम का दौरा किया। रक्षा सचिव ने 6 जुलाई 2020 को वियतनाम के उप रक्षा मंत्री, सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल गुयेन ची विन्ह के साथ टेलीफोन पर वार्ता की और साथ ही चल रही रक्षा साझेदारी की समीक्षा और सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान की। भारत और वियतनाम के सैन्य चिकित्सा विभागों ने एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के लिए 1 जुलाई 2020 को कोविड-19 की रोकथाम और नियंत्रण पर एक ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित किया। सीएलएमवी देशों के सैन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सैन्य चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में, पहला ई-आईटीईसी कार्यक्रम जुलाई 2020 में आयोजित किया गया था, जिसमें वियतनाम के आठ सैन्य अधिकारियों ने भाग लिया था।

द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को कोविड-19 ने प्रभावित किया, दोनों पक्षों ने चल रहे व्यवधानों का सामना करने के लिए नई साझेदारी का पता लगाया। वियतनाम सरकार के वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से संबंधित विघटन के दौरान व्यापार संपर्क की सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा जारी उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। 2020-21 के पहले 6 महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 4.73 बिलियन अमरीकी डॉलर (वाईओवाई आधार पर 31.26% की कमी) पर पहुँच गया। इस अवधि के दौरान, भारत में वियतनाम का निर्यात 2.50 बिलियन अमरीकी डॉलर (वाईओवाई आधार पर 42.38% की कमी) तक पहुँच गया, जबकि वियतनाम के लिए भारत का निर्यात 2.23 बिलियन अमरीकी डॉलर (वाईओवाई आधार पर 12.28% की कमी) था। वियतनाम में भारतीय निर्यात के शीर्ष 5 जिनसें में लोहा और इस्पात, मांस उत्पाद, समुद्री उत्पाद, मोटर वाहन और कपास शामिल हैं। वियतनाम से भारतीय आयात के शीर्ष 4 जिनस इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण, तांबा, अकार्बनिक रसायन और स्टील हैं। वियतनाम की विदेशी निवेश एजेंसी के अनुसार, 2020 में 17 मिलियन अमरीकी डॉलर के नए निवेश के साथ वियतनाम में भारतीय कंपनियों द्वारा कुल निवेश 937.5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। वियतनाम में भारतीय कंपनियों द्वारा आईटी और ऊर्जा क्षेत्रों में नए निजी निवेश किए गए।

विकास साझेदारी भारत-वियतनाम द्विपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब तक, कुल 26 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं (क्यूआईपी) शुरू की गई, जिनमें से 13 पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 2020-21 में, 12 नई क्यूआईपी स्वीकृत की गई हैं और कार्यान्वयन के अधीन हैं, जिनमें मेकांग डेल्टा क्षेत्र में

जल प्रबंधन में 7 क्यूआईपी शामिल हैं। हो ची मिन्ह सिटी में पोस्ट एंड टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (पीटीआईटी) में एक उन्नत आईटी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के अनुबंध में एक परिशिष्ट जोड़ा गया, 1 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की भारतीय सहायता के साथ आईटी प्रशिक्षण और कौशल के लिए एक अत्याधुनिक इकाई स्थापित करने के लिए, इस पर 7 अगस्त 2020 को हस्ताक्षर किए गए, जो वियतनाम की आईटी प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाएगा वियतनामी छात्रों ने भारत में आईआईटी में उच्च अध्ययन के लिए 1000 डॉक्टरेट छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आसियान छात्रों के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत नामांकन कराया।

प्रशांत द्वीप देश

फिजी: भारत-यूननडीपी फंड के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक क्षेत्रीय सोलराइजेशन परियोजना के परियोजना दस्तावेज पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूननडीपी, सुवा) और प्रशांत द्वीप विकास मंच (पीआईडीएफ) के बीच 1 जून 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे, जो प्रशांत के 11 देशों में और सुवा में पीआईडीएफ मुख्यालय में राज्य प्रमुखों के आवासों के सौर ऊर्जाकरण पर जोर देता है। परियोजना की 1,310,000 अमेरिकी डॉलर की कुल लागत में से भारत सरकार भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी निधि (यूननडीपीएफ) से 400,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगी और 700,000 अमेरिकी डॉलर के भारत-यूननडीपीएफ के अंतर्गत कॉमनवेलथ विंडो माध्यम से प्रदान करेगी। परियोजना के लिए लक्षित स्थलों में फिजी, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, पलाऊ, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, सोलोमन आइलैंड्स, तिमोर लेस्ते, टोंगा, तुवालु और वानुअतु शामिल हैं। उच्चायुक्त ने 15 जुलाई 2020 को फिजी की शिक्षा कला और विरासत मंत्री, सुश्री रोज़ी सोफिया अकबर की उपस्थिति में फिजी के गुजरात एजुकेशन सोसाइटी को महात्मा गांधी मेमोरियल हाई स्कूल ऑफ़ सुवा में आईटी सुविधाओं के उन्नयन के लिए भारत की सहायता के रूप में 143,125 अमरीकी डॉलर सौंपे। भारत सरकार ने 19 मई 2020 को दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूननओएसएससी) द्वारा प्रबंधित, भारत -यूननडीपीएफ के माध्यम से, फिजी के परियोजना प्रस्ताव “विकासशील जलवायु आपदा जोखिम वित्तपोषण फ्रेमवर्क और पैरामीट्रिक बीमा” के लिए 850,000,000 अमरीकी डॉलर की धनराशि स्वीकृत की।

इस परियोजना का उद्देश्य फिजियों के लिए वित्तपोषण साधनों के माध्यम से जलवायु और चरम मौसम की घटनाओं के कारण होने वाली आर्थिक क्षति को कम करना है। इस पहल, को फिजी अर्थव्यवस्था मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूननडीपी) और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय (यूननयू) द्वारा प्रबंधित म्यूनिख क्लाइमेट इंश्योरेंस पहल (एमसीआईआई) के संयुक्त तत्वावधान में लागू किया जाएगा। 14 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की तीसरी महासभा के दौरान, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नाउरू को उपाध्यक्ष चुना गया था। दोनों देश आईएसए के संस्थापक सदस्य हैं।

फिजी में 17-18 दिसंबर 2020 को श्रेणी 5 के ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा आया था, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति और विनाश

वियतनाम में पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण में सहायता भारत की सांस्कृतिक आउटरीच के साथ-साथ वियतनाम के साथ विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मध्य वियतनाम में माई सन के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के संरक्षण और पुनर्निर्माण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की 5 वर्ष से चल रही परियोजना अनुसूची के अनुसार आगे बढ़ती रही। 2020-21 में बहाली कार्य के चौथे सत्र में, एएसआई टीम को नौवीं शताब्दी का एक अखंड बलुआ पत्थर का शिव लिंग मिला, जिसने भारत और वियतनाम के बीच समृद्ध सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया।

हुआ था। चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए भारत से राहत सामग्री की पहली खेप जनवरी 2021 के पहले सप्ताह में फिजी पहुंची। भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त द्वारा सुवा में 11 जनवरी 2021 को फिजी के रक्षा और आपदा प्रबंधन मंत्री इनिया सेरुइरातु को राहत सामग्री सौंपी गई थी। भारत-प्रशांत महासागरों की पहल (आईपीओआई1) के अंतर्गत अनुकूल विदेशी देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता के अंतर्गत फिजी की जरूरत के बाद की प्रतिक्रिया पर प्रारंभिक प्रतिक्रिया की गई।

नीयू: भारत की वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ स्थापित, आईटी में भारत-नीयू सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस, अगस्त 2020 में नीयू की सूचना और संचार तकनीक के विकास और संवर्धन में सहायता करने के लिए नीयू की राजधानी अलोफी के दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय में शुरू किया गया था। इससे पहले, 4 जी दूरसंचार सेवाओं के दूसरे चरण के लिए नीयू को 03 मार्च 2020 को 346,085 अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता जारी की गई थी, जिसमें नीयू की कुल आबादी के लिए 4-जी दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने की परियोजना के लिए भारत का कुल समर्थन 12,56,785 डॉलर था।

किरिबाती: भारत सरकार ने यूएनओएसएससी द्वारा प्रबंधित भारत-यूननडीपीएफ के माध्यम से 28 अगस्त, 2020 को कोविड-19 महामारी के लिए किरिबाती की प्रतिक्रिया के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता को मंजूरी दी।

मार्शल द्वीपों के गणराज्य: भारत से आरएमआई के लिए विकास सहायता द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। अगस्त 2020 में, “कोरल एंड कैलम प्रोजेक्ट फेज-II” के लिए आरएमआई में 200,000 अमरीकी डॉलर की राशि वितरित की गई थी, जिसने महिलाओं के रोजगार और स्थायी जलीय कृषि में योगदान देकर स्थानीय समुदाय पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डाला। सितंबर 2020 में, आरएमआई के अनुरोध के जवाब में हाइड्रोक्लोरोक्वीन की 7,500 गोतियों को चिकित्सा सहायता के रूप में भेजा गया था। 18 फरवरी 2020 को राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता से छूट पर भारत और आरएमआई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, आरएमआई ने 30 अक्टूबर 2020 को समझौते के आधार पर प्रवेश के लिए भारत के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मार्शल द्वीपों के गणराज्य (आरएमआई) ने 24 दिसंबर 2020 को

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की। आरएमआई 8 अगस्त 2019 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पलाऊ: 2020 के दौरान, भारत ने यूएनडीएफ के अंतर्गत ग्लोबल विलेज कॉन्फ्रेंस सुविधाओं की स्थापना, पलाऊ सिविक हॉल, पलाऊ कम्युनिटी कॉलेज के नवीनीकरण में पलाऊ के साथ भागीदारी की, जो पलाऊ में आयोजित होने वाले महासागर सम्मेलन 2020 स्लेट सम्मेलन को महत्वपूर्ण संस्थागत समर्थन प्रदान करेगा। पलाऊ के राष्ट्रपति टॉमी रेमेंग्साऊ जूनियर ने 24 सितंबर 2020 को 75वें यूएनजीए को संबोधित करते हुए भारत-यूननडीपीएफ के माध्यम से अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए पलाऊ की मदद करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।

पीएनजी: भारत और पीएनजी के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है। पीएनजी नेतृत्व ने लगातार भारत पर ध्यान केंद्रित करने और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में संबंधों को गहरा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हुए काम कर रहे हैं, जिनमें राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र संगठन शामिल हैं। 2020 के दौरान, पीएनजी में मदन-बैयर और हॉकिंस-किम्बे सड़कों के निर्माण के लिए पीएनजी सरकार को एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया द्वारा विस्तारित 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण (एलओसी) की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दस पूर्ण सुसज्जित एंबुलेंस की जरूरत के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र सहयोग विकास निधि के अंतर्गत पीएनजी के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई थी। पोर्ट मोरेस्बी में महात्मा गांधी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरी तरह कार्यात्मक हो गई है और छात्रों का दूसरा बैच केंद्र में अध्ययन कर रहा है। भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स, पीएनजी के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी, जो दो पेशेवर निकायों के बीच संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करेगा।

समोआ: 12 मार्च 2020 को, समोआ के प्रधानमंत्री और भारत के उच्चायुक्त ने समोआ में एक ‘कर सूचना विनिमय समझौते’ पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के घरेलू कर कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए प्रासंगिक सूचनाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा।

13 मार्च 2020 को, समोआ के प्रधानमंत्री और उच्चायुक्त ने संयुक्त रूप से आईटी में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस केंद्र को भारत सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ समोआ की राजधानी अपिया में

समोआ के अधिकारियों और आम जनता के लिए आईटी में अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया। इस वर्ष से पहले, समोआ की राजधानी एपिया में ‘समोआ नॉलेज सोसाइटी इनिशिएटिव’ आरंभ हुआ था। 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की परियोजना को भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के तत्वावधान में भारत द्वारा वित्त पोषित किया गया है, और इसका उद्देश्य समोआ में ज्ञान-आधारित सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत ने 2019 की अंतिम तिमाही में समोआ में फैली सबसे खराब खसरा महामारी के बाद राहत और पुनर्वास में मदद के लिए समोआ को 250,000 अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी। इस बीमारी में 82 लोगों की जान चली गई और लगभग 6000 अन्य प्रभावित हुए।

सोलोमन द्वीप: भारत-सोलोमन द्वीप में मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देश राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हुए काम कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 17 फरवरी 2020 को होनियारा में आईटी में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में सोलोमन द्वीप का समर्थन करने के लिए भारत-संयुक्त राष्ट्र सहयोग विकास कोष के अंतर्गत सोलोमन द्वीप के लिए 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दी गई थी। सोलोमन द्वीप ने आधिकारिक और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा की छूट के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति व्यक्त की।

टोंगा: भारत सरकार ने यूएनओएसएससी द्वारा प्रबंधित, भारत-यूननडीपीएफ के माध्यम से, 28 अगस्त 2020 को कोविड-19 महामारी के लिए टोंगा की प्रतिक्रिया के समर्थन के लिए 1,018,844 अमरीकी डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी।

टोंगा ने 8 जनवरी 2021 को, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए आईएसए सदस्यता के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन की पुष्टि की।

तुवालु: भारत सरकार ने यूएनओएसएससी द्वारा प्रबंधित भारत-यूननडीपीएफ के माध्यम से 28 अगस्त 2020 को कोविड-19 महामारी के लिए तुवालु की प्रतिक्रिया के समर्थन के लिए 370,353 अमरीकी डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी।

4

पूर्वी एशिया

चीन

पिछले तीन दशकों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्दपूर्ण संबंधों ने अन्य क्षेत्रों में विस्तारित सहयोग के लिए आधार प्रदान किया था। वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ का वर्ष था, इस वर्ष भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया।

अप्रैल 2020 से, पूर्वी लद्दाख से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ चीनी पक्ष द्वारा सैनिकों और सेनाओं का जमाव हुआ था। मध्य मई में चीनी पक्ष ने पश्चिमी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में एलएसी को स्थानांतरित करने के कई प्रयास किए। इसमें कोंगका ला, गोगरा और पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे शामिल थे। एलएसी के साथ बढ़ते टकराव को देखते हुए, दोनों पक्षों के वरिष्ठ कमांडरों ने 6 जून 2020 को एक बैठक में इस बात पर सहमति जताई जिसमें पारस्परिक रूप से टकराव से बचने की कार्रवाई शामिल थी। दोनों पक्ष एलएसी का सम्मान और पालन करने और यथास्थिति को बदलने के लिए कोई गतिविधि नहीं करने पर सहमत हुए। हालाँकि इसके उल्लंघन में चीनी पक्ष 15 जून 2020 को गालवान में एक हिंसक संघर्ष किया था। हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और चीनी पक्ष को हताहतों सहित इसकी कीमत चुकानी पड़ी। विदेश मंत्री ने 17 जून 2020 को चीन के राज्य मंत्री और विदेश मंत्री, वांग यी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें भारत की

चिंताओं से अवगत कराया। विदेश मंत्री ने इस पर भी जोर दिया कि चीनी पक्ष को उचित कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि एलएसी पर शांति बहाल हो सके।

सीमा प्रश्न पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) - भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के विदेश मामलों के मंत्री और विदेश मंत्री वांग यी ने 5 जुलाई 2020 को टेलीफोन पर बातचीत की। वे टकराव वाले क्षेत्रों से सेना का जमाव कम करने और शांति बहाल करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। पर चीनी पक्ष के साथ राजनयिक और सैन्य तनाव बने रहने के समय, चीनी पक्ष ने 29 और 30 अगस्त 2020 की रात को फिर से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के बदले उत्तेजक सैन्य युद्धाभ्यास में लगा रहा। इन प्रयासों को भारतीय बलों द्वारा एहतियाती कार्रवाई से रोका गया।

इसके बाद रक्षा मंत्री ने 04 सितंबर, 2020 को मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के मौके पर चीन के जनरल काउंसलर और रक्षा मंत्री से भेंट की। 10 सितंबर 2020 को, विदेश मंत्री ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वर्तमान तनावों के संबंध में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक की ओर से मॉस्को में चीन के राज्य मंत्री और विदेश मंत्री वांग यी के साथ विस्तृत चर्चा की। वर्तमान स्थिति के दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करने के लिए, टकराव

वाले सभी क्षेत्रों से तनाव कम करने और शांति बहाल करने के लिए मंत्रियों ने पाँच बिंदुओं पर एक समझौता किया। नेतृत्व स्तर की वार्ताओं के दौरान, दोनों पक्ष एलएसी पर बनी स्थिति के लिए शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर निकट संचार बनाए रखने के लिए सहमत हुए।

भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की पंद्रहवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं, अठारहवीं, उन्नीसवीं और बीसवीं बैठक क्रमशः 24 जून 2020, 10 जुलाई 2020, 24 जुलाई 2020, 20 अगस्त 2020, 30 सितंबर 2020 और 18 दिसंबर 2020 को वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई थी। वरिष्ठ कमांडरों (भारतीय पक्ष में चौदहवीं वाहिनी के कमांडर की अध्यक्षता में) के बीच नौ दौर की बैठकें भी हुईं, अंतिम दौर की बातचीत 24 जनवरी 2021 को हुई थी।

राजनयिक और सैन्य स्तर की इन बैठकों के दौरान, दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में एलएसी के पास की स्थिति पर स्पष्ट और गहन विचार-विमर्श किया। उन्होंने पुष्टि की कि दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ तनाव के सभी बिंदुओं पर सैनिकों के पूर्ण विघटन की दिशा में ईमानदारी से काम करना जारी रखेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति की बहाली द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक होगी।

आज की तारीख पर, स्थिति को हल करने और पूर्ण शांति बहाल करने के लिए सैन्य और राजनयिक व्यस्तता जारी है।

कोविड-19 संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

प्रधानमंत्री ने 8 फरवरी 2020 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर लिखा, जिसमें चीन के लोगों के साथ भारत सरकार और लोगों की एकजुटता के बारे में बताया गया और सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की तत्परता दिखाई दी। भारत सरकार ने 26 फरवरी 2020 को चीन को मास्क, दस्ताने और अन्य आपातकालीन चिकित्सा उपकरण सहित 15 टन चिकित्सा सहायता भी प्रदान की। इन

कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य

दिसंबर 1973 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से, भारत और कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता लाने के प्रयासों का लगातार समर्थन करता रहा है।

जापान

इस वर्ष ने भारत-जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को और मजबूत किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2014 में की थी। द्विपक्षीय संबंध आज बहुआयामी हो गया है और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामरिक हितों का अभिसरण हो रहा है।

कोविड-19 महामारी के नियमित यात्राओं और आदान-प्रदान में व्यवधान उत्पन्न करने पर भी, दोनों पक्षों ने आभासी बैठकों और फोन कॉल के माध्यम

चिकित्सा आपूर्तियों पर लगभग 2.11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्हें चीन के वुहान में हुबेई चैरिटी फेडरेशन को सौंपा गया।

विदेश मंत्री ने 24 मार्च 2020 को चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर चर्चा की और इस क्षेत्र में हमारे द्विपक्षीय प्रयासों पर आगे बढ़ने पर सहमत हुए। अलग से, वाणिज्यिक आयात के माध्यम से चीन से पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई), वेंटिलेटर जैसे कोविड-19 से संबंधित आवश्यक उपकरण की खरीद की भी सुविधा की गई थी।

भारत सरकार ने 31 जनवरी 2020, 1 फरवरी 2020 और 26 फरवरी 2020 को 766 लोगों को निकालने के लिए तीन विशेष उड़ानों का आयोजन किया, जिसमें वुहान शहर के छात्रों के साथ-साथ कोरोनावायरस के कारण हुबेई प्रांत जारी तालाबंदी को देखते हुए चीन के हुबेई प्रांत के अन्य शहरों के लोग भी शामिल थे। निकाले गए व्यक्तियों में 723 भारतीय नागरिक और 43 विदेशी नागरिक शामिल थे। विदेशी नागरिकों में बांग्लादेश से 23, मालदीव से 9, म्यांमार से 2, दक्षिण अफ्रीका से 1, मेडागास्कर से 1 और संयुक्त राज्य अमेरिका से 1 व्यक्ति था जो एक भारतीय नागरिक का साथी था। इसके अलावा, 6 चीनी नागरिक जो भारतीय नागरिकों के जीवनसाथी और/या बच्चे थे, उन्हें भी निकाला गया।

भारत और चीन के बीच नियमित हवाई यात्रा और कार्गो की आवाजाही पर कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध लगाए गए थे इसलिए चीन और हांगकांग के शहरों से फैसे हुए भारत के कई नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत की उड़ानों का आयोजन किया गया था। 31 दिसंबर 2020 तक, वंदे भारत की इन उड़ानों में 2,734 भारतीय नागरिकों को चीन और हांगकांग से वापस लाया गया था। इन उड़ानों का उपयोग चीन और हांगकांग में भारतीयों के आवागमन की सुविधा के लिए भी किया गया था। इसके अलावा, हांगकांग से भारत के लिए चार्टर उड़ानों में 170 नाविकों को प्रत्यावर्तित किया गया था।

भारत सरकार ने डीपीआर कोरिया को एंटी-ट्यूबरकुलोसिस दवाओं के रूप में 1 मिलियन अमरीकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी। यह चिकित्सा सहायता डीपीआरके में चल रहे डब्ल्यूएचओ एंटी-ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तत्वावधान में की गई है।

से अपने संबंधों की गति बनाए रखी। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2020 में पूर्व प्रधानमंत्री आबे से बात की थी कि वे कोविड-19 के प्रबंधन के लिए प्रत्येक देश की प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श करें और कोविड के बाद के विश्व में सहयोग को मजबूत करें। सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री आबे के जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ने से ठीक पहले दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत की। 25 सितंबर 2020 को, प्रधानमंत्री ने जापान के नव नियुक्त प्रधानमंत्री

सुगा योशीहाइड से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने आपसी विश्वास और साझा मूल्यों के आधार पर संबंधों को और मजबूत करने का इरादा व्यक्त किया। 21 दिसंबर 2020 को टोक्यो में एसएएमवीएडी संवाद का

छठवां संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश दिया जबकि प्रधानमंत्री सुगा ने व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी दी।



भारत-जापान विदेश मंत्रियों की 13 वीं रणनीतिक वार्ता

विदेश मंत्री ने 07 अक्टूबर 2020 को जापानी विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के साथ भारत-जापान विदेश मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता के लिए टोक्यो का दौरा किया। दोनों मंत्रियों ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की, जिसमें समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विनिर्माण और कौशल विकास, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचा, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं। जापान ने प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर 2019 में घोषित भारत-प्रशांत महासागरों के पहल स्तंभ (आईपीओआई) के संपर्क स्तंभ में प्रमुख भागीदार होने के लिए भी अपनी सहमति व्यक्त की थी। इससे पहले मई 2020 में, विदेश मंत्री ने जापानी विदेश मंत्री मोतेगी के साथ टेलीफोन पर बात की, जिसमें उन्होंने कोविड के बाद के परिदृश्य में भारत-जापान सहयोग पर चर्चा की।

इस वर्ष भी द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत किया गया। रक्षा मंत्री ने टेलीफोन पर 08 मई 2020 को जापान के तत्कालीन रक्षा मंत्री कोनो तारो के साथ और 22 नवंबर 2020 को जापान के नए रक्षा मंत्री किशी नोबुओ से बात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके जापानी समकक्ष कितामुरा शिगरु ने 18 सितंबर 2020 को द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों देशों ने जापान के आत्मरक्षा बलों और भारतीय सशस्त्र बलों (तथाकथित “अधिग्रहण और क्रॉस-सर्विसिंग समझौता” या एसीएसए) के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर निर्णय लिया और हस्ताक्षर किए। समझौते से समुद्री सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र जागरूकता में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। 26-28 सितंबर 2020 के बीच भारतीय नौसेना और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स के चौथे संस्करण के पूरा होने के साथ 2020 में संयुक्त परिचालन संलग्नता जारी रही। जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी दो चरणों में आयोजित मालाबार 2020 में भाग लिया।

पहला चरण बंगाल की खाड़ी में 3-6 नवंबर 2020 तक और दूसरा चरण 17-20 नवंबर 2020 तक अरब सागर में आयोजित किया गया था। जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल इज़सत्सु शुंजी ने 9-10 दिसंबर 2020 को भारत की आधिकारिक यात्रा की।

आर्थिक मोर्चे पर, जापान भारत के विकास और सामाजिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार बना रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, जापानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 3.23 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 2000 के बाद से संचयी निवेश 33.49 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, प्रमुख निवेशकों में जापान का चौथा स्थान था। भारत में पंजीकृत जापानी कंपनियों की संख्या 1454 हो गई। जापान 2019-20 में जेपीवाई 374.44 बिलियन (लगभग 3.7 बिलियन अमरीकी डॉलर) की ओडीए प्रतिबद्धता के साथ भारत का द्विपक्षीय आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) का सबसे बड़ा दानकर्ता रहा। अगस्त 2020 में, जेआईसीए के लिए कोविड-19 आपातकालीन सहायता के रूप में जेपीवाई 50 बिलियन (लगभग 500 मिलियन अमरीकी डॉलर) तक का जापानी ओडीए ऋण प्रदान करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जापान ने कोविड-19 महामारी से निपटने में भारत के प्रयासों की सहायता के लिए जेपीवाई 1 बिलियन की अनुदान सहायता भी प्रदान की। 8 जनवरी 2021 को, जेआईसीए के लिए एक अन्य ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि सामाजिक सुरक्षा के लिए जेपीवाई 30 बिलियन (लगभग 300 मिलियन अमरीकी डॉलर) का एक जापानी ओडीए ऋण प्रदान किया जा सके।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए 08 मई 2020 को अपने जापानी समकक्ष कजियामा हिरोशी के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री के साथ

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 01 सितंबर 2020 को आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (एससीआरआई) का शुभारंभ किया। यह पहल कोविड-19 संकट और हाल के आर्थिक और तकनीकी परिदृश्य में वैश्विक स्तर के बदलाव को देखते हुए लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का प्रयास करती है। प्रायोगिक मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएचएसआर) परियोजना के कार्यान्वयन में और प्रगति हुई। एमएचएसआर पर 11वीं संयुक्त समिति की बैठक, जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार, नीति आयोग और हिरोतो इजुमी की सह-अध्यक्षता में 25 सितंबर 2020 को आभासी प्रारूप में हुई थी।

द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए 2020 में सहयोग के कई द्विपक्षीय ज्ञापन (एमओसी) भी संपन्न हुए हैं। इनमें आईसीटी के क्षेत्र में एमओसी, भारत-जापान स्टील संवाद स्थापित करने के लिए एक एमओसी और निर्दिष्ट कुशल श्रमिकों के आवागमन के लिए बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिए एक एमओसी शामिल हैं।

मंगोलिया

भारत और मंगोलिया मैत्री और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का आनंद लेते हैं। मंगोलिया भारत को ‘आध्यात्मिक तीसरा पड़ोसी’ मानता है। द्विपक्षीय संबंध को प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान 2015 में एक सामरिक भागीदारी में उन्नत किया गया था जो मंगोलिया के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक विशेष घटना साबित हुई है।

मंगोलिया सरकार के मंत्री और मुख्य कैबिनेट सचिव (सीसीएस), ओयुन-एर्डेन ने आईटीईसी पहल के अंतर्गत आईआईएम, इंदौर में एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए जनवरी 2020 में मंगोलिया के सभी 21 प्रांतों से 18 राज्यपालों और 7 उच्च अधिकारियों के एक समूह का नेतृत्व किया। यात्रा के

कोविड-19 के कारण, यात्रा और लोगों से लोगों के संपर्क बाधित हुए। हालांकि, दोनों देशों ने एक-दूसरे के देशों में अपने नागरिकों की यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे की सहायता की। भारत और जापान के बीच राहत उड़ानों का आयोजन न केवल फैसे हुए व्यक्तियों को वापस लाने के लिए किया गया, बल्कि काम करने वाले पेशेवरों और व्यापारियों को अपनी नौकरी और व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए भी किया गया। टोक्यो में भारतीय दूतावास के साथ मंत्रालय फरवरी 2020 में कूज़ लाइनर “डायमंड प्रिंसेस” पर 119 भारतीय चालक दल के सदस्यों को निकालने में शामिल रहा। लोगों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए दोनों देशों के बीच नवंबर 2020 में एक एयर बबल की स्थापना की गई थी। वंदे भारत मिशन और भारत-जापान एयर बबल के अंतर्गत 22 एयर इंडिया उड़ानों से सफलतापूर्वक 4,702 भारतीयों और 132 विदेशी नागरिकों को जापान से भारत वापस लाया गया। भारत से जापान जाने वाले भारतीय नागरिकों की आवाजाही भी इन उड़ानों द्वारा ही हुई थी।

दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से भी भेंट की। हालांकि कोविड-19 और आगामी यात्रा प्रतिबंधों के कारण, वर्ष के अधिकांश भाग में भौतिक बैठकें नहीं हो सकीं, वीसी और टेलीफोन वार्तालापों के माध्यम से आदान-प्रदान किया गया। मई 2020 में, विदेश मंत्री ने अपने मंगोलियाई समकक्ष, डैमदीन सोगतबातर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और महामारी के समय तेजी से प्रतिक्रिया और चिकित्सीय अंतरसक्रियता पर चर्चा की तथा 1.236 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऑयल रिफाइनरी और 20 मिलियन अमरीकी डॉलर के अटल बिहारी वाजपेयी आईटी उत्कृष्टता केंद्र की विकास साझेदारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।



03 दिसंबर 2020 को सहयोग पर भारत-मंगोलिया संयुक्त समिति की सातवीं बैठक में विदेश मंत्री

सहयोग पर भारत-मंगोलिया संयुक्त समिति की सातवीं बैठक आभासी रूप में 03 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री और मंगोलिया

सरकार के मुख्य कैबिनेट सचिव ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने तेल रिफाइनरी परियोजना की प्रगति की समीक्षा सहित द्विपक्षीय

सहयोग को आवृत करने वाले मुद्दों पर संपूर्ण चर्चा की, इस परियोजना को भारत द्वारा विस्तारित 1.236 बिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। दोनों मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि इस परियोजना के सफल समापन से मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा में अत्यधिक योगदान होगा। मंगोलिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने की पुष्टि की। राजनयिक संबंधों की स्थापना के पैंसठवीं वर्षगांठ के उत्सव के हिस्से के

रूप में, विदेश मंत्री ने मंगोलियाई कंजूर के 25 संस्करण जारी किये और मंगोल पोस्ट द्वारा मुद्रित एक स्मारक डाक टिकट का संयुक्त रूप से अनावरण किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई पत्रों का आदान-प्रदान किया।

भारत के चुनाव आयोग और मंगोलिया के आम चुनाव आयोग ने 30 अगस्त 2020 को चुनाव के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन और सहयोग पर हस्ताक्षर किए।

कोरिया गणराज्य

भारत और कोरिया गणराज्य (आरओके) के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गति कई उच्च-स्तरीय यात्राओं के साथ तेज हुई, जिसमें फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री की सियोल यात्रा, जुलाई 2018 में राष्ट्रपति मून जे-इन की भारत यात्रा और नवंबर 2019 में आरओके की प्रथम महिला की यात्रा शामिल है। इस वर्ष वरिष्ठ नेतृत्व की नियमित उच्च-स्तरीय बातचीत के माध्यम से इस संबंध को जारी रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान 08 अप्रैल 2020 और 21 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति मून के साथ टेलीफोन पर बात की और द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और वैश्विक विकास, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

विदेश मंत्री ने 19 मई 2020 को द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 संबंधित सहयोग और यात्रा प्रतिबंधों को आसान बनाने पर चर्चा करने के लिए आरओके के विदेश मंत्री के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। सचिव (पूर्व) ने 23 दिसंबर 2020 को, एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कोरिया गणराज्य के प्रथम उप-विदेश मंत्री के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग और उच्च स्तरीय द्विपक्षीय आदान-प्रदान, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, कोविड-19 प्रतिक्रिया और बहुपक्षीय मंचों में समन्वय सहित पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा की।

आरओके के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जियोंग कियोंग-डो ने 04-06 फरवरी 2020 तक भारत का दौरा किया, इस दौरान उन्होंने लखनऊ में डीईएफईएक्स्पीओ 2020 के उद्घाटन समारोह में भी भाग लिया। रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर 10 जुलाई 2020 को आरओके के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय से टेलीफोन पर बातचीत की। थल सेनाध्यक्ष ने सर्वोच्च सैन्य स्तर पर बातचीत के माध्यम से रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए 28-31 दिसंबर 2020 तक सियोल में सद्भावना यात्रा पर गए 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर 20 अगस्त 2020 को, कोरिया गणराज्य के साथ विचार-विमर्श आभासी प्रारूप में आयोजित किए गए, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास और निरस्त्रीकरण और अप्रसार के क्षेत्र में पारस्परिक हित के समकालीन मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

दोनों देशों ने अपने फँसे हुए नागरिकों की एक-दूसरे देशों में यात्रा की सुविधा भी दी। भारत ने फिर से भारत में परिचालन शुरू करने के लिए आरओके के व्यापारिक उद्यमों के आवश्यक कर्मियों की यात्रा की व्यवस्था की। वीबीएम की 2 उड़ानों द्वारा, 242 भारतीयों को आरओके से भारत वापस लाया गया और 234 भारतीयों को भारत से आरओके की यात्रा करने की सुविधा दी गई। इसके अलावा, लगभग 1350 भारतीयों ने चार्टर्ड उड़ानों द्वारा भारत और आरओके के बीच यात्रा की।

5

यूरेशिया

रूसी संघ

प्रधानमंत्री ने रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 3 दूरभाष वार्ताएं की। 1 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ने रूस में संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रीय मतदान के सफलतापूर्वक पूरा होने पर राष्ट्रपति पुतिन को बधाई दी। 17 सितम्बर 2020 को प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने बात की जबकि 07 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए फोन किया।

दूसरे विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री ने 22-24 जून 2020 के दौरान मास्को का दौरा किया जबकि तीनों सेनाओं के भारतीय दल ने मास्को में सेना की परेड में भाग लिया। दूसरे विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए एस सी ओ(शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन), सी आई एस(कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स), तथा सी एस टी ओ(कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन) के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक के लिए 02-04 सितम्बर 2020 को पुनः मास्को का दौरा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने रूसी संघ के रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु के साथ द्विपक्षीय बैठक की

04 सितम्बर 2020 को विदेश मंत्री ने ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की वीडियो-कॉन्फ्रेंस बैठक में भाग लिया।

9-10 सितम्बर 2020 के दौरान विदेश मंत्री ने एस सी ओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के लिए मास्को का दौरा किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री की रूसी विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई तथा उन्होंने रूस-भारत-चीन (आर आई सी) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया।

द्विपक्षीय सेना-तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए रक्षा सचिव ने 19-22 अक्टूबर 2020 के दौरान मास्को का दौरा किया।

रूस तथा भारत ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत नागरिकों की वापसी को सुगम बनाने के लिए निकट सहयोग किया। अप्रैल 2020 में भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के रूस को निर्यात की अनुमति दी जिसकी रूसी नेतृत्व द्वारा बहुत सराहना की गई। जैव-तकनीकी विभाग(डी बी टी) के अंतर्गत लोक क्षेत्र का उपक्रम बी आई आर ए सी(जैव-तकनीकी शोध सहायता परिषद्) भारत में स्तुतनिक- V वैक्सीन के परीक्षण तथा उत्पादन के संबंध में रूसी प्रत्यक्ष निवेश निधि (आर डी आई एफ) के साथ काम कर रहा है। आर डी आई एफ ने स्तुतनिक V वैक्सीन के क्लीनिकल परीक्षणों तथा आपूर्ति पर सहयोग के लिए कुछ भारतीय कम्पनियों के साथ समझौते भी किए हैं।



विदेश मंत्री 9 सितम्बर 2020 को मास्को में रूस के विदेश मंत्री से मिले

आर्मीनिया

अप्रैल 2020 में भारत ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में आर्मीनिया को हाईड्रोजेनक्लोरोक्वीन टेबलेट मानवीय चिकित्सा सहायता के तौर पर उपलब्ध कराई। आर्मीनिया में फ्रंसे भारतीय नागरिकों की वापसी को वंदे भारत

मिशन के अंतर्गत सुगम बनाया गया। मई 2020 में आर्मीनिया की सरकार और येरेवां की नगरपालिका ने येरेवां में महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

अजरबैजान

04 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव की अध्यक्षता में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन(एन ए एम) संपर्क समूह के

“युनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 पेनडेमिक” शीर्षक ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।



नाम संपर्क समूह के आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, 04 मई 2020

20 मई 2020 को अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगताय शिरालियेव की अध्यक्षता में हुई नाम स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंती ने भाग लिया।

अजरबैजान में फ्रंसे भारतीय नागरिकों की वापसी को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सुगम बनाया गया।

मई 2020 में अजरबैजान की मिली मजलिस (संसद) में सांसद नगीफ हमजायेव की अध्यक्षता में अजरबैजान-भारत अंतर-संसदीय संबंधों पर एस 8 सदस्यीय कार्यकारी समूह बनाया गया।

‘घर पर योग, परिवार के साथ योग’ विषय पर 6ठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के

आयोजनों के हिस्से के तौर पर 21 जून 2020 को अजरबैजान में मिशन द्वारा 11 ऑनलाइन इवेंट आयोजित किए गए।

17 अगस्त 2020 को भारत और अजरबैजान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि(बी आई टी) पर विशेषज्ञ स्तर की बातचीत डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में हुई जबकि भारत-अजरबैजान दोगुना कराधान परिहार समझौता (डी टी ए ए) पर बातचीत 21 सितम्बर 2020 को हुई। कोविड-19 के बावजूद भारत और अजरबैजान से व्यापार शिष्टमंडलों ने ऑनलाइन प्रारूप में अपनी सक्रिय संलग्नता बनाए रखी।

बेलारूस

मई 2020 में बेलारूस में फ्रंसे भारतीय नागरिकों की वापसी को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सुगम बनाया गया। 02 अक्टूबर 2020 को मिंस्क में हमारे

मिशन ने गांधी 150 आयोजन के समापन समारोह पर बेलारूस स्टेट मेडिकल विश्वविद्यालय (बी एस एम यू), मिंस्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया।

जॉर्जिया

मई 2020 में जॉर्जिया की सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की स्मृति में एस डाक टिकट जारी किया। जॉर्जिया में फ्रंसे भारतीय नागरिकों की

वापसी को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सुगम बनाया गया।

कज़ाखस्तान

विदेशी मामलों के मंत्री ने 10 सितम्बर 2020 को मास्को में एस सी ओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के अवसर पर कज़ाखस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार

ल्युबर्दी से मुलाकात की।



विदेश मंत्री 10 सितम्बर 2020 को कज़ाखस्तान के विदेश मंत्री से मिले

विदेशी मंत्री ने 24 सितम्बर 2020 को कज़ाखस्तान के विदेश मंत्री की अध्यक्षता वाली कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस-बिल्डिंग मेज़र्स इन एशिया (सी आई सी ए) के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष वीडियो

कॉन्फ्रेंस बैठक में भाग लिया।

कज़ाखस्तान के विदेश मंत्री मुख्तार ल्युबर्दी ने 28 अक्टूबर 2020 को विदेशी मंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में आयोजित इंडिया-सेंट्रल एशिया

डायलॉग की दूसरी बैठक में भाग लिया।

मास्को में एस सी ओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के अवसर पर रक्षा मंत्री ने 04 सितम्बर 2020 को कज़ाखस्तान के रक्षा मंत्री ले.जन. नुर्लान यर्मकबायेव से मुलाकात की। अप्रैल 2020 में भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में कज़ाखस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टेबलेट उपलब्ध कराई। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत मई-अगस्त 2020 में कज़ाखस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी को सुगम बनाया गया।

27 अक्टूबर 2020 को कज़ाखस्तान की एयरो स्पेस कमेटी और इसरो के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर पहला संयुक्त कार्यात्मक समूह डिजिटल वीडियो-कांफ्रेंस प्रारूप में आयोजित किया गया।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यू एन आई एफ आई एल) में भारतीय बटालियन के साथ तैनात कज़ाख पीसकीपिंग कम्पनी की चौथी वर्तन दो चरणों में क्रमशः 1 अगस्त और 20 अगस्त 2020 को की गई।

किर्गीज़ गणराज्य

विदेशी मंत्री ने 09 सितम्बर 2020 को मास्को में एस सी ओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के अवसर पर किर्गीज़ गणराज्य के विदेश मंत्री चिंगीज़ एदबेकोव से मुलाकात की।

28 अक्टूबर 2020 को आभासी रूप से आयोजित विदेश मंत्री स्तरीय 2सरी भारत-मध्य एशिया वार्ता में किर्गीज़ प्रथम उप विदेश मंत्री नूरान नियाज़ालिएव ने भाग लिया।

अप्रैल 2020 में भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में किर्गीज़ गणराज्य को मानवीय सहायता के तौर पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की टेबलेट दान की। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत किर्गीज़ गणराज्य में फंसे करीब 14000 भारतीय नागरिकों की वापसी को सुगम बनाया गया।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर भारत-कज़ाखस्तान संयुक्त कार्यात्मक समूह का 7वां सत्र 10 सितम्बर को आभासी रूप से आयोजित किया गया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विशेष सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया जबकि कज़ाख शिष्टमंडल का नेतृत्व उप व्यापार मंत्री कैरात तोरेबायेव द्वारा किया गया।

नूर-सुल्तान में मिशन के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एस वी सी सी) ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। 10 अगस्त 2020 को प्रसिद्ध कज़ाख लेखक एवं कवि अबई कुनाबाएव की पुस्तक “बुक ऑफ वर्ड्स” का हिंदी संस्करण जारी किया गया। 08 मई 2020 को रबींद्र जयंती उनके गीतों, कविताओं तथा एकल नृत्य प्रस्तुतियों के साथ मनाई गई। 21 जून 2020 को 6ठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न शहरों में योग प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया तथा योग पर संभाषण दिए गए।

21 जून 2020 को दूतावास परिसर में 6ठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया।

25 सितम्बर 2020 को बिश्केक में भारतीय राजदूत ने किर्गीज़ सेंट्रल कमीशन फॉर इलेक्शंस एंड रेफरेंडा (सी ई सी) को रु 27 लाख से अधिक के आई टी हार्डवेयर तथा उपकरण (पर्सनल कम्प्यूटर, टेबलेट तथा नोटबुक) संसदीय चुनावों के सुचारु संचालन के लिए भारतीय सहायता के तौर पर सौंपे।

25 सितम्बर 2020 को बिश्केक में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई जिसमें किर्गीज़ केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष नूरज़हान शैलदाबेकोवा ने भाग लिया।



विदेशी मंत्री एस सी ओ के अवसर पर किर्गीज़ गणराज्य के विदेश मंत्री से मिले, 09 सितम्बर 2020

ताज़िकिस्तान

कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सहयोग से संबंधित विषयों तथा अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा के लिए विदेशी मंत्री ने ताज़िकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन से टेलीफोन वार्ता की।

द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लक्ष्य से आई एस, एस सी ओ तथा सी एस टी ओ के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक के अवसर पर मास्को में 03 सितम्बर 2020 को रक्षा मंत्री ने ताज़िकिस्तान के रक्षा मंत्री कर्नल जन. शेराली मिर्ज़ो से मुलाकात की। 09 सितम्बर 2020 को मास्को में एस सी ओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के अवसर पर विदेशी मंत्री ने ताज़िकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन से मुलाकात की।

ताज़िकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन ने 28 अक्टूबर 2020 को विदेशी मंत्री की अध्यक्षता में डिजिटल वीडियो-कांफ्रेंस प्रारूप में आयोजित 2सरी भारत-मध्य एशिया वार्ता में भाग लिया।

05 मई 2020 को भारत ने ताज़िकिस्तान को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन तथा

पैरासीटामोल की टेबलेट मानवीय सहायता के तौर पर उपलब्ध कराई। 28 मई 2020 को भारत ने वायु मार्ग से ताज़िकिस्तान को दवाइयाँ पहुँचाई जिन्हें ताज़िकिस्तान प्रथम उप स्वास्थ्य मंत्री ने प्राप्त किया। महत्वपूर्ण दवाइयों की एक अन्य खेप ताज़िकिस्तान प्राधिकारियों को 15 जून 2020 को सौंपी गई। ताज़िकिस्तान में भारत-ताज़िकिस्तान मिलता अस्पताल को भी भारत ने दवाएं भेजी।

ताज़िकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सुगम बनाया गया।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग पर भारत-ताज़िकिस्तान संयुक्त कार्यात्मक समूह की दूसरी बैठक 31 अगस्त 2020 को डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई।

गांधी@150 की परिणति के अवसर पर 03 अक्टूबर 2020 को आई सी सी आर द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबीनार “वीविंग रिलेशंस : टेक्सटाइल ट्रेडिंशंस” में ताज़िकिस्तान विशेषज्ञों ने भाग लिया।

तुर्कमेनिस्तान

15 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति ने भारत-तुर्कमेनिस्तान संबंधों की स्थिति एवं संभावनाओं पर चर्चा के लिए तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति गुर्बांगली बर्दीमुहामेदोव के साथ दूरभाष पर वार्ता की।

मंत्री परिषद के उपाध्यक्ष तथा तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव ने 28 अक्टूबर 2020 को डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस प्रारूप में आयोजित दूसरी भारत-मध्य एशिया वार्ता में भाग लिया। दूतावासीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, वीज़ा सुगमीकरण आदि से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए 9 जुलाई 2020 डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस प्रारूप में तीसरी भारत-तुर्कमेनिस्तान दूतावासीय वार्ता का आयोजन किया गया।

कोविड-19 संबंधी बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए तुर्कमेनिस्तान में वर्चुअल

कार्यक्रमों को पंक्तिबद्ध करते हुए 6ठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 13 जून 2020 को अश्गाबात में योगा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर में एक कार्यक्रम के लिए कर्टेन-रेज़र के रूप में भारत तथा योग पर एक क्लिप आयोजित किया गया। 18 जून 2020 को वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए योग के लाभों पर एक विशेष आभासी सत्र आयोजित किया गया। 19 जून 2020 को योग के इम्यूनिटी-वर्धक लाभों पर एक लाइव ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया। 20 जून 2020 को पूरे तुर्कमेनिस्तान के योग अभ्यासी ऑनलाइन योग दिवस कार्यक्रमों में शामिल हुए।

तुर्कमेनिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सुगम बनाई गई।

यूक्रेन

यूक्रेन को कोविड-19 से लड़ने में सहायता करने के लिए अप्रैल 2020 में भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ऑसेल्टेमिवीर तथा अताज़ानवीर दवाओं के रूप में मानवीय चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जा रहे यूक्रेन के सैनिक दल की सहायता के लिए भारत ने 05 मई 2020 को हैजा, टायफायड, मेनिंगोकोकल के लिए टीके तथा मलेरिया के लिए मेफ्लोक्वीन दवा उपलब्ध कराई गई। 21 जून 2020 को 6ठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यूक्रेन के सैंकडों योग उत्साहियों ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल में भाग लिया।

मई-अगस्त 2020 के दौरान वंदे भारत मिशन उड़ानों के अंतर्गत यूक्रेन से 8,000 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित एवं समय पर वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत और यूक्रेन ने मिलकर काम किया। इन उड़ानों ने सैंकडों यूक्रेनी

नागरिकों की यूक्रेन को वापसी को सुगम बनाया।

14 अगस्त 2020 से यूक्रेन ने भारतीय नागरिकों के लिए व्यापार, व्यक्तिगत दौरे, पर्यटन, उपचार, संस्कृति, विज्ञान, शिक्षा, खेल के क्षेत्र में गतिविधियों के साथ-साथ विदेशी मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सुविधा उपलब्ध कराई।

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 02 अक्टूबर 2020 को क्यीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आयोजित समारोह में यूक्रेन के प्रथम उप विदेश मंत्री एमिन ज़ापारोवा मुख्य अतिथि रहे। अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क के क्षेत्र को और अधिक विस्तार देने के लिए 14 अक्टूबर 2020 को भारत तथा यूक्रेन ने एक एयर बबल प्रबंध की शुरुआत की।

उज़बेकिस्तान



11 दिसम्बर 2020 को भारत-उज़बेकिस्तान आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने व्यापार, निवेश तथा संपर्क संबंधी मामलों पर चर्चा के लिए 21 अप्रैल 2020 को उज़बेकिस्तान के निवेश तथा विदेशी आर्थिक मामलों के उप प्रधानमंत्री सर्दोर उमूर्जाकोव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की।

महामारी लासदी के दौरान जारी सहयोग, द्विपक्षीय संबंधों तथा अफगानिस्तान में घटनाक्रम पर चर्चा के लिए विदेशी मंत्री ने उज़बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ 08 मई 2020 को दूरभाष पर बात की। विदेशी मंत्री ने मास्को में 10 सितम्बर 2020 को एस सी ओ विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के अवसर पर उज़बेक विदेश मंत्री के साथ मुलाकात की।

द्विपक्षीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जाँच के लिए भारत तथा उज़बेकिस्तान की अपनी-अपनी राष्ट्रीय समन्वयन समितियों की पहली बार हुई संयुक्त बैठक राज्य मंत्री तथा उज़बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री सर्दोर उमूर्जाकोव की सह-अध्यक्षता में 24 अगस्त 2020 को डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में आयोजित की गई।

शंघाई सहयोग संगठन (एस सी ओ)

15 जून 2001 को स्थापित की गई शंघाई क्रोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन(एस सी ओ) एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जून 2017 में अस्ताना में हैड ऑफ स्टेट कौंसिल की बैठक के दौरान संगठन के पूर्ण सदस्य का स्तर भारत गणराज्य को प्रदान किया गया। अपनी अध्यक्षता के एक वर्ष

उज़बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुल अज़ीज़ कमिलोव ने विदेशी मंत्री द्वारा अध्यक्षता वाली द्वितीय भारत-मध्य एशिया वार्ता में वर्चुअली भाग लिया।

अप्रैल 2020 में भारत ने उज़बेकिस्तान को कोविड-19 के खिलाफ उसकी लड़ाई में हाईड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा भेंट की। मई-सितम्बर 2020 के दौरान भारत द्वारा ई-आई टी सी कार्यक्रम संचालित किए गए जिनमें उज़बेकिस्तान के चिकित्सा व्यवसायियों ने भाग लिया।

विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के अंतर्गत अप्रैल 2020 में बुखारा राज्य विश्वविद्यालय में भारतीय मल्टीमीडिया शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने वाला एक इंडिया रूम खोला गया है।

अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान उज़बेकिस्तान ने “उज़बेकिस्तान एयरवेज़” की 7 विशेष उड़ानों का प्रबंध किया जिससे उज़बेकिस्तान में फंसे 624 भारतीय नागरिकों की वापसी में सहायता मिली। इन उड़ानों ने भारत में फंसे उज़बेक नागरिकों को उनके देश वापस जाने में भी सहायता की।

पूरा होने पर 30 नवम्बर 2020 को भारत ने सरकार के प्रमुखों की एस सी ओ परिषद की 19वीं बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता उप राष्ट्रपति द्वारा की गई। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सदस्य राष्ट्रों द्वारा कई बैठकें आभासी रूप से की गईं।



उप राष्ट्रपति ने 30 नवम्बर 2020 को सरकार के प्रमुखों की एस सी ओ परिषद के 19वें सत्र की अध्यक्षता की

प्रमुख उपलब्धियाँ

30 नवम्बर 2020 को भारत ने सरकार प्रमुखों की एस सी ओ परिषद की 19वीं बैठक आभासी प्रारूप में आयोजित की जिसकी अध्यक्षता उप राष्ट्रपति द्वारा की गई।

13 मई 2020 को विदेशी मंत्री ने विदेशी मामलों के एस सी ओ मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भाग लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस कोविड-19 महामारी लासदी के परिदृश्य में संयोजित की गई तथा चर्चा इसके व्यापारिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिणामों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित रही।

09-10 सितम्बर तक विदेशी मंत्री ने शंघाई क्रोऑपरेशन संगठन की मास्को में आयोजित विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। बैठक में आगामी एस सी ओ शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का परस्पर आदान-प्रदान भी किया गया।

विस्तृत कार्यक्रम

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने 24 जुलाई 2020 को एससीओ सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रियों की 3री बैठक में भाग लिया। भारतीय पक्ष ने एसडीजी-3 की प्राप्ति के लिए एससीओ स्वास्थ्य मंत्री बैठक के अंतर्गत पारम्परिक औषधि का एक नया उप समूह स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।

पहली एससीओ स्टार्ट-अप फोरम के लिए तैयारी सेमिनार 11 अगस्त 2020 को इनवेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। 20-21 अगस्त 2020 को कॉन्सोर्शियम ऑफ इकोनॉमिक थिंक टैंक्स ऑफ एस सी ओ की प्रथम आभासी बैठक सेंटर फॉर रीजनल ट्रेड द्वारा आयोजित की गई।

मास्को ओब्लास्ट के जिला ओडिंसोवस्की में स्थित एक नगर कुबिका में 04 सितम्बर 2020 को आयोजित एस सी ओ, सी आई एस तथा सी एस टी ओ देशों के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक में रक्षा मंत्री ने भारतीय शिष्टमंडल

का नेतृत्व किया। मंत्रियों ने वर्तमान अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा विषयों, युद्ध तथा सशस्त्र संघर्षों को रोकने के प्रयासों के समेकन के साथ-साथ सैनिक सहयोग को और अधिक सशक्त करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

10 सितम्बर 2020 को संस्कृति मंत्री ने 17वीं एस सी ओ संस्कृति मंत्री बैठक में आभासी माध्यम से भाग लिया। प्रतिभागियों ने पूर्व अवधि में संस्कृति एवं कला में सहयोग के विकास पर चर्चा की, पूर्व एस सी ओ संस्कृति मंत्रियों की बैठकों में हम समझौतों के कार्यान्वयन पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा कोरोना वायरस महामारी के दौरान सांस्कृतिक सुविधाओं को सहयोग देने के लिए उनके देशों में किए गए उपायों पर चर्चा की।

15 सितम्बर 2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एस सी ओ की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 15वीं बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। एस सी ओ सदस्य राष्ट्रों के प्रमुखों की परिषद की बैठक के लिए तैयारी में सुरक्षा परिषदों के सचिवों ने एस सी ओ क्षेत्र में सुरक्षा तथा स्थायित्व सुनिश्चित करने के क्षेत्र में परिस्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया।

22 सितम्बर 2020 को आयुष मंत्री ने “एस सी ओ देशों में सतत विकास लक्ष्य (एस डी जी-3) को प्राप्त करने हेतु आयुर्वेद तथा अन्य पारम्परिक औषधि की भूमिका” विषय पर वेबीनार का उद्घाटन किया। मंत्री महोदय ने बल दिया कि पारम्परिक औषधि के क्षेत्र में सहयोग सभी सदस्य राष्ट्रों में स्वास्थ्य प्रोत्साहन तथा रोगों की रोकथाम के लिए निम्न लागत, सुरक्षित तथा प्रभावी कवरेज तक पहुँच करवाने में शक्ति द्विगुणक के रूप में कार्य कर सकता है।

16 अक्टूबर 2020 को विधि एवं न्याय मंत्री ने एस सी ओ सदस्य राष्ट्रों के न्याय मंत्रियों के 7वें सत्र की अध्यक्षता की।

20 अक्टूबर 2020 को 18वीं प्रोजेक्ट्यूट जनरल्स वर्चुअल मीट के दौरान भारत के सोलिसिटर जनरल ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया।

21 अक्टूबर 2020 को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने एस सी ओ

कृषि मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में उन्होंने निरंतर भोजन सुरक्षा तथा किसान कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारत के उपायों का विस्तृत वर्णन किया।

27 अक्टूबर 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने पहला ऑनलाइन एस सी ओ स्टार्ट-अप फोरम का शुभारम्भ किया। फोरम में 60 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया।

28 अक्टूबर 2020 को एस सी ओ परिवहन मंत्रियों की 8वीं आभासी बैठक के दौरान सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

28 अक्टूबर 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने विदेशी आर्थिक एवं विदेशी व्यापार गतिविधियों के लिए उत्तरदायी एस सी ओ सदस्य राष्ट्रों के मंत्रियों की 19वीं वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। शिष्टमंडलों के प्रमुखों ने एस सी ओ के बहुस्तरीय व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 2021-2025 के लिए ड्राफ्ट एक्शन प्लान तथा अन्य परिणामी दस्तावेजों का अनुमोदन किया।

30 नवम्बर 2020 को भारत ने सरकार प्रमुखों की एस सी ओ परिषद की 19वीं बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता उप राष्ट्रपति द्वारा की गई। अपनी वर्ष भर लम्बी अध्यक्षता के भाग के रूप में भारत द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पहलों को काफी सराहना की गई। भारत ने स्टार्ट अप तथा नवोन्मेष पर एक नए विशेष कार्यात्मक समूह के सृजन तथा अध्यक्षता करने और पारम्परिक औषधि में सहयोग पर एक नया विशेषज्ञ कार्यात्मक समूह की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है।

23 नवम्बर 2020 को बी2बी प्रारूप के दौरान फिक्की ने पहली एस सी ओ बिज़नेस कनक्लेव आयोजित की जिसमें एस सी ओ बिज़नेस कौंसिल के राष्ट्रीय अध्ययों के माध्यम से एम एस एम ई में सहयोग पर विशेष बल दिया गया।

24-28 नवम्बर 2020 के दौरान भारत ने वर्चुअल प्रारूप में सर्वप्रथम एस सी ओ यंग साइंटिस्ट कनक्लेव भी आयोजित की जिसमें 200 से अधिक युवा वैज्ञानिकों ने भाग लिया। एस सी ओ इकोनोमिक थिंक टैंक का सर्वप्रथम कौंसोर्शियम तथा सर्वप्रथम एस सी ओ स्टार्ट अप फोरम भी आयोजित किए गए।

6

खाड़ी, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका

आभासी बैठकों और भौतिक यात्राओं के माध्यम से खाड़ी देशों के साथ भारत का संपर्क जारी रहा। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में सऊदी अरब की अध्यक्षता में आभासी जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने महामारी के दौरान जीसीसी के लगभग हर देश के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने नवंबर 2020 में यूएई और बहरीन का दौरा किया और वर्ष के दौरान यूएई के साथ-साथ जीसीसी ट्रोइका के अपने समकक्षों के साथ आभासी बैठकें कीं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कुवैत के अमीर के निधन पर कुवैत को भारत की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए अक्टूबर 2020 में कुवैत का दौरा किया। भारत ने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के यूएई और बहरीन के फैसले का स्वागत किया।

कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष के दौरान भारत और खाड़ी देशों के बीच व्यापार में तेज गिरावट आई थी। हालांकि, पारस्परिक विश्वास था कि व्यापार सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगा और कोविड के बाद ऊपर की ओर बढ़ेगा। भारत ने खाड़ी देशों से निवेश आकर्षित करना जारी रखा और खाड़ी से ऊर्जा का एक बड़ा खरीदार बना रहा। दोनों पक्ष अपने ऊर्जा संबंधों को और मजबूत करने के लिए नए विस्तारों की तलाश करते रहे। खाड़ी देशों में भारतीय श्रमिकों की संख्या में एक संकुचन भी आया क्योंकि महामारी के कारण रोजगार के अवसर कम हो गए थे। हालांकि, खाड़ी देशों और भारत को भरोसा था कि आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद भारतीय कामगार वापस लौट पाएंगे। भारत और खाड़ी देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में विविधता लाने के लिए पारंपरिक

व्यापार और निवेश और सांस्कृतिक संबंध भी जारी रहे, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, अंतरिक्ष और आतंकवाद जैसे रणनीतिक क्षेत्र शामिल हैं।

भारत और जीसीसी ट्रोइका के बीच वार्षिक राजनीतिक वार्ता 3 नवंबर 2020 को, आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री द्वारा किया गया था और जीसीसी का प्रतिनिधित्व ट्रोइका-स्तर पर जीसीसी के महासचिव बहरीन के विदेश मंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। बैठक में सऊदी अरब, कुवैत और कतर के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उन्होंने लंबित एफटीए और एक रणनीतिक साझेदारी के प्रस्ताव सहित सभी क्षेत्रों में फैले अपने संबंधों की विस्तृत समीक्षा की।

9 जनवरी 2021 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन से पहले जीसीसी-भारत पर 11 दिसंबर 2020 को, दो आभासी पैनल चर्चाएं आयोजित की गई थीं। इन पैनल चर्चाओं के विषय थे: (i) भारत और खाड़ी: ऊर्जा भागीदारी, निवेश के अवसर और 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए उभरती प्रौद्योगिकियाँ; तथा (ii) खाड़ी में भारतीयों के लिए भविष्य के कौशल सेट। पहली पैनल चर्चा में भारत और जीसीसी के बीच लोगों से लोगों के बीच के ऐतिहासिक संबंधों और उत्कृष्ट राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के उन तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई, जिनका 5 ट्रिलियन की अर्थ व्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर एक आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में योगदान करने के

लिए उपयोग किया जा सकता है। ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। जीसीसी में बड़े और सफल भारतीय प्रवासी इस दृष्टि को साकार करने में जो भूमिका निभा सकते हैं, पस चर्चा पर भी चर्चा हुई। दूसरी पैनल चर्चा में खाड़ी क्षेत्र में तकनीकी विकास और आर्थिक परिवर्तनों की गति को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्यबल के कौशल सेटों के सामंजस्य पर बात की गई। इसमें भारत सरकार द्वारा विशेष

रूप से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों पर भी चर्चा हुई। भारत के पैनल सदस्यों के अलावा चर्चा में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई के पैनल सदस्यों ने भी भाग लिया था।

बहरीन

भारत-बहरीन के सभ्यतागत संबंध, सदियों पुराने सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध और लोगों से लोगों के बीच के संपर्क भारत-बहरीन द्विपक्षीय संबंधों की विशेषता है। बहरीन में बड़े पैमाने पर भारतीय समुदाय की उपस्थिति द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बनी हुई है। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री की बहरीन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद, दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध और बढ़े हैं। रक्षा और समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फिनटेक, आईटी और सौर/नवीकरणीय ऊर्जा सहित सहयोग के नए क्षेत्रों को शामिल करने से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में विविधता आई है। 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार

1 बिलियन अमरीकी डॉलर के करीब था, जिसमें भारत से बहरीन के लिए निर्यात 550 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक था और बहरीन से 400 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का आयात किया गया था।

वर्ष के दौरान उच्च स्तर की राजनीतिक बातचीत जारी रही। 06 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री और बहरीन के शाह ने टेलीफोन पर बात की, जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। शाह ने दोनों देशों को बांधने वाले प्रतिष्ठित संबंधों की सराहना की, उन्हें रणनीतिक, गहरी जड़ों वाले और सामान्य हितों के साथ-साथ आपसी सम्मान और समझ के आधार पर बने संबंध कहा। शाह

ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में इसके रचनात्मक योगदान की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 का मुकाबला करने में सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के महामारी से निपटने के लिए सभी सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए प्रयासों की सराहना की।

विदेश मंत्री ने 3 अप्रैल 2020 को, बहरीन के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बात की और दोनों देशों के साझा हितों के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने राज्य में भारतीय समुदाय को निरंतर देखभाल प्रदान करने के लिए बहरीन सरकार के प्रति भारत का आभार व्यक्त किया और कोविड-19 का मुकाबला करने के उनके निरंतर प्रयासों में बहरीन द्वारा प्राप्त सफलता की सराहना की।

11 नवंबर 2020 को बहरीन के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल-खलीफा, दुनिया के सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक और बहरीन के शासक परिवार में एक प्रमुख व्यक्ति का निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने बहरीन के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शाह को शोक संदेश भेजा।



विदेश मंत्री ने 25 नवंबर 2020 को मनामा में क्राउन प्रिंस, डिप्टी सुप्रीम कमांडर और किंगडम ऑफ बहरीन के प्रधानमंत्री से भेंट की

विदेश मंत्री ने 24-25 नवंबर, 2020 को बहरीन की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने एचआरएच प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा, क्राउन प्रिंस और बहरीन के प्रधानमंत्री से भेंट की; शेख अली बिन खलीफा अल खलीफा, बहरीन के उप प्रधानमंत्री और अपने समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने बहरीन के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार की संवेदना व्यक्त की।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, 36,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को एयर इंडिया की 127 विशेष उड़ानों और 115 गल्फ एयर की विशेष उड़ानों के माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में वापस लाया गया। 11 सितंबर, 2020 को भारत और बहरीन के बीच एयर बल की व्यवस्था शुरू की गई थी। एयर बल व्यवस्था के संचालन के बाद 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों ने भारत से बहरीन की यात्रा की। बहरीन ने कोविड-19 से लड़ने में भारतीय समुदाय को चिकित्सा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की। बहरीन को सक्रिय कोविड रोगियों के लिए अपने उपचार प्रोटोकॉल में उपयोग के लिए, अप्रैल 2020 में भारत से 1.5 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियों

इराक

भारत और इराक ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को साझा करते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इराक एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। यह पिछले तीन वर्षों के लिए भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और कच्चे तेल के बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। 2019-20 के दौरान भारत-इराक द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज करते हुए 25.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। तेल आयात में लगभग 88% द्विपक्षीय व्यापार होता है। अप्रैल-अक्टूबर 2020 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 7.41 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें अप्रैल 2020 के महीने में कोविड-19 महामारी कच्चे तेल की कम खपत के कारण कमी आई है।

मिशन के साथ पंजीकृत सभी 8253 भारतीयों को अप्रैल 2020-जनवरी 2021 के दौरान वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सुविधा प्राप्त चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया गया था। भारत और इराक ने सितंबर 2020 में कोविड-19 के मद्देनजर हवाई यात्रा की सुविधा के लिए एयर बल की

कुवैत

दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध वर्ष के दौरान बढ़ते रहे और कोविड-19 महामारी ने दोनों देशों को चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट किया। भारत ने कुवैत के अमीर, शेख सबा अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कुवैत के नेतृत्व को शोक संदेश भेजे। भारत में 04 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय शोक मनाया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 11-12 अक्टूबर को कुवैत का दौरा किया, जिसमें भारत की ओर से कुवैत के नए अमीर शेख नवाफ अल-आमद अल-जबर अल-सबाह से संवेदना व्यक्त की गई।

जैसा कि शेख नवाफ अल-अमेद अल-जबर अल-सबाह ने कुवैत के अमीर का

की एक खेप भी मिली। दोनों पक्षों ने कोविड-19 वैक्सीन में सहयोग की संभावनाओं, विशेष रूप से भारत में बहरीन में विकसित किए जा रहे टीकों की आपूर्ति के लिए बात की।

बहरीन में भारतीय दूतावास द्वारा विभिन्न भारतीय सामुदायिक संगठनों और भारतीय और बहरीन के योग चिकित्सकों के सहयोग से आभासी मंचों पर छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

जनवरी-मार्च 2021 के दौरान होने वाली अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारत और बहरीन के बीच तीसरी एचजेसी बैठक मार्च 2021 में नई दिल्ली में होने वाली है।
- फरवरी/मार्च 2021 में बहरीन में नौसेना स्टाफ (सीएनएस) के प्रमुख का दौरा।

व्यवस्था में प्रवेश किया। भारत चिकित्सा उपचार से कराने के लिए इराकियों का एक पसंदीदा स्थान बना रहा और 2019-20 में जारी किए गए 48,000 मेडिकल वीजा की तुलना में लगभग 8354 चिकित्सा वीजा जारी किए गए थे। लगभग 30,000-40,000 भारतीय, जो प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा के लिए इराक में बगदाद, कर्बला, नजफ और समराह जाते थे, 2020 में अशुरा की अवधि में केवल 575 तीर्थयात्री कर्बला गए।

भारत ने क्षमता निर्माण में इराक की सहायता करना जारी रखा। वर्ष 2020-21 के लिए, आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 200 स्लॉट आवंटित किए गए थे। इराकी अधिकारियों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी प्रबंधन पर ऑनलाइन ई-आईटीईसी कार्यक्रमों में भाग लिया। छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी जयंती कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाये गये। इराक के संस्कृति, पर्यटन और पुरावशेष मंत्री महात्मा गांधी की दो वर्ष लंबी 150 वीं जयंती समारोह की परिणति के भव्य समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे।

पद ग्रहण किया और शेख मिशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने कुवैत के क्राउन प्रिंस का पद ग्रहण किया। प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें बधाई संदेश भेजे गए।

अप्रैल 2020 में, प्रधानमंत्री ने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा खालिद अल-हमद अल-सबाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आपसी प्रयासों, परस्पर-चर्चा की। विदेश मंत्री ने अप्रैल 2020 में, टेलीफोन पर कुवैत के विदेश मंत्री, शेख अहमद नासिर अल-मोहम्मद अल-सबाह के साथ कोविड-19 के बारे में बातचीत की। जुलाई 2020 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री और खालिद नासिर अल-रौदन, कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री के बीच एक आभासी बैठक हुई।

कोविड-19 के प्रसार से लड़ने के लिए कुवैत सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए,

15-सदस्यीय भारतीय त्वरित प्रतिक्रिया टीम को, अप्रैल 2020 में दो सप्ताह की अवधि के लिए कुवैत में तैनात किया गया था, इस टीम में डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर शामिल थे। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, 31 अक्टूबर

2020 तक, 100,000 से अधिक भारतीयों को कुवैत से भारत में प्रत्यावर्तन की सुविधा दी गई थी और उनके प्रत्यावर्तन को भी एमनेस्टी लाभार्थियों के लिए संचालित विशेष उड़ानों में पूरा किया गया था। सितंबर 2020 में, मिशन ने “आत्मानिर्भर भारत” की थीम के अंतर्गत व्यावसायिक प्रचार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की।

ओमान

भारत और ओमान हजारों वर्षों के ऐतिहासिक संपर्कों में निहित मित्रता के गहरे बंधन साझा करते हैं। यह संबंध अब एक जीवंत और बहुमुखी रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो गया है। हाल के वर्षों में उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान ने व्यापार और वाणिज्य, रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में मदद की है।

लंबे समय तक ओमान के शासक और भारत-ओमान रणनीतिक साझेदारी के वास्तुकार, स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद का लंबी बीमारी के बाद 10 जनवरी 2020 को निधन हो गया। 11 जनवरी 2020 को सुल्तान हैथम बिन तारिक को ओमान का नया सुल्तान घोषित किया गया। सुल्तान हैथम बिन तारिक फरवरी 2002 से विरासत और संस्कृति मंत्री थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने 14 जनवरी 2020 को ओमान का दौरा किया और सरकार और भारत के लोगों की ओर से सुल्तान कबूस के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारत सरकार ने भी दिवंगत गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 13 जनवरी 2020 को एक दिन के आधिकारिक शोक की घोषणा की।

कोविड-19 महामारी ने भारत-ओमान संबंधों के लचीलेपन का प्रदर्शन किया।

कोविड-19 के चरम लॉकडाउन के समय भी, जब दुनिया भर में आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुईं, भारत और ओमान के बीच आपूर्ति श्रृंखला कार्यात्मक रही। दोनों देशों ने संबंधित नागरिकों के प्रत्यावर्तन में सहयोग किया। ओमान ने भारत से 1 मिलियन हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) टैबलेट खरीदे और जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें गंभीर रूप से बाधित हुईं तब भारत ने ओमान को भारतीय स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को वापसी की सुविधा प्रदान की। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2020 में सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की और साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की।

विदेश मंत्री ने अगस्त 2020 में नव नियुक्त विदेश मंत्री, सैय्यद बदन बिन हमद बिन हमद अल बसैदी को फोन किया और उनकी नियुक्ति पर बधाई दी तथा द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री, अहमद मोहम्मद अल सईदी और भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सितंबर 2020 में टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 का मुकाबला करने में सहयोग पर चर्चा की।



राज्य मंत्री ने 16 दिसंबर 2020 को मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री से भेंट की

एक अक्टूबर 2020 में संयुक्त आयोग की एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता कायस बिन मोहम्मद अल युसेफ, वाणिज्य

मंत्री, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन ओमान और केंद्रीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय; नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य

मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी। जेसीएम ने आर्थिक, व्यापार, निवेश और सेवा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापार विनिमय बढ़ाने पर चर्चा की। जेसीएम को सालाना आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

स्वास्थ्य, कोविड-19 वैक्सीन विकास सहित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 2 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्री और ओमान के विदेश मंत्री सैय्यद बदन बिन हमद बिन हमद अलबुसैदी के बीच एक आभासी बैठक आयोजित की गई थी।

राज्य मंत्री ने 16 से 17 दिसंबर 2020 तक ओमान सलतनत की आधिकारिक यात्रा की और ओमान के विदेश मंत्री, श्रम मंत्री और वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री से भेंट की।

भारत ओमान रणनीतिक सलाहकार समूह की बैठक का सातवां सत्र 14 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सचिव (सीपीवी) और ओआईएफ ने किया था। ओमान के विदेश मंत्रालय के राजनयिक मामलों के अवर सचिव, शेख खलीफा बिन अली अल-हर्थी, ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी भेंट की।

कतर

कतर के साथ भारत के गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंध पिछले कुछ वर्षों में उत्तरोत्तर मजबूत हुए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण, द्विपक्षीय आदान-प्रदान की गति को आभासी मोड़ में बनाए रखा गया था। प्रधानमंत्री ने 26 मार्च 2020 और 26 मई 2020 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी के साथ टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और कोविड-19 का मुकाबला करने

कोविड की चरम अवधि के दौरान, भारत ने ओमान की स्वास्थ्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों को भारत से ओमान वापसी की सुविधा प्रदान की।

ओमान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन, जिसमें प्रमुख ओमानी और भारतीय मूल के व्यवसायी शामिल हैं, नवंबर 2020 में स्थापित किया गया था। ओमान ने दिसंबर 2020 में भारतीय पासपोर्ट धारकों की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की भी घोषणा की।

ओमान इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। इसने समुद्री परिवहन समझौते (दिसंबर 2019 में हस्ताक्षरित), भारत और ओमान के बीच नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी और न्यायिक सहयोग पर समझौता (फरवरी 2018 में हस्ताक्षरित) और राजनयिक, विशेष और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए आपसी वीजा छूट पर समझौता किया। (फरवरी 2018 में हस्ताक्षर किए गए)।

रक्षा सहयोग मजबूत बना रहा, भारतीय नौसेना के कई जहाजों ने संचालन बदलाव के लिए विभिन्न ओमानी बंदरगाहों का दौरा किया।

और वायरस का प्रसार को रोकने के लिए दोनों देशों के प्रयासों और सहयोग करने के तरीकों पर चर्चा की।

विदेश मंत्री ने अपने कतर के समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ 24 अप्रैल 2020 को टेलीफोन



विदेश मंत्री ने दोहा में कतर के अमीर से भेंट की, 28 दिसंबर 2020

पर बात की और कोविड-19 के प्रसार में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने 12 सितंबर 2020 को दोहा में आभासी प्रारूप में आयोजित इट्रा-अफगान वार्ता के उद्घाटन सत्र में भाग लिया और एक बयान दिया।

विदेश मंत्री ने 27 और 28 दिसंबर 2020 को कतर की दो दिवसीय यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने कतर के अमीर और पिता अमीर के साथ-साथ कतर राज्य के प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ विस्तृत चर्चा की।

वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार की कुल मात्रा 10.94 बिलियन अमरीकी डॉलर थी जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11% कम थी। भारत से कतर को निर्यात 1.26 बिलियन अमरीकी डॉलर और भारत से कतर का आयात 9.68 बिलियन अमरीकी डॉलर था। कतर के संप्रभु धन कोष, कतर इन्वेस्टमेंट

अथॉरिटी (क्यूआईए), ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में 25.1% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए 450 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया। क्यूआईए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंसूर बिन अब्राहिम अल-महमूद ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और 5 नवंबर 2020 को वित्त और राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंडटेबल में भाग लिया।

सेरा वीक द्वारा भारत एनर्जी फोरम के चौथे संस्करण के हाशिये पर, ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री और कतर पेट्रोलियम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साद शेरिदा अल-काबी ने 26 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक आभासी बातचीत सत्र आयोजित किया।



विदेश मंत्री ने 28 दिसंबर 2020 को दोहा में कतर के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भेंट की

वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार की कुल मात्रा 10.94 बिलियन अमरीकी डॉलर थी जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 11% कम थी। भारत से कतर को निर्यात 1.26 बिलियन अमरीकी डॉलर और भारत से कतर का आयात 9.68 बिलियन अमरीकी डॉलर था। कतर के संप्रभु धन कोष, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (क्यूआईए), ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड में 25.1% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए 450 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया। क्यूआईए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंसूर बिन अब्राहिम अल-महमूद ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और 5 नवंबर 2020 को वित्त और राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स राउंडटेबल में भाग लिया।

सेरा वीक द्वारा भारत एनर्जी फोरम के चौथे संस्करण के हाशिये पर, ऊर्जा मामलों के राज्य मंत्री और कतर पेट्रोलियम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री साद शेरिदा अल-काबी ने 26 अक्टूबर 2020 को हमारे प्रधानमंत्री के साथ एक आभासी बातचीत सत्र आयोजित किया।

नीति आयोग के अधिकारी और कतर के कोविड-19 पर नेशनल स्ट्रेटेजिक

ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल्लातिफ अल-खल ने 27 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 के लिए अनुसंधान, निदान, चिकित्सा और वैक्सीन विकास के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर एक आभासी बैठक की।

प्रधानमंत्री ने 8 दिसंबर 2020 को, कतर राज्य के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने भारत में कतर निवेश प्राधिकरण द्वारा निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक विशेष टास्क-फोर्स बनाने का फैसला किया और भारत में संपूर्ण ऊर्जा मूल्य-श्रृंखला में कतर के निवेश का पता लगाने का भी संकल्प लिया।

प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को, मंसूर बिन अब्राहिम, अल-महमूद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कतर निवेश प्राधिकरण के साथ एक आभासी बैठक की और क्यूआईए के लिए भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री की 10 दिसंबर, 2020 को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद, विदेश मंत्री ने कतर के उप प्रधानमंत्री और विदेश मामलों के मंत्री, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल-थानी से टेलीफोन पर बात की।

11 दिसंबर 2020 को, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भारत में संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में कतरी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कतर के ऊर्जा राज्य मंत्री और कतर पेट्रोलियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष, साद शेरिदा अल-काबी के साथ टेलीफोन पर बात की थी।

भारत और कतर के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का चौथा दौर 01 फरवरी 2021 को आयोजित किया गया था।

श्रम और जनशक्ति विकास पर भारत-कतर संयुक्त समिति की छठी बैठक 09 दिसंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी।

भारत और कतर के बीच सहयोग और कानून प्रवर्तन मामलों पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक फरवरी 2021 में आभासी प्रारूप में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

सऊदी अरब

अक्टूबर 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा सऊदी अरब की यात्रा के दौरान प्रदान किए गए प्रोत्साहन के बाद, भारत और सऊदी अरब के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध एक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं और आभासी बैठकों और वाणिज्यिक आदान-प्रदान की बढ़ती आवृत्ति से ये संबंध और मजबूत हुए हैं जो कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी के बावजूद जारी है।

दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक, सऊदी अरब के राजा सलमान ने 09 और 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री को फोन किया। नेताओं ने पारस्परिक हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास के अलावा द्विपक्षीय संबंधों और जी 20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा की। 22 जुलाई 2020 को, सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने विदेश मंत्री को फोन किया। उन्होंने दोनों मिल देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। 24 सितंबर को, दोनों मंत्रियों ने फिर से सभी क्षेत्रों में संयुक्त सहयोग पर चर्चा की, जिसमें जी-20 एजेंडे के साथ-साथ पारस्परिक चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए 12 जून और 05 अगस्त को अपने सऊदी समकक्ष डॉ. माजिद अल कासबी से टेलीफोन पर बात की।

प्रधानमंत्री ने 21 नवंबर 2020 को 15 वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इस वर्ष जी-20 के सफल अध्यक्ष बनने के लिए राज्य को बधाई दी और महामारी को मानवता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ करार दिया।

सेना प्रमुख ने 12-14 दिसंबर 2020 तक रियाद का दौरा किया। यह भारतीय सीओएएस द्वारा सऊदी अरब की पहली यात्रा थी।

04 जनवरी को, विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के साथ बात की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

रणनीतिक भागीदारी परिषद (एसपीसी) की आर्थिक और निवेश समिति के 2 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक मार्च 2021 से पहले होने की आशा है, जिसके बाद इस समिति की मंत्रिस्तरीय व्यस्तता आरंभ होगी।

जनवरी-मार्च 2021 के दौरान रणनीतिक भागीदारी परिषद की राजनीतिक-सुरक्षा-सामाजिक-सांस्कृतिक समिति के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें होने की आशा है।

कोविड-19 महामारी के कारण, दिसंबर 2020 तक वंदे भारत मिशन की उड़ानों से 1 लाख से अधिक भारतीयों को कतर से भारत वापस लाया गया है। 18 अगस्त 2020 से दोनों ओर की उड़ानों के लिए भारत और कतर के बीच एयर बबल की व्यवस्था की जा रही है।

कतर में 700,000 से अधिक का भारतीय समुदाय, सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। दिसंबर 2020 तक, मिशन ने कुल 83,320 राजनयिक संबंधित सेवाएं प्रदान कीं, जिसमें पासपोर्ट जारी करना/नवीनीकरण, विविध कांसुलर सेवा और वीजा/ओसीआई संबंधित सेवाएं शामिल हैं। तत्काल श्रम और राजनयिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए मासिक ओपन हाउस को आभासी आयोजन किया जाता है और समुदाय की शिकायतों को उपयुक्त तरीके से संबोधित किया जाता है।

सऊदी अरब 2.6 मिलियन भारतीय प्रवासियों का घर है और भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत के विस्तारित पड़ोस में एक महत्वपूर्ण भागीदार होने के नाते, सऊदी अरब ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय प्रवासियों की देखभाल की। अक्टूबर 2020 के अंत तक, लगभग 232,500 भारतीयों को सऊदी अरब से भारत वापस लाया गया था। इसमें 276 वीबीएम उड़ानों में 47,000 लोग और 1011 चार्टर उड़ानों में आए 183,000 लोग शामिल थे। सऊदी सरकार के समन्वय के साथ, 2199 भारतीय निर्वासितों को सऊदी एयरलाइंस की 8 विशेष उड़ानों द्वारा भारत में वापस लाया गया।

अक्टूबर 2019 की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान रणनीतिक भागीदारी परिषद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, परिषद के दो वर्टिकल यानी आर्थिक और राजनीतिक ने अपनी संबंधित संरचनाओं को औपचारिक रूप देना शुरू कर दिया। आर्थिक और निवेश ऊर्ध्वधर को अंतिम रूप दिया (i) कृषि और खाद्य सुरक्षा; (ii) ऊर्जा; (iii) प्रौद्योगिकी और आईटी; तथा (iv) अपने चार संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) के रूप में उद्योग और बुनियादी ढांचा। नीति-आयोग और एससीआईएसपी ने वरिष्ठ अधिकारियों-स्तर और संयुक्त कार्य-समूह, दोनों स्तरों पर नियमित बातचीत की। समिति के पहले वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) जुलाई 2020 में आयोजित की गई थी और दूसरा एसओएम नवंबर 2020 के लिए निर्धारित था।

राजनीतिक-सुरक्षा-सामाजिक-सांस्कृतिक (पीएसएससी) समिति ने चार जेडब्ल्यूजी: (i) राजनीतिक; (ii) सुरक्षा; (iii) संस्कृति; तथा (iv) शिक्षा को अंतिम रूप दिया। राजनीतिक-सुरक्षा-सामाजिक-सांस्कृतिक (पीएसएससी) समिति के वरिष्ठ अधिकारियों की उद्घाटन बैठक 2020 के अंत तक आयोजित होने की आशा है।

छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया और इस अवसर पर आयुष मंत्री की भागीदारी सहित एक वेबिनार के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सऊदी अरब के दो अधिकारियों ने वर्ष के दौरान रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और अन्य दो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद के पाठ्यक्रम में भाग लिया।

संयुक्त अरब अमीरात

व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर के साथ, भारत और यूएई के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को द्विपक्षीय आदान-प्रदान द्वारा और मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री ने 25 मई 2020 को 'ईद-उल-फितर' के अवसर पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (एमबीजेड) को फोन किया और क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय विकास की एक सारणी पर चर्चा की, मुख्य रूप से कोविड-19 की वैश्विक महामारी और इसे रोकने तथा इसके खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया।

विदेश मंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान (एबीजेड) के साथ टेलीफोन पर बात की, जिसमें दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने मजबूत भारत-यूएई संबंधों की सराहना की और विशेष रूप से यूएई की "इसके दृष्टिकोण को विशेष बनाने वाली आत्मा की उदारता और नीति की स्पष्टता।" की प्रशंसा की। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए 8 जून 2020 को यूएई के विदेश मंत्री के साथ फिर से आभासी चर्चा की। यूएई के विदेश राज्य मंत्री अनवर गर्गश ने 08 अक्टूबर को दुबई में अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान विदेश मंत्री के साथ चर्चा की।

द्विपक्षीय सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र के स्तर पर, भारत और यूएई ने भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक (जेसीएम) और भारत-यूएई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की आठवीं बैठक (एचएलटीएफआई) आयोजित की। जेसीएम का 13वां सत्र, 17 अगस्त 2020 को यूएई के विदेश मंत्री और विदेश मंत्री की सह-अध्यक्षता में आभासी रूप से आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में द्विपक्षीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र में सहयोग और अन्य बहुपक्षीय मंचों और निवेश जेसीएम में चर्चा के प्रमुख मुद्दों में शामिल थे।

एचएलटीएफआई की आठवीं बैठक 3 नवंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री और अबू धाबी के कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान ने की। भारत और यूएई विशेष रूप से कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर आर्थिक विकास की संभावनाओं वाले प्रमुख भारतीय और यूएई क्षेत्रों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए। यूएई-आधारित फंडों द्वारा निवेश और नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य और कृषि, ऊर्जा और

यमन

भारत और यमन, करीबी और ऐतिहासिक लोगों से लोगों के संपर्क के लंबे इतिहास का आनंद लेते हैं। यमन में राजनीतिक और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने के कारण, 14 अप्रैल 2015 से भारत के यमन के दूतावास को अस्थायी रूप से जिबूती में स्थानांतरित कर दिया गया है। दूतावास ने वर्ष के दौरान जिबूती में अपने कैम्प कार्यालय से अपनी सेवाएं देना जारी रखा।

उपयोगिताओं में सहयोग बैठक में चर्चा के अन्य प्रमुख बिंदु थे।

संस्कृति मंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्ष, नौरा अल काबी के साथ 28 अप्रैल 2020 को टेलिफोन से बातचीत की, कोविड-19 से निपटने के लिए संबंधित सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर विशिष्ट जोर देने के साथ संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

विदेश मंत्री 25-26 नवंबर, 2020 को यूएई की 2-दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए थे। विदेश मंत्री ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद, और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद से भेंट की। यूएई के नेतृत्व के साथ बैठक के दौरान, विदेश मंत्री ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने सेशेल्स से वापस आते समय 29 नवंबर 2020 को दुबई के शासक और यूएई के प्रधान मंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद से भेंट की और चल रहे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

शिक्षा मंत्री ने यूएई के अपने समकक्ष, हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी के साथ 09 दिसंबर 2020 को एक आभासी बैठक की, जिसमें भारत और यूएई के बीच शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई।

राज्य मंत्री ने 19-21 जनवरी 2021 को यूएई का दौरा किया और भारतीय प्रवासी तथा यूएई सरकार के उनके समकक्षों और विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।

यूएई के अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने की दिशा में पहल और प्रयास किए, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग, भारत-यूएई द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक अन्य क्षेत्र के रूप में उभरा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत और यूएई के बीच बढ़ते सहयोग के परिणामस्वरूप यूएई ने भारत को सात टन चिकित्सा आपूर्ति का समर्थन दिया और भारत ने बदले में संयुक्त अरब अमीरात की स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने के लिए भारत के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को अमीरात की स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल होने की अनुमति देकर मदद की। दुनिया भर में फँसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, भारत सरकार ने 07 मई 2020 को अबू धाबी से कोच्चि के लिए 'वंदे भारत मिशन' शुरू किया। भारत ने जुलाई 2020 में यूएई के साथ एक एयर बबल की व्यवस्था बनाई, जिसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया। अक्टूबर 2020 तक, 600,000 से अधिक भारतीयों ने संयुक्त अरब अमीरात से भारत की यात्रा की थी।

भारत ने आशा जताई कि यमन में संघर्ष करने वाले पक्ष शांति के लिए व्यापक युद्ध विराम की बातचीत को फिर से शुरू कर पाएंगे। भारत ने अतीत की तरह अब भी यमन को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

जीसीसी



03 नवंबर 2020 को आयोजित भारत-जीसीसी राजनीतिक वार्ता

भारत और जीसीसी ट्रोइका ने अपनी वार्षिक राजनीतिक वार्ता 03 नवंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आयोजित की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया था। जीसीसी का प्रतिनिधित्व ट्रोइका स्तर पर जीसीसी के महासचिव, नायेफ फतह एम. अल-हज़रफ़, बहरीन के विदेश मंत्री, अब्दुल लतीफ बिन रशीद अल ज़ायनी और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री, अनवर बिन मोहम्मद गर्गश द्वारा किया गया था। बैठक में सऊदी अरब, कुवैत और कतर के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

नेताओं ने भारत-जीसीसी संबंधों की विस्तृत समीक्षा की और पिछले कुछ

ईरान

भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंध वर्ष 2020-21 के दौरान मैत्री, सौहार्दपूर्ण और सहकारी बने रहे। रक्षा मंत्री ने 05 सितंबर 2020 को ईरान का दौरा किया और ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी से भेंट की। विदेश मंत्री ने 09 सितंबर 2020 को ईरान का दौरा किया और अपने समकक्ष जवाद ज़रीफ़ के साथ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार और कनेक्टिविटी परियोजनाओं से संबंधित मामले पर भी चर्चा की।

विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री ज़रीफ़ ने 13 अप्रैल 2020 को टेलीफोन पर भी बात की और क्षेत्रीय विकास पर विचारों के आदान-प्रदान के साथ कोरोना वायरस की संबंधित प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की।

वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ है, जिसे चल रही कोविड-19 महामारी के कारण सीमित तरीके से मनाया गया था।

भारत-ईरान द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल-सितंबर 2020 की अवधि में 1.12 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 64.8% कम है। व्यापार में भारत के कृषि निर्यात का वर्चस्व था। जिन कदमों ने द्विपक्षीय वाणिज्यिक और व्यापारिक जुड़ाव को आगे बढ़ाया, उनमें सितंबर

वर्षों में संबंधों में देखे गए ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र की सराहना की। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि भारत और जीसीसी देशों ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपना करीबी सहयोग जारी रखा है। विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि बड़ी संख्या में भारतीय कामगार और पेशेवर अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए जीसीसी देशों में लौटने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने जीसीसी नेतृत्व से भारत के साथ टिकाऊ यात्रा बुलबुले की व्यवस्था के माध्यम से इसे सुविधाजनक बनाने का आग्रह किया। नेताओं ने आपसी चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का भी आदान-प्रदान किया।

2020 में ईरान की मजलिस द्वारा दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डीटीएए) का अनुसमर्थन शामिल है, जो प्राइमरी ट्रेड एग्रीमेंट (पीटीए) पर उन्नत चर्चा और ईरान और भारत द्वारा के चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की गतिविधि शामिल है।

चाबहार बंदरगाह, कोविड महामारी के दौरान क्षेत्र के लिए मानवीय सहायता देने के लिए "कनेक्टिंग पॉइंट" के रूप में उभरा है। चाबहार बंदरगाह कूटनीति में हमारे लोगों के केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतीक है। भारत ने सितंबर 2020 में चाबहार के माध्यम से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में दिए गए 75,000 मीट्रिक टन गेहूँ की पूरी खेप भेज दी। चाबहार पोर्ट में थोक और सामान्य कार्गो ट्रेफ़िक (12,399 टीईयू से अधिक) और 31 अक्टूबर, 2020 तक क्रमशः 1.54 मिलियन टन से अधिक की निरंतर वृद्धि देखी गई। जून 2020 में, चाबहार ने भारतीय बंदरगाहों के लिए 30 प्रशिक्षित कंटेनर और नौ पारंपरिक कंटेनर (कुल 76 टीईयू) लोड किए। यह एक एकल रिकॉर्ड लोडिंग और चाबहार पोर्ट के विकास पथ में एक मील का पत्थर है। इस बंदरगाह का उपयोग पहली बार दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए किया गया है। सूखे फलों की अफगानिस्तान की पहली पारगमन शिपमेंट चीन में तियानजिन पोर्ट तक पहुंची और ईरान के जलीय उत्पादों की पहली खेप चाबहार पोर्ट के माध्यम से थाईलैंड भेजी गई।

इस वर्ष, ईरान ने पिछले 25 वर्षों में सबसे खराब टिड्डों आक्रमण का अनुभव किया। भारत ने जून 2020 में लगभग 25 मीट्रिक टन मैलाथियान (95 प्रतिशत यूएलवी) की आपूर्ति की, ताकि टिड्डों के खतरे को नियंत्रित करने में मदद मिल सके। इस सहायता ने न केवल ईरानियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि ईरान से पाकिस्तान के रास्ते टिड्डियों के भारत में प्रवास को भी सीमित किया। मैलाथियान एक पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक है जिसका उपयोग कम से कम पानी के साथ किया जा सकता है और यह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त है।

दिसंबर 2020 में चाबहार पोर्ट पर 20 मीट्रिक टन मैलाथियॉन (95% यूएलवी) के दूसरे बैच के पहुंचने की आशा है।

कोविड-19 के खिलाफ हमारी संयुक्त लड़ाई में, भारत ने अप्रैल 2020 में रियल टाइम डायग्नोस्टिक पीसीआर अभिकर्मकों, पीसीआर मशीन, जैव-

पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका

पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश कोविड-19 महामारी के तनाव से जूझ रहे हैं, कोविड के मामले रोज बढ़ रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियाँ हैं। इन मिल देशों की पीड़ा को कम करने के लिए, भारत सरकार ने फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान और मिस्र के लोगों के बीच चिकित्सा सहायता भेजी; जॉर्डन, इज़राइल और मिस्र के लिए दवाओं के आयात की सुविधा दी; 04 अगस्त 2020 के बाद में लेबनान में विस्फोट और सूडान में विनाशकारी बाढ़ और सितंबर 2020 में सूडान और दक्षिण सूडान में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद सूडान, दक्षिण सूडान, और जिबूती और इरिट्रिया से अनुरोध पर खाद्य सहायता और राहत सामग्री भेजी। वाना के विभिन्न देशों में फँसे भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत वापस लाया गया।

महामारी के प्रतिबंध के बावजूद, उच्च स्तर की बातचीत ने मिस्र, इज़राइल, जॉर्डन, सीरिया, जिबूती और अल्जीरिया के साथ टेलीफोन कॉल के माध्यम से हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गति को बनाए रखा। द्विपक्षीय मामलों के मंत्री, अफ्रीकी सहयोग और मोरक्को के प्रवासी नासिर बोरिटा के साथ विदेश मंत्री की आभासी बैठक सहित, सीरिया के विदेश मामलों के मंत्री और प्रवासी मेकडैड के साथ राज्य मंत्री की आभासी बैठक; और फिलिस्तीन के साथ विदेश कार्यालय परामर्श द्विपक्षीय बातचीत को आभासी प्रारूप में ले जाया गया। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में 22 सितंबर 2020 को भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 15वें सीआईआई-एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।

अल्जीरिया

भारत और अल्जीरिया के बीच राजनयिक संबंध कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद मैत्री और सौहार्दपूर्ण बने रहे। भारत में फँसे अल्जीरियाई नागरिकों के चिकित्सा सहयोग और निकासी पर चर्चा करने के लिए 09 अप्रैल 2020 को अल्जीरियाई विदेश मंत्री, साबरी बोकादौम और विदेश मंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। अल्जीरिया को पेरासिटामोल एपीआई और

सुरक्षा कैबिनेट, आरएनए निष्कर्षण किट और पीसीआर मशीनों जैसे पीपीई और परीक्षण उपकरणों की आपूर्ति करके ईरान को सहायता प्रदान की। इसके निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद, ईरान को 3 मिलियन अमरीकी डालर के सर्जिकल मास्क की आपूर्ति की गई थी।

ईरान सरकार के सहयोग से, कोविड-19 के कारण ईरान में फँसे 4000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन की विशेष उड़ानों और दो भारतीय नौसैनिक जहाजों, आईएनएस शार्दूल और आईएनएस जलशवा के जरिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु के हिस्से के रूप में वापस लाया गया। भारतीय नागरिकों में 1100 से अधिक तीर्थयात्री शामिल थे, जिनमें ज्यादातर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों के थे। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और गुजरात के 900 से अधिक मछुआरे थे। इसी तरह, महामारी के कारण भारत में फँसे ईरानियों की वापसी की भी व्यवस्था की गई थी।

भारत ने इजरायल और यूएई के देशों (15 सितंबर 2020), बहरीन (18 अक्टूबर 2020) और सूडान (23 अक्टूबर 2020) के बीच संबंधों के सामान्यीकरण का स्वागत किया। 2018 में दक्षिण सूडान में फिर से छिड़े संघर्ष के समाधान के लिए पुनरीक्षित शांति समझौते और अक्टूबर 2020 में सूडान और विद्रोहियों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इस क्षेत्र में स्थायी शांति की शुरुआत होने की आशा है। मार्च 2020 के बाद से सीरिया में संघर्ष विराम और जेनेवा (23 अक्टूबर 2020) में 5 + 5 संयुक्त सैन्य आयोग की वार्ता के अंतर्गत लीबिया में स्थायी रूप से संघर्ष विराम से क्षेत्र में शांति होने की आशा है।

फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन में, 23 जून 2020 को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (यूपनआरडब्ल्यूए) के असाधारण आभासी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान, राज्य मंत्री ने घोषणा की कि भारत आने वाले दो से अधिक वर्षों तक यूपनआरडब्ल्यूए के लिए लगभग 10 मिलियन अमरीकी डॉलर देगा। भारत ने लेबनान (यूपनआईएफआईएल) में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल और दक्षिण सूडान (यूपनएमआईएसएस) में संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी योगदान देना जारी रखा।

छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत का 74वाँ स्वतंत्रता दिवस, महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ का उत्सव और नए आईटीईसी लोगो का अनावरण, हमारे मिशनों द्वारा सभी वाना देशों में स्थानीय समुदायों और भारतीय प्रवासियों के साथ साझेदारी में और स्थानीय कोविड प्रतिबंधों के अनुरूप मनाया गया।

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एपीआई वाणिज्यिक निर्यात को क्रमशः अप्रैल और मई 2020 में मंजूरी दी गई थी। आठ निजी चार्टर्ड उड़ानों ने संकटग्रस्त भारतीयों को अल्जीरिया से भारत लाने के लिए उड़ान भरी। इस अवधि (अप्रैल - नवंबर 2020) में 1600 से अधिक भारतीयों को भारत वापस लाया गया है।

जिबूती

विदेश मंत्री ने अप्रैल 2020 में जिबूती में कोविड की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अपने जिबूती के समकक्ष, विदेश मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री, महमूद अली यूसुफ से टेलीफोन पर बात की थी। अदन की खाड़ी में डकैती विरोधी गश्त के लिए तैनात आईएनएस सुमेधा ने जनवरी 2020 में जिबूती में भारत के नव स्थापित दूतावास के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर जिबूती बंदरगाह का दौरा किया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, इरिट्रिया से भारत

मिस्र

कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद, मिस्र और भारत के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान जारी रहा। प्रधानमंत्री ने 17 अप्रैल 2020 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ कोविड के प्रसार को रोकने के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए और फिर 26 अप्रैल 2020 को ईद-उल-फितर की शुभकामनाओं के आदान-प्रदान के लिए फोन पर बातचीत की। भारत ने 05 मई 2020 और

इरिट्रिया

निदेशक, एआईआईएमएस के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 26-29 जनवरी 2020 को इरिट्रिया का दौरा किया, ताकि इरीट्रिया के चिकित्सकों की क्षमता निर्माण में भागीदारी स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

आईटीईसी/आईएफएस कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत में आयोजित किए गए विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 20 से अधिक इरिट्रियाईयों ने भाग लिया। 6 सातक और सातकोत्तर/पीएचडी पाठ्यक्रमों की आईसीसीआर छात्रवृत्ति के लिए इरिट्रिया को भी नामित किया गया था। इथियोपिया एयरलाइंस द्वारा दिल्ली से अदिस अबाबा और अदीस अबाबा से अस्मारा तक जाने वाली विशेष उड़ानों द्वारा अगस्त 2020 में फँसे हुए इरीट्रिया के तीन छात्रों को इरिट्रिया वापस भेजा गया। इसी तरह, इरीट्रिया में फँसे हुए तीन भारतीय नागरिकों को अगस्त 2020 में इथियोपियाई एयरलाइंस की विशेष उड़ान से दुबई और

के लिए चार्टर्ड उड़ान द्वारा 88 सदस्यीय फिल्म दल सहित कुल 95 भारतीयों को वापस लाया गया, भारत में फँसे 28 जिबूती नागरिकों को भी निकाला गया।

आईएनएस ऐरावत ने जिबूती के लिए एक एचएडीआर मिशन शुरू किया और 10 नवंबर 2020 को जिबूती को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता पहुंचाई।

29 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए मिस्र के प्रयासों का समर्थन करने के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की दो खेपों का उपहार दिया। मई - जून 2020 में वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, 631 यात्रियों के साथ 03 प्रत्यावर्तन उड़ानें संचालित की गईं और फँसे हुए भारतीय नागरिकों को नाविकों के लिए संचालित विशेष चार्टर्ड उड़ानों से निकाला गया।

भारत वापस ले जाया गया था। इरिट्रिया में फँसे 33 भारतीयों को भी विशेष उड़ान द्वारा भारत लौटने की सुविधा दी गई।

08 सितंबर 2020 को आयोजित वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी सम्मेलन, 22-24 सितंबर 2020 को आयोजित 15वें सीआईआई-एक्जिम बैंक डिजिटल इंडिया-अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप कॉन्क्लेव, में आयोजित किया गया था, जो किया गया था, और महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह आदि को मनाने के लिए आईसीसीआर और यूपी डिजाइन संस्थान द्वारा आयोजित वस्तु बुनाई पर “बुनाई संबंध: कपड़ा परंपरा” पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार जैसे विभिन्न आभासी सम्मेलनों/कार्यक्रमों में इरिट्रिया की भागीदारी को सुविधान्वित किया गया।

आईएनएस ऐरावत ने पोर्ट मासवा के लिए एक एचएडीआर मिशन शुरू किया और 8 नवंबर 2020 को इरीट्रिया में 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता पहुंचाई।



आईएनएस ऐरावत ने 08 नवंबर 2020 को इरिट्रिया को 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता पहुंचाई

इजराइल

अप्रैल 2019-मार्च 2020 के दौरान एक वर्ष के भीतर तीन अभूतपूर्व चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता वाली इजराइल की 35 वीं सरकार ने 17 मई 2020 को शपथ ली। 22 दिसंबर 2020 को केसेट को भंग कर दिया गया था। दोनों प्रधानमंत्रियों ने मार्च 2020 से चार बार बात की है, जबकि विदेश मंत्री और विदेश मंत्री गेबी आशकेनाज़ी ने द्विपक्षीय रूप से सहायता के रूप में बातचीत की है और तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की अध्यक्षता में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और वियतनाम के विदेश मंत्रियों के साथ सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 25 मई 2020, 26 अगस्त 2020 और 22 अक्टूबर 2020 को तीन उड़ानों द्वारा करीब 550 भारतीय नागरिकों को इजराइल से वापस लाया गया था।

इस दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी (अप्रैल 2020) के बीच छोटे उपग्रह के लिए इलेक्ट्रिक प्रणोदन में सहयोग की योजना; सीईआरटी ऑफ इंडिया और इजरायल के बीच साइबर सुरक्षा पर परिचालन सहयोग पर समझौता ज्ञापन (15 जुलाई 2020); 2020-23 (20 अगस्त 2020) के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश सरकार और जल संसाधन मंत्रालय (इजराइल)

(20 अगस्त 2020) के बीच भारत-इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर जल उपयोगिता के क्षेत्र में सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए गए।

इजरायल ने शांति, राजनयिक संबंध और पूर्ण सामान्यीकरण (15 सितंबर 2020) की संधि पर हस्ताक्षर करके और बहरीन के साथ राजनयिक, शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना (18 अक्टूबर 2020) पर संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके यूएई के साथ संबंधों को सामान्य किया। भारत ने "फिलिस्तीनी कारण के लिए हमारा पारंपरिक समर्थन और एक स्वीकार्य दो-राज्य समाधान के लिए सीधी बातचीत की जल्द बहाली की आशा" दोहराते हुए समझौतों का स्वागत किया। 23 अक्टूबर 2020 को, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और सूडान ने एक संयुक्त बयान जारी करके घोषणा की कि इजरायल और सूडान संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सहमत हुए हैं। इजरायल और लेबनान ने 14 अक्टूबर 2020 को समुद्री सीमा पर बातचीत शुरू की।

भारत-इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श का 16वां दौर 7 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व सचिव (सीपीवी) और ओआईए) और इजरायल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक अलोन उशीप ने किया।

जॉर्डन

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2020 में जॉर्डन का दौरा किया। कोविड प्रतिबंधों के बावजूद, 16 अप्रैल 2020 को किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ प्रधानमंत्री के टेलीफोन कॉल से आभासी प्रारूप में उच्च स्तरीय संपर्क जारी रहा। विदेश मंत्री ने 05 अक्टूबर 2020 को जॉर्डन के विदेश और प्रवासियों के मंत्री अयमन अल सफादी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय विकास और कोविड के सहयोग पर चर्चा की गई।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, जॉर्डन में फँसे हुए 812 भारतीय नागरिकों (58

सदस्यीय मलयालम फिल्म चालक दल, जो कि कोविड-19 संकट के कारण जॉर्डन में फँस गया थे) को 21 मई, 29 जून, 04 सितंबर, 07 सितंबर 2020 को संचालित एयर इंडिया की चार विशेष उड़ानों के द्वारा भारत वापस लाया गया था। भारत में फँसे जॉर्डन नागरिकों को भी वापस भेजा गया।

जुलाई 2020 में, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने जॉर्डन के रेलवे क्षेत्र में इरकॉन के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में जॉर्डन पैनोरमा को कंसल्टेंसी एंड डेवलपमेंट (जेपीसीडी) नियुक्त किया।

लेबनान

बेरूत में 04 अगस्त 2020 को बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद, जिसमें लगभग 200 मृत, हजारों घायल और लगभग 300,000 बेघर हो गए, एक बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण, भारत सरकार ने 14 अगस्त 2020 को लेबनान सरकार को 58 मीट्रिक टन आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान की। सहायता को भारत से एक विशेष भारतीय वायु सेना सी -17 विमान द्वारा बेरूत लाया गया था। भारत सरकार द्वारा लेबनान सरकार को पीपीई की 70

पेटियों वाली चिकित्सा सहायता की खेप भी प्रदान की गई थी। भारतीयों को वापस लाने के लिए जून-अगस्त 2020 के बीच तीन विशेष सामुदायिक चार्टर उड़ानें आयोजित की गईं।

दिसंबर 2020 में, भारत सरकार ने लेबनान के अनुरोध पर उनके विदेश मामलों के मंत्रालय को कार्यालय उपकरण (कंप्यूटर, प्रिंटर और फोटोकॉपीयर) दान किए।

लीबिया

भारत ने मुख्य रूप से लीबिया में रहने वाले भारतीयों के कल्याण के लिए पूर्व और पश्चिम लीबिया दोनों के प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखा।

मोरक्को

भारत और मोरक्को के बीच संबंध जीवंत बने रहे, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली आम चुनौतियों में घनिष्ठ सहयोग से यह और सुदृढ़ हुआ। विदेश मंत्री, अफ्रीकी सहयोग और मोरक्को राज्य के मोरक्को के प्रवासियों के बीच विदेश मंत्री और नासर बोरीटा के बीच एक आभासी बैठक 22 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई थी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी।

मोरक्को द्वारा अप्रैल 2020 में भारत से हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट की 6 मिलियन गोलिएं का आयात किया गया था। मोरक्को में फँसे लगभग 100

भारतीय नागरिकों को 5 जून 2020 को वंदे भारत मिशन के अंतर्गत एक विशेष निकासी उड़ान द्वारा वापस लाया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और मोरक्को की सर्वोच्च न्यायिक शक्ति परिषद के बीच 24 जुलाई 2020 को रबात में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के अंतर्गत सी-डीएसी नोएडा द्वारा फरवरी 2021 में मोरक्को राज्य के अर्थव्यवस्था, वित्त और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के 20 अधिकारियों के लिए "साइबर सुरक्षा और मैलवेयर विश्लेषण" पर दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रस्तावित है।



22 अक्टूबर 2020 को मोरक्को के विदेश मंत्री के साथ एक आभासी बैठक में विदेश मंत्री

फिलिस्तीन

द्विपक्षीय विदेश कार्यालय परामर्श का तीसरा दौर 10 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व सचिव सीपीवी और ओआईए) और फिलिस्तीन के उप विदेश मंत्री अमल जादौ शक्का ने किया। फिलिस्तीन के साथ भारत की विकाससात्मक साझेदारी के हिस्से के रूप में, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए पहले से हस्ताक्षरित, समझौतों की औपचारिकताओं को विस्तारित करने के लिए, प्रधानमंत्री डॉ. मोहम्मद शतयेह की उपस्थिति में, 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय

में प्रतिनिधि कार्यालय और फिलिस्तीन सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। फिलिस्तीन के अनुरोध पर, भारत ने जून 2020 में फिलिस्तीन को कैसर-रोधी दवाओं और पीपीई की आपूर्ति की। जुलाई और सितंबर 2020 में, भारत ने वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से 19 फिलिस्तीनियों की वापसी की सुविधा दी। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में निकट पूर्व (यूएनआरडब्ल्यूए) में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और वर्क्स एजेंसी को कुल 5 मिलियन अमरीकी डॉलर में से 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की तीसरी किश्त का योगदान दिया है।

सोमालिया

सोमालिया ने भारत से अपने नागरिकों को निकालने के लिए, 07 जून, 20 जून और 23 जून, 01 जुलाई, 25 जुलाई और 29 जुलाई 2020 को 6 चार्टर्ड उड़ानों का संचालन किया। हैदराबाद से मोगादिशु के लिए इन चार्टर उड़ानों पर लगभग 1500 सोमाली नागरिकों को प्रत्यावर्तित किया गया था। गरोवे (पुंटलैंड) और हर्गोसिया (सोमालिलैंड) में फँसे 23 भारतीयों को 22 जून

2020 को हैदराबाद की चार्टर्ड उड़ान में वापस लाया गया था। 19 सोमालियों ने अप्रैल-अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान ऑनलाइन ई-आईटीईसी पाठ्यक्रमों में भाग लिया। भारत सरकार द्वारा सोमालिया को 5.48 करोड़ की लागत से दान की जा रही 27 मिडी बसों को 20 जनवरी 2021 को जहाज द्वारा भारत से भेजा गया।

दक्षिणी सूडान

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चार निकासी उड़ानों से फँसे हुए भारतीयों और दक्षिण सूडानी नागरिकों को वापस भेजा गया। हाल ही में आई बाढ़ के कारण दक्षिण सूडान के कष्टों को दूर करने के लिए, भारत सरकार ने सूडान को 70 मीट्रिक टन खाद्य सहायता दी। खाद्य सहायता को मुंबई से आईएनएस ऐरावत

के माध्यम से 20 नवंबर 2020 को मोम्बासा बंदरगाह (केन्या) भेजा गया और वहाँ से सड़क मार्ग से जुबा तक पहुँचाया गया। हम जनवरी 2021 तक दक्षिण सूडान में जीवन रक्षक दवाओं की 10 मेट्रिक टन की खेप भेजने की आशा करते हैं।

सूडान

भारत ने सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटाने की घोषणा का स्वागत किया और जुबा शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संक्रमणकालीन सरकार और सूडान के लोगों को बधाई दी। आशा की जाती है कि ये विकास लोकतांत्रिक परिवर्तनों की शुरुआत करेंगे और सूडान के विकास, शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाने में योगदान देंगे। भारत ने सूडान के इजरायल के साथ संबंधों के सामान्यीकरण का भी स्वागत किया। आशा है कि इस कदम से पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता आएगी

आईटीईसी के अंतर्गत, सूडान के दक्षिण कोर्डोफन राज्य के सुदूर गांवों की 6 सूडानी निरक्षर महिलाओं का एक समूह राजस्थान के तिलोनिया में बेयरफुट

कॉलेज (सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर) में सौर विद्युत और वर्षा जल संग्रहण पर 5 महीने का प्रशिक्षण लिया। जून और जुलाई 2020 के दौरान फ्लाई दुबई और बद्र एयर की कई विशेष प्रत्यावर्तन उड़ानों ने फँसे हुए 501 भारतीयों, 5 भूटानी नागरिकों और 1 सूडानी नागरिक को भारत लाया गया और सैकड़ों सूडानी नागरिकों को जून और जुलाई 2020 के दौरान भारत से निकाला गया। आईएनएस ऐरावत ने पोर्ट सूडान के लिए एक एचएडीआर मिशन आरंभ किया और 02 नवंबर 2020 को सूडान को 100 मीट्रिक टन खाद्य सहायता पहुंचाई।

राज्य मंत्री और सूडान के कार्यवाहक विदेश मंत्री, उमर गमर अल्दीन इस्माइल ने 14 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की।

सीरिया

राज्य मंत्री ने 03 सितंबर 2020 को एक आभासी बैठक में सीरियाई विदेश मंत्री और प्रवासी मंत्री, फैजल मेकदाद से विस्तृत बातचीत की। बैठक के दौरान, राज्य मंत्री ने वार्षिक आईटीईसी स्लॉट की संख्या को 90 से बढ़ाकर 150 करने पर सहमति व्यक्त की; अकादमिक वर्ष 2020-21 के दौरान “भारत में अध्ययन” कार्यक्रम के अंतर्गत 250 नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गईं; एसएसआईएफएस में सीरियाई राजनयिकों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने की पेशकश की गई; सीरिया को ई-विद्या और ई-आरोग्य भारती परियोजनाओं आदि से जोड़ने के माध्यम से टेली-शिक्षा और टेली-मेडिसिन सेवाओं का विस्तार करने पर बात हुई।

भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सीरिया की सहायता करने के लिए 02 जुलाई 2020 को दमिश्क को 10 मेट्रिक टन चिकित्सा सहायता भेजी। सीरियाई पक्ष के अनुरोध पर, और सीरियाई लोगों को मानवीय सहायता देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अंतर्गत, सीरिया को 2021 की पहली तिमाही में चावल की 2000 मीट्रिक टन की खेप भेजे जाने की आशा है।

बीएमवीएसएस (जयपुर फुट) के सहयोग से दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 के दौरान “इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी” विषय के अंतर्गत दमिश्क में कृत्रिम अंग लगाने का पहला शिविर आयोजित किया गया था।

ट्यूनीशिया

भारत और अन्य देशों के ट्यूनीशियाई लोगों को वापस लाने के लिए भारत आ रही ट्यूनीशियाई सैन्य उड़ान द्वारा 21 मई 2020 को, ट्यूनीशिया में फँसे हुए 25 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया।

व्यापार और निवेश पर पहला भारत-ट्यूनीशिया जेडब्ल्यूजी 15 दिसंबर

2020 को आभासी प्रारूप में आयोजित किया गया था। इसका नेतृत्व जेएस (एफटी-वाना), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और ट्यूनीशिया के व्यापार और निर्यात विकास मंत्रालय में अरब और एशियाई देशों के साथ सहयोग के निदेशक के रूप में, चाडली मे ने किया था।

7

अफ्रीका

मध्य और पश्चिम अफ्रीका

इस क्षेत्र में पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, मध्य और दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका में 25 देश शामिल हैं। यह क्षेत्र अफ्रीका की सबसे बड़ी आबादी और ऊर्जा संसाधनों और खनिजों के विशाल भंडार के साथ सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से है। भारत इस क्षेत्र से अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% प्राप्त करता है। सभी 25 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों में विभिन्न चुनावों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करना जारी रखा।

कोविड महामारी और परिणामी याला प्रतिबंधों के प्रकोप के बावजूद, 2020-21 के दौरान मध्य और पश्चिम अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंधों पर विकास और प्रगति की भावना हावी रही और इनका लगातार विस्तार और विविधीकरण होता रहा।

भारत वर्तमान में अफ्रीका के लिए टेली-एजुकेशन और टेली-मेडिसिन में एक प्रायोगिक परियोजना लागू कर रहा है जिसे ई-विद्याभारती आरोग्यभारती नेटवर्क प्रोजेक्ट (ई-वीबीएबी) कहा जाता है। अब तक मध्य और पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र के देशों सहित 17 अफ्रीकी देशों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। फरवरी 2020 में स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए नामांकन शुरू हुआ।

याला प्रतिबंधों ने भारत की गतिशील अफ्रीका आउटरीच नीति में बाधा नहीं डाली। भारत सक्रिय रूप से इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने निर्धारित जुड़ाव का संचालन कर रहा है। विदेश मंत्री ने कई देशों के अपने समकक्षों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

वर्ष के दौरान, साओ टोम प्रिंसिपे और सिएरा लियोन में दो और मिशनों के उद्घाटन के साथ-साथ अफ्रीका में भारत की कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ी। मॉरिटानिया, लाइबेरिया, गिनी बिसाऊ और काबो वर्डे में जल्द ही राजनयिक मिशन खोले जाने की संभावना है, उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो चुके हैं।

भारत ने अफ्रीका के साथ अपनी विकास साझेदारी को जारी रखते हुए विभिन्न रियायती ऋणों की घोषणा की। भारत ने लगभग 1.8 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की कोविड दवाएँ प्रदान करके महामारी पर काबू पाने में 14 अफ्रीकी देशों की सहायता की। विभिन्न अफ्रीकी देशों में फँसे हुए हजारों भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने और फँसे अफ्रीकी नागरिकों को निकालने के लिए कई उड़ानों का संचालन किया गया।

अंगोला

वर्ष के दौरान अंगोला के साथ संबंधों में और तेजी आई। विदेश मंत्री और अंगोला के विदेश मंत्री, टेरे एंटोनियो, ने सितंबर 2020 में पहली भारत-अंगोला संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने बड़े पैमाने पर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स,

रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डिजिटलीकरण और दूरसंचार के क्षेत्रों में व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में स्वास्थ्य, राजनयिकों के प्रशिक्षण और वीजा सुविधा पर तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।



7 सितंबर 2020 को आयोजित भारत-अंगोला संयुक्त आयोग की बैठक।

वर्ष में इससे पहले, सामग्री संसाधन और बुनियादी ढाँचे के सचिव, जनरल अफोंसो कार्लोस नेटो की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलने डीईएफईएक्सपीओ 2020 में भाग लिया था। डीईएफईएक्सपीओ के साथ

आयोजित भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्रियों की बैठक में राज्य सचिव ने भी भाग लिया।

बेनिन

जुलाई 2019 में बेनिन के लिए भारत के राष्ट्रपति की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के साथ भारत-बेनिन द्विपक्षीय जुड़ाव बढ़ा। यात्रा के दौरान, वे बेनिन पैट्रिस तालोन के राष्ट्रपति से मिले, और द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से समीक्षा की। इस यात्रा में 4 समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे –

- 2019-23 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- टेलीमेडिसिन और टेली-शिक्षा पर समझौता ज्ञापन
- राजनयिक, आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से पारस्परिक छूट पर समझौता
- निर्यात ऋण और निवेश बीमा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

राष्ट्रीय प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के लिए बेनिन को 100 मिलियन अमरीकी डॉलर का रियायती ऋण देने की भी घोषणा की गई है।

भारत बेनिन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और बेनिन के बीच 2019-20 में 686 मिलियन अमरीकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार दर्ज किया

गया। बेनिन में एक भारतीय निवेश, प्राइमस डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन 08 सितंबर 2020 को कोटोनू में किया गया था। वर्ष के दौरान, बेनिन के रक्षा बलों को आईटीईसी के साथ-साथ अन्य मंचों के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए थे। बेनिन के अधिकारियों ने आईटीईसी कार्यक्रम, आईसीसीआर छालवृत्ति, साथ ही ई-वीएबीबी नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत छालवृत्ति का लाभ उठाना जारी रखा।

भारत ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जुलाई 2020 में बेनिन को आवश्यक दवाओं की 6 टन की खेप दान में दी। कोविड-19 महामारी के दौरान, बेनिन में फँसे हुए कुल 293 भारतीय नागरिकों को 3 उड़ानों में भारत लाया गया।

बेनिन के भारतीय समुदाय के साथ-साथ बेनिन के नागरिकों ने जून 2020 में छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया और मिशन द्वारा वर्चुअल प्रारूप में महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समापन समारोह आयोजित किया गया।

बुर्किना फासो

भारत और बुर्किना फासो के बीच मैत्री और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध हैं। कोविड-19 महामारी के कारण आए संकट में बुर्किना फासो के लोगों और सरकार की मदद करने के लिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां और अन्य

जरूरी दवाएं सौंपी गईं। बुर्किना फासो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत सरकार के इस कदम की सराहना की।

कैमरून

सितंबर 2019 में हमारे मिशन के उद्घाटन के साथ, भारत और कैमरून के बीच संबंध और मजबूत हुए। 12 वर्षों के अंतराल के बाद, 2021 की पहली तिमाही में याउंडे में विदेशी कार्यालय परामर्श आयोजित किए जाने की संभावना है। कैमरून के विदेश संबंधों के मंत्री ने 22-24 सितंबर 2020 को एक आभासी मंच पर आयोजित भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15 वें सीआईआई-एक्विजम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव में भाग लिया।

द्विपक्षीय व्यापार, जो 2019-20 के दौरान यूएसडी 904.81 मिलियन था, 2018-19 की तुलना में 73% बढ़ा है। 2018-19 में भारत का निर्यात 179 मिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 228,45 लाख डॉलर पहुंच गया, इसमें 28% तक की वृद्धि दर्ज की गई। भारत के आयात में 97% की वृद्धि दर्ज की गई जो कि 2018-19 के दौरान 343.30 मिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 676.36 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।

भारत सरकार के 93.50 लाख अमरीकी डॉलर के रियायती ऋण के अधीन बन रही नक्संगम्बा बाफुससम और अबोंग-याओडे की 225किलोवाट संचरण लाइन निर्माण की परियोजना में वर्ष के दौरान अच्छी प्रगति हुई। इस परियोजना के फरवरी 2022 में तय समय पर पूरी होने की आशा है।

कैमरून ने 2021-22 की अवधि के लिए यूएनएस सी की अस्थायी सीट के

लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। कैमरून ने 2020-22 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के अध्यक्ष पद के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

कैमरून सरकार द्वारा छह आलंकारिक स्मारक डाक टिकट जारी कर महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती को चिह्नित किया गया था। इस अवसर पर डाक और दूरसंचार मंत्री मिन्ट लिबोम ली लिकेंग मुख्य अतिथि थे। विदेश कार्यालय (मिनरेक्स) से, राष्ट्रमंडल के विदेश संबंध प्रभारी, मंत्री, फेलिक्स मबायु, विदेश मंत्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए समारोह में शामिल हुए।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, कोविड-19 के कारण कैमरून में फँसे लगभग 100 भारतीय नागरिकों को चार्टर्ड उड़ानों से निकाला गया। मिशन ने महामारी के कारण भारत में फँसे 109 कैमरून नागरिकों की निकासी में कैमरून के अधिकारियों को समर्थन दिया।

मिशन ने 21 जून 2020 को छठवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर कैमरून की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और सीपीए कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एमिलिया मोनजोवा लीपाका मुख्य अतिथि थीं।

हमारे मिशन द्वारा कैमरून में छठवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

काबो वर्डे

काबो वर्डे ने 2021-2022 की अवधि के लिए यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

भारत-काबो वर्डे द्विपक्षीय व्यापार 4.5 मिलियन अमरीकी डॉलर पर अपरिवर्तित रहा। भारत और काबो वर्डे के व्यापारिक समुदायों के बीच व्यापार संपर्क को बेहतर बनाने और द्विपक्षीय व्यापार के नए रास्ते तलाशने के लिए, हमारे मिशन ने डेयरी, वस्त्र, कृषि आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, आदि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किए, जिनमें काफी लोगों ने भाग लिया।

कोविड-19 महामारी के समय, भारत ने सितंबर 2020 में काबो वर्डे को दवाएं

दान कीं। भारत ने विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर कार्यक्रम सहित आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत काबो वर्डे अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट देना जारी रखा। 11 सितंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आईटीईसी दिवस मनाया गया।

छठवाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2020 आभासी प्रारूप में मनाया गया। महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, आईसीसीआर द्वारा उपहार में दी गई महात्मा गांधी की एक प्रतिमा, 02 अक्टूबर 2020 को परिया के सिटी हॉल द्वारा स्थापित की गई थी। गांधीयन फोरम फॉर एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस के मुख्य कार्यवाहक द्वारा 'गांधी की कहानी' सुनाई गई, इसे 24 सितंबर 2020 को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया गया।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य

भारत और मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) के बीच मैत्री और सौहार्दपूर्ण

संबंध रहे। भारत सरकार ने रियायती ऋण के अंतर्गत दो रुकी हुई परियोजनाओं

भारत में 2020 के प्रारंभ में नई दिल्ली में अपना निवासी दूतावास खोला और भारत के 2021 में दूतावास खोलने की संभावना है।

द्विपक्षीय व्यापार 2019-20 में 329.44 मिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज किया गया। भारत सरकार के 15.90 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण के अंतर्गत चाड में ‘कताई मिल परियोजना का विस्तार’ पूरा हो चुका है।

भारत ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जुलाई 2020 में चाड को

आवश्यक दवाओं की 6 टन की खेप दान में दी। कोविड-19 महामारी के दौरान, चाड में फँसे हुए कुल 37 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया था।

भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत चाडियन अधिकारियों को स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है।

चाड के भारतीय समुदाय के साथ-साथ चाड के नागरिकों ने जून 2020 में छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया और मिशन द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समापन समारोह आयोजित किया गया।

चाड ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जुलाई 2020 में चाड को

कोट डि’आइवर

भारत के कोटे डी’वायर के साथ मैत्री पूर्ण संबंध और सहयोग वर्ष के दौरान बढ़ते रहे। कोट डी’आइनर ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विभिन्न चुनावों के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जिसमें 2021-22 की अवधि के लिए यूएन21 में अस्थायी सदस्यता शामिल है।

व्यापार और निवेश के लिए हमारे व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ मेजबान सरकार के साथ भारत का जुड़ाव तेज हुआ। अप्रैल से अगस्त 2020 की अवधि के लिए भारत और कोट डी’आइवर के बीच द्विपक्षीय व्यापार 307.32 मिलियन अमरीकी डॉलर था। कोट डी आइवर को 100 आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट और 10 आईसीसीआर छात्रवृत्ति दी जाती हैं, जिनका प्रत्येक वर्ष संतोषजनक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ, सामान्य ध्यान महामारी की ओर स्थानांतरित हो गया। इस अवधि में मिशन की गतिविधियों को भारतीय समुदाय के साथ संलग्न करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था जो यात्रा प्रतिबंधों के कारण फंस गए थे। 3 चार्टर्ड उड़ानों का आयोजन किया गया और फँसे हुए 631 एनआरआई को कोट डी’आइवर और लाइबेरिया से

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) के साथ द्विपक्षीय संबंध वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण बने रहे। भारत सरकार ने नए रियायती ऋण के अंतर्गत 74 मेगावाट की कुल 6 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कीमत 223.44 मिलियन अमरीकी डॉलर है। बंडुंडु प्रांत में काकोबोला जलविद्युत परियोजना से बिजली उत्पादन के लिए 34.50 मिलियन अमरीकी डॉलर के

मिशन ने विशेष चार्टर्ड उड़ानों का आयोजन करके कोविड-19 के कारण सीएआर में फँसे कई भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान की है।

आवश्यक दवाओं की 6 टन की खेप दान में दी। कोविड-19 महामारी के दौरान, चाड में फँसे हुए कुल 37 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया था।

भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत चाडियन अधिकारियों को स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है।

चाड के भारतीय समुदाय के साथ-साथ चाड के नागरिकों ने जून 2020 में छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया और मिशन द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समापन समारोह आयोजित किया गया।

चाड ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत चाडियन अधिकारियों को स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है।

चाड के भारतीय समुदाय के साथ-साथ चाड के नागरिकों ने जून 2020 में छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया और मिशन द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समापन समारोह आयोजित किया गया।

चाड ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जुलाई 2020 में चाड को

वापस लाया गया। कोट डी’आइवर के भारतीय समुदाय के साथ मिशन ने एक भारत-कोट डी’ आइवर ‘कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष’ आरंभ किया और 40 मिलियन सीएफए मूल्य की राहत सामग्री दान की और बाद में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए 25 हजार अमरिकी डॉलर की कोविड-19 परीक्षण किट दान की।

मिशन ने 21 जून 2020 को छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया, जिसे महामारी की वर्तमान स्थिति में आत्म-प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करने के लाभों को उजागर करते हुए सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के समापन के अवसर पर, मिशन ने दो दिनों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, वीआईटीआईबी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, वृक्षारोपण किया गया और कंप्यूटर असेंबली लाइन के वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की। वीआईटीआईबी में भारत सरकार के रियायती ऋण के अंतर्गत एक भारतीय कंपनी ने महात्मा गांधी आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क (एमजीआईटी-बीपी) स्थापित किया।

विद्युत वितरण परियोजना पर काम चल रहा है और इसके जल्द ही पूरा होने की संभावना है। भारत ने ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती (ई-वीएबीबी) के अंतर्गत डीआरसी को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना जारी रखा है। डीआरसी ने संयुक्त राष्ट्र और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय निकायों के चुनावों में भारत की उम्मीदवारी को समर्थन दिया।

मिशन ने विशेष चार्टर्ड उड़ानों का आयोजन करके कोविड महामारी के कारण

डीआरसी में फँसे 1329 भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान की।

इक्वाटोरियल गिनी

इस अवधि के दौरान भारत-इक्वेटोरियल गिनी के द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार जारी रहा। जून 2020 में, भारत ने आवश्यक दवाओं की खेप भेजकर कोविड-19 महामारी के खिलाफ इक्वेटोरियल गिनी की लड़ाई में सहायता की। भारत और इक्वेटोरियल गिनी के बीच डिप्लोमैटिक और आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता 01 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। वर्ष के दौरान, इक्वेटोरियल गिनी के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा शुरू की

गैबॉन

गैबॉन ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करना जारी रखा। इंडियन ऑयल लिमिटेड के साथ साझेदारी में ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) 3761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र शक्ति ब्लॉक में तेल की खोज कर रही है। तेल की खोज के द्वितीय चरण के 2023 तक जारी

गाम्बिया

भारत और द गाम्बिया के बीच ऐतिहासिक रूप से मैत्री और सौहार्दपूर्ण संबंध थे, अंग्रेजी को एक आम भाषा के रूप में साझा किया जाता है। गाम्बिया ने 2020-22 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अध्यक्षता की भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

विदेश मंत्री ने जुलाई 2020 में गाम्बिया के विदेश मंत्री, मामादौ तंगारा के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर उपयोगी और लाभकर चर्चा की।

रक्षा मंत्री शेख उमर फाये ने भारत में फरवरी 2020 में भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्रियों की बैठक और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी (डेफएक्स 2020) में भाग लिया था।

भारत-गाम्बिया द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी दिखाते हुए, 176 मिलियन अमरीकी डॉलर पर रहा था, हालांकि, भारत से द गाम्बिया में कपड़े और कपास के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

विकासಾत्मक सहायता में ग्रेटर बंजुल क्षे्र में 22.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की दो रियायती ऋण परियोजनाओं- यूपीवीसी पाइप से एस्बेस्टस वॉटर पाइप के प्रतिस्थापन और विद्युत विस्तार परियोजना के 2021 की पहली तिमाही में पूरी होने की संभावना है।

घाना

भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते रहे। सितंबर 2020 में आयोजित 15 वें सीआईआई-एक्जिम बैंक इंडिया-अफ्रीका प्रोजेक्ट

भारत ने विशेष चार्टर्ड उड़ानों का आयोजन करके कोविड महामारी के कारण

डीआरसी में फँसे 1329 भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान की।

आवश्यक दवाओं की 6 टन की खेप दान में दी। कोविड-19 महामारी के दौरान, चाड में फँसे हुए कुल 37 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया था।

भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत चाडियन अधिकारियों को स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है।

चाड के भारतीय समुदाय के साथ-साथ चाड के नागरिकों ने जून 2020 में छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया और मिशन द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समापन समारोह आयोजित किया गया।

चाड ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जुलाई 2020 में चाड को

आवश्यक दवाएं दान की हैं। भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत गांबियाई अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। 11 सितंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आईटीईसी दिवस मनाया गया।

वर्ष 2020 का छठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आभासी प्रारूप में मनाया गया। ‘गांधीजी फोरम फॉर एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस’ की मुख्य कार्यकारी द्वारा गांधी जी की कहानी सुनाई गई, जिसे 24 सितंबर 2020 को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया गया था।

भारत ने कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने द गाम्बिया को बड़ी मात्रा में आवश्यक दवाएं दान की हैं। भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत गांबियाई अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। 11 सितंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आईटीईसी दिवस मनाया गया।

वर्ष 2020 का छठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आभासी प्रारूप में मनाया गया। ‘गांधीजी फोरम फॉर एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस’ की मुख्य कार्यकारी द्वारा गांधी जी की कहानी सुनाई गई, जिसे 24 सितंबर 2020 को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया गया था।

भारत ने कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने द गाम्बिया को बड़ी मात्रा में आवश्यक दवाएं दान की हैं। भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत गांबियाई अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। 11 सितंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आईटीईसी दिवस मनाया गया।

वर्ष 2020 का छठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आभासी प्रारूप में मनाया गया। ‘गांधीजी फोरम फॉर एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस’ की मुख्य कार्यकारी द्वारा गांधी जी की कहानी सुनाई गई, जिसे 24 सितंबर 2020 को फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम किया गया था।

भारत ने कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने द गाम्बिया को बड़ी मात्रा में आवश्यक दवाएं दान की हैं। भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत गांबियाई अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। 11 सितंबर 2020 को आभासी प्रारूप में आईटीईसी दिवस मनाया गया।

पार्टनरशिप कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में, घाना के उप-व्यापार मंत्री और कार्लोस किंग्सले अहेनकोराह और रेल मंत्री जो घरटे ने भाग लिया। 2019-

भारत में द्विपक्षीय व्यापार 2390.97 अमरीकी डॉलर का दर्ज किया गया था। भारत ने 617.42 मिलियन अमरीकी डॉलर के सामान का निर्यात किया और भारत का आयात 1773.55 मिलियन अमरीकी डॉलर था। अप्रैल-जुलाई 2020 के बीच की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार की राशि 557.17 मिलियन अमरीकी डॉलर थी, जिसमें भारत का निर्यात 204.04 मिलियन अमरीकी डॉलर था और भारत 353.13 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात करता था।

20 में द्विपक्षीय व्यापार 2390.97 अमरीकी डॉलर का दर्ज किया गया था। भारत ने 617.42 मिलियन अमरीकी डॉलर के सामान का निर्यात किया और भारत का आयात 1773.55 मिलियन अमरीकी डॉलर था। अप्रैल-जुलाई 2020 के बीच की अवधि के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार की राशि 557.17 मिलियन अमरीकी डॉलर थी, जिसमें भारत का निर्यात 204.04 मिलियन अमरीकी डॉलर था और भारत 353.13 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात करता था।

भारत की विकास साझेदारी ने महत्वपूर्ण प्रगति की। घाना में ‘यांत्रिकीकरण सेवा केंद्रों के सुदृढीकरण’ के लिए 150 मिलियन अमरीकी डॉलर, येंदी में पुनर्वास और उन्नयन योग्य जल प्रणाली के लिए 30 मिलियन अमरीकी डॉलर और विदेशी सेवा संस्थान के निर्माण के लिए 7 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए तीन रियायती ऋण योजनाएँ वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं। 30 जुलाई 2020 को, राष्ट्रपति अकुफो-एडो ने येंदी नगरपालिका और इसके पर्यावरण कर्मियों को रोज़ाना 15,000 क्यूबिक मीटर पानी देने के लिए येंदी जल आपूर्ति परियोजना आरंभ की। 29 सितंबर 2020 को, घाना रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी और एफ़कन्स इन्फ़्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इंडिया ने 419 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो एडुआडिन से ओबुआसी तक अशांति क्षे़त्र में एक रेलवे लाइन का निर्माण करेगा।

उच्चायोग ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के अंतर्गत घाना के व्यापार और उद्योग उप मंत्री, रॉबर्ट अहोमका-लिंग्से और

गिनी गणराज्य

अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की गिनी की यात्रा के बाद, द्विपक्षीय संबंधों को काफ़ी बढ़ावा मिला है। भारत ने जुलाई 2020 में कोविड महामारी से लड़ने के लिए गिनी को 6 टन आवश्यक दवाइयाँ भेंट की हैं। जून और जुलाई 2020

गिनी बिसाऊ

भारत ने वर्ष के दौरान गिनी-बिसाऊ के साथ अपने मौजूदा सौहार्दपूर्ण संबंधों को विकसित करना जारी रखा। गिनी बिसाऊ ने 2021-2022 की अवधि के लिए यूएनएससी की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

कोविड-19 के कारण वैश्विक व्यापार में आई गिरावट के बावजूद भारत-गिनी-बिसाऊ द्विपक्षीय व्यापार 133 मिलियन अमरीकी डॉलर पर स्थिर रहा। मिशन ने डेयरी, वस्त्र, कृत्रिम गहने, इंजीनियरिंग सामान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किए, जैसे कि, आदि बहुत से लोगों ने भाग लिया और सहयोग के नए रास्ते तलाशने में मदद की।

घाना में प्रमुख व्यापारिक घरानों की उपस्थिति में 23 नवंबर 2020 को ‘इंडिया बिजनेस फोरम इन घाना (आईबीएफ)’ का शुभारंभ किया।

भारत और घाना सरकारों के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन और परमाणु ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र के बीच सहयोग के लिए एक और समझौता ज्ञापन, भारत और घाना परमाणु ऊर्जा आयोग हस्ताक्षर के लिए तैयार हैं और 2021 की पहली तिमाही में इन पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।।

भारत ने क्षमता निर्माण में घाना का समर्थन जारी रखा। घाना ने आईटीईसी कार्यक्रम (सिविलियन एंड डिफेंस), भारत-अफ्रीका फोरम समिट निर्णय और आईसीसीआर छात्रवृत्ति के अंतर्गत स्लॉट का उपयोग किया। घाना के 200 से अधिक छात्रों ने ई-वीबीएबी नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत पेश किए गए पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए दाखिला लिया।

कोविड-19 के समय घाना में फँसे 1500 भारतीय नागरिकों को चार्टर्ड उड़ानों द्वारा भारत वापस भेज दिया गया।

छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और हिंदी दिवस क्रमशः 21 जून और 14 सितंबर को आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समापन समारोह में 02 सितंबर 2020 को फेसबुक पर ‘गांधी कथा’ की लाइव स्ट्रीमिंग और 02 अक्टूबर 2020 को कार्यक्रम शामिल था।

कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने अगस्त 2020 में गिनी बिसाऊ को बड़ी मात्रा में दवाओं का दान किया है। भारत ने विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत बिसाऊ-गिनी अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिनमे आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। आईटीईसी दिवस आभासी प्रारूप में 11 सितंबर 2020 को मनाया गया।

कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने अगस्त 2020 में गिनी बिसाऊ को बड़ी मात्रा में दवाओं का दान किया है। भारत ने विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत बिसाऊ-गिनी अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिनमे आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। आईटीईसी दिवस आभासी प्रारूप में 11 सितंबर 2020 को मनाया गया।

के महीनों में 160 फँसे हुए भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाने के लिए दो चार्टर उड़ानों की व्यवस्था की गई थी।

कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने अगस्त 2020 में गिनी बिसाऊ को बड़ी मात्रा में दवाओं का दान किया है। भारत ने विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत बिसाऊ-गिनी अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिनमे आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। आईटीईसी दिवस आभासी प्रारूप में 11 सितंबर 2020 को मनाया गया।

कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने अगस्त 2020 में गिनी बिसाऊ को बड़ी मात्रा में दवाओं का दान किया है। भारत ने विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत बिसाऊ-गिनी अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिनमे आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। आईटीईसी दिवस आभासी प्रारूप में 11 सितंबर 2020 को मनाया गया।

कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने अगस्त 2020 में गिनी बिसाऊ को बड़ी मात्रा में दवाओं का दान किया है। भारत ने विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत बिसाऊ-गिनी अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिनमे आईसीसीआर छात्रवृत्ति भी शामिल है। आईटीईसी दिवस आभासी प्रारूप में 11 सितंबर 2020 को मनाया गया।

2020 के छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक आभासी प्रारूप में मनाया गया। गिनी बिसाऊ के प्रधानमंत्री नूनो गोम्स नाबियम ने 02 अक्टूबर 2020 को दुरदर्शन पर महात्मा गांधी पर एक विशेष संदेश दिया।

लाइबेरिया

भारत और लाइबेरिया ने मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद लेना जारी रखा, हालांकि वर्ष के दौरान कोई उच्च-स्तरीय यात्रा नहीं हुई। लाइबेरिया अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति और विभिन्न चुनावों के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता रहा है, जिसमें यूएन21 में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी भी शामिल है।

भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए लाइबेरिया को 4.2 टन जीवन रक्षक दवाओं का उपहार दिया। एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय

माले

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद माले के साथ भारत का संबंध समृद्ध रहा। विदेश मंत्री ने 25 अप्रैल 2020 को माले के विदेश मंत्री तिबेले ड्रामे के साथ टेलीफोन पर बात की। उन्होंने स्वास्थ्य, सुरक्षा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की।

भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ माले की लड़ाई में समर्थन के लिए माले के अनुरोध का जवाब दिया। भारत सरकार ने माले के लोगों के लिए विभिन्न जीवन रक्षक दवाओं की एक बड़ी खेप दान में दी, जिन्हें माले के स्वास्थ्य और सामाजिक विकास मंत्रालय को सौंप दिया गया।

राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, और विदेश मंत्री ने माले के अपने समकक्षों को पत्र लिखे जिसमें माले की संक्रमणकालीन सरकार की सफलता के लिए भारत के समर्थन व्यक्त किया और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया गया।

विकास साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, 26 अक्टूबर 2020 को सिकसो-बामको से 393 किमी की 225-किलोवाट डबल सर्किट पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए निर्माण शुरू हुआ, जिसका माले के उद्घाटन खान, ऊर्जा और जल मंत्री मंत्री लामाइन सेडॉ ट्राे द्वारा किया गया

मॉरिटानिया

भारत और मॉरिटानिया ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद लगातार काम करना जारी रखा। मॉरिटानिया से तीन चार्टर उड़ानों में 219 भारतीय दिल्ली लौटे।

वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 94.53 मिलियन अमरीकी डॉलर था। 2019-20 के दौरान मॉरिटानिया को पाँच आईटीईसी स्लॉट और तीन

नाइजर

भारत और नाइजर ने कोविड-19 महामारी द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों के बावजूद संलग्न रहना जारी रखा। विदेश मंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को नाइजर के विदेश मंत्री कल्ला अंकुरो के साथ टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय

सहयोग परियोजना 14-सैन्य अस्पताल का पूरी हुई है जिसका केवल कोविड-19 अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 14-सैन्य अस्पताल के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 2 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया था। भारत ने 45 टाटा यात्री बसें और 5 अशोक लीलैंड अग्नि ट्रक उपहार में दिये हैं।

सहयोग परियोजना 14-सैन्य अस्पताल का पूरी हुई है जिसका केवल कोविड-19 अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 14-सैन्य अस्पताल के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 2 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया था। भारत ने 45 टाटा यात्री बसें और 5 अशोक लीलैंड अग्नि ट्रक उपहार में दिये हैं।

भारत प्रतिवर्ष लाइबेरिया को 70 आईटीईसी स्लॉट और 10 आईसीसीआर छात्रवृत्ति प्रदान करता है जिसका संतोषजनक उपयोग किया जा रहा है।

सहयोग परियोजना 14-सैन्य अस्पताल का पूरी हुई है जिसका केवल कोविड-19 अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 14-सैन्य अस्पताल के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 2 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया था। भारत ने 45 टाटा यात्री बसें और 5 अशोक लीलैंड अग्नि ट्रक उपहार में दिये हैं।

था। 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की परियोजना लागत भारत सरकार द्वारा रियायती ऋण के अंतर्गत प्रदान की गई थी।

प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2020 को अपने मन की बात कार्यक्रम में, दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों की दोस्ती और समझ को बढ़ावा देने में माले के सेदोउ डेम्बेले की भूमिका पर प्रकाश डाला। डेंबेले को भारतीय संगीत के प्रति उनके प्रेम के लिए ‘माले के हिंदुस्तानी बाबू’ के रूप में जाना जाता है, वे कई वर्षों से माले में भारतीय संगीत प्रचारित कर रहे हैं।

कोविड-19 महामारी के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता रहा और 2019-20 में यह 184.21 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा।

भारत ने अपने आईटीईसी कार्यक्रम और आईसीसीआर छात्रवृत्ति के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अवसरों की पेशकश जारी रखी।

कोविड-19 महामारी के कारण माले में छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक आभासी प्रारूप में मनाया गया। गांधी जयंती मनाने के लिए गांधीवादी वक्ता द्वारा एक गांधी कथा का आयोजन किया गया था।

सहयोग परियोजना 14-सैन्य अस्पताल का पूरी हुई है जिसका केवल कोविड-19 अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 14-सैन्य अस्पताल के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 2 मिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान दिया था। भारत ने 45 टाटा यात्री बसें और 5 अशोक लीलैंड अग्नि ट्रक उपहार में दिये हैं।

आईसीसीआर छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है।

भारत और मॉरिटानिया संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर लगातार काम करते रहे। मॉरिटानिया ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

भारत और नाइजर ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निकट सहयोग बनाए रखा। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक-दूसरे की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। भारत और नाइजर के पास वर्ष 2021 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में एक साथ काम करने का अवसर होगा।

वर्ष 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 74.50 मिलियन अमरीकी डॉलर था। कोविड-19 द्वारा प्रेरित मंदी के बावजूद, 2020-2021 के पहले चार महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 20.64 मिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज किया गया था।

विकासाम्क सहायता परियोजनाओं ने ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति की। 34.54 मिलियन अमरीकी डॉलर के पहले रियायती ऋण से उपलब्ध उपयोग न किए गए 7.69 मिलियन के उपयोग के अंतर्गत 40 गाँवों के विद्युतीकरण के लिए अनुबंध प्रदान किए गए थे। नाइजर में विस्तारित रियायती ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किए गए नाइजर के दोसो, तिलबरी और ताहौआ के 50 गाँवों के 10 मिलियन डॉलर के सौर ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है।

नाइजीरिया

उच्च-स्तरीय संपर्कों ने द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करना जारी रखा। विदेश मंत्री ने 01 सितंबर 2020 को अपने नाइजीरियाई समकक्ष ज्योफ्री ओनेमा के साथ द्विपक्षीय समीक्षा बैठक की। विदेश मंत्री ने अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर 2020 में ओनेमी के साथ टेलीफोन पर बात की।

राज्य मंत्री ने नाइजीरिया के लोकतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जून 2019 में नाइजीरिया का दौरा किया। यात्रा के दौरान, उन्होंने नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति, यमी ओसिनबाजो से भेंट की। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति ने सितंबर 2020 में आयोजित 15 वें सीआईआई-एक्जिम बैंक इंडिया-अफ्रीका परियोजना साझेगारी कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में भी भाग लिया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अपने नाइजीरियाई समकक्ष ओटुनबा रिचर्ड अडेनीये अदेबेयो के साथ टेलीफोन पर बात की और अक्टूबर के पहले सप्ताह में आभासी प्रारूप में द्विपक्षीय समीक्षा बैठक की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच मौजूद व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों की समीक्षा की।

महामारी के प्रभाव के बावजूद इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता रहा और 14 बिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज किया गया। भारत और नाइजीरिया के व्यापारिक समुदायों के बीच बातचीत जारी रही और इस खंड में और भी उत्साह प्रदान किया गया।

भारत के रक्षा जुड़ाव ने भी वर्ष के दौरान सहयोग को आगे और विविधतापूर्ण बनाया है। नाइजीरियाई रक्षा बलों को आईटीईसी के साथ-साथ अन्य प्लेटफार्मों के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए गए थे। नाइजीरिया के साथ हमारी साझेदारी ने सभी पहलुओं में विस्तार किया

ईबीआईडी ने 500 मिलियन अमरीकी डॉलर के रियायती ऋण से नाइजर को कांडाजी बांध के पुनर्वास स्थलों के विद्युतीकरण और बांध क्षेत्र में बिजली वितरण नेटवर्क के उन्नयन के लिए 10.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त परियोजनाएं, तीन राजधानी, मरांडी, दोसो और डिफ्रा क्षेत्रों के लिए 56.7 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य का जल आपूर्ति नेटवर्क विस्तार और उन्नयन कार्य और 14.6 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के कांडादजी बांध के पुनर्वास स्थलों के लिए कृषि सिंचाई परियोजना को आवंटित किया गया था।

भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने के लिए 6.4 टन जीवन रक्षक और अन्य आवश्यक दवाएं दान कीं। भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम और आईसीसीआर छालवृत्ति के माध्यम से विविध विषयों में शैक्षिक और क्षमता निर्माण के अवसर प्रदान करने में नाइजर को अपना समर्थन जारी रखा।

जून 2020 ने छठवें अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन और गांधी जयंती पर 02 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह के समापन समारोह का आयोजन किया गया था।

है जिसमें जहाज के डिजाइन और निर्माण में सहयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास, समुद्री युद्ध क्षेत् आदि जैसे नए रास्ते शामिल हैं। भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत नाइजीरियाई अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छालवृत्ति भी शामिल है।

भारत ने नाइजीरिया को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए आवश्यक दवाओं की 7.8 टन की खेप दान में दी थी। कोविड महामारी के दौरान, भारत और नाइजीरिया के बीच कुल 29 उड़ानें आयोजित की गईं, और नाइजीरिया में फँसे लगभग 7500 भारतीय नागरिकों और इसी तरह भारत में फँसे नाइजीरियाई नागरिकों का प्रत्यावर्तन किया गया। नाइजीरिया के साथ एक एयर ट्रांसपोर्ट/बबल की व्यवस्था पर भी सितंबर में हस्ताक्षर किए गए थे जो दोनों देशों के बीच विशेष उड़ानों के संचालन को जारी रखने में सुविधा प्रदान करेगा।

अगस्त 2020 में बाहरी अंतरिक्ष में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे और कृषि, पर्यावरण, खनन, सूक्ष्म और लघु उपग्रहों और क्षमता निर्माण में अनुप्रयोगों में सहयोग की परिकल्पना की गई थी।

मिशन ने जून 2020 में छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया था। मिशन ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी जयंती का भी आयोजन किया, जिसमें नाइजीरिया के विदेश मंत्री ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्रोताओं को संबोधित किया।

कांगो गणराज्य

भारत और कांगो गणराज्य सौहार्दपूर्ण और मधुर संबंधों का आनंद लेते हैं। भारत कांगो गणराज्य का एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार है। भारत सरकार द्वारा विस्तारित रियायती ऋण (यूएसडी 250 मिलियन) के अंतर्गत वर्तमान में तीन परियोजनाएं - ग्रामीण विद्युतीकरण, एक शहरी परिवहन प्रणाली का विकास और एक सीमेंट प्लांट की स्थापना चल रही हैं। भारत ने क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कांगो के नागरिकों को स्लॉट भी देना जारी रखा।

भारत ने जून 2020 में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 6 टन से अधिक चिकित्सा सहायता दी। विदेश मामलों और स्वास्थ्य के कांगो के मंत्रियों ने मिलता की सहायता की और स्वीकार किया कि यह महामारी से निपटने के लिए प्राप्त चिकित्सा सहायता की सबसे बड़ी खेपों में से एक थी। भारतीय समुदाय ने महामारी से प्रभावित कमजोर परिवारों को सहारा देने के लिए मई 2020 में स्थानीय अधिकारियों को 100,000 अमरीकी डॉलर मूल्य की खाद्य सामग्री भी दान की।

साओ टोम और प्रिंसिपे

भारत और साओ टोम और प्रिंसिपे ने घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। सितंबर 2020 में साओ टोम में एक राजनयिक मिशन खोला गया था। रक्षा और आंतरिक आदेश मंत्री, ऑस्कर अगुडर सैक्रामेंटो ई सोसा, के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में डेफ-एक्सपो 2020 (5-9 फरवरी 2020) के 11 वें संस्करण और “भारत-अफ्रीका रक्षा

सेनेगल

वर्ष के दौरान सेनेगल के साथ संबंध गहरे और मजबूत होते रहे। सेनेगल ने 2020-22 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष पद और 2021-2022 की अवधि के लिए यूएनएससी अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया।

भारत-सेनेगल द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कमी दिखाते हुए 947 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जिसका मुख्य कारण भारत से सेनेगल में चावल के निर्यात में कमी है। भारत से कपड़ों और फार्मास्युटिकल्स के निर्यात में वृद्धि के कारण यह कुछ हद तक सुधरा था। मिशन ने डेयरी, वस्त्र, कृत्रिम गहने, इंजीनियरिंग सामान विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किए जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया और सहयोग के नए रास्ते तलाशने में मदद की।

महामारी के दौरान, वंदे भारत मिशन की दो उड़ानों ने सेनेगल, द गाम्बिया, गिनी बिसाऊ और मॉरिटानियामें फँसे हुए करीब 300 भारतीयों को निकाला। कोविड-19 महामारी के जवाब में, भारत ने अगस्त 2020 में सेनेगल को बड़ी

इससे पहले मार्च 2020 में, भारत सरकार ने कांगो गणराज्य को बाढ़ राहत के लिए मानवीय सहायता के रूप में 100,000 अमरीकी डॉलर का दान दिया था।

मिशन ने जून 2020 में छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, मिशन द्वारा नवंबर 2019 में इसकी स्थापना के बाद यह पहला उत्सव था। मिशन ने 02 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह का समापन समारोह भी मनाया, जिसमें कांगो के मंत्रालयों और संयुक्त राष्ट्र के निवासी क्षेत्रीय समन्वयक अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर महात्मा गांधी के कार्य और जीवन पर एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई थी।

दूतावास, भारतीय संघ के सहयोग से, जुलाई 2020 में एक विशेष चार्टर उड़ान द्वारा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 100 भारतीय नागरिकों को निकालने में कामयाब रहा।

मंत्रियों की बैठक” में भाग लिया। साओ टोम ने संयुक्त राष्ट्र के चुनाव सहित विभिन्न बहुपक्षीय मंचों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। भारत और साओ टोम आर्थिक सहयोग, पारंपरिक चिकित्सा, औषधीय पौधों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी स्थान की खोज और उपयोग के क्षेत्रों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

मात्रा में दवाएं दान कीं।

विकासाम्क सहायता में, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत कई परिचालन रियायती ऋण परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें चावल आत्मनिर्भरता कार्यक्रम के लिए लिफ्ट सिंचाई के पहले चरण के लिए 62.95 मिलियन अमरीकी डॉलर का एक रियायती ऋण, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के दूसरे चरण के लिए 27.5 मिलियन अमरीकी डॉलर, 19 मिलियन अमरीकी डॉलर मत्स्य विकास परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 19 कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के निर्माण के लिए, सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों के अधिग्रहण के लिए 26 मिलियन अमरीकी डॉलर और सेनेगल की स्वास्थ्य सेवा के उन्नयन और पुनर्वास के लिए 24.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रावधान शामिल है।

भारत ने आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल के अधिकारियों को बड़ी संख्या में स्लॉट की पेशकश जारी रखी, जिसमें भारत में विभिन्न पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आईसीसीआर छालवृत्ति भी शामिल है। आईटीईसी दिवस 11 सितंबर 2020 को आभासी प्रारूप में मनाया गया। 2020 का छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग

दिवस आभासी प्रारूप में मनाया गया। ‘गांधीजी फोरम फॉर एथिकल कॉरपोरेट गवर्नेंस’ की मुख्य कार्यकारी द्वारा 24 सितंबर 2020 को फेसबुक पर ‘गांधी जी की

कहानी’ लाइव स्ट्रीम की गई थी।

सिएरा लियोन

फ्रीटाउन, सिएरा लियोन, में भारतीय उच्चायोग 25 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। सिएरा लियोन के साथ और निवेश और विकास के लिए ईसीओडब्ल्यूएस बैंक (ईबीआईडी) के माध्यम से भारत का विकास सहयोग 217.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के बुनियादी ढाँचा क्षेलों को आवृत करता है। वर्ष के दौरान, भारत सिएरा लियोन के कोनो जिले में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ईबीआईडी के माध्यम से 32 मिलियन अमरीकी डॉलर का नया ऋण प्रदान करने पर सहमत हुआ है।

अक्तूबर 2019 में भारत के उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार, भारत ने नवंबर 2020 में सिएरा लियोन को सद्भावना के संकेत के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल प्रदान किया।

भारत ने विभिन्न अफ्रीकी देशों को हमारी सहायता के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए नवंबर 2020 में सिएरा लियोन को लगभग 7 टन दवाएँ दान में दीं।

सिएरा लियोन ने भारत के नए लॉन्च किए गए ई-विद्याभारती और

टोगो

अफ्रीका में 18 मिशन खोलने के भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप 03 सितंबर 2020 को लोमे में भारत का दूतावास खोला गया था। दूतावास वर्तमान में एक होटल से काम कर रहा है और 01 जनवरी 2021 को एक किराए की इमारत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। राज्य मंत्री ने सितंबर 2019 में टोगो की अपनी यात्रा के दौरान टोगो में भारतीय मिशन खोलने की घोषणा की थी। मिशन अभी भी होटल से काम कर रहा है। टोगो के विदेश मंत्री रॉबर्ट ड्यूसी ने टोगो में भारत के दूतावास खोलने की बात स्वीकार की है। भारत और टोगो सौहार्दपूर्ण संबंधों को साझा करना जारी रखते हैं जो टोगो में भारतीय दूतावास की स्थापना से और मजबूत हुए हैं।

दिसंबर 2020 में विदेश मंत्रालय के सहयोग से कार्नेगी इंडिया द्वारा आयोजित किए जा रहे ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में एक डिजिटल सम्मेलन में टोगो गणराज्य के डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल परिवर्तन मंत्री, सीना लॉसन ने भाग लिया। मिशन ने नवंबर 2020 में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। भारत और पश्चिम अफ्रीका के बीच व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए, पीएचडीसीसीआई ने भारतीय विक्रेताओं और पश्चिम अफ्रीकी खरीदारों के बीच एक आभासी

पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका

कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद इस

कहानी’ लाइव स्ट्रीम की गई थी।

ई-आरोग्यभारती कार्यक्रमों में भाग लिया। 82 सिएरा लियोन वासियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए खुद को पंजीकृत किया।

भारत ने सिएरा लियोन का एक मजबूत व्यापारिक भागीदार बनना जारी रखा और सिएरा लियोन द्वारा आयात के मामले में 5 वें स्थान पर रहा। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 140 मिलियन अमरीकी डॉलर था। सिएरा लियोन को भारत का निर्यात 115 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि आयात 25 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

कोविड-19 के कारण सिएरा लियोन में फँसे 600 से अधिक भारतीयों को जून-सितंबर 2020 के दौरान चार चार्टर्ड हवाई जहाजों में भारत लाया गया था।

सिएरा लियोन भारत और सिएरा लियोन विदेश कार्यालय परामर्श की पहली बैठक मार्च 2021 में सचिव/डीजी स्तर पर आयोजित की जाने वाली है। तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सिएरा लियोन भारत और सिएरा लियोन विदेश कार्यालय परामर्श की पहली बैठक मार्च 2021 में सचिव/डीजी स्तर पर आयोजित की जाने वाली है। तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सिएरा लियोन भारत और सिएरा लियोन विदेश कार्यालय परामर्श की पहली बैठक मार्च 2021 में सचिव/डीजी स्तर पर आयोजित की जाने वाली है। तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सिएरा लियोन भारत और सिएरा लियोन विदेश कार्यालय परामर्श की पहली बैठक मार्च 2021 में सचिव/डीजी स्तर पर आयोजित की जाने वाली है। तारीखों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

शिखर सम्मेलन आयोजित किया। यह मिशन भारत और टोगो के बीच व्यापार की संभावनाएं बढ़ाने की तलाश कर रहा है।

एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इंडिया ने ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं, चावल, मक्का और शर्बत की खेती और खेती, बिजली पारेषण लाइनों की स्थापना और टोगो में सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली द्वारा गाँवों के विद्युतीकरण के लिए 30 जून 2020 तक (150) मिलियन अमरीकी डॉलर की पांच रियायती ऋण जारी किए हैं। 52 मिलियन अमरीकी डॉलर के रियायती ऋण क्रेडिट के माध्यम से 161 केवी बिजली पारेषण लाइन स्थापित करने की परियोजना के नवंबर 2020 तक शुरू होने की आशा है और यह 36 महीनों में पूरी हो जाएगी।

कोविड महामारी के दौरान, 2 उड़ानों का आयोजन किया गया था और टोगो में फँसे 186 भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था और इसी तरह भारत में फँसे टोगो नागरिकों को उनके घर देशों में वापस भेजा गया था। महामारी के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता रहा।

कोविड-19 महामारी के दौरान, बुरुंडी में फँसे हुए 18भारतीय नागरिकों को 02 जुलाई 2020 को बुरुंडी-किगाली-मुंबई से विशेष चार्टर्ड उड़ान (एचसीआई, किगाली द्वारा व्यवस्थित) द्वारा निकाला गया था। आईसीसीआर छानवृत्ति योजना 2020-2021 में अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-

अवधि ने उच्च-स्तरीय आभासी बातचीत को चिह्नित किया। भारत-अफ्रीका

राजनीतिक जुड़ाव ने स्वास्थ्य और व्यापार संबंधों की मजबूती पर ध्यान केंद्रित किया। कोविड-19 महामारी के दौरान अफ्रीकी देशों के साथ एकजुटता में, प्रधानमंत्री ने 17 अप्रैल 2020 को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति रामाफोसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जो अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। अपनी बातचीत में, प्रधानमंत्री ने वायरस के खिलाफ संयुक्त अफ्रीकी प्रयास के लिए भारत के पूर्ण समर्थन से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति योवेरी कागुत मुसेवेनी (09 अप्रैल 2020), मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, (17 अप्रैल और 26 मई 2020), इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबुल अहमद अली (06मई 2020), मॉरीशस के प्रधानमंत्री (23 मई 2020) प्रवीण जुगनौथ, फ़िलिप जैसिटो न्यासी, मोज़ाम्बिक के राष्ट्रपति (03 जून 2020), पॉल कागमे, रवांडा के राष्ट्रपति (05 जून 2020), और जॉन पॉम्बे जोसेफ मगफुली, राष्ट्रपति संयुक्त गणराज्य तंजानिया (12 जून 2020) से टेलीफोन पर बात की।

विदेश मंत्री ने केन्या, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा सहित कई अफ्रीकी देशों में अपने समकक्षों से बात की और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीकी लोगों के साथ भारत की एकजुटता को दोहराया और इस संदर्भ में सभीतरह की सहायता की पेशकश की। उनके प्रस्ताव को इन देशों ने गहराई से सराहा।

कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीका को भारत की चिकित्सा सहायता

इस महामारी के दौरान “दुनिया की फार्मैसी” के रूप में भारत की भूमिका पर ध्यान दिया गया है। भारत में एक विश्व स्तरीय दवा उद्योग है जो सभी भौगोलिक और बाजारों में ब्रांड पहचान के साथ सस्ती महत्वपूर्ण दवाओं के लिए पसंदीदा निर्माता है। सरकारी और कई निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों की कई शाखाओं की समन्वित प्रतिक्रिया में, भारत दुनिया भर में दोस्तों और उपभोक्ताओं को इन दवाओं की बड़ी मात्रा में आपूर्ति करने में सक्षम रहा,

बोत्सवाना

मिशन ने, दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय के माध्यम से, दक्षिणी अफ्रीकी क्षेत्र के लिए भारत से चिकित्सा आवश्यकताओं के राहत प्रयासों का समन्वय किया। बोत्सवाना से वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 252 भारतीयों को निकाला गया। बोत्सवाना ने संयुक्त राष्ट्र में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जिसमें यूएनएससी की अस्थायी सीट; अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा

बुरुंडी

कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान, बुरुंडी में फँसे हुए 18भारतीय नागरिकों को 02 जुलाई 2020 को बुरुंडी-किगाली-मुंबई से विशेष चार्टर्ड उड़ान (एचसीआई, किगाली द्वारा व्यवस्थित) द्वारा निकाला गया था। आईसीसीआर छानवृत्ति योजना 2020-2021 में अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-

इथियोपिया

पर्याप्त घरेलू भंडार सुनिश्चित करने के बाद भारत ने 35 अफ्रीकी देशों को एक अनुदान आधार पर महामारी के लिए उनकी प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए चिकित्सा सहायता प्रदान की है। इन आवश्यक दवाओं के अफ्रीका के विभिन्न देशों में महामारी से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों के पूरक होने की आशा है।

असहाय अफ्रीकी नागरिकों की निकासी

भारत ने अफ्रीका में फँसे हजारों भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की सुविधा प्रदान की।इसने दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी, नामीबिया, जिम्बाब्वे और इथियोपिया सहित कई देशों के अफ्रीकी नागरिकों को भारत से उनके देशों में वापस लाने में सहायता की।

ऋण सेवा छूट

जी-20 के एक सदस्य के रूप में, भारत सबसे गरीब देशों के लिए ऋण सेवा भुगतान को स्थगित करने के लिए जी-20 के हाल के फैसले को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो निषिद्धता का अनुरोध करता है। ऋण राहत के लिए पात्र देश विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन पहल के सबसे गरीब देशों की सूची के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र की अल्प विकसित देशों की सूची के हैं।

अप्रैल 2020 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की जी-20 आभासी बैठक के दौरान, भारत ने सबसे गरीब देशों के लिए आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारों द्वारा ऋण सेवा भुगतान के समयबद्ध निलंबन के लिए सहमति व्यक्त की, जिन्होंने सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 में इस तरह के निलंबन के लिए अनुरोध किया है। तदनुसार, भारत ने आज तक कोविड-19 महामारी के कारण ज़ाम्बिया, इथियोपिया, मलावी, मोज़ाम्बिक और लेसोथो के लिए ऋण को निलंबित कर दिया है, जो सभी अफ्रीकी साझेदार देशों को अपने स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सूचकांकों को एक इशारे के रूप में सुधारने के लिए एकजुटता की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। ।

कोविड-19 महामारी के दौरान, बुरुंडी में फँसे हुए 18भारतीय नागरिकों को 02 जुलाई 2020 को बुरुंडी-किगाली-मुंबई से विशेष चार्टर्ड उड़ान (एचसीआई, किगाली द्वारा व्यवस्थित) द्वारा निकाला गया था। आईसीसीआर छानवृत्ति योजना 2020-2021 में अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-

के लिए अंतर सरकारी समिति में; और प्रशासनिक और बजटीय सवालों पर सलाहकार समिति भी शामिल है। भारतीय मूल के व्यक्ति जमाल अहमद को व्यवसाय में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार -2021 से सम्मानित किया गया। वह बोत्सवाना से इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं।

कोविड-19 महामारी के दौरान, बुरुंडी में फँसे हुए 18भारतीय नागरिकों को 02 जुलाई 2020 को बुरुंडी-किगाली-मुंबई से विशेष चार्टर्ड उड़ान (एचसीआई, किगाली द्वारा व्यवस्थित) द्वारा निकाला गया था। आईसीसीआर छानवृत्ति योजना 2020-2021 में अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-

ग्रेजुएट और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए बुरुंडी को 10 स्लॉट की पेशकश की गई थी। अब तक 8 छात्र छानवृत्ति के प्रस्ताव स्वीकार कर चुके हैं और ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं क्योंकि वे महामारी के कारण भारत की यात्रा नहीं कर सकते थे।

प्रधानमंत्री ने 06 मई 2020 को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ टेलीफोन पर बातची की और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इथियोपिया को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सहित भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री के आश्वासन के अनुसरण में, भारत ने इथियोपिया को एचसीक्यू टैबलेट और अन्य जीवनरक्षक एंटीबायोटिक्स सहित चिकित्सा सहायता प्रदान की। इसे 21 अगस्त 2020 को स्वास्थ्य राज्य मंत्री, डेरेजे दुगुमा को सौंप दिया गया था। इथियोपियाई पक्ष के अनुरोध पर, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वाणिज्यिक आधार पर मैसर्स ट्रिडेंट द्वारा 5 मिलियन अमरीकी डॉलर के सर्जिकल फेसमास्क की आपूर्ति की गई थी। मिशन ने 734 भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन की सुविधा के लिए इथियोपियाई एयरलाइंस की 6 चार्टर्ड उड़ानों की सुविधा प्रदान की।

भारत और इथियोपिया ने ‘एयर बबल’ स्थापित करने के लिए 17 नवंबर 2020 को एयर सर्विसेज समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत इथियोपियाई एयरलाइंस भारत के लिए नियमित उड़ानें संचालित करेगी, जिसमें अदीस-दिल्ली-अदीस क्षेत्र में एक साप्ताहिक उड़ान भी शामिल है। इथियोपिया ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों के संचालन के लिए इथियोपिया के लिए सहमति व्यक्त की, जो एयर इंडिया और इथियोपिया एयरलाइंस के बीच पहले की कोड शेयर व्यवस्था को बदल देगा।

गांधी का ग्रैंड फिनाले @ 150 समारोह इथियोपिया में एक समारोह के साथ

एस्वातिनी

मानवीय सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपये मूल्य की आवश्यक दवाएं जून, 2020 में प्रधानमंत्री एम्ब्रोस मंडलुवो दल्मिनी को सौंपी गई थीं।

अगस्त 2020 में, 200,000 अमरीकी डॉलर कृषि मंत्री काबुल जब्बानी मबुजा को सौंपा गया था, लुबुनेन इरिगेशन स्कीम के लिए भारत की अनुदान सहायता से मेफलालेनी समुदाय को वाणिज्यिक खेती से लाभ मिल रहा था।

02 अक्टूबर 2020 को आयोजित गांधी @ 150 समारोहों के लिए, एक मिनी अर्बन फॉरेस्ट की स्थापना की गई थी, जिसमें मबबेन में 150 स्वदेशी पौधे लगाए गए थे।

नवंबर 2020 में, एस्वातिनी साम्राज्य के 42 कानून/विधायी अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर एक विशेष ई-आईटीईसी पाठ्यक्रम आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए

केन्या

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विदेश मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में सहयोग सहित पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष, विदेश मामलों के कैबिनेट सचिव - राजदूत रायचेल ओमामो के साथ टेलीफोन पर तीन बार बातचीत की।

विदेश मंत्रालय के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, रायचेल ओमामो ने 23 सितंबर 2020 को भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 15वें सीआईआई-

अदीस अबाबा शहर के केंद्र में स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल के परिसर में गांधी प्रतिमा पर आयोजित किया गया था। समारोह के दौरान निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं और “स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष” की स्क्रीनिंग आयोजित की गई।

इथियोपिया के उत्तरी टाइग्रे क्षेत्र के घटनाक्रम के बाद, अदीस अबाबा में मिशन ने संयुक्त राष्ट्र मिशन और इथियोपियाई सरकार के माध्यम से, टाइग्रे क्षेत्र से 206 भारतीय नागरिकों की निकासी (11 जनवरी 2021 तक) की सुविधा प्रदान की। मिशन के सहयोग से फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ) ने कोविड-19 के बाद, 11 जनवरी 2021 को भारत और इथियोपिया के बीच व्यापार और निवेश के अवसरों पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 110 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मिशन के सहयोग से सीआईआई ने 29 जनवरी 2021 को भारत-इथियोपिया व्यापार सत्र पर एक और सेमिनार आयोजित किया 09-11 फरवरी 2021 तक अदीस अबाबा में भारत में अध्ययन शिक्षा मेला आयोजित किया गया था। भारत में इथियोपिया के छात्र अफ्रीका के सबसे बड़े छात्र समूहों में से एक हैं।

उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डेमेके मेकोननिस 18-19 फरवरी 2021 को भारत आए थे याला के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट की, विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया और नई दिल्ली में इथियोपियाई दूतावास के नए चांसरी का उद्घाटन किया।

“तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करने” पर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान द्वारा एस्वातिनी के 13 लेक्चरर/टीचर्स के लिए एक और ई-आईटीआई कोर्स आयोजित किया गया था। प्रदर्शन ऑडिट के लिए एस्वातिनी-अनन्य ई-आईटीईसी कार्यक्रम, अनुपालन ऑडिट जनवरी-मार्च 2021 के बीच आयोजित किए जा रहे हैं।

27 नवंबर 2020 को, एस्वातिनी ने आरआईएमपी के लिए एक नई संसद भवन के निर्माण के लिए 108.28 मिलियन अमरीकी डॉलर और एक आपदा रिकवरी साइट के निर्माण के लिए 108.28 मिलियन अमरीकी डॉलर के एक अन्य रियायती ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को अपनी मंजूरी दे दी। वंदे भारत मिशन की उड़ान के माध्यम से 22 भारतीयों को वापस लाया गया।

एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव में बात की। केन्या के व्यापार मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक सचिव ने भी कॉन्क्लेव को संबोधित किया।

मई 2020 में केन्या के लिए 1.54 मिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यक दवाएं भेंट की गईं। जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान इसके लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी। कोविड-19 से संबंधित दवाओं की एक और खेप 12 अगस्त 2020 को केन्या को सौंप दी गई थी। विदेशी मामलों और

स्वास्थ्य के मुख्य प्रशासनिक सचिव समारोह में उपस्थित थे।

पोस्टल कॉर्पोरेशन ऑफ केन्या ने, जिसे ‘पोस्ता केन्या भी कहा जाता है, 02 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस कार्यक्रम में केन्या के महानिदेशक, संयुक्त राष्ट्र और विदेश मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक सचिव और केन्या के आईसीटी मंत्रालय ने भाग लिया।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत पांच एयर इंडिया उड़ानों और चार चार्टर्ड उड़ानों से कुल 1487 फंसे भारतीयों को वापस लाया गया। इन उड़ानों ने भारत से फंसे केन्याई को भी वापस ले जाया गया। भारत और केन्या के बीच “एयर बबल” व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 29 सितंबर

लिसोथो

भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अप्रैल 2020 में लेसोथो को पैरासिटामोल योगों का निर्यात किया।

मलावी

दोनों पक्षों से उच्च स्तरीय आदान-प्रदान द्वारा प्राप्त गति से भारत-मलावी संबंधों में पिछले एक वर्ष में वृद्धि और विकास देखा गया। भारत मलावी के साथ मिलकर काम कर रहा है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं।

भारत मलावी के विकास का एक सक्रिय भागीदार है और कई विकास परियोजनाओं का समर्थन करता है। एक्जिम बैंक ने मलावी में जल परियोजनाओं के लिए 215.68 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की रियायती ऋण के लिए मलावी सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जुलाई 2020 में, मलावी सरकार को 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की दवाओं का उपहार सौंपा गया था। नवंबर 2018 में उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान की गई घोषणा के अनुसार, अक्टूबर 2020 में मानवीय सहायता के लिए मलावी सरकार को 1000 मीट्रिक टन चावल सौंप दिया गया था।

भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत मलावी में कई विकास परियोजनाएं

मोज़ाम्बिक

उच्च स्तर की टेलीफोन वार्ता के कारण वर्ष के दौरान भारत और मोज़ाम्बिक के बीच संबंधों में गति आई, हाल में उच्च स्तर की बातचीत से उत्पन्न गति पर, कोविड-19, विकासोन्मुख सहयोग परियोजनाओं, और व्यापार और व्यापार के खिलाफ लड़ाई में दवा का दान सांस्कृतिक आयोजन किया गया।

प्रधानमंत्री ने मोज़ाम्बिक फिलिप जैसिंटो न्युसी के राष्ट्रपति के साथ फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी द्वारा दोनों देशों में उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने मोज़ाम्बिक में भारतीय निवेश और विकास परियोजनाओं सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण सरगम पर चर्चा की। 15 जनवरी 2020

2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और केन्या की उड़ानों ने व्यवस्था के अंतर्गत काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत ने 20 नवंबर 2020 को मोम्बासा बंदरगाह पर लंगर डाला और दक्षिण सूडान के लिए 70 मीट्रिक टन खाद्य सहायता दी, जिसमें दक्षिण सूडान के लिए गेहूं का आटा, चीनी और चावल शामिल थे, जिन्हें कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से प्रेरित भोजन की कमी का सामना करना पड़ा था।

केन्या के रक्षा बलों के प्रमुख, जनरल रॉबर्ट किबोची ने 02-06 नवंबर 2020 तक भारत का दौरा किया। कार्यभार संभालने के बाद अफ्रीका के बाहर यह उनकी पहली यात्रा थी। उन्होंने रक्षा कर्मचारियों के प्रमुख और तीनों सेना प्रमुखों से भेंट की।

भारत और लेसोथो के बीच 03 दिसंबर 2020 को राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा माफी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मई 2020 में, भारत और मलावी के बीच एनटीपीसी, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और मलावी में विद्युत उत्पादन कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग स्थापित किया गया था। भारत-अफ्रीका कृषि संस्थान और ग्रामीण विकास की स्थापना, वर्तमान में अपनाई जा रही एक महत्वपूर्ण पहल है, जो लिलोंग्वे कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के परिसर में कृषि क्षेत्र में एक पैन-अफ्रीकी प्रमुख संस्थान है। मलावी के राजनीतिक नेतृत्व और आम जनता द्वारा भारत सरकार की इन सद्भावना पहलों को काफी सराहा गया है।

मिशन ने वर्चुअल इंटरैक्शन के माध्यम से 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया। मिशन ने गांधी @ 150 को एक समारोह भी मनाया, उच्चायोग में मलावी के विदेश मंत्री और भारत के उच्चायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से गांधीजी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया।

को राष्ट्रपति नयुसी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए राज्य मंत्री मोज़ाम्बिक गए।

मोज़ाम्बिक में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन अमरीकी डॉलर के रियायती ऋण पर एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और मोज़ाम्बिक अर्थव्यवस्था और वित्त मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार ने मोज़ाम्बिक के राष्ट्रपति के गृहनगर मियोडा में एक जल परियोजना के लिए 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का अनुदान दिया, जो प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए 5 करोड़ रुपये की लागत

से 2008 में आईएफएस-I में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया था। भारत सरकार ने मोजाम्बिक सरकार को 2.3 करोड़ रुपये की 13 आवश्यक दवाएं दान कीं, जिनमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, एज़िथ्रोमाइसिन और पेरासिटामोल भी शामिल था।

मापुटो में मिशन ने मोजाम्बिक एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स एंड कंपनीज और इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच पहला वर्चुअल बिजनेस इवेंट आयोजित किया। इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर में कॉन्फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक एसोसिएशन, मोज़ाम्बिक और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बीच एक वर्चुअल बिजनेस इवेंट का आयोजन किया गया।

नामीबिया

इस अवधि ने नामीबिया के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मोर्चों पर संबंधों को और मजबूत किया, नामीबिया ने इस वर्ष अपनी स्वतंत्रता के 30 वर्ष पूरे किए।

अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार से चिकित्सा सहायता के लिए नामीबियाई सरकार के अनुरोध के जवाब में, अनुदान आधार पर नामीबिया को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की पेशकश की। नामीबिया ने अलग से भारत से रेमेडीसविर की 3,000 खुराकें भी खरीदीं।

नामीबिया में छोटे पर जीवंत भारतीय समुदाय ने उच्चायोग के समर्थन के साथ अप्रैल 2020 में नामीबिया में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान एन \$ 150,000 (लगभग 7.25 लाख रु.) का योगदान दिया और जरूरतमंद लोगों को वितरण के लिए नामीबियाई सरकार को खाद्य उत्पादों और अन्य आवश्यक वस्तुओं का समर्थन प्रदान किया।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विशेष चार्टर्ड उड़ानों द्वारा जून और अगस्त 2020 के बीच नामीबिया से 35 फँसे हुए भारतीयों को जांबिया के रास्ते भारत लाया गया। इसके अतिरिक्त, भारत में फँसे 6 नामीबियाई आईटीईसी/रक्षा प्रशिक्षुओं को मार्च और जुलाई 2020 के बीच नामीबिया में वापस भेजा गया।

एक तरजीही व्यापार समझौते के समापन के लिए 10 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से भारत और दक्षिणी अफ्रीका सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू), विंडहोक में मुख्यालय से वार्ता शुरू हुई। एसएसीयू पक्ष में समन्वयक के रूप में नामीबिया के साथ 15 जुलाई 2020 को छठवें दौर की वार्ता हुई।

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को भारत से निर्यात पर विशेष ध्यान देने के साथ बढ़ावा दिया गया। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कोविड-19 के प्रभाव

रवांडा

प्रधानमंत्री ने 05 जून 2020 को, रवांडा के राष्ट्रपति, पॉल कागमे के साथ टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंधों और कोविड-19 महामारी द्वारा स्वास्थ्य प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 संकट के

मिशन ने मोजाम्बिक में 100 फँसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए दो विशेष उड़ानों का आयोजन किया और 102 भारतीय यात्रियों के साथ मापुटो और नई दिल्ली के बीच दूसरी उड़ान संचालित की गई।

मोजाम्बिक के नेशनल टेलीविजन पर छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का प्रसारण किया गया। मिशन ने 3 महीने लंबा बॉलीवुड रोंगा रंग 1.1 और 1.2 फिल्म समारोह भी मनाया। 02 अक्टूबर से 01 नवंबर, 2020 तक एक महीने की गांधी और खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। 150 वीं गांधी की वर्षगांठ के अवसर पर, आईआईटी बॉम्बे द्वारा प्रदान किए गए 70 सौर लैंप जोकिम चिसानो विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच वितरित किए गए थे।

के बाद मई 2020 से नियमित व्यापार वेबिनार और बड़ी संख्या में वर्चुअल बी2बी बैठक का आयोजन शुरू किया गया था, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इंडो अफ्रीकन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे प्रमुख व्यापार मंडल, कि शामिल थे।

नामीबिया के औद्योगिकीकरण और व्यापार मंत्री, लूसिया लिपुम्बु ने 23 सितंबर 2020 को भारत-अफ्रीका साझेदारी पर 15 वें सीआईआई-एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव के मंत्रिस्तरीय सत्र में भाग लिया।

महात्मा गांधी की 151 वीं जयंती को चिह्नित करने और दो वर्ष लंबे गांधी @ 150 समारोह के समापन के लिए सितंबर और अक्टूबर 2020 में नामीबिया में गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। एक ऑनलाइन “गांधी कथा” और प्रसिद्ध गांधीवादी विद्वानों द्वारा “सभ्यता और अहिंसा: रचनात्मक संभावनाओं” पर एक ऑनलाइन वार्ता आयोजित की गई। विंडहोक में कई वृक्षारोपण गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनमें नामीबियाई सरकार और अन्य स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से नामीबिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, नितुम्बो नंदी-नदितवाह सहित उच्च-स्तरीय भागीदारी देखी गई।

नामीबिया के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं ने, भारत सरकार द्वारा साथी देशों के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के भारतीय अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अगस्त 2020 में आयोजित विशेष ऑनलाइन आईटीईसी पाठ्यक्रमों “महामारी के समय पुलिसिंग” और “कोविड-19: सुशासन प्रथाओं” में भाग लिया।

फरवरी 2021 में भारत-नामीबिया संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र आयोजित किया गया।

प्रभावी प्रबंधन के लिए रवांडा की सराहना की। राष्ट्रपति कागमे ने चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण दान करने का वादा करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।

उच्चायोग के सहयोग से, 10 जून 2020 को, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

में भारत-रवांडा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वर्चुअल बिजनेस मीट का आयोजन किया। मीट में आईसीटी क्षेत्र की विभिन्न भारतीय और रवांडा कंपनियों की भागीदारी देखी गई।

उच्चायोग ने 21 जून 2020 को, एक आभासी योग अभ्यास सत्र का आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।

विदेश मंत्री ने 25 जून 2020 को रवांडा के विदेश सहयोग मंत्री विंसेंट बिरुता के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने जून 2021 में भारत और रवांडा के बीच द्विपक्षीय सहयोग, कोविड-19 स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और आगामी राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों के बीच केगली में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

उच्चायोग ने 02 जुलाई 2020 को, एक चार्टर्ड फ्लाइट की सुविधा प्रदान की, जो रवांडा में फँसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत ले गई और भारत में फँसे रवांडा के नागरिकों को वापस रवांडा ले गई।

दक्षिण अफ्रीका

कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में सहयोग पर चर्चा करते हुए, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रामाफोसा के बीच भारत का उच्च स्तरीय संपर्क अप्रैल 2020 तक जारी रहा।

सितंबर में, विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री, नलदेई पंडोर के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की, और ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की परिषद और एक आभासी आईबीएसए विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान पंडोर के साथ बातचीत की।

अप्रैल 2020 में व्यापार और उद्योग मंत्री अब्राहिम पटेल के अनुरोध के जवाब में, भारत ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में पेरासिटामोल और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की 2 खेपों के निर्यात की सुविधा प्रदान की।

तंजानिया

भारत सरकार ने अप्रैल 2020 में तंजानिया को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और पेरासिटामोल के वाणिज्यिक निर्यात की अनुमति दी।

जांज़ीबार में 92.18 मिलियन अमरीकी डॉलर की रियायती ऋण जल परियोजना को सौंप दिया गया और इस पर काम शुरू हो गया। एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के पास तंजानिया के 25 शहरों में पानी की आपूर्ति के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर रियायती ऋण के अंतर्गत पूर्व-योग्य भारतीय कंपनियों को दिए जाने के लिए अनुबंध हैं। काम के जल्द ही सौंपे जाने की आशा है। भारत के 268.35 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता के साथ विक्टोरिया झील से एक और जलापूर्ति परियोजना शुरू की गई है।

भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, 6 मई से 31 दिसंबर 2020 के बीच की अवधि के लिए 6 रियायती ऋण परियोजनाओं के संबंध में सॉफ्ट लोन के पुनर्भुगतान के लिए तंजानिया सरकार के अनुरोध को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी।

23 सितंबर 2020 को, रवांडा के व्यापार और उद्योग मंत्री, सोरया हकुज़ियरेमी ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 15 वें भारत अफ्रीका कॉन्क्लेव के मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित किया।

उच्चायोग ने 01 अक्टूबर 2020 को, महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ के समारोह के भाग के रूप में, महात्मा गांधी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित वक्ता द्वारा एक आभासी गांधी कथा का आयोजन किया।

भारत और रवांडा के बीच 01 नवंबर 2020 को, द्विपक्षीय ‘एयर बबल’ समझौता लागू हुआ। समझौते के बाद, रवांडा के राष्ट्रीय वाहक, रवांदिर ने किगाली से मुंबई के लिए सीधी उड़ानें शुरू कीं।

विदेश राज्य मंत्री ने 2021 की पहली तिमाही में रवांडा का दौरा किया। यात्रा के दौरान, किगाली में संयुक्त आयोग की पहली बैठक आयोजित की गई थी।

प्रतिष्ठित टॉल्स्टॉय फार्म और फीनिक्स सेटलमेंट में 02 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया था। क्वाजुलु-नताल में स्थापित महात्मा गांधी फीनिक्स सेटलमेंट के ऐतिहासिक हिस्से को सितंबर 2020 में दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्री नालेह पंडोर ने 11 जनवरी 2021 को विदेश मंत्री सेटेलीफोन पर बातचीत की। फोन पर दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए भारत में उपलब्ध वैक्सीन खुराकों पर विस्तृत चर्चा हुई। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय हित के मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय ‘एयर बबल’ की व्यवस्था की घोषणा 28 अक्टूबर 2020 को की गई थी।

एक समारोह में उच्चायुक्त ने औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को मेडिकल स्टोर विभाग (एमएसडी), दार एस सलाम में तंजानिया सरकार के मुख्य फार्मासिस्ट को आवश्यक दवाओं की दूसरी खेप सौंपी।

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न संस्थानों में अध्ययन करने वाले कुल 15 तंजानियन आईटीईसी विद्वानों को भारत से वापस ले जाया गया।

चूंकि तंजानिया में वंदे भारत मिशन की कोई उड़ान नहीं थी, इसलिए मुंबई, कोच्चि, हैदराबाद और दिल्ली के लिए 23 विशेष चार्टर्ड उड़ानों को 29 मई 2020 से 19 जून 2020 तक संचालित किया गया था, जो 2232 यात्रियों को वापस भारत ले आईं।

मिशन ने 26 सितंबर 2020 को हिंदी के प्रचार में शामिल होने के लिए डार एस सलाम में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र (एसवीसीसी) में एक प्रवासी संगठन ‘स्वरंगंगा’ के सहयोग से हिंदी दिवस मनाया। तंजानियाई बच्चों ने भारत का राष्ट्रगान गाया और भारत-तंजानिया संबंधों की बेहतरी की दिशा में काम करने के लिए हिंदी में भी संकल्प लिया।

मिशन ने 21 जून 2020 को अपना छठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आभासी प्रारूप में मनाया। वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ‘मेरा जीवन, मेरा योग’ को व्यापक रूप से प्रचारित किया गया और मिशन को 40 से अधिक प्रविष्टियाँ मिलीं। दर्शकों और योग चिकित्सकों को घरों पर एक लाइव योग सत्र देने के लिए 21 जून 2020 को मिशन और एसवीसीसी के फेसबुक पेज पर एक विशेष योग वीडियो भी अपलोड किया गया था।

मिशन ने आभासी प्रारूप में गांधी @ 150 को मनाया, आयुर्वेद दिवस और शिक्षक दिवस जैसे विशेष कार्यक्रमों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की गई। इसमें तंजानिया के विदेश मंत्री द्वारा अपने भारतीय शिक्षकों को एक विशेष श्रद्धांजलि और दो स्थानीय हस्तियों द्वारा

युगांडा

प्रधानमंत्री ने 09 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति योवेरी कागुटा मुसेवेनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुसेवेनी को आश्वासन दिया कि भारत इस स्वास्थ्य संकट के दौरान अफ्रीका में अपने दोस्तों के साथ एकजुटता से खड़ा है और युगांडा सरकार के अपने क्षेत्र में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों को हर संभव समर्थन देगा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 स्थिति के दौरान, मेजबान सरकार और समाज द्वारा युगांडा में भारतीय प्रवासी के लिए विस्तारित सद्भावना और देखभाल के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की।

विदेश मंत्री ने 25 अप्रैल 2020 को यूगांडा के विदेश मंत्री सैम कुटेस के साथ टेलीफोन पर बात की। यह कॉल प्रधानमंत्री और युगांडा के राष्ट्रपति के बीच आयोजित टेलीफोनिक बातचीत का अनुवर्ती था। विदेश मंत्री ने भारत से दवा की आपूर्ति के आसन्न खेप की पुष्टि की।

भारतीय उद्योग परिसंघ ने 18 अगस्त 2020 को युगांडा के साथ व्यापार करने पर एक डिजिटल सत्र आयोजित किया। युगांडा और भारत के विभिन्न व्यापार संघों, निजी क्षेत्र फाउंडेशन, युगांडा, युगांडा निवेश प्राधिकरण, एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, अजंता फार्मा लिमिटेड, भारत, समता समूह, भारत आदि ने भाग लिया। सत्र में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 07 अक्टूबर 2020 को फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशन युगांडा के सहयोग से युगांडा में भारतीय खनन क्षेत्र के लिए व्यावसायिक अवसरों पर एक और वेबिनार आयोजित किया गया था।

भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15 वीं सीआईआई - एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन 22-24 सितंबर 2020 को आभासी मंच पर किया गया था। युगांडा के सरकार के व्यापार मंत्री, अमेलिया क्यंबड ने इसमें भाग लिया और “द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय सत्र में महाद्वीपीय स्तर

आयुर्वेद का समर्थन शामिल था।

गांधी जयंती 02 अक्टूबर 2020 को दार एस सलाम विश्वविद्यालय में मनाई गई थी। उच्चायोग और एसवीसीसी के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से 03 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध गांधीवादी वक्ता द्वारा गांधीकथा के रिकॉर्ड किए गए संस्करण की एक विशेष स्ट्रीमिंग की गई थी।

नई दिल्ली में 14-15 जनवरी 2021 को प्रथम भारत-तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई। तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स के 4 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 जनवरी 2021 को नई दिल्ली का दौरा किया। तंजानिया वायु सेना के कमांडर, मेजर जनरल जी. डब्ल्यू. इग्राम ने 03-07 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु में आयोजित एयरो इंडिया 2021 में भाग लिया था।

भारत ने मुख्य भूमि तंजानिया के लिए दो खेपों में 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की दवाइयाँ भेंट कीं और जनवरी 2021 में ज़ांज़ीबार द्वीप पर 1.36 करोड़ रुपये की दवाएँ भेजी गईं।

की साझेदारी के माध्यम से अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार और निवेश को बढ़ाने” पर एक विशेष भाषण दिया।

कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान, चार विशेष चार्टर्ड उड़ानों के द्वारा युगांडा में फँसे भारतीय नागरिकों को निकाला गया था। पहली उड़ान 16 जून 2020 को 188 यात्रियों के साथ मुंबई के लिए आयोजित की गई थी। दूसरी उड़ान 18 जून 2020 को 185 यात्रियों के साथ दिल्ली में आयोजित की गई। 16 जुलाई 2020 को 188 यात्रियों के साथ मुंबई के लिए तीसरी उड़ान और 18 जुलाई 2020 को 171 यात्रियों के साथ तिरुवनंतपुरम के लिए चौथी उड़ान की व्यवस्था की गई थी।

मिशन मोशनवर्क्स रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और भारत और युगांडा औद्योगिक अनुसंधान संस्थान (यूआईआरआई) युगांडा के बीच स्वचालित एन -95 फेस मास्क बनाने की मशीन के वाणिज्यिक निर्यात में तेजी लाया। मशीन युगांडा पहुँच गई है और यूआईआरआई, युगांडा द्वारा प्राप्त की गई है।

भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए मई 2020 में युगांडा को 100,000 एचसीक्यू टैबलेट और 100,000 पेरासिटामोल टैबलेट दान किए। 300,000 एचसीक्यू टैबलेट और 750 किलोग्राम एचसीक्यू एपीआई कच्चे माल के वाणिज्यिक निर्यात की भी अनुमति दी गई थी। भारत ने दवाओं की एक बड़ी खेप (लगभग 1.2 करोड़ रु. + भाड़ा 0.7 करोड़ रु.) भी उपहार में दी। भारत ने युगांडा को 1.9 करोड़ रुपये की अन्य जीवन रक्षक दवाएं भी दान कीं।

कोविड की अवधि के दौरान, अप्रैल-सितंबर 2020 से भारत में फार्मास्यूटिकल्स निर्यात में काफी वृद्धि देखी गई, जो 111.72 मिलियन अमरीकी डॉलर था, यह 2019-20 में 163.84 मिलियन अमरीकी डॉलर और 2018-19 में 160.06 मिलियन अमरीकी डॉलर के कुल निर्यात की तुलना में अधिक था।

जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री की युगांडा यात्रा के दौरान, भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, भारत ने नागरिक और रक्षा बलों के उपयोग के लिए कुल 88 वाहन उपहार में दिये (44 प्रत्येक), नागरिक उपयोग के लिए 44 उपयोगिता वाहन सौंपे गए, मार्च 2020 में विदेश मंत्रालय को, और रक्षा बलों के उपयोग के लिए 36 वाहनों (10 बसों, 10 टुकड़ी वाहक, 2 एम्बुलेंस और 14 मोटरसाइकिल) को 24 अगस्त 2020 को उच्चायुक्त द्वारा युगांडा के रक्षा और वयोवृद्ध मामलों के अधिकारी एडॉल्फ मावेन बेज को सौंप दिया गया था।

युगांडा सरकार के पूर्वी अफ्रीकी सामुदायिक मामलों के मंत्री श्री काहिन्दा ओटफायर को 11 दिसंबर 2020 को चार एसयूवी (महिंद्रा एक्सयूवी) के सौंपे गए थे। जुलाई 2018 की अपनी युगांडा यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के लिए क्षमता निर्माण और सहायक बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए वाहनों का उपहार 929,705 अमरीकी डॉलर के वित्तीय समर्थन का हिस्सा था।

उच्चायुक्त ने 05 अगस्त 2020 को युगांडा सरकार के पूर्वी अफ्रीकी सामुदायिक मामलों के मंत्री मेजर जनरल (भूतपूर्व) कहिन्दा ओताफायर को 20 लैपटॉप भी सौंपे थे।

युगांडा को आईसीसीआर छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2020-21 के लिए अंडर-ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट और पीएचडी के लिए 35 स्लॉट की पेशकश की गई थी। 30 छात्र जिन्होंने छात्रवृत्ति के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है, वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी व्यवधान के कारण वे भारत की यात्रा नहीं कर सकते थे।

युगांडा में आर्ट ऑफ लिविंग के सदस्यों के सहयोग से एक ऑनलाइन कार्यक्रम

जाम्बिया

भारत और जाम्बिया ने अपने सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को जारी रखा। 2005 के डब्ल्यूटीओ हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणा के अंतर्गत भारत की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, भारत ज़ाम्बिया को शुल्क-मुक्त बाज़ार पहुँच और अधिमान्य कर्तव्यों के साथ-साथ व्यापार वीजा-संबंधित रियायतों जैसी व्यापार से संबंधित विभिन्न रियायतें प्रदान करता है। ज़ाम्बिया भारत के निजी निवेशों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना हुआ है, फार्मास्यूटिकल मैनुफैक्चरिंग से लेकर कॉपर केबल और खनन तक 5 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का निवेश हुआ है।

इन वर्षों में, जाम्बिया ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। 2020 में, ज़ाम्बिया ने 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी, प्रशासनिक और बजट संबंधी प्रश्नों पर सलाहकार समिति, और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जो मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का संकेत है।

आर्थिक और विकास सहयोग, जाम्बिया के साथ भारत के जुड़ाव की मुख्य विशेषता है। भारत ज़ाम्बिया को आर्थिक सहायता प्रदान करता है भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन और आईसीसीआर द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति

“योगगृह” के माध्यम से 21 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बाद में, भारतीय उच्चायोग, हिंदू स्वयंसेवक संघ और भारतीय संघ ने भी 28 जून 2020 को एक और ऑनलाइन योग दिवस समारोह का आयोजन किया।

उच्चायोग ने 02 अक्टूबर 2020 को भारतीय समुदाय के सदस्यों और प्रमुख युगांडावासियों के साथ अपने परिसर में महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में लगभग 100 मेहमानों ने भाग लिया और 200 लोगों ने ऑनलाइन देखा। युगांडा के उपराष्ट्रपति, एडवर्ड सेस्केन्डी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने उच्चायोग परिसर में एक ‘चरखे’ का अनावरण किया। चरखा खादी भारत से प्राप्त हुआ था।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में मंत्रालय की ‘इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी’ की पहल के अंतर्गत, 21 नवंबर 2020 - 28 दिसंबर 2020 से कंपाला में भगवान महावीर विकास सहयोग समिति के सहयोग से एक कृत्रिम अंग शिविर का आयोजन किया गया। युगांडा संसद के अध्यक्ष और उच्चायुक्त रेबेका कडगा द्वारा 28 नवंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर शिविर का उद्घाटन किया गया था। युगांडा के बुजुर्ग और विकलांग, निर्माण और परिवहन मंत्री, राज्य के वित्त और निवेश और निजीकरण मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री ने शिविर का दौरा किया। शिविर के दौरान कुल 513 व्यक्तियों को कृत्रिम अंग लगाये गये।

कंपाला में 23 जनवरी 2021 को एक खादी प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, जहाँ खादी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। कंपाला में राजनयिक समुदाय सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हुए।

के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम और आईटीईसी कार्यक्रमों के अंतर्गत पेश किए जाने वाले कौशल विकास पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला में सहायता करता है। आईटीईसी डिफेंस के अंतर्गत, जाम्बियाई सेना का एक उम्मीदवार, डीएसएससी, वेलिंगटन में जुलाई 2020 में डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज कोर्स -76 में शामिल हुआ। जाम्बिया के 8 उम्मीदवारों ने ई-आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कोविड-19 और चिकित्सा संबंधी पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

जाम्बिया में 650 प्राथमिक स्वास्थ्य पोस्टों की स्थापना कार्यान्वयन के एक उन्नत चरण में है, भारत सरकार द्वारा समर्थित 68 मिलियन अमरीकी डॉलर और एक्जिम बैंक द्वारा समर्थित लुसाका की सड़कें अपक्षय परियोजना के एक्जिम बैंक के खरीदारों द्वारा 301 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण से वित्त पोषित होने की आशा है। इसे कोविड-19 संबंधित बाधाओं के बावजूद समय से पहले पूरा करने की आशा है।

जाम्बिया की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को बढ़ाने के लिए, भारत ने मई 2020 में जाम्बिया के स्वास्थ्य मंत्री चीतलू चिलुफिया और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को औपचारिक रूप से 6000 किलो की दवाइयाँ सौंपीं। अगस्त 2019 में जाम्बिया के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान की गई

एक घोषणा के अनुसार, भारत ने 1000 मीट्रिक टन गैर-बासमती चावल भी दान किया।

भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत-जाम्बिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 23 सितंबर 2020 को हुई। दोनों पक्षों ने भूविज्ञान और खनन में क्षमता निर्माण और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियों के बीच इस क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

मिशन ने 8 चार्टर्ड उड़ानों का आयोजन किया, जिसमें 4 विदेशी नागरिकों

सहित 649 व्यक्तियों को भारत में वापस लाया गया। पहली चार्टर्ड उड़ान में नामीबिया से 26 और जिम्बाब्वे से 30 भारतीय नागरिकों को 09 जून 2020 को भारत लाया गया था।

कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए, मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और शिक्षक दिवस मनाया गया, जो मिशन के फेसबुक पेज पर लाइव वेबकास्ट किए गए थे। गांधी @ 150 समारोह के समापन पर, मिशन ने 03 अक्टूबर 2020 को प्रसिद्ध गांधीवादी वक्ता द्वारा गांधी कथा का आभासी प्रसारण किया।

ज़िम्बाब्वे

कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2020 के दौरान भारत-जिम्बाब्वे संबंध विकसित होते रहे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा आवश्यकता की पारस्परिक छूट पर हस्ताक्षर किए गए समझौते को 30 अक्टूबर 2020 से प्रभावी किया गया था।

आभासी प्रारूप के माध्यम से व्यावसायिक वार्ता जारी रही। उपराष्ट्रपति, जनरल (सेवानिवृत्त) कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा और विदेश मामलों के मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री सिबुसिसो मोयो 24 सितंबर 2020 को भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर सीआईआई-एक्जिम बैंक वर्चुअल कॉन्क्लेव में शामिल हुए। 'भारत और जिम्बाब्वे के बीच व्यापार के अवसरों' पर सीआईआई द्वारा 07 अक्टूबर 2020 को आयोजित आयोजित वेबिनार में विदेश मंत्री मोयो ने भी भाग लिया। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए 21 अक्टूबर 2020 को जिम्बाब्वे के स्वास्थ्य और बाल देखभाल

मंत्रालय के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया।

वर्ष के दौरान, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए जिम्बाब्वे सरकार को 1.05 मिलियन अमरीकी डॉलर की दवाएं दान की गईं। चक्रवात ईदई सहित प्राकृतिक आपदाओं से पैदा होने वाली खाद्य कमियों पर काबू पाने में मदद करने के लिए जिम्बाब्वे की सरकार को 22 अक्टूबर 2020 को 1000 मीट्रिक टन चावल की एक खेप सौंपी गई थी। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति द्वारा इन पहलों की सराहना की गई थी।

भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने अनुभव को जिम्बाब्वे सरकार के साथ साझा किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के देश में फँसे हुए नागरिकों के प्रत्यावर्तन को सुनिश्चित करने के लिए समन्वित हैं। जिम्बाब्वे सरकार के अनुरोध पर, भारत ने जून 2020 के महीने में जिम्बाब्वे को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के निर्यात की सुविधा प्रदान की।

8

यूरोप तथा यूरोपीयन यूनियन

अल्बानिया

भारत-अल्बानिया के द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण हैं तथा पारस्परिक विश्वास और समझ के बने रहते हैं। 6ठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आभासी रूप से मनाया

गया। आयुर्वेद दिवस पर आयोजित वेबिनार में अल्बानिया से चिकित्सकों, विशेषज्ञों तथा आयुर्वेद के प्रति उत्साही लोगों ने भाग लिया।

आस्ट्रिया

भारत और आस्ट्रिया के मधुर एवं सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। वैश्विक महामारी के बीच वर्ष के दौरान नेताओं तथा विदेश मंत्रियों के मध्य दूरभाष वार्ताओं, व्यापारिक चर्चाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा लोगों से बातचीत के द्वारा द्विपक्षीय संबंध और अधिक सशक्त हुए।

विदेशी मंत्री की 11 मई 2020 को यूरोप तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों पर आस्ट्रिया के मंत्री के साथ दूरभाष पर बातचीत हुई। उन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के अनुभव सांझा किए तथा वे कोविड-19 की रोकथाम तथा इससे लड़ने पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। आस्ट्रिया में भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए विदेशी मंत्री ने विदेश मंत्री शैलेनबर्ग को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री शैलेनबर्ग ने भी विदेशी मंत्री को वियना आमंत्रित किया।

26 मई 2020 को प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान दर बेलन के साथ

टेलीफोन पर बातचीत हुई। नेताओं ने कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य तथा आर्थिक विपरीत प्रभावों से निपटने के लिए अपने देशों में किए गए उपायों पर विचार सांझा किए। दोनों नेताओं ने कोविड पश्चात के विश्व में भारत-आस्ट्रिया संबंधों को और अधिक सशक्त तथा वैविध्यपूर्ण बनाने की सांझी इच्छा को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, शोध तथा नवोन्मेष, एसएमई आदि जैसे क्षेत्रों में और अधिक सहयोग के लिए अवसरों को उभारा।

भारत-आस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग की प्रारम्भिक बैठक 29 सितम्बर 2020 आयोजित हुई। बैठक में जे ईसी तंत्र में जान डालने तथा इसे और अधिक परिणामोन्मुखी बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई।

विपना में हम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने 2 नवम्बर 2020 को आस्ट्रिया के साथ एकजुटता प्रकट की। आस्ट्रिया गणराज्य के फेडरल

चांसलर सेबेस्टियन कूर्ज़ ने प्रधानमंत्री के संदेश का उत्तर दिया और प्रधानमंत्री को सराहना पत्र भी भेजा ।

आस्ट्रिया गणराज्य के डिजिटल एवं आर्थिक मामलों के मंत्री मार्गरेट श्रैमबॉक ने 14-18 दिसम्बर 2020 के दौरान मंत्रालय के साथ कार्नेजी एनडोअमेंट

बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना

बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना (बी आई एच) के साथ भारत का संबंध वर्ष के दौरान स्थिर बने रहे। बी आई एच की जनता जिसने पूर्व में गहन जातीय संघर्ष देखा है, के द्वारा भारत को इसके जीवित लोकतंत्र तथा विविधता के लिए पसंद किया

फॉर इंटरनेशनल पीस इंडिया द्वारा आयोजित 5वीं वार्षिक वर्चुअल ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के दौरान “ इंडिया एंड आस्ट्रिया : इम्पीरिटिव्स फॉर ए डिजिटल फ्यूचर” पर विशेष संबोधन दिया ।

जाता है। संस्कृति और योग द्विपक्षीय संबंधों के लोकप्रिय तंतु हैं। जनवरी-जुलाई 2020 की अवधि के लिए कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 40.8 मिलियन यू एस डॉलर था ।

बुल्गारिया

बुल्गारिया द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में दोनों तरह से शक्तिशाली साझेदार रहा जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट, युनेस्को, पोस्टल ऑपरेशंस कौंसिल आदि के लिए भारत की आशावादी को समर्थन देता रहा है।

विदेशी मंत्री तथा बुल्गारिया के न्यायिक सुधार के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इकातरिना ज़हारीवा ने वैश्विक महामारी द्वारा लाई गई चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री इकातरिना ज़हारीवा ने बुल्गारिया और ईयूके नागरिकों को विशेष उड़ानों द्वारा आकस्मिक निकास सुलभ कराने के लिए विदेशी मंत्री को धन्यवाद दिया जिसमें अंतिम उड़ान 09 अप्रैल को भरी गई थी। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बोयको बोरिसोव ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री को बधाई दी तथा योग के लाभों का वर्णन किया।

6ठा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अलेक्ज़ेंडर नेव्स्की केथेड्रल तथा सोफिया में नेशनल थियेटर जैसे प्रतिष्ठित स्थानों सहित बुल्गारिया के 39 शहरों और नगरों में मनाया गया। कोविड महामारी के चलते 74वां स्वतंत्रता दिवस सोफिया में एक हाइब्रिड कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। साथ ही, गांधी@150 समारोह का ग्रैंड फिनाले बुल्गारिया की समुद्री राजधानी वार्ना में आई सी सी आर द्वारा भेंट की गई गांधी जी की प्रतिमा के अनावरण से हुआ। नवम्बर 2020 में वर्चुअल टैगोर इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट्स फेस्टिवल, विश्व रंग 2020 के लिए बुल्गारिया एक साझेदार देश था।

बुल्गारिया गणराज्य के न्यायिक सुधार के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इकातरिना ज़हारीवा के 'रायसीना डायलॉग 2021' में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की अपेक्षा है।

क्रोएशिया

क्रोएशिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तथा एन एस जी में भारत की सदस्यता का समर्थन करता है। क्रोएशिया ने भारत से क्लोरोक्वीन फास्फेट की 400,000 टेबलेट आयात की जो महामारी की स्थिति वाली संकटमय अवधि में 20,000 कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा है। वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम था 02 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की अर्ध-प्रतिमा की

स्थापना जो क्रोएशिया की ऐसी पहली अर्ध-प्रतिमा है। इस अर्ध-प्रतिमा का अनावरण क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज लेंकोविस(क्रोएशिया के प्रधानमंत्री द्वारा अर्ध-प्रतिमा के अनावरण का ऐसा पहला दृष्टांत) तथा ज़गरेब मेयर मिलान बेंदिक द्वारा किया गया।

साइप्रस

साइप्रस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन करता रहा। साइप्रस ने युनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आई सी एच) के रक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में भी भारत की आशावादी को पारस्परिक समर्थन उपलब्ध कराया है।

भारत में 8वां बड़ा निवेशक साइप्रस है जिसका अप्रैल 2000 – जून 2020 के दौरान सकल निवेश 10.757 बिलियन यू एस डॉलर था। एफ डी आई इक्विटी इनफ्लो के रूप में ये निवेश सेवाओं, कम्प्यूटर व सॉफ्टवेयर, वाहन निर्माण, विनिर्माण उद्योग, रीयल इस्टेट, कार्गो हैंडलिंग, निर्माण, शिपिंग तथा दवा निर्माण के क्षेत्रों में किए गए। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान

भारतीय नागरिकों को सतत सहयोग के अलावा 15 जुलाई 2020 को एस चार्टर फ्लाइट से भारतीय नागरिकों (137 यात्री) की वापसी हुई। इज़राइल के माध्यम से भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्वीन की एक खेप साइप्रस को सुलभ कराई जिसके लिए साइप्रस की सरकार ने आभार व्यक्त किया तथा कोविड-19 की अपूर्व महामारी के निपटने में साइप्रस को मदद के लिए भारत के सहयोग के लिए सराहना प्रकट की।

राजनीतिक निदेशक तथा संयुक्त सचिव के स्तर पर विदेश कार्यालय विचार-विमर्श(एफ ओ सी) 10 दिसम्बर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई।

चेक गणराज्य

इस वर्ष भारत-चेक द्विपक्षीय संबंधों में उन्नति देखी गई जो 2018 से भारत के राष्ट्रपति के चेक गणराज्य को तथा चेक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के भारत को उच्च स्तरीय दौरों से उत्पन्न हुई 2020 को दोनों देशों के मध्य सशक्त तथा विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक तथा रक्षा संबंध वाला देखा जा सकता है। 1.5 बिलियन यू एस डॉलर के लगभग का द्विपक्षीय व्यापार और भारतीय व चेक कंपनियों के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश दोनों देशों के लिए व्यापार तथा निवेश संबंध के महत्व को दर्शाता है।

कोविड त्रासदी के दौरान विदेशी मंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को चेक विदेश मंत्री टॉमस पेद्रीसेक का बात की तथा कोविड संबंधी मामलों सहित द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने में रुचि प्रकट की। चेक विदेश मंत्री ने चेक गणराज्य जाने वाले कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए कोटा बढ़ाने तथा उनकी वीज़ा प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने में भी रुचि दर्शाई। महामारी के प्रारम्भिक चरण के दौरान अनुरोध के उत्तर में चेक कम्पनियों ने पी पी ई, मास्क आदि महत्वपूर्ण उपकरण के विनिर्माण के लिए भारतीय कम्पनियों के साथ काम करने में समर्थन का प्रदर्शन

डेनमार्क

इस वर्ष के दौरान द्विपक्षीय संबंध सशक्त होते रहे और विदेशी मंत्री तथा डेनिश विदेश मंत्री और साथ ही दोनों प्रधान मंत्रियों के मध्य दूरभाष तथा वर्चुअल शिखर सम्मेलनों के माध्यम से गहन वार्ताएं हुईं। महामारी के बावजूद 4 जे

किया। छात्रों सहित 100 से अधिक फंसे भारतीय नागरिकों को वंदे भारत उड़ानों के द्वारा चेक गणराज्य के अलग-अलग भागों का भारत वापस भेजा गया।

बापू@150 के समारोहों की परिणति में प्रधानमंत्री अंद्रेज बाबीस, विदेश मंत्री टॉमस पेद्रीसेक और पर्यावरण मंत्री रिचर्ड ब्राबेक की ओर से वीडियो संदेश/ट्वीट के माध्यम से चेक सरकार ने उच्चतम स्तर पर सक्रिय रूप से भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग से जुड़े कई चेक संगठनों तथा चेक नागरिकों ने पूरे देश में आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भाग लिया।

भारत और चेक गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र निकायों तथा अन्य बहुपक्षीय संगठनों के चुनावों में एक-दूसरे की आशावादी का समर्थन किया है। चेक प्रधानमंत्री अंद्रेज बाबिस ने उनके नेतृत्व वाली सर्वोच्च रैंड कौंसिल में भारतीय वैज्ञानिक को नामित भी किया था।

नार्मार्क द्वारा उठाए गए कदमों पर टिप्पणियों का मिलान किया।

डब्लु जी आयोजित की गई तथा 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जबकि डेनिश कम्पनियों द्वारा भारत में कई महत्वपूर्ण निवेश किए गए।



प्रधानमंत्री और डेनमार्क के प्रधानमंत्री 28 सितम्बर 2020 को भारत-डेनमार्क वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में

भारत और डेनमार्क के बीच 3सरी जेसीएम 12 मई 2020 को वीडिओ कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित की गई। विदेशी मंत्री तथा डेनिश विदेश मंत्री जेपे कोफोद ने भारत-डेनमार्क संबंधों पर तथा द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त करने पर चर्चा की जिसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी, शहरीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित समाधानों, भोज्य पदार्थों के प्रसंस्करण तथा और अधिक शक्तिशाली राजनीतिक साझेदारी के साथ-साथ भारत और डेनमार्क के मध्य हरित सामरिक साझेदारी सृजित करने पर फोकस रहा।

14 मई 2020 को प्रधानमंत्री तथा डेनिश प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिकसन ने टेलीफोन पर बात की जिस दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत व डेनमार्क द्वारा उठाए गए कदमों पर टिप्पणियों का मिलान किया।

प्रधानमंत्री तथा डेनिश प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिकसन ने अपना सर्वप्रथम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 28 सितम्बर 2020 को किया जिसमें वे भारत-डेनमार्क संबंधों

को हरित सामरिक सांझेदारी तक ले जाने पर सहमत हुए। भारत या डेनमार्क द्वारा किसी देश के साथ हस्ताक्षरित की जाने वाली यह प्रथम हरित सामरिक सांझेदारी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक नए युग की सांझेदारी है और यह द्विपक्षीय संबंधों में एक नए आयाम जोड़ेगी और आर्थिक संबंधों तथा हरित वृद्धि को विस्तार देने, वैश्विक चुनौतियों को सम्बोधित करने में सहयोग को सशक्त करने में सहायक होगी जिसमें पेरिस समझौते के कार्यान्वयन तथा जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों पर फोकस है।

डिजिटलीकरण की अवधि के दौरान(25 जून 2020) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा डेनिश एजेंसी फॉर डिजिटाइज़ेशन के बीच तीन संयुक्त कार्यात्मक समूह (जे डब्लू जी) आभासी रूप से आयोजित किए गए; आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, बिज़नेस एंड फाइनेंशल अफेयर्स के बीच शहरी विकास (26 जून 2020), तथा विद्युत मंत्रालय और डेनिश एनर्जी एजेंसी के बीच ऊर्जा सहयोग (8 सितम्बर 2020) पर। ऊर्जा सहयोग पर दूसरा जे डब्लु जी 18 नवम्बर 2020 को विद्युत मंत्रालय तथा डेनिश एनर्जी एजेंसी के बीच आयोजित हुआ।

की कई कम्पनियों के साथ वर्चुअल सी आई आई इंडिया-नॉर्डिक-बाल्टिक कनक्लेव में भाग लिया । जैवप्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा यंत्रों में सहभागिता के लिए 25 जून 2020 को इनवेस्ट इंडिया वेबीनार आयोजित किया गया ।

एस्तोनिया

इस वर्ष के दौरान एस्तोनिया के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। कोविड-19 महामारी के कारण आभासी बैठकों तथा कार्यक्रमों पर फोकस रहा । एस्तोनिया के विदेश मंत्री उर्मास रींसालु ने 5 नवम्बर2020 को एस्तोनिया

फिनलैंड

फिनलैंड के साथ भारत के संबंध मधुर एवं मैत्रीपूर्ण रहे । 22 अक्तूबर2020 को विदेशी मंत्री की फिनलैंड के विदेश मंत्री पेका हाविस्तो के साथ टेलीफोन पर बात हुई । साइबर सुरक्षा, जैवप्रौद्योगिकी, तथा व्यापार एवं निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्रों में होने वाले वर्चुअल सेमीनारों तथा बैठकों से आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध केंद्र बिंदु रहे ।

विल सिनारी, विकास सहयोग एवं विदेशी व्यापार मंत्री ने 5 नवम्बर2020 को फिनलैंड की कई कम्पनियों के साथ वर्चुअल सी आई आई इंडिया-नॉर्डिक-बाल्टिक कनक्लेव में भाग लिया । विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर एक संयुक्त

ग्रीस

भारत-ग्रीस विदेशी कार्यालय विचार-विमर्श का 12वां राउंड 09 अक्तूबर 2020 को आयोजित हुआ । आभासी रूप से आयोजित एफ ओ सी के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहूपक्षीय तथा ई यू प्राथमिकताओं एवं उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई ।

29 अक्तूबर 2020 को विदेशी मंत्री और उनके ग्रीक समकक्ष निकोस डेंडियास के बीच वर्चुअल बैठक हुई । बातचीत का केंद्र बिंदु द्विपक्षीय, क्षेत्रीय

हंगरी

वर्ष के दौरान हंगरी के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों में वृद्धि हुई हालांकि महामारी के कारण गतिविधियों एवं विनिमयों की गति महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुई । 2021-2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अस्थायी सदस्यता को हंगरी ने समर्थन दिया । दोनों देश द्विपक्षीय तथा बहूपक्षीय क्षेत्रों में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमत हुए । इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आई सी डब्लु ए), नई दिल्ली तथा

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा डेनिश एजेंसी फॉर डिजिटाइज़ेशन के बीच तीन संयुक्त कार्यात्मक समूह (जे डब्लू जी) आभासी रूप से आयोजित किए गए; आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा डेनिश मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, बिज़नेस एंड फाइनेंशल अफेयर्स के बीच शहरी विकास (26 जून 2020), तथा विद्युत मंत्रालय और डेनिश एनर्जी एजेंसी के बीच ऊर्जा सहयोग (8 सितम्बर 2020) पर। ऊर्जा सहयोग पर दूसरा जे डब्लु जी 18 नवम्बर 2020 को विद्युत मंत्रालय तथा डेनिश एनर्जी एजेंसी के बीच आयोजित हुआ।

की कई कम्पनियों के साथ वर्चुअल सी आई आई इंडिया-नॉर्डिक-बाल्टिक कनक्लेव में भाग लिया । जैवप्रौद्योगिकी तथा चिकित्सा यंत्रों में सहभागिता के लिए 25 जून 2020 को इनवेस्ट इंडिया वेबीनार आयोजित किया गया ।

समिति की आभासी बैठक 17 नवम्बर 2020 को आयोजित की गई जिसमें दोनों देशों के बीच 5जी,स्थिरता और क्वांटम कम्प्यूटिंग को भविष्य के सहयोग के तीन क्षेत्रों की पहचान की गई ।

26 नवम्बर 2020 को दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा पर्यावरण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । एक अन्य समझौता ज्ञापन 3 दिसम्बर 2020 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा जीयोलॉगिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड के बीच भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों के क्षेत्र में हस्ताक्षरित हुआ ।

तथा अंतरराष्ट्रीय मामलों पर था जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने तथा पूर्वी मेडीटेरेनियन तथा दक्षिण एशिया के घटनाक्रम पर बल दिया गया ।

विदेशी मंत्री ने निकट भविष्य में ग्रीस का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की । मार्च 2021 में एथेंस में आयोजित किए जाने वाले ग्रीस 'फूड एक्सपो' में भारत हिस्सा लेगा ।

इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड (आई एफ ए टी), बुडापेस्ट के बीच दूसरी वार्ता 10 सितम्बर 2020 को हुई । 29 जुलाई 2020 को इंडिया-हंगरी संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति की 11वीं बैठक हुई । जल के क्षेत्र में पहली पूर्व-जे डब्लु जी वर्चुअल बैठक 20 नवम्बर 2020 को हुई जिसमें आगामी जे डब्लु जी बैठक के दौरान चर्चा के लिए रोड मैप तैयार हुआ

आइसलैंड

संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सकारात्मक सहयोग के साथ भारत और आइसलैंड के बीच संबंध मधुर एवं मैत्रीपूर्ण बने रहे । सतत मत्स्य विकास के क्षेत्र में सहयोग पर इंडिया-आइसलैंड ज्वायंट वर्किंग ग्रुप (जे डब्लु जी)की पहली बैठक 2 जुलाई 2020 वर्चुअल रूप में हुई । दोनों पक्षों ने ठोस परिणामों के लिए मत्स्य के क्षेत्र में सहयोग के तरीकों पर चर्चा की ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

लिथुआनिया

2021-22 की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने पर लातविया के विदेश मंत्री एड्गर्स रिकेविक्स ने भारत को बधाई दी । लातविया ने संगीत शिक्षा एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग पर नागालैंड राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार द्वारा 18 नवम्बर को ई-वैश्विक शिखर सम्मेलन “इंडिया एंड लातविया : ए

लिचेन्सटीन

भारत और लाइचेंसटीन की रियासत के बीच द्विपक्षीय संबंध सुचारू रूप से बने रहे । दूतावास ने 24 7 आपातकालीन नम्बर स्थापित किए तथा कोविड-19 लॉकडाउन के कारण लाइचेंसटीन की रियासत में फंसे भारतीय नागरिकों को

लिथुआनिया

भारत और लिथुआनिया के सौहार्दपूर्ण संबंध हैं व नज़दीकी सांस्कृतिक संपर्क हैं । हाल के वर्षों में आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों में उन्नति हुई है और भारत व लिथुआनिया के बीच 2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 373 मिलियन यू एस डॉलर रहा । लिथुआनिया में भारतीय निवेश में इंडोरामा ग्रुप का विनिर्माण संयंत्र में 200 मिलियन यू एस डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है और एच सी एल टेक्नोलॉजीज़ ने हाल ही में विलिनियस में 500 से अधिक कर्मचारियों वाली बाक्टर्लेज़ की आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाएं संपाली हैं । इंडोरामा ने प्लास्टिक रेज़िन के विनिर्माण के लिए क्लार्ईपीडा इकोनॉमिक ज़ोन में एक संयंत्र स्थापित किया है । यह निम्नतम कार्बन फुटप्रिंट वाला यूरोप में सबसे बड़ा एकल लाइन

माल्टा

भारत और माल्टा इस अवधि के दौरानउच्चतम स्तरों सहित फलतः जुड़े रहे जो द्विपक्षीय संबंधों के अलावा संयुक्त राष्ट्र तथा बहूपक्षीय मंचों पर सहयोग

यूरोप तथा यूरोपीयन यूनियन

भारतीय सह-अध्यक्ष ने सूचित किया कि ओ एन जी सी एनर्जी सेंटर द्वारा आइसलैंड जियोसर्वे (आईएसओआर) के साथ मिलकर संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में भू-तापीय परियोजना विकसित की जा रही है और लद्दाख को कार्बन-उदासीन बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाएं भी बताईं जहाँकि भू-तापीय ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । लद्दाख में भू-तापीय ऊर्जा पायलट परियोजना का परिणाम भारत में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र के और अधिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा । आर्कटिक कौंसिल की जो बैठकें और कार्यक्रम 2020 के दौरान आइसलैंड में होने वाली थीं वे कोविड-19 के फैलने के कारण अनुपयुक्त याला परिस्थितियों के कारण वर्चुअल प्रारूप में की गईं । आर्कटिक कौंसिल का वर्तमान अध्यक्ष आइसलैंड है और भारत इसका प्रेक्षक है ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

पी ई टी रेज़िन संयंत्र है । इस निवेश ने भारत को लिथुआनिया में दृश्यता प्रदान की है ।लिथुआनिया ने 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में तथा 2021-2023 की अवधि के लिए प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में भारत की आशावारी को समर्थन दिया । फरवरी 2020 में म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस के अवसर पर विदेशी मंत्री ने लिथुआनिया गणराज्य के विदेश मंत्री के साथ बैठक की । दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार तथा गहरी भारत-लिथुआनिया सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंधों के पोषण पर चर्चा की ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

भारत और आइसलैंड के बीच नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग पर 3री संयुक्त समिति बैठक 28 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई । बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और आइसलैंड में भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र पर प्रस्तुतियाँ दीं । दोनों पक्षों ने भू-तापीय क्षेत्र में सभी मुख्य के बीच सम्प्रेषण पुनर्स्थापित किया, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत में अनुमानित 10000 मेगावाट भू-तापीय ऊर्जा की महत्वपूर्ण क्षमता है ।

के मंत्री ने विदेशी मंत्री को बधाई संदेश भेजा। इस अवधि में वाणिज्यिक क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच उन्नत सहयोग की प्रवृत्ति भी देखी गई जो माल्टा को भारत

के बड़े हुए निर्यात विशेषकर फार्मा निर्यात के द्वारा हुआ।

मोलदोवा

द्विपक्षीय संबंध मैत्रीपूर्ण हैं तथा परस्पर विश्वास एवं समझ के बने रहते हैं। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत मोल्दोवा से 237 भारतीय छात्रों को चार्टर्ड उड़ान द्वारा वापस भेजा गया। कोविड-19 के संदर्भ में मोल्दोवा गणराज्य को भारत की सहायता के रूप में लगभग 6000 कि.ग्रा. दवाएं, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं तथा अन्य चिकित्सा सामग्री दान की गई। इसके अलावा जून-जुलाई 2020

में भारत से मोल्दोवा को दवाओं का अलग से निर्यात भी किया गया।

मोलदोवा के रक्षा मंत्री विक्टर गैसिउक को रक्षा मंत्री द्वारा बंगलूरु में 03-07 फरवरी 2021 को एयरो इंडिया-2021 में आमंत्रित किया गया है।

मोंटेनेग्रो

मोंटेनेग्रो के साथ भारत के संबंध उस समाजवादी संघीय गणराज्य युगोस्लाविया (एस एफ आर वाय) के दिनों से परम्परागत रूप से नज़दीकी और मैत्रीपूर्ण रहे

हैं जिसका यह एक घटक गणतंत्र था। मोंटेनेग्रो में भारत के लिए काफी सद्भावना और मित्र-भाव है।

उत्तरी मैसेडोनिया

उत्तरी मैसेडोनिया भारत का दीर्घकाल से मित्र है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूप से विश्वसनीय साझेदार बना रहा है। इसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (2021-22) में अस्थायी सीट, प्रशासनिक तथा बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार

समिति (एसीएबीक्यू) के लिए भारत की आशावारियों को समर्थन दिया है। विदेशी मंत्री ने अपने समकक्ष बुजर उस्मानी को उनके उत्तरी मैसेडोनिया के विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण करने पर सत्कार पत्र भेजा।

नॉर्वे

विदेशी मंत्री ने 12 जून 2020 को नॉर्वे के विदेश मंत्री इनि एरिक्सन सोरेदे के साथ वर्चुअल बैठक की तथा आर्थिकरिक्वरी तथा कोविड परिस्थिति, सागर प्रबंधन एवं बहुपक्षीयता सहित परस्पर हित के विषयों पर चर्चा की। कोविड-

19 से मुकाबला, वैश्विक स्वास्थ्य और बढ़ता सतत विकास तथा सागर प्रबंधन के क्षेत्रों में नॉर्वे भारत के साथ सशक्त साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध था।



05 नवम्बर 2020 को इंडिया-नॉर्डिक-बाल्टिक कनक्लेव में विदेशी मंत्री

भारत और नॉर्वे के बीच 6ठी संयुक्त आयोग बैठक वर्चुअल प्रारूप में 13 अक्टूबर 2020 को हुई। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेशी मंत्री ने किया तथा नॉर्वे के शिष्टमंडल का नेतृत्व नॉर्वे के विदेश मंत्री इनि एरिक्सन सोरेदे ने किया। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले में गहराई से सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और वैक्सीन तक स्वच्छ वैश्विक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए कोवेक्स प्लान्स की स्थापना का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने इंडिय-नॉर्वे डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट (डीटीआई) तथा सागर वार्ता में हुई महत्वपूर्ण उन्नति और सतत विकास के लिए नील अर्थव्यवस्था

पर टास्क फ़ोर्स के अंतर्गत पहलों पर भी संतोष व्यक्त किया तथा मैरीटाइम, मरीन, हाइड्रोकार्बन, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा पर ज्वायंट वर्किंग ग्रुप (जे डब्लू जी) के अंतर्गत गतिविधियों को उल्लिखित किया। इसके साथ-साथ चूंकि भारत और नॉर्वे दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आने वाले सदस्यों के रूप में चुने गए, दोनों पक्षों ने सदस्यता अवधि 2021-22 के दौरान सुरक्षा परिषद के विषयों पर उच्च अधिकारी स्तर पर नियमित विचार-विमर्श में सम्मिलित होने पर सहमत हुए।

पोलैंड

भारत और पोलैंड के बीच शक्तिशाली राजनीतिक साझेदारी, जीवंत आर्थिक जुड़ाव तथा परम्परागत सांस्कृतिक संपर्कों वाला लम्बा मैत्रीपूर्ण संबंध है। संबंधों में विशेषकर आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों में एक सकारात्मक प्रवृत्ति एक दशक से अधिक की अवधि के द्विपक्षीय व्यापार में करीब 200 प्रतिशत वृद्धि में परिलक्षित होती है यानि 2009-10 में 808 मिलियन अमेरिकी डालर से 2019-20 में 2398 मिलियन अमेरिकी डालर। मध्य और पूर्वी यूरोप में पोलैंड, भारत का सबसे बड़ा व्यापार एवं निवेश का साझेदार है। व्यापार संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहा है। पोलैंड में भारत का निवेश 3 बिलियन अमेरिकी डालर आकलित है जो 25000 नागरिकों को रोज़गार दे रहा है और पोलैंड का भारत में निवेश, जो भी काफी बढ़ा है, 673.62 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक आकलित है।

भारत और पोलैंड के बीच 9वीं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस (एफ ओ सी) 10 अगस्त 2020 को वर्चुअल आयोजित की गई। इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आई सी डब्लू ए) – द पोलिश इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (पी आई एस एम) के बीच सामरिक वार्ता का 7वां सत्र 27 अक्टूबर 2020 को वर्चुअल हुआ। भारत और पोलैंड विदेश नीति वार्ता नियमित रूप से करने पर सहमत हुए हैं जिसमें पहली वार्ता दिसम्बर 2020 में प्रारम्भ होगी। 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य और प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति (एसीएबीक्यू) में 2021-2023 की अवधि के लिए आशावारियों के लिए भारत को समर्थन दिया था।

रोमानिया

रोमानिया के साथ भारत के संबंध परस्पर विश्वास तथा गहरी समझ पर आधारित मधुर एवं मैत्रीपूर्ण हैं। 26 जून 2020 को कम्यूनिटी ऑफ डेमोक्रेसीज़ की 20वीं वर्षगांठ की वर्चुअल कांफ्रेंस में राज्य मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया जिसकी अध्यक्षता रोमानिया के विदेश मंत्री बोगदान ओरेस्कु द्वारा की गई। 19 जून 2020 को सचिव(पश्चिम) तथा रोमानिया के विदेशी मामलों के मंत्रालय के स्टेट सेक्रेटरी के बीच वर्चुअल विचार-विमर्श हुआ। भारत और रोमानिया के बीच फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस (एफ ओ सी) भी 27 अक्टूबर

2020 को जे एस/ डी जी स्तर पर वर्चुअल तरीके से हुई।

रोमानिया के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री श्री लोनेल निकोलई सिउका तथा रोमानिया के अर्थव्यवस्था, ऊर्जा तथा व्यापार वातावरण मंत्री वर्जिल-डेनियल पोपेस्क्यु को रक्षा मंत्री द्वारा 03-07 फरवरी 2021 तक बंगलूरु में एयरो इंडिया-2021 में आमंत्रित किया गया है।

सर्बिया

सर्बिया में नई सरकार के बनने के बाद भारत और सर्बिया के बीच पारम्परिक नज़दीकी सम्बंध जारी रहे तथा वर्ष के दौरान और अधिक मजबूत हुए। सर्बिया के लोग भारतीय कला और संस्कृति में बहुत रुचि लेते हैं।

138.6 मिलियन अमेरिकी डालर पर पहुँचा। सर्बिया को फार्मास्यूटिकल और रसायनों का निर्यात जिसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएण्ट्स (एपीआई) शामिल हैं, 43% बढ़ा। कोरोना महामारी के विरुद्ध लड़ाई में उपयोग हेतु सर्बिया ने भारत से ग्लव्स और फेस मास्क का आयात किया। भारतीय फार्मास्यूटिकल कम्पनियों की शक्ति को सर्बिया के मीडिया में विस्तृत कवरेज प्राप्त हुई।

स्लोवाकिया

भारत-स्लोवाकिया के संबंध मैत्रीपूर्ण तथा बड़े द्विपक्षीय विषयों से मुक्त हैं।

दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अच्छे से सहयोग कर रहे हैं तथा एक-दूसरे की



आशावारियों को ज़्यादातर समर्थन देते हैं । स्लोवाकिया ने 2021-2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए; 2020-2024 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत(आईसीएच) की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की इंटरगवर्न्मेंटल कमेटी में; 2021-2023 की अवधि के लिए प्रशासनिक तथा बजटीय प्रश्नों पर प्रतिष्ठित सलाहकार कमेटी (एसीएबीक्यु) के लिए भारत की आशावारी का समर्थन किया ।

जनवरी-जुलाई 2020की अवधि के लिए स्लोवाकिया को भारत का निर्यात 159.6 मिलियन अमेरिकी डालर पर पहुँच गया जो 2019 की समान अवधि

स्लोवेनिया

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत-स्लोवेनिया के द्विपक्षीय संबंधमधुर बने रहे । विदेशी मंत्री तथा स्लोवाकिया के विदेश मंत्री एंज़े लोगार के बीच वर्चुअल बैठक 17 जून 2020 को हुई । महामारी की पहली लहर के दौरान भारतीय आपूर्तिकर्ताओं ने स्लोवेनिया को पीपी ई उपलब्ध कराई । स्लोवेनिया के वैज्ञानिकों तथा भारत के सीरम इंस्टिट्यूट के बीच कोविड-19 वैक्सीन पर शोध जारी है । बहूपक्षीय मंचों पर स्लोवेनिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए 2021-22 की अवधि हेतु भारत की आशावारी को बिना शर्त समर्थन दिया । मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए 2020-24 की अवधि के लिए भारतीय आशावारी को भी इसने समर्थन दिया ।

फॉरेन ऑफिस कंसलटेशंस तथा ज्वायंट कमेटी ऑन टेक्नीकल एंड इकोनोमिक कोऑपरेशन (जेसीटीईसी) 2021 की पहली तिमाही में होनी है ।

स्वीडन

स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने चल रहे कोविड-19 महामारी तथा भारतीय और स्वीडिश शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के बीच सहभागिता और डाटा शेअरिंग के लिए क्षमता पर चर्चा करने के लिए 07 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री से बात की ।

अप्रैल-अक्तूबर 2020 के दौरान कई मंत्री स्तरीय दूरभाषीय वार्ताएं हुईं। वाणिज्य, उद्योग एवं रेल मंत्रालय तथा स्वीडन के विदेशी व्यापार और नॉर्डिक अफेयर्स मंत्री अन्ना हालबर्ग के बीच 26 मई 2020 को दूरभाष वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने वर्तमान वैश्विक कोरोना वायरस महामारी की स्थिति तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और अधिक बढ़ाने के तरीकों, डब्लु टी ओ सुधारों, समग्र बीटीआईए हस्ताक्षर करने आदि पर चर्चा की ।

स्विट्ज़रलैंड

स्विस फेडरल कौंसिल ने कोविड-19 के कारण 16 मार्च 2020 को एक ‘असामान्य परिस्थिति’ की घोषणा की । कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई में सभी भारतीयों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए प्रतिष्ठित मैटरहॉर्न पर्वत पर

की तुलना में 15.8% कम है । स्लोवाकिया से आयात 57.7 मिलियन अमेरिकी डालर रहा जिसमें वर्ष दर वर्ष 3.4% की वृद्धि है । कुल व्यापार 12% की कमी के साथ 217.3 मिलियन अमेरिकी डालर रहा । कुल 30 भारतीय नागरिकों ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत वापसी सुविधा का लाभ लिया ।

हम दोनों देशों के बीच ज्वायंट इकोनॉमिक कमीशन (जे ईसी) का अगला सल 2021 में स्लोवाकिया में राजनयिक प्रणालियों द्वारा परस्पर सहमत हुई तारीख को होने वाला है ।



(1) नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार और स्लोवेनिया के ऊर्जा मंत्रालय, (2) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद तथा डिज़ाइन इंस्टिट्यूट ऑफ स्लोवेनिया, (3) दोनों देशों के संस्कृति मंत्रालयों के बीच – अगले वर्ष भारतीय सांस्कृतिक समारोह- नमस्ते इंडिया के लिए तथा (4) भारत-स्लोवेनिया व्यापार परिषद को पुनर्जीवित करने संबंधी सहयोग पर सहमतियाँ और समझौता ज्ञापन 2021 की पहली तिमाही में हस्ताक्षरित होने के लिए अंतिम रूप दिये जाने से लेकर वार्ताओं तक के चरणों में हैं ।

सितम्बर 2019 में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान हस्ताक्षरित सहयोग समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दो परियोजनाएं आई आई टी कानपुर और स्लोवेनिया के वदनोगोस्पोदस्की बिरो के बीच अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं ।



स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा के लिए स्वीडन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक मामले के मंत्री लीना हैलेंग्रेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री के साथ वर्चुअल विचार-विमर्श किया । मंत्री हैलेंग्रेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रीय मंत्री को डब्लु एच ओ एग्ज़ेक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर बधाई दी तथा परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए भारत की प्रशंसा की । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के निमंत्रण पर 23 सितम्बर को स्वीडन के स्वास्थ्य एवं सामाजिक मामले के मंत्री लीना हैलेंग्रेन ने आरोग्य मंधन 2.0 – मूविंग टूवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कोविड-19 से निपटने के स्वीडन के अनुभव तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से और अधिक मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों को उत्प्रेरित करने के बारे में बात की



भारतीय ध्वज प्रदर्शित किया । स्विस सरकार ने भारत में फंसे स्विस/यूरोपीय नागरिकों के लिए वापसी की उड़ानों की व्यवस्था भी की । 4 जून 2020 को सचिव (पश्चिम) की स्विस एक्टिंग स्टेट सेक्रेटरी एवं राजनीतिक मामलों के

निदेशालय के प्रमुख क्रिस्टीना मार्टी से टेलीफोन पर बात हुई । 08 सितम्बर 2020 को भारत-यूरोपीयन फ्री ट्रेड एसोसिएशन(ईएफटीए) के ट्रेड एंड इकोनोमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट(टीईपीए) पर पेनल चर्चा बर्न में हुई । स्विस एसोसिएशन ऑफ आयुर्वेदा फिजीशियंस एंड थेरेपिस्ट्स(वीएसएएमटी) ने 15 सितम्बर – 14 अक्तूबर 2020 तक “सीआईआई ग्लोबल आयुर्वेदा सम्मिट” के 4थे संस्करण में भाग लिया । फेडरल कौंसिलर गाइ परमेलिन, स्विस फेडरल कौंसिल के उपाध्यक्ष तथा फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर्स, एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रमुख ने 19 नवम्बर 2020 को बंगलूरी टेक समिट के 23वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल रूप में संबोधित किया । जेनेवा हेल्थ फोरम (जीएचएफ) के 8वें संस्करण में भारत विशिष्ट अतिथि था जो 16-18 नवम्बर 2020 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुआ ।

तुर्की

एक द्विपक्षीय तंत्र ‘इंडिया-टर्की पॉलिसी प्लानिंग डायलॉग’ दोनों विदेश मंत्रियों के मध्य संस्थागत रूप दिया गया जिसका पहला राउंड 22 अक्तूबर 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ । दोनों देशों में आंशिक लॉकडाउन तथा व्यक्ति तथा सामान का सीमित संचार होने के बावजूद भारत और तुर्की के बीच द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल-सितम्बर 2020 के दौरान 2.36 बिलियन अमेरिकी डालर था । इस अवधि के दौरान दोनों देशों के विशेषज्ञ समूहों, सांस्कृतिक संगठनों तथा वाणिज्य एवं उद्योग के चैम्बरों के बीच परस्पर विचार-विमर्श सहित कई गतिविधियाँ हाइब्रिड/वर्चुअल प्रारूप में जारी रही । अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तथा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक

यूनाइटेड किंगडम

इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा पेश की गई चुनौतियों के बावजूद भारत और यूके के बीच नज़दीकी सांझेदारी देखी गई ।

कोविड-19 सहयोग

अप्रैल 2020 के प्रारम्भ में भारत ने यूके को महत्वपूर्ण दवाएं तथा चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति की जिसमें45.36 मिलियन पैरासिटामोल टेबलेट तथा 4.0 मी.टन की दो खेप तथा 19.2 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) टेबलेट शामिल हैं । जून 2020 में भारत ने यूके को 10.95 मिलियन 2/3 प्लाइ सर्जिकल मास्क की आपूर्ति भी की। तदनंतर, भारत सरकार ने प्रतिबंधित निर्यात वस्तुओं में से अधिकतर का निर्यात खोल दिया जिससे भारत से यूके को मास्कों, पी पी ई तथा फार्मास्युटिकल उत्पादों का सतत प्रवाह सुलभ हो गया ।

यूके सरकार के साथ करीबी सहयोग से महामारी के दौरान यूके में फंसे भारतीयों की निकासी संभव हुई । उन लोगों के समाप्त हो गए यूके वीज़ा की वैधता बढ़ाई गई जिन्हें समय पर निकाला नहीं जा सका । भारत में फंसे ब्रिटिश

मार्च 2021 तक जिन कार्यक्रमों के होने की अपेक्षा है वे हैं : रेलवे, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा गाइ परमेलिन, फेडरल कौंसिलर, स्विट्ज़रलैंड के फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर्स, एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रमुख के बीच वर्चुअल बैठक; वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम द्वारा डिजिटल रूप से संयोजित की जाने वाले ‘द्वोस डायलॉग्स’ में भारत सरकार की प्रतिभागिता; वर्चुअल भारत-स्विट्ज़रलैंड फाइनेंशल डायलॉग; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय तथा स्विस फेडरल ऑफिस ऑफ पब्लिक हेल्थ के बीच स्वास्थ्य सहयोग पर वर्चुअल बैठक; स्विस ट्रेडिंग फर्मों के लिए भारत में अवसरों पर वेबीनार; स्विस निवेशकों को भारतीय स्टार्ट अप्स के साथ जोड़ने वाला वर्चुअल इनवेस्टर पिच इवेंट; प्रवासी भारतीय दिवस समारोहों तथा इसके साइड कार्यक्रमों में स्विट्ज़रलैंड से वर्चुअल प्रतिभागिता आदि ।



कार्यक्रमों के अलावा सोशल मीडिया के विस्तृत उपयोग द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क को प्रोत्साहित किया गया ।

(i) भारत-तुर्की ज्वायंट कमेटी ऑन इकोनोमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन (जेसीईटीसी) तथा (ii) फॉरेन ऑफिस कंसलटेशंस (एफ ओ सी) के होने की संभावना है । तथापि, इन कार्यक्रमों का होना कई कारकों पर आश्रित है जिसमें चल रही महामारी के कारण उभरती परिस्थिति तथा दोनों पक्षों द्वारा परस्पर सहमत तारीखों को अंतिम रूप देना ।

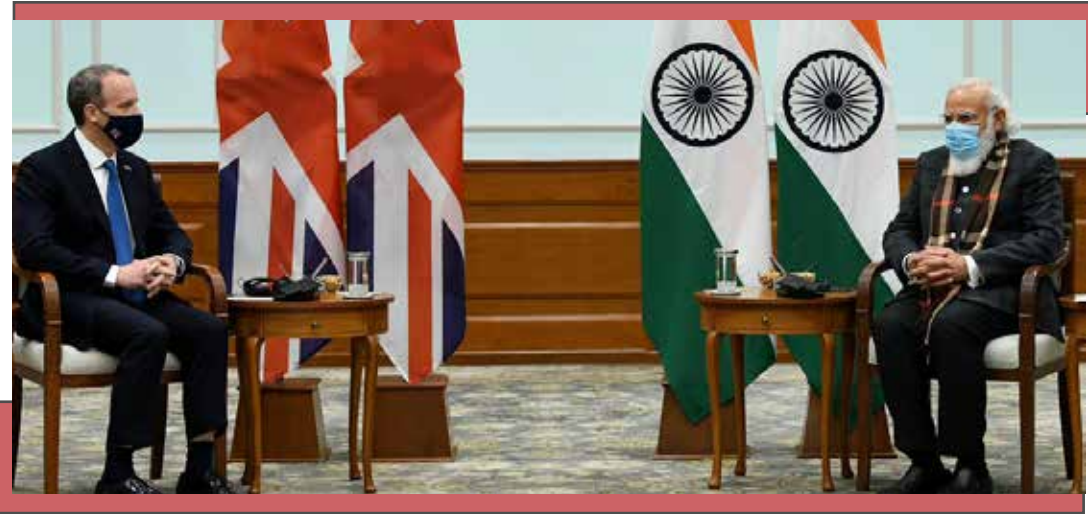


नागरिकों के लिए भारत सरकार ने भी वैसा ही किया । लॉकडाउन अवधि के दौरान 200 से अधिक उड़ानों में 50,000 से अधिक भारतीयों को निकाला गया ।

हाल के उच्च-स्तरीय राजनीतिक विनिमय

यूके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट एम्बीशन समिट में भाग लिया जिसे 12 दिसम्बर 2020 को यूके द्वारा सह आयोजित किया गया । प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई तथा शपथ ली कि शतवर्षीय भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत न केवल इसके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा बल्कि सभी देशों की उम्मीदों से आगे निकलेगा ।.

यूके के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स डोमिनिक राब ने 14-17 दिसम्बर 2020 तक भारत का दौरा किया और विदेशी मंत्री के साथ चर्चा की । यूके के ईयू को छोड़ने तथा कोविड-प्रभावित विश्व में बड़े भूराजनैतिक परिवर्तनों के संदर्भ में दोनों मंत्रियों ने विभिन्न



यूके के विदेश सचिव ने 16 दिसम्बर 2020 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से भेंट की



विदेशी मंत्री तथा यूके के विदेश सचिव 15 दिसम्बर 2020 को हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में मंत्री स्तरीय वार्ता करते हुए

क्षेत्रों जैसे कि व्यापार एवं निवेश, रक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शोध एवं नवोन्मेष, ऊर्जा तथा जलवायु परिवर्तन में बेहतर सहभागिता के लिए अपार अवसरों की बात स्वीकार की। उन्होंने भारत-यूके साझेदारी को अगले स्तर तक उन्नत करने के लिए महत्वाकांक्षी 360 डिग्री रोडमैप को अंतिम रूप देने को प्राथमिकता देने पर सहमत हुए। बहु-ध्रुवीय विश्व तथा बहुपक्षीयता में विश्वास के प्रति अपनी सांझी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दोनों मंत्रियों ने परस्पर हित के कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मामलों पर चर्चा भी की। उन्होंने इंडो-पेसिफिक में सहयोग मजबूत करने, आतंकवाद और कट्टरपंथी अतिवाद का मुकाबला करने तथा साइबर, मेरीटाइम और अंतरिक्ष के क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों को सम्बोधित करने के लिए तरीके खोजे। याला के दौरान डोमिनिक राब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा शिक्षा मंत्री से भी मिले।

विम्बलडन के लॉर्ड तारिक अहमद, दक्षिण एशिया एवं कॉमनवेल्थ मंत्री, एफ सी डी ओ, ने दो अवसरों पर राज्य मंत्री से बात की तथा महामारी से सम्बंधित मामलों पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय सरकारों के बारे में चर्चा के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री तथा पवन ऊर्जा में अवसरों पर अन्यो के साथ वर्चुअल बैठक की और राजस्थान में यूके समर्थित सोलर प्लांट की वर्चुअल यात्रा की।

उच्च शिक्षा में और अधिक सहभागिता, छाल गतिशीलता तथा कोविड-19 में मिलकर काम करने पर चर्चा के लिए यूके के शिक्षा मंत्री गैविन विलियमसन ने 16 जुलाई को एच आर डी मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की।

विदेश सचिव ने 3 व 4 नवम्बर 2020 को युनाइटेड किंगडम का दौरा किया। अपनी याला के दौरान विदेश सचिव यूके की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल तथा फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) राज्य मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद से मिले तथा यूके के एफसीडीओ में परमानेंट अंडर सेक्रेटरी सर फिलिप बर्टन के साथ व्यापक द्विपक्षीय परामर्श किए। विदेश सचिव यूके के

कार्यवाहक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेविड क्रेरी से भी मिले तथा यूके की विदेश एवं सुरक्षा नीति की जारी एकीकृत समीक्षा, इंडो-पेसिफिक तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से सम्बंधित मामलों पर चर्चा की। विदेश सचिव ने पॉलिसेी एक्सचेंज में “इंडियाज़ विज़न ऑफ द इंडो-पेसिफिक” पर भाषण भी दिया।

भारत के गृह मंत्री ने 15 जनवरी 2021 को अपने यूके समकक्ष के साथ वीडियो काल की तथा प्रवासन और गतिशीलता, आतंकवाद, कट्टरपंथ तथा प्रत्यर्पण मामलों संबंधी विषयों पर चर्चा की।

23 नवम्बर 2020 को सी आई आई ग्लोबल पार्लियामेंटेरियंस फोरम वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांसदों तथा सब देशों के सांसदों के साथ उद्योग जगत के जुड़ाव के स्तर को बढ़ाना था। नीतिगत विषयों के विशेष विकास, भारत और यूके के मध्य आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाना इस कार्यक्रम का लक्ष्य था। फोरम की अध्यक्षता श्री सुरेश प्रभु (सांसद- भारत) द्वारा की गई, बॉब ब्लैकमैन (सांसद-यूके), वीरेंद्र शर्मा (सांसद-यूके) तथा अन्य बहुत से गणमान्य व्यक्तियों ने इस वर्चुअल फोरम में भाग लिया।

रक्षा सहयोग

विभिन्न सहयोगी अनुसंधान और अकादमिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 17 अगस्त को पुणे के डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (डीआईएटी), और पश्चिमी इंग्लैंड (यूडब्ल्यूई), ब्रिस्टल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों दलों ने आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों की योजना बनाने और क्रियान्वित करने और युवाओं के बीच एस्टीईएम करियर को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। यह एमओयू पांच वर्षों के लिए वैध है।

27 अगस्त 2020 को ‘दोहरी डिग्री कार्यक्रम’ पर डीआईएटी, पुणे, और क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय, यूके के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू छात्रों को दो साल के सेगमेंट में दो साल के मास्टर डिग्री प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है - एक वर्ष भारत में और एक वर्ष लंदन में। कार्यक्रम में एयरोस्पेस, गन सिस्टम डिज़ाइन, निर्देशित हथियार प्रणाली और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

भारतीय वायु सेना और रॉयल एयर फोर्स के बीच 15वीं एग्ज़ेक्यूटिव स्टीयरिंग ग्रुप (ई एस जी) की वर्चुअल बैठक 12 नवंबर 2020 को हुई। दोनों सेनाओं ने क्षमता विकास और अपनी स्वयं की सेवा के विकास की दिशा में काम करने के लिए बातचीत की। एयरो इंडिया - 2021 को 3-7 फरवरी, 2021 के दौरान वायु सेना स्टेशन, येलहंका, बेंगलुरु में आयोजित करने की योजना है।

भारत-पाक युद्ध 1971 के दौरान ‘ओपरेशन ट्राइडेंट’ की सफलता के उपलक्ष्य में लंदन में भारत के उच्चायोग ने 4 दिसंबर 2020 को ‘भारतीय नौसेना दिवस’ मनाया। इस अवसर पर, उच्चायुक्त ने भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानवीय कार्यों में भारतीय नौसेना द्वारा दिए गए योगदान को रेखांकित किया। एक नौसेना प्रदर्शनी, नौसेना सप्ताह थीम वीडियो के प्रदर्शन का आयोजन किया गया।

फ्रांस

भारत और फ्रांस के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। 1998 में, दोनों देशों ने एक सामरिक साझेदारी की जो क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों की श्रृंखला पर उनके विचारों के केंद्रीकरण का प्रतीक है। इस मजबूत द्विपक्षीय संबंध ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग और असैन्य परमाणु सहयोग और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे क्षेत्रों में अधिक गहराई हासिल की है।

सहयोग के इन पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा भारत और फ्रांस सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला,

गया।
चीफ ऑफ स्टाफ, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवने ने 1 दिसंबर 2020 को जनरल सर मार्क कार्लटन-स्मिथ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ब्रिटिश आर्मी के साथ टेलीफोन पर बात की। बातचीत का केंद्र दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय जुड़ाव बढ़ाने पर रहा। एग्ज़ेक्यूटिव स्टीयरिंग ग्रुप (ईएसजी) की 11वीं बैठक (आर्मी स्टाफ टाक्स) 10 मार्च 2021 को नई दिल्ली में होनी प्रस्तावित है।

विविध

भारतीय उच्चायोग और ऑल पार्टी पार्लियामेंटी ग्रुप - इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेज (एपीपीजी-आईटीएस) ने 13 नवंबर 2020 को संयुक्त रूप से 5वां आयुर्वेद दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में लॉर्ड्स, बैरोनेस, सांसदों और भारत और अन्य देशों के कई विशेषज्ञों और आयुर्वेद के दिग्गजों ने भाग लिया।

युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का ऑनलाइन कार्यक्रम 8 जनवरी 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। उच्चायोग द्वारा 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का ऑनलाइन आयोजन भी किया गया। 10 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित जलवायु परिवर्तन और सतत वृद्धि और विकास में तेजी से लगे हुए हैं।

भारत और फ्रांस के बीच जीवंत सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंध हैं जो बढ़ते हुए व्यक्ति-से-व्यक्ति के संपर्क से परिलक्षित होता है। माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर से यह और मजबूत हुआ, जिसके फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 2021 की शुरुआत में लागू होने की आशा है। महानगर फ्रांस और इसके विदेशी विभागों / क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की एक बड़ी उपस्थिति है।

हाल के उच्च-स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान

प्रधानमंत्री ने 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए और 31 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के संभावित संयुक्त प्रयासों पर चर्चा के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। 24 जुलाई, 2020 को राष्ट्रपति मैक्रॉन ने पैरासिटामोल जैसी जीवनरक्षक दवाओं पर से निर्यात प्रतिबंध हटाने के भारत के फैसले के लिए धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जो महामारी की पहली लहर के दौरान फ्रांस को निर्यात किया गया था। उन्होंने चिकित्सा उपकरण और तकनीकी विशेषज्ञता सांझा करके कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता भी व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने 11-13 नवंबर, 2020 को आयोजित पेरिस पीस फोरम में “बाउंसिंग बैक टू ए बैटर प्लेनेट” थीम पर वर्चुअल संबोधन दिया।

दोनों नेताओं ने 7 दिसंबर 2020 को फिर से टेलीफोन पर बातचीत की, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रॉन को फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की, और आतंकवाद, उग्रवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के प्रति भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। नेताओं ने आपसी हित के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें कोविड-19 टीकों के जुटाने और पहुंच में सुधार, कोविड के बाद आर्थिक सुधार, भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा, बहुपक्षीयता को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता शामिल हैं।

26 जून और 26 सितंबर 2020 को, विदेशी मंत्री ने एलायन्स फॉर मल्टीलेटरलिज़्म की वर्चुअल बैठकों में भाग लिया। उन्होंने 30 जून 2020 को अपने फ्रांसीसी समकक्ष जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी की।

भारत और फ्रांस ने अपनी वार्षिक सामरिक वार्ता 7 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जबकि फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोन ने किया। दोनों पक्षों ने भारत-फ्रांस सामरिक साझेदारी के लिए उच्च प्राथमिकता की पुष्टि की और दोनों देशों के बीच विचारों के अभिसरण पर प्रकाश डाला।

भारत और फ्रांस ट्रेक 1 प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लिपक्षीय वार्ता में भी शामिल हुए। विदेश सचिव ने वार्ता की सह-अध्यक्षता की, जहां तीनों पक्षों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की जैसे कि समुद्री वैश्विक कॉमन्स, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) और समुद्री सुरक्षा सहयोग।

29 जून 2020 को, विदेश सचिव ने अपने समकक्ष फ्रांस्वा देलात्ते, यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय के महासचिव के साथ आभासी विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया।

29-30 अक्टूबर 2020 को, विदेश सचिव ने अपने समकक्षों और फ्रांसीसी सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय परामर्श और बैठकों के लिए फ्रांस का दौरा किया। उन्होंने एलिस गुड्टन, महानिदेशक, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के महानिदेशक और फ्रांसीसी राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुएल बोन से भी मुलाकात की।

कोविड -19 सहयोग

रक्षा संबंधी वर्तमान प्रमुख परियोजनाओं में राफेल विमानों की खरीद और पी-75 स्कॉर्पीन परियोजना शामिल है। पहले पांच राफेल जेट 29 जुलाई 2020 को भारत आए और 10 सितंबर 2020 को अंबाला में वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायु सेना में शामिल किए गए। सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने व्यक्तिगत रूप से आगमन समारोह में भाग लिया और हमारे रक्षा मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। तीन राफेल का दूसरा जत्था भी भारत पहुंच चुका है।

दोनों नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज़ वरुण 19 - 23 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया। फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी (आई एल ओ) गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र (आई एफ सी-आई ओ आर) के लिए सूचना संलयन केंद्र में शामिल हुए और इस तरह समुद्री क्षेत्र जागरूकता के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा किया।

रक्षा सहयोग

रक्षा संबंधी वर्तमान प्रमुख परियोजनाओं में राफेल विमानों की खरीद और पी-75 स्कॉर्पीन परियोजना शामिल है। पहले पांच राफेल जेट 29 जुलाई 2020 को भारत आए और 10 सितंबर 2020 को अंबाला में वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायु सेना में शामिल किए गए। सशस्त्र बल के मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने व्यक्तिगत रूप से आगमन समारोह में भाग लिया और हमारे रक्षा मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। तीन राफेल का दूसरा जत्था भी भारत पहुंच चुका है।

दोनों नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज़ वरुण 19 - 23 अक्टूबर 2020 को आयोजित किया गया। फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी (आई एल ओ) गुरुग्राम में हिंद महासागर क्षेत्र (आई एफ सी-आई ओ आर) के लिए सूचना संलयन केंद्र में शामिल हुए और इस तरह समुद्री क्षेत्र जागरूकता के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा किया।

अंतरिक्ष सहयोग

फ्रांस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पुर्जों और उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। इसरो और सीएनईएस वर्तमान में 2024 और 2030 के बीच तृष्णा अवरक्त उपग्रह परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दे रहे हैं।

असैन्य परमाणु सहयोग

मार्च 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, एनपीसीआईएल और ईडीएफ ने एक “औद्योगिक मार्ग अग्रेषण समझौता” संपन्न किया। ईडीएफ और एनपीसीआईएल के बीच जेएनपीपी परियोजना के शीघ्र प्राप्ति के उद्देश्य से चर्चा चल रही है। इस संबंध में, जेएनपीपी वित्त पोषण समिति की बैठक नवंबर 2020 में परियोजना के वित्तपोषण तंत्र को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई

आर्थिक संबंध

फ्रांस अप्रैल 2000 से दिसंबर 2019 तक 7.10 बिलियन अमरीकी डालर के संघयी एफडीआई स्टॉक के साथ भारत में नौवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का 1.55% है। फ्रांस में (सहायक कम्पनियों सहित) 150 से अधिक भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं, जो 7,000

से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती हैं। मई 2020 में, द्विपक्षीय व्यापार 456 मिलियन अमरीकी डालर था।

दोनों पक्षों के वाणिज्य और विदेश व्यापार मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त आर्थिक समिति मौजूद है। 18 वीं संयुक्त आर्थिक समिति की बैठक लगभग 27 नवंबर, 2020 को राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग और फ्रेंक रिस्टर, विदेश व्यापार और आर्थिक आकर्षण के लिए मंत्री प्रतिनिधि के बीच वर्चुअल रूप में आयोजित की गई। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की और भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के लिए फास्ट ट्रेक तंत्र का शुभारंभ किया।

जर्मनी

यूरोपीय संघ में नेतृत्व की भूमिका और भारत के साथ जी 4 की सदस्यता के नाते जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। अपने इंडो-पैसिफिक दिशानिर्देशों के जारी होने के साथ, जर्मनी ने इस क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने में रुचि प्रदर्शित की है और यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार मानता है।



विदेश सचिव ने 02 नवंबर, 2020 को बर्लिन, जर्मनी के दौरे के दौरान राज्य मंत्री, जर्मन विदेश कार्यालय से मुलाकात की

आर्थिक हित के अलावा, अभिसरण के अन्य क्षेत्रों में एक खुला, स्वतंत्र और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र, सुधरे बहुपक्षवाद की इच्छा और एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शामिल है।

दोनों पक्ष परस्पर हित और सहयोग के व्यापक क्षेत्रों को कवर करते हुए हर दो साल में एक बार अंतर सरकारी परामर्श (आईजीसी) आयोजित करते हैं। आईजीसी का अगला संस्करण, छठा, 2021 में जर्मनी में आयोजित किया जाना है।

सांस्कृतिक सहयोग

पेरिस इंटरनेशनल बुक फेयर (लिट्रे पेरिस) के 2020 संस्करण के लिए भारत को सम्मानित अतिथि देश होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस फेयर को रद्द करना पड़ा। 2021 में भारत के सम्मानित अतिथि देश बनने की संभावना है। नमस्ते फ्रांस का अगला संस्करण 2021-2022 में आयोजित किया जाएगा। आखिरी संस्करण 2016 में आयोजित किया गया था और फ्रांस में बहुत पसंद किया गया था।

एसएंडटी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग

वर्तमान में, लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में विभिन्न पाठ्यक्रमों में संलग्न हैं। दोनों देशों ने 2025 तक इस संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।

महामारी के बाद के परिदृश्य की अनिश्चितता में, जर्मनी अब अपनी आर्थिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने की कोशिश में है, इस प्रकार भारत को इस प्रयास में एक आकर्षक और विश्वसनीय भागीदार बना रहा है।

उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए जर्मनी भारतीय छात्रों का पसंदीदा स्थान है। जर्मनी में वर्तमान में 25,000 से अधिक भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। लगभग 800 जर्मन छात्र भारत में पढ़ रहे हैं या इंटरशिप कर रहे हैं।

हाल के उच्च-स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रधानमंत्री और कुलाधिपति मैक्रेल ने 02 अप्रैल 2020 को टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2020 में चांसलर मैक्रेल को उनके चांसलर के रूप में 15 वर्षों पूरे होने पर बधाई देते हुए

पत्र लिखा और भारत-जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मामलों में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना की।

दोनों नेताओं ने 6 जनवरी 2021 को एक वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के प्रति अनुक्रिया, द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों सहित पारस्परिक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।

26 जून और 26 सितंबर 2020 को, विदेशी मंत्री ने फ्रांस और जर्मनी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्लायन्स फॉर मल्टीलेटरलिज़्म की वर्चुअल बैठकों में भाग लिया।

26 जून 2020 को, विदेश सचिव ने अपने समकक्ष मिगुएल बर्जर, राज्य सचिव, जर्मन संघीय विदेश मंत्रालय के साथ वर्चुअल विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया।

2 नवंबर 2020 को, विदेश सचिव ने अपने समकक्ष और जर्मन सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय परामर्श और बैठकों के लिए जर्मनी का दौरा किया। वह नील्स एनन, राज्य मंत्री, जर्मन संघीय विदेश मंत्रालय से भी मिले और जर्मन चांसलर के विदेश एवं सुरक्षा नीति सलाहकार से मुलाकात की।

रक्षा सचिव और उनके जर्मन समकक्ष के बीच उच्च रक्षा समिति की वर्चुअल बैठक 12 जनवरी 2021 को आयोजित की गई, जहाँ उन्होंने रक्षा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की।

कोविड-19 सहयोग

भारत और जर्मनी ने दोनों देशों में महामारी के चरम पर होने पर निकट सहयोग किया। भारत ने इन जीवन रक्षक दवाओं पर निर्यात प्रतिबंध हटाने के बाद जर्मनी को लगभग 1.5 टन एच सी क्यू और 240 मी.टन पेरासिटामोल (एपीआई) की आपूर्ति की। भारत ने जर्मनी को 8 मिलियन 3 प्लाई सर्जिकल मास्क का निर्यात भी किया। अपनी ओर से जर्मनी ने महामारी से सबसे अधिक प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत को 20 मिलियन यूरो और 460 मिलियन यूरो के अनुदान लघु अवधि के ऋण के रूप में देने का वादा किया। जर्मनी ने महामारी की शुरुआत में भारत को 5000 परीक्षण किट भी उपलब्ध कराई। 22 जुलाई 2020 से दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सुगम यात्रा के लिए “एयर बबल” की व्यवस्था की।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

जर्मनी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यह लगातार भारत के शीर्ष दस वैश्विक भागीदारों में से एक रहा है और वित्त वर्ष 2019-20 (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अगस्त 2020 तक 7वां) में यह आठवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

2019-20 में द्विपक्षीय व्यापार 22 बिलियन अमरीकी डालर था। इस अवधि के दौरान भारतीय निर्यात 6.87% घटकर 8.29 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया और भारतीय आयात 9.7% घटकर 13.69 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2020-21 के दौरान (अगस्त 2020 तक), द्विपक्षीय व्यापार 6.74 बिलियन अमरीकी डालर था। 2019 में वैश्विक आर्थिक मंदी और

उसके बाद कोविड-19 महामारी ने द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

भारत के लिए जर्मनी 7 वां सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत है। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक जर्मनी से भारत में कुल एफडीआई 12 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 में, भारत में जर्मन एफडीआई 488 मिलियन अमरीकी डालर था। इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स के अनुसार, भारत में 1,700 से अधिक जर्मन कंपनियां हैं। भारत में जर्मन निवेश मुख्य रूप से परिवहन, विद्युत उपकरण, धातुकर्म उद्योग, सेवा क्षेत्र (विशेष रूप से बीमा), रसायन, निर्माण गतिविधि, व्यापार और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में किया गया है।

आज तक जर्मनी में भारतीय निवेश, 7 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक है। सीआईआई के अनुसार, जर्मनी में 213 से अधिक भारतीय कंपनियां चल रही हैं, और ट्रेडिंग, मैनुफैक्चरिंग, आरएंडडी और इनोवेशन और सेवाओं में शामिल हैं। भारतीय कंपनियों ने जर्मनी में मुख्य रूप से विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) के माध्यम से निवेश किया है। निवेश ज्यादातर आईटी, ऑटोमोटिव, फार्मा, बायोटेक और मैनुफैक्चरिंग में हैं। जर्मन बाजार में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों की पैठ बढ़ती जा रही है। भारतीय कंपनियों के प्रमुख समूह उत्तरी राइन वेस्टफेलिया, हेसे, बावेरिया और बाडेन-वुर्टेमबर्ग राज्यों में हैं।

जर्मनी में हाल के भारतीय निवेशों में डिजिटल अंतरण में अपने ग्राहकों का समर्थ करने के लिए इन्फोसिस द्वारा डसेलडोर्फ में एक नया डिजिटल इनोवेशन सेंटर खोलना, जेबीएम ग्रुप का जर्मन ऑटो कंपोनेंट निर्माता लिंडे-विमेन जीएमबीएच में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण, हीरो मोटोकॉर्प द्वारा म्यूनिख के पास पहला वैश्विक आरएंडडी सेंटर की स्थापना और अपने बैंकिंग और वित्तीय सेवा सॉफ्टवेयर खंड को मजबूत करने के लिए एल एंड टी द्वारा जर्मन आईटी फर्म नीलसन + पार्टनर का अधिग्रहण।

भारत और जर्मनी में कंपनियों के मुद्दों / शिकायतों को दूर करने के लिए डीपीआईआईटी और आर्थिक मामलों और ऊर्जा के जर्मन मंत्रालय (बीएमडब्ल्यूआई) द्वारा फास्ट ट्रेक तंत्र लागू किए गए हैं।

विकास सहयोग

जर्मनी कई दशकों से एक महत्वपूर्ण विकास सहयोग भागीदार रहा है। 1958 में शुरुआत से कुल द्विपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहयोग, लगभग 22.73 बिलियन अमरीकी डालर हुआ है। ऊर्जा, सतत आर्थिक विकास और पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। जर्मनी से वित्तीय सहायता मुख्य रूप से सॉफ्ट लोन, समग्र ऋण या केएफडब्ल्यू, जर्मन सरकार के विकास बैंक के माध्यम से अनुदान के रूप में दी गई है। जर्मन सरकार की विकास एजेंसी, जीआईज़ेड के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

प्रमुख सामरिक परियोजनाएं ऊर्जा क्षेत्र (नवीनीकरण, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंडो-जर्मन सोलर पार्टनरशिप), कौशल विकास और सतत शहरी विकास (जल / स्वच्छता / अपशिष्ट, जलवायु अनुकूल शहरी गतिशीलता, स्मार्ट शहरों) में हैं।

मोनाको

भारत और मोनाको ने आधिकारिक रूप से 2007 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, हालांकि कंसुलर संबंध 1954 से ही मौजूद थे। पेरिस में भारत के राजदूत को समकालिक रूप से मोनाको की रियासत से मान्यता प्राप्त है।

भारत और मोनाको के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और दोनों देशों ने धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को विकसित किया है। व्यापार, पर्यटन और कराधान मामले सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में से कुछ हैं।

पुर्तगाल

भारत और पुर्तगाल ने सांझा इतिहास, सांस्कृतिक संबंधों और लोकतंत्र और बहुलवाद के साझा मूल्यों के 500 वर्षों में उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं। यह तथ्य कि पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा, पश्चिमी दुनिया में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री हैं, इन गहरे संबंधों का एक साक्ष्य है।

फरवरी 2020 में पुर्तगाली राष्ट्रपति द्वारा भारत में सफल सरकारी यात्रा के बाद, जिसमें 57 नए सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, पुर्तगाल और भारत ने रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, बहुपक्षीय सहयोग, कोविड प्रबंधन, प्रवासन और गतिशीलता, आईटी और स्टार्टअप, आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना और विविधता प्रदान करना जारी रखा।

हाल के उच्च-स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान

05 मई 2020 को, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के साथ फोन पर बात की। कोविड-19 से लड़ने के उद्देश्य से अनुसंधान और नवाचार पर सहयोग कैसे किया जाए पर आपसी सहायता का वादा करते हुए, नेताओं ने प्रकोप को रोकने के अपने प्रयासों पर टिप्पणियों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने पुर्तगाल में भारतीय यात्रियों की वीजा की वैधता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कोस्टा का धन्यवाद किया, जबकि पीएम कोस्टा ने भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में पुर्तगाली नागरिकों को दी गई मदद को स्वीकार किया।

14 अक्टूबर को एक आभासी बैठक में, विदेशी मंत्री और उनके पुर्तगाली समकक्ष विदेश मंत्री ऑगस्टो सांतोस सिल्वा ने द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें फरवरी 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति के भारत के राज्य दौरे के परिणामों और समझौतों की समीक्षा और कोविड-19 संकट से संबंधित सहयोग शामिल है।

कोविड-19 सहयोग

‘वन्दे भारत’ पहल के अंतर्गत लगभग 120 भारतीय नागरिकों को विशेष उड़ानों में भारत लाया गया। कोविड-19 के दौरान के लिए आधिकारिक पुर्तगाली अनुरोध के बाद, भारत ने निर्यात प्रतिबंध हटा दिया, जिससे पुर्तगाल को 2.5 मिलियन एच सी क्यू टेबलेट की बिक्री हुई। भारत ने पुर्तगाल को 15 टन सेनेटरी उपकरण जैसे सुरक्षात्मक दस्ताने की आपूर्ति भी की।

आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध

भारत और मोनाको कर मामलों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए समझौते के अंतर्गत कर मुद्दों पर सहयोग करते आ रहे हैं और अब तक दोनों ओर से सूचना अनुरोधों के आदान-प्रदान के लिए संतोषजनक रूप से उत्तरदायी रहे हैं। दोनों पक्ष 2018 से प्रथम स्वचालित एक्सचेंजों के लिए प्रतिबद्ध हैं और दोनों कार्यक्षेत्रों में वित्तीय संस्थान 1 जनवरी 2017 से दूसरे क्षेत्र के निवासियों के संबंध में वित्तीय खाते की जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

इतिहास में पहली बार 2019 कैलेंडर वर्ष में सामान का द्विपक्षीय व्यापार 1 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया, जो कि 1.06 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया और वर्ष-दर-वर्ष 21% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। पेट्रोकेमिकल्स, औद्योगिक सांचों, वस्त्रों और चमड़े जैसे क्षेत्रों में दिसंबर 2019 तक भारत में पुर्तगाली निवेश पिछले दो वर्षों में 49 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 99 मिलियन अमरीकी डालर हो गया है।

भारतीय निवेश ने भी पुर्तगाल में 350 मिलियन अमरीकी डालर का आंकड़ा छू लिया है और हाल के वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण सौदे देखे हैं। हालांकि, जनवरी और अगस्त 2020 के बीच भारत-पुर्तगाल व्यापार को मुख्य रूप से कोविड-19 (2019 में 13.79% नीचे) के कारण 483.22 मिलियन यूरो तक नीचे आया, जिसमें व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में मजबूती से जारी है। भारतीय आयात 62.68 मिलियन यूरो (2019 से 27.89% नीचे) थे, जबकि भारतीय निर्यात 420.54 मिलियन यूरो (2019 से 13.3% नीचे) रहा।

रक्षा

राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान साइन किए गए समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) और ईएनपी शिपयार्ड पुर्तगाल, फेरी बोट्स, लैंडिंग क्राफ्ट्स, ओपीवी के सह-उत्पादन और अफ्रीकी तथा लैटिन अमेरिकी बाजारों में बाजार के अवसरों की खोज पर चर्चा कर रहे हैं। एचएएल की लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टरों के लिए ईएएसए (यूरोपियन अथॉरिटी फॉर एविएशन सेफ्टी) सर्टिफिकेट प्राप्त करने में मदद के लिए और नासिक में सिविल एमआरओ सर्विसेज फैसिलिटी स्थापित करने के लिए पुर्तगाली रक्षा कंपनी सीईआईआईए के साथ चर्चा कर रही है। भारत की वी ईडीए डिफेंस और पुर्तगाली यूए विज़न भारतीय वायु सेना के संभावित उपयोग के लिए यूएवी प्रोटोटाइप के संयुक्त डिजाइन और विकास पर काम कर रहा है।

विज्ञान और तकनीक

पुर्तगाल उन 4 देशों में से एकमात्र देश है, जिनके साथ भारत हर दो साल में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करता है। 2017 में प्रधानमंत्री की पुर्तगाल यात्रा के दौरान घोषित 4 मिलियन यूरो के संयुक्त अनुसंधान निधि के अंतर्गत, प्रस्तावों के प्रारम्भिक कॉल के जवाब में अगस्त 2020 में 423 संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव जमा किए गए, जिसमें कोविड-19 संबंधित अनुसंधान भी शामिल हैं।

भारत और पुर्तगाल के बीच मजबूत वैज्ञानिक सहयोग इस तथ्य में भी स्पष्ट है कि इस वर्ष के शुरू में राष्ट्रपति के दौरे से 16 एस्पेंडटी संबंधी परिणाम सामने आए थे। वास्तव में, एक अकेले पुर्तगाली संस्थान आईएनईएससी-टीईसी के भारत में अपने समकक्ष संस्थानों के साथ 11 समझौता ज्ञापन हैं। महामारी के बावजूद, आईएनईएससी-टीईसी औरआईआईटी मद्रास, एनआईटी गोवा, और सीएसआईआर-एनआईओ जैसे भारतीय समकक्षों ने समुद्र विज्ञान, रोबोटिक्स, अरब सागर में प्लास्टिक स्तर का आकलन और आपदा प्रबंधन के लिए ड्रोन का उपयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में परियोजनाएं शुरू कर दी हैं।

भारत-पुर्तगाल प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 7-9 दिसंबर 2020 के दौरान ऑनलाइन आयोजित किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी - भारत) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी फाउंडेशन (एफसीटी-पुर्तगाल) द्वारा संयुक्त रूप से भारतीय उद्योग परिसंच (CII - भारत) के

आयरलैंड

कोविड-19 महामारी और परिणामस्वरूप लॉकडाउन के कारण, मिशन की बहुत सारी गतिविधियों को कम करना पड़ा या डिजिटल प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित करना पड़ा। दूतावास ने बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनाया और स्थानीय दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉन्सुलर, वीज़ा और पासपोर्ट सेवाओं को प्रदान करने सहित अपने कार्यों को जारी रखा।

कोविड-19 चुनौती के बावजूद भारत और आयरलैंड के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक और आर्थिक संबंध उत्साहपूर्ण रहे। महामारी के बीच में, प्रधानमंत्री ने महामारी के खिलाफ संयुक्त वैश्विक लड़ाई में फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा अनुसंधान में सहयोग पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन आयरिश प्रधानमंत्री लियो वरादकर (22 अप्रैल 2020 को) के साथ एक टेलीकॉन किया। वरादकर ने भारतीय डॉक्टरों और नर्सों द्वारा कठिन समय में निभाई गई असाधारण भूमिका की सराहना की। 28 जून 1920 को ब्रिटिश सेना में सेवारत आयरिश सैनिकों द्वारा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अवज्ञा के सबसे असाधारण कृत्यों में से एक, कर्नाट रेंजर्स म्युटिनी की स्मारक शताब्दी, डबलिन में आयोजित की गई थी, जिसका नेतृत्व लियो वरादकर ने किया था। एकिस्टा के पास आयरलैंड के दक्षिण पश्चिम तट पर एयर इंडिया कनिष्क की दुर्घटना की 35वीं वर्षगांठ को स्थानीय समुदाय के साथ वस्तुतः (23 जून 2020) चिह्नित किया गया था। महामारी प्रतिबंधों को उठाने के साथ, मिशन ने विदेश मंत्री / CIM के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने के लिए Q-I 2021 में भारत के लिए एक आयरिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की उच्च स्तरीय यात्रा का प्रस्ताव दिया है। बहुपक्षीय स्तर पर, भारत और आयरलैंड दोनों को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था, आयरिश विदेश मंत्री साइमन कोवेनी ने विदेश मंत्री (04 अगस्त 2020) को बहुपक्षवाद, शांति स्थापना, जलवायु परिवर्तन के आम एजेंडे पर चर्चा करने के लिए बोला था। नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय आदेश। आयरलैंड ने जनसंख्या और विकास आयोग (2021-25), महिलाओं की स्थिति पर आयोग (2021-25) और कार्यक्रम और समन्वय समिति (2021-23); यूनेस्को-आईसीएच; और एसीएबीक्यू के लिए भारत की आशावादी का समर्थन किया।

सहयोग से आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन में हेल्थटेक, क्लीनटेक, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, वाटरटेक, एग्रोटेक, स्पेस-ओशन इंटरैक्शन और आईटी / आईसीटी और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर विषयगत सत्र शामिल थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने 7 दिसंबर 2020 को शिखर सम्मेलन और डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सम्मानित अतिथि के रूप में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा मंत्री मैनुअल हेइटर ने उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया

संस्कृति

150वीं जयंती मनाने के लिए, 02 अक्टूबर, 2020 को प्रसिद्ध पर्यटक शहर अल्बुफेइरा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा स्थापित की गई, जो बड़े और बढ़ते भारतीय प्रवासियों का निवास भी है।

आईडीवाई और आयुर्वेद दिवस 2020

आईडीवाई 2020 आयरलैंड में फ्रंटलाइन स्टाफ, नर्सों, पुलिस बल, अग्रिशमन सेवा, राष्ट्रीय एम्बुलेंस, डबलिन बस, अस्पतालों और सफाई सेवाओं (20 जून 2020) के लिए समर्पित था। यह रेखांकित किया गया था कि समग्र स्वास्थ्य, सामुदायिक संपर्क, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने वाले योग का सर्वोत्कृष्ट संदेश कोविड के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक था और महामारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कोर मूल्य प्रणाली के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित हुआ। लाइव-स्ट्रीम किए गए कार्यक्रम में स्थानीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार, घर में अभ्यास कर रहे 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। अन्य कार्यक्रमों में वर्चुअल योग क्लिज़ प्रतियोगिता, मेरा जीवन-मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता, ऑनलाइन योग फ़िल्में और कुछ संस्थानों द्वारा संचालित मुफ्त ऑनलाइन योग कक्षाएं शामिल थीं। आयुर्वेद चिकित्सकों, रोगियों और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से आयुर्वेद दिवस (13 नवंबर 2020) को परिलक्षित किया गया।

गांधी @ 150 समापन कार्यक्रम

स्थानीय संस्थानों / कॉलेजों / स्कूलों के सहयोग से दूतावास ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, मुख्यतः आभासी प्लेटफार्मों पर। इनमें शामिल हैं: शोभना राधाकृष्ण, गांधियन फोरम फॉर एथिकल कार्पोरेट गवर्नेंस द्वारा “गांधी कथा” (28 सितंबर 2020); “लगे रहो मुन्ना भाई” का प्रदर्शन (29 सितंबर 2020); बच्चों के लिए गांधी पर ड्राइंग प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी (30 सितंबर 2020); गांधी सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट, स्वदेश और गांधी दर्शन के संस्थापक और निदेशक जैकब पुलिकान द्वारा चर्चा (01 अक्टूबर 2020); यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन (यूसीडी) के साथ साझेदारी में पैल चर्चा(02 अक्टूबर 2020); जॉन स्कॉट्स स्कूल, डबलिन में गांधी स्मारक कार्यक्रम, (1987 में स्कूल शुरू से ही संस्कृत पढ़ा रहा है) (02 अक्टूबर 2020); और वैदिक हिंदू कल्चरल सेन्टर ऑफ आयरलैंड (VHCCI) द्वारा आयोजित “महात्मा गांधी की विश्व धर्म और आध्यात्मिकता में योगदान” पर अंतर-सांस्कृतिक चर्चा(03 अक्टूबर 2020)। पूर्व आयरिश पीएम, बर्टी अहर्न (वह 1997 से 2008 तक पीएम थे और 2006 में भारत आए थे) ने गांधी के अपने छात्रों पर एक लघु वीडियो

संदेश के साथ समारोह में योगदान दिया। दूतावास आयरिश उद्योग के साथ खादी सहभागिता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है।

संस्कृति

दूतावास ने क्षेत्रीय त्योहारों को आभासी रूप में मनाने में भारतीय समुदाय की सहायता की। आयरलैंड में समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक-धार्मिक आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन (22 अगस्त 2020) वैदिक हिंदू संस्कृति केंद्र, आयरलैंड (VHCCI) द्वारा किया गया। भारतीय संस्कृति, भाषाओं और मूल्य पद्धति के प्रचार-प्रसार पर केंद्रित शिक्षक दिवस का आयोजन(07 सितंबर 2020) आयरलैंड में भारतीय मूल के शिक्षकों के साथ आभासी पैल चर्चा के माध्यम से किया गया। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस #WordOfHindi के आसपास केंद्रित कार्यक्रमों के सप्ताह भर के अभियान के माध्यम से चिह्नित किए गए। संविधान दिवस (26 नवंबर 2020) को विभिन्न आयरिश विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय छात्रों के साथ मिलकर आयोजित कार्यक्रमों द्वारा चिह्नित किया गया था। आयरलैंड में 11वां भारतीय फिल्म महोत्सव (IFFI) क्षेत्रीय फिल्मों और वृत्तचित्रों, पैल चर्चाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्क्रीनिंग के साथ एक आभासी मंच पर (20-23 नवंबर 2020) आयोजित किया गया। पीबीडी 2020 के कार्यक्रमों को स्थानीय प्रवासियों की जबर्दस्त भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। भारतीय महाविद्यालय में ICCR अल्पकालिक अध्यक्षा का प्रस्ताव यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क, ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन के लिए किया गया। 20वीं शताब्दी में गुरु ग्रंथ साहिब का अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय प्राप्त मैक्स आर्थर मैकॉलिफ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लिमरिक में एक पट्टिका के अनावरण से संबंधित परियोजना को सांस्कृतिक एकीकरण श्रेणी में आयरिश सरकार द्वारा शीर्ष पुरस्कार के लिए चयनित किया गया।

आर्थिक

2019-20 के लिए भारत और आयरलैंड के बीच व्यापार 1.08 बिलियन यूरो था, जिसमें भारतीय निर्यात 590.43 मिलियन यूरो था और 495.74 मिलियन यूरो का आयात करता है, जो भारत के पक्ष में 94.69 मिलियन यूरो का व्यापार संतुलन छोड़ता है। पिछले उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सेवाओं में व्यापार 4.02 बिलियन यूरो की राशि है, आयरलैंड में 3.12 बिलियन यूरो का निर्यात होता है और 896 मिलियन यूरो में आयात होता है, जिसमें आयरलैंड के पक्ष में 2.23 बिलियन यूरो का व्यापार होता है। अप्रैल-सितंबर 2019 तक व्यापार अप्रैल से सितंबर 2019 तक 429.75 मिलियन यूरो की तुलना में 339.94 मिलियन यूरो था, जो महामारी से प्रभावित 20.89% की कमी को दर्शाता है। भारतीय निर्मित पीपीई और नैदानिक किटों के निर्यात के अवसरों का पता लगाया गया। टीसीएस आयरलैंड ने प्रूडेंट फाइनेंशियल इंक (पीएफआई) के साथ एक समझौता (नवंबर 2020) किया, कंपनी लेटरकेनी में स्थित पीएफआई की सहायक कंपनी प्रामेरिका सिस्टम्स आयरलैंड लिमिटेड

बेल्जियम

भारत और बेल्जियम के द्विपक्षीय संबंध उत्कृष्ट हैं। जबकि बेल्जियम के पास

की 1500 कर्मचारियों और चुनिंदा संपत्तियों का अधिग्रहण किया। प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर प्रमुख समझौता ज्ञापन और साथ ही IFSCA और सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड के बीच आपसी सहयोग किया गया। दूतावास ने व्यापार के अग्रणियों के साथ नियमित वेबिनार के साथ आभासी प्लेटफार्मों पर अपनी गतिविधियां संचालित कीं, जो पोस्ट-कोविड द्विपक्षीय वाणिज्यिक अवसरों के आसपास केंद्रित हैं, जिनमें नई आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकियों, फिनटेक, मेडटेक और दूरस्थ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों के साथ-साथ आयरलैंड में अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती की संभावनाएं शामिल हैं। राजदूत ने, विशेष रूप से, इंडियन बिजनेस एसोसिएशन (IIBA), ABP समाचार, बिजनेस स्टैंडर्ड, आयरिश “डिप्लोमैट.आईई” और टेकस्पार्क्स (भारत के प्रमुख स्टार्ट-अप टेक सम्मेलन) को साक्षात्कार दिए। VAIBHAV 2020 में भारतीय-आयरिश वैज्ञानिकों की जबर्दस्त भागीदारी थी। आईसीटी, फार्मास्यूटिकल्स, सिविल एविएशन और आयरिश हार्ड-टेक पर ब्रेक्सिट के प्रभाव के क्षेत्रों में वाणिज्यिक रिपोर्ट बनाई गई थी। डबलिन और कॉर्क (Q-I 2021) के लिए चिकित्सा और कल्याण पर्यटन पर ध्यान देने के साथ पर्यटन रोड शो की योजना बनाई गई थी।

प्रांतीय आउटरीच

आंतरिक यात्रा प्रतिबंधों में ढील के आधार पर, दूतावास अपनी प्रांतीय आउटरीच गतिविधियां जारी रखी, मुख्य रूप से कोविड-पश्चात सहयोग का पता लगाने के लिए, विशेष रूप से आर्थिक और चिकित्सा क्षेत्रों में। राजदूत ने स्लाइगो (जून); पोर्ट लॉज, मोनाघन, विकलो और कार्लो (जुलाई); मीअथ, लेट्टिम और कैरिक-ऑन-शैनन (अगस्त); क्लेयर और ऑफली (सितंबर), साथ ही गैलवे और वॉटरफोर्ड (दिसंबर) की काउंटियों का दौरा किया। इन यात्राओं के दौरान, महापौरों / नगर परिषद के अधिकारियों, स्थानीय चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड एंटरप्राइज सेंटर्स के अध्यक्षों और विश्वविद्यालयों के प्रमुखों के साथ बैठकें की गईं। भारत के साथ सहयोग की संभावना वाली स्थानीय व्यापार फर्मों का साइट दौरा किया गया। कोविड के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए शहर के अस्पतालों में भारतीय अग्रणी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये महत्वपूर्ण अवसर भी थे। दूतावास के पूर्ण समर्थन का आश्वासन देने के लिए कार्यक्रम का एक प्रमुख तत्व काउंटियों में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करना था।

भारतीय समुदाय

आयरलैंड में भारतीय मूल के लगभग 45,000 लोग हैं, लगभग 26,500 PIOs 18,500 NRI हैं। समुदाय के अधिकतर लोग स्वास्थ्य सेवा, आई टी, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के वरिष्ठ पदों पर हैं। समुदाय आयरिश समाज से अच्छी तरह से एकीकृत है। अप्रैल - नवंबर 2020 की अवधि के दौरान, 1,528 पासपोर्ट और 110 वीजा जारी किए गए, 421 दस्तावेजों को सत्यापित किया गया, और 127 नए जन्म और 5 निधन पंजीकृत किए गए।

2019-2020 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी

सदस्यता थी, बहुपक्षीय जुड़ाव को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित रखते हुए संबंध और अधिक मजबूत हुए

कोविड-19 सहयोग

सामान्य तौर पर, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग द्विपक्षीय एजेंडे पर हावी था। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद HCQ (API) के 1000kgs का निर्यात बेल्जियम को किया गया।

व्यापार और आर्थिक संबंध

भारत-बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों का केंद्रीय स्तंभ पारंपरिक रूप से व्यापार और निवेश रहा है। भारत और बेल्जियम के बीच जनवरी से जुलाई 2020 तक के बीच सामान का कुल द्विपक्षीय व्यापार 4.39 बिलियन यूरो (अमरीकी डॉलर 4.87 बिलियन) होता है। भारत और बेल्जियम के बीच सेवाओं में कुल द्विपक्षीय व्यापार 1.05 बिलियन यूरो (अमरीकी डॉलर 1.24 बिलियन) है। भारत में बेल्जियम का कुल निवेश अप्रैल 2000 से जून 2019 तक 1,876 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो इसे भारत का 19वां सबसे महत्वपूर्ण

निवेशक बनाता है।

सांस्कृतिक सहयोग

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में, 02 अक्टूबर 2020 को एंटरवर्प शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था।

वैज्ञानिक सहयोग

बेल्जियम की कंपनी AMOS ने अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के लिए 2.5m टेलीस्कोप के अपने प्रोजेक्ट की सफल पूर्णता पर 16 अक्टूबर 2020 को एक समारोह का आयोजन किया। श्री विली बोरसस, वालोनिया के उपाध्यक्ष, और अर्थव्यवस्था मंत्री ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर को शानदार बनाया। टेलीस्कोप को माउंट आवू, राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत) और बेल्जियम के संघीय विज्ञान नीति कार्यालय के बीच भारत-बेल्जियम संयुक्त समिति की 5वीं बैठक 18 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी।

लक्समबर्ग

भारत के लक्समबर्ग के ग्रैंड डची के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

राजनीतिक विमर्श

प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2020 को, लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल

के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन किया, जो दोनों देशों के बीच लगभग 20 वर्षों में पहला उच्च स्तरीय संपर्क था। एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया और शिखर सम्मेलन के साथ तीन वित्तीय क्षेत्र के समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुए और शिखर सम्मेलन के साथ तीन वित्तीय क्षेत्र के समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुए



19 नवंबर 2020 को आयोजित भारत-लक्समबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन

30 जुलाई 2020 को, द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) का लक्समबर्ग चैप्टर लॉन्च किया गया; यह कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री के साथ वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बिरादरी को मुख्य भाषण दिया और आज तक 50 ऐसे अध्यायों के साथ आईसीएआई की वैश्विक उपस्थिति के विस्तार की अनूठी उपलब्धि हासिल की।

1997 में स्थापित भारत-बेल्जियम लक्समबर्ग इकोनॉमिक यूनियन जॉइंट कमीशन (भारत-बीएलईयू जेसीएम) द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक मुद्दों पर विचार-विमर्श का मुख्य मंच है। इस मंच पर व्यापार विविधीकरण, निवेश, आर्थिक सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ-तकनीक, जल उपचार, आईसीटी, सेवाओं, पारंपरिक दवाओं, योग, पर्यटन, बाजार पहुंच मुद्दों, बहुपक्षीय सहयोग आदि सहित कई विषयों पर चर्चा की जाती है।

जनवरी से जुलाई 2020 तक भारत और लक्समबर्ग के बीच सामान का कुल द्विपक्षीय व्यापार 29 मिलियन यूरो (अमरीकी डॉलर 32.19 मिलियन) रहा

आर्थिक संबंध

जबकि सेवाओं के व्यापार में यह आंकड़ा 221 मिलियन यूरो (अमरीकी डॉलर 261 मिलियन) था। भारत में लक्समबर्ग द्वारा कुल निवेश अप्रैल 2000 से

जून 2019 तक 2,845 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो इसे भारत में 16वां सबसे महत्वपूर्ण निवेशक बनाता है।

नीदरलैंड

उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान

विदेशी मंत्री और स्टेफ ब्लॉक, नीदरलैंड के विदेश मामलों के मंत्री ने जून और नवंबर 2020 में टेलीफोन पर बातचीत की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मई 2020 में नीदरलैंड के विदेश व्यापार और विकास सहयोग मंत्री, अपने समकक्ष सिग्नीड काग से बात की थी।

कोविड-19 सहयोग

भारत और नीदरलैंड ने प्रत्यावर्तन के लिए एयरलाइन परिचालन को सुगम किया और एक दूसरे के फंसे हुए नागरिकों के लिए वीजा का विस्तार भी किया। नीदरलैंड में फंसे 2000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया।

निर्यात पर प्रतिबंध हटने के बाद 350 हजार से अधिक एचसीक्यू टैबलेट नीदरलैंड को निर्यात किए गए, जिसकी नीदरलैंड सरकार ने सराहना की। नीदरलैंड के साथ एक एयर बबल व्यवस्था 1 नवंबर 2020 से प्रभावी हुई

आर्थिक सहयोग

जल शक्ति मंत्रालय और डच इन्फ्रास्ट्रक्चर और जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन के अंतर्गत द्वितीय संयुक्त कार्य समूह की बैठक 22 अक्टूबर 2020 को एक आभासी प्रारूप में हुई।

बहुपक्षीय सहयोग

भारत और नीदरलैंड वैश्विक प्रयासों और बहुपक्षीय संगठनों में एक दूसरे का सहयोग और समर्थन करते रहे। मई 2020 में नीदरलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की आशावादी के लिए नीदरलैंड ने समर्थन दिया। नीदरलैंड ने डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए गठबंधन में शामिल होने पर भी सहमति व्यक्त की है।

डच प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी 2021 को नीदरलैंड द्वारा आयोजित जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।

इटली

भारत कोविड-19 महामारी के चरम पर लोगों और इटली सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा रहा। भारत ने मार्च 2020 में 40,000 सर्जिकल मास्क, 100,000 हैंड ग्लव्स, 20,000 हेडकवर और 20,000 शू कवर इटली को भेंट किए, जिसकी इटली सरकार ने काफी सराहना की। विदेश मंत्री डि मैयो ने शिपमेंट के पहुंचने पर अपनी सरकार की ओर से आभार व्यक्त किया और इतालवी विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम ज़रूरत के इस समय में मिलता और उदारता के लिए आभारी हैं"।

उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान

भारत और इटली के संबंधों को 08 मई 2020 को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री ग्विसेपे कोन्ते के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत से एक नई ताकत मिली। भारत और इटली के बीच 6 नवंबर 2020 को आयोजित व्यापक द्विपक्षीय समीक्षा की व्यापक रूपरेखा की समीक्षा के लिए और द्विपक्षीय संबंध और कोविड-19 महामारी सहित आम वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए इस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के साथ इस गति को आगे बढ़ाया गया। दोनों देशों ने भारत और इटली (2020-2024) के बीच एक बड़ी हुई साझेदारी के लिए कार्य योजना को अपनाया। शिखर सम्मेलन के साथ विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, मत्स्य पालन, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि में 15 समझौता ज्ञापनों / समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

विदेशी मंत्री ने अपने इतालवी समकक्ष लुइगी डि मैओ के साथ 11 दिसंबर 2020 को वर्चुअल समिट स्तर के परिणामों और कोविड-पश्चात परिदृश्य में सहयोग की संभावनाओं सहित द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा के लिए

एक आभासी बैठक की।

आर्थिक संबंध

नवंबर में वीवीआईपी शिखर सम्मेलन की तैयारी में, 07 अक्टूबर को यूरोपीय व्यापार और प्रौद्योगिकी केंद्र के साथ बैठक सहित कई बैठकें आयोजित की गईं; 14 अक्टूबर को मत्स्य क्षेत्र में उभरते अवसरों पर एक उच्च स्तरीय बैठक; 26 अक्टूबर को SNAM के साथ; 27 अक्टूबर को भारतीय-इतालवी स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ; 28 अक्टूबर को अर्थशास्त्र संबंध पर भारत-इटली उच्च स्तरीय वार्ता; 29 अक्टूबर को Fincantieri के अध्यक्ष के साथ; और 30 अक्टूबर को इटली में स्थित भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ।

24 नवंबर 2020 को फास्ट ट्रेक मैकेनिज्म मीटिंग का दूसरा संस्करण हुआ।

श्रमिक और प्रवासी श्रमिक मुद्दे

बड़ी संख्या में श्रमिक इटली में रोजगार चाहते हैं। उनका शोषण होता है। एक अंतर-मंत्रालयी निकाय की स्थापना और प्रवासी श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए 2020-2022 के लिए तीन-वर्षीय कार्य योजना अपनाते सहित इटली शोषण से निपटने के लिए कई उपाय कर रहा है। मंत्रालय प्रवासी श्रमिकों को एकीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए भी सहयोग दे रहा है। इस गतिविधि के अंतर्गत, 2019 में जालंधर में एक पूर्व-प्रस्थान सुविधा प्रदान की गई, जिसने लगभग 50 भारतीय श्रमिकों को लाभाञ्चित किया। दोनों पक्षों ने प्रवासी श्रमिकों



06 नवंबर 2020 को आयोजित भारत-इटली शिखर सम्मेलन

के शोषण से निपटने के लिए इतालवी पक्ष द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी के उचित प्रसार पर सहमति व्यक्त की। एक माइग्रेसन और

मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा चल रही है जो सम्पन्न होने पर रोजगार पाने वालों की मदद करेगा।

सैन मैरिनो

सैन मैरिनो के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। दोनों देशों ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों के अंतर्गत, बल्कि समान हित के मुद्दों पर द्विपक्षीय स्तर पर एक उपयोगी सहयोग स्थापित किया है।

सैन मैरिनो ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में भारत की आशावादी के लिए समर्थन दिया है और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के

गठबंधन (सीडीआरआई) पर भारत की पहल का भी समर्थन किया है।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 की तुलना में 2019-20 में 29% की वृद्धि को दर्शाते हुए 0.40 मिलियन अमरीकी डालर पर था। सैन मैरिनो को भारत का निर्यात 62.65% बढ़ा और 0.25 मिलियन अमरीकी डालर रहा, जबकि सैन मैरिनो का आयात 5.11% घटकर अमरीकी डॉलर 0.15 मिलियन तक पहुँच गया।

स्पेन

स्पेन और भारत करीबी संबंध बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 04 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज़ से बात की। विदेशी मंत्री ने 16 फरवरी 2020 को म्युनिख सुरक्षा सम्मेलन के अवसर पर स्पेनिश विदेश मंत्री अरंचा गोंजालेज़ लाया से मुलाकात की। विदेशी मंत्री ने महामारी के शुरुआती चरण के दौरान दो बार स्पेनिश विदेश मंत्री के साथ बात की। स्पेन के विदेश मंत्री ने संकट के चरम पर स्पेन में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और अन्य दवाएं भेजने के लिए भारत को धन्यवाद दिया।

विदेशी मंत्री ने 23 दिसंबर 2020 को अपने स्पेनिश समकक्ष के साथ एक आभासी बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा की और हाल के वर्षों में देखे गए द्विपक्षीय संबंधों में ऊर्ध्वगामी रूझान की सराहना की। वे विशेष रूप से सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे गतिशीलता, रक्षा सहयोग और ऊर्जा में गति बनाए रखने के लिए सहमत हुए। नेताओं ने भारत - यूरोपीय संघ के संबंधों पर भी चर्चा की और आगामी भारत-यूरोपीय संघ के नेताओं के सम्मेलन के संदर्भ में बारीकी से काम करने पर सहमति व्यक्त की जो मई 2021 में पुर्तगाल में आयोजित होने का प्रस्ताव है।

6ठे भारत-स्पेन विदेश कार्यालय परामर्श 21 जुलाई को सचिव (पश्चिम) और स्पेन के विदेश मामलों के विदेश सचिव, इबेरो-अमेरिका और कैरिबियन क्रिस्टीना गैलाच की सह-अध्यक्षता में आयोजित किए गए। दोनों पक्षों ने कोविड-19 की प्रतिक्रिया और कोविड की पुनर्प्राप्ति प्राथमिकताओं और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने आर्थिक और व्यापारिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक और लोगों के स्तर के सहयोग को मजबूत करने के लिए विचार और तरीकों के अंतर्गत समझौतों की समीक्षा की।

कोविड -19 सहयोग

स्पेन कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक था, जिसके दौरान उच्च-स्तरीय सहयोग बना रहा। भारत ने इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2500 किलोग्राम एचसीक्यू (एपीआई) स्पेन को निर्यात किया।

आर्थिक सहयोग

भारत और स्पेन के बीच वाणिज्यिक संबंध मजबूत हैं। जनवरी में पर्यटन मेला एफआईटीयूआर 2020 और फरवरी में उपहार और सजावट मेले इंटरगिफ्ट

के साथ व्यापार प्रतिनिधिमंडल एक हाई नोट पर शुरू हुआ। व्यापार मंडलों, निवेश एजेंसियों, व्यापार संघों, परामर्श और कानून फर्मों के साथ वेबिनार और वीबीएसएम के माध्यम से आभासी जुड़ाव जारी रहा। भारत में कोविड-19 पश्चात सुधारों और अवसरों को स्पेनिश कंपनियों से काफी रुचि मिली।

सांस्कृतिक संबंध

गांधी @ 150 समारोह के समापन पर क्रिस्टोबाल गबरोन द्वारा गांधी जी पर पेंटिंग 'दी हेड ऑफ़ द जाइंट ऑफ़ द जायंट' का अनावरण जो स्पेन के सबसे महान जीवित मिक्स-मीडिया कलाकार में से एक है, 24 अक्टूबर 2020 को

वल्लडोलिड में अपने कामों के लिए समर्पित एक प्रभावशाली प्रदर्शनी में और मारियापिलर ल्लोप क्युएन्का, स्पेन की सीनेट के अध्यक्ष की ओर से विशेष वीडियो संदेश समर्पित है।

महामारी के शुरू होने के बाद से स्पेन ने आईसीसीआर के पहले सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की और भारत के बाहर अपनी शताब्दी में भारत रत्न पंडित रविशंकर को मनाने वाला भी पहला। दी रविशंकर क्रांटे टूअर (07-12 अक्टूबर) और भारत के 6ठे संस्करण एन कॉनसीरो बाईइनियल फेस्टिवल (09-11 अक्टूबर) ने पहले भौतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को चिह्नित किया।

एंडोरा

भारत और अंडोरा की रियासत के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहे। अंडोरा में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह 27 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में एंडोरन विदेश मंत्री, मारिया उबाक फॉन्ट उपस्थित हुई। सचिव (पश्चिम) ने 24 फरवरी को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र

मानवाधिकार परिषद उच्च-स्तरीय सेगमेंट के अवसर पर एंडोरन विदेश मंत्री से मुलाकात की। एक पी आई ओ, मधु जेटानी को 07 सितंबर 2020 को हमारे मानद कौंसल के रूप में नियुक्त किया गया था।

यूरोपीय संघ



प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2020 को 15 वें भारत-यूरोपीय संघ आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया

उच्च-स्तरीय सहभागिता

15वीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण आभासी मोड में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया जबकि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लीन ने यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व किया। शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के प्रति संयुक्त अनुक्रिया, भारत-यूरोपीय संघ सामरिक भागीदारी और इसके विभिन्न आयामों को मजबूत करने के साथ-साथ बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और समकालीन विकास को कवर करने वाले वैश्विक क्षेत्र पर सहयोग शामिल है। शिखर सम्मेलन ने यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी को मजबूत करने में मदद की और 2025 तक एक नया रोडमैप प्रदान किया, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश पर उच्च-स्तरीय बातचीत और समुद्री सुरक्षा पर एक नया संवाद तंत्र

स्थापित करने सहित सभी क्षेत्रों में संबंध को उन्नत किया गया।

नेताओं ने यूरोपीय संघ-भारत सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, भारत-यूरोपीय संघ सामरिक साझेदारी: 2025 के लिए रोडमैप और संसाधन दक्षता और वृत्तीय अर्थव्यवस्था पर संयुक्त घोषणा को अपनाया। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते का नवीनीकरण 5 साल के लिए किया गया।

लोक सभा के अध्यक्ष और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली के बीच 13 जनवरी 2021 को एक आभासी बैठक हुई। 28 मई 2020 को विदेशी मंत्री ने ई यूके उच्च प्रतिनिधि / उपाध्यक्ष, जोसेफ बोरेल के साथ टेलीफोन पर

बातचीत की।

शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच विदेश नीति और सुरक्षा परामर्श के 7वें दौर का आयोजन 22 अक्टूबर 2020 को आभासी मोड में किया गया। भारतीय पक्ष का नेतृत्व सचिव (पश्चिम) ने किया, जबकि ई यू पक्ष का नेतृत्व डिप्टी सेक्रेटरी जनरल फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, यूरोपीयन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस द्वारा।

आर्थिक संबंध

15वें भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों पक्षों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंत्री स्तर पर एक उच्च-स्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई थी। वार्ता की पहली बैठक 22 जनवरी 2021 को आयोजित की गई और वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और यूरोपीय व्यापार आयुक्त, वाल्डिस डॉम्ब्रोव्स्की द्वारा सह-अध्यक्षता की गई।

उपरोक्त के अलावा, भारत-यूरोपीय संघ वित्तीय सेवा वार्ता की वार्षिक बैठक (10 जून 2020); प्रवासन और गतिशीलता पर भारत-यूरोपीय संघ कॉमन एजेंडा के अंतर्गत तकनीकी परियोजना की तीसरी परियोजना सलाहकार समिति (02 जुलाई 2020); सेनेटरी और फाइटोसैनेटिक उपाय / व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर 13वां संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) (09 जुलाई 2020); फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा

उपकरणों पर जे डब्लू जी (15 अक्टूबर 2020); रिन्यूएबल्स पर जेडब्ल्यूजी (13 नवंबर 2020); कृषि और समुद्री उत्पादों पर 11 वीं जेडब्ल्यूजी (9 दिसंबर 2020); ऊर्जा दक्षता, स्मार्ट ग्रिड और बिजली बाजार पर जेडब्ल्यूजी (4 दिसंबर 2020); ऊर्जा सुरक्षा पर जेडब्ल्यूजी (14 जनवरी 2021); और पहली भारत-यूरोपीय संघ बौद्धिक संपदा अधिकार वार्ता (14 जनवरी 2021) आयोजित की गई।

जनवरी से जुलाई 2020 तक भारत और यूरोपीय संघ -27 के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार EUR 36.11billion (अमरीकी डॉलर 40.09 बिलियन) था, जो कि 2019 में समान व्यापार अवधि (EUR 36.11billion) की तुलना में EUR 46.61billion की तुलना में 22.5% की गिरावट है।) है। भारत और EU के बीच सेवाओं में कुल द्विपक्षीय व्यापार EUR 29.6bn (अमरीकी डॉलर 33.15 बिलियन) है। कुल एफडीआई का 17.31% के साथ, यूरोपीय संघ भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। एफडीआई अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक यूरोपीय संघ के 27 से प्रवाहित होकर कुल 81.35 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।

सुरक्षा सहयोग

भारत और यूरोपीय संघ के पास सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिए 4 संवाद तंत्र हैं। सभी संवादों की बैठकें - 12 वीं काउंटर टेररिज्म डायलॉग (19 नवंबर 2020); निरस्त्रीकरण और अप्रसार पर 6ठा परामर्श (23 नवंबर 2020); 6ठी साइबर वार्ता (14 दिसंबर 2020); और प्रथम समुद्री सुरक्षा संवाद (20 जनवरी 2021), आभासी प्रारूप में आयोजित किए गए थे।

9

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका

उच्च-स्तरीय सहभागिता

प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने कोविड-19 महामारी पर 04 अप्रैल 2020 को, टेलीफोन पर विचारों का आदान-प्रदान किया और वैश्विक कल्याण और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव और कोविड-19 का प्रभावी प्रतिकार करने के लिए भारत-अमेरिका भागीदारी की पूरी ताकत लगाने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने 2 जून 2020 को भी बात की और कोविड-19 महामारी सहित सामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री को अमेरिका में आयोजित होने वाले अगले जी -7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया (जो बाद में स्थगित कर दिया गया था)।

प्रधानमंत्री ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन (एएपीआई) की वार्षिक बैठक को 27 जून 2020 को, संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई 2020 को, यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल के वर्चुअल इंडिया आइडियाज समिट और 45वीं वार्षिक बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 03 सितंबर 2020 को यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने 17 नवंबर 2020 को ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को वर्चुअली संबोधित किया।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के दृढ़ नेतृत्व

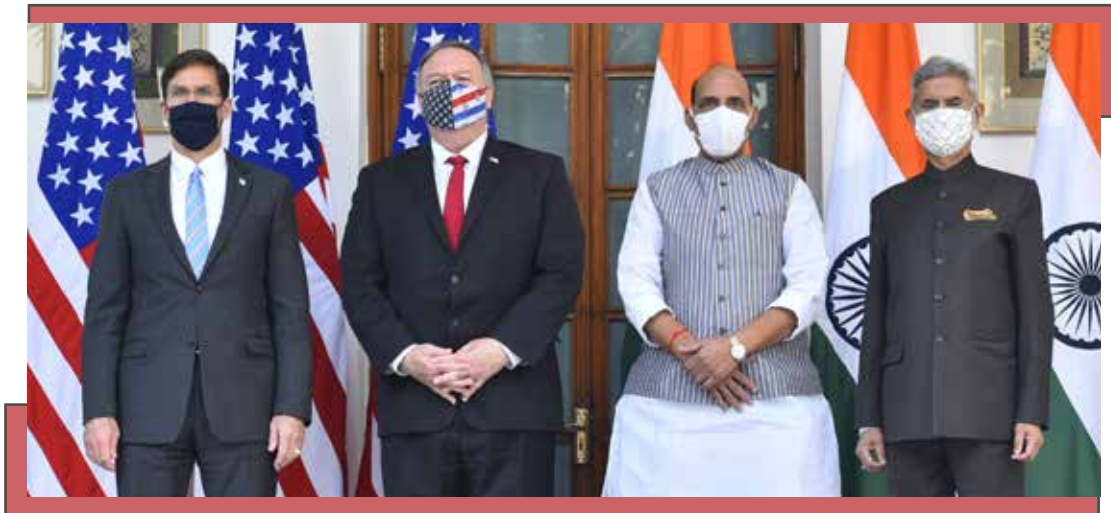
और वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उद्भव के लिए दृष्टिकोण और भारत-अमेरिका सामरिक साझेदारी के संवर्धन और वैश्विक शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा किए गए अनुकरणीय योगदान को मान्यता देते हुए उच्चतम अलंकार, लीजन ऑफ मेरिट, डिप्टी चीफ कमांडर से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। मुख्य कमांडर की उच्चतम डिप्टी लीजन ऑफ मेरिट, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो प्रायः राष्ट्र के प्रमुखों अथवा राष्ट्राध्यक्षों को प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडन और उपाध्यक्ष कमला हैरिस को उनके चुने जाने पर सोशल मीडिया पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडन बाइडन के साथ टेलीफोन पर 17 नवंबर, 2020 को गर्मजोशीपूर्ण और दोस्ताना बातचीत की। वे भारत-अमेरिका को अग्रसर करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। उन्होंने व्यापक वैश्विक सामरिक साझेदारी और कोविड-19 महामारी युक्त, सस्ते टीकों की पहुंच को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की।

भारत-अमेरिका 2 + 2 मंत्रिस्तरीय संवाद: तृतीय वार्षिक भारत-अमेरिका 2 + 2 मंत्रिस्तरीय संवाद 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में हुआ, जिसका नेतृत्व हमारी ओर से रक्षामंत्री और विदेशी मंत्री ने किया, जिसमें अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व पूर्व रक्षा सचिव मार्क टी.एस्पर तथा राज्य के सचिव माइकल आर. पोम्पियो ने किया। उन्होंने रक्षा, सामरिक और सुरक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ

महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। सचिव पोम्पेओ और सचिव एस्पर ने क्रमशः रक्षामंत्री, श्री राजनाथ सिंह और विदेशी मंत्री के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें कीं।

[चित्र: प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई 2020 को 15 वें भारत-यूरोपीय संघ आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया] : 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद]



भारत-अमेरिका के बीच 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद

यात्रा के दौरान, सचिव पोम्पेओ और सचिव एस्पर ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री से मिले। दो पूर्व सचिवों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ भी बैठक की। संवाद के समापन पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन /समझौते

रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय भू-स्थानिक-खुफिया एजेंसी, अमेरिकी रक्षा विभाग के बीच आधारभूत आदान-प्रदान और सहयोग समझौता।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के बीच पृथ्वी निरूपण और पृथ्वी विज्ञान में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।

वैश्विक नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी केंद्र, भारत के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन की अवधि का विस्तार।

डाक परिचालकों के बीच सीमा शुल्क आंकड़ों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान के लिए समझौता।

आयुर्वेद और कैसर अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के बीच आशय- पत्र।

मंत्रिस्तरीय बैठकें

भारत-अमेरिका के सीईओ फोरम का 14 जुलाई 2020 को, आभासी प्रारूप में आयोजन किया गया था। वर्चुअल फोरम के बाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, और पूर्व अमेरिकी वाणिज्य सचिव, विलबर रॉस ने टेलीफोन पर बातचीत की और पारस्परिक हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।

भारत-अमेरिका सामरिक ऊर्जा साझेदारी मंत्रिस्तरीय बैठक 17 जुलाई 2020 को, आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और पूर्व अमेरिकी ऊर्जा सचिव डैन ब्रोडलेट द्वारा की गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और अमेरिकी ऊर्जा विभाग के बीच को सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 02 जुलाई 2020, 26 अगस्त 2020 और 9 जनवरी 2021 को पूर्व अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट ई. लाइटज़र के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।

विदेश मंत्री ने अपने तत्कालीन समकक्ष सचिव पोम्पेओ के साथ नियमित टेलीफोन वार्ता के अलावा, टोक्यो में 06 अक्टूबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की द्वितीय बैठक के अवसर पर सचिव पोम्पेओ के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

अमेरिका के पूर्व उप-विदेश मंत्री स्टीफन बीगन ने विदेश सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक के लिए 12-14 अक्टूबर 2020 तक भारत का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की भी समीक्षा की। उप सचिव बीगन ईएएम और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिले। उन्होंने चौथे भारत-अमेरिका फोरम के उद्घाटन सत्र में 12 अक्टूबर 2020 को आभासी प्रारूप में भाग लिया।

विदेश सचिव ने 19 नवंबर 2020 को अमेरिका -भारत स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ) के बोर्ड के सदस्यों के साथ वर्चुअल बातचीत की। विदेश सचिव ने 7 जनवरी 2020 को तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री स्टीफन ई बीगन को विदाई देने के लिए टेलीफोन पर बातचीत की।

अन्य प्रमुख बैठकें

वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 16 से 19 अक्टूबर 2020 तक हवाई में अमेरिकी सेना के प्रशांत कमान का दौरा किया। अफगानिस्तान सुलह के लिए अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि, ज़ल्माय खिलज़ाद ने मई और सितंबर 2020 में भारत का दौरा किया और विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।

कोविड-19 महामारी से निपटने में सहयोग

भारत और अमेरिका एक दूसरे के देशों में भारतीय नागरिकों की निकासी की सुविधा के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, दवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रहे हैं, कोविड-19 प्रबंधन पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करते हैं और कोविड-19 का प्रतिकार करने के लिए चिकित्सा विज्ञान और टीके के विकास पर सहयोग का विस्तार किया है।

भारत ने फार्मास्यूटिकल्स (हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पेरासिटामोल और एपीआई), पीपीई, मास्क और अन्य आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के लिए अमेरिकी अनुरोध को स्वीकार किया। अमेरिकी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी एजेंसी के माध्यम से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को 200 वेंटिलेटर दान किए।

वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावासों ने अमेरिका से 325 से अधिक वंदे भारत मिशन उड़ानों के माध्यम से अक्टूबर -2020 के अंत तक अमेरिका में 80,000 से अधिक फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने की सुविधा प्रदान की। भारत के नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा अमेरिका सहित 24 देशों के लिए एक विशेष द्विपक्षीय यात्रा व्यवस्था (हवाई परिवहन बबल) की स्थापना की गई।

परामर्श / संवाद

कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, वर्चुअल प्रारूप में द्विपक्षीय संपर्क निरंतर जारी रहा।

रक्षा सहयोग: रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास, कार्मिक आदान-प्रदान और समुद्री सुरक्षा और काउंटर पायरेसी में सहयोग में गहनता के साथ रक्षा संबंधों ने अपने सकारात्मक कार्य जारी रखे। निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:

- 22 जुलाई 2020 को भारतीय रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ-आईडीईएक्स) और अमेरिकी रक्षा नवाचार इकाई के बीच उद्घाटन बैठक।
- भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की 10 वीं बैठक 15 सितंबर 2020 को वर्चुअल आयोजित की गई। इस बैठक में रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में चल रहे सहयोग की समीक्षा की गई।
- भारत-अमेरिका रक्षा साइबर संवाद की पहली बैठक 17 सितंबर 2020 को वर्चुअल रूप में आयोजित की गई।

सैन्य अभ्यास: भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के नौसेना बलों की भागीदारी से हिंद महासागर में दो चरणों में 3-6 नवंबर 2020 तथा 17-20 नवंबर 2020 को क्रमशः मालाबार नौ सैनिक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध: पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध सुदृढ़ बने रहे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (वस्तु एवं सेवाएं संयुक्त)। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 4.3% बढ़कर 148.8 अमेरिकी डालर तक पहुंच गया। वर्ष 2020 में अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 26.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

अमेरिका, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिका के अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में अमेरिका का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2018 के 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से 8%



मालाबार 2020 में भाग लेते हुए भारतीय नौ सेना के जेट विमान

बढ़कर वर्ष 2019 में 45.9 बिलियन अमरिकी डॉलर पहुँच गया। दोनों तरफ निवेश बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 16.7 बिलियन अमरिकी डॉलर का संचयी निवेश किया है और अमरीका में लगभग 125000 नौकरियों का सृजन किया है।

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा अमरीका पैटेंट और ट्रेड मार्क कार्यालय, वाणिज्य विभाग के बीच 2 दिसंबर 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष सहयोग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत-अमरीका सहयोग बहुआयामी है तथा अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षरित भारत-अमरीका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता जिसे सितंबर 2019 में दस वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था, के ढांचे के अंतर्गत सहयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक द्वि-राष्ट्रीय स्वायत्त संगठन भारत-अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम (आईयूएसएसटीएफ) इस क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के उपरांत, भारत एवं अमरीका दोनों सहयोग की ओर केन्द्रीत हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में। आईयूएसएसटीएफ ने 8 अनुसंधान केन्द्रों तथा 11 स्टार्ट-अप को वर्चुअल पुरस्कार प्रदान किए हैं। कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए कम से कम 4 भारतीय कंपनियां अमरीका स्थित एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही हैं, जो नैदानिक विकास और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

भारत और अमरीका का नागरिक अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का एक लंबा इतिहास है जिसमें पृथ्वी का निरूपण, उपग्रह नेवीगेशन, अंतरिक्ष प्रक्षेपण और अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में सहयोग, शामिल हैं। इसरो-एनएसए की जारी संयुक्त गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 28 सितंबर को वैज्ञानिक सचिव, भारतीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा थोमस जुरबुचीन, सहयोगी प्रशासक, अमेरिका राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन के बीच एक वर्चुअल बैठक आयोजित हुई।

इसरो और नासा पृथ्वी के निरूपण के लिए एक संयुक्त माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग उपग्रह को साकार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम नासा-इसरो सिंथेटिक अपरचर रडार (निसार) है। इस संयुक्त अभियान को 2022 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है। निसार संयुक्त संचालन की बैठक 18 अगस्त 2020 को वर्चुअल रूप से हुई थी।

इसके अतिरिक्त, भारत में वन्य जीव संरक्षण पर स्वास्थ्य प्रभाव के आकलन की समीक्षा में सहयोग पर नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा कॉर्नेल विश्वविद्यालय, न्यूयार्क के बीच दिनांक 5 नवंबर 2020

कनाडा

उच्च स्तरीय कार्यक्रम:प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो से 28 अप्रैल 2020 तथा 16 जून 2020 को टेलीफोन पर दो बार वार्ता की तथा

को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

भारतीय द्रुतावास तथा वाणिज्य द्रुतावासों ने ‘घर पर घर-घर से योग-योग’ विषय पर वर्चुअल रूप से दिनांक 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया। समस्त अमरीका से बड़ी संख्या में योग के प्रति उत्साही लोग योग दिवस के वर्चुअल समारोह में शामिल हुए।

गांधी@150

भारतीय द्रुतावास एवं वाणिज्य द्रुतावासों ने, महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के दो-वर्ष लंबे समारोह के भाग के रूप में महात्मा गाँधी के दर्शन, आदर्शों एवं शिक्षाओं को दर्शाते हुए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसका समापन 02 अक्टूबर 2020 को आयोजित स्मारण गाँधी@150 समारोह में हुआ।

विद्वता विनिमय पहल अधिनियम

अमरीका ने वर्ष 2020 में गांधी किंग विद्वता विनिमय पहल अधिनियम लागू किया है, जो गाँधी-किंग डवलपमेंट फाउंडेशन, एक ग्लोबल अकादमी तथा एक व्यावसायिक विनिमय कार्यक्रम जो महात्मा गाँधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साझा आदर्शों तथा मूल्यों को आगे बढ़ाने के क्रम में विद्वता विनिमय पहल के रूप में जाना जाता है, की स्थापना करेगा।

थिंक टैंक एक्सचेंज

भारत-अमरीका संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भारत एवं अमरीका में थिंक टैंक के बीच विचारों का जीवंत संपर्क और आदान प्रदान वर्चुअल रूप में जारी है। विदेश मंत्रालय ने, अनंत केन्द्र के सहयोग से दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को चौथी भारत-अमरीका संगोष्ठी का आयोजन वर्चुअल रूप से किया जो भारत-अमरीका संबंधों पर व्यापक चर्चा के लिए सरकार, राजनीति, थिंक-टैंक, उद्योग तथा मिडिया जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक साथ ला रहा है।

लोगों का लोगों से संपर्क

लोगों का लोगों से संपर्क भारत-अमरीका साझेदारी का एक महत्वपूर्ण घटक है। अमरीका में 4 मिलियन बहुसंख्य प्रवासी भारतीयों ने दोनों देशों के नजदीक आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय कुशल व्यवसायियों ने अमरीका की अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं विकास में योगदान दिया है तथा भारत-अमरीका सामरिक साझेदारी की वृद्धि एवं विकास में एक स्थायी आधार प्रदान किया है। वर्तमान में 200,000 से अधिक भारतीय छात्रों के अमरीका के संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकित होने के साथ अमरीका भारतीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान बना हुआ है।

क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने फेयरफेक्स फाइनेन्शियल होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा 08 अक्टूबर को आयोजित वर्चुअल इनवेस्ट इंडिया

2020 कॉन्फ्रेंस में स्वागत भाषण दिया।

विदेश मंत्री ने कनाडा के विदेश मंत्री फ्रेंकोइस-फिलिप शैम्पेन के साथ कोविड-19 महामारी प्रबंधन, फंसे हुए नागरिकों को निकालने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर नियमित रूप से बात की। कोविड-19 प्रतिक्रिया पर समन्वय के लिए 3 नवंबर 2020 को कनाडा के विदेश मंत्री द्वारा बुलाई गई विदेश मंत्रियों के मंत्री समूह की एक बैठक में विदेश मंत्री ने भाग लिया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कनाडा की लघु व्यवसाय, निर्यात संवर्धन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मेरी एनजी से उनके अवसरों पर चर्चा की तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं; औषधीय उत्पादों की उपलब्धता;जी-20 सहयोग तथा द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित मामलों के अनुरक्षण से संबंधित मुद्दों पर बात की।

वित्त, व्यापार तथा उद्योग

द्विपक्षीय व्यापार 01 अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक 2.17 बिलियन अमरिकी डॉलर का था। इस अवधि के दौरान भारत का कनाडा में निर्यात 1.006 बिलियन एवं कनाडा से भारत में आयात 1.174 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कनाडा की पेंशन निधि ने भारत में 50 बिलियन से अधिक अमेरिकी डॉलर निवेश करने का वादा किया है। भारत में 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां हैं और 1000 से अधिक कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से व्यापार कर रही हैं। भारत और कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) तथा द्विपक्षीय निवेश संवर्धन तथा संरक्षण समझौते (बीआईपीपीए) पर चर्चा कर रहे हैं। भारत तथा कनाडा के बीच सीईपीए तथा बीआईपीपीए पर वर्चुअल बैठकें दिनांक 22 जून 2020 और 27 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गईं।

भारत-कनाडा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने तथा भारत में कनाडा के निवेश को आकर्षित करने के क्रम में दोनों पक्षों से मंत्री स्तरीय भागीदारी के साथ अनेक सम्मेलनों एवं क्रेता-विक्रेताओं की बैठकों को कनाडाई तथा भारतीय व्यापारों के बीच उद्योग संघों तथा वाणिज्य मण्डलों के सहयोग से वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा प्राकृतिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान परिषद, कनाडा (एनएसईआरसी), कनाडा के बीच भारत-कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम के अंतर्गत, सुरक्षित और सतत आधारभूत संरचना, ऊर्जा संरक्षण और एकीकृत जल प्रबंधन के क्षेत्रों में 10 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। डीएसटी भी कनाडा के साथ औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें प्रयोज्यता की क्षमता है। आईसी-भारत-कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का वर्चुअल वार्षिक सम्मेलन 6-7 अगस्त 2020 से आयोजित किया गया था।

भारतीय जीवविज्ञान सर्वेक्षण और इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ कॉरपोरेशन कनाडा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर विभिन्न प्रजातियों के

डीएनए बारकोडिंग पर इन्वेंट्री बनाने और जैवविविधता की निगरानी करने के लिए 29 जून 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे।

भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने कनाडा के प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, डॉ. नेमेर के साथ 5 नवंबर 2020 को कोविड-19 सहयोग पर वर्चुअल बातचीत की थी।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान राष्ट्रीय केन्द्र तथा पोलर नॉलेज कनाडा द्वारा संचालित कनाडियन हाई आर्कटिक रिसर्च स्टेशन के बीच सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर 26 फरवरी 2020 को हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैवप्रौद्योगिकी, भारत तथा नेचुरल साइंसेस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन भी 2021 की पहली तिमाही में नवीकृत होना संभावित है।

शिक्षा

कनाडा में अध्ययनरत 230,000 भारतीय छात्रों के साथ भारत अब विदेशी छात्रों का शीर्ष स्रोत बन गया है। ग्लोबल इनिशीएटिव ऑफ अकेडमिक वर्क्स प्रोग्राम फॉर टीचिंग असाइमेन्ट्स इन इंडियन इंस्टिट्यूट्स के अंतर्गत अब तक 69 प्रतिष्ठित कनाडाई संकाय सदस्यों ने भारत का दौरा किया है। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लक्ष्य के लिए एक पहल के रूप में अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत शामिल किए गए 28 देशों में से एक कनाडा है। अब तक स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलोब्रेशन और 106 अंडर ग्लोबल इनिशीएटिव ऑफ अकेडमिक नेटवर्क्स के अंतर्गत 19 परियोजनाओं को कनाडा के संकायों को सौंपा गया है।

सुरक्षा सहयोग

आतंक्रोधी संयुक्त कार्यदल ने 26 अगस्त 2020 को भारत-कनाडा आतंकवाद रोधी कार्य योजना पर चर्चा की तथा दुनियाभर में और अपने-अपने देश में आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरों की समीक्षा की। उन्होंने आतंकवाद का सामना करने, हिंसक चरमपंथ और हिंसा के कट्टरपंथीकरण को रोकने के लिए किए गए कार्यों पर भी चर्चा की।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान

भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने शुभकामनाएं दीं। द हैलिफेक्स रिजनल काउंसिल, नोवा स्कोटिया ने अगस्त 2020 को भारतीय स्वतंत्रता माह घोषित किया।

बैशाखी, पुथांडू और नवरात्री त्यौहारों के अवसर पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने त्यौहार मनाने वाले लोगों को शुभकामनाएं दीं। अल्बर्टा और सस्केचेवान के प्रांतों ने माह अगस्त 2020 को "द हिंदू हेरिटेज मंथ" घोषित किया। भारतीय उच्चायोग द्वारा कनाडा में 3 दिवसीय ग्रेट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। 6ठें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 50 से अधिक वर्चुअल कार्यक्रमों के साथ मनाया गया।

भारत-कनाडा ट्रेक 1.5 संवाद

द्वितीय भारत-कनाडा ट्रेक 1.5 संवाद गेटवे हाउस, मुंबई और सेंटर फॉर इंटरनेशनल गवर्नेंस इन्वेस्टेशन, कनाडा के बीच 22 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था। भारत-कनाडा ट्रेक 1.5 संवाद की 3वीं बैठक 17 नवंबर 2020 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। विदेश मंत्री और कनाडा के विदेश मंत्री, फ्रेकोइस-फिलिप शैम्पेन ने वार्ता का उद्घाटन किया।

कोविड-19 के दौरान परस्पर सहयोग

भारत सरकार ने कनाडा के लिए पैरासिटामोल टेबलेट, हाईड्रोओक्सीक्लोरोक्वीन टेबलेट, हाईड्रोओक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट यूएसपी (एपीआई) तथा पीपीई किटों के निर्यात की अनुमति दी। भारत में फंसे हुए कनाडा के नागरिकों को

निकालने के लिए भारत ने कनाडा उच्च आयोग द्वारा संचालित विशेष चार्टर उड़ानों को सुविधा प्रदान की है। एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत, एयर कनाडा ने 51 उड़ाने संचालित की हैं। मई 2020 से, वंदे भारत मिशन की कनाडा से भारत में 24107 यात्रियों (06 नवंबर 2020 तक) को निकालने वाली 142 उड़ानें संचालित हुई हैं।

भारत का इस क्षेत्र में देशों के साथ लंबे समय से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध जीवंत और गतिशील भारतीय प्रवासीयों जिनकी संख्या कैरिबियन क्षेत्र में एक मिलियन से अधिक थी के द्वारा प्रबलित होता रहा। भारत और एलएसीदेशों ने अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय मंचों में एक-दूसरे के साथ सहयोग जारी रखा।

अर्जेंटीना

अर्जेंटीना के साथ भारत के द्विपक्षीय सहयोग को कई द्विपक्षीय वार्ता तंतों के साथ-साथ जी -20, डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से बातचीत में हुई बढ़ोत्तरी द्वारा चिह्नित किया गया था। 05 मई 2020 को, विदेश मंत्री ने फेलिप सोला, अर्जेंटीना के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्षिक मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कोरोनावायरस स्थिति, आर्थिक सुधार, बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। अर्जेंटीना में नई सरकार के साथ यह पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी। 10 सितंबर 2019 को, 5 वीं भारत-अर्जेंटीना विदेश कार्यालय परामर्श वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए गए, जिसका नेतृत्व भारतीय पक्ष में सचिव (पूर्व) और अर्जेंटीना की ओर से उप विदेश मंत्री ने किया। दोनों पक्षों ने सामरिक साझेदारी के ढांचे के भीतर द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण सरगम की समीक्षा कोविड-19 महामारी के दौरान अनुभवों के साथ-साथ सामान्य हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और बहुपक्षीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

जनवरी-जून 2020 से, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि का रूझान 22.74% की वृद्धि के साथ जारी रहा (विशेष रूप से, अर्जेंटीना के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2019-2020 में 3.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड आंकड़े पर पहुंच गया)। इस अवधि के दौरान द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 1.57 बिलियन अमरीकी डॉलर था (भारतीय निर्यात का मूल्य 401 मिलियन अमरीकी डॉलर और भारतीय आयातों का मूल्य 1.17 बिलियन अमरीकी डॉलर था)। भारत और अर्जेंटीना के बीच संयुक्त व्यापार समिति की तीसरी बैठक 20 अक्टूबर 2020 को लगभग तीन दशकों के अंतराल के बाद वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग की व्यापक समीक्षा की और आगे की कार्रवाई पर चर्चा की। कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 01 जुलाई 2020 को वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी जिसमें दोनों पक्षों के हित के साथ-साथ कार्य योजनाओं (2019 में हस्ताक्षरित) के कार्यान्वयन के लिए पारस्परिक बाजार पहुंच प्रदान करने पर चर्चा की गई थी।

मार्च 2020 में अर्जेंटीना एक संस्थापक सदस्य के रूप में कोएलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) में शामिल हो गया।

खनन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धी में, केएबीआईएल (खान मंत्रालय के अंतर्गत पीएसयू) और अर्जेंटीना की दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों यथा वाईपीएफ (अर्जेंटीना राज्य ऊर्जा कंपनी) और जीईएमएसई (जुजुय प्रांत का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के बीच समझौता ज्ञापनों पर 10 जुलाई 2020 और 10 सितंबर 2020 क्रमशा: हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापनों ने लिथियम की खोज, पहचान और दोहन के साथ-साथ परियोजनाओं के संयुक्त विकास के लिए संस्थागत सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की।

दोनों देशों ने कोविड -19 महामारी के परिपेक्ष्य में भी सहयोग किया। भारत ने अर्जेंटीना को छूट दी, भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन और पैरासिटामोल के निर्यात की अनुमति दी। अर्जेंटीना ने भारत को वेंटिलेटर के निर्यात के लिए छूट दी।

14 अक्टूबर 2020 को, एक द्विपक्षीय व्यापार मण्डल, ‘भारत-अर्जेंटीना व्यापार परिषद’ को औपचारिक रूप से भारत के राजद्रुत और अर्जेंटीना के उत्पादक विकास मंत्री मतिस कुल्फस द्वारा शुरू किया गया था। परिषद की एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में अवधारणा है, जिसमें अर्जेंटीना में स्थित प्रमुख भारतीय कंपनियां और अर्जेंटीना की कंपनियों जिनकी भारत में व्यावसायिक रुचि है, शामिल हैं।

अर्जेंटीना के विदेश मंत्री फेलिप सोला ने भी महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाग लिया। भारतीय दूतावास ने “योग एट होम” के नारे के अंतर्गत विशेष रूप से बनाई गई वेबसाइट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एक आभासी स्मरणोत्सव आयोजित किया। अर्जेंटीना की कई शीर्ष हस्तियों ने भी संसरोध के समय में अपने अनुभव और योग के लाभ को साझा किया और वेबसाइट को लगभग 40,000 आगंतुक मिले।

ब्यूनस आयर्स में भारत के दूतावास ने तीन देशों, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से कई वीडियो सम्मेलनों का आयोजन, समन्वय और भागीदारी की। इनमें भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा “भारत और विश्व” संगोष्ठी; इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर काउंसिल ऑफ इंडिया और सीईएसएसआई (अर्जेन्टाइनचैंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स)

के बीच क्रेता-विक्रेता की बैठक; पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा संगोष्ठी का शीर्षक “भारत-अर्जेंटीना व्यापार संवर्धन, चुनौतियां और अवसर - पोस्ट कोविड -19”; भारत-अर्जेंटीना वाणिज्यिक संबंधों पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (एफआईईओ) द्वारा वेबिनार; “भारत अर्जेंन्टीना व्यापार संबंधों का भविष्य” पर फिक्की द्वारा एलएसी क्षेत्रीय परिषद सत्र; आभासी परिधान; और भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि सहयोग पर यूपीएल अर्जेंटीना द्वारा आयोजित वेबिनार शामिल हैं।

विदेश मंत्री और अर्जेंटीना के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वार्षिक, मंत्रीफेलिप सोला ने नई विश्व व्यवस्था में भारत और अर्जेंटीना के समापन सत्र में टिप्पणी दी: भारतीय और अर्जेंटीना के थिंक टैंकों के बीच संवाद को विकासशील देशों के अनुसंधान और सूचना प्रणाली के लिए सह-आयोजित किया गया तथा 06 नवंबर 2020 को सेंटर फॉर इप्लीमेन्टेशन ऑफ पब्लिक

बोलिविया

बोलिविया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध उच्च स्तरीय बातचीत और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग के साथ मजबूत होते रहे। अक्टूबर 2020 में हुए आम चुनावों में जीत के बाद मूवमेंट फॉर सोशलिज्म (एमएएस) की लुइस एर्स के नेतृत्व वाली नई सरकार सत्ता में आई।

बोलीविया में भारत के निर्यात में 2019-20 में 9.39% की वृद्धि देखी गई और इसकी कीमत 113.4 मिलियन अमरीकी डॉलर थी (959.35 मिलियन अमरीकी डालर के कुल व्यापार में से।) भारत बोलीविया के लिए दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा।

विकास साझेदारी के क्षेत्र में मजबूत सहयोग था। भारत ने कोविड -19 महामारी परिस्थिति में 300,000 एचसीक्यू टैबलेट, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित बोलीविया को एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा। महामारी के दौरान संक्रमण की रोकथाम, नीतिगत विकास और अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए तथा कोविड-19 महामारी का प्रबंधन करने के

ब्राज़िल

भारत और ब्राजील ने बहुस्तरीय मंचों जैसे ब्रिक्स, बेसिक, जी -20, जी -4, आईबीएसए, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में निरंतर उच्च स्तरीय सहभागिता और सहयोग के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को गहरा किया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने 04 अप्रैल 2020 को टेलीफोन पर चर्चा की जिसमें उन्होंने कोविड -19 महामारी की वैश्विक स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति बोल्सनारो के अनुरोध पर, भारत ने ब्राज़ील को छूट दी और भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के आयात की अनुमति दी। राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने 08 अप्रैल 2020 को अपने राष्ट्रीय संबोधन में प्रधानमंत्री और भारत के लोगों को इस सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। भारत ने जनवरी 2021 में 2 मिलियन कोविशिल्ड टीके ब्राजील भेजे।

23 अप्रैल 2020 को, विदेश मंत्रीने ब्राज़ील के विदेश मंत्री अर्नेस्टो अराज़ो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने जनवरी 2020 में राष्ट्रपति

पॉलिसीज फॉर इक्विटी एण्ड ग्रोथ आयोजित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 20 नवंबर 2020 को अपने अर्जेंटीना के समकक्ष लुइस बेस्टर के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया और अर्जेंन्टीन में भारतीय कृषि निर्यात को बढ़ाने और कृषि अनुसंधान में सहयोग की संभवानाओं के लिए चर्चा की। आउटर स्पेस में सहयोग पर भारत-अर्जेंटीना संयुक्त समिति की दूसरी बैठक वर्चुअल रूप से 02 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और अर्जेंटीना राष्ट्रीय अंतरिक्ष गतिविधि आयोग के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित की गई थी। CAMYEN, कैटामार्का, अर्जेंटीना प्रांत का एक सार्वजनिक उपक्रम और काबिल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर लिथियम पर केन्द्रित खनन के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिसंबर 2020 में हस्ताक्षरित किया गया था।

लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर विशेष पाठ्यक्रमों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत भारत द्वारा प्रस्तावित विशेष पाठ्यक्रमों में 2 बोलिवियन विशेषज्ञों ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूपनडीपी), भारत सरकार और बोलिविया के विकास योजना मंत्रालय के बीच 02 फरवरी 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बोलीविया के योग चिकित्सकों ने जून 2020 में 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। बोलीविया में भारतीय समुदाय की भागीदारी के साथ संविधान दिवस 26 नवंबर 2020 को ऑनलाइन मनाया गया। इसमें वार्ता और भारत के संविधान के महत्व पर प्रकाश डालने वाली फिल्में की स्क्रीनिंग शामिल थी। इसने साल भर की गतिविधियों के निष्कर्ष और “मेरे कर्तव्य” अभियान को चिह्नित किया जो कि संविधान और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से थे।

बोल्सनारो की इस देश की यात्रा के लिए आगे की कार्यवाही में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की और कोरोनावायरस महामारी सहित वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। बहुपक्षीय ढांचे जैसे ब्रिक्स (04 सितंबर 2020), आईबीएसए (17 सितंबर 2020), जी4 (23 सितंबर 2020) और 4 नवंबर 2020 को चुनिंदा सात देशों के विदेश मंत्रियों के साथ विदेश मंत्रीकी बातचीत के अंतर्गतवार्ता भी आयोजित की गई थी। 25 मई 2020 को रक्षा उद्योग साझेदारी में सहयोग के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और ब्राजीलियन एसोसिएशन ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी मटीरियल्स इंडस्ट्रीज के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक विकास पर एफएम अराजू के साथ वर्चुअल रूप से द्विपक्षीय चर्चा की। दोनों पक्ष ब्रिक्स और आईबीएसएसहित बहुपक्षीय मंचों में निकटता से काम करने के लिए सहमत हुए।

22 फरवरी 2021 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा एक ब्राजीलियाई उपग्रह अमोजोनिया-आई लॉन्च किया जाना है। ब्राजील के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मार्कोस पोंट्स ने उपग्रह के प्रक्षेपण का साक्षी बनने के लिए भारत का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की है। ब्राजील के खान एवं ऊर्जा मंत्री बेंटो अल्बुकर्क ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित तीसरी ग्लोबल री-इनवेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो को वर्चुअल रूप से 28 नवंबर 2020 को संबोधित किया। भारत के दूतावास, ब्रासीलिया ने भारत और ब्राजील की निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण कंपनियों के बीच व्यावसायिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 8 दिसंबर 2020 को “भारत और ब्राजील के बीच सुरक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। मिशन ने भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों और भारत

के डेटा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा में सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन किया है। इस पहल के अंतर्गत, 19 नवंबर 2020 को पहले वेबिनार में ब्राजील की राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों और ब्राजील में सक्रिय भारतीय आईटी कंपनियों के प्रमुखों ने भाग लिया। दूसरा वेबिनार 14 दिसंबर 2020 को न्याय तथा सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय ब्राजील और भारतीय आईटी कंपनियों के बीच आयोजित किया गया था। फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से मिशन ने “भारत-ब्राजील: फार्मास्युटिकल क्षेत्र में मजबूत साझेदारी” नामक एक वेबिनार का आयोजन किया और 26-27 नवंबर, 2020 को भारतीय और ब्राजील की कंपनियों के बीच बायर-सेलर-मीट का आयोजन किया जिसमें 102 भारतीय और 46 ब्राजील की कंपनियों ने भाग लिया।

चिली

भारत और चिली के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार बढ़ रहे हैं और बहुपक्षीय मंचों में निरंतर वार्ता और सहयोग के साथ मजबूत होते रहे हैं। 16 अक्टूबर 2020 को विदेश मंत्री और आंद्रेस अलामंड, चिली के विदेश मंत्री के साथ सह-अध्यक्ष के रूप में वर्चुअल मोड में पहली भारत-चिली संयुक्त आयोग की बैठक हुई। मुंबई में चिली द्वारा एक वाणिज्य दूतावास खोलने के प्रस्ताव को भारत की स्वीकृति के साथ द्विपक्षीय संबंधों में एक नया आयाम जोड़ा गया।

चिली द्वारा लार्सन एंड टुब्रो से एक नौसैनिक जहाज की खरीद ने दोनों देशों के बीच सहयोग का एक और अवसर प्रशस्त किया। गांधी फिल्म फेस्टिवल और फेस्टिवल ऑफ इंडियन पैट्रियोटिक फिल्मस की वर्चुअल स्क्रीनिंग, के साथ-

साथ ही भारतीय दूतावास के यूट्यूब चैनल पर ऋग्वेद पर स्पेनिश में स्थानीय रूप से निर्मित वीडियो की एक श्रृंखला का शुभारंभ द्विपक्षीय सांस्कृतिक सहयोग में मुख्य आकर्षण थे।

मार्च 2021 तक प्रत्याशित कार्यक्रमों में भारत और चिली के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के 7 वें दौर में शामिल होना, भारत-चिली अधिमन्य व्यापार समझौते के दूसरे विस्तार पर एक समझौते पर पहुंचना, और लुइस बेट्स, अधिवक्ता और चिली के पूर्व न्याय मंत्री द्वारा गांधीज कैरियर एज ए लॉयर एण्ड हाव देट एफेक्टेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ नामक एक पुस्तक का विमोचन, हैं।

कोलंबिया

कोलंबिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध अच्छे और सौहार्दपूर्ण रहे। 29 अप्रैल 2020 को, विदेश मंत्री ने कोलंबिया के विदेश मंत्री क्लाउडिया ब्लम डी बारबेरी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और व्यापार और ऊर्जा विकास साझेदारी के साथ-साथ महामारी के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की समीक्षा की। भारत और कोलंबिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने इस अवधि के दौरान एक स्थिर मार्ग बनाए रखा और अप्रैल-अगस्त 2020 की अवधि में इसका मूल्य 710 मिलियन अमरीकी डालर का मूल्य था।

विकास साझेदारी के अंतर्गत, कोविड प्रबंधन रणनीतियों पर ई-आईटीईसी कार्यक्रमों में कोलंबिया के स्वास्थ्य पेशेवरों ने भाग लिया। कोविड -19 महामारी के दौरान, भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन और पेरासिटामोल के निर्यात की अनुमति देने के लिए भारत ने कोलंबिया को छूट दी।

जनवरी 2021 में, भारत - कोलंबिया संयुक्त व्यापार विकास सहयोग समिति के चौथे दौर का आयोजन हुआ। पारस्परिक बाजार पहुंच, एक आंशिक गुंजाइश व्यापार समझौते सहित उदासीन व्यापार शासन, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य और दवा, सूचना प्रौद्योगिकी सहित अन्य के लिए वार्ता विषयों पर चर्चा हुई। 27 नवंबर 2020 को, कोलंबिया के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में भारतीय निवेश पर एक वर्चुअल राउंड टेबल का आयोजन दूतावास के सहयोग से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और प्रो कोलंबिया (कोलंबिया में एक संगठन जो कोलंबिया में आंक निवेश का समर्थन करता है) द्वारा किया गया था। बोगोटा में भारत के दूतावास ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और कोलंबिया के बाहर स्थित भारतीय और कोलंबिया आईटी कंपनियों के लगभग 76 प्रतिनिधियों ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया।

क्यूबा

भारत और क्यूबा ने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। 2020 में, दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60 वीं वर्षगांठ मनाई। विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत ने क्यूबा को एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा,

जिसमें 300,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत के विभिन्न

संस्थानों में पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले क्यूबा के 10 नागरिकों की वापसी को भी सुकर बनाया।

दिनांक 13 नवंबर 2020 को धन्वंतरि दिवस पर आयुर्वेद दिवस के साथ हवाना में ला प्रेरा में आयुर्वेद केंद्र की पहली वर्षगांठ मनाई गई। मिशन ने 12

इक्वेडोर

भारत और इक्वेडोर ने अपने मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखा। 12 अक्टूबर को विदेश मंत्री ने इक्वेडोर के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और स्वास्थ्य, व्यापार और विकास साझेदारी में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ कौंसुली मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग में प्रगति हुई थी, और दिनांक 12 अगस्त 2020

मेक्सिको

भारत और मेक्सिको के बीच 2020 में द्विपक्षीय संबंध निरंतर रूप से मजबूत हुए हैं, जिसने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70 वीं वर्षगांठ मनाई गई। विदेश मंत्री और मेक्सिको के विदेश मंत्री मार्सेलो एबराड कसुबोन की सह-अध्यक्षता में 8 वीं संयुक्त आयोग की बैठक 29 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में संपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और वाणिज्य, अंतरिक्ष, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और फार्मास्युटिकल्स, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने मई 2020 और अगस्त 2020 में मेक्सिको के विदेश मामलों के सचिव मार्सेलो एबराड से बात की, जिसमें कोविड-19 महामारी और आर्थिक सुधार और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग पर चर्चा हुई। वर्ष 2020 में, भारत और मेक्सिको ने 2021-2022 में अपने साझा कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपसी प्राथमिकताओं पर एक सक्रिय बातचीत भी शुरू की।

भारत विश्व स्तर पर मेक्सिको का 9 वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना

नवंबर 2020 को क्यूबा सरकार द्वारा आयोजित एक समारोह में प्रथम उप मंत्री एना तेरसिता गोंजाज़ फ्रेगा को भारत की ओर से दवा और सुरक्षात्मक उपकरण सौंपे।

को भारत, गगनयान के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और इक्वेडोर के भौगोलिक सैन्य संस्थान के बीच चर्चा हुई। भारत ने इक्वेडोर को 400,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण और सुरक्षात्मक उपकरण सहित एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा।

रहा। अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 1.98 बिलियन अमरीकी डॉलर था। व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर भारत-मेक्सिको द्विपक्षीय उच्च स्तरीय समूह की 5 वीं बैठक 09 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के वाणिज्य सचिव और मेक्सिको के विदेश व्यापार मंत्री लूज मारिया डे ला मोरा ने की। व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के उपायों और आपसी हित के लिए कृषि उत्पादों हेतु बाजार में पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और मेक्सिको के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जैसे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद और मेक्सिकन चैंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्यूनिकेशन एंड इंफोरमेशन टेक्नोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मेक्सिकन विदेश व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



भारत-मेक्सिको 8 वीं संयुक्त आयोग की बैठक 29 अक्टूबर 2020 को आयोजित की गई

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

पैराग्वे

कोविड -19 महामारी के दौरान, भारत ने अपने देश से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात की अनुमति देने के लिए मैक्सिको को छूट प्रदान की।

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद 12 नवंबर, 2020 को आयोजित किया गया था, जिसके दौरान दोनों पक्षों के लिए विचारार्थ कौंसुली मुद्दों पर चर्चा की गई। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडिया मेक्सिको बिजनेस चैंबर ने 14 दिसंबर 2020 को सिरेमिक पर एक वर्चुअल बायर-सेलर मीट का आयोजन किया। मेक्सिको के विदेश व्यापार उप मंत्री ने 15-18 दिसंबर 2020 से आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन

पेरू

भारत और पेरू ने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। दिनांक 28 अप्रैल 2020 को, विदेश मंत्री ने गुस्तावो मेजा-कुआड़ा, (तत्कालीन) पेरू के विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 महामारी और विकास साझेदारी पर जानकारी का आदान-प्रदान किया। भारत ने पेरू को 900,000 हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण और सुरक्षात्मक उपकरण सहित एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा। पेरू ने कोयलेशन फॉर डिसिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) की सदस्यता लेने के अपने निर्णय से औपचारिक रूप से अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के अंतर्गत 08 सितंबर 2020 को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, पेरू के ऊर्जा और खान मंत्री ने इसमें भाग लिया और “ऊर्जा क्षे्र से परे सौर” नामक एक सत्र को संबोधित किया।

उरुग्वे

भारत ने उरुग्वे के साथ अपने निकट द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखा है। विदेस मंत्री ने 29 अप्रैल 2020 को, उरुग्वे के विदेश मंत्री अर्नेस्टो तलावी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न दोनों देशों की स्थिति के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान किया और आर्थिक सहयोग की संभावनाओं को तलाशा।

अर्जेंटीना में भारतीय राजदूत ने लैटिन अमेरिकी एकीकरण संघ द्वारा 21 जुलाई

वेनेजुएला

वेनेजुएला के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। अप्रैल-अगस्त 2020 तक द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 382.21 मिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत से अधिकांश निर्यात खनिज ईंधन और फार्मास्यूटिकल्स में होता है। वेनेजुएला को निर्यात की जाने वाली चाय की माला में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अप्रैल-अगस्त 2020 की अवधि में इसकी कीमत 120,000 अमरीकी डॉलर (12,000 किलोग्राम) है।

विकास साझेदारी के अंतर्गत, भारत ने वेनेजुएला को 740,000

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

पैराग्वे

काउंसिल ने वाणिज्य और उद्योग विभाग की मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना के अंतर्गत मैक्सिकन खरीदारों के साथ भारतीय निर्यातकों के लिए 17-18 मार्च 2021 से 2-दिवसीय वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की।

भारत और पैराग्वे के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत होते रहे। दिनांक 30 अप्रैल 2020 को, विदेश मंत्री ने कोरोना वायरस की स्थिति और आर्थिक सुधार पर पैराग्वे के विदेश मामलों के मंत्री एंटोनियो रिवास पलासियोस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। विकास साझेदारी के अंतर्गत, भारत ने पैराग्वे को 200,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सहित चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा।

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

भारत-पेरू न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक 7 दिसंबर 2020 को ऑनलाइन पद्यति के माध्यम से आयोजित की गई। इसरो और कोनिडा (नेशनल कमीशन ऑन एयरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट) के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर भारत-पेरू संस्थागत ढांचे के एक भाग के रूप में, 9 नवंबर 2020 को कोनिडा द्वारा एक वेबिनार आयोजित किया गया। फार्मास्यूटिकल क्षे्र पर फोकस करते हुए तेलंगाना सरकार, तेलंगाना चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड लोकल चैंबर के सहयोग से 26 नवंबर 2020 को राज्य-सुविधा वेबिनार भी आयोजित किया गया। 9 पेरू नागरिकों ने बुद्ध की शिक्षा, विपश्यना और अनुसंधान और मानसिक स्वास्थ्य में इसके प्रयोग पर प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

2020 को उरुग्वे में “इंडिया एट द इंटरनेशनल कॉन्सर्ट एंड इट्स रिलेशंस विद लैटिन अमेरिका: कमर्शियल, इकोनॉमिक चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज” पर आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। (एएलएडीआई 13 सदस्य देशों अर्थात अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, इक्वाडोर, मैक्सिको, पैराग्वे, पनामा, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला का सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी एकीकरण समूह है, जिसका मुख्यालय मोंटेवीडियो, उरुग्वे में है।

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सहित चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा।

फिक्की के सहयोग से भारतीय और वेनेजुएला की फार्मास्युटिकल कंपनियों के साथ एक वर्चुअल फार्मास्युटिकल बी 2 बी/जी 2 बी 09 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। वेनेजुएला के 2 अभ्यर्थियों ने आईटीईसी के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में भाग लिया। वेनेजुएला के 1 छात्र ने आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पीएचडी पाठ्यक्रम में भाग लिया।

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

बेलेीज़

भारत और बेलीज के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बनाए रखे हैं। अप्रैल-अगस्त 2020 के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 3.02 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें 2.74 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात हुआ और 0.28 मिलियन अमरीकी डालर का आयात हुआ।

विकास साझेदारी के अंतर्गत, भारत ने मार्च 2020 में बेलीज विश्वविद्यालय के

कोस्टा रिका

भारत और कोस्टा रिका ने मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखा है। विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत ने कोस्टा रिका को 140,000 हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियां, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सहित एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा। कोस्टा रिका के 3 अभ्यर्थियों ने ई-आईटीईसी कोविड प्रबंधन और हेपाटोलॉजी पाठ्यक्रमों में भाग लिया। मार्च 2020 में, राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा की आवश्यकता से छूट पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञान पर हस्ताक्षर किए

अल साल्वाडोर

ईएल सल्वाडोर के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध निरंतर रूप से बढ़ रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में 7% की संचयी वृद्धि देखी गई और 2019-20 में इसका मूल्य 82.55 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन था। भारत ने अल सल्वाडोर को 200,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सहित एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा।

भारत की आशावारी का समर्थन करने के लिए अल साल्वाडोर के साथ

ग्वाटेमाला

भारत ने ग्वाटेमाला के साथ करीबी द्विपक्षीय संबंध बनाए रखे हैं। विदेश मंत्रालय ने ग्वाटेमाला के विदेश मंत्री पेड्रो ब्रो विला के साथ दिनांक 30 अप्रैल 2020 को टेलीफोन पर बातचीत की और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग पर विस्तार से चर्चा की।

ग्वाटेमाला के साथ भारत के व्यापार में पिछले 3 वर्षों में 8% की संचयी वृद्धि देखी गई, जिसमें भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन था। विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत ने 500,000 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों सहित ग्वाटेमाला को एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा। भारत और ग्वाटेमाला बहुपक्षीय मंचों में सहयोग करते रहे हैं, जिसमें आशावारी के लिए समर्थन भी शामिल था।

अमेरिका

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

पैराग्वे

कोविड -19 महामारी के दौरान, भारत ने अपने देश से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात की अनुमति देने के लिए मैक्सिको को छूट प्रदान की।

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद 12 नवंबर, 2020 को आयोजित किया गया था, जिसके दौरान दोनों पक्षों के लिए विचारार्थ कौंसुली मुद्दों पर चर्चा की गई। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडिया मेक्सिको बिजनेस चैंबर ने 14 दिसंबर 2020 को सिरेमिक पर एक वर्चुअल बायर-सेलर मीट का आयोजन किया। मेक्सिको के विदेश व्यापार उप मंत्री ने 15-18 दिसंबर 2020 से आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट में एक वक्ता के रूप में भाग लिया। बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन

पेरू

भारत और पेरू ने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे हैं। दिनांक 28 अप्रैल 2020 को, विदेश मंत्री ने गुस्तावो सेगुरा, कोस्टा रिका के उप विदेश मंत्री एड्रियाना बोलानोस अर्गेटा ने दिनांक 9 दिसंबर 2020 को भारत और कोस्टा रिका के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसर सृजित करने के लिए भारत के दूतावास द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया।

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

बहुपक्षीय मंचों में भी काफी सहयोग रहा जैसे 2021-22 के लिए यूपनएससी की गैर-स्थायी सीट और प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति।

एल साल्वाडोर के कई प्रमुख खरीदारों ने एग्रो मशीनरी, ऑटो के पुर्जों, औद्योगिक बॉयलर, चिकित्सा उपकरण, और बिजली के उपकरणों सहित भारत के अत्याधुनिक इंजीनियरिंग उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन के सहयोग से भारतीय दूतावास द्वारा 20 नवंबर 2020 को आयोजित क्रेता-विक्रेता बैठक में भाग लिया।

भारत और मैक्सिको के बीच दुसरा कौंसुली संवाद

दिनांक 20 नवंबर 2020 को, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से भारतीय दूतावास ने भारत के अत्याधुनिक इंजीनियरिंग उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एक क्रेता-विक्रेता-बैठक का आयोजन किया, जिसमें कृषि मशीनरी, ऑटो उपकरण, औद्योगिक बॉयलर, चिकित्सा उपकरण, और बिजली के अनुप्रयोग शामिल हैं। इसमें भारत की 20 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया और अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। मध्य अमेरिका से ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर और होंडुरास के 75 से अधिक खरीदारों ने भाग लिया।

मिशन ने दिनांक 04 नवंबर 2020 को, ग्वाटेमाला की फिनटेक एसोसिएशन के साथ मिलकर भारतीय आईटी और फिनटेक इंडस्ट्री की सफलता पर एक वेबिनार का आयोजन किया।

निकारागुआ

निकारागुआ के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। विदेश मंत्री ने 05 जून 2020 को, डेनिस रोनाल्डो मोनकाडा कोलिंद्रेस के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और स्वास्थ्य, ऊर्जा और निवेश और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

अप्रैल-अगस्त 2020 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 32.86 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें भारत का निर्यात 30.30 मिलियन अमरीकी डालर था और इस अवधि में आयात 2.56 मिलियन अमरीकी डालर था। विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत ने निकारागुआ को 170,000 हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण

पनामा

भारत ने पनामा के साथ मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बनाए रखे हैं। विदेश मंत्री ने 28 अप्रैल 2020 को पनामा के विदेश मंत्री एलेजांद्रो गुइलेर्मो फेरर लोपेज़ के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें कोविड -19 महामारी से लड़ने में भारत की मदद का आश्वासन दिया। अप्रैल-अगस्त 2020 में पनामा के साथ द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 66.16 मिलियन अमरीकी डॉलर था, जिसमें भारत का निर्यात 46.53 मिलियन अमरीकी डालर और आयात 19.63 मिलियन अमरीकी डालर था।

विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत ने पनामा को 1,10,000 हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन की गोलियाँ, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सहित एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा।

कैरेबियाई देश

एंटीगा और बरबूडा

भारत तथा एंटीगा एवं बरबूडा ने अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को गर्मजोशी से साझा करना जारी रखा है। 5 जून, 2020 को, ईएएम ने एंटीगा और बरबूडा के विदेश मंत्री, ई.पी. ग्रीने के साथ टेलीफोन पर बातचीत और कोविड के बाद आर्थिक बहाली के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य क्षमता निर्माण में सहयोग पर बातचीत की।

विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गतभारत ने एंटीगा तथा बरबूडा को 10,000

बाहामास

बाहामास के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधो का जोशपूर्ण व मैत्रीपूर्ण रहना जारी है। 27 अक्टूबर, 2020 को ईएएम ने बाहामास के विदेश मंत्री, हुसैन हेनफील्ड के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कोविड-19 के संदर्भ में साझेदारी, सहयोग के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र एवं राष्ट्र मंडल विषयो पर विचार-विमर्श किया। विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने बाहामास को

सहित एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा। 17 निकारागुओं ने विभिन्न आईटीईसी पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

फरवरी 2020 में, भारत सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में वर्तमान 3 ऋण सहायता के अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्र में 20.10 मिलियन अमरीकी डालर और 7.35 मिलियन अमरीकी डालर की दो नई ऋण सहायता प्रदान की।

निकारागुआ ने 22 जुलाई 2020 को आईएसए कार्यढ़ांचे समझौते पर हस्ताक्षर किए और 28 सितंबर 2020 को इसकी पुष्टि की।

पनामनियन चैम्बर्स ऑफ टेक्नोलॉजीज, इन्फॉर्मेशन, इनोवेशन एंड टेलीकम्यूनिकेशन के सहयोग से भारत के आईटी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों और पनामनियन कंपनियों के बीच 24 नवंबर 2020 को वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। मुंबई में ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के अंतर्गत पनामा के पर्यावरण मंत्रालय के साथ इसी तरह की परियोजना की तर्ज पर तोकुमेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पनामा मेट्रो स्टेशनों में प्लास्टिक की बोतलों की रीसाइक्लिंग परियोजना के कार्यान्वयन में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 9 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में रीसाइक्लिंग क्षेत्र में काम करने वाली कई भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

हाइड्रोक्लोरोक्यू टैबलेटों, आवश्यक दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों सहित चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा। यूएनएससी (2020-21) तथा एसीएबीक्यू में एक गैर-स्थायी सीट की भारत की आशावारी के लिए उपना सहयोग पदान करने में एंटीगा और बरबूडा के साथ बहुपक्षीय बाज़ार के सहयोग में दृढ सहयोग था।

20,000 एचसीक्यू टैबलेटों, आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सीय उपकरणों सहित चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा।

बारबाडोस

भारत तथा बारबाडोस द्वारा घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों तथा यूएन, राष्ट्र मंडल एवं एनएएम में वृहद सहयोग का लुप्त उठाना जारी है। 05 जून, 2020 को, ईएएम ने कोविड-19 के संदर्भ में जेरोम वालकोट, विदेश मंत्री, विदेश व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के साथ फोन पर बातचीत की।

डोमिनियाई गणराज्य

भारत द्वारा डामिनिका गणराज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का लुप्त उठाया जाना जारी है। 30 अप्रैल, 2020

को ईएएम ने कैन्नेथ, डैरैक्स, विदेश मंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और सूत में सहयोग तथा दूरस्थ शिक्षा पर चर्चा की। विकास साझेदारी

डोमिनियाई गणराज्य

डोमिनियाई गणराज्य के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों का मैत्रीपूर्ण व जोशपूर्ण रहना जारी है। दोनों देशों को बहुपक्षीय मंचो पर मजबूत सहयोग जारी है।

कोविड-19 महामारी के संदर्भ में डोमिनियाई गणराज्य भारत से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने वाला पहला देश था एचसीक्यू एवं अन्य दवाइयो की पहली खेप अप्रैल 2020 में डिलीवर हुई थी। आवश्यक दवाइयों एवं सुरक्षात्मक गेयटों की दूसरी खेप जुलाई 2020 में डिलीवर हुई थी। चिकित्सा सहायता की औपचारिक सुपुदर्गी, डेमिनियाई गणराज्य द्वारा आयोजित

ग्रेनाडा

भारत और ग्रेनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधो का मैत्रीपूर्ण व जोशपूर्ण रहना जारी है। 29 अप्रैल, 2020 को विदेश मंत्री ने ग्रेनाडा के विदेश मंत्री पीटर डेविड के साथ टेलीफोन पर बातचीत की तथा स्वास्थ्य एवं विकास साझेदारी में सहयोग पर विचार विमर्श किया।

विकास साझेदारी के अंतर्गत भारत ने ग्रेनाडा को 10,000 एचसीक्यू टैबलेटों,

गयाना

भारत तथा गयाना का द्विपक्षीय संबंधो का बनाये रखना जारी है। इंडिया यूएनडीपी फंड के अधीन कोविड-19 से लड़ने के लिए क्लिक इम्पैक्ट कम्प्यूनिटी डेवलपमेंट फंड के एक भाग के तौर पर भारत ने गुयाना को कोबिड-19 महामारी से लड़ने हेतु 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की। भारत ने 30,000 एचसीक्यू टैबलेटों, आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों से युक्त चिकित्सा सहायता भी गयाना को भेजी।

विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने बारबोडोस को 10,000 एचसीक्यू टैबलेटों, आवश्यक दवाइयों तथा चिकित्सीय उपकरणों का चिकित्सा पैकेज भेजा।

कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने डानिमिका को 1000 एचसीक्यू टैबलेटों, आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सीय उपकरणों का चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा। भारत और डामिनिका, आशावारी के लिए सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त बहुपक्षीय बाज़ारों में सहयोग प्रदान किया जाना जारी है।

समारोह में हुई थी और इस कार्य के बहुत अधिक सराहा गया।

विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री रोबर्टो अल्वारेज के साथ 3 दिसम्बर, 2020 को टेलीफोन पर एम वर्चुअल बातचीत की। दोनों नेताओं ने अपने मजबूत द्विपक्षीय संबंधो को आईटीईसी एवं पीसीएफडी, आईएसए आदि के अंतर्गतफारमास्यूटिकल्स, सौर उर्जा तथा क्षमता निर्माण पहलों के क्षेत्र में व्यापार कि संबंधों में बदलने के रोडमैप पर चर्चा की।

आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सीय उपकरणों सहित चिकित्सा सहायता भेजी।

राजनायिकों एवं कार्यालयी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं मे छूट के लिए भारत और ग्रेनाडा अक्टूबर 2020 को एक समझौतें में शामिल हुए। भारत तथा ग्रेनाडा आशावारी को समर्थन प्रदान करने सहित बहुपक्षीय मंचो मे सहयोग प्रदान करना जारी रखे हुए हैं।

विकास सहयोग साझेदारी के अंतर्गत 4 परियोजनाएं यथा ईसूट कोसूट-ईसूट बैंक डेमैरारा लिंक रोड प्रोजेक्ट, महासागर नौका की खरीद, हाइ कैपेसिटी फिक्सड तथा मोबाइल ड्रेनेज पम्पूस का अधिग्रहण एवं 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अपग्रेडेशन कार्यान्वयन के अधीन है। बहुपक्षीय मंचो पर मजबूत सहयोग मौजूद था।

हैती

भारत का हैती के साथ घनिष्ठ संबंध जारी है 30 जुलाई, 2020 को ईएएम ने क्लाउड जोसेफ विदेश मंत्री हैती के साथ टेलीफोन पर बातचीत की जिसमें कोविड-19 महामारी एवं बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग विषयों पर बातचीत की गई।

भारत हैती को कोविड-19 से लड़ाई में सबसे पहले मदद पहुँचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय देशों में से एक था जहाँ इसने 30,000 हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन

टैबलेटों, आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों को हैती को भेजा था। अपने देश में कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने की अपनी कोशिश में इसे सहायता प्रदान करने के लिए अपने राष्ट्र पति जोवेनील मोइस, की ओर से विदेश मंत्री क्लाउड जोसेफ ने भारत की मदद को प्राप्त करते हुए भारत सरकार को धन्यवाद दिया।

होंडुरास

होंडुरास के साथ भारत के संबंधों का जोशपूर्ण व मैत्रीपूर्ण रहना जारी है। पिछले तीन वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में काफी विकास देखने को मिला है। 2019-20 में भारत के पक्ष में संतुलित व्यापार के साथ द्विपक्षीय व्यापार 204.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

विकास साझेदारी के अधीन 2,60,000 हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेटों, आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों के साथ भारत ने होंडुरास को चिकित्सा सहायता भेजी।

जमैका

जमैका के साथ द्विपक्षीय संबंधों का मज़बूती से बढ़ना जारी है। जमैका में 03 सितम्बर, 2020 को हुए आम चुनावों में जमैका लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री पद के आशावार एंड्रयू हालनेस ने 63 प्रतिनिधियों के सदन में 49 सीटों के बड़े अध्यादेश के साथ विपक्षी दल पीपल्स नेशनल पार्टी के ऊपर जीत दर्ज की।

29 अप्रैल 2020 को विदेश मंत्री की अपने समकक्षी जमैका के विदेश मंत्री कमीना जॉनसन स्मिथ के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई तथा कोविड-19 द्वारा उठाई गई चुनौतियों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। जमैका ने भारत के अपने पहले निवासी उच्चायुक्त को नियुक्त किया है जो कि जैलन कीट हाल है और जो एक पेशेवर राजनीतिज्ञ है।

विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने जमैका को 80,000 एचसीक्यू,

बहुक्षीय मंचों में मज़बूत सहयोग मौजूद था।

20 नवंबर 2020 को अन्य सहित एग्री मशीनरी, आटो कंपोनेंटो, इंडस्ट्रियल बॉयलरों, चिकित्सा उपकरण तथा इलैक्ट्रिक एप्लीकेशनों के भारत के अत्याधुनिक इंजीनियरी उत्पादों को शोकेस करने के लिए दूतावास ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ मिलकर खरीददार-विक्रेता-मीट में होंडुरास के खरीददारों ने भागीदारी की।

आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों की चिकित्सा सहायता का पैकेज भेजा। यह पूर्व में दिये गये 40,000 एचसीक्यू टैबलेटों की अतिरिक्त दी गई सहायता थी। भारत ने जमैका को भारत से हाइड्रॉक्लोरोक्वीन निर्यात के लिए छुटे भी प्रदान की। दोनों देशों ने विस्तृत रूप से क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय मंचों में सहयोग किया।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (25 नवंबर 2020) को मनाये जाने के क्रम में तथा एड्स दिवस (1 दिसम्बर, 2020), मनाए जाने के क्रम में उच्चायोग ने, ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा आयोजित किए गए व भारतीय, ईयू कनाडा के एवं अमेरिका के मिशनो द्वारा जमैका में सह मेजबानी किए गए ऑनलाइन पैनल में भाग लिया।

सेंट कीट्स एवं नेविस

भारत का सेंट लूसिया के साथ घनिष्ठ सहयोग जारी है। 01 मई 2020 को विदेश मंत्री (ईएएम) ने सेंट लेसिया के विदेश मंत्री सारा फ्लड-बीबून के साथ टेलीफोन पर बातचीत की तथा कोविड-19 से पैदा हुई परिस्थितियों पर अर्थव्यवस्था बहाली की चुनौतियों तथा कैरीकाम क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों पर विचार-विमर्श किया

विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत ने 10,000 एचसीक्यू टैबलेट, आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों का एक पैकेज सेंट लूसिया को भेजा। एक-दूसरे की आशावारी को समर्थन देते हुए भारत तथा सेंट लूसिया ने बहुपक्षीय मंचों पर आपस में सहयोग किया।

सेंट लूसिया

भारत का सेंट लूसिया के साथ घनिष्ठ सहयोग जारी है। 01 मई 2020 को विदेश मंत्री (ईएएम) ने सेंट लेसिया के विदेश मंत्री सारा फ्लड-बीबून के साथ टेलीफोन पर बातचीत की तथा कोविड-19 से पैदा हुई परिस्थितियों पर अर्थव्यवस्था बहाली

की चुनौतियों तथा कैरीकाम क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों पर विचार-विमर्श किया। विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत ने 10,000 एचसीक्यू टैबलेट,

आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों का एक पैकेज सेंट लूसिया को भेजा। एक-दूसरे की आशावारी को समर्थन देते हुए भारत तथा सेंट लूसिया ने

बहुपक्षीय मंचों पर आपस में सहयोग किया

सेंट विसेंट तथा दि ग्रेनाडीनिश

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय संबंधों में भारत तथा सेंट विसेंट और दि ग्रेनाडीनिश का घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाये रखना जारी है। 30 अप्रैल, 2020 को विदेश मंत्री ने सेंट विसेंट एवं ग्रेनेडेनिश के विदेश मंत्री लुईस स्ट्राकर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी तथा अर्थव्यवस्था बहाली एवं समुदाय विकास परियोजनाओं पर विचार विनिमय किया विकास साझेदारी कार्यक्रम के अधीन भारत ने 10,000 एचसीक्यू टैबलेटों, आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों की एक चिकित्सा सहायता पैकेज सेंट विसेंट एवं ग्रेनाडीनिश को भेजा।

कुछ त्वरित प्रभावी समुदाय विकास परियोजनाएं भी कार्यान्वयन के अधीन हैं। भारत से अनुदान के साथ त्वरित प्रभावी परियोजना पर समझौता ज्ञापन के अधीन तीन समुदाय विकास-संबंधी परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

भारत-यूएनडीपी फंड के अधीन स्थायी तथा पर्यावरणीय प्रत्यास्थी एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए एरोसर इंडस्ट्री मार्डनाइजेशन पर संचालन समिति की पहली बैठक नवंबर 2020 में हुई थी।

सूरीनाम

भारत और सूरीनाम के द्विपक्षीय संबंधों ने हाल के वर्षों में नई ऊंचाइयों को छुआ है। श्री चंद्रिकाप्रसाद संतोखी, एक पीआईओ (इस पद को ग्रहण करने वाले दूसरे पीआईओ) का राष्ट्र पति पद का चुनाव इस वर्ष का मुख्य आकर्षण रहा, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री द्वारा 'मन की बात' में भी किया गया था, जहां उन्होंने राष्ट्र पति पद की शपथ लेते समय उनके द्वारा किए गए वैदिक मंत्र के जाप का उल्लेख किया गया। 27 अक्टूबर 2020 को, विदेश मंत्री ने सूरीनाम के विदेश मंत्री अल्बर्ट रामादीन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, और लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, स्वास्थ्य सहयोग पर चर्चा की और एक

विकासशील भागीदारी के रूप में भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

विकास साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने सूरीनाम को 20,000 एचसीक्यू टैबलेट, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सहित एक चिकित्सा सहायता पैकेज भेजा। कार्यान्वयन के अंतर्गत विकास साझेदारी परियोजनाओं में काफी प्रगति हुई है जैसे दूध केंद्रीय प्रसंस्करण संयंत्र; ट्रांसमिशन नेटवर्क का अद्यतन; 50 चेतक हेलीकॉप्टर का रखरखाव और सर्विसिंग एवं 50 गांवों का सौर विद्युतीकरण।



02 दिसंबर 2020 को आयोजित 7वें भारत-सूरीनाम जेसीएम में उपस्थित राज्य मंत्री

त्रिनिदाद और टोबैगो

महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासी आबादी वाले एक गिरमिटिया देश त्रिनिदाद और टोबैगो और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध सदैव जोशपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे हैं। 29 अप्रैल 2020 को विदेश मंत्री ने त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश

मंत्री, श्री डेनिस मूसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की जहां उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के संबंध में चर्चा की।

विकास साझेदारी के अंतर्गत भारत ने 40,000 एचसीक्यू टैबलेट, आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण सहित एक चिकित्सा पैकेज लिनिदाद और टोबैगो को भेजा। 12 नवंबर, 2020 को मिशन एंड द महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट फॉर कल्चरल को-ऑपरेशन (एमजीआईसीसी) ने मुख्य विपक्षी दल यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस के नेताओं, एमपीएस और भारतीय प्रवासी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर नवनिर्मित एमजीआईसीसी केंद्र में दीपावली के पर्व को मनाया। 23 नवंबर, 2020 को कार्यक्रम में मिशन द्वारा सरकार और

लोगों को चिकित्सा सहायता की खेप सौंपी सौंपी गई जिसे विदेश मंत्री और कार्मिक मामलों के मंत्री एमी ब्राउन ने प्राप्त किया। एमजीआईसीसी और लिनिदाद तथा टोबैगो आईएनसी के हिंदी फाउंडेशन के सहयोग से मिशन द्वारा 16 जनवरी 2021 को लिनिदाद तथा टोबैगो सरकार के सांसदों और नौकरशाहों के साथ मिलकर भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति में विश्व हिंदी दिवस 2021 मनाया गया।

कैरीकॉम

कैरेबियन समुदाय (सीएआरआईसीओएम) के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध जोशपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बने रहे हैं। कोविड-19 महामारी के संदर्भ में भारत द्वारा सभी कैरिबियन देशों को आवश्यक दवाएं, चिकित्सा उपकरण और सुरक्षात्मक उपकरण सहित चिकित्सा सहायता भेजी गई। इंडिया-कैरिबियन लीडर्स प्रोजेक्ट

के अंतर्गत एंटीगुआ और बारबुडा और गुयाना को वेंटिलेटर सहित दवाओं और चिकित्सा की आपूर्ति भेजी गई थी। बारबाडोस, सेंट लूसिया, सेंटकिट्स और नेविस, डोमिनिका और हैती द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाएं कार्यान्वित हैं।

पेसिफिक गठबंधन

भारत पेसिफिक एलायंस में एक ऑब्जर्वर स्टेट है जो चिली, कोलंबिया, पेरू और मेक्सिको के साथ प्रशांत महासागर की सीमा से लगे देशों का एक क्षेत्रीय समूह है। चिली गठबंधन का वर्तमान अस्थायी अध्यक्ष है।

परोक्ष रूप में आयोजित किया गया था। ऑब्जर्वर राज्य के तौर पर भारत ने एक छोटी सी मध्यस्थता के साथ वर्चुअल फोरम में भाग लिया। उद्घाटन सल में संयुक्त सचिव (एलएसी) द्वारा भाग लिया गया जिसमें परस्पर लाभकारी सहयोग के लिए प्रशांत गठबंधन के देशों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होने में भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की गई।

चिली की अस्थायी अध्यक्षता के अंतर्गत दूसरा सहयोग फोरम (ऑब्जर्वर राज्यों के साथ सहयोग के लिए 2019 में स्थापित किया गया) 12 नवंबर 2020 को

10

बिम्स्टेक, सार्क एवं नालंदा

सार्क

प्रधानमंत्री की पहल पर, 15 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी का सामना करने के लिए क्षेत्रीय प्रतिक्रिया पर चर्चा हेतु सार्क प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपति; बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, पाकिस्तान के स्वास्थ्य राज्य मंत्री और सार्क के महासचिव सभा में शामिल हुए। भारत ने महामारी से निपटने की तत्काल लागतों को पूरा करने के लिए कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष की स्थापना सहित कई पहलों की घोषणा की। भारत द्वारा अन्य सार्क सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का स्वैच्छिक योगदान दिया गया तत्पश्चात अन्य सार्क सदस्यों द्वारा भी योगदान दिया गया। क्षेत्रीय देशों के अनुरोध पर प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने आवश्यक दवाओं, चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों, कोविड-19 के संरक्षण हेतु परीक्षण किटों एवं अन्य उपकरणों की आपूर्ति के लिए आपातकालीन 17.1 करोड़ (लगभग 2.3 मिलियन डॉलर) का कोष जारी किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषित की गई अन्य पहलों के साथ भारत ने 26 मार्च, 2020 को स्वास्थ्यसेवा महानिदेशक केस्तर के स्वास्थ्यपेशेवरों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी मेजबानी की जिसमें क्षेत्रीय सार्क सदस्यों के बीच जानकारी एवं सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा किया गया। 8 अप्रैल, 2020 को, भारत ने सार्क देशों के व्यापार कि अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की

मेजबानी की जिसमें कोविड-19 की स्थिति को मध्यनज़र रखते हुए प्रतिबंधों के प्रभाव और आयात प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर चर्चा की गई। 4,6 एवं 8 मई, 2020 को एमूस, नई दिल्ली द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन, परीक्षण रणनीतियों, संक्रमण नियंत्रण उपायों और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर अनुभव साझा करने के लिए सार्क देशों के चिकित्सा पेशेवरों के मध्य एक वेबिनार का आयोजन किया।

भारत ने 12 मई 2020 को कोविड-19 सूचना विनिमय मंच 'कोएनेक्स' की भी शुरुआत की, ताकी सार्क देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों के मध्यरोग की निगरानी, आपसी संपर्क पर नजर रखना, पृथक्करण एवं संगरोधन से संबंधित विशेष जानकारी का आदान-प्रदान किया जा सके।

अल्पावधि की तरलता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत ने मालदीव (150 मिलियन अमेरिकी डॉलर) भूटान (200 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और श्रीलंका (400 मिलियन अमेरिकी डॉलर) को विदेशी मुद्रा विनिमय विस्तारित किया।

भूटान के खाद्यान्नों का भंडारण करने के लिए भारत द्वारा रखे गए खाद्यान्न भंडारों से 2000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के भूटान के अनुरोध को पूरा करने के लिए मई 2020 में पहली बार सार्क फूड बैंक तंत्र को सक्रिय किया

गया था। खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहे सदस्य देशों द्वारा आपात स्थिति और सामान्य समय दोनों के दौरान खाद्यान्न का लाभ उठाने के लिए खाद्य पदार्थों की कमी का सामना कर रहे सदस्य देश आपात स्थिति और सामान्य समय दोनों के दौरान खाद्यान्न का लाभ उठाने के लिए 2007 में सार्क फूड बैंक की स्थापना के बाद से अब तक किसी देश द्वारा यह पहला लेन-देन किया गया था। 24 सितंबर 2020 को, यूएनजीए के साथ वर्चुअल मोड में सार्क मंत्रिपरिषद की वार्षिक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई थी। ईएएम ने बैठक में भाग लिया जिसमें मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के क्षेत्रीय प्रयासों की समीक्षा की गई। प्रतिभागियों ने मार्च 2020 में सार्क नेताओं का वीडियो सम्मेलन बुलाने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की विशेष रूप से सराहना की। ईएएम ने दोहराया कि भारत एक जुड़ा हुआ, एकीकृत, सुरक्षित और समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। 19वें सार्क शिखर सम्मेलन और उसकी पिछली बैठकों के लिए तारीखों पर विचार के मुद्दे पर ईएएम ने सदस्य देशों के बीच आम सहमति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर शिखर स्तर के जुड़ाव को सार्थक

या उत्पादक बनाना है तो सीमा पार आतंकवाद, संपर्क पहलों को अवरुद्ध करने और व्यापार समझौतों पर प्रगति में अनिच्छा के मुद्दों को ईमानदारी से संबोधित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य देशों के लिए वर्तमान प्राथमिकता कोविड-19 चुनौती से निपटना था और इस समय अगले शिखर सम्मेलन की बात करना समय पूर्व था।

सार्क वित्त मंत्रियों की 15वीं अनौपचारिक बैठक 16 सितंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की 53वीं वार्षिक बैठक के साथ वर्चुअल मोड में हुई थी। बैठक में सभी सार्क सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों/प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (एफबी और एडीबी) डीईए ने किया था। प्रतिभागियों ने कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गिरावट पर अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को साझा किया और सार्क के अंतर्गत व्यापार और आर्थिक मुद्दों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।



15 मार्च 2020 को सार्क प्रतिनिधियों को कोविड-19 के संघर्ष के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने संबोधित किया।

सार्क शिक्षा मंत्रियों की बैठक 08 अक्टूबर 2020 को नेपाल द्वारा वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई थी। एआईसीटीई के अध्यक्ष ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत ने 23 अप्रैल 2020 को कोविड-19 की स्थिति पर विचार-विमर्श हेतु पाकिस्तान द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो सम्मेलन में भी भाग लिया।

सार्क योजना सचिवों की बैठक से पहले सार्क योजना मंत्रियों की उद्घाटन बैठकें क्रमशः 23 और 25 नवंबर 2020 को वर्चुअल प्रारूप में आयोजित की गई थीं। नीति आयोग के सीईओ ने योजना मंत्रियों की बैठक में भारतीय

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

सार्क की प्रोग्रामिंग कमेटी का 58वां सत्र 15 दिसंबर 2020 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बीएसएन) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

भारत ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण के लिए समर्थन देना जारी रखा, जिसने कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के बावजूद संतोषजनक भौतिक प्रगति की है।

बिम्स्टेक

बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्स्टेक) इस क्षेत्र में भारत की मुख्य चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' की भारत की प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकताओं को पूरा करने वाला दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाला एक अनूठा क्षेत्रीय संगठन है। भारत वर्तमान में कुल 14 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से चार यथा- प्रति आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध; परिवहन और संचार; पर्यटन; और पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में बिम्स्टेक सहयोग का नेतृत्व कर रहा है।

बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों ने क्रम के अनुसार, वर्णमाला रोटेशन के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए बिम्स्टेक के तीसरे महासचिव के रूप में तेंजिन लेकफेल (भूटान) के नामांकन को मंजूरी दी। लेकफेल ने 6 नवंबर 2020 को कार्यभार संभाला था।

30 जून 2020 को विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली द्वारा कोविड-19 पश्चात युग में बिम्स्टेक में आर्थिक सहयोग की समीक्षा पर एक वेबिनार आयोजित की गई थी। विदेश राज्य मंत्री ने उद्घाटन भाषण दिया जिसमें उन्होंने बिम्स्टेक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।

बिम्स्टेक वरिष्ठ अधिकारियों की 21वीं बैठक (सोम) 02 सितंबर 2020 को कोलंबो में आयोजित की गई थी। बैठक में 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक के अनुमोदन के लिए बिम्स्टेक चार्टर के अंतिम पाठ का पृष्ठांकन किया गया। सोम ने मंत्रिस्तरीय बैठक द्वारा अनुमोदन पर अगले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए जाने वाले निम्नलिखित साधनों का भी पृष्ठांकन किया: (i) आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्स्टेक सम्मेलन; (ii) कोलंबो, श्रीलंका में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी अंतरण सुविधा की स्थापना और (iii) बिम्स्टेक सदस्य देशों की राजनयिक अकादमियों/प्रशिक्षण संस्थानों के

बीच पारस्परिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर एसोसिएशन का ज्ञापन। बैठक में बिम्स्टेक केन्द्रों/संस्थाओं की स्थापना पर मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के टेम्पलेट पर भी विचार किया गया और उसे अंतिम रूप दिया गया। सोम ने 31 अगस्त 2020 को बिम्स्टेक स्थायी कार्यसमिति की चौथी पूर्व बैठक की थी।

कोलंबो में 03 मार्च, 2020 को सोम की 20वीं बैठक हुई थी, जिसमें बिम्स्टेक के कार्य में ध्यान केंद्रित करने के लिए सहयोग के क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को युक्तिसंगत बनाने की संस्तुति की गई थी, जिसे बिम्स्टेक की सतहवीं मंत्रिस्तरीय बैठक के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

भारत की अध्यक्षता में 8 दिसंबर 2020 को वर्चुअल प्रारूप में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में सदस्य देशों द्वारा सभी सदस्य देशों की 'सैद्धांतिक रूप से' सहमति प्राप्त करने वाले बिम्स्टेक मास्टर प्लान के प्रारूप को सदस्य देशों ने अंतिम रूप दिया था।

बिम्स्टेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक की 5वीं बैठक 21-22 दिसंबर 2020 को वर्चुअल प्रारूप में रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीस (आरआईएस) द्वारा आयोजित की गई थी।

15-16 जनवरी 2021 को वर्चुअल प्रारूप में स्टार्ट-अप इंडिया इंटरनेशनल समिट के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में बिम्स्टेक स्टार्ट-अप निर्वाचिका सभा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, स्टार्ट-अप और निवेशकों ने भाग लिया।

सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, व्यापार, नीली अर्थव्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि के विविध क्षेत्रों में 2018 में काठमांडू में पिछले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कई एकतरफा पहलों पर कार्रवाई चल रही है।

नालंदा विश्वविद्यालय

नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 ने विश्वविद्यालय की स्थापना की और शिक्षण 2014 में शुरू हुआ। विश्वविद्यालय ने भौतिक अवसंरचना के साथ-साथ अकादमिक कार्यक्रमों दोनों के संदर्भ में निरंतर प्रगति की है। विश्वविद्यालय परिसर निर्माण का 70% से अधिक पूरा हो चुका है। विश्वविद्यालय को नेट जीरो एनर्जी कैम्पस के लिए 09 अक्टूबर 2020 को गृह परिषद द्वारा एकीकृत पर्यावास मूल्यांकन, बड़े विकास (गृह एलडी-5 स्टार) के लिए 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था। विश्वविद्यालय ने अपने अभिनव अकादमिक वास्तुकला के लिए शिक्षा में उत्कृष्टता में सीएसआर पुरस्कार भी जीता।

विश्वविद्यालय ने अपनी शैक्षणिक और प्रशासनिक गतिविधियों की शुरुआत नए परिसर से की। वर्तमान में 12 विदेशी संकाय सहित 38 संकाय सदस्य हैं, और कुल 834 नियमित और अंशकालिक छात्र हैं, जिनमें 23 देशों के 134 विदेशी छात्र शामिल हैं। अकादमिक कार्यक्रमों की संख्या 12 तक बढ़ी। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 5 स्कूल हैं जिनमें एक नया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज शामिल है जिसने शैक्षणिक सत्र 20-21 में सतत विकास और प्रबंधन में एमबीए कार्यक्रम शुरू किया था। विश्वविद्यालय ने 2020 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए 4 वर्षीय वैश्विक पीएचडी कार्यक्रम भी शुरू किया।

11

भारत-प्रशांत

हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मिलकर एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थान बनाते हैं जो वैश्विक जनसंख्या के 64 प्रतिशत से अधिक लोगों का घर है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार का लगभग आधा भाग समुद्री व्यापार मार्गों के माध्यम से होता है। इन वर्षों में, इस क्षेत्र ने प्रशांत रिम, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र और अफ्रीका के पूर्वी और दक्षिणी तट पर फैले मजबूत और सतत आर्थिक विकास को देखा है। इस आर्थिक गतिशीलता ने जहां कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय एकीकरण और अधिक आर्थिक अवसरों को बढ़ाया है, वहीं यह आम खतरों और चुनौतियों को भी ले आया है। इन बदलावों ने वैश्विक जगत का स्वाभाविक तौर पर अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित किया है और हिंद-प्रशांत की अवधारणा को व्यक्त किया है। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, भारत के प्रधानमंत्री ने जून 2018 में हिंद-प्रशांत के भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट नीति तत्वों और कार्यक्रम उपलब्ध करके स्पष्ट किया। मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में हमारे हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण और इसके कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देने और संगठनात्मक तालमेल के लिए हिंद-प्रशांत डिवीजन की स्थापना की।

वर्ष 2020-21 के दौरान, महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत ने विभिन्न हिंद-प्रशांत ढांचों: आसियान, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए), एशिया-यूरोप मीटिंग (एएसईएम), मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन (एमजीसी), अयावाडी-चाओ फ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (एसीएमईसीएस), और हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल आईपीओआई) के साथ अपना व्यवसाय करने में तेजी लाना जारी रखा।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ

आसियान की केंद्रीयता भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू रही है और बनी रहेगी, जो भारत की विदेश नीति में केंद्रीय मूल वस्तु है। इस वर्ष आसियान की अध्यक्षता वियतनाम द्वारा की गई है और थाईलैंड भारत और आसियान के बीच देश के समन्वयक का स्थान रखता है।

22वें आसियान-भारत के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 16 जुलाई 2020 को एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई थी। सभी दस आसियान देशों और भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने आसियान-भारत सहयोग और इसके भविष्य के निर्देशों पर चर्चा की और विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति और उस पर एक एकजुट, समन्वित और बहुपक्षीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की।

ईएएम ने 12 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आसियान-भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में समुद्री सहयोग, संपर्क, शिक्षा और क्षमता निर्माण और जन-जन के बीच संपर्क और कई क्षेत्रों में आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में नई आसियान-भारत कार्य योजना (2021-2025) को अंगीकृत किया गया। मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से थाईलैंड के विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगस्त 2020 में आसियान-भारत नेटवर्क आफ थिंक टैंक (एआइएनटीटी) के 6वें संस्करण का आयोजन किया। चुललॉन्गकोर्न यूनिवर्सिटी, बैंकॉक स्थित विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली पर आधारित आसियान-भारत केंद्र (एआइसी) और आसियान अध्ययन केंद्र गोलमेज सम्मेलन के आयोजक भागीदार थे। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से ईएएम और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री डॉन प्रमुदविनई द्वारा किया गया था। आसियान के महासचिव लिम जॉक होई ने उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। गोलमेज का विषय था 'आसियान-भारत: कोविड युग के पश्चात् साझेदारी को सुदृढ़ बनाना' और चर्चाएं भारत-प्रशांत महासागर के लिए भारत और आसियान के विचारों के पूरक के संदर्भ में आगे के रास्ते पर भी केंद्रित थीं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आइआइटी) में आसियान छात्रों के लिए 1000 एकीकृत पीएचडी फेलोशिप कार्यक्रम के पहले दो बैचों के लिए स्वागत समारोह 16 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। इस समारोह में भारत की तरफ से शिक्षा मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, सचिव शिक्षा और सचिव पूर्व, एमईए और भारत में आसियान देशों के राजदूत उपस्थित हुए। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आसियान-भारत स्मारक सम्मेलन की 25 वीं वर्षगांठ पर प्रधान मंत्री द्वारा फेलोशिप की घोषणा की गई और सितंबर 2019 में ईएएम और मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। कुल 300 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ, फेलोशिप कार्यक्रम आसियान के साथ अपनी साझेदारी में भारत की सबसे बड़ी क्षमता निर्माण पहल है।

ऑक्सर्वर रिसर्च फाउंडेशन की साझेदारी में मंत्रालय द्वारा 12 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में साइबर मुद्दों पर दूसरा आसियान-भारत ट्रैक 1.5 संवाद आयोजित किया गया था। संवाद में आसियान के सदस्य राज्यों और भारत के सरकारी प्रतिनिधियों और साइबर विशेषज्ञों की भागीदारी देखी गई। वार्ता में चर्चा हुई कि कैसे भारत और आसियान देश साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा, इस क्षेत्र में बी-2-बी साझेदारी की सुविधा और उभरती प्रौद्योगिकियों और 5 जी के क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौतियों से निपट सकते हैं और भारत और आसियान की राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच भागीदारी खोज कर सकते हैं।

17वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, जो 12 नवंबर 2020 को वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया था, की सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक द्वारा की गई थी। सभी दस आसियान सदस्य राज्यों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन ने आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की और कनेक्टिविटी, समुद्री सहयोग, व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और क्षमता निर्माण आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया। नेताओं ने आसियान-भारत की भागीदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और इस संदर्भ में आसियान-भारत योजना (2021-2025) को अपनाते का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए आसियान की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला और कोविड -19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन अमरीकी डालर के योगदान की घोषणा की।



17वां आसियान-भारत वर्चुअल शिखर सम्मेलन, 12 नवंबर 2020

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ई.ए.एस.)

ई.ए.एस. वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 20 जुलाई 2020 को वर्चुअल तौर पर आयोजित की गई। 18 ई.ए.एस. भाग लेने वाले देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोविड महामारी, पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और समुद्री सहयोग सहित ई.ए.एस.सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

09 सितंबर 2020 को आयोजित 10वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन के विदेश

मंत्रियों की बैठक में राज्य मंत्री ने भाग लिया। यह बैठक वर्चुअली पर तौर आयोजित की गई। बैठक में ईएएस के भाग लेने वाले देशों के विदेश मंत्री उपस्थित हुए और वियतनाम के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री फाम बिन मिन्ह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में नेताओं की अगुवाई वाले ईएएस प्लेटफॉर्म को मजबूत करने और इसकी 15वीं वर्षगांठ पर उभरती चुनौतियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के तौर तरीकों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने कोविड -19 महामारी सहित वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों और शीघ्र और स्थायी आरोग्यता प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करने पर विचारों का आदान-प्रदान किया।



विदेश मंत्री दिनांक 14 नवंबर 2020 को आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए

ईएएम ने 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुच ने अपनी क्षमता के अनुसार आसियान अध्यक्ष के रूप में की। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में सभी 18 ईएएस देशों ने भाग लिया। ईएएम ने अपनी टिप्पणी में, रणनीतिक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए नेताओं के नेतृत्व वाले फोरम के रूप में ईएएस के महत्व की फिर से पुष्टि की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने और नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के महत्व की बात की। नेताओं ने कोविड -19 टीकों को सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने शीघ्र और स्थायी आर्थिक सुधार के लिए खुली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, कोरियाई प्रायद्वीप और राखीन देश की स्थिति पर भी चर्चा की गई। हा नोई उद्घोषणा के अतिरिक्त, शिखर सम्मेलन में समुद्री स्थिरता; महामारी निवारण और प्रतिक्रिया; महिला, शांति और सुरक्षा; और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के सतत् विकास पर अन्य चार नेताओं के वक्तव्यों को भी स्वीकृत किया गया।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आइ.ओ.आर.ए.)

मार्च 2020 के पश्चात् सभी आइओआरए कार्यक्रमलाप कोविड-19 द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण वर्चुअल तौर पर आयोजित किए गए थे। आइओआरए ने मई 2020 में कोविड-19 पर संवाद भागीदार वचनबद्धता: प्रतिक्रिया, सहयोग और साझेदारी तथा वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (सीएसओ) की असाधारण बैठक की मेजबानी की। भारत ने बैठक में भाग लिया और कोविड-19 से निपटने में क्षेत्र को अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। भारत ने जून 2020 में आयोजित 10वीं अर्धवार्षिक आइओआरए सीएसओ बैठक में भी भाग लिया और छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और आइओआरए के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया।

शैक्षणिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आइओआरए प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर प्रमुख देश के रूप में - भारत ने अगस्त 2020 के अंत में शैक्षणिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आइओआरए विशेषज्ञ समूह की द्वितीय बैठक की मेजबानी की।

भारत ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आइओआरए के सदस्य देशों द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में भी भाग लिया जिनमें आइओआरए सचिवालय द्वारा आयोजित छठवीं सलाहकार समिति की बैठक, आइओआरए सदस्य देशों द्वारा देय राशि के गैर-भुगतान की समीक्षा करने के लिए कार्यशाला, अगस्त 2020 में यूएई द्वारा आयोजित पर्यटन पर आइओआरए कोर समूह की पहली बैठक; आइओआरए में ब्लू कार्बन पहल पर वेबिनार, इंडोनेशिया द्वारा आयोजित मतस्य पालन में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर वेबिनार, इंडोनेशिया द्वारा आयोजित आधुनिक संधारणीय मतस्य पालन प्रबंधन पर वेबिनार, आइओआरए सदस्य देशों द्वारा कार्यान्वित कोविड-19 अनुसंधान एवं नवाचार कार्यक्रम और परियोजनाएं तथा सितम्बर, 2020 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित संवाद भागीदार कार्यक्रम; यूएई द्वारा आयोजित भारतीय महासागरीय रिम व्यवसाय फोरम की 25वीं बैठक, आइओआरए कार्य योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्यशाला और यूएई एवं बांग्लादेश द्वारा आयोजित नई योजना की तैयारी, इटली द्वारा आयोजित संधारणीय समुद्री पर्यटन पर इटली-आइओआरए वेबिनार और अक्टूबर, 2020 में कोरिया गणराज्य द्वारा आयोजित पहला आइओआरए-आरओके सहभागिता सेमिनार शामिल हैं।

भारत ने क्रमशः अक्टूबर और नवंबर 2020 में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र (समुद्र तल को समझना) और मतस्य पालन (मतस्य उद्योग समुद्र विज्ञान) के क्षेत्र में आइटीसीओओ, आइएनसीओआईएस द्वारा आनलाइन आयोजित दो क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों के लिए आइओआरए सदस्य देशों को आमंत्रित किया।

17 दिसंबर, 2020 को राज्य मंत्री ने भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन परिषद की 20वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसकी मेजबानी वर्चुअल तौर पर यूएई द्वारा की गई। बैठक में आइओआरए के सदस्य

देशों द्वारा सामान्य हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। सीओएम ने अमीरात कम्युनिक और आइओआरए की एकजुटता और कोविड -19 के प्रत्युत्तर में सहयोग वक्तव्य को स्वीकृत किया। राज्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में आइओआरए नामक दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, आपदा जोखिम प्रबंधन और शैक्षणिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समन्वित देश के रूप में भारत द्वारा किए गए योगदान का उल्लेख किया। महामारी के उपरांत व्यापक स्वास्थ्य लाभ को ध्यान में रखते हुए, राज्य मंत्री ने आइओआरए के सदस्य देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग करने का आह्वान किया। आइओआरए को और अधिक सुदृढ़ बनाने में भारत के योगदान के रूप में, राज्य मंत्री ने आइओआरए सचिवालय में ई-ऑफिस प्रणाली के कार्यान्वयन और महात्मा गांधी पुस्तकालय की स्थापना के रूप में भारत की पहल की घोषणा की। भारत ने फ्रांस की आइओआरए सदस्यता बोली का भी समर्थन किया, जो इस सीओएम में आइओआरए का 23वां सदस्य बन गया। सीओएम का आयोजन 15-16 दिसंबर 2020 को आइओआरए की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (सीएसओ) की 22वीं बैठक से पहले किया गया था।

एशिया - यूरोप बैठक (ए.एस.ई.एम.)

एएसईएम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) वर्चुअल रूप से 02 और 03 जुलाई, 2020 को आयोजित की गई थी। कनेक्टिविटी और कोविड-19 महामारी 2 मुख्य मुद्दे थे, जिन पर एसओएम नेताओं के मध्य विचार-विमर्श हुआ। कोविड -19 पर एएसईएम का वक्तव्य 07 सितंबर, 2020 को स्वीकार किया गया। इस बैठक ने 2020 की एएसईएम विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जमीन तैयार की और कंबोडिया वर्ष 2020 के लिए एएसईएम का अध्यक्ष बना। एएसईएम शिखर सम्मेलन 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

भारत ने 29-30 सितंबर, 2020 को कंबोडिया द्वारा वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई “उप-मानक एवं नकली दवाइयों की रोकथाम” पर एशिया-यूरोप फोरम में हिस्सा लिया। भारत ने बांग्लादेश द्वारा आयोजित 6 नवंबर, 2020 को आयोजित 14वीं एएसईएम वित्त मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया।

मेकांग गंगा कार्पोरेशन (एम.जी.सी.)

12वें वर्ष मेकांग गंगा कॉर्पोरेशन की 20वीं वर्षगांठ है जिसकी स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी और यह मेकांग क्षेत्र की सबसे पुरानी पहलों में से एक है। इस उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए, उत्सव के कार्यक्रमलापों की मेजबानी करने की योजना वर्ष के दौरान बनाई गई। हालांकि, कोविड-19 के कारण, इनमें से कुछ गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। फिर भी, पिछले बीस वर्षों में हुई प्रगति और भविष्य की कार्यवाही की योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एआईसी, आरआईएस और आईसीडब्ल्यूए के सहयोग से मई और नवंबर 2020 में वेबिनार सहित एमजीसी के दो दशकों को चिह्नित करने के लिए अनेक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

12वीं एमजीसी वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (12वीं एमजीसी एसओएम) वर्चुअल तरीके से 03 सितंबर, 2020 को आयोजित की गई थी, जहां भारत, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम के वरिष्ठ अधिकारियों ने 01 अगस्त, 2019 को बैंकॉक में आयोजित 10वीं एमजीसी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान स्वीकृत एमजीसी कार्य योजना (2019-22) के अंतर्गत विभिन्न पहलों में हुई प्रगति की समीक्षा की।

त्वरित प्रभाव परियोजना (क्यूआईपी) योजना एमसीजी के प्रमुख मुख्य आधारों में से एक रही है। ये क्षेत्र में सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अल्पकालिक, कम लागत, सामुदायिक उन्मुख परियोजनाएं हैं। भारत और म्यांमार ने फरवरी, 2020 में म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान क्यूआईपी अम्ब्रेला समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत पहले से ही कम्बोडिया, लाओ पीडीआर और वियतनाम के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। वर्ष 2020 में, क्यूआईपी योजनाओं के अंतर्गत कुल तेईस परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिसमें वियतनाम के लिए 12 परियोजनाएं, कंबोडिया के लिए 8 और लाओ पीडीआर के लिए 3 परियोजनाएं शामिल हैं। जल संसाधन प्रबंधन को क्यूआईपी योजना के तहत सहयोग के एक नए क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया था, जिसके तहत वियतनाम को अपने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कुशल जल प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। भारत ने मेकांग देशों में भारतीय निजी क्षेत्र द्वारा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए परियोजना विकास कोष भी स्थापित किया है।

आयेयावाडी-चोफ्राया-मेकांग आर्थिक सहयोग रणनीति (ए.सी.एम.ई.सी.एस.)

भारत जुलाई 2019 में ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एसीएमईसीएस में एक विकास भागीदार के रूप में शामिल हुआ। भारत आसियान क्षेत्र में कनेक्टिविटी और डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए नवंबर 2015 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन आफ क्रेडिट को खर्च करके एसीएमईसीएस की प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से उपयुक्त परियोजनाओं की पहचान करने के लिए उत्सुक है। इस पहल के तहत, भारत वर्तमान में आइएमटी लिपक्षीय राजमार्ग के पूर्वी दिशा में विस्तार के लिए लाओ पीडीआर को 167 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन आफ क्रेडिट का विस्तार करने पर विचार कर रहा है।

हिंद-प्रशांत महासागरीय पहल

हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण को मॉरीशस की अपनी यात्रा के दौरान मार्च 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त किया गया और महासागर के लिए हिंदी शब्द “सागर” में समझाया गया, अर्थात् “क्षेत्र में सभी की सुरक्षा एवं विकास” भारत-पैसिफिक की हमारी व्यापक अभिव्यक्ति को दर्शाता है। इसे जून 2018 में शांगरी ला डायलॉग में प्रधानमंत्री के मुख्य अभिभाषण में व्यापक रूप से सम्बोधित किया गया था। भारत का दृष्टिकोण सहयोग और संगठन पर आधारित है। आसियान इस समुद्री अंतरिक्ष के केंद्र में है। पश्चिमी हिंद महासागर में, भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आइओआरए) का सदस्य है। भारत इस क्षेत्र में वास्तुकला के लिए सहयोग करना चाहता है जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि बढ़ती है।

भारत का हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण मुक्त, खुले, समावेशी क्षेत्र की परिकल्पना करता है, जो प्रगति और समृद्धि की सामान्य खोज में सभी का आलिप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी सामान्य समृद्धि और सुरक्षा के लिए संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, परामर्श, सुशासन, पारदर्शिता, व्यवहार्यता और स्थिरता के लिए सम्मान के साथ क्षेत्र के लिए संवाद के माध्यम से, एक सामान्य नियम-आधारित आदेश के तहत क्रमिक विकास की आवश्यकता होती है।

हिंद-प्रशांत के भारतीय दृष्टिकोण की स्वाभाविक प्रगति के रूप में और इसे मूर्त रूप देने के लिए, प्रधानमंत्री ने नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित ईस्ट एशिया समिट में हिंद-प्रशांत महासागर की पहल (आईपीओआई) की घोषणा की। आईपीओआई खुली, समावेशी और सहयोगात्मक तरीके से वैश्विक चुनौतियों के सहयोगात्मक समाधान तलाशने पर ध्यान केंद्रित करने पर है। एक खुली वैश्विक पहल के रूप में, यह मौजूदा क्षेत्रीय सहयोग वास्तुकला और तंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है जो समुद्री सुरक्षा के आसपास सात केंद्रीय

स्तंभों पर ध्यान केंद्रित है; जिनमें समुद्री पारिस्थितिकीय समुद्री संसाधन; क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण; आपदा जोखिम में कमी और प्रबंधन; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग; व्यापारिक सम्बद्धता और समुद्री परिवहन शामिल हैं। समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के स्तंभों को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने इच्छुक देशों को आईपीओआई के एक या एक से अधिक स्तंभों पर साथ आने के लिए आमंत्रित किया है।

12

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन

आम सभा का 75वां सत्र

आम सभा का 75वां सत्र 15 सितंबर, 2020 को आरंभ किया गया। दिनांक 21 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में "द फ्यूचर वी वांट; द यूएन वी नीड: रीएफर्मिंग ऑवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म" विषय पर विधानसभा की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित किया। बहुपक्षीयता के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने एक उचित बहुपक्षीयता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जो आज की वास्तविकताओं को दर्शाता है, सभी हितधारकों को स्वर देता है, समकालीन चुनौतियों का समाधान करता है और मानव कल्याण पर केंद्रित है।

75 वें यूएनजीए आम चर्चा का विषय "द फ्यूचर वी वांट; द यूएन वी नीड: रीएफर्मिंग ऑवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म-कन्फ्रंटिंग कोविड-19 थ्रू इफेक्टिव मल्टीलेटरल एक्शन" था। दिनांक 26 सितंबर, 2020 को आम बहस में आम सभा (पूर्व में दर्ज संदेश के माध्यम से) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार करने और भारत के मतों को अपने निर्णय लेने के पहलुओं में शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया में भारत के योगदान को भी रेखांकित करते हुए घोषणा की कि भारत, विश्व को एक परिवार के रूप में देखने के अपने दर्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमताओं को बाकी दुनिया को उपलब्ध कराएगा।

कोविड-19 महामारी के दौर में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक विशेष सत्र 03-04 दिसंबर 2020 को आयोजित किया गया था। सचिव (पश्चिम) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और महामारी के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के साथ-साथ इस संबंध में 150 अन्य देशों को भारत की सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की।

राष्ट्र संघ की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को एक डाक टिकट जारी किया। इस कार्यक्रम में भाषण देते हुए, ईएएम ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों की नींव डालने से लेकर अपनी शांति बनाए रखने में सबसे आगे रहकर इसमें पूर्णरूपेण योगदान दिया है।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों और उद्देश्यों को अपने सदस्य राष्ट्रों की आकांक्षाओं के करीब लाने और इससे भी अधिक उनके लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए हाथ मिलाने और उत्साह और समर्पण के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।



विदेश मंत्री दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र की 75 वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी करते समय उपस्थित रहे

सुरक्षा परिषद

वर्ष 2020-21 के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कई खुली बहसों में भाग लिया। भारत ने वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2538 को भी सह-प्रायोजित किया जिसमें सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और क्षेत्रीय संगठनों सहित वरिष्ठ नेतृत्व के पदों सहित सभी स्तरों पर और सभी पदों पर शांति अभियानों में वर्दीधारी और नागरिक महिलाओं की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए

अपने सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान, बोस्निया और हर्जेगोविना और यमन के विषयों पर सुरक्षा परिषद की अरिया फॉर्मूला बैठकों में भी भागीदारी की। भारत ने वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में इस सीट का कार्यभार संभाला था।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

वर्ष 2020-21 में, भारत ने जी-4 और एल-69 जैसे सुधार उन्मुखी समूहों के साथ अपने सक्रिय संबंधों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

74वें यूननजीए सत्र के दौरान सरकारों के बीच वार्ताएं (आईजीएन) प्रक्रिया को इन-पर्सन बैठकों पर कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों द्वारा कम कर दिया गया था। वर्ष के दौरान आयोजित दो आईजीएन बैठकों में आम अफ्रीकी स्थिति के लिए सदस्य देशों से समर्थन बढ़ रहा था, साथ ही आईजीएन के बेहतर कामकाज के तरीकों के लिए आवाजें उठ रही थीं। 75वें यूननजीए सत्र में, भारत ने सुरक्षा परिषद सुधार पर पाठ आधारित वार्ताओं को तत्काल शुरू करने सहित ठोस प्रगति सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले प्रतिनिधिमंडलों के साथ काम किया।

संयुक्त राष्ट्र अपनी 75वीं वर्षगांठ पर दिनांक 16 सितंबर, 2020 को जारी संयुक्त मंत्रिस्तरीय बयान में आईबीएसए (भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका) के विदेश मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर ठोस प्रगति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

जी-4 के विदेश मंत्रियों (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) ने 75 वीं यूननजीए उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान 23 सितंबर, 2020 को वर्चुअल पद्धति से अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की। एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में मंत्रियों ने दोहराया कि दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद का विस्तार निकाय में ज्यादा लोग भाग ले पाएंगे, उसे वैध और प्रभावी बनाने के लिए अपरिहार्य है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ वर्ष में ठोस परिणाम देने के लिए ठोस पाठ आधारित वार्ताएं आरंभ करने का आह्वान किया।

जी-77 आयोजन

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने दिनांक 29 अक्टूबर 2020 को "मैनटेनिंग ए लो कार्बन डेवलपमेंट पाथ टूवर्ड द 2030 एजेंडा इन द एरा ऑफ कोविड-19" विषय पर वर्चुअल प्लैगशिप जी-77 मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। उन्होंने दिनांक 12 नवंबर, 2020 को जी-77 वार्षिक विदेश

मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया। बैठक का विषय "ग्लोबल रिसपांस टू द कोविड-19 पेनडेमिक एंड द आब्सटेकलस टू द पोजिज़ टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 2030 एजेंडा एंड एचीवमेंट ऑफ द एसडीजी" था।

भारत और शांति स्थापना

भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का लगातार सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना रहा, जिसने वर्ष 1950 के दशक से लगभग 253,000 सैनिकों का योगदान किया है। दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक, भारत ने 08 शांति अभियानों में 5,353 कर्मियों की तैनाती के साथ पांचवां सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है। आज की तारीख में 175 भारतीय शांतिरक्षकों ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भारत द्वारा तैनात पुलिस कर्मियों में 44 प्रतिशत महिला पुलिस अधिकारी रही (27 में से 12)।

संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श में, भारत 'मेनडेट' तैयार करने में सेना का योगदान वाले देशों (टीसीसी) के साथ गंभीर और संस्थागत परामर्श करने की आवश्यकता पर बल देता आ रहा है; 'मेनडेट' को प्राथमिकता देने और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधनों के आवंटन की आवश्यकता; प्रदर्शन में बाधा बनने वाली सभी राष्ट्रीय चेतावनियों को हटाने की आवश्यकता; समर्पित आईईडी-रोधी उपायों की आवश्यकता; शिविरों की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी आवश्यकता; 'मजबूत 'मेनडेट' जारी किए जाने के मुद्दे पर उचित सावधानी; और मजबूत आक्रामक अभियानों में सैनिकों के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय

करने पर बल देता आ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से प्राप्त अनुरोध के आधार पर इस अवधि के दौरान भारत ने गोमा (डीआरसी) और जुबा (दक्षिण सूडान) में 15 चिकित्सा कर्मियों की दो चिकित्सा टीमों तैनात की। मोनुस्को के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुख्य केंद्र गोमा, डीआरसी में स्थित है। गोमा में भारत की सहायता से निर्मित अस्पताल जनवरी, 2005 से चालू है, जिसमें 18 विशेषज्ञों सहित 90 भारतीय नागरिक हैं। इस क्षेत्र में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए, "लेवल-3" सुविधा, जो एक तैनात की गई संयुक्त राष्ट्र इकाई द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा देखभाल का उच्चतम स्तर है, को अब लेवल-3 प्लस सुविधा में अद्यतन किया जा रहा है। दिसंबर 2016 से चालू जुबा, दक्षिण सूडान (अनमिस) में भारत द्वारा "लेवल-2 प्लस" अस्पताल में 12 विशेषज्ञों सहित 77 भारतीय नागरिक हैं। जुबा में भारतीय सुविधा वर्तमान में दक्षिण सूडान में मौजूद चिकित्सा सुविधाओं के उच्चतम स्तर में से एक है। इस सुविधा को अब लेवल-2 प्लस से लेवल-3 सुविधा में अद्यतन किया जा रहा है।

सुरक्षा परिषद चुनाव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए गैर-स्थायी सीटों के लिए चुनाव 17 जून, 2020 को आयोजित किए गए थे। भारत, एशिया-प्रशांत समूह का समर्थन प्राप्त उम्मीदवार था और नए सिरे से आरंभ कर रहा था। डाले गए 192 वोटों में से भारत ने 184 वोट हासिल किए और दिनांक 01 जनवरी 2021 को सुरक्षा परिषद में अपनी सीट हासिल की। यह आठवीं बार है जब भारत सुरक्षा परिषद में अपनी सेवाएं दे रहा है। चुनावों के

दौरान, भारत ने "एनओआरएमएस: न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्मड थीम मल्टीलेटरल सिस्टम" के अति महत्वपूर्ण विषय के तहत पांच प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रगति के लिए नए अवसर, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया, बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण और मानवीय स्पर्श के साथ प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

ईसीओएसओसी चुनाव

भारत को तीन ईसीओएसओसी निकायों के सदस्य के रूप में भी चुना गया था- महिलाओं की स्थिति पर आयोग, जनसंख्या और विकास संबंधी आयोग, और

दिनांक 14 सितंबर, 2020 को आयोजित चुनावों में कार्यक्रम और समन्वय के लिए समिति।

अंतर-संसदीय संघ

अंतर-संसदीय संघ की शासी परिषद का 206 वां सत्र दिनांक 01-04 नवंबर 2020 को वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र में भाग लिया। सितंबर में हुए चुनावों में भारत को महिलाओं की स्थिति संबंधी आयोग का सदस्य चुना गया था। भारत, अफगानिस्तान और चीन

ने एशिया-प्रशांत समूह में दो सीटों के लिए चुनाव लड़ा जिसमें भारत और अफगानिस्तान विजेता के रूप में उभर रहे हैं। भारत को समन्वय और आयोग संबंधी समिति तथा जनसंख्या और विकास संबंधी आयोग के लिए भी चुना गया था Int.

गुटनिरपेक्ष आंदोलन

प्रधानमंत्री ने दिनांक 04 मई, 2020 को आयोजित कोविड-19 पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (एनएएम) संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें 30 से अधिक अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के साथ कोविड-19

महामारी के संबंध में प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई। "यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19" विषय पर ऑनलाइन गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह शिखर सम्मेलन को अजरबेजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के अध्यक्षता में आयोजित किया

गया था, ताकि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा दिया जा सके और महामारी से निपटने के लिए राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को जुटाया जा सके। इस कार्यक्रम में शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीयता और कूटनीति दिवस भी मनाया गया।

प्रधानमंत्री की भागीदारी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति भारत की पुरानी प्रतिबद्धता को अपने प्रमुख संस्थापक सदस्य के रूप में रेखांकित किया। अपने हस्तक्षेप में, प्रधानमंत्री ने इस संकट के प्रति विश्व द्वारा समन्वित, समावेशी और न्यायसंगत प्रतिक्रिया के महत्व पर बल दिया, जिसमें भारत द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों को रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री ने विशेषरूप से आतंकवाद और फर्जी समाचारों जैसे अन्य

बहुपक्षीयता के लिए एलायंस

दिनांक 26 जून, 2020 को, 'एलायंस फॉर मल्टीलेटरिज्म' ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ मनाने के लिए एक वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की। अपने पूर्व दर्ज वीडियो संदेश में ईएएम ने इस बात को रेखांकित किया कि आज दुनिया दोनों एक महामारी और एक 'इन्फोडेमिक' दोनों का सामना करना पड़ रहा है और यह कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक गतिशील बहुपक्षीय आदेश समय की मांग है।

लोकतंत्र संबंधी पहल

लोकतंत्र का समुदाय, राष्ट्रों का एक वैश्विक अंतरसरकारी गठबंधन है ताकि एक विश्वभर में लोकतांत्रिक नियमों और लोकतांत्रिक मानदंडों तथा संस्थानों को सुदृढ़ करने के सामान्य लक्ष्य की प्राप्त हितु सरकारों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को एक साथ लाया जा सके। इसने दिनांक 26 जून, 2020 को वर्चुअल पद्धति से वारसाँ घोषणापत्र की 20वीं वर्षगांठ लगभग मनाई। राज्य मंत्री ने रिकॉर्डेड संदेश के माध्यम से इस कार्यक्रम में वक्तव्य दिया।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (आईआईडीईए) की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिनांक 19 से 20 नवंबर, 2020 को 'डेमोक्रेसी नॉओ एंड नेक्स्ट' विषय पर एक वर्चुअल वैश्विक वर्षगांठ सम्मेलन आयोजित

तपेदिक पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने डब्ल्यूएचओ और रूसी परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए गए "प्रोग्रेस एंड मल्टी सेक्टरल एकशन टूवर्ड्स एचिविंग ग्लोबल टार्गेट टू एंड टीबी" विषय पर दिनांक 23 सितंबर,

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर मंत्रिस्तरीय बैठक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 को आयोजित उच्च स्तरीय कार्यक्रम में "वन ईयर कमेमोरेशनऑफ द हाई लेवल मीटिंग: मेजरिंग प्रोग्रेस, चैलेंजिज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन द कॉन्टेक्ट ऑफ

वायरसों के विरुद्ध विश्व द्वारा किए जाने वाले निरंतर प्रयास के महत्व पर भी बल दिया।

दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 को, राज्य मंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वार्षिक मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जो लगभग 75वें यूएनजीए सत्र के साथ साथ आयोजित की गई थी। "बांडुंग+65: मोर रेलेवेट, यूनाइटेड एंड इफेक्टिव एनएएम अगोस्ट एमरजिंग ग्लोबल चैलेंजिज़ इन्क्लूडिंग कोविड-19" विषय पर बोलते हुए उन्होंने विभाजनकारी मुद्दों को उठाने की बजाय एक साथ खड़े होने और एक स्वर में बोलने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

दिनांक 25 सितंबर 2020 को जलवायु परिवर्तन, साइबर स्पेस, लिंग और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर एक और वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई। ईएएम ने भागीदारी करते हुए फिनटेक प्लेटफार्मों, नवीकरणीय ऊर्जा और टीकों के क्षेत्र में नई क्षमताओं का निर्माण करके विश्व अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में भारत के योगदान के बारे में बताया।

किया गया था। राज्य मंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए एक बधाई वीडियो संदेश दर्ज किया जिसमें लोकतंत्र के महत्व और विश्वभर में लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में आईआईडीईए के योगदान को रेखांकित किया गया।

भारत ने सामुदायिक सक्रियता, चुनावी प्रक्रियाओं, लैंगिक समानता, मीडिया और सूचना की स्वतंत्रता, कानून और मानवाधिकारों के शासन, सरकार के साथ नागरिक समाज संपर्क को मजबूत करने, ज्ञान और युवाओं के जुड़ाव के लिए साधन सहित विश्वभर में लोकतंत्र संबंधी पहल का समर्थन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में भी 1,50,000 अमरीकी डॉलर का योगदान दिया।

2020 को आयोजित कार्यक्रम में एक पूर्व-दर्ज किया गया संदेश दिया। यह सह-आयोजन तपेदिक पर वर्ष 2018 की संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक के दो वर्ष होने पर आयोजित किया गया था।

कोविड-19" विषय पर आयोजित एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम में वक्तव्य (पूर्व रिकॉर्डेड) दिया।

'कोविड-19 टूल्स एक्सीलेटर (एसीटी-एक्सीलरेटर)' तक पहुंच पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने दिनांक 30 सितंबर, 2020 को "टैक्लिंग कोविड-19 टूगेदर थ्रू द एसीटी-एक्सलरेटर" विषय पर आयोजित

एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में (वर्चुअल तरीके से) भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) का उच्च स्तरीय खंड

प्रधानमंत्री ने दिनांक 17 जुलाई 2020 को ईसीओएसओसी के उच्च स्तरीय खंड में स्वागत भाषण दिया। सत्र का विषय था "मल्टीलेट्रीज्म ऑफ्टर काविड 19: वॉट काइन्ड ऑफ यूएन डू वी नीड एट द 75 एनिवर्सिरी?" विषय पर प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी में एसडीजी को प्राप्त करने के लिए भारत

की प्रतिबद्धता और कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किए गए कार्यों जैसे कई विषयों को छुआ। प्रधानमंत्री ने सुधार बहुपक्षीयता और मानव केंद्रित वैश्वीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला।

भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा

सतत् विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा के अनुवर्ती और समीक्षा के भाग के रूप में, सदस्य देशों द्वारा 17 एसडीजी की प्राप्त की दिशा में की गई प्रगति की नियमित समीक्षा करते हैं। इन स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षाएं (वीएनआर) को हर वर्ष जुलाई माह में इसीओएसओसी के तत्वावधान में आयोजित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (एचएलपीएफ) में प्रस्तुत की जाती हैं। भारत ने वर्ष 2017 एचएलपीएफ में अपना पहला वीएनआर प्रस्तुत किया और दिनांक 13 जुलाई, 2020 को आयोजित 2020 एचएलपीएफ में अपना दूसरा वीएनआर

वर्चुअल पद्धति से प्रस्तुत किया। नीति आयोग के उप सभापति ने भारत का वीएनआर प्रस्तुत किया। हमारे दूसरे वीएनआर में, हमने उप-राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों, नागरिक समाज के संगठनों, स्थानीय समुदायों, असुरक्षित स्थितियों में रह रहे लोगों और निजी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए "संपूर्ण समाज" पद्धति में आमूल-चूल परिवर्तन किया। एसडीजी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को "सबका साथ सबका विकास" के हमारे आदर्श वाक्य में यथा परिलक्षित राष्ट्रीय विकास एजेंडे को रेखांकित करते हुए प्रस्तुत किया गया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

यह साल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (2019-2021) में भारत की तीन साल की सदस्यता का दूसरा साल था। भारत ने अन्य बातों के साथ-साथ मानवाधिकार परिषद (एचआरसी) के सत्रों, वार्षिक मंच की बैठकों, अंतरसरकारी कार्य समूह की कार्यवाहियों और मानवाधिकार संघि निकायों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अपने कार्य और भागीदारी जारी रखा। एचआरसी के 44वें (जून 2020) और 45 वें (सितंबर 2020) सत्रों के दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण, तकनीकी सहायता और सहयोग एवं क्षमता निर्माण पर अपने समर्थन को उद्भूत करना जारी रखा। भारत ने चार संकल्पों यथा कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के प्रस्ताव; 'मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन'; 'न्यायपालिका, जूरी सदस्यों और मूल्यांकनकर्ताओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता, और वकीलों की स्वतंत्रता';

'फिलीपींस में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण' को सह प्रायोजित किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर से भारत मानवाधिकारों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने, मानवाधिकार और एकतरफा बलपूर्वक प्रयोग तथा 'विकास का अधिकार' संबंधी संकल्पों हेतु मुख्य प्रायोजक था। भारत ने विशेष रूप से 'बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय', जलवायु परिवर्तन, 'मध्यलिंगी लोगों के अधिकार' और अन्यो के साथ 'तकनीकी सहायता और क्षमता वर्धन' एवं गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किए गए मानवाधिकारों के विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त वक्तव्यों के साथ भी स्वयं को जोड़ा। भारत ने 28 सदस्य देशों से संबंधित सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा प्रक्रिया के चल रहे तीसरे चक्र में अपनी भागीदारी जारी रखी, जिसकी समीक्षा 2020 में की गई थी। 45 वें सत्र में, भारतीय उम्मीदवार को एचआरसी द्वारा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को अक्टूबर 2020 से जून 2021 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के शासी निकाय (जीबी) का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ने 02-14 नवंबर 2020 से वर्चुअल

मोड में आयोजित आईएलओ के शासी निकाय के 340 वें सत्र की कार्यवाही की अध्यक्षता की। श्रम और रोजगार मंत्री ने 08-09 जुलाई, 2020 को आईएलओ द्वारा आयोजित उच्च स्तरीय वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्यूएचए) का 73वां सत्र जिनेवा में 18-19 मई 2020 और 09-14 नवंबर 2020 को कोरोनावायरस महामारी के कारण एक आभासी प्रारूप में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किया। 18-19 मई 2020 को डब्ल्यूएचए सत्र में कोविड 19 पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे भारत द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। इस प्रस्ताव के कारण महामारी हेतु तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया गया ताकि डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पूर्व सचिव को स्वतंत्र पैनल के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत ने दिसंबर 2020 में स्वतंत्र पैनल में डब्ल्यूएचओ सुधारों पर एक दृष्टिकोण पत्र प्रस्तुत किया। भारत को मई 2020 से 3 साल की अवधि के लिए डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) के लिए चुना गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को एक वर्ष की

अवधि के लिए 21 मई 2020 को डब्ल्यूएचओ के ईबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। भारत ने 05-06 अक्टूबर 2020 को आयोजित ईबी के विशेष सत्र और 16 नवंबर 2020 को आयोजित ईबी के नियमित सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भारत ने जीएवीआई, ग्लोबल फंड आदि जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न परामर्शों और समन्वय बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। आयुर्वेद दिवस 2020 के अवसर पर डब्ल्यूएचओ ने भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की घोषणा की। केंद्र का उद्देश्य पारंपरिक और पूरक चिकित्सा के बारे में साक्ष्य, अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को मजबूत करना होगा। केंद्र डब्ल्यूएचओ की पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2014 से 2023 तक लागू करने के डब्ल्यूएचओ के प्रयासों में भी सहायता करेगा।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के साथ भारत के संबंधों में 2020 में और प्रगति हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने डब्ल्यूआईपीओ के एक प्रमुख कार्यक्रम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) की रिपोर्ट को जारी करने में भाग लिया। भारत की वैश्विक रैंकिंग इस साल जीआईआई में

और सुधर कर 48 पर पहुंच गयी, जो 2015 के बाद से 33 स्थानों की छलांग है। डब्ल्यूआईपीओ के ग्लोबल डिजाइन डाटाबेस और ग्लोबल ब्रांड डाटाबेस ने भारत के 2 मिलियन ट्रेडमार्क अवधारणाओं और 58000 से अधिक डिजाइन मॉडलों के राष्ट्रीय संग्रह को जोड़ा।

शरणार्थी और प्रवासी

भारत ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में इसके कार्यकारी और स्थायी समितियों के सदस्य के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम)

द्वारा आयोजित बैठकों में भी भाग लिया, विशेष रूप से अक्टूबर 2020 में आयोजित 5वें विशेष सत्र में जिसमें आईओएम संविधान में संशोधन किया गया।

दक्षिण केंद्र

भारत और दक्षिण केंद्र के बीच चल रहे सहयोग तंत्र 2020 में जारी रहा। अप्रैल 2020 में श्री मोहनदास पाई को दक्षिण केंद्र के शासी बोर्ड का सदस्य

नियुक्त किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी)

भारत ने 2020 में यूएनसीटीएडी की सभी बैठकों में सक्रिय और रचनात्मक रूप से भाग लेना जारी रखा। यूएनसीटीएडी निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार,

भारत 2019 में शीर्ष 10 एफडीआई प्रवाह स्थलों में शामिल था।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)

दूरसंचार विभाग के सचिव ने 22 जून से 10 सितंबर 2020 तक जिनेवा में आभासी रूप से आयोजित सूचना सोसायटी (डब्ल्यूएसआईएस) फोरम संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय नीति संबंधी सत्र में भाग लिया। इस

कार्यक्रम का विषय “डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना: सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूएसआईएस कार्य रूपरेखा” था। भारत ने आईटीयू की साझेदारी में फरवरी-मार्च 2022 में

हैदराबाद, तेलंगाना में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (डब्ल्यूटीएसए-21) की मेजबानी करने का प्रस्ताव किया है। यह पहले नवंबर 2020 में आयोजित

किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन

नवंबर 2020 में ब्रिटेन के ग्लासगो में होने वाले जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय (यूएनएफसीसीसी) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था कांफ्रेंस ऑफ पार्टिज (सीओपी-26) की 26वीं बैठक को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब यह नवंबर 2021 में होगी।

प्रधानमंत्री ने 22 नवंबर 2020 को जी-20 शिखर सम्मेलन के इतर आयोजित कार्यक्रम ‘द सेफगार्डिंग द प्लैनेट - द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी अप्रोच’ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत 2022 के लक्ष्य वर्ष से पहले अच्छी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के 175 जीडब्लू के लक्ष्य को पूरा करेगा तथा 2030 तक 450 जीडब्लू हासिल करने की कोशिश करेगा।

ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस के साथ मिलकर इटली और चिली की साझेदारी में 12 दिसंबर 2020 को पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आभासी जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का सह-आयोजन किया। जलवायु परिवर्तन संबंधी यूएनएफसीसीसी का पेरिस समझौता 01 जनवरी

आर्कटिक काउंसिल

भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में आर्कटिक काउंसिल के साथ अपना कार्य करना जारी रखा और 17-19 नवंबर 2020 को एसएओ (वरिष्ठ आर्कटिक अधिकारियों) की पूर्ण आभासी बैठक में भाग लिया। भारत ने आर्कटिक काउंसिल को अपनी द्विवार्षिक पर्यवेक्षक रिपोर्ट भी सौंपी जिसमें आर्कटिक

2021 से प्रभावी है। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की राह पर है, बल्कि उम्मीदों से आगे है। भारत ने 2005 के स्तर से अधिक उत्सर्जन तीव्रता में 21% की कमी की है। भारत वन क्षेत्र के विस्तार और जैव विविधता की सुरक्षा में भी सफल रहा है। प्रधानमंत्री ने दो प्रमुख वैश्विक पहलों-अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा लचीला बुनियादी ढांचा (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2047 में एक आधुनिक, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 100 साल का जश्न मनाएगा और वादा किया कि सौ साल का भारत न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा, बल्कि उम्मीदों से आगे भी जाएगा।

प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड सरकार और ग्लोबल कमीशन फॉर अडॉप्शन (जीसीए) द्वारा आयोजित 25 जनवरी 2021 को वर्चुअल क्लाइमेट अडॉप्शन सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत जीसीए के सह संयोजकों में से एक है।

जैव विविधता सम्मेलन

जैव विविधता पर पहला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 30 सितंबर 2020 को उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान “सतत विकास हेतु जैव विविधता पर तत्काल कार्रवाई” विषय पर आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में 140 से अधिक सदस्य देशों की आभासी भागीदारी थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भी एक पूर्व में रिकॉर्ड किए गए वीडियो वक्तव्य के जरिए

सम्मेलन में हिस्सा लिया। अपने बयान में मंत्री महोदय ने जैव विविधता के संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 26 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित और वनों की कटाई वाली भूमि पर फिर से वन लगाना और 2030 तक भूमि-क्षरण तटस्थता हासिल करना है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी)

भारतीय मिशन ने क्रमशः 30 अप्रैल 2020 और 14 सितंबर 2020 को आभासी रूप से आयोजित यूएनईपी के स्थायी प्रतिनिधियों की समिति की

150 वीं और 151 वीं बैठकों में भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र- पर्यावास

संयुक्त राष्ट्र पर्यावास के कार्यकारी बोर्ड के 2020 का पहला सत्र 29 जून 2020 को ऑनलाइन आयोजित किया गया था। भारत 36 सदस्यीय

कार्यकारी बोर्ड का सदस्य है। भारतीय मिशन ने संयुक्त राष्ट्र- पर्यावास के 2020 कार्यकारी बोर्ड के दूसरे सत्र में भी भाग लिया जिसे 27 से 29 अक्टूबर

2020 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)

यूनेस्को की गतिविधियों और कार्यक्रमों पर कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस प्रकार, यूनेस्को ने संगठन के कामकाज के लिए आगे की राह पर विचार-विमर्श करने के लिए 08-09 जून 2020 से छठे विशेष सत्र का आयोजन किया।

किया गया था। सत्र में भारत के राष्ट्रीय वक्तव्य में शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। भारत ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 21 सदस्यीय अंतःसरकारी समिति के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन निर्वाचित नहीं हो सका।

कार्यकारी बोर्ड का 209वां अधिवेशन 02-10 जुलाई 2020 से आयोजित

बीजिंग महिला सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 'लैंगिक समानता लाने में तेजी लाने और सभी महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तिकरण' विषय के तहत 01 अक्टूबर 2020

को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में एक वक्तव्य (पूर्व दर्ज) दिया।

अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस

02 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक आभासी स्मरणोत्सव का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने "गांधी की 150वीं जन्मशती: शांति और विकास के लिए अहिंसक

दृष्टिकोण" विषय के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र में 20 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों के स्थायी प्रतिनिधियों के विशेष संदेश भी देखे गए। अपने संदेशों में वक्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र के लिए गांधीवादी सिद्धांतों की सतत प्रासंगिकता और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

21 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो के रूप में संयुक्त राष्ट्र के मंचों के माध्यम से "स्वास्थ्य हेतु योग – आवास से योग" विषय पर एक आभासी समारोह का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजजानी मुहम्मद-बांदे ने समारोह में भाग लिया और विशेष रूप से मौजूदा महामारी की स्थिति के संदर्भ में योग के महत्व को रेखांकित करते हुए एक भाषण दिया।

डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र-जल द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत, नाइजीरिया और सिंगापुर के स्थायी मिशनों ने 19 नवंबर 2020 को विश्व शौचालय दिवस का आयोजन किया। इस वर्ष इसका विषय 'सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन' था।

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी

संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक संचार में हिंदी का उपयोग (संयुक्त राष्ट्र के समाचार, संयुक्त राष्ट्र रेडियो और संयुक्त राष्ट्र के सोशल मीडिया पर साप्ताहिक ऑडियो बुलेटिन) मार्च 2018 में किसी भी देश के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षरित पहले समझौता ज्ञापन के बाद शुरू हुआ। तब से हमने संयुक्त राष्ट्र की हिंदी

वेबसाइट और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित उसकी सोशल मीडिया साइटों पर हिंदी सामग्री की माला और आवृत्ति में लगातार वृद्धि देखी है। हिंदी के उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र के साथ हुए एमओयू को 2025 तक पांच साल और बढ़ा दिया गया है।

13

बहुपक्षीय आर्थिक संबंध

जी20

इस वर्ष जी20 के लिए कोविड-19 महामारी के प्रति हमारे प्रयास एक ऐसी वैश्विक प्रतिक्रिया का सुनिश्चय करने पर केन्द्रित रहे हैं जिससे मानव केन्द्रित, समावेशी एवं संवहनीय विकास हो सके। प्रधानमंत्री द्वारा महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करने और वैश्विक समन्वित प्रतिक्रिया देने के लिए 26 मार्च 2020 को सऊदी राष्ट्रपति के साथ असाधारण वर्चुअल जी 20 शिखर सम्मलेन में भाग लिया गया था। शिखर सम्मेलन में, नेताओं ने कोविड -19 वैश्विक महामारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का सामना करने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक के योगदान के लिए प्रतिबद्ध किया। ऋण सेवा स्थगन पहल के अंतर्गत कम आय वाले देशों के लिए सरकार द्वारा सरकारी ऋण के लिए अस्थायी निलंबन की भी घोषणा की गई थी और इसे लागू किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री ने वर्चुअल स्वरूप में दिनांक 21-22 नवंबर, 2020 को सऊदी अरब द्वारा आयोजित 15वें जी20 शिखर सम्मलेन में भाग लिया। यह शिखर सम्मलेन "21 सदी में सभी को अवसरों को साकार करने का अनुभव प्रदान करने" के थीम पर केन्द्रित था। शिखर सम्मलेन के अंत में स्थायी भविष्य के

निर्माण के लिए लचीली और समावेशी पुनर्प्राप्ति का निर्माण करने वाले तत्वों का निर्माण करने की घोषणा को भी अंगीकार किया गया था।

सऊदी अरब की अध्यक्षता में 3 सितम्बर, 2020 को जी 20 के अध्यक्ष सऊदी अरब द्वारा 03 सितंबर 2020 को आयोजित की गई जी20 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक में विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्री द्वारा परीक्षण एवं संगरोध प्रक्रियाओं एवं "मूवमेंट तथा ट्रांजिट के प्रोटोकॉल के मानकीकरण के साथ "जी20 के सिद्धांतों के अनुसार लोगों की समन्वित क्रॉस बार्डर मूवमेंट" का स्वैच्छिक निर्माण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

भारत के जी20 शेरपा ने भी खोबार, सऊदी अरब में 11-12 मार्च, 2020 को आयोजित जी20 शेरपा बैठक तथा दिनांक 25 मार्च, 2020, 29-30 सितम्बर एवं 27-29 अक्टूबर, 2020 को आयोजित आभासी बैठक में भाग लिया। जी20 वित्त एवं स्वास्थ्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन 17 सितम्बर, 2020 को किया गया था जिसमें विद्यमान संकट की स्थितियों के समाधान के लिए सुदृढ़ आर्थिक लोचकता एवं विकास को अंगीकार करने का एक संयुक्त विवरण प्रस्तुत किया गया था।



22 नवंबर 2020 को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर ग्रह की सुरक्षा के लिए नेतृत्व पक्ष कार्यक्रम में प्रधान मंत्री

विदेश मंत्रियों द्वारा वैश्विक महामारी के मद्देनजर भारत की ओर से आरोग्य सेतु एप्प जारी किए जाने, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज तथा भारत की ओर से लगभग 85 देशों को दवाओं एवं स्वास्थ्यउत्पादों की आपूर्ति किए जाने जैसे विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला गया । ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की दूसरी वर्चुअल

बैठक 4 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जिसमें वैश्विक स्थिति और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरों और चुनौतियों पर केंद्रित चर्चा हुई। ब्रिक्स एनएसए की 10 वीं बैठक 17 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी, जिसमें वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा के खतरों पर चर्चा की गई थी।

आईएसबीए

विदेशी मंत्री द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। बैठक में, आईबीएसए मंत्रियों ने आईबीएसए सहकार्यता का संवर्धन करने तथा आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, निशःस्त्रीकरण, अप्रसार में मामलों सहित वैश्विक महत्व के विभिन्न मुद्दों तथा दक्षिण-दक्षिण

सहकार्यता पर चर्चा हुई। उन्होंने अपने-अपने देशों में कोविड -19 की स्थिति पर अपने अनुभव भी साझा किए। गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन के लिए आईबीएसए निधि के उपयोग से किए गए कार्यों की सलाहना की गई। इस अवसर पर, मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ के साझा प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर आईबीएसए संयुक्त मंत्रिस्तरीय वक्तव्य भी जारी किया।

ब्रिक्स



प्रधान मंत्री द्वारा 17 नवंबर, 2020 को 12वें ब्रिक्स सम्मेलन में प्रतिभागिता

प्रधान मंत्री द्वारा वर्चुअल स्वरूप में “वैश्विक स्थिरता, सहभाजित सुरक्षा और अभिनव दृष्टिकोण” विषय पर रूस द्वारा आयोजित 12 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया गया। नेताओं ने वैश्विक संदर्भ में इंटर-ब्रिक्स सहयोग और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, कोविड -19 महामारी के जारी प्रभाव को कम करने के उपाय, आतंकवाद निवारण, व्यापार, स्वास्थ्य,

ऊर्जा और व्यक्तियों के मध्यविनिमय क्रियाओं में सहकार्यता शामिल हैं। शिखर सम्मेलन के अंत में मास्को घोषणा को अंगीकार किया गया था। भारत द्वारा रूस से 1 जनवरी, 2013 को 13 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व ग्रहण किया।

रूस की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में रूस,

14

विकास सहकार्यता



विकास साझेदारी प्रशासन (डीपीए) का गठन जनवरी 2012 में संकल्पना, प्रक्षेपण, निष्पादन और पूर्णता के चरणों के माध्यम से भारत की विकास सहायता परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए किया गया था। डीपीए मंत्रालय में प्रादेशिक प्रभागों के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है, जो उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करने में भागीदार देशों के साथ प्रमुख संभाषी हैं। डीपीए परियोजना निर्माण, मूल्यांकन,

कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के चरणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में परियोजनाओं को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता को उत्तरोत्तर विकसित कर रहा है।

ऋण सहायता

पिछले कुछ वर्षों में भारत के विकास सहायता का एक प्रमुख पहलू अन्य विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर लाइन ऑफ़ क्रेडिट (एलओसी) का विस्तार या ऋण का विस्तार करना है। इन वर्षों में, 31.6 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक के कुल 308 एलओसी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों को विस्तारित किए गए हैं, जिनमें से 12.87 बिलियन अमरीकी डालर अफ्रीकी देशों के लिए हैं, 16.4 बिलियन अमेरिकी डालर एशियाई देशों के लिए और 2.43 बिलियन लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और कॉमनवेल्थ ऑफ़ इंडिपेंडेंट स्टेट्स देशों के लिए विस्तारित किए गए हैं। समीक्षाधीन वर्ष (अक्टूबर 2020 तक) के दौरान, विभिन्न देशों के लिए लगभग 1.36 बिलियन अमरीकी डालर के 9 एलओसी विस्तारित किए गए हैं। 6 एलओसी परियोजना को 2020-21 (31 अक्टूबर 2020 तक) में पूरा किया गया है। भौगोलिक रूप से, एलओसी

अब रूस और मध्य एशियाई देशों तक बढ़ा दिया गया है। रक्षा, कनेक्टिविटी, आईसीटी, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल रिफाइनरी, जल और स्वच्छता आदि जैसे नए क्षेत्रों में वित्त पोषण परियोजनाओं के लिए क्षेत्र में एलओसी का विस्तार किया गया है।

सभी पूर्ण एलओसी परियोजनाओं में से 90% से अधिक परियोजनाएं निर्धारित बजट के भीतर पूरी हुई हैं। तथापि, कुछ जटिल उच्च मूल्य वाली एलओसी परियोजनाएं इस तथ्य के कारण विलंबित हो गईं कि इन्हें विश्व के दूरस्थ और अल्प-विकसित क्षेत्रों में मुश्किल ऑपरेटिंग वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा था, लगभग एक तिहाई एलओसी परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हो गई हैं।

ऋण सहायता का उद्देश्य

लाइन ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से, भारत परियोजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों जैसे परियोजना निर्माण, तकनीकी अध्ययन और उपयुक्त परियोजना प्रबंधन सलाहकारों और निष्पादन कंपनियों की पहचान करने में भागीदार देशों की मदद कर सकता है। लाइन ऑफ़ क्रेडिट के अंतर्गत भागीदार देशों को कम ब्याज दरों, 5 साल की लंबी अधिस्थगन अवधि और 20-25 वर्षों की विस्तारित पुनर्भुगतान अवधि का लाभ मिलता है। साझेदार देशों में अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं

के आधार पर क्षेत्रों की पहचान करने और परियोजनाओं को चुनने में बहुत लचीलापन है। इसके अलावा, चूंकि लाइन ऑफ़ क्रेडिट के अंतर्गत किसी भी विकास परियोजना का पर्याप्त भाग स्थानीय उप-ठेकेदारों द्वारा स्थानीय सामग्री का उपयोग करके किया जाता है, अतः इससे स्थानीय उद्योग और साझेदार देशों में अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है।

ऋण सहायता को विदेश में प्रोत्साहन

भारत सरकार सोशल मीडिया, मासिक समाचार पत्र इत्यादि के माध्यम से विश्व भर में लाइन ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से विकास साझेदारी पहल का विसृत प्रचार कर रही है। नई डिजिटल आउटरीच पहल के अंतर्गत एलओसी पर नियमित अपडेट के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है। हमारे मिशन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर एलओसी समझौतों पर हस्ताक्षर, शिलान्यास और प्रारंभिक समारोह, उद्घाटन समारोह आदि जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर इसके महत्व को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

देश	नवीन एलओसी स्वीकृति	राशि (यूएसडी मिलियन)
गुआना	कानकन तथा नजेरेकोरे में क्षेत्रीय अस्पताल का निर्माण एवं उन्नयन	20.51
केन्या	पावर ट्रांसमिशन लाइनें, सबस्टेशन तथा समबद्ध अवसंरचना	93
नाइजीरिया	दो सौर परियोजनाएं: (i) बाउची में 50 मेगावाट पावर प्लांट, (यूएसडी 66.60 मिलियन) (ii) नाइजीरिया के छः राजनैतिक जोनों में सौर पीवी नवीकरणीय ऊर्जा सूक्ष्म उपयोग्यता (आईईएमयू) (यूएसडी 8.36 मिलियन)	74.96
सियेरा लियोने	चार समुदायों के लिए विद्यमान पेय जल की सुविधाओं का पुनरूद्धार	15
एस्वातिनी	नए पार्लियमेंट भवन का निर्माण	108.28
मालदीव	ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना	400
श्रीलंका	सौर परियोजनाएं	100
सिरिया	तिश्रीन थर्मल पावर परियोजना, 100 मिलियन डालर तथा 40 मिलियन डालर के दो नए एलओसी भाग	140
उजबेकस्तान	सोशल अवसंरचना तथा अन्य विकास परियोजनाएं	448

व्ययितनाम	4 अपतटीय पेट्रोल वैसलूलस	180
व्ययितनाम	हाई स्पीड गार्ड बोट	120
व्ययितनाम	सबमेरनि बैटरियों की 10 यूनिटें	50
व्ययितनाम	सबमेरनि रोधी युद्धपोत 159ए तथा 159 एई (पेटया श्रेणी शपि) का उन्नयन	150
केन्या	<ul style="list-style-type: none"> 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत केन्या में ट्रकों पर माउंट की गई ड्रिलिंग रिग एंड टेस्टिंग पंप यूनिट । 15 मिलियन अमरीकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ केन्या में स्टीम बॉयलर और वाष्प का चूषण करने वाले चिलर्स का निर्माण । 15 मिलियन अमरीकी डॉलर के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत केन्या में बायोमास ब्रिकेटिंग संयंत्र की आपूर्ति । 	
म्यांमार	<ul style="list-style-type: none"> म्यांमार को लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत विस्तारित 86.31 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की लुकास निर्मित हाइड्रोलिक री-रेलिंग उपकरण और डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की आपूर्ति । म्यांमार को लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत विस्तारित 86.31 मिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की कास्ट मैंगनीज स्टील क्रॉसिंग तथा टर्नआउट के लिए हैड हार्डनड स्विच (स्पीपर बियर्स के साथ) और फिशिंग उपकरण सहित एडॉप्टर रेल की आपूर्ति । म्यांमार को लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत विस्तारित 86.31 मिलियन डॉलर मूल्य की कैरिज और वैगन के लिए स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति । 	

विकास साझेदारी: पड़ोसी पहले

अफगानिस्तान

भारत गंभीर सुरक्षा चुनौतियों के बावजूद अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और विकास के प्रयासों में निरंतर भागीदार रहा है। अफगानिस्तान के लिए भारत की विकास सहायता का मुख्य केंद्र अफगान नागरिकों की क्षमता और सार्वजनिक सेवा के वितरण और सामाजिक-आर्थिक अवसरचना को विकसित करने, सुरक्षित जीवन जीने और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए अपने संस्थानों का निर्माण करना रहा है।

अफगानिस्तान की कुछ प्रमुख भारतीय परियोजनाएँ काबुल (2015) में नए 'पार्लियमेंट भवन, और अफगान भारत मैत्री बांध, जिसे पहले सलमा बांध (2016) के नाम से जाना जाता था, हैं जो एक संयुक्त, लोकतांत्रिक और समृद्ध अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं। दोनों देशों ने अफगानिस्तान को भारत की विकास सहायता को और बढ़ाने के लिए सितंबर 2017 में 'न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप' शुरू की है। भारत ने शतूत बांध परियोजना शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, जो काबुल के निवासियों को मौजूदा सिंचाई और जल निकासी नेटवर्क के पुनर्वास के लिए पीने का पानी प्रदान करेगी और परियोजना के लिए आवश्यक परीक्षण और सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

भारत अनुदान सहायता प्रदान करके अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में विस्तारित उच्च प्रभाव की सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) के लिए सहयोग कर रहा है। 2005 के बाद से, भारतीय अनुदानों द्वारा वित्तपोषित और कृषि, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले सामुदायिक-आधारित परियोजनाओं के 4 चरणों को अफगान सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया गया है और इस प्रकार परियोजना

प्रबंधन के लिए स्थानीय क्षमता का निर्माण किया गया है। 2005-2009 के दौरान कार्यान्वित प्रथम चरण I और II के तहत 116 परियोजनाओं के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान किए गए थे। 2012 में शुरू किए गए चरण III के अंतर्गत, 420 परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण प्रदान किया गया था, जिनमें से 336 पूर्ण हो चुके हैं।

शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए समर्थन अफगानिस्तान के साथ भारत की विकास साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा प्रशासित अफगान नागरिकों की विशेष छात्रवृत्ति योजना (एसएसएसएएन) के अंतर्गत, पूरे भारत में विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अध्ययन के लिए अफगान छात्रों को 1000 वार्षिक छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2006 से, 10,000 से अधिक अफगान छात्रों को इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों के शहीदों के बच्चों / आश्रितों और कृषि अध्ययन के लिए 614 फैलोशिप, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से प्रशासित एक और 500 छात्रवृत्ति स्लॉट प्रदान किए जाते हैं। भारत कंधार में अफगानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएनएएसटीयू) की स्थापना के लिए भी सहयोग कर रहा है जो अफगानिस्तान में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है।

अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान, भारत ने कोविड -19 की चुनौतियों के बावजूद अनुदान सहायता के रूप में अफगानिस्तान सरकार को 75,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की है।

म्यांमार

भारत म्यांमार में तीन प्रमुख सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान कर रहा है जिसका उद्देश्य म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सड़क नेटवर्क का निर्माण करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना है। कलादान मल्टी मोडल

ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (केएमएमटीटीसी) परियोजना के अंतर्गत म्यांमार के सितवे में एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बनाया गया है। सितवे बंदरगाह को पलटेवा से जोड़ने वाली कलादान नदी के खिंचाव को दिक्कचालन के लिए विकसित किया गया है और



भारत से गेहूं की खेप को इरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान के लिए भेजा गया।

पलटेवा में एक अच्छी तरह से पुनर्निर्मित अंतर्देशीय जल टर्मिनल स्थापित किया गया है। भारत-म्यांमार सीमा पर पलेतवा और ज़ोरिनपुई के बीच एक सड़क बनाने के लिए भी काम चल रहा है। भारत ने म्यांमार में भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) लिपक्षीय राजमार्ग से संबंधित दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन को समर्थन दिया है, अर्थात्, 69 पुलों का फिर से निर्माण और तमू-काइगोन-कालवा सड़क खंड (150 किलोमीटर) और उनके अपग्रेड में उनका दृष्टिकोण कालवा-यार्गी सड़क खंड (120 किलोमीटर)। एक बार पूरा हो जाने के बाद, लिपक्षीय राजमार्ग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों म्यांमार, थाईलैंड और अन्य एशियन देशों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और माल और यातायात की आवाजाही की सुविधा प्रदान मिल सकेगी।

भारत ने म्यांमार में क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए मांडले में म्यांमार सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईआईटी) की स्थापना और नैपीडाव के पास उन्नत कृषि अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (एसीएआरई) के लिए भी समर्थन प्रदान किया है।

नेपाल

भारत-नेपाल विकाससात्मक साझेदारी से रेलवे, सड़क, बिजली पारेषण लाइन, पुलिस प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अवसरचनात्मक परियोजनाओं सहित परियोजनाओं का विस्तृत प्रसार हुआ है। भारत व्यक्तियों और माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिए नेपाल में रेल संपर्कता का विकास कर रहा है। पहले चरण के तहत, जयनगर-बर्दीबास रेल लिंक (68.72 किलोमीटर) और जोगबनी-बिराटनगर रेल लिंक (18.60 किलोमीटर) का विकास लगभग 950 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। रक्सौल को काठमांडू से जोड़ने वाली एक नई विद्युतीकृत रेल लाइन के निर्माण की प्रक्रिया भारत की कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) द्वारा की जा रही है।

भारत ने माल और यातायात के व्यापार और आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए नेपाल के बीररगंज और बिराटनगर में दो एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) का निर्माण किया है। इन्हें क्रमशः 2018 और 2020 में नेपाल सरकार को सौंप दिया गया था। नेपालगंज और भैरहवा में योजनाबद्ध दो और आईसीपी पर काम शुरू हो गया है। विकास परियोजनाओं के लिए भारत की सहायता के दायरे में, नेपाल-भारत मैत्री पॉलिटेक्निक को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नेपाल के हेटुडा में बनाया जा रहा है। भारत नेपाल को पानुती में नेपाल पुलिस अकादमी बनाने में भी सहायता कर रहा है।

श्रीलंका

भारत-श्रीलंका विकास साझेदारी के अंतर्गत जाफना में एक आधुनिक अत्याधुनिक सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण किया गया है। सांस्कृतिक केंद्र में एक 2-मंजिला संग्रहालय, 12-मंजिला शिक्षण टॉवर, एक सभागार ब्लॉक, एक पब्लिक स्क्वायर और सांस्कृतिक प्रदर्शन के लिए एक अस्थायी मंच शामिल है।

इससे पहले, भारत ने 2018 -2019 के दौरान श्रीलंका में कुल 209 एम्बुलेंस के साथ एक द्वीप व्यापक आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा स्थापित करने में मदद की थी।

मालदीव

भारत और मालदीव के बीच अनुदान और एलओसी सहायता दोनों में विकास की साझेदारी बढ़ रही है। 2019 में पूरी होने वाली परियोजनाओं में माले में स्ट्रीटलाइट्स की स्थापना, रुपे कार्ड लॉन्च करना, अडसु एटोल में मछली प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना पर सीजीएस कामियाब और समझौता ज्ञापनों का उपहार शामिल है।

भारत मालदीव के लिए एक नए रक्षा मंत्रालय भवन के निर्माण में सहायता कर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। भारत की सहायता से निर्मित माफ़िलाफ़ुशी द्वीप में समग्र प्रशिक्षण केंद्र में अतिरिक्त सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया गया है।

वर्ष 2020 के दौरान, मालदीव भारत की कोविड संबंधित सहायता का सबसे बड़ा प्रापक रहा है। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर और 400 मिलियन अमरीकी डालर के एलओसी के माध्यम से समर्थन की घोषणा की है।

मॉरीशस

पोर्ट लुई में मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट का पहला चरण भारत - मॉरीशस विकास साझेदारी के अंतर्गत बनाया गया था और 2020 में चालू किया गया था, जो पहले साल में रिकॉर्ड संख्या में राइडरशिप के साथ सफल प्रमाणित हुआ है। पोर्ट

पड़ोसी देशों के लिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट

लाइन ऑफ़ क्रेडिट के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाले देशों के संबंध में किए गए विकास प्रयासों में विशेष रूप से भारत के पड़ोस में स्थित देशों के मामले में भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति का अनुसरण किया गया है:

बांग्लादेश: भारत सरकार द्वारा विस्तारित लाइन ऑफ़ क्रेडिट का पोर्टफोलियो बांग्लादेश के मामले में सबसे अधिक है। भारत ने बांग्लादेश सरकार को 7.862 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि 4 एलओसी के अंतर्गत के अंतर्गत विस्तारित की है, जिसमें रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर एलओसी शामिल है। इन एलओसी के अंतर्गत 46 परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें से 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

अनुदान सहायता के साथ विकास परियोजनाएं

पड़ोसी देशों में भारत सरकार अनुदान सहायता के साथ की जा रही विकास परियोजनाएं अवसंरचना के विकास से लेकर निर्माण, सड़क और पुल, जलमार्ग और ट्रांसमिशन लाइनों जैसे बिजली उत्पादन, कृषि, क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों की एक श्रृंखला को समाहित करती हैं।

श्रीलंका हाउसिंग परियोजना: श्रीलंका के साथ भारत की विकास साझेदारी एक

मध्यएशिया क्षेत्र में विकास साझेदारी

विदेश मंत्री द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को आयोजित भारत-मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रों में प्राथमिकता वाले विकासात्मक परियोजनाओं के लिए 5 मध्य एशियाई देशों यथा कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उजबेकिस्तान और किर्गिस्तान के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर की भारतीय एलओसी की

लुइस में भारत से 28.12 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान सहायता के साथ निर्मित नई सुप्रीम कोर्ट की इमारत का उद्घाटन 30 जुलाई 2020 को प्रधान मंत्री और मॉरीशस के प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। मॉरीशस में किए गए अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना और क्षमता निर्माण परियोजनाएं में

ईएनटी अस्पताल का निर्माण तथा पोर्ट लुइस में सामाजिक आवास परियोजना और मॉरीशस में प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए ई-टैबलेट परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। भारत ने पोर्ट लुइस में एक सिविल सेवा कॉलेज के निर्माण के लिए अनुदान सहायता भी प्रदान की है। अगस्त 2020 में मॉरीशस के तट पर प्रलयकारी तेल-रिसाव के मद्देनजर, भारत ने तेल-रिसाव नियंत्रण कार्यों में सहायता के लिए 30 टन तकनीकी उपकरण और सामग्री भेजी है।

मालदीव: भारत सरकार ने मालदीव के लिए 1.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 4 विस्तारित किए हैं। मालदीव में सबसे बड़ी इंफ्रा परियोजना ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना की घोषणा इस वर्ष की गई है।

मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना इस परियोजना में माले, विलिंगिली, गुलिफाल्हू और थिलाफुशी द्वीपों को जोड़ने के लिए पुल, काँजवे और सड़क के 6.7 किमी लंबे संयोजन का निर्माण शामिल है। यह देश की सबसे लंबी कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक है और यह संभावना है कि यह मालदीव के लिए आर्थिक रेखा का आधार बनेगी।

परामर्शात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो श्रीलंका सरकार की प्राथमिकताओं को विचार में लेकर बनाई गई है। श्रीलंका में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के पुनर्वास के लिए 50,000 घरों के निर्माण के लिए जारी आवासीय परियोजना अच्छी प्रगति कर रही है। उत्तरी और पूर्वी प्रांतों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए 46,000 घरों के निर्माण और मरम्मत के कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

पेशकश की घोषणा की गई है।

अफ्रीका में विकास परियोजनाएं

अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी सहयोग और विकास के अनुभवों के साझाकरण पर आधारित है, और यह अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों को संबोधित करने पर केंद्रित है। विभिन्न विकास साझेदारी पहलों के माध्यम से अफ्रीकी देशों के साथ की गई संलिप्तता में पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। 2008, 2011 और 2015 में तीन भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन [आईएएफएस I, II और III] ने महाद्वीप के साथ विकास साझेदारी को और मजबूत किया है।

भारत सरकार द्वारा बिजली संयंत्रों, पनबिजली, बिजली पारेषण और वितरण नेटवर्क, बांधों, सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, कृषि और सिंचाई, औद्योगिक इकाइयों, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों में 12.87 बिलियन अमरीकी डालर की कुल 211 एलओसी का विस्तार किया गया है। कौशल विकास, नागरिक निर्माण

अन्य विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुदान परियोजनाएं

दक्षिण-दक्षिण सहकार्यता के प्रति भारत द्वारा अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आर्थिक सहयोग और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से अनुदान सहायता परियोजनाओं के माध्यम से विकासात्मक सहायता प्रदान की जा रही है। इस संदर्भ में, मलावी में एक बिजनेस इनक्यूबेटर सेंटर स्थापित किया गया है और बेलीज में इंडो-बेलीज सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग और जंजीबार में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (वीटीसी) भारतीय अनुदान सहायता के तहत स्थापित किया जा रहा है।

मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए की प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए डीपीए II जारी रखा गया है और डीबीआरके को 1 मिलियन

आईडीईएस दिशानिर्देशों का पुनः निर्धारण

भारत सरकार भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत 2005-06 से विकासशील देशों के लिए एलओसी का विस्तार किया जा रहा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंजूरी के साथ 2010 और 2015 में 5 साल की अवधि के लिए आईडीईए योजना को दो बार बढ़ाया गया है। एलओसी के लिए मौजूदा आईडीईएस दिशानिर्देश 2015 में जारी किए गए थे। योजना के महत्व और रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, आईडीईए योजना का विस्तार अगले 5-वर्ष की अवधि अर्थात 2020-2025के लिए प्रस्तावित किया गया है। विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय

जी 20 ऋण सेवा निलंबन पहल

अत्यधिक गरीब देशों पर कोविड -19 के अप्रत्याशित प्रभाव के कारण, जी 20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने 15 अप्रैल 2020 को आयोजित एक बैठक में अत्यधिक गरीब देशों के लिए आधिकारिक द्विपक्षीय लेनदारों द्वारा ऐसे ऋण सेवा भुगतान के निलंबन के मुद्दे पर सहमति व्यक्त की जो इसे वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। इस जी 20 डीएसएसआई के मानक टैम्पलेट के

आदि नए क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, रक्षा और सौर ऊर्जा को भी भारत सरकार ने अफ्रीका के लिए एलओसी के अंतर्गत शामिल किया है। अफ्रीका में भारत द्वारा कुछ बड़ी प्रतिष्ठित परियोजनाओं में संसद भवन, कन्वेंशन सेंटर आदि का निर्माण शामिल है। पेयजल और स्वच्छता और ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में लोग उन्मुख परियोजनाएं अफ्रीकी देशों में भी की जा रही हैं। भारत सरकार ने अफ्रीका के विभिन्न देशों में सीमेंट प्लांट्स, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आदि जैसे पहले विनिर्माण उद्योग स्थापित किए हैं। भारत सरकार द्वारा कई अनुदान सहायता परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिनमें 27 मिडी बसों (30 + 1) सीटर को सोमालिया, तंजानिया को 10 एम्बुलेंस, माली को 5 एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरण और लाइबेरिया को सीटी स्कैन मशीन की आपूर्ति शामिल है।

अमरीकी डालर मूल्य की टीबी-रोधी दवाओं के प्रापण और अन्य 1 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की गेहूं की आपूर्ति का निष्पादन किया गया है। भारत ने 20,000 लीटर मालाथियन प्रदान करके टिड्डियों के हमलों से निपटने में ईरान के अनुरोध पर भी प्रतिक्रिया दी है। वाना क्षेत्र में संघर्ष-ग्रस्त देशों के साथ हमारे निरंतर जुड़ाव के अंतर्गत डीपीए II ने फिलिस्तीन को कैसर रोधी दवाओं की खरीद और आपूर्ति में सहायता दी है, दक्षिण सूडान और डिजबोटी को खाद्य सहायता; कोमोरोस को चिकित्सा और खाद्य सहायता का एक व्यापक पैकेज वर्तमान में निष्पादित किया जा रहा है।

और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के बीच व्यापक विचार-विमर्श किया गया और अन्य मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया गया है। दिसंबर 2015 में जारी मौजूदा आईडीईएस दिशानिर्देशों के लिए समीक्षा करने और फिर से अभ्यास करने का निर्णय लिया गया है।

2020-2025 से अगले 5- साल की अवधि के लिए भारतीय विकास और आर्थिक सहायता (आईडीईए) योजना के प्रस्तावित विस्तार के संबंध में, नीति आयोग को आईडीईए योजना की विस्तृत समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।

तदनुसार, सरकार ने जी 20 ऋण सेवा निलंबन पहल के अंतर्गत 13 ऋणी सरकारों यथा कैमरून, डिग्बोटी, इथोपिया, लेसोथो, मलावी, मोज़ाम्बिक, म्यांमार, कांगो गणराज्य, सेनेगल, तंजानिया, ज़ाम्बिया, टोगो और मालदीव के

ऋण सेवा निलंबन राहत के लिए किए गए अनुरोध को मंजूरी दे दी है। अन्य एलओसी- प्राप्तकर्ता देशों से प्राप्त अनुरोधों पर भी तदनुसार विचार में लिया जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी)

भारत सरकार के प्रायोगिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में आइटेक कार्यक्रम की उपस्थिति 160 देशों में है और इसने 1964 में इसकी शुरुआत के बाद से 2,00,000 पेशेवरों की क्षमताओं का संवर्धन दिया है। भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति का एक सशक्त औजार होने के अतिरिक्त आइटेक कार्यक्रम दक्षिण-दक्षिण सहयोग में क्षमता निर्माण पहलों का भी नेतृत्व कर रहा है।

आईटीईसी द्वारा न केवल शासन के पारंपरिक क्षेत्रों में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है, अपितु यह एआई, नैनो टेक्नोलॉजी, फोरेसिक और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए भी विस्तारित किया गया है। आईटीईसी अब भाग लेने वाले पेशेवरों को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके कार्यक्रमों और पंजीकरणों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, एनएलयू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के माध्यम से अपने प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करता है। भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक शक्तिशाली उपकरण

आईटीईसी के अंतर्गत नागरिक प्रशिक्षण

वर्तमान स्थिति के अनुसार, विभिन्न आईटीईसी कार्यक्रमों के अंतर्गत विकासशील देशों में नागरिक पेशेवरों के लिए भारत में 98 संस्थानों में 383 पाठ्यक्रमों में लगभग 12000 प्रशिक्षण स्लॉट के माध्यम से आईटीईसी सामग्री प्रदान की जाती है। इन नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा, विदेशी सरकारों से प्राप्त अनुरोध के आधार पर समय-समय पर देश विशेष से संबंधित विशेष पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम विशिष्ट क्षमता निर्माण आवश्यकताओं जैसे अंग्रेजी भाषा (विभिन्न खाड़ी, मध्य एशियाई और एलएसी देशों के लिए), योग प्रशिक्षक, फोरेसिक जांच और पुलिस प्रशिक्षण (सेशेल्स के लिए), शिक्षकों के लिए दक्षता-सह-व्यावसायिक विकास पाठ्यक्रम (बांग्लादेश), एथलेटिक्स (मालदीव) के लिए, सिविल सेवकों के लिए मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (बांग्लादेश और म्यांमार), आतिथ्य और पर्यटन प्रबंधन (कंबोडिया) इत्यादि के लिए हैं।

भौतिक /भारत में दिये जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त तीन अन्य व्यापक चैनलों के माध्यम से भी नागरिकों के लिए ऑनलाइन तथा रीयल-टाइम प्रशिक्षण दिया जाता है। आइटेक ऑनसाइट चैनल के अंतर्गत अल्प समय के लिए प्रशिक्षण पेशेवरों को प्रतिनियुक्त करके उसी देश में प्रशिक्षित करने के लिए हमारे भागीदार देशों को स्व-निर्धारित विषय-वस्तु मुहैया कराया जाता है। इन कार्यक्रमों की विषय-वस्तु मुख्यतः उर्वरक प्रौद्योगिकी; मत्स्य प्रौद्योगिकी; कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान; मुफ्त शिक्षा संसाधन; प्रतिभूति बाजार; पवन उर्जा; ग्रामीण विद्युतीकरण; दक्षिण-दक्षिण सहयोग इत्यादि

होने के अलावा, आईटीईसी कार्यक्रम ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग में क्षमता निर्माण की पहल में नेतृत्व का भार भी ग्रहण किया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कोविड -19 वैश्विक महामारी के प्रकोप और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण इन-पर्सन आईटीईसी पाठ्यक्रम काफी सीमा तक निलंबित रहे हैं। मंत्रालय ने 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लागू करने के समय भारत में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में फंसे लगभग 1200 आईटीईसी प्रशिक्षकों के सफल प्रत्यावर्तन का आयोजन किया था। इसके बाद आईटीईसी कार्यक्रम को ऑनलाइन ई-आईटीईसी पाठ्यक्रमों के माध्यम से जारी रखा गया है, जो व्यापक रूप से जन स्वास्थ्यआपूर्ति एवं कोविड-19 के प्रबंधन की रणनीतियों पर केंद्रित था। इस अवधि के दौरान कुल 20 ऐसे ई-आईटीईसी पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जनवरी-मार्च 2021 की अवधि के दौरान कुल छह और आईटीईसी विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया जाना है।

जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भागीदार देशों की जरूरतों पर केन्द्रित होते हैं। आइटेक एक्ज्यूक्यूटिव तीसरा चैनल है जो हमारे भागीदार देशों में वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम है; यह चैनल सम्मलेनों कार्यशालाओं एवं अध्ययन/ बाहरी दौड़ों के माध्यम से विषय-वस्तु को प्रस्तुत करता है जिससे भारत की प्रथाओं एवं प्रणालियों के बारे में समझ भी बनती है।

वित्त वर्ष 2020-21 में, कोविड -19 के कारण निर्धारित नियमित भौतिक / इन-इंडिया पाठ्यक्रम, आईटीईसी ऑनसाइट कार्यक्रम या आईटीईसी-एक्ज्यूक्यूटिव कार्यक्रमों में से कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका है। तथापि, डिजीजन ने ई-आईटीईसी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक नियमित कैलेंडर जारी रखा है। प्रकोप की शुरुआत में सार्क देशों के संबंध में प्रधान मंत्री की प्रतिक्रिया में, डिजीजन ने तुरंत सार्वजनिक स्वास्थ्य और कोविड -19 प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 12 ई-आईटीईसी पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। इन पाठ्यक्रमों को एम्स और पीजीआई, चंडीगढ़ जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में वितरित किया गया। बांग्लादेश के अनुरोध की प्रतिक्रिया में बांग्ला भाषा में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सार्वजनिक स्वास्थ्य के अलावा, ई-आईटीईसी पाठ्यक्रम भी लिंग समावेशी गवर्नेंस, चुनावी व्यवस्था, पारंपरिक चिकित्सा / आयुर्वेद और विपासना ध्यान जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर आयोजित किए गए थे।

आईटीईसी के अंतर्गत रक्षा प्रशिक्षण

वर्ष 2020-21 के दौरान, भागीदार देशों को 1351 रक्षा प्रशिक्षण स्लॉट आवंटित किए गए थे। तटरक्षक मुख्यालय द्वारा सुरक्षा और रणनीतिक अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मरीन हाइड्रोग्राफी, काउंटरइन्सर्जेंसी और जंगल युद्धकला, समुद्री कानून और परिचालन पाठ्यक्रम पर ये कवर पाठ्यक्रम वैसे आयोजित किए गए थे जैसे एनडीसी, नई दिल्ली और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के प्रमुख भारतीय संस्थानों में तीन सेवाओं

में युवा अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम भी स्थापित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में, पहला रक्षा ई-आईटीईसी पाठ्यक्रम कोविड -19 के प्रबंधन और रोकथाम के विषय पर कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पीडीआर और वियतनाम के चिकित्सा अधिकारियों के लिए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं की सहायता से संचालित किया गया था।

आईटीईसी विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति

वर्तमान स्थिति के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों के 37 विशेषज्ञ स्वास्थ्य, कृषि, आपदा प्रतिक्रिया, पुरातत्व, आयुर्वेद, कानूनी विशेषज्ञ और अंग्रेजी शिक्षक आदि के क्षेत्रों में भागीदार देशों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। कई रक्षा प्रशिक्षण टीमों को तंजानिया,

वियतनाम में भी प्रतिनियुक्त किया गया है। म्यांमार, सेशेल्स, नामीबिया, लाओ पीडीआर। युगांडा में मौजूदा आईएमटीटी टीम के प्रतिस्थापन के लिए जीएसएल जारी किए गए हैं।

सांस्कृतिक कूटनीति और विकास साझेदारी

विश्व भर में सांस्कृतिक कूटनीति भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एक लंबे समय से प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग रही है। भारत विभिन्न साझेदार देशों में सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण परियोजनाओं में शामिल रहा है। मंत्रालय ने डीपीए के भीतर जनवरी 2020 में विरासत संरक्षण के लिए एक समर्पित प्रभाग बनाया है। भारत सरकार की वर्तमान सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण गतिविधियाँ उत्खनन, मंदिरों की बहाली और अन्य धरोहरों / धार्मिक स्थलों जैसे

मस्जिदों और भित्ति-स्थलों से लेकर भित्ति चित्र, संग्रहालय से संबंधित कार्य, आइकोग्राफिक सर्वेक्षण, वियतनाम में माई सोन मंदिर परिसर की पुनर्स्थापना शामिल हैं। ता प्रोम और कंबोडिया में प्रीह विहेयर मंदिर, और लाओ पीडीआर में वात फु मंदिर कुछ प्रमुख चालू परियोजनाएँ हैं जो प्रभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।



वाट फोउ हिन्दू मंदिर काम्प्लेक्स, लाओ पीडीआर

15

आर्थिक राजनय

आर्थिक व्यवहार नीति डिवीजन (ईडी) द्वारा अपने प्रयासों में वर्ष 2020-21 के दौरान ढेरों प्रयास करके देश की विदेश नीति की आर्थिक व्यवहार्यता के आयाम

पर ध्यान केंद्रित दिशानिर्देशन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की तृतीय महासभा

डिवीजन द्वारा नोडल मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समन्वय करके आईएसए की तीसरी महासभा को आयोजित करने में प्राप्त सहायता से 14 अक्टूबर 2020 को एक अनुकूलित वर्चुअल मंच पर आयोजित की गई थी। बैठक में विश्व भर से 53 से अधिक सदस्य देशों ने भाग लिया। ईडी डिवीजन द्वारा विदेश में स्थित मिशनों एवं पोस्टों के माध्यम से गहन आउटरिच करते हुए आईएसए महासभा की अध्यक्षता के एक और कार्यकाल के लिए में भारत के पुनः चयन की प्रक्रिया की गई थी तथा तीसरी महासभा में आईएसए के सदस्य देशों ने एकमत से भारत का चयन आईएसए महासभा के अध्यक्ष के रूप

में अर्थात वर्ष 2022 तक के लिए किया गया।

अब तक, 88 देशों ने आईएसए के फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इनमें से 70 देशों ने फ्रेमवर्क करार की पुष्टि की है। 03 अक्टूबर 2018 को आयोजित आईएसए की पहली आम सभा के दौरान, आईएसए महासभा ने भारत के प्रस्ताव आईएसए की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के लिए खोलने के फ्रेमवर्क में संशोधन करने पर विचार किया। अब तक 38 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की संशोधित रूपरेखा को स्वीकार कर लिया है / पुष्टि कर दी है।

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए सहकार्यता

ईडी डिवीजन द्वारा आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के निर्माण हेतु सहकार्यता का समन्वय किया जाता है। कॉशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) के कामकाज का समन्वय करता है। सीडीआरआई की प्रथम शासी परिषद की बैठक दिनांक 20 मार्च 2020 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री के

प्रधान सचिव और व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति, यूनाइटेड किंगडम के राज्य सचिव की सह-अध्यक्षता में हुई थी। सीडीआरआई की कार्यकारी समिति की पहली बैठक 29 जून 2020 को आयोजित की गई थी, जिसमें बिजली, हवाई अड्डे और स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं सहित कई

महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। वर्तमान में, 18 राष्ट्रीय सरकारों के 22 सदस्य तथा 4 बहुपक्षीय संगठन सीडीआरआई में शामिल हैं। आपदा प्रतिरोधी संरचना (आईसीडीआरआई 2021) का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वर्चुअल स्वरूप में 17-19 मार्च 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा।

सीडीआरआई ने सदस्यता के लिए सात देशों को संज्ञान में लिया है- नीदरलैंड, इंडोनेशिया, रूस, कनाडा, मैक्सिको, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका। मंत्रालय इन देशों की सदस्यता के लिए मेजबान सरकारों सहित सीडीआरआई के साथ मिलकर समन्वय कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 53 वां सत्र

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था का मुख्य कानूनी निकाय है। विश्व भर में वाणिज्यिक कानून सुधार में 50 से अधिक वर्षों की विशेषज्ञता से युक्त सार्वभौमिक सदस्यता वाले कानूनी निकाय यूएनसीआईटीआरएएल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का आधुनिकीकरण और सामंजस्य करने के कार्य किए जाते हैं। यूएनसीआईटीआरएएल की स्थापना महासभा (17 दिसंबर 1966 के संकल्प 2205) द्वारा 1966 में की गई थी। आयोग की स्थापना करते हुए महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय कानूनों में असमानताओं से व्यापार के प्रवाह में उत्पन्न बाधाओं को संज्ञान में लिया था और आयोग को एक ऐसे वाहन की संज्ञा दी गई जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ऐसी बाधाओं को कम करने या हटाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

यूएनसीआईटीआरएएल छह कार्य समूहों के माध्यम से अपना काम करता है जिन्हें समय-समय पर करने के लिए विशिष्ट विषय सौंपे जाते हैं। ईडी डिवीजन ने सितंबर, 2020 में यूएनसीआईटीआरएएल के 53 वें सत्र और इसके अंतर-सत्र कार्य समूहों में भाग लिया है। ये सत्र वाणिज्यिक कानून के कई प्रमुख क्षेत्रों में विधायी और गैर-विधायी साधनों के उपयोग और प्रोत्साहन को तैयार करने और बढ़ावा देने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कानून को संगत बनाने और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से आयोजित किए गए थे। डिवीजन के अधिकारियों ने कोरियाई न्याय मंत्रालय और एशिया प्रशांत के यूएनसीआईटीआरएएल क्षेत्रीय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भी भाग लिया था। डिवीजन द्वारा नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी के प्रयासों का भी समन्वय भी किया गया था जो महामारी के कारण आगे नहीं बढ़ सका था।

भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक कॉन्क्लेव

मध्ययूरोप डिवीजन द्वारा आर्थिक कूटनीति डिवीजन के सहयोग से, और सीआईआई ने 05 नवंबर 2020 को प्रथम भारत-नॉर्डिक-बाल्टिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। विदेश मंत्री उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता थे, डेनमार्क,

एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड और लातविया द्वारा भी इसमें मंत्रालयीनस्तर पर प्रतिभागिता की गई थी।



विदेश मंत्री दिनांक 5 नवंबर, 2020 को भारत-नॉर्डिक कॉन्क्लेव में भाग लेते हुए

सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए)

सामाजिक सुरक्षा करार की विस्तृत परिभाषा यह है कि ये भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय करार होते हैं जो सीमा पार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए किए गए हैं, अर्थात्, विदेशों में काम करने वाले भारतीय, साथ ही साथ उन करारबद्ध देशों के नागरिक जो भारत में काम कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा करार का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के श्रमिकों को 'नो कवरेज' या डबल कवरेज' से बचाव करने तथा समानता का व्यवहार प्रदान करना है।

द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारों से भारतीय व्यवसायिकों के हितों की रक्षा होती है, विदेशों में काम करने वाले कुशल श्रमिकों को तीन लाभ प्रदान होते

नागर विमानन

नागरिक विमानन फ्रंट पर, डिवीजन द्विपक्षीय विमान सेवा परक्रामण के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करता है। डिवीजन इन मुद्दों पर और पर्यटन को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय / बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उड़ान संचालन या कोड शेयर की आवश्यकता पर भी इनपुट प्रदान करता है। डिवीजन ने यूके, इज़राइल, बांग्लादेश, जापान, यूएई और सऊदी अरब के साथ किए गए परक्रामण में भी भाग लिया है।

कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के दौरान, अंतरराष्ट्रीय उड़ान परिचालन पूरी तरह से रूक गया था। न्यूनतम आवश्यक विमान सम्पर्कता को बहाल करने के लिए, देश-वार आधार पर देश में एयर बबल परिवहन व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, नागर विमानन मंत्रालय ने राजनयिक नोटों के माध्यम से विभिन्न देशों से संपर्क करने के लिए इस मंत्रालय को अनुरोध भेजना शुरू

द्विपक्षीय निवेश संधियां (बीआईटी)

भारत सरकार से सम्बद्ध द्विपक्षीय निवेश संधियां (बीआईटी) तथा निवेशक राज्य विवाद समाधान (आईएसडीएस) विवाचन मामलों: ईडी डिवीजन सक्रिय रूप से निवेश संधि परक्रामण में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता करता है तथा ऐसे परक्रामण के समन्वय और नीति / राजनीतिक दृष्टिकोण से और अंतरराष्ट्रीय कानून के नजरिए से अपेक्षित इनपुट प्रदान करता है। भारत द्वारा अपनी पूर्व युग की निवेश संधियों के समापन की प्रक्रिया की जा रही है और सक्रिय रूप से 30 से अधिक देशों के साथ 2015 के नए मॉडल बीआईटी पर आधारित द्विपक्षीय निवेश संधियों पर परक्रामण किया जा रहा है। निवेश संधियों से संबंधित मामलों में मूल देश / विदेशी संबंध शामिल होते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून से संबंधित मुद्दे भी शामिल होते हैं। विदेश मंत्रालय बीआईटी परक्रामण का अभिन्न अंग है तथा इसके द्वारा अपेक्षित इनपुट भी प्रदान की जाती है। अन्य देशों के साथ बीआईटी के बारे में पलाचार मंत्रालय के माध्यम से नोट वर्बलिज्म, इत्यादि ईडी डिवीजन के माध्यम से किया जाता है जो निवेश संधि या ऐसे मामलों के लिए मंत्रालय में नोडल प्रभाग है।

भारत को 30 निवेश संधियों के संबंध में 100 बिलियन अमेरिकी डालर से भी अधिक संचयी राशि के दावों का सामना करना पड़ा है। इसके मामले विभिन्न चरणों में हैं तथा इनमें कुछ ऐसे मामले भी शामिल हैं निर्णय हो चुका हैं। भारत सरकार के अंतर-मंत्रालयी समूह के एक हिस्से के रूप में डिवीजन आवश्यक

हैं- वे दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान करने से बचते हैं; लाभों का आसान प्रेषण (निर्यात क्षमता); और लाभ के नुकसान (टोटलाइजेशन) को रोकने के लिए योगदान अवधि (दो देशों में) एकल करना है। मंत्रालय सामाजिक सुरक्षा करार परक्रामण के लिए “सक्षम प्राधिकारी” है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सामाजिक सुरक्षा करार के प्रावधानों को संचालित करने और अधिनियम के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को कवरेज के प्रमाण पत्र (सीओसी) जारी करने के लिए संपर्क एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। अब तक, भारत ने कुल 19 देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

कर दिया। विदेश मंत्रालय ने इस प्रक्रिया में गहन भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय द्वारा दोनों देशों के पाल यालियों के संदर्भ में नागर विमानन मंत्रालय को इनपुट की सुविधा प्रदान करने, अन्य देशों के साथ नियम और शर्तों पर परक्रामण करने और एयर बबल परिवहन व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न देशों के नागर विमानन मंत्रालयों और नागरिक उड्डयन अधिकारियों के बीच सक्रिय रूप से समन्वय करने की प्रक्रिया की गई है। इसके परिणामस्वरूप, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, नाइजीरिया, जापान, केन्या, यूक्रेन, ओमान, इराक, फ्रांस, जर्मनी, तंजानिया, रवांडा, नीदरलैंड, यूएसए, यूके एवं करार नामक 21 देशों के लिए एयर बबल परिचालन किए गए हैं। इसके अलावा, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रूस, इजरायल, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, कजाकिस्तान, मलेशिया और थाईलैंड को एयर बबल के लिए मौखिक नोट जारी किए गए हैं।

इनपुट्स प्रदान करने, सुनवाई की सुविधा प्रदान करने और विदेशी न्यायालयों में इन मामलों में अन्य संबंधित कार्यों की सुविधा और समन्वय करके विवाद के हर चरण में सक्रिय रूप से शामिल है।

ये मामले अंतरराष्ट्रीयट्रिब्यूनलों की विदेश स्थित पीठों के सम्मुखविचाराधीन हैं और इनमें अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रश्न समाहित हैं जिनके लिए मंत्रालय से परामर्श प्राप्त किया जाता है। डिवीजन ने “भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियों” विषय पर संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में भी भाग लिया था, जहाँ भारत और इससे जुड़ी निवेश संधियों सहित ऐसी संधियों के तहत होने वाले विवादों पर चर्चा हुई थी।

अब तक, भारत के खिलाफ निवेशकों द्वारा 35 विवाद नोटिस दिए गए हैं, जिनमें से भारत ने 04 विवाचनों में सफलता प्राप्त की हैं, 04 विवाचनों में असफलता मिली है जबकि 02 विवादों का सौहार्दपूर्वक हल किया गया है और 04 विवादों में, निवेशकों ने अपना दावा वापस ले लिया है। 14 विवाद अभी भी विवाचन के विभिन्न चरणों में सक्रिय हैं और अन्य 07 विवादों में, बीआईपीए के तहत प्रारंभिक अनुरोध के बाद दावेदारों ने मामले का अनुगमन नहीं किया है। जारी विवादों में अन्यों सहित सीसी / देवास, वोडाफोन, खेतान होल्डिंग्स, मैक्सिस कम्प्युनिकेशंस शामिल हैं।

स्थायी विवाचन न्यायालय: स्थायी विवाचन न्यायालय (पीसीए), एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें भारत 1950 से सदस्य है, ने 2008 में भारत के साथ एक स्थायी सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तथापि, यह कार्य प्रगति पर है, पीसीए मेजबान देश समझौते के दायरे में पीसीए-इंडिया कॉन्फ्रेंस और कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है,

बाजार विस्तार क्रियाकलाप

भारतीय उद्योग और व्यापार की बढ़ती मांगों पर विदेशों में हमारे मिशनो / पोस्टों द्वारा प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए इस डिवीजन के पास “बाजार विस्तार क्रियाकलाप” के नाम से एक बजट शीर्ष है। विदेशों में द्विपक्षीय व्यापार के परिमाण (तेल आयात के अलावा) के आधार पर बजट शीर्ष के अंतर्गत मिशन और पोस्ट के लिए धन निर्धारित किए जाते हैं। इस बजट से हमारे वाणिज्यिक पंख प्रभावी ढंग से और समयबद्ध तरीके से भारतीय निजी क्षेत्र की अपेक्षाओं को नियमित व्यापार और निवेश संबंधी पूछताछ से निपटने में सक्षम बन पाए हैं, जो

वेबसाइट तथा वैश्विक मानचित्रण संसाधन

ईडी डिवीजन ने अपनी वेबसाइट को फिर से चालू कर दिया है, जो विदेशी उद्यमों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापारिक वातावरण के साथ-साथ विदेश जाने वाले भारतीय व्यवसायियों में और भारतीय मिशनो और पोस्टों के लिए सभी सूचनाओं की प्राप्ति का वन-स्टॉप स्रोत है। वेबसाइट का एक भाग संसाधन प्लेटफॉर्म के लिए समर्पित है, जहां से तीन क्षेत्रों में विश्व संसाधन एंडोवमेंट (अक्षय निधि) और अवसरों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है:

(क) खनिज संसाधन: यह प्लेटफार्म भारत के लिए खनिज रणनीतिक के वैश्विक भंडार का पता लगाने के लिए वैश्विक एटलस के कार्य करता है।

भारतीय कृषि निर्याता उत्तोलन की रणनीति

ईडी डिवीजन कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग और वाणिज्य विभाग के साथ कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहा है। इसके लिए यह भारत की कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रणनीति के प्रारूप में शामिल किया गया है और एक कार्य योजना के माध्यम से इसके कार्यान्वयन को शामिल किया गया है जिसमें अन्य प्रक्रियाओं के साथ साथ निर्यात प्रोत्साहन, ब्रांड इंडिया और फार्म-टू-टाइम के साथ कृषि-वस्तुओं के लिए खाड़ी अभियानों के लिए समय सीमा सहित देश विशिष्ट रणनीति को शामिल करने के साथ साथ चिन्हित मिशनो में कृषि व्यापार के लिए समर्पित नोडल बिंदुओं का निर्माण के कार्य शामिल किए गए हैं।

यह डिवीजन कृषि निर्यात के लिए ध्यान केन्द्रित किए गए देशों में हमारे कृषि निर्यातों के विस्तार के उद्देश्य से संबंधित कृषि मंत्रालयों के साथ सक्रिय सहकार्यता

औद्योगिक आउटरिच तथा निवेश प्रोत्साहन एवं प्रचार

- भारत-कनाडा कृषि प्रौद्योगिकी:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से ईडी डिवीजन द्वारा इंडो-कैनेडियन बिजनेस चैंबर और सीआईआई ने

जिसमें इस डिजीवन से सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, भारत के अधिकांश निवेश संधि मामलों को पीसीए और डिवीजन द्वारा, हेग में मिशन के माध्यम से प्रशासित किया जाता है, ऐसे मामलों में पीसीए के साथ समन्वय किया जाता है।

उनके अधिकार क्षेत्र के देशों में आर्थिक और व्यावसायिक जलवायु पर जानकारी प्रदान करने के साथ साथ बाजार सर्वेक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, उद्योग संघों आदि को लक्षित करने वाली प्रचार गतिविधियों को संज्ञान में लेकर नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान की पहचान भी करते हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत मिशन / पोस्ट द्वारा किया जाने वाला व्यय “बाजार विस्तार बजट के लिए व्यय दिशानिर्देश” द्वारा नियंत्रित होता है। इस वर्ष प्रभाग ने विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनो / पोस्टों से 10 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

(ख) कृषि निर्यात के अवसर: यह प्लेटफॉर्म भारतीय कृषि उत्पादों को दुनिया भर के देशों में उनकी मांग के केंद्रों के साथ अनुकूलन करता है, इस प्रकार इससे निर्यातकों को कृषि निर्यात के संभावित अवसरों की पहचान में सहायता मिल सकेगी।

(ग) हमारे नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर: भारत की बढ़ती हुई जनसांख्यिकीय लाभ स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह प्लेटफार्म विदेशों में कुशल / अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की पहचान करने में सहायक होगा।

कर रहा है। इस 'देश-विशिष्ट निर्यात रणनीतियों' को, ध्यान केन्द्रित देशों में मिशनो से प्राप्त इनपुट के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर विकसित किया गया है। ये रणनीतियां संज्ञान में लिए गए देशों को निर्यात बढ़ाने के संभावित क्षेत्रों, हमारे निर्यातकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और कदमों और आगे बढ़ने पर केंद्रित हैं। कृषि-निर्यात और खाद्य-प्रसंस्करण को बढ़ाना निकट भविष्य में हमारे प्राथमिक क्षेत्रों में से एक होगा, जो वर्ष 2022 तक हमारे किसान की आय को दोगुना करने के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। चिन्हित लक्षित देशों में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील। चीन, जापान, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन, अमेरिका और वियतनाम शामिल हैं।

और कृषि-खाद्य मंत्री द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत और कनाडा के कई हितधारकों के साथ उत्पादकता संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला को कार्यकुशल बनाने, इष्टतम प्रसंस्करण के समाधानों पर चर्चा के लिए प्लॉट-प्रोटीन एवं कृषि प्रबंधन व्यवस्था पर ध्यान केंद्रण के साथ किया गया था।

- **भारत-अफ्रीका परियोजना भागीदारी पर 15 वां सीआईआई एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव:** ईडी डिवीजन द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और सीआईआई के सहयोग से, भारत-अफ्रीका परियोजना साझेदारी के लिए 22-24 सितंबर 2020 को आयोजित 15 वें सीआईआई एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन करने में सहायता प्रदान की गई है।
- **विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मलेन:** ईडी डिवीजन द्वारा आईएसए सचिवालय और फिक्की के सहयोग से, 08 सितंबर 2020 को सौर के क्षेत्र में नव प्रौद्योगिकियों एवं नवोपायों पर ध्यान केंद्रित वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मलेन के आयोजन में सहायता प्रदान की गई है।
- **भारत म्यांमार वर्चुअल व्यापार सम्मलेन 2020:** डिवीजन ने सीआईआई और संबंधित प्रादेशिक डिवीजन के साथ मिलकर 22 अप्रैल 2020 को भारत म्यांमार वर्चुअल बिजनेस मीट आयोजित करने में सहायता दी है।
- **भारत थाईलैंड डिजिटल सम्मेलन, 2020:** डिवीजन ने सीआईआई और संबंधित प्रादेशिक प्रभाग के सहयोग से, 11 जून 2020 को फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स पर भारत थाईलैंड डिजिटल सम्मेलन और वर्चुअल व्यापार सम्मलेन आयोजित करने में मदद की है।
- **बांग्लादेश के साथ व्यापार:** 29 जून 2020 को, सीआईआई के सहयोग से, डिवीजन ने बांग्लादेश के साथ व्यापार करने पर डिजिटल सम्मेलन के आयोजन में सहायता प्रदान की है।
- **प्रथम भारत एशियान सामुद्रिक व्यापार सम्मलेन एवं प्रदर्शनी :** 04 अगस्त 2020 को, सीआईआई और संबंधित प्रादेशिक डिवीजन के सहयोग से डिवीजन ने प्रथम भारत एशियान सामुद्रिक व्यापार सम्मलेन एवं प्रदर्शनी के आयोजन में मदद की है।
- **वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन 2020:** 15 सितंबर 2020 को, ईडी डिवीजन, आयुष मंत्रालय, सीआईआई और विदेश में स्थित हमारे मिशन और पोस्ट के सहयोग से, वैश्विक मंच पर 'रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आयुर्वेद' विषय पर आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन आयोजित करने में मदद की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

- **आयुर्वेद दिवस 2020:** इस प्रभाग ने 13 नवंबर 2020 को आयुर्वेद दिवस के सफल आयोजन के लिए मिशनों और पदों के साथ समन्वय किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के संदेश का प्रसार भी शामिल था।
- **भारत-फिलीपींस द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंध:** 25 सितंबर 2020 को, डिवीजन ने सीआईआई के सहयोग से भारत-फिलीपींस द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों पर आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन के लिए समन्वयन एवं आयोजन किया गया है।
- **वर्चुअल वैश्विक निवेशक राउंडटेबल:** वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश एवं अवसरचना निधि (एनआईआईएफ) के सहयोग से ईडी डिवीजन ने 05 नवंबर 2020 को आयोजित वर्चुअल वैश्विक निवेशक राउंडटेबल के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की है। इस आयोजन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की और केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसमें प्रतिभागिता की है। राउंडटेबल सम्मेलन में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन और संप्रभु निधियों में से 20 की भागीदारी कुल प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति यूएसडी 6 ट्रिलियन देखी गई है।
- **वर्चुअल डिप्लोमेसी:** ईडी डिवीजन ने अनेक ऐसे डिजिटल वेबिनारों में भाग लिया है, जिनकी मेजबानी बिजनेस चैंबर्स, अकादमिक सर्कल, थिंक-टैंक द्वारा की गई है तथा जिनमें अन्य ों के साथ साथ पीएचडीसीसीआई, नॉसकॉम, सीआईआई, फिक्की, एक्सोचेम जैसे नाम शामिल हैं। भारत द्वारा किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों की सही दिशा के सुनिश्चित के लिए डिजिटल वर्ल्ड का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इस तथ्य को विचार में लेते हुए कि कोविड वैश्विक महामारी से व्यापार मेलों के एक भौतिक आचरण की संभावनाएं उत्पन्न हो सकेंगी और क्रेता-विक्रेता किसी एक पड़ाव पर पहुंचेंगे, हमारे मिशन ऐसे प्रभावी विपणन और संवर्धन रणनीतियों को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल रूप से किए जा सकते हैं। भारतीय व्यापार मंडलों और स्थानीय व्यापार निकायों के बीच वर्चुअल व्यवसाय से व्यवसाय और बी 2 सी बैठकों का आयोजन भी इस कार्यसूची का एक भाग है।
- **व्यापार और आर्थिक आउटरीच उत्पादों का प्रसार:** ईडी डिवीजन द्वारा अन्य प्रक्रियाओं के साथ साथ भारत के नीति वातावरण, नीतिगत निर्णय, निवेश के अवसरों, व्यापार से संबंधित मामलों से सम्बद्ध प्रासंगिक प्रचार, प्रचार और ज्ञान / सूचना सामग्री प्रदान करके आर्थिक और व्यावसायिक आउटरीच गतिविधियों में विदेश में मिशनों / पोस्टों को सहायता की जाती है।

सचिवों का सेक्टरल समूह (एसजीओएस)

ईडी डिवीजन द्वारा सचिव (पूर्व) और सचिव (ईआर) को सहयोग किया जाता है, जो क्रमशः संसाधन और अर्थव्यवस्था पर क्षेत्रीय सचिवों (एसजीओएस) के समूह 3 और 7 में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समूह का व्यापक जनादेश भौतिक सम्पर्कता, प्रतिस्पर्धी अनुमोदनों, निवेशक मित्त नीतियों,

विकासशील निर्यात एवं उच्चतर आयात आश्रिता को कम करके भारत में निवेश के परिवेश में सुधार लाना है। विदेश मंत्रालय से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल को बढ़ाने, सीमा हाट निर्माण, आईसीपीएस, अफ्रीका के साथ विकास साझेदारी, और 3-टी (व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी) में सुधार

किए जाने शामिल हैं। इसके लिए, डिवीजन विशिष्ट सम्पर्कता परियोजनाओं और विकास साझेदारी पहल पर हुई प्रगति पर नियमित रूप से अपडेट प्रदान

कर रहा है।

आत्मनिर्भर भारत प्रयास के लिए समन्वय

- आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत ईडी डिवीजन अन्य देशों में भारत की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रणनीति के निर्माण के लिए मिशनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। डिवीजन ऐसे क्षेत्रों और देशों की पहचान करने की प्रक्रियाएं कर रहा है जिन क्षेत्रों के लिए हमारे निर्माताओं में आयात के लिए कम लागत वाले पसंदीदा विकल्प के रूप में उभरने की क्षमता है। मिशन भारत की छवि को एक ऐसे सुरक्षित और विश्वसनीय गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, जहां संबंधित निवेश संबंधी सभी आवश्यकताओं को सुविधा प्रदान करने की योजना बनाने वाली इकाइयों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, ताकि वे भारत में अपना आधार कोविड के बाद की स्थिति में परिवर्तित कर सकें।
- मिशन हमें अपने संबंधित देशों के संबंध में भारतीय निर्यातकों द्वारा अनुभव की जाने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं से निपटने की आधिकारिक स्वीकृति पर विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। ईडी डिवीजन, मिशनों के सहयोग से, वस्तुओं और सेवाओं की नए क्षेत्रों के साथ-साथ नए गंतव्यों की पहचान करने के लिए भी काम कर रहा है जहां भारत के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है।
- ईडी डिवीजन भारत की छवि को दुनिया की फार्मैसी के रूप में बनाने के लिए मिशनों के साथ काम कर रहा है, जो कि हाल ही में कोविड संकट के दौरान कई देशों को पेरासिटामोल और हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वाइन प्रदान करने

मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमित कोविड रिपोर्टें

मार्च 2020 में, विदेश सचिव ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सचिवों की समिति के सम्मुखकोविड वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव की एक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई जो विदेशों से प्राप्त इनपुट पर आधारित थी। इस प्रयास को जारी रखते हुए, ईडी डिवीजन द्वारा हमारे मिशनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, दुनिया भर में कोविड की स्थिति से संबंधित साप्ताहिक रिपोर्टों का संकलन

3टी - व्यापार, पर्यटन एवं प्रौद्योगिकी के लिए प्रयास

प्रधान मंत्री के निदेशानुसार मंत्रालय 3टी- व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी को भारत में बढ़ावा देने के लिए मिशनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके लिए, मिशनों को उनके आउटरीच प्रयासों में हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है,

के प्रयासों से सुदृढ़ बन गई है। डिवीजन उन मिशनों के साथ निकट समन्वय में काम कर रहा है, जिन्हें भारत में निर्यातकों और निर्माताओं को निर्यात के अवसरों पर वास्तविक समय की जानकारी प्रसारित करने के लिए भारत व्यापार पोर्टल (एफआईआईओ द्वारा व्यवस्था पित) जैसे उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।।

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्याप्त अंतरालों की पहचान करने और तत्काल पूर्णता करने के लिए, मिशन, विदेश मंत्रालय और डीपीआईआईटी के सहयोग से, पहले से ही विभिन्न देशों में स्रोतन और निर्यात के अवसरों की खोज करने की प्रक्रिया तथा संभावित आपूर्तिकर्ताओं एवं क्रेताओं की सम्पर्कता हमारे ईपीसी और उद्योग से करने के लिए निर्यातकों का मार्गदर्शन करने की प्रक्रिया के साथ साथ उनके लिए व्यापार से व्यापार बैठकों की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। ईपीसी / उद्योग निकायों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सीधे हमारे मिशनों के साथ संपर्क करें और आपूर्ति की बाधाओं के जोखिमों को रोकने के लिए और आपूर्ति अंतराल को भरने के लिए जहां भी संभव हो वहां व्यापार से व्यापार बैठकों का आयोजन करें। उद्योग के लिए भी कुछ उत्पाद समूहों के संबंध में प्रशासनिक विभाग सहायता प्राप्त की जा रही है, जिससे उनके उद्योग के स्टैकधारकों तक पहुंचने और उन क्षेत्रों में उत्पादन में तेजी लाई जा सके जहां हम नए और मौजूदा बाजारों में आपूर्ति अंतराल को भरना चाहते हैं।

किया गया था। इन रिपोर्टों को एक साप्ताहिक आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया और विश्व भर में व्याप्त कोविड परिदृश्य पर अद्यतन रखने के लिए इसमें देश की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव और विभिन्न सरकारों द्वारा घोषित देश-विशिष्ट आर्थिक और अन्य राहत उपायों के इनपुट शामिल थे।।

विस्तारित किए जा सके जहां भारत के निर्यात को बढ़ाया जा सकता है;

अपने संबंधित देशों में माल के उन क्षेत्रों को संज्ञान में लेना जिनका भारत में आयात किया जा रहा है परन्तु जो घरेलू विनिर्माण से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं;

राज्य सरकारों के साथ सहकार्यता करके राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए आउटरीच और प्रचार गतिविधियाँ बढ़ाना;

अपने संबंधित देशों में आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त करके भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना;

अपने संबंधित देशों में आर्थिक नेतृत्व एवं अन्य सम्बद्ध स्टेकधारकों के साथ सहकार्यता करके नए अवसर ज्ञात करना;

आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों में वैकल्पिक और विश्वसनीय कम लागत

विभिन्न बोर्डों / समितियों को इनपुट

एएस (ईआर) ईओयू और एसईजेड (ईपीसीईएस) (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), इवैस्ट इंडिया, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईटीएफ), इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ईईपीसी), डब्ल्यूएपीसीओएस, निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) जैसे अनेकों बोर्डों / समितियों का सदस्य है। ईडी डिवीजन के अन्य अधिकारी

ऊर्जा

ईडी डिवीजन अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के साथ भारत के संयुक्त सहयोग का समन्वय करता है। ईडी डिवीजन ने भारत और आईईए के बीच विकसित किए गए द्विवार्षिक कार्य कार्यक्रमों में योगदान दिया है, जिसमें 2015-17 के लिए संयुक्त वक्तव्य और संयुक्त कार्रवाई की अनुसूची (जेएस एवं एसजेए) शामिल है, नीति आयोग और आईईए के बीच मंतव्य विवरण (एसओआई) और साथ ही आईईए और भारत सरकार के बीच 2018-2021 के संयुक्त कार्यक्रम के संबंध में ईडी डिवीजन प्राथमिक समन्वयकारी एजेंसी भी है। ईडी डिवीजन आईईए के साथ भारतीय ऊर्जा मंत्रालयों की प्रतिबद्धताओं की सुविधा प्रदान करने की प्रारंभिक समन्वय एजेंसी भी है। यह प्रभाग भारत के लिए आईईए सदस्यता के लिए संभावित रास्तों सहित संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के लिए एक फ्रेमवर्क / रणनीतिक भागीदारी के लिए आईईए और संबंधित लाइन मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रहा है। बहुपक्षीय मंच पर

जीएफआर, 2017 नियम 144 (XI) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रापण के लिए भूमि सीमा वाले देशों से आपूर्ति प्राप्त करने वाली बिडर्स का पंजीकरण:

अन्य देशों से प्रापण के प्रतिबंधों / सूक्रिनिंग के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (सार्वजनिक प्रापण डिवीजन) द्वारा जीएफआर 2017 के नियम 144 में किए गए संशोधन का अनुसरण करते हुए उद्योग प्रोत्साहन एवं आंतरिक

वाले विनिर्माण गंतव्य के रूप में भारत की छवि को बढ़ावा देना, जहां कोविड के पश्चात् की स्थिति में विनिर्माण इकाइयों को भारत में अपना आधार स्थानांतरित करने की योजना बनाने के लिए निवेश संबंधी सभी आवश्यकताओं को सुगम बनाया जा सकता है;

विदेश में मिशन के माध्यम से मंत्रालय ने 15 लक्षित देशों में कृषि निर्यात की मदों, निर्यात वस्तुओं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान पर कृषि-निर्यात के डेटा प्राप्त किए हैं जहां भारत अंतर को भर सकता है और भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा दे सकता है।

देश में निर्यातकों / निर्माताओं को निर्यात के अवसरों पर समयानुकूल जानकारी का प्रसार करने और वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ विनिर्माण क्षेत्र को एकीकृत करने में मदद करने के लिए भारत व्यापार पोर्टल जैसे उपलब्ध डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देना।

भी मत्स्य सक्विडी, कोल प्रिपेरेशन सोसायटी ऑफ इंडिया (सीपीएसआई), ग्रुप ऑफ कार्टेलिज़ेशन / होर्डिंग ऑफ पल्स, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) जैसी समितियों में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन बोर्डों / समितियों के अभिन्न अंग के रूप में ईडी डिवीजन नियमित रूप से उनकी बैठकों में भाग लेते हैं और विदेश मंत्रालय की आवश्यकता इनपुट उपलब्ध करते और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

भारत की ऊर्जा भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के अलावा, ईडी डिवीजन भी विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद को आगे बढ़ाने से संबंधित मंत्रालयों के समूह का एक भाग है।

कोविड के प्रकोप के दौरान कई देशों के सम्मुखरेगिस्तानी टिड्डियों के खतरों का सामना करना पड़ा था। मंत्रालय ने ईरान को 20000 लीटर कीटनाशक मैलाथियोन 96% यूवी की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया था जिससे उनके सिस्तान बलूचिस्तान और होर्मोज़गन प्रांतों में टिड्डे की घुसपैठ को रोकने में मदद मिल सके। इस प्रस्ताव का ईरान ने स्वागत किया था। तदनुसार, मंत्रालय ने ईरान को 25 टन मैलाथियान 95% यूएलवी के निर्माण और आपूर्ति के लिए एचआईएल के लिए आदेश जारी किया था।

व्यापार विभाग द्वारा विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं सेक्टरल मंत्रालय के सदस्यों से युक्त एक पंजीकरण समिति (आरसी) का गठन किया गया है। ईडी डिवीजन इस समिति में विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पंजीकरण

समिति पंजीकरण के मामलों को तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। विदेश मंत्रालय ने अब तक आयोजित पंजीकरण समिति की सभी 5 बैठकों में भाग लिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने आशय और लक्ष्यों के दृष्टिकोण से पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया की जांच की है और डीपीआईआईटी को पर्याप्त महत्वपूर्ण विस्तृत इनपुट प्रदान किए हैं जिसे बहु-मंत्रालय पंजीकरण समिति द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया है। ये इनपुट आवेदकों से विस्तृत जानकारी लेने और प्रशासनिक

भूमि सीमा वाले देशों के साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के विनियम

भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.04.2020 को जारी किए गए प्रेस नोट 3 के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए हैं, जिससे अब सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों को सरकारी अनुमोदन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एफडीआई नीति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में डीपीआईआईटी ने इस तरह के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण के लिए मुद्दों को देखने और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति (आईएमसी) का गठन किया है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीपीआईआईटी और प्रशासनिक मंत्रालय आईएमसी के सदस्य हैं।

कोविड प्रतिक्रिया

• वंदे भारत मिशन: वंदे भारत मिशन की प्रक्रिया के अंतर्गत, एएस (ईआर) ने 976 उड़ानों में तेलंगाना राज्य में 132,963 व्यक्तियों और 19 नवंबर, 2020 तक 284 उड़ानों में आंध्र प्रदेश राज्य में 38,191 व्यक्तियों की निकासी का व्यवस्था पन किया है। सभी आवश्यक विवरण / मंजूरी / मुद्दे आदि संबंधित राज्यों के साथ सामंजस्य स्थापित, समन्वित और साझा किए गए हैं। इससे विभिन्न देशों से विभिन्न राज्यों से आने वाली भारतीय यात्रियों की सहज निकासी / आवाजाही में सहायता मिली है।

• मंत्रिमंडल सचिवालय को नियमित कोविड रिपोर्टें : मार्च 2020 में, विदेश सचिव ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सचिवों की समिति के सम्मुखकोविड वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव की एक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई जो विदेशों से प्राप्त इनपुट पर आधारित थी। इस प्रयास को जारी रखते हुए, ईडी डिवीजन द्वारा हमारे मिशनों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, दुनिया भर में कोविड की स्थिति से संबंधित साप्ताहिक रिपोर्टों का संकलन

मंत्रालयों के सार्थक परिश्रम प्रक्रिया के लिए प्रोफार्मा का भाग हैं। जैसा कि इनमें से अधिकांश आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीनी संस्थाओं से आपूर्ति कर रहे हैं, ये प्रावधान नीचे की गई सूचीबद्धता के अनुसार महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब तक, मंत्रालय को डीपीआईआईटी से 40 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं, जबकि एक मामले में इनपुट डीपीआईआईटी को भेजे जा चुके हैं।

विदेश मंत्रालय ने डीपीआईआईटी को निम्नलिखित जानकारी सहित इनपुट दिए हैं जो विशेष रूप से चीन और उसके क्षेत्रों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की जांच करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिसमें निवेश की वांछनीयता; स्थानीय प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव; रोजगार सृजन की संख्या और तकनीकी / तकनीकी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के संदर्भ में मूल्यवर्धन को भी शामिल किया गया है। अब तक, मंत्रालय को भूमि सीमा वाले देशों से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लगभग 150 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि अन्य समयबद्ध तरीके से परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं।

किया गया था। इन रिपोर्टों को एक साप्ताहिक आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा गया और विश्व भर में व्याप्त कोविड परिदृश्य पर अद्यतन रखने के लिए इसमें देश की अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड वैश्विक महामारी के आर्थिक प्रभाव, विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव और विभिन्न सरकारों द्वारा घोषित देश-विशिष्ट आर्थिक और अन्य राहत उपायों के इनपुट शामिल थे।

• कोविड प्रतिक्रिया के प्रति शक्ति प्राप्त समूह 6: एएस (ईआर) सम्बद्ध मंत्रालयों, उद्योग प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संयुक्त राष्ट्र और संबद्ध संगठनों के साथ निकट सहयोग में प्रभावी कोविड प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए गठित शक्ति प्राप्त समूह 6 का भाग था। डिवीजन ने मिशनों के साथ समन्वय करके वैश्विक रूप से बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के मद्देनजर उत्पाद निर्यात बढ़ाने के संभावित अवसरों की पहचान की है।

16

स्टेट्स प्रभाग

राज्य डिवीजन ने विदेशों में भारतीय मिशनों और पोस्टों के नेटवर्क और भारत में शाखा सचिवालय / क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के माध्यम से राज्यों के बाहरी आर्थिक प्रतिबद्धताओं की सुविधा प्रदान की है। स्टेट्स डिवीजन ने अपने जनादेश का अग्रसक्रिय होकर पालन किया है तथा डेक्कन डायलॉग के तीसरे संस्करण (16 नवंबर, 2020 को आईएसबी हैदराबाद में) जैसे आयोजन किए गए हैं, जिसमें वर्चुअल स्वरूप में 2020 में राज्यों की राजनयिक आउटरीच तथा राज्य स्तर पर

आर्थिक राजनयिक संवाद को बढ़ावा देने और राज्य सुविधा और ज्ञान सहायता निधि का उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए भाग लिया गया था।

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों में उनके निवासी आयुक्तों के साथ नियमित संपर्क साधन किया गया था। डिवीजन द्वारा राज्य सरकारों और विदेशी प्रतिस्थानी नगरों के मध्य सिस्टर-स्टेट तथा नगर भागीदारी की स्थापना के लिए अनेक समझौता ज्ञापनों को सुगम बनाया गया था।

राज्यों द्वारा डिप्लोमेटिक आउटरीच किए जाने के लिए सहयोग प्रदान करना

स्टेट्स डिवीजन ने सक्रिय रूप से - 20 अक्टूबर 2020 को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स और वियतनाम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सह-संगठित भारत - वियतनाम बिजनेस फोरम के आयोजन में प्रतिभागिता की गई थी। इस आयोजन की अध्यक्षता मंत्रालय से सचिव (पूर्व) ने की।

डिवीजन ने अक्टूबर 29, 2020 को चेल्याबिंस्क के क्षेत्रीय गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित एससीओ (शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन) के सदस्य देशों के प्रमुखों (प्रशासनिक-प्रशासनिक इकाइयों) के प्रथम फोरम में हरियाणा की भागीदारी की सुविधा प्रदान की है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने भारत के प्रमुखों के फोरम में प्रतिनिधित्व किया था।

डेक्कन डायलॉग: डेक्कन डायलॉग के तीसरा संस्करण, “क्राइसिस एंड कोऑपरेशन: इन द टाइम्स ऑफ पैनेडेमिक एंड बियाँड” के अंतर्गत 16 नवंबर 2020 को

इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद के सहयोग से आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। आवास और शहरी मामलों के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन (स्वतंत्र प्रभार); तथा राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग, के साथ अनेक राजदूतों, व्यापारिक नेताओं, निर्णय निर्धारकों और अन्य गणमान्य लोगों ने इस आयोजन में भाग लिया था। इस अवसर पर भारत और विश्व के सम्मुख व्याप्त अभूतपूर्व संकट से जूझने की प्रक्रिया में, विशेषकर आर्थिक वास्तविकताओं के साथ-साथ अवसरों पर ज्ञानवर्धक और उत्साही चर्चाएँ आयोजित की गई थी।

इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, स्टेट डिवीजन ने ब्राजील के टूर ऑपरेटर्स, ट्रेवल एजेंटों, मीडिया प्रतिनिधियों और निर्णय निर्धारकों के साथ दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र, गुजरात और केरल राज्यों की भागीदारी से एक वर्चुअल सम्मेलन की व्यवस्था की गई थी।

सरकार की पैरा डिप्लोमेसी पहल के अंतर्गत पूर्वोत्तर संवाद को शुरू करने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। स्टेट्स डिवीजन इस वार्ता का आयोजन करेगा, जिसे इस साल के शुरू में आयोजित किया जाएगा। डेक्कन संवाद पहल की सफलता के आकर्षण से यह संवाद शैक्षिक संस्थानों के साथ साझेदारी में

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहरी जुड़ाव और आर्थिक विकास की सुविधा के लिए एक साझा मंच पर कई हितधारकों को एक साथ लाने का भी संगत प्रतिरूप होगा।

मिशन / पोस्टों की ओर से विदेश में राज्यों को सुविधाएं प्रदान करना

स्टेट्स डिवीजन ने विदेश में स्थित भारतीय मिशनों और पोस्टों के माध्यम से उनके देश के अधिकार क्षेत्र से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध सुविधाएं प्रदान करने के क्रियाकलापों से संबंधित एक आयोजन किया गया था। इस क्रियाकलाप के लिए डिवीजन द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि ‘स्टेट फैसिलिटेशन एब्रांड’ बजट शीर्ष के अंतर्गत उपयोग में लाई गई थी।

राज्य प्रचार को सुविधाजनक बनाने के लिए कोविड महामारी की आशंका के विचार से वर्चुअल कार्यक्रमों, प्रसार कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं, आदि के माध्यम

से निम्नलिखित राज्य सुविधा प्रोत्साहन आयोजित किए गए थे:

- भूटान में भारत के दूतावास ने 08 दिसंबर 2020 को भूटान और सिक्किम के स्टेटधारकों के लिए जैविक खेती पर एक वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया।
- सीजीआई, जोहान्सबर्ग ने ओणम महोत्सव का आयोजन किया।
- सीजीआई, न्यूयॉर्क ने हिमाचली बुनकरों की बुनाई परंपरा के प्रदर्शन का एक कार्यक्रम आयोजित किया।

राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क साधन

राज्य डिवीजन ने राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों के साथ विदेश मंत्रालय की सम्बद्धता सुगम बनाने के लिए अन्य प्रक्रियाओं के साथ साथ उच्च-स्तरीय व्यापार प्रतिनिधि मंडलों की आवाजाही यात्राओं के समन्वयन किया जाता है।

- नवंबर-दिसंबर 2020 में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (एनईएसआईडीएस) के संदर्भ में आयोजित अनेक वेबिनारों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों के मुद्दों पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श में विदेश मंत्रालय की ओर से स्टेट डिवीजन ने भाग लिया।
- प्रभाग ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की सुविधा भी प्रदान की, जो विदेश मंत्रालय और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के बीच संपर्क बिन्दु के कार्य करता है।
- एक प्रमुख पहल के रूप में स्टेट्स डिवीजन ने 04-08 दिसंबर 2020 के दौरान सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस में राज्यों के प्रशिक्षण वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक सप्ताह के विशेष कार्यक्रम की संकल्पना एवं आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संलिप्तता के लिए शुरू किया गया था तथा इसका

उद्देश्य टीम भावना को बढ़ावा देना है, जिससे विश्व में टीम इंडिया के भाग के रूप में राज्यों की संलिप्तता स्थापित की जा सके। विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैरा-डिप्लोमेसी, वायु, जल और भूमि से जुड़े सम्पर्कता के मुद्दों, भारत के प्रति विदेशी यात्रियों के आकर्षण, कोविड वैश्विक महामारी के निवारण में राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों की भूमिका तथा विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में आने जाने की विजिटों सहित भारत की विदेश नीति, समान हित के क्षेत्र के विषयों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया था।

- स्टेट्स डिवीजन द्वारा वर्ष 2021-22 में पहली बार विदेशी मीडिया के लिए परिचायक यात्राओं की सुविधा प्रदान की गई है। इससे राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को सहयोग की संभावनाओं को प्रदर्शित करने और उन सामाजिक-आर्थिक विकास को उजागर करने का अवसर मिला है जो राज्यों द्वारा पंजीकृत किए गए हैं, जो अक्सर रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। नागालैंड, गुजरात और महाराष्ट्र के पहले दौर में शामिल होने की संभावना है।
- शाखा सचिवालय द्वारा प्रदान की गई खरीद की सुविधा जीईएम पोर्टल पर डिवीजन ने प्राथमिक खरीदार के रूप में अपनी भूमिका की शुरुआत की है।

विदेशी नगरों / राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों की सुविधा

वर्ष 2019-20 के दौरान, स्टेट डिवीजन ने विदेशी संस्थाओं के साथ, जैसे नगर और राज्य सरकारें, निम्नलिखित एमओयू पर हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान की है, (कुछ वर्तमान में प्रक्रियाधीन हैं):

- साइनस (पुर्तगाल) और कोझीकोड नगर निगम, केरल राज्य (भारत) के बीच द्विनिर्गम संबंध पर करार। (ईडब्ल्यू डिवीजन द्वारा मंजूरी दे दी गई है)
- पोर्ट ब्लेयर और सबंग (इंडोनेशिया) के बीच सिस्टर पोर्ट सिटी समझौता।

i) सिस्टर-सिटी / सिस्टर स्टेट भागीदार

- सास फ्री (वलिस् स्विटज़रलैंड) और अल्मोड़ा (उत्तराखंड) के बीच सिस्टर सिटी की व्यवस्था।
- मुंबई, भारत और हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए करार।
- चियांग माई प्रांत, थाईलैंड और असम, भारत के बीच सिस्टर राज्य संबंधों की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।
- तमिलनाडु / चेन्नई, भारत और फुज़ियान / गुआनझो सिटी (चीन) के मध्यसिस्टर स्टेट एंड सिस्टर सिटी भागीदारी करार।

ii) अन्य करार

- खेल विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत गणराज्य के केरल राज्य तथा नीदरलैंड साम्राज्य के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय समझौता ज्ञापन।
- भारत गणराज्य के कर्नाटक राज्य के शहरी विकास विभाग और कर्नाटक नगरीय अवसंरचना विकास एवं वित्त निगम और नवोपाय केंद्र डेनमार्क, के बीच समझौता ज्ञापन।
- आर्थिक विकास, नौकरी सृजन और व्यापार, ऑटोरियो, कनाडा तथा उद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार, भारत के बीच समझौता ज्ञापन।
- पंजाब निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो, पंजाब सरकार और अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एवं पंजाब में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एमओसीएएम इंडिया की अमेरिकी सदस्य कंपनियों के मध्यसमझौता ज्ञापन।
- जीआईआई GIZ (जैसेल्लसचफ्ट फुर इंटरनेशनले जुसाम्मेनजबेट)

और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफोरेस्ट्री के मध्यकरार।

- भारत में इन्वेस्ट यूपी और अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच समझौता ज्ञापन पर करार।
- उत्तर प्रदेश और इंडो स्कैंडिक संगठन के बीच समझौता ज्ञापन पर करार।
- इन्वेस्ट यूपी और ईबीजी (यूरोपीय बिजनेस ग्रुप) फेडरेशन, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर करार।
- डेनमार्क के रॉयल डेनिश दूतावास, नई दिल्ली के माध्यम से नर्मदा, जल संसाधन, जल आपूर्ति और कल्पसर विभाग, गुजरात सरकार और डेनमार्क सरकार के बीच जल प्रौद्योगिकी गठबंधन, भारत का समझौता करार।
- गुजरात सरकार (औद्योगिक विस्तार ब्यूरो, उद्योग और खान विभाग) और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के बीच समझौता करार।
- असम सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग और नानयांग पॉलिटेक्निक इंटरनेशनल, सिंगापुर के बीच समझौता करार पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

विदेशी राजनयिकों के साथ राज्यों की अन्य गतिविधियां

विदेश में विभिन्न मिशनों / पोस्टों की माँगों को ध्यान में रखते हुए और वित्त वर्ष 2020-21 में 'स्टेट फेसिलिटेशन अब्रॉड' के तहत धन की उपलब्धता के बाद डिवीजन ने 25 जून 2020 को विदेश में 131 भारतीय मिशनों / पोस्टों को 4.42 करोड़ रुपए तथा उसके पश्चात् सितंबर-अक्टूबर 2020 के दौरान अन्य अनेक मिशनों / पोस्टों के लिए 1,419,200 रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की है।

राज्य सुविधा एवं ज्ञान सहायता निधि

- प्रमुख व्यापार निकायों जैसे कि फिक्की / एशोचे के साथ 'कनेक्ट टू रिक्नेक्ट' शीर्षक इत्यादि जैसे शीर्षक के अंतर्गत शाखा सचिवालय, कोलकाता के माध्यम से व्यावसायिक सेमिनारों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया था जिसमें बिहार और भूटान आदि शामिल हैं।
- इस प्रभाग ने झारखंड के विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, भारत

अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला 2019-20 के आयोजन में भाग लेने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, रांची को समर्थन प्रदान किया है।

- प्रभाग ने शाखा सचिवालय, कोलकाता के माध्यम से कला और कलात्मकता द्वारा पश्चिम बंगाल की वैश्विक पहुंच पर एक दिन का कार्यक्रम आयोजित किया है।

बाहरी एजेंसियों से निधियन प्राप्त राज्य परियोजनाओं के लिए मंजूरी

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान, डिवीजन ने पूर्वोत्तर राज्यों में किए जाने वाले 38 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी की सुविधा प्रदान की, जो बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों जैसे कि

डब्ल्यूबी-आईबीआरडी, एबीडी, जेआईसीए इत्यादि द्वारा वित्त पोषित हैं। कुछ और परियोजना अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

17

निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग

संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति

संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति के दिनांक 06 अक्टूबर से 10 नवंबर, 2020 के दौरान न्यूयॉर्क में आयोजित 75 वें सत्र में भारत ने निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुई चर्चा में भाग लिया है और वैश्विक, गैर-भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। विदेश सचिव ने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन करने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक के अवसर पर एक वीडियो संदेश प्रस्तुत किया है।

भारत के पारंपरिक संकल्प जिसका शीर्षक "आतंकवादियों द्वारा सामूहिक विनाश के लिए हथियार प्राप्त करने को बाधित करने के उपाय", को प्रथम समिति द्वारा एक बार फिर से बिना किसी मतदान के बिना अंगीकार किया गया था। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों से आतंकवादियों को बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार प्राप्त करने से रोकने और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने के उद्देश्य से उपाय करने का आह्वान किया गया है। भारत के दो अन्य संकल्प निम्नलिखित से संबंधित हैं:

निरस्त्रीकरण सम्मेलन

परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के उपयोग के खतरे या खतरे को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर बातचीत शुरू करने के लिए निरस्त्रीकरण के सम्मेलन को दोहराया गया है; और (ख) संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों द्वारा पूर्ण समर्थन के साथ डी-अलर्टिंग और डी-टारगेटिंग के माध्यम सहित न्यूक्लियर खतरे को कम करने, जिसमें परमाणु सिद्धांत की समीक्षा किए जाने तथा हथियारों के आशित अथवा

आकस्मिक उपयोग के जोखिम को कम करने के उपायों की आवश्यकता पर बल दिया गया है, तथा इसके परमाणु सिद्धांतों की आवश्यकता और तत्काल कदमों को अंगीकार किया गया है।

एक अन्य भारत-प्रायोजित संकल्प "अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका" पर आम सहमति से अंगीकार

किया गया था। प्रस्ताव में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आउटरीच की घटनाओं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुपक्षीय संवाद समवर्ती विकास और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और निरस्त्रीकरण प्रयासों पर संभावित प्रभाव को सुविधाजनक

बनाने पर बल दिया गया है। संकल्प 2019 के अंतर्गत पारित यूएनएसजी की रिपोर्ट, 2019 में अनिवार्य, वैज्ञानिक विकास और उनके संभावित प्रभावों की समीक्षा की गई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

भारत ने संकल्प 1540 (2004), जिसके अंतर्गत राष्ट्रों को अन्यो के साथ साथ नॉन स्टेट एक्टों को परमाणु, रासायनिक अथवा जैविक हथियारों के विकास, अधिप्राप्ति, परिवहन, हस्तांतरण अथवा उपयोग अथवा उनकी डिलीवरी व्यवस्था के प्रति किसी भी स्वरूप में सहायता न दिए जाने की व्यवस्था की गई है, के अनुसरण में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति के साथ समन्वय किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी नवीनतम राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें निर्यात नियंत्रण और यूएनएस 1540 के कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए उपायों और गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

वर्ष 2021 की व्यापक समीक्षा के अंतर्गत यूएनएससीआर 1540 समिति ने 1540 समिति के प्रति भारत की मैट्रिक्स की समीक्षा की जिसका प्रकाशन

1540 समिति द्वारा 2020 में किया जाना है। मैट्रिक्स ने कानूनी अनुपालन (नियामक और प्रवर्तन दोनों) के संदर्भ में यूएनएससीआर 1540 के सामूहिक विनाश के हथियारों, उनकी वितरण प्रणाली और संबंधित सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों से संबंधित निषेध, उपाय और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का राष्ट्रीय-स्तर पर किए गए कार्यान्वयन का आकलन किया।

जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्राप्ति के बाद से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों को प्रभावित करने वाले विचार-विमर्श में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा तय किए गए बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के अप्रसार के उपायों से संबंधित विशिष्ट मामलों पर भारत संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिक समितियों के साथ भी जुड़ा हुआ है।

यूएनएसजी यूनाइटेड ग्रुप ऑफ़ डिसॉर्डर मैट्रेस (एबीडीएम)

भारत के प्रतिनिधि ने 29-31 जनवरी 2020 तक जिनेवा में आयोजित यूएनएसजी के एबीडीएम के 73 वें 74 वें सत्रों में और वर्चुअल स्वरूप में क्रमशः

15, 19, 24 और 25 जून 2020 को भाग लिया गया, जिसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्त्रीकरण मामलों पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है।

रासायनिक हथियार सम्मलेन

रासायनिक हथियारों के निषेध (ओपीसीडब्ल्यू) के लिए संगठन की कार्यकारी परिषद (ईसी) के एक सदस्य के रूप में भारत ने रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय प्रतिभागिता की है जिसके अंतर्गत रासायनिक हथियार विनाश, उद्योग सत्यापन, राष्ट्रीय कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता शामिल है। रासायनिक हथियारों के निषेध (ओपीसीडब्ल्यू) के कार्यान्वयन से संबंधित राष्ट्रों के साथ भारत की संलिप्तता कार्यकारी परिषद के वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न सत्रों में बनी रही है। भारत ने सीडब्ल्यूसी के अंतर्गत विभिन्न मामलों पर वार्षिक प्रस्तुतियों के अलावा, भारत में एक एकल लघुस्तरीय सुविधा के निर्माण के लिए सितंबर 2020 में ओपीसीडब्ल्यू के लिए

अपनी प्रारंभिक घोषणा प्रस्तुत कर दी है।

सीडब्ल्यूसी में रसायनों के अनुलग्नकों की अनुसूची 1 में रसायन जोड़ने से संबंधित भागीदार राष्ट्रों 24 वें सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में सीडब्ल्यूसी अधिनियम, 2020 के अंतर्गत राजपत्र अधिनियम (दिनांक 12 मई, 2020) के अंतर्गत सम्मलेन के रसायनों के अनुलग्नकों की अनुसूची में परिवर्तन अंगीकार किए गए हैं। भागीदार राष्ट्रों के 25 वें सम्मेलन (सीएसपी) का पहला भाग 30 नवंबर से 01 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया गया था जिसने वर्ष 2021 के लिए ओपीसीडब्ल्यू बजट को अंगीकार किया था।

जैविक एवं विषाक्त हथियार सम्मलेन

जैविक और विषाक्त हथियार कन्वेंशन (बीटीडब्ल्यूसी) में कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण वर्चुअल माध्यम से संचालित सीमित क्रियाकलाप किए गए थे। वर्ष 2021 के लिए योजनाबद्ध सम्मलेन के आगामी 9वें समीक्षा सम्मेलन के संदर्भ में, भारत ने सम्मलेन के संस्थागत सुदृढीकरण के लिए अपना आह्वान दोहराया है, जिसमें भागीदार राष्ट्रों द्वारा प्रभावी, सार्वभौमिक और गैर-भेदभावपूर्ण सत्यापन तंत्रव्यवस्था के लिए एक व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की व्यवस्था को सुदृढ बनाने प्रस्तावना

है। वर्ष 2020 के लिए विशेषज्ञों और भागीदार राष्ट्रों की वार्षिक बैठक अगले साल के लिए स्थगित कर दी गई है। भारत ने विशिष्ट प्रस्तावों और सहायता के अनुरोधों का मिलान करके सहायता का प्रावधान करने के लिए एक अनुच्छेद VII डेटाबेस स्थापित करने के लिए भागीदार राष्ट्रों के साथ परामर्श करना जारी रखा है।

विशिष्ट पारम्परिक हथियारों के विषय पर सम्मलेन

अग्रणी राष्ट्रों के विशेषज्ञों द्वारा अत्यधिक सीमित उपस्थिति और वर्चुचल योगदान के साथ विशिष्ट पारंपरिक हथियारों के विषय के सम्मेलन (सीसीडब्ल्यू) की बैठकें 2020 के दौरान एक हाइब्रिड स्वरूप में आयोजित की गई थीं। भारत ने सितंबर 2012 से घातक स्वायत्त हथियार सिस्टम के संबंध में समूह के सरकारी विशेषज्ञों (जीजीई) की 21-25 सितम्बर 2020 को आयोजित बैठक, युद्ध के विस्फोटक अपशिष्ट से संबंधित विशेषज्ञों के प्रोटोकॉल V (28 सितम्बर, 2020) तथा विशेषज्ञों के समूह के संशोधित प्रोटोकॉल-II में (29-30 सितम्बर, 2020) भाग लिया है। सीसीडब्ल्यू के उच्च संविदाकारी भागीदारों राष्ट्रों की

अन्य बैठकें नवंबर 2020 में आयोजित की जानी थीं जो जिनेवा में कोविड-19 की स्थिति बिगड़ने के कारण 2021 तक के लिए स्थगित की गई है।

भारत ने 16-20 नवंबर 2020 तक वर्चुअल फॉर्मेट में एंटी-माइंस और माइंस, बूबी-ट्रैप्स एवं अन्य उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंधों या प्रतिबंधों पर सीसीडब्ल्यू संशोधित प्रोटोकॉल II के संदर्भ में आयोजित एंटी-पर्सनेल माइन्स बैन कन्वेंशन के 18 वें सत्र में एक प्रेक्षक के रूप में भाग लिया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के प्रावधानों का सम्मान करता है।

स्मॉल आर्म्स एवं लाइट वेपन्स

भारत ने वर्ष 2020 से संबंधित अपनी वार्षिक राष्ट्रीय रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के कार्रवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत कर दी है, जिसमें सभी छोटे-छोटे पहलुओं (यूएनपीओए) में छोटे आर्म्स और हल्के वेपन्स के अवैध व्यापार को रोकने और

उनका उन्मूलन करने के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक व्यापक सेट प्रदान किया गया है। भारत यूएनपीओए और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट की प्रस्तुत और कार्यान्वयन के लिए भी संलिप्त रहा है।

निर्यात नियंत्रण शासन पद्धति

भारत ने निर्यात नियंत्रण और विशिष्ट वस्तुओं की सूची और सरोकार की प्रौद्योगिकियों के लिए दिशा-निर्देशों के माध्यम से अप्रसार के लक्ष्यों में योगदान करने की दिशा में बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भाग लिया है। भारत जून 2016 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, दिसंबर 2017 में वासेनार अरेंजमेंट और जनवरी 2018 में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का सदस्य बन गया है।

भारत के बहु-एजेंसी प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी 2020 में एजी इंटर-सेशनल बैठक में भाग लिया है और अक्टूबर और नवंबर 2020 में एजी उप-समूह वर्चुअल बैठकों में प्रतिभागिता की है। कोविड -19 स्थिति के कारण, 2020 में एमटीसीआर और डब्ल्यू की अनुसूचित बैठकें स्थगित अथवा रद्द कर दी गईं लेकिन इन शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत विनिमय डिजिटल स्वरूप में किए गए थे।

वर्ष के दौरान, संबंधित बहुपक्षीय 2019 के दिशानिर्देशों और नियंत्रण सूचियों तथा सम्बल बहुविषय विशेषज्ञ तंत्रव्यवस्था एवं रसायन हथियार सम्मलेन के रसायनों से संबंधित अनुलग्नक की अनुसूची 1 से तारतम्यता के लिए विशेष रसायन, जैविक, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (एससीओएमईटी) की भारत की निर्यात नियंत्रण सूची 11 जून 2020 (10 जुलाई 2020 से प्रभावी) को अद्यतन की गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

भारत ने सितंबर 2015 में वियना में आयोजित आईएईए की महासभा (जीसी) के 64 वें सत्र में भाग लिया है और साथ ही मार्च, जून और सितंबर 2020 में आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विभिन्न बैठकों में प्रतिभागिता की है। भारत ने आईएईए सुरक्षा उपायों के तहत तीन अधिक सुविधाएं रखने की घोषणा 63 वीं

मंत्रालय ने एससीओओएमईटी के अंतर्गत नियंत्रित दोहरे उपयोग की वस्तुओं के के नियंत्रण के लाइसेंस के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयीय कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) में योगदान जारी रखा है। इसी प्रकार, मंत्रालय ने एससीओओएमईटी की श्रेणी 6 (युद्ध सामग्री सूची) की वस्तुओं के निर्यात के प्राधिकार पर रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) के साथ मिलकर कार्य किया है। मंत्रालय ने निर्यात नियंत्रण प्रणाली के अनुरूप राष्ट्रीय प्रवर्तन तंत्र में भी योगदान दिया है।

मंत्रालय ने निर्यात नियंत्रण प्रणाली के कार्यान्वयन के अभिन्न अंग के रूप में आउटरीच गतिविधियों के लिए डीजीएफटी और सीबीआईसी में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम किया है। मंत्रालय ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में निर्यात नियंत्रण पर उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए कार्यशाला के लिए इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी) के साथ मार्च 2020 में कोलकाता में और जून, जुलाई तथा सितम्बर, 2020 में क्रमशः भारत के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए भागीदारी की है। रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण (एसटीए) -1 पर तीन वेबिनार सत्रों के रूप में आउटरीच कार्यक्रम, भारत की एससीओएमईटी सूची और निर्यात नियंत्रण प्रणाली पर अपडेट, जुलाई 2020 में यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी) और भारतीय रक्षा निर्माताओं की सोसायटी (एसआईडीएम) के साथ आयोजित किए गए थे।

सेंटर फॉर परमाणु ऊर्जा साझेदारी ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक संस्थागत संरचना के रूप में कार्य किया। भारत ने विकिरण प्रौद्योगिकियों के विभिन्न अनुप्रयोगों, जैसे स्वास्थ्य सेवा, कृषि, इत्यादि के समर्थन में गतिविधियों में भी योगदान दिया।

सिविल परमाणु सहकार्यता

परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए भारत सरकार और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय के बीच एक समझौता 15 जुलाई 2020 को संपन्न हुआ था। भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन की अवधि का विस्तार 27 अक्टूबर 2020

भारत यूरोपीय संगठन के लिए परमाणु अनुसंधान परिषद (सीईआरएन) परिषद, वित्त समिति और वैज्ञानिक नीति समिति के सत्र के दौरान वर्ष 2012 से सीईआरएन के एसोसिएट सदस्य के रूप में भाग लेता रहा है।

को ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में सहकार्यता के विस्तार की घोषणा के अवसर पर किया गया था। भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड और वियतनाम एजेंसी फार रेडिएशन एंड नुक्लियर सेफ्टी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर 21 दिसंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे।

आउटर स्पेस

निरस्त्रीकरण के सम्मेलन में आउटर स्पेस की बैठकों के अलावा, भारत ने वियना और इसके सहायक निकायों में आउटर स्पेस के शांतिपूर्ण उपयोगों (सीओपीयूओएस) पर संयुक्त राष्ट्र समिति की बैठकों में भाग लिया, जिसमें भारत ने आउटर स्पेस के शांतिपूर्वक उपयोग से संबंधित अपनी तकनीकी क्षमताओं और दृष्टिकोणों के संबंध में प्रस्तुति दी है। कोविड -19 वैश्विक

महामारी के कारण, विधिक उपसमिति (एनएससी) और सीओपीयूओएस ने लिखित प्रक्रियाओं के माध्यम से अपने सहायक निकायों की निरंतरता के संबंध में सुनिश्चय किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारत ने विभिन्न देशों के साथ बहुपक्षीय गतिविधियों और अंतरिक्ष सेवाओं के प्रावधान के शांतिपूर्ण उपयोग पर द्विपक्षीय रूप से सहयोग करना जारी रखा है।

यूरोपीय आर्गेनाइजेशन फॉर नुक्लियर रिसर्च (सीईआरएन)

भारत वर्ष 2017 से एसोसिएट सदस्य के रूप में। सीईआरएन परिषद की वित्त

समिति और वैज्ञानिक नीति समिति के सत्रों में भाग ले रहा है।

सामुद्रिक सुरक्षा मामले

भारत के महत्वपूर्ण हित भारत-प्रशांत क्षेत्र और विश्व स्तर पर समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के सहकार्यता को बढ़ाने से जुड़े हुए हैं। इस दिशा में, भारत ने विभिन्न साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संस्थाओं के माध्यम से सक्रिय भागीदारी जारी रखी है। सूचना प्यूजन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर) मित देशों के साथ समुद्री सुरक्षा साझेदारी और सामूहिक रूप से समुद्री जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में तेजी से विकसित हुआ है। 22 देशों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौतों सहित अन्य देशों के साथ सहयोग का विस्तार करने के कार्यों प्रगति हुई है।

लाल सागर में पायरेसी तथा चोरी एवं सशस्त्र डकैती के जहाजों के दमन के लिए सहयोग करना है। भारत ने इस क्षेत्र में समुद्री मामलों पर भाग लेने वाले देशों के साथ परामर्श करने के लिए अगस्त 2020 से फ्रेंड्स ऑफ गल्फ ऑफ गिनी (जी 7 + एफओजीजी) की कार्य स्तर की बैठकों में भी भाग लिया है।

भारत ने 23 सितंबर 2020 को फ्रेंड्स ऑफ द चेरर ऑफ द कॉटेक्ट ग्रुप ऑन ऑन पॉयरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया (सीजीपीसीएस) और 17-18 दिसंबर 2020 के दौरान सीजीपीसीएस की वर्चुअल बैठक बैठकों में प्रतिभागिता की है।

भारत 2007 में इंटरनेशनल मेरीटाइम आर्गेनाइजेशन (आईएमओ) की “प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल शिपिंग लेन” की पहल के तहत मालक्का और सिंगापुर (एसओएमएस) के सहकारी तंत्र सेटअप का सक्रिय सदस्य रहा है। इस क्षेत्र में एड्स से लेकर नेविगेशन फंड (एएनएफ) समिति की बैठकों में भारत का योगदान रहा है।

हेग आचरण संहिता

भारत ने जून 2016 से हेग आचरण संहिता (एचसीओसी) में एक भागीदार के रूप में, भारत ने पारदर्शिता और विश्वास निर्माण उपायों पर अपने प्रावधानों का पालन करना जारी रखा है और नियमित रूप से भारत के बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष प्रक्षेपणों की पूर्व-लॉन्च सूचनाएँ जारी की हैं। भारत ने एचसीओसी

की 19 वीं वार्षिक नियमित बैठक में भाग लिया है, जो 12 अक्टूबर 2020 को वियना में आयोजित की गई थी। भारत ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी वार्षिक घोषणा भी प्रस्तुत की है।

एशिया में अन्योनयक्रिया एवं आत्मविश्वास निर्माण के उपायों से संबंधित सम्मलेन (सीआईसीए)

विदेश मंत्री द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2020 को वर्चुअल स्वरूप में आयोजित सीआईसीए राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की एक विशेष मंत्रिस्तरीय बैठक में ने भाग लिया गया। बैठक में कजाखस्तान की नई सीआईसीए अध्यक्षता के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई और कोविड -19 वैश्विक महामारी की प्रतिक्रिया के लिए विचार-विमर्श किया गया। विदेश मंत्री ने सीआईसीए के भागीदार देशों के साथ कोविड - 19 के

पश्चात् की स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से भारत द्वारा दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। भारत ने सीआईसीए देशों में डिजिटल अर्थव्यवस्था और लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के विकास में इसकी भूमिका के संबंध में 20 अक्टूबर 2020 को आयोजित ऑनलाइन गोलमेज चर्चा सहित वर्ष के दौरान सीआईसीए कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

एशियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) तथा एडीएमएम+

भारत की एक्ट ईस्ट 'नीति के अनुसरण में भारत ने एआरएफ के तत्वावधान में आयोजित इंटर-सेशनल बैठकों (आईएसएम) और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) में भाग लिया है। राज्य मंत्री द्वारा 12 सितंबर 2020 को वर्चुअल स्वरूप में आयोजित 27 वीं एआरएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया जिसमें क्षेत्रीय वैश्विक विकास के व्यापक हितों पर चर्चा की गई। बैठक ने इंटर-सेशनल वर्ष 2020-2021 के लिए एआरएफ ट्रैक I क्रियाकलापों की सूची को अंगीकार किया गया जिसमें भारत इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फेसिलिटी सिक्योरिटी कोड (आईएसपीएस कोड) पर एआरएफ इवेंट की और एआरसीएल पार्टनर देशों के साथ यूएनसीएलओएस को लागू करने पर एक कार्यशाला की सह-अध्यक्षता

करेगा।

एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस (एडीएमएम प्लस) की 10 दिसंबर 2020 को आयोजित वर्चुअल बैठक में रक्षा मंत्री द्वारा भाग लिया गया था। भारत और इंडोनेशिया भाग लेने वाले देशों को अनुभव साझा करने और अभ्यास साझा करने के लिए, मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) पर एशियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस विशेषज्ञों के कार्यकारी समूह (ईडब्ल्यूजी) के वर्तमान सह अध्यक्ष हैं।

निरस्त्रीकरण शिक्षा एवं फैलोशिप

भारत निरस्त्रीकरण और अप्रसार के लिए भारत की प्रतिबद्धता अंतर्गत, और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शिक्षा और समझ की भूमिका को संज्ञान में लेकर भारत और विदेशों में व्यापक समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें जनवरी 2020 में विदेशी राजनयिकों के लिए वार्षिक निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों

की फैलोशिप कार्यक्रम शामिल हैं। भारत की पहल से “निरस्त्रीकरण और अप्रसार शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र का अध्ययन” यूएनजीए संकल्प 71/57 को भी अंगीकार किया गया है यह हमारे विश्व एवं हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने की यूएनएसजी निरस्त्रीकरण की कार्यसूची के अनुरूप है।

18

विधि एवं संधि प्रभाग

विदेश मंत्रालय के संबंध में सभी कानूनी और संधि संबंधी मामलों की देखरेख के लिए विधि एवं संधि डिवीजन को उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। पिछले वर्ष, भारत ने 52 देशों / संगठनों के साथ 97 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं; 15 करारों के लिए

अनुसमर्थन दिया है ; और 10 उपक्रमों के लिए पूर्ण शक्तियां संसाधित की गई हैं। (उपर्युक्त से संबंधित विवरण एलएंडटी डिवीजन द्वारा अनुरक्षित भारतीय संधियों के डेटाबेस और अनुबंध- I के भाग के रूप में प्रस्तुत हैं)

संयुक्त राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून

संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति (विधिक)

छठी समिति, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की मुख्य समितियों में से एक है और अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों पर विचार के लिए एक प्राथमिक मंच है, की महासभा के 75 वें सत्र का आयोजन 06 अक्टूबर से 19 नवंबर 2020 किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्रवें सत्र में छठी समिति द्वारा विचार में लिए गए महत्वपूर्ण विषय / मुद्दों में निम्नलिखित

शामिल हैं -

- (i) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के अनुपालन की व्यवस्था ;
- (ii) सार्वभौमिक क्षेलाधिकार के सिद्धांत का दायरा और अनुप्रयोग;

(iii) अपने 53वें सत्र के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून संबंधित संयुक्त राष्ट्र आयोग की रिपोर्ट,

(iv) अंतर्राष्ट्रीय कानून, शिक्षण, अध्ययन, प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यापक प्रशंसा में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम,

(v) अपने 72वें सत्र से संबंधित कार्य पर अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग की रिपोर्ट,

(vi) डिप्लोमैटिक प्रोटेक्शन

(vii) मेजबान देश के साथ संबंधों पर समिति की रिपोर्ट,

(viii) मिशन पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और विशेषज्ञों की आपराधिक जवाबदेही,

(ix) एलियंस का निष्कासन

(x) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित उत्तरदायित्व

(xi) मानवता के प्रति अपराध

(xii) अंतर्राष्ट्रीय संधि ढांचे को मजबूत करना और बढ़ावा देना

(xiii) 1949 के जिनेवा सम्मेलनों के अतिरिक्त प्रोटोकॉल और सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों की सुरक्षा से संबंधित स्थिति

(xiv) संयुक्त राष्ट्र के चार्टर तथा संगठनों भूमिका के सुदृढ़ीकरण पर विशेष समिति की रिपोर्ट। “आपदाओं की स्थिति में व्यक्तियों का संरक्षण” की कार्यसूची मद को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया था।

छठी समिति ने अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग की मौखिक रिपोर्ट पर भी विचार किया और चर्चा की।

यूएनजीए की छठी समिति के मुख्य सत्र के दौरान, भारत ने वर्चुअल स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने के उपायों पर वस्तुतः नौ बयान दिए; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का शासन; मिशनों पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और विशेषज्ञों की अपराधों के प्रति उत्तरदेयता; सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत का दायरा और अनुप्रयोग; संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर विशेष समिति की रिपोर्ट और संगठन की भूमिका को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय

विधि आयोग (आईएलसी), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल); और जीए प्लेनरी में अंतर्राष्ट्रीय न्याय न्यायालय।

अक्टूबर 2020 में, भारत ने सीसीआईटी पर वार्ता के लिए कार्यकारी समूह की बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। डब्ल्यूजी की वार्ता के दौरान, बकाया मुद्दों को सुलझाने और सदस्य राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया।

जारी कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण, महासभा द्वारा अन्य ों के साथ साथ वर्ष 2021 में आईएलसी के सत्रहवें सत्र को आयोजित करने का निर्णय लिया और यह भी निर्णय लिया कि वर्तमान आईएलसी सदस्यों के कार्यालय की शर्तों को एक वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए (31 दिसंबर 2022 तक)।

इसके अलावा, छठी समिति ने ऑब्जर्वर स्टेटस के संबंध में (i) स्माल आईलैंड डेवलपिंग स्टेट्स डॉक (बेरीज द्वारा प्रस्तुत), (ii) सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंस्टीट्यूट (चीन द्वारा शुरू किया गया), (iii) एशियन फॉरिस्ट कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (कोरिया गणराज्य द्वारा प्रारंभ) और (iv) ग्लोबल ड्राईलैंड प्लायंस (कतर द्वारा प्रस्तुत) पर किसी प्रकार के मतदान के बिना विचार किया गया।

भारत ने सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया और कुछ विषयों पर वक्तव्य प्रस्तुत किए।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (यूएनसीआईटीआरएएल)

विधि एवं संधि डिवीजन ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (यूएनसीआईटीआरएएल) के अंतर्गत गठित निम्नलिखित कार्य समूहों में भाग लिया:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का कार्यकारी समूह

कार्यकारी समूह के 34 वें सत्र में यूएनसीआईटीआरएएल द्वारा सीमित देयता संगठन से संबंधित मसौदा गाइड पर अपना विचार-विमर्श जारी रखा। मसौदा गाइड में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया था। यह आशा है कि आगामी सत्र में भी यह चर्चा जारी रहेगी।

विवाचन और सुलह / विवाद निपटान पर कार्य समूह

कार्यकारी समूह ने अभी तक एक्सपीटेड आर्बिट्रेशन प्रोविजंस (ईएपी) की अंतिम प्रस्तुति का निर्धारण न किए जाने को विचार में लेकर इस आशय से ईएपी पर विचार करने का फैसला किया कि ऐसा करके वे यूनीसेशनल आर्बिट्रेशन रूल्स (यूएआर) के परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत होंगे और इसके संबंध में विचार-विमर्श के बाद के चरण में रूप और प्रस्तुति एवं चर्चा की जाएगी। सामान्य तौर पर समझा गया कि ईएपी (इसके बाद, “मार्गदर्शन दस्तावेज़”) के साथ

एक मार्गदर्शन सामग्री या व्याख्यात्मक नोट तैयार करना उपयोगी होगा। यह कहा गया था कि जबकि ईएपी को खुद को स्पष्ट और आसानी से समझ आने योग्य बनाए जाने की आवश्यकता है, इस तरह के मार्गदर्शन दस्तावेज़ ईएपी के उपयोगकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं, विशेष रूप से उनकी जो ऐसी प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं। चर्चा के दौरान, यह उल्लेख किया गया था कि वर्किंग ग्रुप के काम को अन्य वर्किंग ग्रुप्स के वर्क ओवरलैप से बचना चाहिए, विशेषकर वर्किंग ग्रुप III (आईएसडीएस रिफॉर्म) के।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान सुधार पर कार्य समूह III

वर्किंग ग्रुप, वियना में 05-09 अक्टूबर 2020 से आयोजित अपने 39 वें सत्र में, निवेशक-राज्य विवाद निपटान सुधार पर अपने विचार-विमर्श जारी रखा गया। विशेष रूप से, आईएसडीएस रिफॉर्म के अंतर्गत शेरधारक के दावे और चिंतनशील नुकसान, विवाद की रोकथाम और शमन - वैकल्पिक विवाद समाधान के उपाय, संधि दलों द्वारा निवेश संधियों की व्याख्या, लागत और तुच्छ दावों के लिए सुरक्षा, कई कार्यवाही और काउंटरक्लिम्स और आईएसडीएस सुधार पर बहुपक्षीय उपकरण के मुद्दों पर।

यूएनसीआईटीआरएएल सचिवालय और आईसीएसआईडी सचिवालय ने भी अधिनिर्णयन के लिए एक आचार संहिता का मसौदा तैयार किया था और

हितधारकों से इनपुट मांगे थे।

इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर वर्किंग ग्रुप IV

कार्यकारी समूह द्वारा आईडीएम मैनेजमेंट और ट्रस्ट सर्विसेज से जुड़े कानूनी मुद्दों पर विचार जारी रखा गया। कार्यकारी समूह ने अपने आगे के विचार के लिए सहमत संशोधनों के साथ मसौदा प्रावधानों को मंजूरी दी। कानूनी और संधियों के प्रतिनिधि मंडल ने कार्यदल के विचार-विमर्श और निर्णयों में भाग लिया। कार्यकारी समूह ने चालीसवें सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट को अंगीकार करने अथवा न करने के संबंध में विचार किया। इसके संबंध में 19 अगस्त 2020

भारत निहित अंतर्राष्ट्रीय विवाद न्यायनिर्णय

एंटरिका लैक्सी मामला (इटली तथा भारत)

द लॉ ऑफ़ द सी (यूनसिएलओएस) ने संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन के अनुलग्नक- VII के अंतर्गत गठित न्याय ट्रिब्यूनल द्वारा 21 मई 2020 को अपना न्यायनिर्णय दिया था। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल से इटली द्वारा 26 जून 2015 को एनरिका लेक्सी घटना के विवाद के संबंध में स्थापित किया गया था। यूनसिएलओएस के प्रावधानों तथा नियमों के अनुसार पार्टियों द्वारा प्रक्रिया के प्रति सहमति व्यक्त की गई है, न्यायनिर्णय का उच्चारण कर दिया गया है। निम्नलिखित मुख्य आकर्षण हैं:

- ट्रिब्यूनल ने यूनसिएलओएस के प्रावधानों के तहत घटना के संबंध में भारतीय अधिकारियों के आचरण को बरकरार रखा। यह माना जाता है कि इटली के सैन्य अधिकारियों की कार्रवाई और, परिणामस्वरूप, इटली ने यूनसिएलओएस अनुच्छेद 87 (1) (ए) और 90 के तहत भारत की नेविगेशन की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया।

- ट्रिब्यूनल ने यह प्रेक्षण किया कि भारत और इटली का इस घटना पर समवर्ती अधिकार क्षेत्र था और मरीन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही करने के लिए एक वैध कानूनी आधार था। ट्रिब्यूनल ने मरीन को हिरासत में लेने के मुआवजे के इटली के दावे को खारिज कर दिया। हालांकि, यह पाया गया कि राज्य के अधिकारियों ने भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अपवाद के रूप में मरीन का लाभ उठाया और इसलिए, उन्हें मरीन का न्याय करने से रोक दिया।

- ट्रिब्यूनल ने इटली द्वारा 15 फरवरी 2012 की घटनाओं में अपनी आपराधिक जांच फिर से शुरू करने के लिए व्यक्त की गई प्रतिबद्धता की ओर ध्यान दिया।

- ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि भारत “सेंट एंटनी” के कप्तान और अन्य चालक दल के सदस्यों द्वारा जीवन की क्षति, शारीरिक नुकसान, संपत्ति को नुकसान और नैतिक नुकसान के संबंध में मुआवजे के भुगतान का हकदार है। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि भारत के कारण मुआवजे की राशि पर समझौते तक पहुंचने के लिए पार्टियों को एक दूसरे के साथ परामर्श करने के लिए आमंत्रित करने की स्वतंत्रता है। ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्णय लिया कि वह अधिकार क्षेत्र बनाए रखेगा यदि पार्टी या दोनों पक्ष भारत को देय मुआवजे की माला निर्धारित करने के संबंध में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से कोई निर्णय लेने के लिए आवेदन करना

को यूनसिएआईटीआरएल के राष्ट्रों के सदस्यों द्वारा अंगीकार गए निर्णय का स्मरण करवाया था, जिसके अनुसार अध्यक्ष और रैपरोट एक मसौदा सारांश तैयार करेंगे, जिसमें विचार-विमर्श को दर्शाया जाएगा और सत्र के दौरान किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। अध्यक्ष और रैपरोट द्वारा प्रसारित मसौदा सारांश की समीक्षा करने के बाद, कार्य समूह ने आयोग को अपनी रिपोर्ट के रूप में प्रसारण के लिए इसे अपनाने पर सहमति व्यक्त की। वर्किंग ग्रुप ने इस सत्र के लिए अनंतिम एजेंडे में शामिल विषयों पर चर्चा करने के लिए अनौपचारिक विचार-विमर्श करने के लिए भी सहमति व्यक्त की, जिन पर चर्चा नहीं की गई थी।

चाहते हैं।

निवेश संबंधी विवाचन मामले

परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (पीसीए) के तत्वावधान में गठित विभिन्न आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने भारतीय गणराज्य के खिलाफ निम्नलिखित निवेश संधि विवादों पर फैसला सुनाया।

डॉयचे टेलीकॉम का मामला, भारत-जर्मनी द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत: डॉयचे टेलीकॉम, देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड में एक निवेशक थे। भारत सरकार के खिलाफ दावों का कारण नेशनल मार्केट ग्राउंड पर एंट्रिक्स और देवस के बीच एक अनुबंध को रद्द किया जाना था। ट्रिब्यूनल ने मेरिट पर अपना निर्णय देने के बाद, इस वर्ष क्वांटम पर अपना निर्णय दिया है।

सीसी देवास भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय निवेश संधि के अंतर्गत: मॉरीशस सीसी देवास, मॉरीशस द्विपक्षीय निवेश संधि के अंतर्गत: सीसी देवास, देवास मल्टीमीडिया लिमिटेड के निवेशकों में से एक थे जिन्होंने एंट्रिक्स के साथ एक अनुबंध किया था। यह दावा राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर एंट्रिक्स-देवास अनुबंध को रद्द करने से उत्पन्न हुआ। मेरिट पर अपना निर्णय देने के बाद, ट्रिब्यूनल ने 2020-21 क्वांटम पर अपना निर्णय दिया गया। तथापि, मेरिट पर निर्णय देने को चुनौती देने की कार्यवाही डच न्यायालयों के समक्ष लंबित है।

वोडाफोन केस:भारत के तहत वोडाफोन और भारत के बीच विवाद में गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण- नीदरलैंड द्विपक्षीय निवेश संधि ने सितंबर 2020 में निर्णय जारी किया है, जिसमें भारत को संधि के निष्पक्ष और न्यायसंगत उपचार प्रावधान के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया गया।

निसान मोटर कंपनी लिमिटेड मामला: निसान और भारत-जापान सीईपीए के बीच का विवाद पार्टियों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया और इस प्रकार से मध्यस्थता की कार्यवाही बंद हो गई।

खेतान मामला : खेतान होल्डिंग्स मॉरीशस लिमिटेड बनाम भारतीय गणराज्य के बीच विवाद में, भारत-मॉरीशस बीआईपीए के तहत विवाद, वस्तुतः अधिकार क्षेत्र पर सुनवाई अगस्त 2020 में आयोजित की गई थी और अधिकार क्षेत्र पर निर्णय प्रतीक्षित है।

जीपीआईएक्स मामला: भारत के खिलाफ जीपीआईएक्स द्वारा प्रस्तुत किए गए विवाद में भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत एक मध्यस्थ

न्यायाधिकरण का भी गठन किया गया था। मामला वर्तमान में पीसीए द्वारा देखा जा रहा है।

प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हेग सम्मलेन (एचसीसीएच)

पेरेंटेज / सरोगेसी परियोजना पर विशेषज्ञों के समूह की सातवीं बैठक 12 से 16 अक्टूबर 2020 के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। इसमें 26 विशेषज्ञों, 3 पर्यवेक्षकों और एचसीसीएच के पैरामाउंट ब्यूरो (पीबी) के सदस्यों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों के 23 सदस्य देशों

संधि वार्ताएं

विधि एवं संधि डिवीजन ने राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व के विभिन्न विषयों से संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनमें से सबसे उल्लेखनीय बहुपक्षीय वार्ताएं निम्नलिखित

हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में आईसीटी के क्षेत्र में सरकारी उत्तरदायित्व को आगे बढ़ाने के सरकारी विशेषज्ञों के समूह का ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप (ओईडब्ल्यूजी) ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से जून 2020 से समय-समय पर वार्ता कर रहा है।

- घातक स्वायत्त प्रणालियों (एलएडब्ल्यूएस) पर सरकारी विशेषज्ञों के समूह (जीजीई) की बैठक (हाइब्रिड मीटिंग) जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 21-25 सितंबर 2020 के दौरान आयोजित की गई थी। इसमें आईएचएल की प्रयोज्यता, एलएडब्ल्यूएस की परिभाषा, ह्यूमन इन लूप और एलएडब्ल्यूएस से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण की संभावना के मुद्दों पर चर्चा की गई।

- विधि एवं संधि डिवीजन ने फिलीपींस, यूएई, मैक्सिको और कुछ अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौतों से संबंधित दस्तावेजों की बातचीत और परीक्षण की प्रक्रिया में भाग लिया।

ऑनलाइन संधि डेटाबेस

भारतीय विदेश मंत्रालय के विधि एवं संधि डिवीजन द्वारा बनाए गए भारतीय संधि डेटाबेस सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ भारत द्वारा संपन्न संधियों / समझौतों से संबंधित जानकारी प्रदान करने में आम जनता के लिए एक बड़ा योगदान है। नवीनतम संधि जानकारी को प्रतिबिंबित करने के लिए ऑनलाइन संधियों डेटाबेस को लगातार अपडेट किया जा रहा है। संधि डेटाबेस को निम्नलिखित वेब

का प्रतिनिधित्व किया। कानूनी पेरेंटेज (कन्वेंशन) पर एक सामान्य निजी अंतरराष्ट्रीय कानून उपकरण और एक अंतरराष्ट्रीय सरोगेसी व्यवस्था (प्रोटोकॉल) के परिणामस्वरूप स्थापित कानूनी पेरेंटेज पर एक अलग प्रोटोकॉल में दोनों को शामिल करने के लिए संभावित प्रावधानों पर चर्चा हुई।

लिंक पर पहुंचा जा सकता है: <https://www.mea.gov.in/TreatyList.htm?1>। इसमें 1950 से लेकर 2020 तक की अवधि की संधियाँ शामिल हैं। वर्तमान में इस तरह की संधियाँ 3,300 से अधिक हैं।

विधिक दस्तावेजों का परीक्षण/पुनरीक्षा

विधि एवं संधि डिवीजन ने समझौता ज्ञापन, संधियों / समझौतों के साथ-साथ मंत्रिमंडलीय नोटों सहित कई अंतरराष्ट्रीय कानून उपकरणों की जांच की है और कानूनी राय प्रदान की है। डिवीजन ने अन्य कार्यों के साथ साथ रक्षा सहकारिता, कृषि, रेलवे, सार्क, स्वास्थ्य, जैव-प्रौद्योगिकी, आउटर स्पेस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ब्रिक्स, (रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन बंगाल की खाड़ी के लिए बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्स्टेक), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित समझौते, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी / नशीले पदार्थों; गोपनीयता पर भी समझौते; हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना; गैस और ऊर्जा; सांस्कृतिक सहयोग, ऑडियो विजुअल सहयोग, सड़क परिवहन, व्यापार और निवेश, अन्य देशों में लागू होने वाली परियोजनाएं, शिक्षा, पर्यटन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर द्विपक्षीय समझौते; जल संसाधन; जैव-विविधता; सौर गठबंधन; ओजोन क्षयकारी पदार्थ; हाइड्रोग्राफी, जुड़वाँ / सिस्टर अथवा सिस्टर राज्य समझौते और सीमा शुल्क सहयोग समझौते, इत्यादि पर अपनी राय प्रदान की है।

संधियों की सूची

भारत ने वर्ष 2020 के दौरान अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कई बहुपक्षीय / द्विपक्षीय संधियों / समझौतों पर हस्ताक्षर / अनुसमर्थन किया है। ऐसे समझौतों / संधियों की एक व्यापक सूची अनुलग्नक- I में रखी गई है। वर्ष 2020 के दौरान जारी किए गए इंस्ट्रूमेंट ऑफ रैटिफिकेशन / एक्सेस की सूची अनुलग्नक- II में है; और वर्ष 2020 के दौरान जारी किए गए पूर्ण शक्तियों की लीस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अनुलग्नक- III में है।

19

नीति नियोजन और अनुसंधान प्रभाग



विदेश सचिव ने 28 अगस्त, 2020 को दिल्ली स्थित प्रमुख थिंक-टैंक के साथ चर्चा की

नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग रणनीतिक और अकादमिक समुदाय के साथ जन कूटनीति पहलों के आयोजन और नीति नियोजन के लिए मंत्रालय का

नोडल प्रभाग है। यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ प्रमुख सम्मेलन पहलों का वचन देता है और नियमित आधार पर मंत्रालय

के लिए संस्थानिक नीति विश्लेषण आयोजित करता है। यह प्रभाग विशेष रूप से क्रॉस-कटिंग पहलों में मंत्रालय के प्रयासों का नेतृत्व करता है जिनमें भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय शामिल है।

नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग आईसीडब्ल्यूए और आरआईएस- दो स्वायत्त निकायों से संबंधित मामलों के लिए प्रशासनिक प्रभाग है जो मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। यह प्रशासनिक रूप से विदेश मंत्रालय पुस्तकालय और सीमा प्रकोष्ठ के प्रभारी भी है।

महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग ने अपने अधिदेशों में तीव्र गति से कार्य किया। इस प्रभाग का मुख्य कार्यात्मक ढांचा, जैसे नीति नियोजन संवादों को आयोजित करना, सम्मेलनों और ट्रैक 1.5/2 संवादों के माध्यम से थिंक टैंक के साथ सार्वजनिक कूटनीति पहल, संसदीय मामलों पर अनुसंधान और नीतिगत जानकारी प्रदान करना, डोमेन

विशेषज्ञों के साथ जुड़ाव, विशेष अंतर-एजेंसी मामलों, समाचार पत्र थिंक-टैंक संकलन आदि जैसी पत्रिकाओं को तैयार करना, और मंत्रालय के अन्य प्रभागों द्वारा सौंपे गए अन्य नीति विशिष्ट कार्यों- 2020-22 में विस्तार किया। इसके अलावा, प्रभाग ने स्वास्थ्य कूटनीति, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई, आतंकवाद का मुकाबला, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सुधार बहुपक्षीयता, समुद्री संपर्क, बड़ी तकनीक और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने के प्रमुख क्षेत्रों में कई प्रमुख नीति विश्लेषण कार्य किए।

25 दिसंबर 2020 को मंडल ने प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी वार्षिक स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया। यह व्याख्यान अमेरिका-भारत व्यापार परिषद की अध्यक्ष और अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स में दक्षिण एशिया के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष निशा देसाई बिस्वाल ने दिया। विदेश मंत्री ने इस अवसर पर उद्घाटन भाषण दिया।

नीति नियोजन संवाद

वार्षिक नीति नियोजन संवाद नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग के मुख्य अधिदेशों में से एक है। महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समझ की समानता विकसित करने के लिए हमारे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय राजनयिक भागीदारों के साथ संवाद आयोजित किए जाते हैं। 2020-21 में, प्रभाग ने विदेशों की नीति नियोजन इकाइयों के साथ मजबूती से कार्य किया और कुल 11 नीति नियोजन संवाद आयोजित किए। कोविड महामारी के कारण, इन सभी संवादों को अक्सर कई दौर के माध्यम से आभासी मंच के द्वारा आयोजित किया गया। वर्चुअल प्रारूप के नए अनुकूलन ने नीति नियोजकों को द्विपक्षीय विचारों के स्पष्ट और

गहन आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की।

2020-21 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, इजराइल, पोलैंड, तुर्की, वियतनाम, ब्रिटेन, अमेरिका, ईयू और ब्रिक्स के साथ नीति संवाद आयोजित किए गए। इन संवादों ने उभरती हुई भू-राजनीतिक और भू-अर्थशास्त्र प्रवृत्तियों पर दृष्टिकोणों के समृद्ध आदान-प्रदान को आयोजित किया। इन संवादों के रणनीतिक आयात का मंत्रालय की दीर्घकालिक विदेश नीति योजना पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा।

सार्वजनिक कूटनीति बढ़त

2020-21 के दौरान, प्रभाग ने उच्च पदाधिकारियों के साथ बातचीत को संस्थागत रूप देकर रणनीतिक समुदाय के साथ मंत्रालय के संबंधों में काफी वृद्धि की। इसने 28 अगस्त 2020 को विदेश सचिव और दिल्ली स्थित थिंक टैंक के चुनिंदा प्रमुखों के बीच एक उच्चस्तरीय बातचीत का आयोजन किया।

सितंबर-नवंबर 2020 के उत्तरवर्ती महीनों में, प्रभाग ने चुनिंदा डोमेन विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत के कई दौर आयोजित किए।



विदेश मंत्री ने दिनांक 25 दिसंबर 2020 को पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल व्याख्यान का उद्घाटन भाषण दिया

2020-21 में, प्रभाग ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ साझेदारी करके कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ ट्रेक 1.5 संवादों की सुविधा प्रदान की।

अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में, नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग ने प्रमुख थिंक टैंक और अकादमिक संस्थानों के साथ साझेदारी में भारत और विदेश दोनों में प्रमुख सम्मेलनों का आयोजन जारी रखा। ये सम्मेलन उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित भू-राजनीति, भू-अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति के विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल निर्वाचिका सभा के रूप में संरचित होते हैं जो मंत्रियों और उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ नीति चिकित्सकों के स्तर पर निर्णयकर्ताओं व्यापार और उद्योग से अग्रणी व्यक्तित्व और सामरिक समुदाय, मीडिया और शिक्षा समुदाय के सदस्यों को शामिल करते हैं।

अन्य प्रशासनिक कार्य

इस प्रभाग ने दो स्वायत्त निकायों आईसीडब्ल्यूए और आरआईएस के कामकाज को प्रशासनिक मार्गदर्शन प्रदान किया जो मंत्रालय के भीतर अनुसंधान संस्थानों के रूप में काम करते हैं। इसमें पुस्तकालय की गतिविधियों के विस्तार

भारतीय विश्व मामलों की परिषद

प्रभाग आईसीडब्ल्यूए के लिए अनुदान सहायता के साथ-साथ आईसीडब्ल्यूए के शासन से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए प्रशासनिक प्रभाग है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईसीडब्ल्यूए के लिए अनुदान 13 करोड़ रुपये था।

आईसीडब्ल्यूए ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और व्यापक वैश्विक भू-सामरिक वातावरण में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा विकास के अनुसंधान और अध्ययन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करना जारी रखा। निष्कर्षों का प्रचार-प्रसार मुद्दा संक्षेप, दृष्टिकोण और विशेष रिपोर्टों के रूप में किया गया था, जिन्हें आईसीडब्ल्यूए वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा आईसीडब्ल्यूए ने अपने अकादमिक परिणामों को हिंदी में अनुवाद करने की प्रक्रिया जारी रखी जिसे नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इसके अलावा, अप्रैल 2020 के बाद से, परिषद पुस्तकों और सप्रू हाउस अभिलेखों को प्रकाशित किया है।

2020-21 के दौरान, आईसीडब्ल्यूए फैलो ने विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस):

यह प्रभाग आरआईएस के लिए अनुदान सहायता के साथ-साथ आरआईएस के शासन से संबंधित प्रशासनिक मामलों के लिए नोडल प्रभाग है। आरआईएस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में कुशल है। यह वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच प्रभावी नीतिगत वार्ता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देता है। आरआईएस दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है और विभिन्न मंचों पर बहुपक्षीय वार्ताओं में विकासशील देशों के साथ सहयोग करता है। थिंक टैंक के अपने

दिसंबर 2020 में वैश्विक टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए आयोजित किया गया था। रायसीना वार्ता, एशियाई आर्थिक वार्ता और हिंद महासागर सम्मेलन 2021 में बाद में आयोजित किया जाना है, जिससे व्यापक नीति समुदाय के साथ मंत्रालय का जुड़ाव तेज हो गया है। बिस्मटेक/बीबीआईएन उप-क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर में नई सार्वजनिक कूटनीति की घटनाएं भी पाइपलाइन में हैं। नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग द्वारा जिन विषयों पर फ्लैगशिप सम्मेलनों का आयोजन किया गया है, उनकी पूरी सूची संदर्भ के लिए संलग्न है।

इस वर्ष के दौरान, प्रभाग ने प्रत्येक मामले के आधार पर अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने में विश्वविद्यालयों को अपने समर्थन का विस्तार किया। इसने अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति के मुद्दों पर अकादमिक सेमिनारों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इन घटनाओं की एक पूरी सूची संलग्न है।

की निगरानी की गई। पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों और डेटाबेस के लिए सदस्यता प्राप्त की गई।

मामलों में सभी प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक रुझानों और विकास के विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान किया। शोध आउटपुट मुद्दा संक्षेप, दृष्टिकोण, विशेष रिपोर्ट, और सप्रू हाउस अभिलेखों के रूप में प्रकाशित किए गए थे। 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर 2020 की अवधि के दौरान परिषद ने अनुसंधान संकाय द्वारा लिखे गए 76 वेब लेख प्रकाशित किए जिनमें 47 मुद्दा संक्षेप, 24 दृष्टिकोण और 4 विशेष रिपोर्ट शामिल हैं। इन 44 वेब लेखों में से (31 मुद्दा संक्षेप और 13 दृष्टिकोण) विशेष रूप से दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में कोविड के प्रभाव की पहचान करने से संबंधित थे। शोध संकाय ने मीडिया और अन्य अकादमिक पत्रिकाओं में विभिन्न लेख भी प्रकाशित किए।

दर्शकों तक व्यापक पहुंच के लिए आईसीडब्ल्यूए ने अपने अकादमिक लेखों के अनुवादित संस्करणों को हिंदी में प्रकाशित करना जारी रखा। इस उद्देश्य के अनुपालन में 45 मुद्दा संक्षेप और 22 दृष्टिकोण और 3 विशेष रिपोर्ट का हिंदी में अनुवाद कर परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

गहन नेटवर्क के माध्यम से, आरआईएस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों और विकास साझेदारी केनवास पर नीतिगत सामंजस्य को मजबूत करना चाहता है।

2020-21 के दौरान, आरआईएस ने कोविड-19 महामारी पर केंद्रित कई नीतिगत संवादों का आयोजन किया। इनमें अन्य लोगों के अलावा, भारत-वियतनाम एस एंड टी सहयोग, पोस्ट-कोविड युग में बिस्मटेक, इंडोनेशिया की कोविड-19 निकास योजना और द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग की क्षमता,

अन्तः निर्भर विश्व में दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने की संभावनाएं और दृष्टिकोण, भारत और कोटे डी आइवर के बीच सहयोग पहलों को मजबूत करना, एसडीजी के लिए एसटीआई, दक्षिण एशिया से कोविड-19 के लिए बहुपक्षीय प्रतिक्रिया, कोविड-19 से वसूली में तेजी लाने के लिए दक्षिण एशियाई सहयोग की जरूरत, आसियान-भारत साझेदारी को मजबूत करना और बिस्मटेक नेटवर्क ऑफ पॉलिसी थिंक टैंक (बीएनपीटीटी) की 5वीं बैठक में मंत्रालय के सहयोग से बिस्मटेक देशों के थिंक टैंक को एक साथ लाना, शामिल थे।

2022 में भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के लिए प्राथमिकताओं और अनुबंध समूहों की भूमिका पर राष्ट्रीय और वैश्विक विचारकों की भागीदारी वाले वेबिनार आयोजित किए

पुस्तकालय और सीमा प्रकोष्ठ

विदेश मंत्रालय पुस्तकालय प्रशासनिक रूप से जेएस (पीपीआर) द्वारा संभाला जाता है। विदेश मंत्रालय पुस्तकालय, दुर्लभ पुस्तकों, वर्तमान पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक संग्रह बनाए रखने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों, पत्रिकाओं और डेटाबेस के लिए सदस्यता प्रदान करने के लिए प्रभारी भी है।

सीमा प्रकोष्ठ की देखभाल प्रशासनिक रूप से नीति योजना और अनुसंधान प्रभाग द्वारा की जाती है। सीमा प्रकोष्ठ भारतीय सर्वेक्षण और अन्य एजेंसियों द्वारा प्राप्त

गए थे। आरआईएस में वैश्विक विकास केंद्र ने महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवसायियों के प्रशिक्षण पर अपने साथी देशों के साथ पीएचएफआई के साथ मिलकर आभासी वेबिनार की एक श्रृंखला भी आयोजित की और अपने आर्थिक विकास के लिए भारत के प्रमुख कार्यक्रमों पर जीडीसी फैलोशिप कार्यक्रम किए।

इस वर्ष के दौरान, आसियान उप-क्षेत्रीय अध्ययनों पर अनुसंधान करने वाले आरआईएस के भीतर एक विशेष निकाय आसियान इंडिया सेंटर के कार्यात्मक दायरे और जनादेश का विस्तार करने के लिए एक परामर्शी ढांचे पर विचार-विमर्श किया गया और इसे कार्यकारी कार्रवाई में डाल दिया गया। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आरआईएस के लिए 12.46 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था।

मानचित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा (आईबी) की पुनरीक्षण से संबंधित है; आईबी के संरेखण की विधिवत जांच करने के बाद उनकी अनापत्ति/टिप्पणियों के लिए प्रादेशिक प्रभाग को भेजना; सीमा से संबंधित मामलों पर प्रादेशिक प्रभागों के साथ बातचीत; भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा संबंधी कार्यों के लिए धन से संबंधित अनुरोधों का संकलन और प्रसंस्करण और इसके लिए मंजूरी जारी करना; और मानचित्रों पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गलत चित्रण से संबंधित शिकायतों और शिकायतों का निपटारा करना।



MEA Library
Ministry of External Affairs, Government of India



Welcome to MEA Library

MEA Library is one of the oldest and biggest in Ministries of Government of India. This library was renamed from Foreign Department Library to MEA Library after independence. The library has a unique and rare collection. This is a very special library in the field of International Relations covering topics of Foreign Policy, Foreign Relations, Area Studies, History, Political Science, International Trade and Economy, Indian Diasporas, Terrorism and related subjects.

The Ministry's Library has over one hundred thousand books, rich resource material and a large collection of maps, microfilms and official documents.

www.mealib.nic.in

Read More

20

आतंकवाद का मुकाबला

T2020-21 के दौरान, आतंकवाद का मुकाबला करने के मुद्दे को सभी स्तरों पर विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में प्रमुख रूप से उल्लेख मिलना जारी रहा। इस तरह की सभी बातचीत के दौरान भारत ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने, आतंक के किसी भी कृत्य के औचित्य को अस्वीकार करने, आतंक को धर्म से जोड़ने के किसी भी औचित्य को अस्वीकार करने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी देशों को एकजुट होने की आवश्यकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच अधिक स्वीकार्यता पाई गई और यह द्विपक्षीय शिखर सम्मेलनों और विभिन्न देशों और क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर मंत्रिस्तरीय बैठकों के बाद जारी किए गए कई परिणाम दस्तावेजों में परिलक्षित होता है।

भारत वर्तमान में 25 देशों के वरिष्ठ वार्ताकारों और यूरोपीय संघ, बिस्सटेक और ब्रिक्स जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद से मुकाबला पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी-सीटी) के तंत्र के माध्यम से जुड़ा है। इस वर्ष के दौरान, भारत ने कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली सीमाओं के बावजूद विभिन्न साझेदार देशों के साथ जेडब्ल्यूजी-सीटी के माध्यम से संरचित परामर्श जारी रखा। वर्ष 2020-21 में भारत ने फ्रांस के साथ जेडब्ल्यूजी-सीटी के तंत्र के माध्यम से और वस्तुतः ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ (ईयू), ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय आतंकवाद निरोधक परामर्श आयोजित किया। सितंबर 2020 में, जेडब्ल्यूजी-सीटी बैठक के साथ-साथ तीसरी भारत-अमेरिका पदनामीत वार्ता भी आयोजित की गई थी। भारत ने ब्रिक्स काउंटर में भी हिस्सा लिया।

आतंकवाद कार्य समूह और उप-समूह की बैठकें 31 अगस्त 2020 से 02 सितंबर 2020 तक वर्चुअली आयोजित की गईं। उक्त बैठकों के दौरान ब्रिक्स आतंकवाद निरोधक रणनीति दस्तावेज को मंजूरी दी गई।

जेडब्ल्यूजी-सीटी बैठकें आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए एक उपयोगी मंच प्रदान करती हैं, जिसमें सीमा पार आतंकवाद, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के संबन्धित विषयों में, आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई में बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने, पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधों में तेजी लाने, एजेंसी-टू एजेंसी सहयोग को सुगम बनाने और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद (सीसीआईटी) पर एक व्यापक अभिसमय को शीघ्र अपनाने के महत्त्व पर जोर देने सहित वैश्विक आतंकवाद के बारे में सूचना, अनुभव और आकलन को साझा करने में सक्षम बनाया गया है।

भारत वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सबसे आगे रहा है और उसने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रमुख वैश्विक पहलों में हिस्सा लिया है। भारत ने 28 देशों के साथ सुरक्षा सहयोग, 42 प्रमुख देशों के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों, 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों और 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था पर द्विपक्षीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत आतंकवाद से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सभी 13 क्षेत्रीय सम्मेलनों का पक्षकार है। इस वर्ष के दौरान, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्टूबर 2020 में कानून प्रवर्तन आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर निरंतर सहयोग के समर्थन में आशय के एक बयान पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष 2020-21 के दौरान, सचिव (पूर्व) ने आतंकवाद से पीड़ितों के मिलों के समूह की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया जो 28 सितंबर, 2020 को वर्चुअली हुई थी। संयुक्त सचिव (सीटी) के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय (यूएनओसीटी) द्वारा आयोजित वर्चुअल आतंकवाद रोधी सप्ताह में भी भाग लिया। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम (जीसीटीएफ) के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत नियमित रूप से इसकी विभिन्न बैठक में भाग लेता है। इस वर्ष के दौरान, भारत ने 29 सितंबर, 2020 को जीसीटीएफ समन्वय समिति की 17वीं बैठक और जीसीटीएफ के विभिन्न कार्य समूहों की कई अन्य बैठकों में भाग लिया। भारत 2010 से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का सदस्य रहा है और नियमित रूप से विभिन्न कार्य समूहों और पूर्ण बैठकों में

भाग लेता रहा है। इस वर्ष के दौरान भारत ने जून, अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021 में आयोजित एफएटीएफ वर्चुअल समय एवं कार्यकारी समूह की बैठकों में भाग लिया। भारत एफएटीएफ स्टाइल रीजनल बोडीज (एफएसआरबी) जैसे- यूरोशियन समूह (ईएजी) और एशिया पैसिफिक ग्रुप (एपीजी) का भी सदस्य है और इस वर्ष के दौरान आयोजित उनकी बैठकों में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधियों ने नियमित रूप से शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (एससीओ-आरएटीएस) की बैठकों में भी भाग लिया।

2020-21 के दौरान, भारत के प्रमुख आतंकवाद निरोधक बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) ने श्रीलंका के अधिकारियों के लिए आतंकवाद का मुकाबला करने पर क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया।

21

साइबर कूटनीति प्रभाग, ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी

साइबर कूटनीति (सीडी)

मंत्रालय का साइबर कूटनीति प्रभाग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय साइबर मुद्दों पर कार्यवाही करता है। साइबर कूटनीति प्रभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस), गृह मंत्रालय (एमएचए), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई), इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिसपांस टीम (सीआईआरटी-इन), राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और दूरसंचार विभाग (दूरसंचार विभाग) आदि अन्य एजेंसियों के परामर्श से साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों, डेटा संरक्षण और इंटरनेट गवर्नेंस पर चर्चा के लिए 'नोडल केन्द्र' के रूप में कार्य करता है।

भारत अपने विचारों को स्वरूप देने, वैश्विक साइबर नीतियों को आकार देने और अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर संवादों, सम्मेलनों और समझौतों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और योगदान दे रहा है। अभिशासन के बहु-हितधारक मॉडल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, भारत साइबर नीति को आकार देने और रणनीति तैयार करने के लिए निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षाविदों के साथ गतिविधियां कर रहा है।

(i) अलग-अलग देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध

साइबर कूटनीति प्रभाग की द्विपक्षीय साइबर चर्चा आयोजित करने में विशिष्ट भूमिका है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत ने दिनांक 04 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में एक निर्बाध, स्वतंत्र, सुरक्षित इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए और उत्तरा उत्तर दोनों राष्ट्रों को समृद्धि प्रदान करने के लिए एक सक्षम परिवेश मुहैया करवाने के लिए एक पंचवर्षीय कार्य योजना (2020-2025) सहित साइबर और साइबर-सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहयोग पर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेमवर्क के तहत पंचवर्षीय कार्ययोजना लागू की जा रही है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईसीटी और साइबर सुरक्षा पर संयुक्त कार्य समूहों (जेडब्ल्यूजी) का गठन शामिल है; डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार पर केंद्रित अनुसंधान को प्राथमिकता देना, सुदृढ़ साइबर फोरेंसिक और जांच क्षमताओं को बढ़ावा देने और क्वैटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के व्यावहारिक अनुप्रयोगों में अनुसंधान पर सहयोग को प्राथमिकता देने के लिए "ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटिजिक रिसर्च फंड" का सृजन करना शामिल है।

भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय सहयोग ज्ञापन (एमओसी) को अंतिम रूप दिया है।

15 सितंबर 2020 को भारत और अमरीका ने डिप्लोमैटिक एनएसए, श्री आर. खन्ना के नेतृत्व में एक साइबर वार्ता का आयोजन किया। भारत की ओर से एनएससीएस, गृह मंत्रालय, दूरसंचार और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। भारत और अमेरिका ने दिनांक 01 अक्टूबर 2020 को लगभग एक आईसीटी कार्य समूह की बैठक भी आयोजित की।

दिनांक 11 दिसंबर 2020 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर 5वीं भारत-जर्मनी साइबर चर्चा का आयोजन किया गया था।

छठी भारत-यूरोपीय संघ साइबर वार्ता दिनांक 14 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी। संयुक्त सचिव (ईजी एंड आईटी एंड सीडी) ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया जिसमें एनएससीएस, गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और एमआईआईटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारत ने जुलाई 2020 में इजरायल के साथ और अक्टूबर 2020 में फ्रांस के साथ सीईआरटी एमओयू के लिए सीईआरटी पर भी हस्ताक्षर किए।

(ii) साइबर मुद्दों के क्षेत्र में क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2019-2021 की अवधि के लिए चल रहे यूनाईटेड नेशनस ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट्स (यूएनजीजीई) में चयनित 25 विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ के रूप में भाग लिया। छठे यूएनजीजीई का पहला सत्र न्यूयॉर्क में दिनांक 09-13 दिसंबर, 2019 को आयोजित किया गया था और यूएनजीजीई का दूसरा सत्र दिनांक 24 से 28 फरवरी 2020 से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। भारत 'ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप' (ओईडब्ल्यूजी) की बैठकों में भी भाग ले रहा है जिसका उद्देश्य साइबर संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करना है। ओईडब्ल्यूजी की अंतिम ठोस बैठक न्यूयॉर्क में दिनांक 10-14 फरवरी 2020 से आयोजित की गई थी। मार्च, 2021 में प्रस्तावित अगली ठोस बैठक की तैयारी में, ओईडब्ल्यूजी अनौपचारिक वर्चुअल बैठकें आयोजित कर रहा है। संयुक्त सचिव (ईजी एंड आईटी एंड सीडी) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 29 सितंबर से 01 अक्टूबर, 2020 तक आयोजित अंतिम आभासी अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। ओईडब्ल्यूजी अनौपचारिक बैठक का तीसरा और चौथा सत्र क्रमशः

दिनांक 17-19 नवंबर, 2020 और 01 से 03 दिसंबर, 2020 को आयोजन किया गया था। ओईडब्ल्यूजी की बैठक का अंतिम सत्र दिनांक 08-12 मार्च, 2021 से होना प्रस्तावित है।

भारत ने दिनांक 27-29 जुलाई 2020 तक साइबर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (आईईजी) की वर्चुअल बैठक के यूएनओडीसी के छठे सत्र में भाग लिया। संयुक्त सचिव (ईजी और आईटी और सीडी) ने भारत पक्ष का नेतृत्व किया, जिसमें एनएससीएस, गृह मंत्रालय, सीबीआई और मंत्रालय के एलएंडटी मंडल के प्रतिनिधि शामिल थे।

भारत ने दिनांक 21-22 सितंबर 2020 तक आयोजित 'क्षेत्रीय साइबर क्षमता निर्माण: 'सीजिंग द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन' पर एक ऑनलाइन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला ने ईएएस सहभागी देशों को अपनी साइबर क्षमता निर्माण आवश्यकताओं पर चर्चा करने, साइबर क्षमता निर्माण पर सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी साझा करने, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए साझेदारी तैयार करने और साइबर सुरक्षा पर आसियान मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित करने, सिंगापुर में आसियान-सिंगापुर साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र (एएससीसीई) और बैंकॉक में आसियान-जापान साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण केंद्र के माध्यम से पहले से चल रहे सहयोग को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। संयुक्त सचिव (ईजी और आईटी और सीडी) ने भारत की ओर से नेतृत्व किया, जिसमें बैठकों में एनएससीएस, एमआईआईटीवाई और सीईआरटी-इन के प्रतिनिधि शामिल थे।

भारत ने दिनांक 05 से 09 अक्टूबर, 2020 से सिंगापुर में साइबर सुरक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित पांचवें सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय साइबर सप्ताह (एसआईसीडब्ल्यू) और साइबर सुरक्षा पर पांचवें आसियान मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीसी) में भी भाग लिया। सम्मेलन का विषय "कोविड पश्चात् के भविष्य में सहयोग" था। भारत ने दिनांक 26 से 27 अगस्त, 2020 को आईसीटी के उपयोग में सुरक्षा के संबंध में वर्चुअल पद्धति से आयोजित ब्रिक्स कार्य समूह की छठी बैठक में भाग लिया।

भारत ने दिनांक 29 जुलाई, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर शंघाई सहयोग संगठन विशेषज्ञ समूह की बैठक में भी भाग लिया।

भारत दिनांक 11 अक्टूबर, 2020 को एंड टू एंड तक एन्क्रिप्शन और सार्वजनिक सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य पर आह्वान में शामिल हुआ।

ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी

अन्य कार्यों के साथ-साथ ई-गवर्नेंस और सूचना प्रौद्योगिकी (ईजी एंड आईटी) प्रभाग, मंत्रालय के लिए विभिन्न ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और रखरखाव में शामिल रहा है। ईजी एंड आईटी प्रभाग, सभी आईटी बुनियादी ढांचे की खरीद, रखरखाव और अनुरक्षण के लिए विदेशों में मंत्रालय और मिशन/पदों को सभी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित सहायता भी प्रदान करता है।

इस अवधि के दौरान, ईजी और आईटी प्रभाग ने मंत्रालय और विदेशों में सभी मिशनों और पोस्ट पर लागू करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विभिन्न घटकों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। मंत्रालय में कामकाज के सभी

स्तरों पर तालमेल हासिल करने और सरकारी अधिकारियों को कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वचालन और नेटवर्किंग का एक साधन के रूप में दोहन किया जा रहा है। निम्नलिखित ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को दिनांक 01 अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान लागू किया गया है:

ईजी और आईटी प्रभाग की देखरेख में विकसित विदेश मंत्रालय निष्पादन निगरानी डैशबोर्ड, मंत्रालय की सभी प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों को शामिल करते हुए तीन लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कई प्रमुख योजनाओं को शामिल किया गया है और पांच क्लस्टरों (डायस्पोरा को सम्मिलित करना, विकास साझेदारी, अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव, व्यापार और वाणिज्य और नागरिक

सेवाएं) में अनेक सूचकों को बांटा तथा साझा किया गया है। मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं के विवरण को प्रदर्शित करते हुए एक नया मॉड्यूल शामिल करने के लिए डैशबोर्ड को अपग्रेड किया गया है।

यूआरएल <https://repat.videshapps.gov.in> पर उपलब्ध वंदे भारत मिशन पोर्टल (रिपैट पोर्टल) को मंत्रालय द्वारा 06 मई 2020 को शुरू किया गया था ताकि मिशन मोड के तहत यात्रा को सुकर बनाकर कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को घर वापस लाया जा सके। यह पोर्टल प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में शामिल हितधारकों को पंजीकरण और पहुंच प्रदान करता है। पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वास्तविक समय के आधार पर हितधारकों के बीच डेटा साझा किया गया है।

मीडोज ऐप एक इनहाउस पोर्टल है जिसे एक 'बास्केट' के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसमें कई उपयोगी ऐप शामिल हैं जैसे एपीएआर फाइलिंग, लीव मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिल प्रबंधन, कर्मियों की तैनाती आदि। इसे विकसित किया जा रहा है और शीघ्र ही आरंभ किए जाने की संभावना है।

रिश्ता पोर्टल विदेशों में भारतवंशियों को जोड़ने हेतु केंद्रित है। रिश्ता पोर्टल और ऐप एक 'विजन' परियोजना है जो प्रवासी भारतीय समुदाय (एनआरआई, ओसीआई और पीआईओ) को साथ जोड़ने की परिकल्पना करती है और उन्हें विभिन्न नई और मौजूदा सरकारी योजनाओं से जोड़ती है जिससे उन्हें विभिन्न रुचि के क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। यह पोर्टल और ऐप किसी भी संकट प्रबंधन के दौरान सहायता करेगा और भारतवंशियों को मदद प्रदान करेगा। प्रवासी रिश्ता पोर्टल की शुरुआत 30 दिसंबर 2020 को राज्यमंत्री ने की थी।

ग्लोबल इंडियन स्टूडेंट पोर्टल विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को जोड़ने पर केंद्रित है। यह विकास के तहत एक 'विजन प्रोजेक्ट' है, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों और योजनाओं

के बारे में जानकारी होगी। यह पोर्टल बहुत मददगार होगा और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पेशेवर पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विदेश जाने वाले हमारे छात्रों को नवीनतम प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा।

एकीकृत मिशन लेखा प्रणाली संस्करण 2.0 (आईएमएस 2.0) पोर्टल: मिशन लेखा प्रणाली का नवीनतम संस्करण सभी मिशनों और पोस्टों के वास्तविक समय पर वित्तीय आंकड़े प्रदान करेगा। आईएमएस 2.0 को शीघ्रतापूर्व सभी मिशनों और पोस्टों पर लागू किए जाने की परिकल्पना है।

मंत्रालय में सुरक्षा ढांचे की समीक्षा की गई है और साइबर सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए नई पीढ़ी के नेटवर्किंग और खतरे प्रबंधन उपकरणों के साथ मौजूदा आईटी बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया गया है। इस प्रभाग ने समय-समय पर साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांतों, साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें साइबर खतरों के प्रबंधन और कम करने में सक्षम बनाने के लिए साइबर सुरक्षा के बुनियादी सिद्धांतों, साइबर सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अनेक कक्षाओं/व्याख्यानों का आयोजन किया है।

ई-गवर्नेंस सेवा परियोजनाओं को लागू करने के अलावा, ईजी और आईटी प्रभाग ने विदेशी राजनयिकों और अधिकारी प्रशिक्षुओं को विदेशी सेवा संस्थान में साइबर सुरक्षा, सुरक्षित और सुदृढ़ कंप्यूटिंग और अन्य संबंधित विषयों पर कई व्याख्यान और प्रशिक्षण भी दिए हैं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग: कोविड-19 महामारी के कारण, ईजी एंड आईटी प्रभाग ने प्रवासी भारतीय दिवस सहित सभी स्तरों पर मंत्रालय के अधिकारियों के लिए 500 से अधिक वीडियो कांफ्रेंसिंग का आयोजन किया है।

22

कांसुलर, पासपोर्ट एवं वीजा सेवाएं

मंत्रालय का सीपीवी डिवीजन ऑनलाइन (ई-सनद) के माध्यम से शैक्षिक, वैयक्तिक और वाणिज्यिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के लिए विदेश में व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए मैनुअल मोड से प्रमाणीकरण और एपोस्टिल (हेग एपोस्टिल कन्वेंशन के अंतर्गत) सेवाएं प्रदान करता है।

फरवरी 2015 में गुड गवर्नेंस के अंतर्गत विदेश में भारतीयों की कौंसुलर शिकायतों के समाधान के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक वेब पोर्टल एमएडीएडी (मदद) (ऑनलाइन कांसुलर सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम) लॉन्च किया गया है। विदेश और साथ ही विदेश मंत्रालय की शाखा सचिवालय और राज्य /

केंद्रशासित प्रदेशों में सभी भारतीय मिशनों और पोस्टों को कांसुलर शिकायतों के निवारण के लिए इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मदद ऑनलाइन पोर्टल से ऑनलाइन पंजीकरण, अप्रेशन, ट्रेकिंग और वृद्धि के माध्यम से कांसुलर शिकायतों से निपटने में गुणात्मक सुधार हुआ है।

वर्ष 2021 के दौरान, डिवीजन ने विभिन्न ई-कांसुलर संवाद, वीजा छूट समझौते, प्रत्यर्पण संधियाँ, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) और ई-वीजा योजना इत्यादि का संचालन किया है, जिसका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

वीजा-छूट करार

भारत ने 114 देशों के साथ राजनयिक तथा / अथवा आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के संबंध में वीजा छूट समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 101 वर्तमान में चालू हैं जबकि शेष अनुसमर्थन के विभिन्न चरणों में हैं। इस वर्ष के दौरान, फ्रेनाडा और मार्शल द्वीप समूह के साथ राजनयिक तथा / अथवा

आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा, राजनयिक और / या आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौतों को कोस्टा रिका, इक्वेटोरियल गिनी, ओमान और मार्शल द्वीप के साथ प्रचालनात्मक बनाया गया था।



www.meadashboard.gov.in

कांसुलर संवाद तंत्रव्यवस्था

विभिन्न देशों के साथ कांसुलर मामलों की व्यापक समीक्षा के लिए स्थापित तंत्रव्यवस्था के अंतर्गत में ईरान, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, नाइजीरिया, रूस, कनाडा, सऊदी अरब, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के साथ वर्ष 2019 में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस और तुर्कमेनिस्तान 2020 में कांसुलर

प्रत्यर्पण

विदेश मंत्रालय सक्रिय रूप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, वित्तीय जालसाजी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों में शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों के लिए विभिन्न देशों के साथ वार्ता करता है। यह सरकार की नीति है कि कई देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों को समाप्त किया जाए जिससे भगोड़े अपराधियों को न्याय से न बचने का सुनिश्चय हो सकेगा। विदेश मंत्रालय आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि, नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि और सजा प्राप्त

कांसुलर मुद्दे

भारतीय मिशन / पोस्ट विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेजों का सत्यापन, भारतीय नागरिकों का जन्म और मृत्यु का पंजीकरण और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय नागरिकों के लिए नश्वर अवशेषों का परिवहन भारत में करना, भारतीय नागरिकों के विवाह का अनुष्ठान / पंजीकरण, विदेशी जेलों में, विदेशों में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों को भारतीय न्यायालयों के सम्मन प्रदान करना, कल्याणकारी सहायता आदि प्रदान करने जैसी विभिन्न कांसुलर सेवाएं प्रदान करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय समुदाय को मिशन / पोस्ट भी

ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया (ओआईसी) कार्ड योजना

भारतीय डायस्पोरा पर एक उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसरण में भारत सरकार ने भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए अगस्त 2005 में ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ़ इंडिया कार्ड योजना शुरू की है। भारत के पूर्ववर्ती व्यक्ति विदेशी नागरिक कार्ड भारत आने के लिए एक आजीवन वीजा होते हैं। 1999 में शुरू की गई भारतीय मूल (पीआईओ) कार्ड योजना की 2015 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ़ इंडिया योजना के साथ विलय कर दी गई थी। सितंबर 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ओसीआई कार्ड के आवेदन जमा करने की प्रणाली को और सुव्यवस्थित किया गया और ओसीआई प्रस्तुत करने के अधिकार क्षेत्र

ई-वीजा योजना

ई-वीजा योजना: भारत सरकार ने 27 नवंबर 2014 को ई-वीजा योजना शुरू की थी। प्रारंभ में यह योजना केवल 43 देशों के लिए ई-पर्यटक वीजा के लिए

संवाद आयोजित किए गए थे । इनमें से इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, नाइजीरिया और कनाडा के साथ कांसुलर संवाद पहली बार आयोजित किए गए। वर्तमान में, भारत के पास 24 देशों के साथ ई-कांसुलर संवाद तंत्रव्यवस्था है।

व्यक्तियों के हस्तांतरण पर समझौते के लिए बातचीत की सुविधा भी प्रदान करता है। भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए, भारत सरकार ने आज तक 50 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, भारत ने 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण की व्यवस्था की है। वर्ष के दौरान, भारत ने 17 प्रत्यर्पण अनुरोध प्राप्त किए, और विभिन्न विदेशी देशों को 18 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे हैं। इस वर्ष 2020 में, दो भगोड़े अपराधियों को विदेश से भारत में प्रत्यर्पित किया गया था।

परामर्श देते हैं, सहायता करते हैं और विभिन्न स्थानों पर मिशन / पोस्ट और कांसुलर कैम्प में शिकायतों की सुनवाई और भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए ओपन हाउस भी संचालित करते हैं।। खाड़ी देशों में जहां बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक हैं, हमारे मिशनों और पोस्टों में विशेष समुदाय कल्याण विंग और श्रम विंग हैं। एसईडब्ल्यूए सेवा, एक ऑनलाइन कांसुलर सेवा मॉड्यूल इस वर्ष में 19 मिशनों में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है।

पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वर्ष 2020 में, ओसीआई कार्ड सुविधा भारतीय मूल के छठी पीढ़ी से आगे के सेंट डेनिस, रियूनियन आइसलैंड नागरिकों के लिए विस्तारित किया गया है। इससे पहले 2017 और 2019 में, इसी तरह की सुविधाओं को क्रमशः मॉरीशस और सूरीनाम के भारतीय प्रवासी के लिए बढ़ाया गया था। वर्तमान तिथि के अनुसार, लगभग 3,705,568 ओसीआई कार्ड जारी किए गए हैं। वर्ष के दौरान, अब तक, जारी किए गए ओसीआई कार्ड की संख्या 191,613 है।

खुली थी और केवल पाँच हवाई अड्डों पर प्रवेश के लिए प्रतिबंधित थी। पिछले पांच वर्षों के दौरान, इस योजना को धीरे-धीरे उदार बनाया गया और दूसरे देशों

के लिए विस्तारित किया गया है। वर्तमान में, यह योजना 171 देशों / क्षेत्रों तक विस्तारित है और 28 भारतीय हवाई अड्डों 5 भारतीय बंदरगाहों को ई-वीजा सेवा प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। योजना पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में लागू की गई है। मार्च 2019 में, ई-वीजा को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया था यानी ई-टूरिस्ट वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस और ई-मेडिकल अटेंडेंट और अवधि 1 वर्ष तक बढ़ा दी गई। अगस्त 2019 में इसमें और उदारीकरण किया गया है । ई-टूरिस्ट वीजा की अवधि को 5 साल

पासपोर्ट सेवाएं

मंत्रालय का पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) डिवीजन भारत और विदेशों में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली पासपोर्ट सेवा सबसे उल्लेखनीय वैधानिक और नागरिक-केंद्रित सेवाओं के दायरे में आती है। मंत्रालय मातात्मक और गुणात्मक परिवर्तन कर रहा है, जिससे नागरिकों को समय पर, पारदर्शी, अधिक सुलभ, विश्वसनीय विधि से और सुव्यवस्थित वातावरण में सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं द्वारा और प्रतिबद्ध, प्रशिक्षित और प्रेरित कार्यबल पासपोर्टों की आपूर्ति की जा सके।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पासपोर्ट (साथ में अन्य यात्रा दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण पत्र, भारत लौटने के लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, सरेंडर सर्टिफिकेट, जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश में नियंत्रण रेखा यात्रा परमिट) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) द्वारा तथा 36 पासपोर्ट कार्यालयों के सम्पूर्ण भारत में विस्तारित भारतीय नेटवर्क, सीपीवी डिवीजन (केवल राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट) और अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के माध्यम से जारी किए जाते हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) स्वरूप में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) और 426 डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) (इन 36 पासपोर्टों के विस्तारित भाग के रूप में डाक विभाग के सहयोग से) को मिलाकर इन नेटवर्क का विस्तार किया गया है। पीएसके और पीओपीएसके सहित देश में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की कुल संख्या 31 दिसंबर, 2020 तक 519 थी। विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए, पासपोर्ट और इमरजेंसी सर्टिफिकेट 196 भारतीय मिशन / डाक के माध्यम से विदेशों में जारी किए जा रहे हैं।

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी)

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम (पीएसपी), एक मिशन के स्वरूप की परियोजना है जो सेवा प्रदाता के रूप में मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) स्वरूप में कार्यान्वित किया गया है और 12 जून, 2012 को इस सेवा के प्रारंभ के पश्चात् से ये पिछले साढ़े सात वर्ष से अपने प्रचालन सफलतापूर्वक कर हैं।

भारत और विदेश में मिशन / पोस्ट में पासपोर्ट सेवाएं

वर्ष 2020 के दौरान, मंत्रालय को भारत और विदेशों में उसके मिशन / पोस्ट के माध्यम से 66.8 लाख से अधिक पासपोर्ट और पासपोर्ट संबंधी आवेदन प्राप्त हुए थे।

और बढ़ा दिया गया है और कम शुल्क पर ई-टूरिस्ट वीजा की तीन-महीने की अवधि (30 दिनों के ठहराव के साथ) की नई श्रेणी प्रारंभ की गई। ऑफ सीजन के महीनों (अप्रैल-जून) में 3 महीने के ई-टूरिस्ट वीजा की फीस को और कम कर दिया गया है। सामान्य पेपर वीजा के संबंध में ई-वीजा का हिस्सा 2019 के लिए लगभग 46% है। ई-वीजा आवेदकों का रूझान निरंतर बढ़ रहा है। हालांकि, मार्च 2020 से ई-वीजा योजना चल रही कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण निलंबित है।

मंत्रालय ने वर्ष 2020 के दौरान भारत में लगभग 55.80 लाख पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित आवेदनों को पर प्रक्रिया की गई थी, जबकि वर्ष 2019 में यह आंकड़ा 1.18 करोड़ था। तथापि, भारत में 58.44 पासपोर्ट और संबंधित दस्तावेज जारी किए गए थे।

विदेशों में भारतीय मिशनों / पोस्टों ने 10.99 लाख पासपोर्ट और पासपोर्ट-संबंधित आवेदन प्राप्त किए और 9.82 लाख पासपोर्ट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट (ईसी) और पासपोर्ट से संबंधित अन्य विविध दस्तावेज जारी किए। इसमें 362,556 पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) और 24,507 इमरजेंसी सर्टिफिकेट (ईसी) शामिल थे, जिनमें से आधे से ज्यादा ईसी एमनेस्टी योजनाओं के दौरान विदेश में नागरिकों की कठिनाइयों को कम करने और उनके भारत लौटने के लिए जारी किया गया थे। इस प्रकार, भारत सरकार ने 2020 के दौरान 68.26 लाख से अधिक पासपोर्ट और पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेज जारी किए हैं।

राजस्व अर्जन

मंत्रालय ने सभी पासपोर्ट सेवाओं से वर्ष 2019 के दौरान अर्जित 1853.85 करोड़ रुपए की तुलना में कुल 2020 के दौरान 1346.60 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।। पासपोर्ट सेवा केंद्रों में वर्ष 2020 के दौरान कोविड -19 वैश्विक महामारी के दौरान लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण बहुत कम आवेदन आवेदन प्राप्त हुए थे जिससे मंत्रालय को 507.25 करोड़ रुपयें से कम आय हुई है।

पासपोर्ट सेवा आपूर्ति में सुधार

पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन और मंत्रालय द्वारा निरंतर किए गए प्रयासों से देश में पासपोर्ट सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) स्वरूप से देश भर में अच्छी सुविधाओं के साथ स्थापित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) से लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान की जा रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत आवेदकों को अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने, संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने, डेबिट / क्रेडिट कार्ड या भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) नेट बैंकिंग / एसबीआई चालान के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के पश्चात् नियुक्ति का समय निर्धारित करके पासपोर्ट सेवा केंद्र / डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना पड़ता है। यह पोर्ट उपयोगकर्ता के अनुकूल उपलब्ध कराया गया है। जब आवेदक पासपोर्ट सेवा केंद्र / डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाता है तो आवेदकों की आवाजाही की निगरानी के लिए

पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक कतार प्रबंधन प्रणाली (ईक्यूएमएस) सभी पासपोर्ट सेवा केंद्र / डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र में उपलब्ध करवाई गई है। आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को स्वयं पोर्टल और एसएमएस सेवाओं के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। पासपोर्ट जारी करने की वर्तमान प्रणाली में, किसी भी स्तर पर कोई मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होता है, और पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से एकल विज़िट क्लियरेंस के माध्यम से और उसके पश्चात् विशेष रूप से निर्मित प्रक्रिया के साथ प्रवाहित होती है ॥

एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप

एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन, अपॉइंटमेंट, पे और शेड्यूल अपॉइंटमेंट की अतिरिक्त सुविधाओं के साथ एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफार्मों में उपलब्ध है। वर्ष 2020 में, एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप का उपयोग करके 1.87 लाख आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। जुलाई 2016 में जारी किए जाने के पश्चात् से से इस ऐप से 8.06 लाख आवेदन प्राप्त किए गए हैं। पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए नागरिकों को कंप्यूटर और प्रिंटर तक पहुंच की आवश्यकता नहीं है। एम पासपोर्ट सेवा ऐप पासपोर्ट सेवाओं के नीचे दिए गए संवर्धित सेट को सपोर्ट करती है:

- i. नए यूजर का पंजीकरण
- ii. पंजीकृत यूजर एकाउंट में साइन इन
- iii. पासपोर्ट के लिए आवेदन फार्म भरना तथा पुलिस क्लियरेंस प्रमाणपत्र
- iv. पासपोर्ट सेवाओं के लिए भुगतान
- v. अप्वाइंटमेंट शैड्यूल करना
- vi. आवेदन जमा करने का स्ट्टेस जांचना
- vii. डाक्यूमेंट एडवाइजर
- viii. शुल्क कैलकुलेटर

भारत में कहीं से भी आवेदन करना

आवेदक अब भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय (पीओ) और इस प्रकार वांछित पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) / डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) पीओ सेवा चुनने की सुविधा दी गई है, जहां वे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहते हैं, भले ही वर्तमान आवासीय पता निर्दिष्ट हो आवेदन पत्र में चयनित पीओ के अधिकार क्षेत्र के भीतर हो अथवा न हो। पुलिस सत्यापन अधिकार क्षेत्र में वर्णित पते के पुलिस थाने द्वारा किया जाता है, और आवेदक द्वारा आवेदन जमा

करने के लिए चयनित पीओ द्वारा पासपोर्ट को भी प्रिंट किया जाएगा और उसी पते पर भेजा जाएगा। कैलेंडर वर्ष 2020 के दौरान इस योजना के तहत लगभग 9.11 लाख आवेदन प्रस्तुत किए गए थे।

नियुक्तियां

मंत्रालय द्वारा प्रति दिन लगभग 45,000 आवेदकों के लिए अप्वाइंटमेंट जारी की जाती है, जो 426 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के लिए लगभग 16,000 अप्वाइंटमेंट प्रतिदिन हैं। पासपोर्ट सेवा केंद्र में पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन नियुक्तियों को आसान बनाया गया है। वर्तमान प्रावधान आवेदकों को पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए नियुक्ति के समय-निर्धारण / पुनर्निर्धारण के लिए शुरुआती पांच उपलब्ध तारीखों (कार्य दिवसों) में से किसी भी नियुक्ति तिथि को चुनने की अनुमति दी जा रही है। इस विधि ने पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को आसान और त्वरित बना दिया है।

31.12.2020 की स्थिति के अनुसार अगले दिन के लिए 410 पासपोर्ट केंद्रों पर अप्वाइंटमेंट उपलब्ध थी, 2 से 7 दिनों के भीतर 72 पासपोर्ट केंद्रों के लिए तथा 7 दिन से अधिक की अवधि के लिए 37 पासपोर्ट केंद्रों पर अप्वाइंटमेंट उपलब्ध थी।

आवेदनों की संख्या

31.12.2020 की स्थिति के अनुसार प्राप्त होने वाले पासपोर्ट आवेदनों की संख्या के मामले में शीर्ष पांच राज्य थे केरल (6,59,728), महाराष्ट्र (5,71,861), पंजाब (4,77,822), तमिलनाडु (4,77,599) और उत्तर प्रदेश (4,75,612), जो 31 दिसंबर 2020 तक देश भर में प्राप्त कुल (55.8 लाख) आवेदनों लगभग 48% है।

31.12.2020 की स्थिति के अनुसार प्राप्त आवेदनों की संख्या के मामले में शीर्ष पांच पासपोर्ट कार्यालय मुंबई (3,63,708), बेंगलुरु (3,33,983), चंडीगढ़ (3,32,908), कोझीकोड (2,91,918) और अहमदाबाद (2,91,506) थे।

पासपोर्ट सेवा केंद्रों में ऑफसाइट पासपोर्ट सेवा शिविर और मेले

पासपोर्ट सेवा केंद्रों का आयोजन पासपोर्ट सेवा केंद्र / डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र से दूर निवास करने वाले नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न स्थलों पर किया जाता है।

नागरिकों पासपोर्ट की मांग की पूर्ति और पासपोर्ट सेवा केंद्र / डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र से अप्वाइंटमेंट प्राप्त करने में होने वाली असुविधा के विचार वर्ष 2020 के दौरान 62 पासपोर्ट मेलों का आयोजन किया गया था। इन मेलों में कुल 24,188 आवेदनों पर प्रक्रिया की गई थी।

2020 में निम्नलिखित सहित अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं :-

- (i) 28 फरवरी 2020 को, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम ने ग्राहक सेवा में नवाचार की

श्रेणी में सिल्वर स्टीवी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत में पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली में लाए गए परिवर्तन के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है।

- (ii) 28 नवंबर, 2020 पासपोर्ट सेवा परियोजना, पीएसपी डिवीजन, विदेश

पासपोर्ट सेवाओं की आउटरीच

क. पासपोर्ट कार्यालय

मंत्रालय ने आम जनता के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय किए गए हैं। इनमें पासपोर्ट संबंधी नियमों का सरलीकरण और पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के वितरण को सुगम बनाया जाना शामिल है। सरकार का उद्देश्य पासपोर्ट की मांग को पूरा करने और पासपोर्ट कार्यालयों से दूर रहने वाले लोगों तक अपनी पहुंच स्थापित करना है। 36 पासपोर्ट कार्यालयों की सूची अनुलग्नक में प्रस्तुत की गई है।

ख. पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके)

इसके अंतर्गत मंत्रालय द्वारा मई 2014 से 16 पीएसके खोले गए हैं, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर भाग के सभी राज्य शामिल हैं। 31 दिसंबर, 2020 की स्थिति के अनुसार देश में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्य कर रहे हैं। इन 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

ग. डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके)

मंत्रालय ने डाक विभाग (डीओपी) के साथ मिलकर 24 जनवरी, 2017 को प्रधान डाकघरों (एचपीओ) / डाकघरों (पीओ) में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने की घोषणा की थी, जिसे 'डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र' (पीओपीएसके) कहा जाता है। मंत्रालय ने अनुलग्नक की सूची के अनुसार 31 दिसंबर 2020 तक 426 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) की सुविधा प्रदान की है।

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) अन्य मौजूदा पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) की तरह काम करते हैं। पीओपीएसके के खुलने के बाद पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव नहीं हुआ है। आवेदक, जो पासपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, एक नियुक्ति का समय निर्धारित कर सकते हैं और फिर पासपोर्ट के संबंध में पीएसके में आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट पीओपीएसके पर जाते हैं। फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक्स और सहायक दस्तावेजों को पीओपीएसके में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किया जाता है और आवेदक को पासपोर्ट जारी करने से पहले उन्हें फिर से नहीं जाना होता है।

घ. विदेश स्थित मिशनों/केंद्रों का पीएसपी में एकीकरण

विदेशों में भारतीय मिशनों / पोस्टों को पीएसपी में एकीकृत करने की प्रक्रिया अक्टूबर 2018 में प्रारंभ किए जाने के पश्चात् से जारी है। इसका उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वह समान केंद्रीकृत पासपोर्ट जारी करने की आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध करवाना है जो पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए एकल केंद्रीकृत डेटाबेस पर की जाती है। मंत्रालय ने 147 भारतीय मिशनों /

मंत्रालय को 'रिस्पॉन्स टू कोविड' की श्रेणी में को 'स्कोच गोल्ड अवार्ड' प्रदान किया गया, जो महामारी की स्थिति के दौरान नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को समय पर सक्षम करने की स्वीकृति का प्रमाण है।

पोस्टों में पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को सफलतापूर्वक पीएसपी सिस्टम में एकीकृत कर दिया है। ये मिशन / पोस्ट विदेशों में जारी किए जाने वाले कुल पासपोर्टों में से 95% से अधिक पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। मंत्रालय शेष 45 भारतीय मिशनों / पोस्टों के एकीकरण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रहा है। संदर्भ अनुलग्नक में दिए गए हैं।

पुलिस सत्यापन

पासपोर्ट जारी किए जाने की प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय ने पुलिस सत्यापन को त्वरित बनाने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों के साथ मिलकर काम किया है। पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में 2020 में अब 18 दिन है। वर्ष 2020 के दौरान 88% सत्यापन 21 दिन में पूरे किए गए थे। पूरा हो गया (वर्ष 2019 में 87%)।

कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने कम समय में पुलिस सत्यापन करने की अपनी प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश पुलिस सत्यापन केवल दो दिनों में पूरी करती है और आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा चार दिनों में और केरल छह दिनों में पूरा करती है। मंत्रालय के निरंतर और ठोस प्रयासों से जिलों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे पसंदीदा जिला पुलिस मुख्यालय सत्यापन मॉडल पर स्विच कर रहे हैं। अब तक 833 पुलिस जिलों में से 795 पुलिस जिलों ने जिला मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया है।

मंत्रालय ने एंड-टू-एंड पेपरलेस डिजिटल प्रवाह के लिए एंड्रॉइड-आधारित mPassport Police App लॉन्च की है। ऐप में पासपोर्ट आवेदक के व्यक्तिगत विवरणों और तस्वीरों को कैचर करने और इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित स्टेटेधरकों को प्रेषित करने की प्रक्रिया की जाती है। ऐप के उपयोग से पुलिस द्वारा क्षेत्र सत्यापन की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदक के निवास स्थान के स्थान निर्देशांक को भी किया जा सकता है। 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 243 जिला पुलिस मुख्यालय mPassport Police App का उपयोग कर रहे हैं। MPassport Police App की शुरुआत के बाद से 31 दिसंबर 2020 तक कुल 84,42,181 आवेदन मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं।

शासन व्यवस्था को प्रबल बनाने और अधिकतम सरकारी सेवाएं करने के लिए कार्यात्मक संवर्धन / प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना

(क) भारत और विदेश में रहने वाले नागरिकों की कठिनाईयों को न्यून करने के उद्देश्य से पासपोर्ट की अवधि समाप्ति के 3 वर्ष तक पश्चात् पुनः जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने की तिथि के अनुसार सभी मामलों को नो-पीवी के आधार पर निपटा दिया जाएगा।

(ख) पीसीसी के लिए दिशानिर्देश में अन्य ों के साथ साथ यह उल्लेख है कि व्यक्तिगत विवरणों में किसी भी परिवर्तन अर्थात पते का परिवर्तन; पति / पत्नी के नाम आदि के लिए आवेदकों को पहले नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होता है और फिर पीसीसी के लिए आवेदन करने से संबंधित प्रक्रिया को उचित रूप से उदार बनाया गया है। पीसीसी के लिए वर्तमान पते में परिवर्तन और पति या पत्नी के नाम के अतिरिक्त परिवर्तन के लिए आवेदक को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

पासपोर्ट सेवा दिवस 2020

पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून, 2020 का आयोजन दिनांक 24 जून, 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। इस अवसर को स्मृतिमय बनाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विदेश मंत्री और राज्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पासपोर्ट अधिकारियों को संबोधित किया गया था।

अपने मुख्य भाषण में, विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के पिछले छह वर्षों के दौरान पासपोर्ट वितरण प्रणाली में एक पूर्ण परिवर्तन हुआ था। उन्होंने यह बताया कि देश में अधिक पीओपीएसके खोलकर पासपोर्ट सेवाओं को लोगों के करीब ले जाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विदेश मंत्रालय को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने दोहराया कि पासपोर्ट बनाने के नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए। इसके अलावा, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। MPassport Police और mPassport Seva Apps जैसी पहल से सिस्टम और ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार आया है। ई-पासपोर्ट की प्रक्रिया इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

अपने संबोधन में, राज्य मंत्री ने हमारे नागरिकों के लाभ के लिए पारदर्शी और कुशल पासपोर्ट वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में करने के लिए भारत और विदेशों में सभी पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी कहा कि एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र, जिसे दक्षता के लिए सीपीग्राम में मान्यता दी गई थी, से हमारी सेवाओं की डिलीवरी में और सुधार किया।

पासपोर्ट सेवा पुरस्कारों की घोषणा सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाएं करने वाले पासपोर्ट कार्यालयों और सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मियों के लिए की गई थी। पुलिस सत्यापन पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए पुलिस विभागों द्वारा पुलिस क्लीयरेंस के लिए प्रदान की गई त्वरित पुलिस मंजूरी के लिए पुलिस विभाग का विशेष उल्लेख इस अवसर पर किया गया था।

लोक शिकायत निवारण तंत्र

पासपोर्ट सेवा परियोजना के अंतर्गत विदेश मंत्रालय ने एक सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली का व्यवस्था पन किया है, जिसमें शिकायतों और नागरिक प्रतिक्रिया से निपटने सहित पासपोर्ट संबंधी विभिन्न सेवाओं के बारे में जानकारी का प्रसार 17 भाषाओं में और 24X7 आधार पर काम कर रहे एक टोल फ्री नंबर (1800-258-1800) के साथ एक बहुभाषी राष्ट्रीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है तथा यह वर्तमान में एक केंद्रीय सिस्टम प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहा है। इसमें वर्ष 2020 में प्रति दिन लगभग 9,000 कॉल प्राप्त हुई हैं (जिसमें से 46% हिंदी में थे, 29 अंग्रेजी में% और क्षेत्रीय भाषाओं में 25% थी)। पासपोर्ट

पोर्टल में एक ईमेल-आधारित हेल्पडेस्क भी है, जहां सुझावों और शिकायतों के लिए लॉग इन किया जा सकता है। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने पासपोर्ट आवेदन / शिकायत की स्थिति की ऑनलाइन निगरानी भी कर सकते हैं।

संयुक्त सचिव (पीएसपी) तथा सीपीओ के सुपरवीजन में पीएसपी डिवीजन में एक सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (पीजीआरसी) की स्थापना की गई है, जिसे केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के लिए लोक शिकायत मंत्रालय के निदेशक के रूप में भी नामित किया गया है। यह आम जनता से सीधे टेलीफोन, ई-मेल और डाक के माध्यम से सीधे प्राप्त की जाने वाली शिकायतों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों जैसे कि राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए है। इसके अलावा, सभी पासपोर्ट कार्यालय (पीओ)) द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सीपीग्राम वेबसाइट (https://pgportal.gov.in) और पासपोर्ट शिकायतों अर्थात सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) के अंतर्गत पासपोर्ट पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जनता की शिकायतों का समाधान किया जाता है। सूचना और सुविधा काउंटर, लोक शिकायत प्रकोष्ठ, शिकायत / सुझाव बॉक्स और आवेदकों की सहायता और शिकायतों / शिकायतों के समाधान में तीव्रता लाने के लिए पीओ और पीएसके जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। लोक शिकायत अधिकारी का नाम, पता और फोन नंबर पीओ / पीएसके और पीओ की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं। एक समय-सीमा नागरिकों से किसी भी शिकायत की जांच करने और उसका निवारण करने की समय सीमा के साथ सभी पीओ में एक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है।

सीपीग्राम के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान 25,237 शिकायतें प्राप्त हुईं (2019 की बकाया 119 शिकायतों सहित) थी जिसमें से 25,050 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस अवधि के दौरान, 58,464 सार्वजनिक शिकायत याचिकाएं (ईमेल, पोस्ट, फैक्स, जो शिकायतों / पृष्ठताछ से संबंधित हैं और ऊपर बताए अनुसार सीपीग्राम से प्राप्त 33,227 सम्मिलित हैं) प्राप्त हुईं, जिनमें से 58,254 शिकायतों का निपटान किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए निर्देशों के साथ आवेदन की अद्यतन स्थिति वेबसाइट पर पोस्ट जाती है, जिसे जनता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।

पासपोर्ट अदालतें

पासपोर्ट कार्यालय पासपोर्ट आवेदकों की शिकायतों के निवारण के लिए नियमित रूप से पासपोर्ट अदालतों का आयोजन करते हैं। 2017 में आवेदकों के साथ सीधे बातचीत के माध्यम से कुछ 7000 पुराने और जटिल मामलों के निपटान में ये अदालतें काफी उपयोगी रहीं हैं।

हज यात्री

भारतीय हज समिति (संसद के अधिनियम, संख्या 35, 2002 के अंतर्गत गठित) द्वारा यह निर्णय लिया गया है, केवल मान्य पासपोर्ट धारक ही हज के लिए आवेदन कर सकते हैं। पिछले वर्षों की तरह, सभी पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे संभावित हज यात्रियों के पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया को उच्च प्राथमिकता दें और अपेक्षित दस्तावेज, पुलिस

सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाने, सुविधा काउंटर खोलने, ऐसे आवेदकों के लिए नियुक्ति स्लॉट आरक्षित करने और बहुत ही त्वरित तरीके से ऐसे नागरिकों से प्राप्त अनुरोधों / शिकायतों की याचिकाओं पर प्रक्रिया करने का सुनिश्चय करें।

पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण

सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई)

सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पीएसपी डिवीजन में भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सीपीओ) केवल मंत्रालय में पीएसपी डिवीजन से संबंधित मामलों के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। 17 जून 2014 से, सभी पासपोर्ट कार्यालयों में एक सीपीआईओ पोर्टल ऑनलाइन बनाया गया है। वर्ष 2020 के दौरान, कुल 5,880 ऑनलाइन सूचना अधिकार आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5,454 का निस्तारण किया गया है।

अपील (पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत)

पीआईए के निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रभावित व्यक्तियों को पासपोर्ट अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत प्रदत्त वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। संयुक्त सचिव (पीएसपी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी इन मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकरण है। दिसंबर 2020 तक, 16 अपील सत्र आयोजित किए गए, जिनमें 41 अपीलकर्ताओं / काउंसल्स की सुनवाई की गई है।

यात्रा दस्तावेजों का निर्माण करना एवं उन्हें व्यक्ति आधारित करना

सभी भारतीय यात्रा दस्तावेजों का निर्माण भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक द्वारा किया जाता है, जो कि सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के अध्यक्षीन एक इकाई है। भारतीय पासपोर्ट की समग्र गुणवत्ता, कार्यक्षमता और सुरक्षा में सुधार करने के लिए, विभिन्न उपाय किए गए हैं। पासपोर्ट कार्यालयों में नए डिजाइन और लेआउट में पासपोर्ट पुस्तिकाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सभी पासपोर्ट कार्यालय, मुख्यालय और विदेशों में चुनिंदा मिशन / पोस्टों को मशीन पठनीय पासपोर्ट प्रिंटर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी पासपोर्ट कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मशीन-पठनीय पासपोर्ट जारी करते हैं।

पीएसपी डिवीजन की नई दिल्ली में स्थित सेंट्रल इंडियन पासपोर्ट प्रिंटिंग सिस्टम (सीआईपीपीएस) में विदेशों में स्थित 168 दूतावासों / कांसुलेटों और सहायक सचिव (पासपोर्ट) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर के लिए घोस्ट इमेज सुरक्षा फीचर के साथ मशीन पठनीय पासपोर्ट (एमआरपी) मुद्रित होते हैं। सीआईपीपीएस ने दिसंबर 2020 तक (487 राजनयिक पासपोर्ट और 397 आधिकारिक पासपोर्ट सहित) 1,43,858 पासपोर्ट मुद्रित किए। विदेश में सीआईपीपीएस / ओसीआई कक्ष और मिशनों में वर्ष के दौरान व्यक्ति आधारित

विभिन्न राज्यों में पासपोर्ट कार्यालयों के साथ-साथ पीएसके और पीओपीएसके का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि उनकी प्रक्रियात्मक और परिचालन दक्षता और संतोषजनक ढंग से नागरिक केंद्रित सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता में सुधार हो सके। पूरे भारत में पासपोर्ट सेवा केंद्रों का नियमित आधार पर गैर-तकनीकी सेवारत स्तरीय समझौतों (एसएलए) के अंतर्गत भी निरीक्षण किया गया है।

1,91,613 ओसीआई कार्डों का मुद्रण भी किया गया है।

ई-पासपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की अनुशंसाओं के अनुसरण में मशीन पठनीय यात्रा दस्तावेजों में बायोमेट्रिक डेटा को शामिल करने लिए भारत ने अपने मौजूदा पासपोर्ट को उन्नत करने और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर मुद्रण और कागज की गुणवत्ता के साथ नागरिकों के लिए सक्षम ई-पासपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार ने भारतीय सुरक्षा प्रेस (आईएसपी), नासिक को ई-पासपोर्ट के विनिर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनिक संपर्क रहित इनले की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। ई-पासपोर्ट से जालसाजी और फेरबदल के प्रति अधिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।

अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ)

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) की मशीन पठनीय यात्रा दस्तावेजों के तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) के सदस्य की भूमिका का निर्वाह किया है और एमआरटीडी के संबंध में आईसीएओ के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करता रहा है। आईसीएओ दस्तावेज 9303 के अनुबंधों के अनुसरण में इकाओ के नागर विमानन सुरक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विश्व स्तर पर इंटर-ई-पासपोर्ट सत्यापन योजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्रीय संदर्भ के रूप में आईसीएओ द्वारा पब्लिक की डायरेक्ट डायरेक्टरी (पीकेडी) की स्थापना लागत का सहभाजन करने के आधार पर की गई है। पीकेडी बोर्ड के सदस्यों को पीकेडी के भागीदार देशों द्वारा नामित किया जाता है और आईसीएओ परिषद द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। भारत फरवरी 2009 से आईसीएओ पीकेडी का सदस्य है।

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन

केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) का गठन 1959 में मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में किया गया था और इसका नेतृत्व संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी करते हैं, जो पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी और वित्तीय शक्तियां नियमावली, 1978 के अंतर्गत विभाग के प्रमुख के रूप में नामित है।

1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार सीपीओ की स्वीकृत जनशक्ति 2741 और कार्यबल 1804 था। इसके अलावा, 15 तकनीकी और 6 सहायक कर्मचारी पासपोर्ट सेवा परियोजना के परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) के अंतर्गत थे। वर्तमान में समूह 'क' स्तर पर 38, समूह 'ख' के राजपत्रितस्तर पर 541 और समूह 'ग' में गैर-राजपत्रितस्तर पर 358 अर्थात 937 रिक्तियां हैं। समूह

‘क’ स्तर पर अन्य सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी प्राप्त करके रिक्तियां भरी गई हैं। मंत्रालय ने स्वीकृत शक्ति और गैर-राजपलित की कार्य क्षमता के बीच अंतर को पाटने के उद्देश्य से एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पासपोर्ट कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए रिक्त गैर-राजपलित पदों के प्रति 347 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 51 कार्यालय सहायकों (एमटीएस) को भी तैनात किया है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 4 सहायक अधीक्षक, 17 कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक, 8 कार्यालय सहायक (एमटीएस), 33 कनिष्ठ अनुवादक और 1 आशुलिपिक (ग्रेड- II) के पदों को भरने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है।

मंत्रालय ने सीपीओ कैडर की पुनः संरचना और विस्तार करके सीपीओ कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे उपलब्ध रिक्त पद भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधनों के साथ तेजी से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का सुनिश्चय किया जा सके। उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस) मानदंडों के आधार पर पूर्व-निर्धारित और पारस्परिक रूप से सहमति के आधार पर व्यक्तिगत प्रदर्शन को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। यह भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अनूठी योजना है। सीपीओ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई मेधावी सेवाओं को मान्यता देने की दृष्टि से और इस प्रकार, देश में शासन को बेहतर बनाने में योगदान करते हुए, पासपोर्ट सेवा पुरस्कारों की स्थापना की गई है। प्रतिवर्ष पासपोर्ट अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान पासपोर्ट कार्यालयों के चयनित कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की नियमित बैठकें वर्ष के दौरान सीपीओ में आयोजित की गई हैं। दिसंबर 2020 तक वरिष्ठ अधीक्षक से 04 वरिष्ठ अधीक्षक, सहायक अधीक्षक से 160 अधीक्षक, वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक से 02 सहायक अधीक्षक, जूनियर पासपोर्ट सहायक से 26 वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक, और जूनियर अनुवादक के लिए 09 वरिष्ठ अनुवादक की पदोन्नति के लिए मंजूरी दी गई है। वरिष्ठ पासपोर्ट अधीक्षक के सहायक पासपोर्ट अधिकारी (एपीओ) के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी के प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किए गए हैं। सीपीओ के अठारह अधिकारियों को विभिन्न ग्रेडों में एमएसीपी के लिए विचार में लिया गया था। 18 में से 3 सहायक अधीक्षक, 1 वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक, 9 जूनियर पासपोर्ट सहायकों, 1 जूनियर अनुवादक, 02 कार्यालय सहायकों और 2 चालकों को एमएसीपी दिया गया है। 82 अधिकारियों अर्थात् 22 सहायक अधीक्षक, 16 जूनियर पासपोर्ट सहायक, 37 कार्यालय सहायक, 3 जूनियर अनुवादक और 4 आशुलिपिक (ग्रेड- II) की विभिन्न ग्रेड में पुष्टि की गई है।

कैडर समीक्षा: केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (सीपीओ) द्वारा 2010 से 2020 तक 36 पासपोर्ट कार्यालयों, 93 पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 426 पीओपीएसके के नेटवर्क के माध्यम से संसाधित किए गए पासपोर्ट आवेदनों में 100% वृद्धि के मद्देनजर, कैडर पुनर्गठन और सीपीओ की कैडर शक्ति की समीक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई है। व्यय विभाग की कर्मचारी निरीक्षण इकाई (एसआईयू) द्वारा सीपीओ के भौतिक निरीक्षण और स्टाफ के अध्ययन के लिए एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को नवंबर 2019 में भेजा गया है।

23

प्रवासी भारतीय मामले

ओआईए-1

कोविड-19 महामारी के साथ पूरे विश्व को तहस-नहस करते हुए 2020-21 बहुत चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस वायरस से अपने देशवासियों का जीवन बचाने के लिए देश-व्यापी लॉकडाउन को लगाना पड़ा। जैसा कि विदेशों में फंसे लाखों असहाय भारतीयों की देशवापसी के लिए वंदे भारत मिशन उड़ाने सरकार द्वारा प्रारंभ की गई, विश्वभर में फंसे भारतीयों को

हर प्रकार की यथासंभव सहायता प्रदान की गई। लॉकडाउन के कारण प्रभाग की कई योजनाओं और लक्ष्यों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है, तथापि, जहाँ भी संभव हो पाया है, आनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए कामों को जारी रखने का प्रयास किया गया। इस प्रभाग के संबंध में 2020-21 के अंतर्गत मुख्य प्रगतियां निम्नानुसार है:

भारतीय समुदाय कल्याण निधि (आईसीडब्ल्यूएफ)

2009 में स्थापित, भारतीय समुदाय कल्याण निधि का लक्ष्य एक साधन परीक्षण के आधार पर सबसे आवश्यक मामलों में संकट और आपातकाल के समय में प्रवासी भारतीय नागरिकों की सहायता करना है। भा.स.क.नि. कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण सहायक रहा है। निधि से सहायता लेकर, हमारे मिशनों/प्रहरियों ने मौजूदा दिशानिर्देशों के क्रम में आगे बढ़कर असहाय तथा

फंसे हुए भारतीय नागरिकों की मदद की। 31 दिसंबर 2020 तक 1,56,000 से अधिक भारतीयों को सुविधा पहुँचाने में लगभग 33.5 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका था। यह सहायता निकासी, बोर्डिंग एवं लॉजिंग, चिकित्सा देखभाल, देशवापसी और अन्य विविध मामलों जैसे कि मास्क, खाने के पैकेट और सुखा राशन प्रदान करने के लिए प्रदान की गई।

भारतीय प्रवासी मजदूरों का कल्याण एवं सुरक्षा

2020-21 के दौरान, जापान के साथ एक सहयोग का ज्ञापन, “विशिष्ट कौशल कामगार” योजना के अंतर्गत जो कि जापान की एक श्रेणी है, भारतीय कुशल कामगारों की गतिशीलता के लिए 18 जनवरी 2021 को हस्ताक्षरित किया गया था।

प्रवासन एवं गतिशीलता के लिए भारत-ईयू की आम कार्ययोजना (सीएएमएम) परियोजना सलाहकारी समिति (पीएसी) की तीसरी बैठक वर्चुअल माध्यम से 2 जुलाई 2020 को आयोजित हुई थी। अगले एक साल के दौरान सीएएमएम के सभी चारों स्तंभों के संतुलित कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए की जाने वाली

गतिविधियों पर बनी आम सहमति के साथ बैठक समाप्त हुई। भारत ने यूएई की अध्यक्षता में प्रवासन एवं गतिशीलता पर ऑनलाइन जीएफएमडी-एडीडी क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रियाओं में भाग लिया।

2020-21 के दौरान भारतीय मजदूर कल्याण पर एक संयुक्त समिति बैठक भी

आयोजित हुई थी। इसके अलावा, प्रवासन एवं गतिशीलता मामलों में सहभाग पर करारों/समझौता ज्ञापनों को हस्ताक्षरित करने में कई देशों जैसे कि रूस, बेनेलक्स देशों, पुर्तगाल एवं यूके के साथ वार्तालापों में आगे की कार्यवाई की गई।

प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई)

विदेश मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता (एमएसडीई) के मध्य एक संयुक्त साझेदारी, प्रवासी कौशल विकास योजना (पीकेवीवाई), विदेशों में उनके रोजगार की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के क्रम में, चयनित क्षेत्रों एवं कार्य भूमिकाओं में सशक्त प्रवासी मजदूरों को उनके कौशल के संवर्धन को लक्षित करती है।

इस योजना के दो घटक हैं। पहला, राष्ट्रीय कौशल विकास कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी) के माध्यम से एमएसडीई द्वारा प्रदान किया जाने वाला, पूर्व के अधिगमों को मान्यता देना, मूल्यांकन एवं प्रमाणन वाला एक तकनीकी टॉप-अप प्रशिक्षण है। दूसरा प्रशिक्षण विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला व्यवहार कौशल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसे “प्रस्थान-पूर्व अनुकूलन एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी)” कहते हैं, यह एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

जहाँ एक बाजार-आधारित, टॉप-अप कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का विकास एमएसडीई द्वारा किया जा रहा है वहीं विदेश मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पीडीओटी प्रशिक्षण भी काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मंत्रालय द्वारा एमएसडीई एवं राज्य सरकारों के सहयोग से खोले गये 28 पीडीओटी केंद्रों में से भुवनेश्वर, कोलकाता, तिरुअनंतपुरम, अमृतसर एवं जालंधर में पाँच नये प्रशिक्षण केंद्र अक्टूबर 2020 में खोले गये थे। देश में प्रमुख विदेशी प्रवासी स्थानों पर अन्य बहुत से केंद्रों की स्थापना की योजना बनाई गई है। 20 जनवरी 2021 तक लगभग 96,000 प्रत्याशित प्रवासियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। 5 लाख कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, मौजूदा ऑफलाइन कक्षा प्रशिक्षण मॉडल के अतिरिक्त एक ऑनलाइन पीडीओटी मॉडल को अपनाया जा रहा है।

प्रवासन हेतु भारतीय केंद्र

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन से संबंधित सभी मामलों पर प्रवासन हेतु भारतीय केंद्र (आईसीएम) मंत्रालय का एक अनुसंधान विचार मंच है। आईसीएम के व्यापक क्षेत्रों की गतिविधियां अनुसंधान, क्षमता निर्माण एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन एवं गतिशीलता से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करना शामिल है। वर्ष के दौरान, आईसीएम ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन पर तथा वापस आने वाले प्रवासियों के प्रवाह पर कोविड 19 के प्रभाव पर दो विशेष रिपोर्टें तैयार की थीं जिससे कि उपयुक्त पुनःएकीकरण उपायों को प्रचलन में लाया जा सके।

आईसीएम की सामान्य परिषद बैठक के दौरान दिसंबर 2020 में लांच किए जाने हेतु आईसीएम ने कानून प्रवर्तन एजेन्सियों तथा महिला कामगारों पर दो हैंडबुक भी विकसित की थी। कोविड-19 के प्रभाव पर विशेष फोकस करते हुए प्रवासन एवं गतिशीलता से संबंधित थीमों पर अठारह पैनल विमर्श वर्ष 2020-21 के दौरान आयोजित किए गए थे और अन्यों को आयोजित किया जाना क्रम में है। इसके अलावा, पीडीओ ट्रेनिंग टीचर्स के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की गई।

ओआईए-II

विदेशी भारतीय मामला प्रभाग-II, भारतीय प्रवास से संबंधित मामलों को डील करता है। इस प्रभाग द्वारा डील किए जाने वाली योजनाओं में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, प्रवासी भारतीय दिवस कांफ्रेंसेस, क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस, भारत को जाने कार्यक्रम, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, भारत को

जाने क्रिज, एनआरआई वैवाहिक विवादों, प्रवासियों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, छात्रों के मामले, प्रवास से संबंधित शिकायतें, प्रवास से संबंधित कोई और मामला तथा सरकार द्वारा समय-समय पर की जाने वाली नयी पहलें शामिल हैं।

प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी)

विदेशी भारतीय समुदाय के भारत सरकार से संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए तथा भारत में उनकी जड़ों से उन्हें पुनः जोड़ने के लिए 2015 से पीबीडी को प्रत्येक दो वर्षों में एक बार मनाया जाता है। सम्मेलन के दौरान, चुनिंदा विदेशी भारतीयों को, भारत और विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में उनके शानदार योगदान के लिए प्रतिष्ठित “प्रवासी भारतीय सम्मान” के पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

प्रमुख पीबीडी सम्मेलन के लिए, दिल्ली में दो पीबीडी सम्मेलनों के बीच थीम आधारित पीबीडी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिन्हें बाद में पीबीडी सम्मेलनों के दौरान आयोजित होने वाले प्रारंभिक सत्रों में प्रदर्शित किया जाता है।



प्रधान मंत्री ने 9 जनवरी, 2020 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया

16वें पीबीडी सम्मेलन को “आत्मनिर्भर भारत में योगदान” थीम पर, वर्चुअल अथवा हाईब्रिड मोड पर 9 जनवरी, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पीबीडी सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया। सम्मेलन में प्रवासियों के प्रख्यात सदस्यों को, आत्मनिर्भर भारत के विजन को

आगे बढ़ाने में प्रवासन कैसे भूमिका अदा कर सकता है तथा कोविड के बाद विश्व की स्थिति विषयों पर विमर्श करते हुए पाया गया। राष्ट्रपति जी ने पीबीडी को चिन्हित करते हुए समापन भाषण दिया।

विदेश में रहने वाले भारतीय बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एसपीडीसी)

विभिन्न क्षेत्रों (मेडिकल एवं इससे संबंधित क्षेत्रों को जो छोड़कर) में भारतीय विश्वविद्यालय संस्थानों में उच्च शिक्षा को विदेश में रहने वाले भारतीय बच्चों की पहुंच में लाने तथा भारत को उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा एसपीडीसी को वर्ष 2006-07 के शैक्षणिक वर्ष में प्रारंभ किया गया था वर्तमान में इस योजना के अधीन भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओ, प्रवासी भारतीयों तथा ईसीआर देशों के भारतीय कामगारों के बच्चों को डेढ़ सौ छात्रवृत्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। इसमें भारत में केंद्रीय

विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ष 4000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष प्रदान करना शामिल है यह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यय भारत परिषद द्वारा प्रदत्त ‘ए’ ग्रेड संस्थानों तथा डीएसएए (DASA) योजना के अधीन आने वाले अन्य संस्थानों पर भी लागू है। शैक्षणिक वर्ष 2006-07 के दौरान 1227 छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी हैं। कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 अकादमिक वर्ष हेतु योजना की घोषणा नहीं की गई है।

प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना (पीटीडीवाई)

भारतीय मूल के 45 से 65 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों को उनकी जड़ों से दोबारा जोड़ने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पीटीडीवाई को वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रारंभ किया गया था। यह कार्यक्रम गिरमिटिया देशों, फिजी, गुयाना, मोरिशियस, सूरीनाम, लिनियाद एवं टोबैगो की यूनिजन आइसलैंड रीप के उन भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो न्यूनतम आय समूहों से हैं तथा भारत की यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं। यह एक 17 दिवसीय कार्यक्रम

है तथा भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से संचालित किया जाता है 160 पीआईओ की भागीदारी से अभी तक इस कार्यक्रम के चार संस्करण सफलतापूर्वक संचालित किए जा चुके हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केआईपी के दो संस्करण अनुसूचित हैं लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अभी तक इनकी घोषणा नहीं हो पाई है।

प्रवासियों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना (पीसीटीडी)

पीसीटीडी के अंतर्गत ओआईए- II प्रभाग भारतीय मिशन विदेशी भारतीय समुदायों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने भारतीय विरासत एवं संस्कृति की असाधारण भव्यता को संरक्षित रखने एवं प्रदर्शित करने के उद्देश्यों हेतु की जाने वाली पहलों में समर्थन के लिए अनुदान प्रदान करता है। यह योजना भारत तथा इसके प्रवासियों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को पोषित एवं मजबूत करने का उद्देश्य रखती है इस योजना का लक्ष्य प्रवासी भारतीय मूल के व्यक्तियों को संस्कृति की पहचान पर पूर्ण बल देना है। विदेशी भारतीय समुदायों को आयोजित

करने वाले भारतीय विचार मंचों तथा संगठनों को अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष में 40 मिशनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

डेटा रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर (डीआरआरसी), नई दिल्ली की अनुसंधान गतिविधियों के लिए अंतर राष्ट्रीय सहयोग परिषद (एआरएसपी) को वित्तीय अनुदान भी दिया गया है।

भारत को जानें कार्यक्रम (केआईपी)

केआईपी इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ वित्तीय वर्ष 2003-04 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य विदेश में रहने वाले 18 से 30 वर्ष के भारतीय युवाओं को अपनी मातृभूमि से जोड़ने तथा समकालीन भारत में घटित हो रहे परिवर्तनों से उन्हें परिचित कराते हुए मोटिवेट कराना है यह कार्यक्रम उन्हें भारत की कला कौशल विरासत संस्कृति के विविध रूपों से उन्हें परिचित कराने का लक्ष्य भी

रखता है। इसके प्रारंभ से मंत्रालय अभी तक इस कार्यक्रम के 57 संस्करण संचालित कर चुका है जिसमें कुल 2061 प्रवासियों युवाओं ने अपनी भागीदारी की है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केआईपी के 6 संस्करण अनुसूचित किए गए हैं लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अभी तक इनकी घोषणा नहीं हो पाई है।

जागरूकता अभियान एवं मीडिया योजना

जैसा कि विज्ञापन अनुमोदन परिषद (एएसी) द्वारा सुझाया गया है कि विज्ञापनों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जा सकता है तथा न्यूनतम खर्च पर सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। तदनुसार, प्रभाग ने अनेकों प्रतिष्ठित व्यक्तियों से स्वैच्छिक आधार पर उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए संपर्क किया कई प्रतिष्ठित व्यक्ति मीडिया जागरूकता अभियान के लिए स्वैच्छिक आधार पर अपना समय (40 से 50) सेकंड देने के लिए तैयार हुए हैं।

विदेशी मामलों की स्थाई समिति की संस्तुतियों के अनुसार इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन प्रभाव मूल्यांकन को संचालित कर रहा है इसके अनुसंधान, गतिविधियों पर आधारित रिपोर्टों को नवंबर 2020 में जमा किया गया जिसके बाद अध्ययन की प्राथमिक खोजें 2020 में पूरी की गईं अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2021 में जमा की गई।

विदेश मंत्रालय राज्य पहुंच सम्मेलन

विदेश मंत्रालय ने हाल में वर्षों में विदेशी भारतीय समुदायों के कल्याण एवं सुरक्षा को लक्ष्य बनाते हुए उनके पहले लॉज तथा विश्व भर में भारतीय प्रवासियों के साथ हमारे संबंधों को मजबूती देने के लिए प्रारंभ की है इस उद्देश्य के साथ विदेश संपर्क के बैनर के साथ 2017 में विदेश मंत्रालय ने राज्य में पहुंच कार्यक्रम को प्रारंभ किया था जो कि मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के बीच बहुत महत्वपूर्ण है। इन राज्य पहुंच कार्यक्रमों को तेलंगाना (2017) महाराष्ट्र (2017) तथा केरल (2017) गुजरात (2018) तथा मध्य प्रदेश (2018) के साथ साझेदारी करके विदेशों में हमारे नागरिकों की रक्षा एवं कल्याण से संबंधित मुद्दों के समाधान के

लिए तथा विदेशी भारतीय समुदाय के संबंधों तथा कल्याण से संबंधित मंत्रालय की पहलों के विषय में राज्य सरकारों को बताने एवं गैर कानूनी प्रवासन पर बल देने हेतु राज्य पहुंच कार्यक्रमों की आयोजन किया गया।

2019 के बाद से, विदेश मंत्री द्वारा निवेश, व्यापार और विदेशी संबंधों को कवर करने के लिए सहभागिता के दायरे के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। इस नए आदेश के साथ विदेश संपर्क कार्यक्रम बेंगलुरु कर्नाटक में 26 फरवरी 2020 को आयोजित हुआ था

अनिवासी वैवाहिक मतभेद

विदेश मंत्रालय के पास भारतीय नागरिकों ज्यादातर महिलाओं जो विशेषकर विदेशी व्यक्तियों से विवाहित हैं तथा और अपने अनिवासी भारतीय पति पत्नी द्वारा पीड़ित एवं सताएं हुए हैं से बड़ी संख्या में याचिकाएं एवं शिकायतों के मामलों जैसे कि उनके पति पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा। यह जानने के लिए कि उनकी वर्तमान

स्थिति क्या है के संबंध में प्राप्त होती हैं। प्रति वर्ष पत्नी को वापस भेजने इसके अलावा संभरण तलाक अथवा बच्चों की रखवाली एवं कानूनी तथा वित्तीय संबंधी, जीवन साथी के विरुद्ध केस दायर करने के लिए वित्तीय सहायता आवेदन दर्ज किए जाते हैं। 1 अप्रैल 2020 तथा 31 अक्टूबर 2020 के बीच में मंत्रालय ने

अपने पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं की 618 शिकायतों का निवारण किया मंत्रालय ने सुनिश्चित किया कि याचिका कर्ताओं को परामर्श की क्रियाओं के विषय में मार्गदर्शन एवं जानकारी विदेशी भारतीय जीवन साथी को व्यक्तिक सम्मान प्रदान करना। मंत्रालय ने सुनिश्चित किया है कि याचिकाकर्ताओं को परामर्श, मार्गदर्शन और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी, प्रवासी भारतीय पति /

पत्नी पर न्यायिक समन भेजने के लिए व्यवस्था, भारत में केस दर्ज करना, लुक आउट सर्कुलर जारी करना, पति या पत्नी के भारतीय पासपोर्ट को रद्द करना, प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। भारतीय मिशनों की पहुंच वकीलों और गैर सरकारी संगठनों तक है।

भारत को जानिए

प्रधानमंत्री द्वारा 13 वी पीबीडी सम्मेलन जो 8 जनवरी 2015 को गांधीनगर में हुआ था उस में की गई घोषणा के क्रम में विदेशी युवा भारतीयों को अपने संबंधों को मजबूत बनाने एवं उनको उनके मूल देशों को अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में 18 से 35 वर्षों के आयु वर्ग के युवा विदेशी भारतीयों के लिए एक ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज का आयोजन 2015-16 में किया गया इसके अंतर्गत क्विज 2018-19 में आयोजित किया गया था।

तीसरे चरण की भारत को जानिए (बीकेजी) क्विज 2020-21, 30 सितंबर 2020 को लांच हुई थी इस क्विज में ऑनलाइन फॉर्म्स में चार चरण थे बीकेजी

3 श्रेणियों की प्रतिभागियों के लिए खुली थी पीआईओ एनआरआई एवं 18 से 35 वर्ष के विदेशियों के लिए लिंक www.bharatkojaniye.in है। अनेकों प्रतिस्पर्धी चरणों में प्रतिभाग करने के साथ कुल 15 विजेताओं, प्रत्येक श्रेणी से पांच का चयन किया जाता है तथा प्रत्येक श्रेणी को शेष तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। जनवरी 2021 में पीकेडी इवेंट के दौरान बीकेजे क्विज़ के फाइनलिस्ट को सम्मानित किया गया। क्विज़ के नवीनतम संस्करण के सभी 15 विजेताओं को कोविड की स्थिति में सुधार के बाद भारत के दौरे के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

24

नई, उभरती हुई एवं रणनीतिक प्रौद्योगिकियां

आगे के अवसरों की पहचान करते हुए अर्थव्यवस्थाओं, रोजगार, सुरक्षा, सामाजिक इकटिरी और वैश्विक संबंधों को कमजोर करने वाले विघटनकारी, भविष्यवादी, उभरती हुई, रणनीतिक और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को समझने, विश्लेषण करने और प्रत्याशित करने की बढ़ती आवश्यकता है। जनवरी 2020 में स्थापित, न्यू इमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज डिवीजन नई प्रौद्योगिकी कूटनीति पहलुओं में सम्मिलित है और वैश्विक मंचों में इस तरह की चर्चाओं की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहलुओं से भी संबंध रखता है। यह संयुक्त राष्ट्र और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित बहुपक्षीय या बहुपक्षीय संदर्भ में प्रौद्योगिकी संचालन नियमों, मानकों और वास्तुकला के संदर्भ में वार्तालाप में भारत द्वारा उठाए गए विषयों के लिए समन्वय बिंदु होगा।

एनईएसटी प्रभाग इस संदर्भ में प्रमुख भागीदार देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ इंटरफेस का निर्माण करेगा। यह लाइन मंत्रालयों के सहयोग से भारत में नई उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों की मांग चालित आवश्यकताओं का आकलन कर रहा है और वार्ताकार/भागीदार इंटरफेस को सूत्रयुग्मन के तौर पर उनके अधिग्रहण, सुदृढ़ीकरण के लिए विशेषकर, इस प्रक्रिया में भारतीय मिशनों की भूमिका के लिए सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

एनईएसटी प्रभाग ने भारत सरकार में वर्तमान में चल रही नई विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 विचार-विमर्श पर मजबूत बातचीत में भाग लिया है।

एनईएसटी प्रभाग ने भारत में सहयोगी मंत्रालयों और संस्थानों के साथ मिलकर, वैभव (वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक), शिखर सम्मेलन 2020 के अंतर्गत डायस्पोरा और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए आकार देने में मदद की।

यह राष्ट्रीय पोर्टल “प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क” (प्रभास) के लिए सुझाव हेतु नोडल था, जिसे भारतीय वैश्विक एसएंडटी समुदाय के साथ प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए स्थापित किया जा रहा है।

इसने अक्टूबर, 2020 में एमआईआईटीवाई द्वारा आयोजित सामाजिक सशक्तिकरण हेतु उत्तरदायी एआइ (रईस 2020) में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए मिशनों के साथ भी काम किया।

एनईएसटी प्रभाग, प्रौद्योगिकी विभाग (नई प्रौद्योगिकियों पर आइटीयू संबंधित पहलुओं के लिए); एसआईआईटीवाई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी हेतु)

तथा खान मंत्रालयों के साथ आंकड़ा सुरक्षा जैसे उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर भारत सरकार के भीतर अंतर-मंत्रालयी परामर्श का समन्वय कर रहा है।

एनईएसटी प्रभाग ने 31 अगस्त, 2020 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय और नई उभरती हुई और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रौद्योगिकी की तीव्रता को गति प्रदान करने के लिए विज्ञान नीति फोरम के साथ-साथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पहल की शुरुआत की। इसे वेबसाइट www.thesciencepolicyforum.org/initiatives/eti पर लॉन्च किया गया है और इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।

“एनईएसटी मासिक न्यूजलैटर” का प्रकाशन मई, 2020 से प्रारंभ हुआ है।

इसमें, देश के भीतर एनईएसटी की गतिविधियों के बारे में इंटर-एमईए और मिशन/पोस्ट को सूचित किया जाता है। शामिल किए गए उदाहरणों में कोविड से जुड़ी प्रौद्योगिकियां; सोलर/ईवी सेल; एल्युमिनियम/क्वांटम प्रौद्योगिकियां आदि शामिल हैं।

विदेशों में एनईएसटी प्रभाग से संबंधित गतिविधियों (जैसा कि मिशनों द्वारा रिपोर्ट किया गया है) को भारत सरकार/राज्यों में संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों को भेज दिया जाता है। कुछ उदाहरण जिन्हें सहयोग के लिए खोजा जा रहा है, उनमें शामिल हैं: लिथियम-आयन बैटरी की आपूर्ति (जापान), महासागर की लहर बिजली उत्पादन तकनीक (इजराइल), रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति (कनाडा, अन्य) और हाइड्रोजन भरने वाले स्टेशन (स्विट्जरलैंड) शामिल हैं।

25

प्रोटोकॉल

कार्य प्रदर्शन के संबंध में, प्रोटोकॉल- I राष्ट्र प्रमुखों/सरकार के प्रमुखों/उपराष्ट्रपति तथा विदेश मंत्रियों, राष्ट्रपति, विदेशी उप-राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं, मनोरंजन (कार्यालयी लंचों, डिनरो एवं विदेश मंत्रालय की ओर से अभिनंदनों) तथा समारोहिक कार्यक्रमों, हवाई अड्डा पासों, समारोहों तक पहुंच

एवं आरक्षित लांज आदि में डील करता है।

द्विपक्षीय मुलाकातों तथा वर्चुअल सम्मेलनों का विवरण अनुबंध-II पर सीमांकित है।

प्रोटोकॉल-III एवं प्रोटोकॉल विशेष खण्ड

अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक प्रोटोकॉल -III तथा प्रोटोकॉल (आवासन) खण्ड दिल्ली निवासी सभी विदेशी प्रतिनिधियों जिनमें राजनयिकों के प्रस्थान हेतु आवश्यक क्लियरेंस शामिल है, के लिए ग्रह राज्य मंत्रियों तथा राजनयिकों को सुविधा प्रदान की। विदेशी प्रतिनिधियों को विधिवत सूचित किया गया और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जारी कोविड-19 संबंधी परिपत्रों/ आदेशों/ दिशानिर्देशों (विभिन्न पहलुओं जैसे कि यात्रा/ वीजा प्रतिबंधों, चिकित्सा सुविधाओं, लॉकडाउन के बदलते दिशानिर्देशों आदि) से उन्हें नियमित रूप से संवेदनशील बनाया गया। मिशनों के निवासी प्रमुखों तथा भारत द्वारा कोविड-19 वैक्सिन के विकास समुदाय के राजनयिकों के लिए एक ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था।

यह विदेशी राजनयिकों को भारतीय विश्वविद्यालयों में नामांकन , भारत में विदेशी प्रतिनिधियों एवं उनके निवासों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं; संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों; तथा पारस्परिकता के सिद्धांत पर कर रियायतों से संबंधित मामलों; राजनयिकों/ कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न न्यायलयों द्वारा न्यायालय समनों के अग्रेशन तथा भारत में राजनयिक मिशनों तथा उत्पाद शुल्क मुक्त आयातों एवं मोटर वाहनों की खरीद से संबंधित अनुरोधों हेतु अनुमति प्रदान करता है।

प्रोटोकॉल-III निम्नलिखित नियमित कार्यों का निष्पादन करता है:

- राष्ट्रपति भवन में प्रत्यय-पत्र समारोह का आयोजन का आयोजन करता है जहाँ मिशनों के आने वाले प्रमुख भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय को अपने प्रत्यय-पत्र सुपुर्द करते हैं।
- मिशनों के आने वाले प्रमुखों को प्रथम बार उनके आने तथा अंतिम प्रस्थान पर प्रोटोकॉल की सुविधाएं प्रदान करता है।

- नए कंसुलेट जनरल, उप उच्चायोगों, वाणिज्यिक कार्यालयों तथा सांस्कृतिक केन्द्रों का अनुमोदन देता है।
- पारस्परिकता के अधीन भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों/ केन्द्रों को प्रति वर्ष स्थायी हवाई अड्डा प्रवेश पासों को प्रक्रियाबद्ध करता है जिनका निर्धारण विदेशों स्तित हमारे सभी मिशनों/ केन्द्रों से प्राप्त इनपुटों के आधार पर किया जाता है।
- अवैतनिक कौंसुल, कौंसुल जनरलों; विदेशी राष्ट्रों के उप उच्चायुक्तों (राष्ट्रमंडल देशों हेतु केन्द्रों के प्रमुख) तथा उसके बाद मान्यतापत्र/ गजट अधिसूचनाओं को तैयार करना।
- भारतीय कर्मचारियों को बाध्य राष्ट्रों द्वारा दिए जाने वाले अवार्डों से संबंधित अनुमोजनों को प्रोसेस करता है।
- वीवीआईपी (राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ईएएम) से संदेशों

को विदेशी राष्ट्रों के प्रमुखों तथा सरकार के प्रमुखों को अग्रेषित करना। विदेशी राष्ट्रों के सरकारी प्रमुखों तथा राष्ट्र प्रमुखों से संदेशों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ईएएम एवं भारत सरकार के कर्मचारियों को आगे प्रेषित करना।

- (जहाँ लागू हो) मिशनों के प्रमुखों तथा राजनयिकों को गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, संसद के संयुक्त सत्रों, प्रधानमंत्री के शपथग्रहण समारोहों, योग दिवस आदि के लिए मिशन प्रमुखों तथा राजनयिकों को सुविधा प्रदान करता है।
- एचओएम/ एचओपी द्वारा शिष्टाचार अनुरोधों तथा अन्य दिए गए अन्य कार्यालयी कार्य।
- भारत में स्थित विदेशी मिशनों द्वारा मनाए जाने वाले विदेशी राष्ट्रों के राष्ट्रीय दिवसों के लिए मुख्य अतिथियों की व्यवस्था करना तथा यह सुनिश्चित करना कि वेन्यू पर प्रोटोकॉल के दिसानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो।
- ब्यौरे हेतु अनुबंध-II देखें।

प्रोटोकॉल हाउसिंग खण्ड

सीपीडब्ल्यूडी की बागवानी, लोक एवं इलैक्ट्रिकल विंग के साथ समन्वय के साथ प्रोटोकॉल हाउसिंग खण्ड हैदराबाद हाउस के अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसमें इलैक्ट्रिक/ सिविल/ बागवानी की मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य शामिल हैं।

की आवाजाही और संचालन तथा सीपीडब्ल्यूडी एवं राजनयिक मिशनों के एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, एमटीएनएल आदि जैसी सेवाओं के संबंध में सहायता प्रदान करना।

इसके अतिरिक्त यह खण्ड, प्रशासनिक, प्रबंधन एवं परिचालन व्यय के निमित्त आईटीडीसी के भुगतानों की प्रोसेसिंग को भी देखता है। इसके अन्य कार्यों में दिल्ली स्थित सभी राजनयिक मिशनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में भूमि की खरीद/ बिक्री/ भूमिका आबंटन; निर्मित संपत्ति, पट्टे आदि शामिल हैं। राज्य सरकारों के साथ भूमि आबंटन के लिए पत्र व्यवहार, स्थायी पट्टे पर हस्ताक्षर करना आदि दिल्ली तथा अन्य राज्यों में जमींदारों एवं राजनयिक मिशनों के बीच के विवादों/ न्यायलयी मामलों की देखरेख; शामिल हैं;

इसके आगे, पिछले कुछ वर्षों से यह प्रभाग, द्वारका, नई दिल्ली में बनने वाले दूसरे राजनयिक इन्कलेवपर अनेक हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करता आ रहा है। उन विदेशी केन्द्रों जिनकी स्थापना हेतु नई दिल्ली में भूमि की आवश्यकता है उसके लिए कुल 85 एकड़ की भूमि आबंटन हेतु उपलब्ध है। इन्हें अपनी वास्तविक अपेक्षाओं और संभावित भूमि उपयोग को प्रेषित करने की आवश्यकता है।

01 अप्रैल, 2020 से 31 जनवरी 2021 तक स्वीकृत मिशन/व्यापार कार्यालयों/ महावाणिज्य दूतावास/उप/ उच्चायोगों/मानद कांसलों की स्वीकृत सूची

- निवासी मिशन: नौरू, सेंट वीसेंट, और ग्रेनेडाइंस
- महावाणिज्य दूत/उप उच्चायोग:

स्थानीय एजेन्सियों जैसे कि एनडीएमसी, डीडीए, एमसीडी, जल बोर्ड, एमटीएनएल, बिजली बोर्ड आदि के साथ मिशनों के सिविल मुद्दों को उठाया गया और अधिकतर का समाधान किया गया; एयर फोर्स स्टेशन पालम पर मिलिट्री इंजीनीयरिंग सर्विसेज (एमईएस) की मदद से वीवीआईपी अभिग्राहकों

1	चिली	मुंबई
2	इटली	मुंबई
3	ऑस्ट्रेलिया	कोलकाता
4	संयुक्त अरब अमीरात	मुंबई
5	ऑस्ट्रेलिया	मुंबई
6	इजराइल	मुंबई
7	बांग्लादेश	अगरतला
8	अफ़ग़ानिस्तान	हैदराबाद
9	फ्रांस	पुदुचेरी

• व्यापार अधिकारी: शून्य

• सांस्कृतिक केंद्र: शून्य

मानद महावाणिज्य दूतावास/मानद वाणिज्य दूतावास

1	मेक्सिको	गोवा
2	कजाखस्तान	कोलकाता
3	लक्समबर्ग	चेन्नई
4	ऑस्ट्रिया	हैदराबाद
5	पोलैंड	बेंगलुरु
6	सर्बिया	बेंगलुरु
7	मोजाम्बिक	चेन्नई
8	सेंट विसेंट और ग्रेनेडाईस	नई दिल्ली
9	मालदीव	कोलकाता
10	तंजानिया	चेन्नई
11	मालदीव	मुंबई
12	इजराइल	गुवाहाटी
13	मंगोलिया	मुंबई
14	लिसोटी	हैदराबाद
15	मोरक्को	मुंबई
16	मोरक्को	कोलकाता

01 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2021 तक, भारत में विदेशी राजनयिक मिशनों में 53 नए पदों का सृजन किया गया है। 53 नए पदों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

1	अप्रैल	10
2	मई	2
3	जून	2
4	जुलाई	4
5	अगस्त	5
6	सितंबर	2
7	अक्टूबर	7
8	नवम्बर	13
9	दिसम्बर	7
10	जनवरी (11.01.2021 तक)	1
	कुल	53

26

विदेश प्रचार एवं लोक राजनय प्रभाग



Performance Smart Board

CLICK HERE

- 196 missions & posts (Trade Events and Engagements)
- 192+ Trading Partners [\$ MN] (Bilateral Trade)
- 2,110 MOUs and Agreements
- 84+ Solar Alliance Country

Video Briefings | **Media Updates** | Twitter Updates | Facebook Updates

February 11, 2021, Press Releases

Shri R. Masakui has been concurrently accredited as the next High Commissioner of India to... February 11, 2021, Press Releases

Remarks by External Affairs Minister at World Sustainable Development Summit - High Level... February 11, 2021, Speeches & Statements

Prime Minister receives a telephone call from H.E. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada February 10, 2021, Press Releases

Dr. S. Jaishankar
External Affairs Minister
Profile
Speeches & Interviews

V. Muraleedharan
Minister of State for External Affairs
Profile
Speeches & Interviews

अपने आदेश के क्रम में विदेश लोकप्रियता एवं लोक कूटनीति विभाग महत्वपूर्ण विदेश नीति मामलों में भारत की स्थिति को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के अपने प्रयासों को जारी रखना है। इसी के साथ-साथ भारत की कहानी तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इसकी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के समकक्ष लाना के प्रयास

भी जारी हैं। जबकि कोविड -19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों ने अपनी चुनौतियों का एक समूह प्रस्तुत किया, आभासी प्लेटफार्मों के रचनात्मक उपयोग के साथ, डिजिटल वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों की गति को बनाए रखने में सक्षम था।

मीडिया से जुड़ाव

प्रेस कवरेज

कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन तथा उसके पश्चात देशों के बीच व्यक्तियों के आगमन पर लगे प्रतिबंधों के कारण इस अवधि के दौरान ज्यादातर दौरे घटित नहीं हुए। तथापि कोविड-19 वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अधिक वार्तालाप हुआ जिसे डिजिटल द्वारा कवर किया गया घटनाओं के कारणों का प्रचार किया गया।

इस अवधि के दौरान एक्सपीडी डिजिटल द्वारा कवर की गई कुछ प्रमुख वर्चुअल घटनाओं में जून 2020 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री के साथ प्रधान मंत्री का वर्चुअल शिखर सम्मेलन, जुलाई 2020 में भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, वस्तुतः डेनमार्क के प्रधान मंत्री के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन, प्रधानमंत्रियों में भारत-श्रीलंका शिखर सम्मेलन शामिल हैं। सितंबर 2020 में यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में प्रधान मंत्री स्तर पर विशेष मुख्य भाषण। नवंबर 2020 में, प्रधान मंत्री की सहभागिता में इटली के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल समिट, एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट्स के 20वें शिखर सम्मेलन में रूपे कार्ड

का शुभारंभ शामिल था। द्वितीय भूटान के पीएम के साथ, 17वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, भारत-लक्ज़मबर्ग वर्चुअल शिखर सम्मेलन और 15वां जी 20 लीडर्स समिट। दिसंबर 2020 में, प्रधान मंत्री ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रधान मंत्री और वियतनाम के प्रधान मंत्री के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया।

विदेश मंत्री की मुख्य सहभागिताओं में अप्रैल 2020 में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि के साथ अफगानिस्तान समन्वय पर वर्चुअल बैठकें शामिल हैं। भारत फ्रांस तथा भारत जर्मनी के विदेश मंत्री के कार्यालय परामर्श वर्चुअल विधि से जून 2020 में आयोजित हुए थे जिनमें विदित रूप से कवर किया गया यूएनएससी सैनिक पद के लिए भारत की उम्मीदवारी का लॉन्च भारत स्पेन तथा भारत अमेरिका विदेश कार्यालय विमर्श को वर्चुअल विधि से आई एम द्वारा जुलाई 2020 में अटेंड किया गया। 17वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग बैठक, भारत यूएई संयुक्त आयोग बैठक, आईडीएसए शेरपा बैठकों का आयोजन वर्चुअल विधि से अगस्त 2020 में हुआ। सितंबर में हुए विदेश मंत्री के अनुबंधों में सीआईसीए वर्चुअल बैठक आईबीएसए अनुसूचिय बैठक

What's New in Missions

- EMBASSY OF INDIA ORGANIZES "FLAVOURS OF INDIA" FOOD FESTIVAL (Guatemala) ... February 13, 2021
- Statement by India at the 29th Special Session of Human Rights Council on the human r... February 12, 2021
- 10th Chartered Flight for repatriation of Indian nationals from Brunei to India on 12... February 12, 2021

[View All](#)

Missions Abroad | Foreign Relations | Division | Division

A-to-Z Indian Missions

India Perspectives | Distinguished Lectures | Documentaries | E-Book

INDIA PERSPECTIVES
TAKING INDIA TO THE WORLD

Share your ideas & suggestions with the PM **MANN KI BAAT** on 26th February, 2021

Click Here or Dial 1800 11 7800 (Toll-Free)

The phone lines shall remain open from 4th to 26th February, 2021

Important links

- 1 Year of Modi 2.0
- List of countries in which development grant projects are undertaken w.r.t. Order (Public Procurement No. 2) dated 23 July 2020
- List of Countries to which LoC has been extended w.r.t. Order (Public Procurement no. 2) dated 23 July 2020
- WEBSITE ON COVID-19 for the SAARC REGION
- India's Diplomatic journey 2014-18 "Unprecedented Outreach Unparalleled Outcomes"
- Prime Minister's National Relief Fund
- Indian Treaties Database
- Youth and Education
- MEA Media Campaigns
- National Voters' Service Portal
- Project Preparation Facility (PPF) for Lines of Credit
- Revised Guidelines for Lines of Credit
- Emergency numbers: Indian Missions/Posts
- 24/7 Help-lines in Gulf Countries & Malaysia
- Migrant Resource Centres Kochi, Hyderabad, Gurgaon, Chennai and Lucknow
- NGOs and Law Firms to assist Distressed Indians in Foreign Countries
- Recruitment - Consultants for PMU
- Japanese Language Teachers' Training Centre
- Azi Bhashanter Kojana
- India-Afghanistan - A Historic and Time Tested Friendship
- Draft Emigration Bill, 2019
- Announcing the Opening of the 2020-2021 Fulbright Fellowship Application Season
- Hindi at United Nations
- संयुक्त राष्ट्र सभा
- संयुक्त राष्ट्र समिति
- Common Terms and Uses in the Ministry of External Affairs

www.mea.gov.in

ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस जी20 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक भारत अर्जेंटीना तथा भारत पुलिस तीन विदेश कार्यालय विमर्श शामिल हैं। भारत मेक्सिको संयुक्त आयोग बैठक भारत मध्य एशिया वार्ता 7वीं भारतीय विदेश नीति एवं सुरक्षा विमर्श भारत चिली संयुक्त आयोग बैठक भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग बैठक भारत जापान विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता द्वितीय भारत-ऑस्ट्रेलिया ज्ञापन यूएसए अनुसूचियां बैठक तथा भारत म्यानमार विदेश कार्यालय विमर्श का आयोजन भी वर्चुअल तरीके से अक्टूबर 2020 में हुआ नवंबर 2020 में विदेश मंत्री ने भारत-जीसीसी राजनीतिक वार्ता में भाग लिया चौथी भारत-फिलीपींस संयुक्त आयोग बैठक, अपने ब्राजील साझेदार के साथ वर्चुअल बैठक तथा 15वां पूर्वी एशियाई सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया दिसंबर 2020 में विदेश मंत्री की ओमान तथा स्पेन के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित हुई तथा इसने भारत-

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

एक्सपीडी प्रभाग ने सभी मिशनों तथा केंद्रों के प्रमुखों के लिए अक्टूबर 2020 में सोशल मीडिया पर प्रशिक्षण मोड्यूल का आयोजन किया इस मोड्यूल का

डिजिटल पहुँच

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.mea.gov.in भारत की विदेश नीति तथा द्विपक्षीय, चौपक्षीय एवं बहुपक्षी संबंधों सहित विदेशी संबंधों पर अपने रुख का संप्रेषण करती है। वेबसाइट द्विभाषी, प्रयोक्ता अनुकूल, आरोग्य, मानकों विशिष्टताओं के प्रति दृढ़ एवं अनुपालक है। 'विदेश मंत्रालय के एमल केंद्र' के रूप में है।

वेबसाइट, विदेश मंत्रालय की घोषणाओं, भारतीय विदेश नीति और विदेशी संबंधों, विदेश मंत्रालय एवं इसके संबद्ध कार्यालयों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, महत्वपूर्ण सरकारी संगठनों को जोड़ने वाले लिंको, सभी मिशनों/केंद्रों पर जानकारी तथा उनकी वेबसाइट से लिंको को जोड़ने, लोक कूटनीति पहुँच (मल्टीमीडिया विषयवस्तु), विदेश में रहने वाले भारतीय भारतीय दिवस जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर जानकारी, कैलास मानसरोवर यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आदि, राष्ट्र पति, उप-राष्ट्र पति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, के डेटाबेस आदिस्तर पर सभी विदेशी एवं घरेलू मुलाकातों, भारतीय संधिपत्रों के डेटाबेस आदि के विवरण के एकल केंद्र के रूप में है। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट दृश्य एवं श्रव्य विकलांगता युक्त व्यक्तियों की पहुँच के अधीन है। सितम्बर 2012 में इसके औपचारिक लांच से वेबसाइट पोर्टल पर 55 मिलियन से अधिक पंजीकरण हुए हैं जिनमें से 4.8 मिलियन ने तो जनवरी 2020 में वेबपोर्टल पर विजिट किया। मंत्रालय का मोबाइल एप (meaindia) एंड्रॉयड तथा आईओएस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध है।

मीडिया प्लेटफार्म

सभी प्लेटफार्मों पर लगातार बढ़ती हुई अनुगमनकर्ताओं की संख्या के साथ भारत सरकार एक मज़बूत मीडिया मौजूदगी तथा डिजिटल पहचान को अपनाने में विदेश मंत्रालय पथ प्रदर्शक रहा है।

मंगोलिया संयुक्त समिति की अध्यक्षता की इन सभी कार्यक्रमों को विधिवत रूप से विज्ञापित किया गया तथा मीडिया की कवरेज सुनिश्चित की गई।

विदेश मंत्री ने सितंबर 2020 में एससीओ अनुसचिवीय बैठक के लिए मॉस्को तथा जापान का दौरा किया डॉक्टर अब्दुल्ला अध्यक्ष अफगानिस्तान के राष्ट्रीय समन्वय हेतु उच्चायोग ने अक्टूबर 2020 में भारत का दौरा किया तथा भारत अमेरिका 2+2 वार्ता भी अक्टूबर 2020 में आयोजित हुई थी। विदेश मंत्री ने यूएई तथा सेचिलिस (Seychelles) सेशेल्स का नवंबर 2020 में दौरा किया तथा दिसंबर 2020 में कतर का दौरा करने के अलावा यूके के विदेश राष्ट्र मंडल एवं विकास मामलों के सचिव की मेजबानी भी की। इन सभी कार्यक्रमों को प्रभाग द्वारा विज्ञापित किया गया।

संचालन वर्चुअल मोड पर चार सत्रों में किया गया।

क) 2019-20 से लगभग 2,00,000 फॉलोवरों को जोड़ते हुए विदेश मंत्रालय के पास @meaindia पर 2.1 मिलियन फॉलोवरों के साथ कुछ 3.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं। मिशन एवं केंद्र भी मेजबान देशों में, विदेशों में रहने वाले भारतीयों तथा स्थानीय जनता के साथ, सोसियल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सक्रियता से उपयोग कर संबंधों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज 189 मिशन/केंद्र ट्विटर पर मौजूद है तथा 185 मिशन/केंद्र फेसबुक पर मौजूद है तथा लगभग 73 केंद्र इंस्टाग्राम पर मौजूद है तथा साथ अन्यो को प्लेटफार्म पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्रालय की चारों ओर इस डिजिटल पहुँच ने मंत्रालय पर सूचनाओं तथा मिशन/केंद्रों की गतिविधियों को तीव्र गति से सीधे एवं सटीक प्रसार के साथ न केवल भारत की जनता बल्कि विश्व भर में प्रसारित कर रही है।

ख) मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं के त्वरित प्रसारण के लिए ट्विटर एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विश्वभर के सभी एमओएफए के मध्य @MEAINdia अब तीसरा सबसे अधिक फालो किया जाने वाला हैंडल है। इस प्लेटफार्म का उपयोग भारतीय विदेश संबंधों पर नवीनतम जानकारी को अपडेट करने के लिए किया जाता है। द्विपक्षीय, चौपक्षीय एवं बहुपक्षीय अनुबंधों के संबंध में ट्विटर को वास्तविक समय में अद्यतन किया जाता है। दोनों ही ट्विटर हैंडलों ने उन मल्टीमीडिया विषयवस्तु का उपयोग किया जाता है जिन्होंने अपनी पहुँच एवं प्रभाव को बढ़ा दिया है।

ग) विदेश मंत्रालय के यूट्यूब चैनल-प्रभाग मंत्रालय के लिए दो यूट्यूब चैनलों को मैनेज करता है। नवंबर 2020 तक MEAINdia चैनल के कुल 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, इंडियन डिप्लोमेसी चैनल के 1,21,000 सब्सक्राइबर हैं। इन दोनों चैनलों के संयुक्त व्यूज 27 मिलियन से अधिक हैं, जो कि पिछले वर्ष के दौरान 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

घ) विदेश मंत्रालय ने इंस्टाग्राम पर जो कि सबसे अधिक देखा जाने वाला

प्लेटफॉर्म है, ने फॉलोवरों की संख्या में असाधारण वृद्धि की है। पिछले वर्ष में 31 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, विदेशमंत्रालय के पास अब लगभग 5,23,000 फॉलोवर्स हैं। युवाओं में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है जोकि विशेष रूप से जनसंख्या सेगमेंट के प्रति विशेषरूप से उत्सुक है।

ङ) MEA Flickr account (MEA photogallery) विदेश मंत्रालय के भारत एवं विदेश के सभी मुख्य कार्यक्रमों के फोटो के संग्रहक के तौर पर कार्य कर रहा है जिसकानवंबर 2020 तक 42,417 एचडी फोटो का फोटों बैंक मौजूद है।

च) मंत्रालय का SoundCloud account (MEAINdia) सभी मीडिया ब्रीफिंग्स की ऑडियो क्लिपों तक पहुँच के लिए एक उपयोगी ऑडियो क्लिप डेटाबेस है। सभी मिडिया ब्रीफिंग के फोटो यूट्यूब पर भी अपलोड किए जाते हैं।

छ) Linkdin पर अनुगामियों की संख्या में पिछले वर्ष के दौरान कुल 25,280 अनुगामियों के साथ महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है जोकि 620 प्रतिशत वृद्धि है।

दृश्यात्मक पहुँच-फिल्में व डॉक्युमेंटरी

एम्सपीडी प्रभाग विदेशों में भारत की एक सकारात्मक इमेज को प्रस्तुत करते हुए वीडियो तथा डॉक्युमेंटरी फिल्मों का निष्पादन करता है। उन डॉक्युमेंटरी को विस्तृत सामाजिक पहुँच के लिए विदेश मंत्रालय के 'Indian Diplomacy' यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। 2020-21 में, गुरुनानक देवजी की 550वीं वर्षगांठ, गांधी@150 उत्सवों, भारत का सहयोग विकास, यूएन के शांति-स्थापना मिशनों में भारत की भूमिका आदि जैसे कार्यक्रमों को चिन्हित

जनता तक पहुँच

कोविड-19 महामारी के द्वारा जनित विघ्न के कारण हार्डकॉपी प्रकाशनों के द्वारा जनता तक पहुँच को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा। प्रभाग ने 2020 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं तथा गतिविधियों जैसे कि जम्मू-कश्मीर संघशासित प्रदेश पर 'एक नई किरण' भारत संगठनात्मक एवं वैश्विकस्तर पर आश्रित पाठ, कोविड युग में जीवन, भारत@75 को 21 प्रदर्शित करने के लिए ई-पुस्तकों को

पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएं

पुस्तक समिति

पुस्तक समिति जिसकी स्थापना 2003 में मिशनों, पुस्तकालयों के साथ-साथ प्रस्तुतीकरण उद्योगों के लिए पुस्तकों का चयन करने के लोक राजनायिक उपकरण के रूप में 2003 में स्थापित किया गया था ने नवंबर 2020 में अपनी 42वीं बैठक आयोजित की। 42वीं पुस्तक समिति ने भारतीय क्लासिक्स, विदेश नीति एवं मामलों, तकनीकी एवं लोक-प्रिय विज्ञान, हिंदी एवं संस्कृत, कला एवं संस्कृति जैसी श्रेणियों में से शीर्षकों का चयन किया था मिशनों एवं केंद्रों से प्राप्त अनुरोधों की सरल प्रोसेसिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है तथा अपनी मांगो को अपलोड किए जाने के लिए इनके द्वारा इनका वृहदरूप से उपयोग किया जा रहा है।

ज) मंत्रालय, महत्वपूर्ण अवसरों जैसे कि महात्मा गांधी के 151वें जन्मदिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, गुरुनानक देवजी के 500वें जन्म वर्षगांठ आदि को सभी सोसियल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अग्रसक्रिय रहा है। मंत्रालय, कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत सरकार के प्रयासों को विज्ञापित करने के साथ-साथ इसके पड़ोसी देशों को महामारी से निपटने में सहायता प्रदान करने को विज्ञापित कर रहा है।

झ) महामारी के आलोक में, मंत्रालय तथा इसके मिशन/केंद्रों ने विशेषरूप से उस समय में जब भौतिक जमावड़ों से बचा जाना चाहिए था, डिजिटल शक्ति को उत्तोलित किया है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय समुदाय तक पहुँच, हमारे संभाषियों तक पहुँच एवं भारत की कोमल शक्ति के प्रोत्साहन को अबाध रूप से सुनिश्चित किया गया।

डिजिटल पहुँच तथा स्वयं को 'एक' डिजिटल रूप से अग्र के रूप में ब्रैंडिंग करने के विदेश मंत्रालय के प्रयासों सहित मंत्रालय की लोकप्रियता एवं सफलता को सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अनुयायियों में वृद्धि के साथ प्रदर्शित किया गया।

करने के लिए प्रभाग द्वारा लगभग 10 डॉक्युमेंटरीफिल्मों/विज्ञापन वीडियों को सम्पादित किया गया। उसके अलावा, प्रभाग ने कोविड-19 महामारी पर भारत की प्रतिक्रिया, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख (जे एण्ड के: मार्चिंग अहैड) आदि विषयों पर कई छोटे वीडियो संपादित किए हैं। हमारे मिशन/केंद्रों द्वारा प्रस्तुतीकरण/विज्ञापन उद्देश्यों के लिए प्रभाग ने भारतीय संस्कृति (वाद्यसंगीत एवं स्वर) संगीत कार्डों के आठ शीर्षकों की खरीद की है।

संपादित किया। इनके अलावा प्रभाग 'What Gandhi Means to Me; An Anthology' जो महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 2019 में जारी किया गया था, का अद्यतन संस्करण लेकर आ रहा है।

भारत के दृष्टिकोण

'मंत्रालय की द्विभाषिक प्रमुख मैगजीन अब डिजिटल फॉर्मेट में 16 भाषाओं में उपलब्ध है। मैगजीन का वेब संस्करण इसकी विषयवस्तु के विशिष्ट रूप से निर्माण करने तथा इसे डाउनलोड करने का विकल्प प्रदान करने तथा मिशनों एवं केंद्रों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित करने का विकल्प प्रदान करता है। यह मैगजीन चयनित विषयों जैसे कि साझेदारी, लाइफ एण्ड स्टाइल, नवाचार एवं संस्थान, अर्थव्यवस्था तथा खेल, टूर एण्ड ट्रेवल आदि को कवर करता है। इसे www.indiaperspectives.gov.in and www.mea.gov.in पर ऑनलाइन पढ़ा जा सकता है।

27

प्रशासन, स्थापना और सूचना का अधिकार

प्रशासन

मंत्रालय में प्रशासन प्रभाग का मुख्य उत्तरदायित्व मुख्यालय और 197 भारतीय मिशन/पोस्टों और 3 प्रतिनिधि कार्यालयों दोनों में जनशक्ति संसाधन उपलब्ध कराना है। इस संबंध में, प्रभाग संवर्ग प्रबंधन की देखरेख करता है जिसमें भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती/स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति और आजीविका प्रगति शामिल है।

इसके अलावा, प्रभाग विदेशों में तैनात भारतीय कर्मियों और भारतीय मिशनों व पोस्टों में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों से संबंधित सभी संगत नियमों और विनियमों की संरचना, संशोधन और सुधार का कार्य भी करता है।

इस प्रभाग ने ई-समीक्षा पोर्टल, मुख्यालय और मिशन/पोस्टों के बीच एक ऑनलाइन इंटरफेस जैसे तकनीकी उपकरणों का सक्रिय रूप से उपयोग किया, जो विचार-आदान-प्रदान, डिजिटाइज्ड प्रक्रियाओं, सूचना एकल करने और मिशन/पोस्टों के कार्यात्मक क्षेत्रों की प्रभावी निगरानी के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में है। छुट्टी, पेंशन प्रक्रियाओं आदि सहित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटाइज्ड करने के प्रयास भी जारी हैं।

2018-21 के दौरान अफ्रीका में 18 नए मिशन खोलने के लिए मार्च 2018 में मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसरण में, पहले चरण में छह मिशनों का उद्घाटन-रवांडा, जिबूती, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, बुर्किना फासो और गिनी और दूसरे चरण में तीन मिशन - एस्वतीनी, इरिट्रिया और कैमरून का खोलने का पूरा किया गया। जून, 2019 और सितंबर, 2020 के बीच, तीन चरणों में छह और

मिशन खोले गए - सिप्रा लियोन, साओ टोम एंड प्रिंसिप, लाइबेरिया, रिपब्लिक ऑफ टोगो, रिपब्लिक ऑफ चाड और मॉरिटानिया। केप वर्डे, गिनी बिसाऊ और सोमालिया में नए मिशनों की स्थापना की दिशा में प्रारंभिक प्रशासनिक और स्थापना संबंधी उपाय शुरू किए गए थे। मंत्रिमंडल ने हाल ही में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में तीन नए मिशन खोलने की मंजूरी दी है।

मंत्रालय की वर्तमान स्वीकृत संख्या 4297 (परिशिष्ट VI) है जिसमें इनमें से लगभग 53% पद विदेशों में मिशन और पोस्टों में हैं। पदों की कुल संख्या मंत्रालय के विभिन्न संवर्गों जैसे आईएफएस, आईएफएस सामान्य संवर्ग शाखा ख, स्टेनोग्राफर संवर्ग, दुभाषिण संवर्ग, कानूनी और संधियों संवर्ग में विभाजित है। मंत्रालय ने संवर्ग प्रबंधन के हिस्से के रूप में, भर्ती वर्ष 2018-19 में सीधी भर्ती (डीआर) और विभागीय प्रोन्नति (डीपी) के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर कर्मियों की भर्ती करके अपनी जनशक्ति में वृद्धि की।

मंत्रालय ने आर्थिक कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून, साइबर सुरक्षा, लिंग बजटिंग, लेखांकन, कांसुलर और पासपोर्ट सेवाओं, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग आदि पर विशेष मॉड्यूल के साथ-साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर उचित ध्यान केंद्रित किया। व्याख्या स्तर सहित अधिकारियों के विदेशी भाषाई कौशल के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। समय के साथ, इसके परिणामस्वरूप सेवा (परिशिष्ट VI) के भीतर गुणवत्तापूर्ण विदेशी भाषा कौशल वाले अधिकारियों का एक यथोचित बड़ा पूल का निर्माण हुआ है।

स्थापना

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए ईडी ने भारत में और विदेशों में मिशन/पोस्ट में “स्वच्छता पखवाड़ा” के साथ-साथ श्रमदान का आयोजन किया।

इसके अलावा, विदेशों में विभिन्न मिशनों/पोस्टों पर भी स्थानीय स्तर पर ऐसी सामग्रियों की कमी को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय द्वारा उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाईयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे। ईडी के एसपीएम अनुभाग ने विदेशों में विभिन्न मिशनों/पोस्टों के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से रबर स्टैप, गोदरेज सेफ, पैडलॉक्स, खादी/सिल्क इंडियन नेशनल प्लैग्स आदि जैसी विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की खरीद की और आपूर्ति की। वर्ष के दौरान विदेशों में मिशनों/पोस्टों में एचओएम/एचओपी के आवासों के लिए क्रॉकरी, कटलरी और रसोई के बर्तनों की आपूर्ति के लिए जीएफआर के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अनुसार, निविदा प्रक्रिया शुरू की गई। तोशाखाना अनुभाग विदेशी स्त्रोतों से विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों को प्राप्त उपहार वस्तुओं की ई-नीलामी की प्रक्रिया करता है। इस संबंध में एनआईसी द्वारा उपहार वस्तुओं की ई-नीलामी के लिए ई-पोर्टल तैयार किया जा रहा है।

स्थापना प्रभाग जेएनबी, साउथ ब्लॉक और पटियाला हाउस में तीन विभागीय पेंटी और जेएनबी और साउथ ब्लॉक में दो आउटसोर्स कैटीन और शास्त्री भवन और अकबर भवन में दो पेंटी का संचालन भी करता है।

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विदेशों में मिशनों/पोस्टों से सरकारी वाहनों के प्रतिस्थापन/खरीद के लिए तीस से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से मंत्रालय द्वारा लगभग 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे।

वैश्विक संपदा प्रबंधन प्रभाग

विदेश स्थित भारतीय राजनयिक मिशनों/केन्द्रों के लिए संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण और नवीनीकरण को सक्रिय रूप से देखता है। इस तरह के आवास की उपलब्धता में मौजूदा कमी को प्रभावी ढंग से पूरा करने और विदेश मंत्रालय की आवास की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विदेश मंत्रालय

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, मंत्रालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों का संचालन करता है।

अप्रैल से अक्टूबर 2020 तक आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने वाले कुल 1570 आरटीआई आवेदन और 183 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई हैं और उनका संतोषजनक निस्तारण किया गया है। सामान्य तौर पर, आवेदनों में विदेशी संबंध, प्रशासनिक मुद्दे, द्विपक्षीय दौरे, नमस्ते ट्रंप इवेंट, कोविड-19 महामारी, वंदे भारत उड़ानें और उस पर किए गए खर्च जैसे विषय शामिल हैं।

आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन प्राप्ति और निपटान की प्रणाली को विदेशों में 192 मिशनों/पोस्टों में आरटीआई वेब पोर्टल के साथ संरेखित करके लागू किया गया है।

महामारी के दौरान, स्वतः प्रकटीकरण पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(एमईए) के अधिकारियों के लिए नई दिल्ली में उपलब्ध आवास को बढ़ाने के लिए एक पहल की गई थी।

तेहरान (चांसरी का उपभवन), पारामारिबो (चांसरी और रिहायश के लिए भूमि) और आबिदजान (चांसरी, राजदूत आवास और अन्य रिहायश आवासों के लिए भूमि) में संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नई दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेल गाँव परिसर में स्थित 50 फ्लैटों को विदेश मंत्रालय को आवंटित किया, जिन्हें विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के लिए रिहायशी आवास के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव था। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में एक भूखंड का औपचारिक अधिग्रहण कर लिया है, जिसे आवासन और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त कार्यालय के निर्माण के लिए लगभग 2.5 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

निर्माण परियोजनाएं तेज गति से आगे बढ़ी हैं और पूरी होने वाली परियोजनाओं में खार्तूम (चांसरी और स्टाफ रिहायश), पोर्ट ऑफ स्पेन (सांस्कृतिक केंद्र), बैंकॉक (राजदूत का निवास और रिहायशी आवास), इस्लामाबाद (आवासीय परिसर) और काठमांडू (चांसरी और आवासीय परिसर) शामिल हैं। काबुल (आवासीय), वेलिंग्टन (चांसरी एवं आवासीय) और फुएन्थोलिंग (चांसरी और आवासीय) में निर्माण परियोजनाओं में पर्याप्त प्रगति हुई है। ब्रुनेई दारुस्सलाम (चांसरी, राजदूत का आवास और स्टाफ रिहायशी आवास) और जिनेवा (चांसरी) में निर्माण परियोजनाएं निर्माण चरण में डिजाइन चरण से आगे बढ़ गई हैं।

नवीनीकरण से संबंधी कार्यों में उल्लेखनीय उपलब्धियों में दार-एस-सलाम (राजदूत आवास), हरारे (राजदूत आवास), यांगून (इंडिया केंद्र) और हेलसिंकी (आवास) में प्रमुख नवीनीकरण कार्य शामिल हैं। हैदराबाद स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भवन में प्रमुख नवीनीकरण कार्य किया गया, जिससे उपलब्ध स्थान में काफी बढ़ोतरी हुई और विदेश मंत्रालय के अन्य कार्यालयों जैसे शाखा सचिवालय, आईसीसीआर क्षेत्रीय कार्यालय और उत्पवासी संरक्षक को एक ही परिसर में समायोजित किया जायगा।

(डीओपी एंड टी) के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आरटीआई आवेदनों/अपीलों/प्रतिक्रियाओं और मासिक आरटीआई आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन पर अपलोड करना लागू किया गया है।

सभी केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की सुनवाई में संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और आरटीआई सेल के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तिमाही रिटर्न सीआईसी के साथ आवश्यक के रूप में, निर्धारित समय पर दायर किया गया है।

‘सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान’ के सहयोग से सीआईसी के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में सभी सीपीआईओ द्वारा समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन स्वतः (पारदर्शी लेखापरीक्षा) का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

28

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने और लागू करने के लिए मंत्रालय की सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। मंत्रालय द्वारा अपने मिशनों के माध्यम से किए गए सतत प्रयास के परिणामस्वरूप, हिंदी को अब 70 से अधिक मिशनों और पोस्टों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में बढ़ाया जा रहा है।

इस प्रभाग ने 2008 से, मॉरीशस सरकार के साथ एक द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत मॉरीशस में 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना की है, जिससे दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा दिया गया है। विश्व हिंदी सचिवालय के बजट को दोनों देशों ने समान रूप से बांटा है।

मंत्रालय ने हिंदी कक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षकों को शामिल करने के लिए विदेशों में मिशनों/पोस्टों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इसके अलावा हिंदी कक्षाओं के आयोजन के लिए हमारे मिशन के माध्यम से शिक्षण सामग्री और पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गईं।

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने 10 अक्टूबर 2020 को मंत्रालय के सरकारी कार्य में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग का निरीक्षण किया और सुधार के तरीके सुझाए।

मंत्रालय में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था जिसमें कोविड-19 की

मौजूदा परिस्थितियों के बावजूद काफी भागीदारी देखी गई। राजभाषा विभाग के सचिव ने एक प्रतियोगिता के दौरान अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

विदेश मंत्रालय को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित कंठस्थ के माध्यम से आयोजित अनुवाद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट कार्य के लिए मान्यता दी गई थी।

अरबी, चीनी, फ्रेंच, जापानी, रूसी और स्पेनिश में हिंदी भाषा की व्याख्या के लिए 'विशेष दुभाषिण' का एक पूल बनाने की दिशा में भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) द्वारा अटल भाषांतर योजना (एबीवाई) की स्थापना की गई है।

इस योजना के अंतर्गत, पहले बैच के तीन उम्मीदवारों, अरबी, चीनी और रूसी में एक-एक को, व्याख्या और अनुवाद में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पहले ही भेजा जा चुका है। उन्होंने अपना पहला वर्ष पूरा कर लिया है और अब अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम वर्ष में हैं।

29

वित्त और बजट

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंत्रालय को आवंटित कुल बजट अनुमान (बीई) चरण में 17,346.71 करोड़ रुपये है। प्रमुख आवंटनों के लिए बजट का क्षेत्रीय वितरण नीचे दिया गया है:

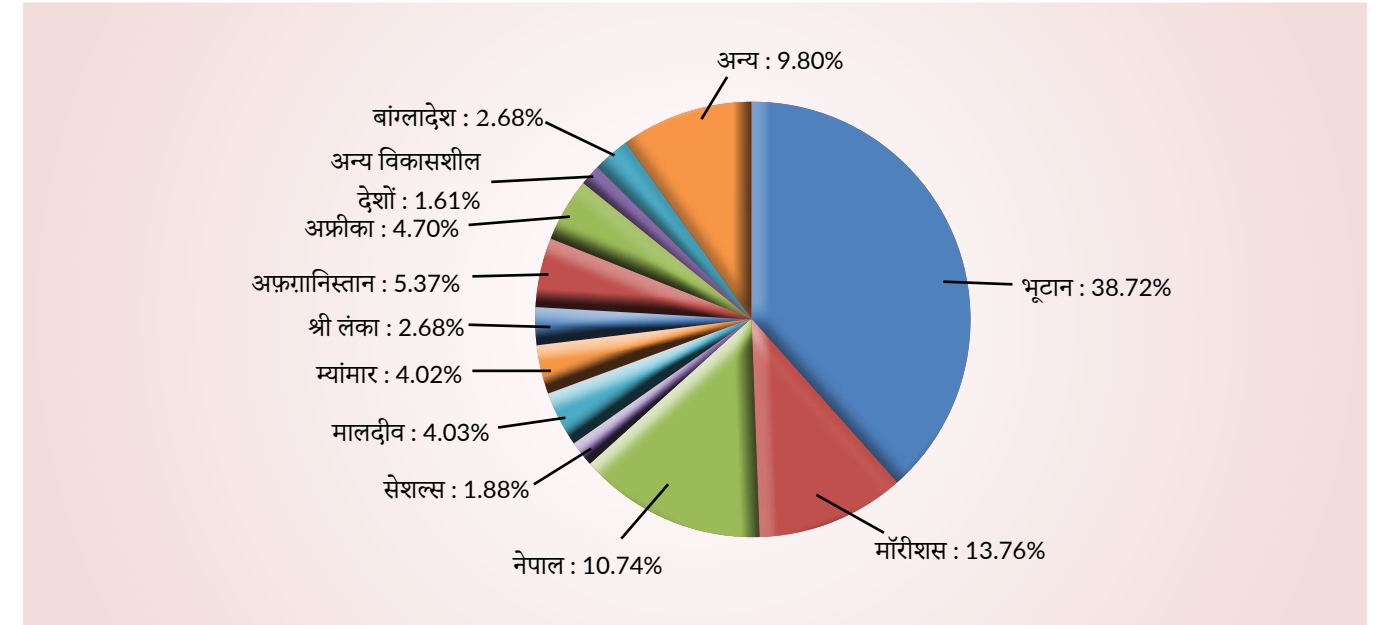
क्षेत्र		आवंटन (करोड़ रुपये में)
विदेशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी)	अनुदान	6617.37
	ऋण	832.28
	कुल टीईसी	7449.65
विदेशों में भारतीय मिशन और पोस्ट		2994.06
विशेष राजनयिक व्यय		2800.01
पासपोर्ट और उत्सवास		1348.59
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग		1084.56
लोक निर्माण और आवास पर पूंजी परिव्यय		500.00
विदेश मंत्रालय सचिवालय		520.96
स्वायत्त निकायों और अन्य संस्थानों को सहायता		323.72
अन्य		325.16

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल बीई	17,346.71
-----------------------------------	-----------

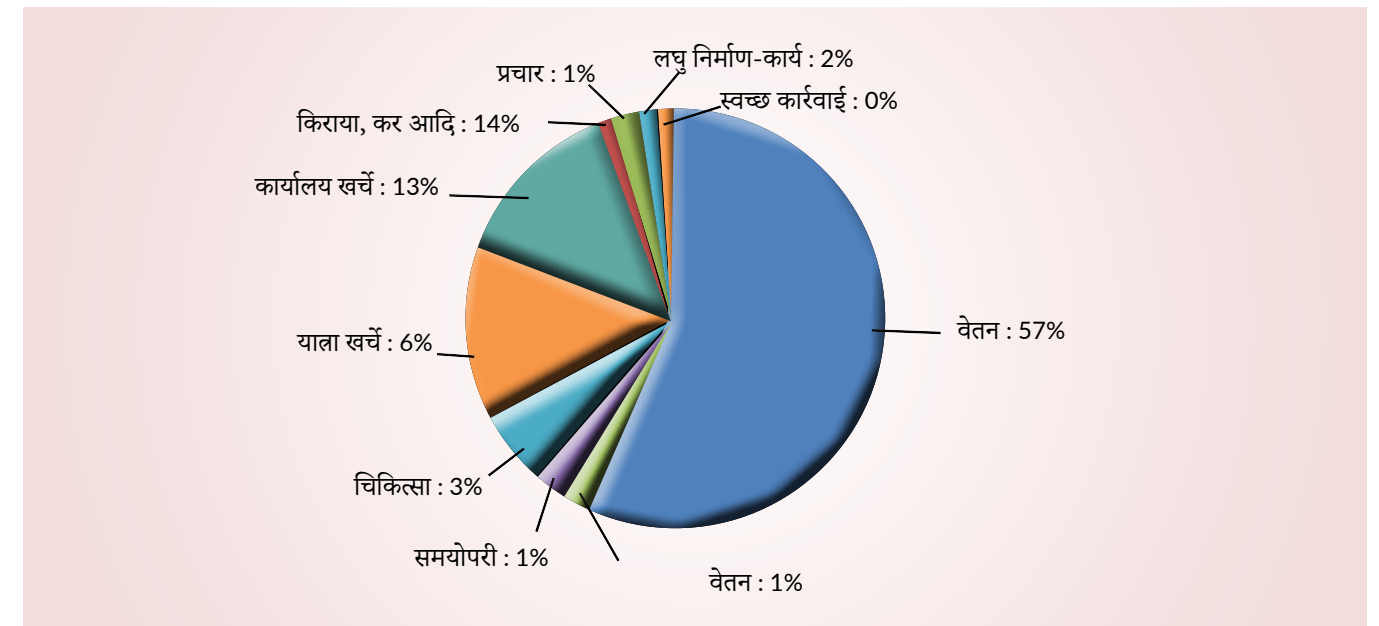
मंत्रालय के बजट में सबसे बड़ा आवंटन अनुदान और ऋण के रूप में सहायता के माध्यम से विदेशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) के लिए है। वित्त वर्ष 2020-21 में 17,346.71 करोड़ रुपये के कुल बजट में टीईसी परिव्यय 42.95 प्रतिशत या 7449.65 करोड़ रुपये है, जिसमें से 6617.37 करोड़ रुपये (38.15 प्रतिशत) अनुदान कार्यक्रमों के लिए है और 832.28 करोड़ रुपये (4.80%) ऋण के लिए है।

तकनीकी और आर्थिक सहयोग (टीईसी) शीर्ष	आवंटन (करोड़ रुपये में)	कुल टीईसी आवंटन का %
बांग्लादेश को सहायता	200.00	2.68%
भूटान	अनुदान	2052.37
	ऋण	832.28
	कुल भूटान	2884.65
नेपाल को सहायता	800.00	10.74%
मॉरीशस को सहायता	1025.00	13.76%
अफगानिस्तान को सहायता	400.00	5.37%
सेशेल्स को सहायता	140.00	1.88%
म्यांमार को सहायता	300.00	4.02%
आईटीईसी कार्यक्रम	220.00	2.95%
अफ्रीकी देशों को सहायता	350.00	4.70%
श्रीलंका को सहायता	200.00	2.68%
चाबहार पोर्ट, ईरान	100.00	1.34%
मालदीव को सहायता	300.00	4.03%
अन्य विकासशील देशों को सहायता	120.00	1.61%
निवेश प्रचार और संवर्धन कार्यक्रम	250.00	3.36%
हिंद-प्रशांत सहयोग	45.00	0.60%
यूरोशियन देशों को सहायता	45.00	0.60%
बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम	20.00	0.27%
लैटिन अमेरिकी देशों को सहायता	20.00	0.27%
आपदा राहत के लिए सहायता	20.00	0.27%
सार्क कार्यक्रम	8.00	0.11%
मंगोलिया को सहायता	2.00	0.03%

कुल	7449.65
-----	---------



मंत्रालय के बजट में दूसरा सबसे बड़ा आवंटन विदेशों में 190 से अधिक भारतीय राजनयिक मिशनों और पोस्टों के रखरखाव के लिए है। वित्त वर्ष 2020-21 में, सभी मिशनों और पोस्टों के लिए एक साथ आवंटन मंत्रालय के कुल बजट का 17.26% या 2994.06 करोड़ रुपये है, जिसका शीर्ष-वार वितरण (प्रतिशत-वार) नीचे दिया गया है:



वित्त वर्ष 2020-21 के कुल बजट में से 17,346.71 करोड़ रुपये के आवंटन में स्थापना प्रमुखों और गैर-प्रतिष्ठान प्रमुखों के बीच आवंटन का विभाजन क्रमशः 28 प्रतिशत (4890 करोड़ रुपये) और 72 प्रतिशत (12457 करोड़ रुपये) है। मंत्रालय ने अपने कुल बजट के 30% के भीतर स्थापना प्रमुखों पर अपने व्यय

को लगातार बनाए रखा है।

मंत्रालय वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों (आरई) में इसके लिए आवंटित धन का अधिकतम उपयोग कर रहा है, जैसा कि पिछले दसवित्तीय वर्षों के लिए नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	बीई आवंटन	आरई आवंटन	वास्तविक व्यय	बीई के % के रूप में उपयोग	आरई के % के रूप में उपयोग
	करोड़ रुपये में; पूर्णांकित				
2010-11	6375	7120	7154	112 %	100 %
2011-12	7106	7836	7873	111 %	100 %
2012-13	9662	10062	10121	105 %	100 %
2013-14	11719	11794	11807	101 %	100 %
2014-15	14730	12620	12149	82 %	96 %
2015-16	14967	14967	14541	97 %	97 %
2016-17	14663	13426	12772	87 %	95 %
2017-18	14798	13690	13750	93 %	100 %
2018-19	15011	15582	15526	103%	99%
2019-20	17885	17372	17272	97%	99%

मंत्रालय में वित्त वर्ष 2020-21 में 31 अक्टूबर 2020 तक पासपोर्ट सेवाओं (583.56 करोड़ रुपये), वीजा शुल्क (24.85 करोड़ रुपये) और अन्य प्राप्तियों (149.73 करोड़ रुपये) से 758.14 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हैं। वित्त

वर्ष 2016-2017 से वित्त वर्ष 2020-2021 तक पिछले 5 वित्तीय वर्षों की राजस्व प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

वर्ष	शीर्ष	राशि	प्रतिशत
2016-17	पासपोर्ट	2285.85	45%
	वीजा	2018.04	40%
	अन्य	717.07	14%
	कुल	5020.96	
2017-18	पासपोर्ट	2479.08	47%
	वीजा	2152.15	41%
	अन्य	668.38	12%
	कुल	5299.61	
2018-19	पासपोर्ट	2679.75	44%
	वीजा	2688.9	44%
	अन्य	680.06	11%
	कुल	6048.71	
2019-20	पासपोर्ट	2522.71	49%
	वीजा	1792.11	35%
	अन्य	856.16	17%
	कुल	5170.98	

2020-21 (*आंकड़े 31 अक्टूबर 2020 तक)	पासपोर्ट	583.56	77%
	वीजा	24.85	3%
	अन्य	149.73	20%
	कुल	758.14	

मंत्रालय ने जनवरी 2019 में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंड एजी) की 2017 की रिपोर्ट संख्या 12 से केवल 1 अनुच्छेद लंबित था। 2020 की सीएंडएजी की रिपोर्ट नंबर 6 में 4 और अनुच्छेद शामिल किए गए थे। इन पांचों

अनुच्छेदों के लिए प्रक्रियागत कृत कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएनएस) प्रस्तुत करने की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	सीएंडएजी रिपोर्ट	अनुच्छेदों की कुल संख्या	प्रस्तुत कृत कार्रवाई टिप्पणियां	प्रक्रियागत कृत कार्रवाई टिप्पणियां
2017	2017 की रिपोर्ट संख्या 12	4	3	1
2018	2018 की रिपोर्ट संख्या 4	5	5	शून्य
2019	सीएंडएजी ने विदेश मंत्रालय के लिए कोई रिपोर्ट नहीं बनाई है	-	-	-
2020	2020 की रिपोर्ट संख्या 6	4	शून्य	3
	कुल	13	8	4

इन सीएंडएजी अनुच्छेदों का विवरण और स्थिति नीचे दिया गया है:

सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	स्थिति
2017 की 12	9.3	ईओआई टोक्यो में सरकारी खाते के बाहर प्राप्तियां और व्यय	सीएंडएजी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इस अनुच्छेद के लिए पीएसी की प्रक्रिया शुरू हो गई। 13 अक्टूबर 2017 को हुई सुनवाई में पीएसी के माननीय सदस्यों ने मंत्रालय को इस अनुच्छेद के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सिफारिशें करने के निर्देश दिए थे। इसे किया गया था और उसके बाद, सीएंडएजी प्रक्रिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पहला एटीएन 03 दिसंबर 2019 को सीएंडएजी को प्रस्तुत किया गया था जिसका पुनरीक्षण 29 जनवरी 2020 को लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। 24 जुलाई 2020 को प्रस्तुत संशोधित मसौदा एटीएन का पुनरीक्षण 26 अगस्त 2020 को लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। मंत्रालय द्वारा अंतिम एटीएन तैयार किया जा रहा है।
6 of 2020	8.1	सार्क वस्त्र और हस्तशिल्प संग्रहालय की स्थापना में देरी	मंत्रालय द्वारा एटीएन का मसौदा तैयार किया जा रहा है
	8.2	एचसीआई वेलिंगटन द्वारा विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने के परिणामस्वरूप राजस्व का संग्रह कम होता है	मसौदा एटीएन प्रस्तुत किया गया। लेखापरीक्षा पुनरीक्षित टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
	8.3	आरपीओ द्वारा 4.11 करोड़ की स्पीड पोस्ट सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च	मंत्रालय द्वारा एटीएन का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
8.4		उपरि दूरी और उपकरण/करोड़ों को गलत तरीके से अपनाना जिसके परिणामस्वरूप नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त लागत	मंत्रालय द्वारा एटीएन का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

पीएसी अनुच्छेद

वर्ष	पीएसी रिपोर्ट संख्या	कुल अनुच्छेदों की संख्या	प्रस्तुत एटीआर	एटीआर देय	टिप्पणियां
2018	पीएसी रिपोर्ट संख्या 112	7	7	-	अनुच्छेदों का निपटान हो गया है।
2020	पीएसी रिपोर्ट संख्या 17	3	शून्य	3	मंत्रालय द्वारा एटीएन का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

बकाया पीएसी अनुच्छेद का ब्यौरा और स्थिति निम्नानुसार है:

लोक सभा सं.	रिपोर्ट संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय	स्थिति
17	17	12	सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या-112 वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में शामिल समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति की टिप्पणियां "ओटावा और उसके वाणिज्य दूतावासों में विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने" पर निहित हैं। 2016 अध्याय VII अनुच्छेद 7.1 के 11 [समिति ने दोहराया कि (i) निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, (ii) सभी मिशन कर्मचारियों को मूल/रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाए, और (iii) यह जांचने के लिए कि ऐसी लूटियां नहीं हो रही हैं, सभी मिशनों की समीक्षा की जा सकती है। मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने की परियोजना के एकीकरण के बाद से ऐसे मुद्दों की वास्तविक समय की निगरानी के बारे में विशिष्ट आंकड़े प्रस्तुत कर सकता है।]	पीएसपी प्रभाग द्वारा मसौदा कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार की जा रही है
		17	समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति की टिप्पणियों पर टिप्पणी "एचसीआई लंदन द्वारा सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ" पर निहित है, जैसा कि 2016 अध्याय VII अनुच्छेद 7.2 के सीएंडएजी रिपोर्ट संख्या 11 में निहित है [समिति को सीईओ द्वारा नेतृत्व वाली टीम की जांच के विस्तृत निष्कर्षों से अवगत कराया जाना चाहिए। टीम द्वारा की गई सिफारिशें और उसके कार्यान्वयन की स्थिति। निरीक्षण करने वाली टीम की सिफारिशों पर विचार किया जाए और एक निश्चित समय सीमा के भीतर लागू किया जाए।]	पीएसपी प्रभाग द्वारा मसौदा कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार की जा रही है
		22	समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई पर समिति की टिप्पणियों पर टिप्पणी "ओटावा और उसके वाणिज्य दूतावासों में विनिमय दर को गलत तरीके से अपनाने" पर अपनी 112 वीं रिपोर्ट (16 वीं लोकसभा) में निहित है, जैसा कि सी में निहित है। 2016 अध्याय VII अनुच्छेद 7.1 की एजी रिपोर्ट संख्या 11 [समिति वैश्विक पासपोर्ट सेवा परियोजना के विवरण के साथ-साथ निगरानी और वास्तविक समय रिपोर्टिंग पर परिणामी प्रभाव से अवगत कराना चाहेगी। समिति यह भी जानना चाहेगी कि क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन से विशेष रूप से उनके द्वारा पूर्व सिफारिश में उठाई गई चिंताओं का समाधान किया जाता है।]	पीएसपी प्रभाग द्वारा मसौदा कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) तैयार की जा रही है

30

संसद और समन्वय प्रभाग

संसद अनुभाग

मंत्रालय का प्रयास संसद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर प्रभावी और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना रहा है जिसमें अंतर-संसदीय संघ, संसदीय आदान-प्रदान कार्यक्रम, संसदीय मैली समूह आदि से संबंधित मुद्दों पर सहायता शामिल है। संसद अनुभाग मंत्रालय के सभी संसद संबंधी कार्यों के लिए इंटरफेस और केंद्र बिंदु है।



विदेश मंत्री ने दिनांक 16 जनवरी, 2021 को 'भारत की वैश्विक रणनीति' पर परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की



बजट सत्र 2020 के दौरान लोकसभा में उत्तर देते हुए विदेश मंत्री

जनवरी-दिसंबर 2020 के दौरान, विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने निम्नलिखित विषयों पर 17 बैठकें आयोजित कीं:

- समुद्री डकैती रोधी विधेयक 2019
- एनआरआई के विवाह का पंजीकरण बिल 2019
- वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की मांग
- कोविड-19 महामारी - वैश्विक प्रतिक्रिया, भारत का योगदान और भावी राह
- भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक राजनयिक: संभावनाएं और सीमाएं
- भारत और अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिसमें विदेशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां, शरण मुद्दे, अंतरराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दे शामिल हैं
- भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियां

- भारत की पड़ोसी प्रथम नीति

विदेश मंत्री ने 18 जनवरी 2020 को 'भारत की पड़ोस प्रथम नीति' पर सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारत के परामर्शदात्री, गैर-पारस्परिक और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण कार्यों पर प्रकाश डाला गया।

विदेश मंत्री ने 16 जनवरी 2021 को 'भारत की वैश्विक रणनीति' पर वर्ष 2021 की प्रथम सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

संसद के बजट सत्र के दौरान 128 प्रश्नों को स्वीकार किए गए और उनके उत्तर दिए गए। शून्यकाल के दौरान नियम 377 और विशेष उल्लेख के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के 40 मामलों का उत्तर दिया गया।

जबकि संसद के मानसून सत्र के दौरान, शून्यकाल के दौरान और नियम 377 के अंतर्गत तत्काल सार्वजनिक महत्व के 10 मुद्दों पर 57 प्रश्न स्वीकार किए गए और उनके उत्तर दिए गए।

समन्वय अनुभाग

समन्वय अनुभाग प्रभावी रूप से मंत्रालय और भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त निकायों और गैर सरकारी संगठनों सहित निजी संस्थानों के बीच प्रभावी ढंग से संवाद करता है।

यह अनुभाग मंत्रिमंडल सचिवालय के पोर्टल और शिकायत निवारण और कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा पर प्रधानमंत्री के प्रगति वीडियो-सम्मेलन में मंत्रालय की भागीदारी के लिए मंत्रालय की प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है।

यह प्रभाग पद्म पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, टैगोर पुरस्कार, भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के विद्वानों को राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण-पत्र और शास्त्रीय तमिल के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से संबंधित कार्यों का भी समन्वय करता है।

मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ

मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा विदेशों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू/समझौतों की समीक्षा को उनकी निरंतर प्रासंगिकता और स्थिति के दृष्टिकोण से समन्वित करने का जनादेश है।

कुल 3178 समझौता ज्ञापन/समझौते विद्यमान हैं जिनमें से अब तक 3038 समझौता ज्ञापनों/समझौतों की समीक्षा की जा चुकी है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2294 समझौता ज्ञापन/समझौते जारी रखने और 744 समझौता ज्ञापन/

समझौतों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय ने विच्छेदन के लिए 744 में से 694 समझौता ज्ञापन/समझौतों की जांच की है जबकि 50 की जांच की जा रही है। मंत्रालय द्वारा जांचे गए 694 समझौता ज्ञापनों में से 602 समझौता ज्ञापनों को बंद करने का निर्णय लिया गया है जबकि 92 को जारी रखने की अनुशंसा की गई है।

31

सम्मेलन प्रभाग

सम्मेलन प्रभाग (सीडी) भारत और विदेशों में विदेश मंत्रियों/प्रतिनिधियों की अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय भागीदारी सहित बैठकों/कार्यक्रमों/संगोष्ठी/सम्मेलनों के आयोजन में विदेश मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को सभी साजो-सामान की व्यवस्था प्रदान करता है। प्रोटोकॉल, प्रतिनिधियों की सुरक्षा और उच्चतम स्तर की परिशुद्धता से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए सीडी ने 08 इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों (ईएमसी) का पैनल बनाया है। आयोजन के लिए ईएमसी का चयन मंत्रालय के संबंधित प्रभाग की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

01 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक की अवधि के दौरान, अधिकांश निर्धारित कार्यक्रमों को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित/रद्द कर दिया था। सीडी ने हालांकि 20-21 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में आयोजित दूसरी सीसीसीएस संगोष्ठी में सभी साजो-सामान की सहायता प्रदान की।

इसके अलावा, सीडी सुषमा स्वराज भवन (एसएसबी) (पूर्व में पीबीके) के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करता है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 02 अक्टूबर 2016 को किया था। पीबीके के उद्घाटन के बाद से, राष्ट्रपति ने 3 कार्यक्रमों में भाग लिया है, उपराष्ट्रपति ने 09 कार्यक्रमों में भाग लिया है और प्रधानमंत्री ने सम्मानित अतिथि के रूप में 15 कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसके

अलावा प्रधानमंत्री ने एसएसबी में मंत्रिपरिषद् की 06 बैठकों की भी अध्यक्षता की है। एसएसबी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और अन्य सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित आधिकारिक आयोजनों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि के लिए एक पसंदीदा स्थल बना हुआ है। एसएसबी में आयोजित कार्यक्रमों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	अवधि	कार्यक्रमों की संख्या
1	अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017	45
2	अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018	144
3	अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019	210
4	अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020	89
	कुल	488

एसएसबी में आयोजित आयोजनों की कुल संख्या संगठन-वार इस प्रकार है:

क्र. सं.	कार्यक्रम आयोजक	अक्टूबर, 2016 से मार्च, 2017	अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018	अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019	अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020	कुल
1	विदेश मंत्रालय	23	69	89	23	204
2	अन्य मंत्रालय/विभाग	16	59	95	40	210
3	अन्य सरकारी संगठन	0	10	3	18	31
4	अन्य संगठन	6	6	23	8	43
	कुल	45	144	210	85	488

एसएसबी अब लगभग 300 अधिकारियों के लिए कार्य स्थान के साथ जी-20 शिखर सम्मेलन सचिवालय के रूप में सेवा करने के लिए सुविधाओं का उन्नयन/सृजन रहा है और यथासमय चालू होने की आशा है।

32

अभिलेखागार

मंत्रालय का अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन (एआरएम) प्रभाग, अभिलेखागार और अभिलेख प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों से संबंधित है। रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर (आरईएम) का उन्नयन, मौजूदा सॉफ्टवेयर का प्रतिस्थापन और नए सर्वर के साथ मौजूदा सर्वर के प्रतिस्थापन के साथ-साथ पुराने डेस्कटॉप जिनका उपयोग रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा तक पहुंचने के लिए किया जा रहा है, नियमित रूप से किया जा रहा है। रेम का उन्नयन, मौजूदा सॉफ्टवेयर का प्रतिस्थापन, और नए कंप्यूटरों के साथ मौजूदा कंप्यूटरों का प्रतिस्थापन वर्तमान में चल रही एक प्रक्रिया है।

इस अवधि के दौरान, कंप्यूटर कक्ष, ब्राउज़िंग कक्ष, कॉम्पैक्टर कक्ष, फाइलों के साथ 282 रैक वाले छह कॉम्पैक्टर रिकॉर्ड सर्वरों द्वारा साफ किए गए और सभी फाइलों को स्थानांतरण के लिए बक्सों में पैक किया गया।

मंत्रालय का एआरएम प्रभाग वर्तमान में दो स्थानों से काम कर रहा है, अर्थात् आईएसआईएल भवन की तीसरी मंजिल, भगवान दास रोड के कुछ कमरों से और सी-1 हटमेंट्स द्वारा शुकोह रोड में कुछ कमरों से। लोधी रोड स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सभी अभिलेखीय अभिलेखों को चिन्हित कमरों में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है।

रिपोर्ट अवधि के दौरान, कंप्यूटर कक्ष, ब्राउज़िंग कक्ष, कॉम्पैक्टर कमरे के (फाइलों के साथ 282 रैक वाले छह कॉम्पैक्टर) रिकॉर्ड सर्वरों द्वारा भाग लिया गया था, और कई फाइलें सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अंतिम स्थानांतरण के लिए बक्सों में पैक की गई थीं। यह आशा है कि रैक के लिए सीजीओ परिसर में आवश्यक स्थान उपलब्ध होने पर अभिलेखीय अभिलेखों को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित करने का कार्य 2021 की तीसरी तिमाही तक पूरा हो जाएगा।

33

सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान

परिसर में, एसएसआईएफएस संस्थान में प्रतिवर्ष बुनियादी संरचना और सुविधाओं के रखरखाव, नवीकरण, उन्नयन और आधुनिकीकरण के संबंध में अनेक परियोजनाओं का निष्पादन किया जाता है। इसके अलावा, यह

आईएफएस अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिन्हें नीचे विवरण में वर्णित किया गया है:

भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) अधिकारियों के लिए संवर्ग प्रशिक्षण कार्यक्रम

इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम

2019 बैच के तीस आईएफएस ओटीएस और दो भूतानी राजनयिक 09 दिसंबर 2019 से छह माह के इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एसएसआईएफएस में शामिल हो गए, जिसे कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण निर्धारित छह महीने की अवधि से आगे बढ़ाकर 24 जुलाई 2020 कर दिया गया। एसएसआईएफएस में ओटीएस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय संबंधों, विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और बड़ी शक्तियों और बहुपक्षीय संगठनों के सिद्धांतों पर मॉड्यूल शामिल थे। इसमें वित्त, लेखा, प्रशासन, स्थापना, कांसुलर कार्य, पासपोर्ट और वीजा, अंतरराष्ट्रीय कानून, प्रोटोकॉल, आर्थिक और वाणिज्यिक कूटनीति, रक्षा कूटनीति, एसएंडटी, साइबर सुरक्षा, घरेलू नीति, स्वास्थ्य मॉड्यूल,

पर्यटन, आतिथ्य और मीडिया प्रबंधन पर मॉड्यूल भी शामिल थे। सॉफ्ट पावर और कम्युनिकेशन स्किल पर जोर दिया गया।

प्रशिक्षुओं को ज्ञान के प्रभावी प्रसार के लिए, अनुभवी सिविल सेवकों, सेवानिवृत्त राजदूतों, वरिष्ठ संकाय और विभिन्न मंत्रालयों, संस्थानों और चिंतनों के शोध अध्येताओं को संसाधन व्यक्तियों के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एसएसआईएफएस ने आईएफएस ओटी के साथ बातचीत करने के लिए विदेशों के राजदूतों/उच्चायुक्तों (P5 देशों सहित) को भी आमंत्रित किया। कनाडा के विदेश सेवा संस्थान (सीएफएसआई) ने एसएसआईएफएस और सीएफएसआई के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में ओटीएस को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताओं पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया।



विदेश मंत्री ने 2020 बैच के आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षकों और भूटानी राजनयिकों के साथ 22 दिसंबर 2020 को बातचीत करते हुए

आईएफएस ओटी को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न अभिनव शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाए गए थे और प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों) के संचालन में अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उपकरणों का उपयोग किया गया था। शैक्षणिक उपकरणों में इंटरैक्टिव व्याख्यान, सिमुलेशन, भूमिका नाटक, कार्यशालाएं, हस्त-प्रशिक्षण, मामला-अध्ययन, सफलता की गाथाएं, संरचित सलाह कार्यक्रम, विदेशी और भारतीय राजनयिकों के बीच संवाद, क्षेत्र का दौरा और विभिन्न विधियों के माध्यम से प्रकटन शामिल थे।

ओटीएस ने भारत-प्रशांत संरचना के अंतर्गत भारतीय मिशनों अर्थात इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम, के साथ 03 से 07 फरवरी 2020 तक एक सप्ताह तक मिशन ओरिएंटेशन अटैचमेंट किया था ताकि उन्हें विदेशों में भारतीय मिशनों के काम से परिचित करवाया जा सके। ओटीएस ने सीमा प्रबंधन और क्षेत्र में सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत के बारे में बेहतर परिप्रेक्ष्य बनाने के लिए भारतीय सेना (09-13 मार्च 2020) के साथ एक सप्ताह कार्य किया था। कोविड-19 महामारी के कारण देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, विरासत और पर्यटन क्षमता से बेहतर परिचित कराने के लिए 10 दिन तक चलने वाली भारत दर्शन यात्रा (15-23 मार्च 2020) में कटौती करनी पड़ी। ओटीएस ने प्रतिनिधि के रूप में हिंद महासागर वार्ता (13 दिसंबर 2019), दिल्ली संवाद (14 दिसंबर 2019) और रायसीना वार्ता (15-16 जनवरी 2020) में भाग लिया।

ओटीएस ने मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष में कर्तव्यों का निर्वहन किया और वे विदेश मंत्रालय के कोविड-19 से संबंधित कार्यों से निपटने में अग्रिम पंक्ति के कामगार थे। विशेष रूप से, उन्हें वंदे भारत मिशन उड़ानों सहित उन देशों/क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों/एनआरआई/पीआईओ के प्रश्नों का उत्तर देने का कार्य सौंपा गया था।

इससे ओटीएस को आपदा प्रबंधन का प्राथमिक अनुभव प्रदान किया गया।

आईएफएस 2019 बैच से शुरू करते हुए एसएफएस ने निर्धारित शासनादेश के अनुरूप ओटीएस के वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मूल्यांकन की नई व्यवस्था शुरू की। इस वर्ष गुजरात फोरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय, गांधीनगर द्वारा आयोजित 11 फरवरी से 25 मई 2020 तक 'साइबर सुरक्षा' में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत और 29 अप्रैल से 01 मई 2020 तक 'रैपिड रीडिंग' की शुरुआत भी देखी गई, जो ओट्स के लिए शिकागो के आईरिस रीडिंग द्वारा वस्तुतः आयोजित की गई थी।

आईएफएस ओटीएस के 2019 बैच के प्रशिक्षण के समापन के अवसर पर 24 जुलाई 2020 को एक समापन समारोह का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में विदेश मंत्री ने की थी। इस अवसर पर 2019 बैच के सर्वश्रेष्ठ ओटी के लिए विदेश मंत्रालय का स्वर्ण पदक, एस्पिट डी कोर के लिए राज्यमंत्री रजत पदक, सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध के लिए राजदूत विमल सान्याल मेमोरियल पदक, सर्वश्रेष्ठ समिति (सिनेमा समिति) के लिए ट्राफी और भूटानी राजनयिकों के लिए ट्राफी प्रदान की गई।

2020 बैच के 24 आईएफएस ओटीएस 21 दिसंबर 2020 को एसएफएसआईएफएस में अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे। दिसंबर 2020 में ओरिएंटेशन मॉड्यूल के पूरा होने पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों (द्विपक्षीय और बहुपक्षीय), रक्षा और सुरक्षा, पड़ोस, प्रमुख शक्तियों, निरस्त्रीकरण, पर्यावरण और जलवायु, प्रशासन मामलों को कवर करने वाले आईटीपी के चरण-1 4 जनवरी 2021 को शुरू होने वाले हैं। इंडक्शन प्रशिक्षण का समापन 18 जून 2021 को होगा।

मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम III

1994 बैच के आईएफएस अधिकारी के लिए एक अनुपूरक आजीविका-मध्यप्रशिक्षण कार्यक्रम-III 05-09 अक्टूबर 2020 से आयोजित किया गया

था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विदेश नीति का मॉड्यूल और विदेश नीति पर एक शोध शामिल था।

मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम I

2008 बैच के आईएफएस अधिकारियों के लिए एक आजीविका-मध्यप्रशिक्षण कार्यक्रम-1 (एमसीटीपी-1) 23 नवंबर से 04 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन

आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विदेश नीति का मॉड्यूल, विदेश नीति का कागज और भारत की विदेश नीति पर पुस्तक समीक्षा शामिल थी।

अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. दुभाषिण संवर्ग के लिए पदोन्नति संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम: मंत्रालय के दुभाषिण संवर्ग के सात अधिकारियों के लिए पदोन्नति से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम 06-17 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन मोड के माध्यम से एसएफएसआईएफएस द्वारा आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दो विषय शामिल थे-विदेश नीति मॉड्यूल और व्याख्या मॉड्यूल।

आभासी आयोजित किया गया था और मिशनों/पोस्टों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया।

ख. सोशल मीडिया पर मिशन/पोस्ट के प्रमुखों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल

मंत्रालय के बाह्य प्रचार (एक्सपी) प्रभाग के समन्वय से 12-16 अक्टूबर 2020 तक एसएफएसआईएफएस द्वारा सोशल मीडिया पर मिशनों/पोस्टों के प्रमुखों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग. मंत्रालय के स्टेट प्रभाग के सहयोग से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के लिए 04 से 08 जनवरी 2021 तक एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाना और उन्हें विश्व के साथ जुड़ने के लिए आवश्यक अभिविन्यास, ज्ञान और व्यवसायिक कौशल प्रदान करना है ताकि उनके संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एफडीआई, प्रौद्योगिकी गठबंधन, संयुक्त उद्यम, व्यापार और पर्यटन आदि को आकर्षित किया जा सके।

आईएफएस की शाखा ख के लिए गैर-प्रतिनिधित्व ग्रेड (एनआरजी) प्रशिक्षण कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, गैर-प्रतिनिधित्व ग्रेड (एनआरजी) अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए वेबिनार के माध्यम से निम्नलिखित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया:

- 76वें आईएमए (एकीकृत मिशन लेखा प्रणाली) प्रशिक्षण कार्यक्रम में 10-12 जून 2020 तक 88 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 13 जून 2020 को आईवीएफआरटी (इमिग्रेशन, वीजा, विदेशियों के पंजीकरण और ट्रेकिंग) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सहायक अनुभाग अधिकारियों (एसओ) और वैयक्तिक सहायकों (पीए) के लिए पदोन्नति संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम 31 अगस्त से 04 सितंबर 2020 में 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 09 सितंबर, 2020 को सीधी भर्ती करने वाले निजी सहायकों और आशुलिपिकों के लिए छमाही अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा में 19 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 14-15 सितंबर, 2020 तक आईवीएफआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- 25 सितंबर 2020 को सीधी भर्ती वाले सहायक अनुभाग अधिकारियों के लिए त्रैमासिक टंकण परीक्षा में 04 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- वरिष्ठ सचिवीय सहायकों (एसएसए), कनिष्ठ सचिवीय सहायकों (जेएसए) और आशुलिपिकों के लिए पदोन्नति से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम 28 सितंबर से 05 अक्टूबर 2020 में 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 12-16 अक्टूबर 2020 तक 77 वें आईएमए प्रशिक्षण कार्यक्रम में 83 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 24-25 नवंबर, 2020 तक आईवीएफआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम में 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- 14-18 दिसंबर 2020 से 78वां आईएमएएस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 66 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- प्रत्यक्ष भर्ती व्यक्तिगत सहायकों के लिए छमाही अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा; आशुलिपिक और लेखा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईएमएएस प्रशिक्षण की तैयारी में); 2021 की पहली तिमाही में 79 वां आईएमए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

एसएसआईएफएस 2020 में विदेशी राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद आयोजित:

सीरियाई राजनयिकों के लिए तीसरा विशेष पाठ्यक्रम और इराकी राजनयिकों के लिए चौथा विशेष पाठ्यक्रम संयुक्त रूप से 24 फरवरी-07 मार्च 2020 से आयोजित किया गया जिनमें 14 राजनयिकों ने भाग लिया।

सूरीनामी राजनयिकों के लिए प्रोटोकॉल पर पहला विशेष पाठ्यक्रम 14-25

सितंबर 2020 से ऑनलाइन आयोजित किया गया था जिसमें 19 राजनयिकों ने भाग लिया था।

सुषमा स्वराज व्याख्यान 2020 भारत के आधार 2020 भारत परिचय के आधार पर इंडिया फाउंडेशन के साथ 15-16 अक्टूबर 2020 (भाग- I) और 19-20 नवंबर 2020 (भाग- II) को आयोजित किया गया जिसमें 39 राजनयिकों ने भाग लिया था।

समझौता ज्ञापन

2020 के दौरान, एसएसआईएफएस ने निम्नलिखित विदेशी समकक्ष संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए:

- 14 फरवरी 2020 को पुर्तगाली गणराज्य के विदेश मंत्रालय।

- 25 अगस्त 2020 को वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के विदेश मंत्रालय की वियतनाम राजनयिक अकादमी।

- वेनान्सिओ दा सिल्वा मौरा इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, विदेश संबंध मंत्रालय, अंगोला गणराज्य 07 सितंबर 2020 को।

34

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद



आईसीसीआर भारत सरकार की साफ्ट और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और परस्पर समझ को बढ़ावा देना और मजबूत करना है।

परिषद महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में प्रमुख वेबिनार का आयोजन करती है, परिषद के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा आईसीसीआर के स्थापना दिवस का ऑनलाइन उत्सव, कविता लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करती हैं। अपनी मेगा परियोजना के अंतर्गत, इसने भारतीय पारंपरिक ज्ञान और संस्कृति पर ज्ञान कैप्सूल प्रदान करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल शुरू किया।

उपलब्धियां (2020-21)

इसने विदेशी नागरिकों को 3454 छालवृत्ति स्लॉट के विरुद्ध 26 योजनाओं के अंतर्गत 131 देशों के भारतीय विश्वविद्यालयों/131 देशों के यूजी/पीजी/एमफिल/पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 3454 छालवृत्तियों की पेशकश की, 2617 प्रवेश की पुष्टि की गई है।

आईसीसीआर ने महामारी के दौरान, विश्वविद्यालयों/संस्थानों के माध्यम से 900 से अधिक नए भर्ती छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा प्रदान की ताकि उन्हें अकादमिक वर्ष की हानि से बचाया जा सके।

इसके अलावा, अपने गृह देशों में वापस जाने में रुचि रखने वाले छात्रों को सुविधा दी गई और लगभग 503 छात्रों को दो महीने की अवधि में अर्थात मार्च से मई 2020 तक उन्हें वापस भेजा गया।

विदेशों में भारतीय अध्ययन और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए, आईसीसीआर ने विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ परामर्श करके दुनिया भर के विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन (राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध अध्ययन) और हिंदी, संस्कृत, उर्दू और बंगाली (नृत्य और संगीत) के पीठों की स्थापना की।

परिषद और मेजबान विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (समझौता ज्ञापन) के आधार पर पीठों की स्थापना करती है। अक्टूबर 2020 तक, आईसीसीआर के पास दुनिया भर में 57 परिचालनिक पीठ थीं।

सम्मेलन

आईसीसीआर हर वर्ष भारत-दर्शन, बौद्ध धर्म, सूफीवाद, भारतीय संपर्क, भारतीय अध्ययन आदि जैसे विषयों पर अनेक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन और समर्थन करता है। कोविड-19 के दौरान आईसीसीआर ने व्यक्तिगत रूप से और अन्य एजेंसियों के सहयोग से आभासी सम्मेलन और संगोष्ठी आयोजित करने की पहल की।

सेंटर फॉर रोमा स्टडीज एंड कल्चरल रिलेशंस (सीआरएससीआर) -एआरएसपी (24 जुलाई 2019 को स्थापित) ने 26 मई 20 जून और 05 अगस्त 2020

को, तीन आभासी अंतरराष्ट्रीय रोमा सम्मेलनों का आयोजन किया। अप्रैल 2020 में, आईसीसीआर के 70 वें स्थापना दिवस पर दो श्रेणियों के लिए ऑनलाइन एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी अर्थात भारत में आईसीसीआर के छात्रों और विदेशों में आईसीसीआर के पूर्व छात्रों के लिए और भारतीय प्रवासी (एनआरआई और पीओआई दोनों) के लिए।

आईसीसीआर ने 21 मई 2020 को विश्व संस्कृति दिवस पर इटली के मिलान से आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉ एंटोनियो मोरांडी द्वारा तृतीय पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंटरनेशनल ओरेशन का आयोजन किया।

लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 01 अगस्त 2020 को एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वेबिनार “लोकमान्य तिलक-स्वराज से अत्मनिरभर भारत” का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया था।

इसने “नमस्ते 2020-भारतीय सॉफ्ट पावर का वैश्विक उत्सव” के लिए 15 अगस्त से 06 सितंबर 2020 तक, सेंटर ऑफ सॉफ्ट पावर (सीएसपी) के साथ सहयोग किया। इसने महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती के समापन के भव्य समारोह के उपलक्ष्य में विदेशों में मिशनों के साथ समन्वय किया। 19-21 नवंबर, 2020 से यह भारत-दर्शन पर वेबिनार आयोजित किया।

हिंदी: आईसीसीआर ने जून 2020 में हिंदी द्विमासिक पत्रिका “गगनांचल” नंबर 5-6 प्रकाशित की। 14 सितंबर 2020 को आजाद भवन में हिंदी कार्यशाला “टेक्स्ट टू स्पीच- स्पीच” का आयोजन किया गया।

भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक राजनयिक विश्व स्तर पर योग, वेद और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए परिषद ने भारतीय संस्कृति के शिक्षक (आईसीटी) को अपने आईसीटी में भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, हिंदुस्तानी/कान्नाटिक वोकल, तबला और हिंदी भाषा आदि विषयों में विभिन्न मिशनों/पोस्टों /आईसीसीआर और भारत आधारित शिक्षकों के लिए तैनात किया। इसके अतिरिक्त, परिषद ने योग, भारतीय नृत्य के शिक्षकों के रूप में संसाधन व्यक्तियों को भी तैनात किया है जहां आईसीसीआर के सांस्कृतिक केंद्र नहीं हैं।

विदेश में कोविड-19 के दौरान, आईसीसीआर ने “इंडिया ग्लोबल वीक”-लंदन, “द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल (टीजीआईएफ)-ओटावा”, “सारंग-2020-कोरिया गणराज्य में भारत का छठा वार्षिक महोत्सव” और “भारत एन कंसियटो महोत्सव के लिए प्रायोजित सितार समूह- स्पेन” जैसे विदेशों में त्योहारों पर रिकॉर्ड किए गए प्रदर्शनों को स्ट्रीमिंग करके ऑनलाइन/वर्चुअल परफॉर्मेंस पेश करने की पहल की।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) 2020 दुनिया भर में अधिकांशतः आभासी मोड में मनाया गया था। आईसीसीआर ने 114 भारतीय मिशनों और 39 पोस्टों के माध्यम से 147 देशों में छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस -2020 के आयोजन को सुगम बनाया।



अनुबंध-1

2020 -21 के दौरान निष्पादित पूर्ण शक्तियों की सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	देश	हस्ताक्षर करने की तारीख	प्रशासनिक मंत्रालय
1.	रक्षा संबंधित उपकरणों के उत्पादन प्रॉपण, अनुसंधान और विकास तथा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	फिनलैंड	15.01.2020	रक्षा मंत्रालय
2.	ब्राजील संघ गणराज्य और भारत गणराज्य के मध्य निवेश सहयोग तथा सरलीकरण संधि	ब्राजील	17.01.2020	वित्त मंत्रालय
3.	करो के संबंध में सूचना आदान-प्रदान करने के लिए भारत और समोआ के मध्य करार	समोआ	20.01.2020	वित्त मंत्रालय
4.	26 अप्रैल 1988 को नई दिल्ली में आयकर के संबंध में भारत और ब्राजील के मध्य दोहरे कराधान और वित्तीय कर चोरी से बचने के लिए हस्ताक्षर की गई कन्वेंशन को संशोधित करने के संबंध में प्रोटोकॉल	ब्राजील	21.01.2020	वित्त मंत्रालय
5.	भारत और ब्राजील के मध्य सामाजिक सुरक्षा पर करार	ब्राजील	22.01.2020	विदेश मंत्रालय
6.	भारत और चिल्ली के मध्य दोहरे कराधान को हटाने और वित्तीय करावंचन को रोकने तथा आयकर और इसके प्रोटोकॉल को रोकने के संबंध में करार	चिल्ली	10.02.2020	वित्त मंत्रालय
7.	जापान के सुरक्षाबलों और भारतीय सशस्त्र बलों के मध्य आपूर्ति और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित भारत और जापान के मध्य करार	जापान	02.09.2020	रक्षा मंत्रालय
8.	भारत और फिलीपींस के मध्य सीमा शुल्क मामलों के संबंध में आपसी सहायता और सहयोग के संबंध में करार	फिलीपींस	03.11.2020	वित्त मंत्रालय
9.	न्यू डेवलपमेंट बैंक और भारत के मध्य भारत में न्यू डेवलपमेंट बैंक के भारतीय क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के संबंध में करार	न्यू डेवलपमेंट बैंक	03.12.2020	वित्त मंत्रालय

परिशिष्ट

अनुबंध-1: 2020-21 के दौरान निष्पादित पूर्ण शक्तियों की सूची

अनुबंध -II: 2020-21 के दौरान भारत द्वारा अनुसमर्थित संधियों की सूची

अनुबंध -III: 2020-21 के दौरान की गई संधियों, करारों, समझौता ज्ञापनों आदि की सूची

अनुबंध-IV : 2020-21 में द्विपक्षीय यात्राएं

अनुबंध-V : अप्रैल, 2020 से जनवरी, 2021 तक वर्चुअल शिखर सम्मेलन

अनुबंध-VI : 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक विदेशी मिशन प्रमुखों द्वारा प्रत्याह्व पत्र प्रस्तुतीकरण

अनुबंध-VII : 2020-21 के दौरान मुख्यालय और विदेश स्थित मिशनों में संवर्ग पदों की संख्या

अनुबंध -VIII: विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त आईएफएस अधिकारियों की संख्या

अनुबंध -IX: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची (आरपीओ)

अनुबंध -X: पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) की राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची

अनुबंध XI: डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची

अनुबंध-II

भारत द्वारा 2020 -21 के दौरान अनुसमर्थित संधियों की सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	देश/संगठन	हस्ताक्षर करने की तारीख	अनुसमर्थन करने की तारीख	प्रशासनिक मंत्रालय
1	भारत और अल्जीरिया के मध्य कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट के संबंध में करार	अल्जीरिया	31.08.2019	19.06.2020	विदेश मंत्रालय
2	भारत और ब्राज़ील के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता के लिए करार	ब्राज़ील	25.01.2020	03.03.2020	गृह मंत्रालय
3	भारत और चिली के मध्य आयकर के संबंध में दोहरे कराधान को हटाने और वित्तीय करावंचन को रोकने के लिए करार	चिली	09.03.2020	18.09.2020	वित्त मंत्रालय
4	भारत और इक्वेटोरियल गिनी के बीच कूटनीतिक और आधिकारिक/सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा की छूट के संबंध में करार	इक्वेटोरियल गिनी	18.08.2017	12.03.2020	विदेश मंत्रालय
5	फ्रांस के साथ प्रवासन और आवाजाही भागीदारी के संबंध में करार पर हस्ताक्षर	फ्रांस	10.03.2018	14.02.2020	विदेश मंत्रालय
6	भारत और ग्रैंडा के बीच कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा की छूट के संबंध में करार	ग्रैंडा	06.02.2020	27.02.2020	विदेश मंत्रालय
7	भारत और जापान के बीच भारतीय वायुसेना और जापान के सशस्त्र रक्षा बलों के मध्य सामान और सेवाओं के परस्पर आदान प्रदान करने के लिए करार	जापान	09.09.2020	11.11..2020	विदेश मंत्रालय
8	भारत और मलावी के बीच प्रत्यर्पण संधि	मलावी	05.11.2020	27.07.2020	विदेश मंत्रालय
9	भारत और मार्शल द्वीप समूह के बीच कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा की छूट के संबंध में करार	मार्शल द्वीप समूह	18.02.2020	27.02.2020	विदेश मंत्रालय
10	भारत गणराज्य सरकार और ओमान सलतनत सरकार के बीच समुद्री यातायात के लिए करार	ओमान	24.12.2019	10.02.2020	पोत परिवहन मंत्रालय
11	भारत और पुर्तगाल के बीच समुद्री यातायात और बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार	पुर्तगाल	14.02.2020	10.09.2020	पोत परिवहन मंत्रालय
12	भारत और समोआ के बीच करों के संबंध में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए करार	समोआ	12.03.2020	22.05.2020	वित्त मंत्रालय
13	भारत गणराज्य सरकार और सरबिया गणराज्य सरकार के बीच रक्षा सहयोग के संबंध में करार	सरबिया	07.11.2019	24.12.2020	रक्षा मंत्रालय
14	भारत और सियरा लियोन के बीच कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षा की छूट के संबंध में करार	सियरा लियोन	03.03.2020	27.02.2020	विदेश मंत्रालय
15	यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन में दसवीं अतिरिक्त प्रोटोकॉल शामिल करना	यू पी यू	07.09.2018	10.01.2020	डाक विभाग
16	परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के संबंध में स्टॉकहोम अभिसमय के अनुबंधों में संशोधन	यू एन ओ		02.12.2020	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अनुबंध-III

2020-21 के दौरान की गई संधियों, करारों, समझौता ज्ञापनों आदि की सूची

क्र. सं.	शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
1.	सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत गणराज्य और वेनांसीओ डा सिल्वा मोरा अंतरराष्ट्रीय संबंध संस्थान, विदेश संबंध मंत्रालय, अंगोला गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	अंगोला	07.09.2020	विदेश मंत्रालय
2.	भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साइबर सहयोग संबंधी फ्रेमवर्क	ऑस्ट्रेलिया	04.06.2020	विदेश मंत्रालय
3	जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता ज्ञापन	ऑस्ट्रेलिया	20.05.2020	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
4.	भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश के लोक गणराज्य की सरकार के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन पर प्रोटोकॉल के लिए दूसरा अनुशेष	बांग्लादेश देश	20.05.2020	पौत परिवहन मंत्रालय
5.	निवेशों के संबंध में भारत और बेलारूस के बीच 24/09/2018 हस्ताक्षरित संधि की अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान संबंधी प्रोटोकॉल	बेलारूस	05.03.2020	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
6.	भारत गणराज्य की सरकार और बेल्जियम अधिराज्य की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि	बेल्जियम	21.03.2020	विदेश मंत्रालय
7.	बेनिन के साथ राजनयिक / आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट संबंधी करार	बेनिन	08.03.2020	विदेश मंत्रालय
8.	बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग हेतु भूटान की शाही सरकार और भारत गणतंत्र की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	भूटान	19.11.2020	इसरो
9.	पशुपालन और डेयरी उत्पादन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ब्राज़ील के बीच जेडीआई	ब्राज़ील	25.01.2020	पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
10.	बायोपेनेर्जी सहयोग पर भारत और ब्राज़ील के बीच समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील	25.01.2020	पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
11.	भारत और ब्राज़ील के बीच सामाजिक सुरक्षा संबंधी करार	ब्राज़ील	25.01.2020	मंत्रालय विदेश मंत्रालय
12.	आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर भारत और ब्राज़ील के बीच करार	ब्राज़ील	25.01.2020	गृह मंत्रालय
13.	भारत और ब्राज़ील के बीच के समझौते को लागू करने के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग कार्यक्रम 2020-23	ब्राज़ील	25.01.2020	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
14.	भारत और ब्राज़ील के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम 2020-24	ब्राज़ील	25.01.2020	संस्कृति मंत्रालय
15	भूविज्ञान और खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ब्राज़ील के बीच समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील	25.01.2020	खान मंत्रालय
16	भारत और ब्राज़ील के बीच निवेश सहयोग और सुविधा संधि	ब्राज़ील	25.01.2020	वित्त मंत्रालय
17	साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत गणराज्य के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसपांस टीम (सीईआरटी-इन) और ब्राज़ील संघीय गणराज्य के जनरल कॉऑर्डिनेशन ऑफ नेटवर्क इन्शिडेंट ट्रिटमेंट सेंटर (सीजीसीटीआईआर) के बीच सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील	25.01.2020	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई टी मंत्रालय
18	प्रारंभिक बाल्य अवस्था के क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील के बीच समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील	11.02.2020	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
19	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ब्राज़ील के बीच समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील	07.02.2020	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
20	चिकित्सा की परंपरिक प्रणालियों और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ब्राज़ील के बीच समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील	07.02.2020	आयुष मंत्रालय
21	इनवेस्ट इंडिया और ब्राज़ील की व्यापार एवं निवेश संवर्धन (एपेक्स ब्राज़ील) के बीच समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील	25.01.2020	वित्त मंत्रालय
22	भारत और ब्राज़ील के बीच तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	ब्राज़ील	25.01.2020	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

क्र. सं.	शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
23	ब्रुनेई दारुस्सलाम और भारत के बीच करों के संबंध में सूचना के आदान- प्रदान और संग्रह में सहायता के लिए करार	ब्रुनेई दारुस्सलाम- सलाम		वित्त मंत्रालय
24	रॉयल कम्बोडियन सशस्त्र बलों के लिए आईएनजी उपकरण (आरसीएएफ) के लिए डिमाइनिंग उपकरण के प्रावधान के लिए 1.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के अनुदान के क्रियान्वयन के लिए भारत और कंबोडिया के लिए करार	कंबोडिया		रक्षा मंत्रालय
25	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन यह नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च (एनसीपीओआर) और पोलर नॉलेज (पोलर) कनाडा द्वारा संचालित कैनेडियन हाइ आर्कटिक रिसर्च स्टेशन (सीएचएआरएस) के बीच सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन	कनाडा	25.01.2020	रमं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
26	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) और वित्तीय और उपभोक्ता मामले प्राधिकरण, सस्केचेवान, कनाडा (एपसीएए) के बीच पारस्परिक सहयोग और सूचना के आदान- प्रदान के बीच समझौता ज्ञापन ।	कनाडा		मंत्रालय के वित्त
27	आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के उन्मूलन और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के संबंध में चिली और भारत के बीच करार	चिली	25.01.2020	वित्त मंत्रालय
28	कोस्टा रिका के साथ राजनयिक / आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट संबंधी करार	कोस्टा रिका		विदेश मंत्रालय
29	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार और दानिश पेपेट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, उद्योग, व्यापार एवं वित्तीय मामले मंत्रालय, डेनमार्क अधिराज्य के बीच बौद्धिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	कोस्टा रिका	30.01.2020	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
30	ऊर्जा सहयोग से संबंध में भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन	डेनमार्क		बिजली विद्युत मंत्रालय
31	योग में शैक्षिक सहयोग स्थापित करने के लिए इक्वाडोर के डिवाइन वेल्यूज स्कूल के साथ समझौता ज्ञापन	इक्वाडोर		मंत्रालय आयुष मंत्रालय
32	इंफिटोरियल गिनी के साथ राजनयिक / आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट संबंधी करार	इंफिटोरियल गिनी		मंत्रालय विदेश मंत्रालय
33	परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए भारत सरकार और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय के बीच करार	यूरोपीय संघ		परमाणु परमाणु ऊर्जा विभाग
34	रक्षा संबंधी उपकरणों के उत्पादन, खरीद अनुसंधान एवं विकास तथा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के बीच समझौता ज्ञापन	फिनलैंड		रक्षा मंत्रालय
35	भारत और फिनलैंड के बीच पर्यावरण सहयोग पर समझौता ज्ञापन	फिनलैंड		पर्यावरण मंत्रालय
36	भारत और फ्रांस के बीच 17 सितंबर 2022 तक ऑथोराइजेशन प्रोविजोर डी सेजोर (एपीएस) और फ्रेंच इंटरनेशनल इंटरनशिप ओरोग्राम (वीआईई) योजना का विस्तार जिसके तहत फ्रांस में भारतीय छात्रों को वीजा प्रदान किया गया, जो अपनी मास्टर स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद 12 महीने तक फ्रांस में रह सकेंगे, जिससे उन्हें संबंधित क्षेत्रों में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलता है और भारत सरकार स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करने के एक वर्ष के भीतर फ्रांसीसी छात्रों को 12 महीने के लिए इंटरनशिप के लिए वीजा प्रदान करती है।	फ्रांस		विदेश मंत्रालय
37	साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच समझौता ज्ञापन	इजराइल		- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
38	साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सीईआरटी आईएन, मेटा और फ्रेंच नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, फ्रांस के बीच सहयोग का कार्यक्रम	जापान		- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
39	इस्पात उद्योग के क्षेत्र में भारत के इस्पात मंत्रालय और जापान के इकनोमी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन	जापान		इस्पात मंत्रालय
40	भारत और ग्रेनेडा के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट संबंधी करार	ग्रेनेडा		विदेश मंत्रालय

क्र. सं.	शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
41	ग्रेनेडा के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा से छूट संबंधी करार	ग्रेनेडा		विदेश मंत्रालय
42	छोटे उपग्रह के लिए इलेक्ट्रिक प्रोग्राम में सहयोग के संबंध में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग योजना	इजराइल		इसरो
43	औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत और एमएफए, इटली के बीच वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिए कार्यकारी प्रोटोकॉल के लिए अनुशेष	इटली		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
44	स्मारकों के लिए पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए आईआईटी कानपुर और सौप्रिनटेनडेंजा आर्कियोलॉजिकल, इटली के बीच समझौता ज्ञापन	इटली		मानव मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय
45	'भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इटली के संस्कृति मंत्रालय के बीच सह-उत्पादन करार के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया संबंधी नियमावली हेतु टिप्पणियों का आदान-प्रदान	इटली		सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
46	द्विपक्षीय वाणिज्यिक साझेदारी को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और इतालवी व्यापार एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन	इटली		वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
47	लक्षित क्षेत्रों में निवेशों का स्त्रोत ज्ञात करने, जांच करने, आकलन, निवेश हेतु सहयोग को सुदृढ़ करने और सुविधा प्रदान करने तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए एनआईआईएफ, भारत और सीडीपी, इटली के बीच करार	इटली		वित्त मंत्रालय
48	भारतीय वायुसेना और जापान के आत्मरक्षक बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के संबंध में भारत और जापान के बीच करार	जापान		विदेश मंत्रालय
49	कजाखस्तान गणराज्य में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में भारत और कजाखस्तान के बीच समझौता ज्ञापन	कजाखस्तान		विदेश मंत्रालय
50	भारत और लेसेथो ग्रेनेडा के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट संबंधी करार	लेसेथो		विदेश मंत्रालय
51	खेल एवं युवा मामलों के संबंध में भारत और मालदीव के बीच करार	लदीव		खेल एवं युवा मामले मंत्रालय
52	ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए 100 मिलियन अमरीकी डॉलर की अनुदान सहायता के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन ।	लदीव		विदेश मंत्रालय
53	मालदीव में हनीमाधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पुनर्विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच करार	लदीव		भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं विदेश मंत्रालय
54	भारत और मार्शल दीवसमूह के बीच राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं छूट संबंधी करार	मार्शल द्वीपसमूह		विदेश मंत्रालय
55	मार्शल दीपसमूह के बीच राजनयिक/आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट संबंधी करार	मार्शल द्वीपसमूह		विदेश मंत्रालय
56	ईओ डेटा और क्षमता निर्माण का प्रयोग करते हुए वनअग्नि प्रबंधन के संबंध में भारत गणराज्य के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और यूनाइटेड मैक्सिकन स्टेट्स की मैक्सिकन स्पेस एजेंसी के बीच विशिष्ट सहयोग करार	मेक्सिको		इसरो
57	भारत के सुप्रीम कोर्ट और मोरक्को के सुप्रीम काउंसिल ऑफ ज्यूडिशियल पावर के बीच सहयोग करार	मोरक्को		विधि एवं न्याय मंत्रालय
58	पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत गणराज्य और विद्युत एवं ऊर्जा मंत्रालय, म्यांमार संघीय गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	म्यांमार		पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

क्र. सं.	शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
59	लोगों की तस्करी को रोकने; तस्करी द्वारा ले जाए गए लोगों को बचाने और उनकी सहायता करने, प्रत्यावर्तन और पुनः एकीकरण के लिए सहयोग हेतु भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघीय गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन	म्यांमार		गृह मंत्रालय
60	राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत बृटहाइड्रुंग टाउनशिप में क्यॉली-ऑंग-ओह्लम्पू रोड, क्रियांग तुंग क्यवा पंग सड़क के निर्माण के लिए, भारत के राजदुतावास, यंगून और राखीन राज्य सरकार के बीच परियोजना करार	म्यांमार		विदेश मंत्रालय
61	भारतीय दुतावास, यांगून और राखीन राज्य सरकार के बीच राखीन राज्य विकास कार्यक्रम परियोजना के तहत मरोक टाउनशिप अस्पताल में इन्सिनिरेटर का निर्माण, जीडब्ल्यू टाउनशिप में बीज भंडार गृह और जल आपूर्ति प्रणालियों के निर्माण के लिए परियोजना समझौता	म्यांमार		विदेश मंत्रालय
62	भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच इमारती लकड़ी की तस्करी और टाइगर और अन्य वन्य जीव के संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन	म्यांमार		पर्यावरण मंत्रालय
63	भारत गणराज्य की सरकार और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार के बीच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (क्यूआईपी) के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता पर समझौता	म्यांमार		विदेश मंत्रालय
64	भारत गणराज्य के संचार मंत्रालय और म्यांमार संघ गणराज्य के परिवहन और संचार मंत्रालय के बीच संचार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन	म्यांमार		संचार मंत्रालय
65	भारतीय दुतावास, यांगून और समाज कल्याण, राहत एवं पुनर्वास मंत्रालय के तहत राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत प्री स्कूल के निर्माण के लिए परियोजना समझौते	म्यांमार		विदेश मंत्रालय
66	भारत के दुतावास, यंगून और राखीन राज्य सरकार के बीच राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत राखाइन राज्य की पांच टाउनशिप में सौर ऊर्जा द्वारा बिजली के वितरण के लिए परियोजना समझौता	म्यांमार		विदेश मंत्रालय
67	भारत के दुतावास, यांगून और शिक्षा मंत्रालय म्यांमार सरकार के बीच पुस्तकालय सामग्री के प्रावधान और सॉफ्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए परियोजना समझौता	म्यांमार		विदेश मंत्रालय
68	कृषि मंत्रालय, पशुधन और सिंचाई और भारतीय दुतावास यंगून के बीच राखीन राज्य विकास कार्यक्रम के तहत कस्टम हायरिंग सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रीकरण सब-स्टेशन के उन्नयन के लिए परियोजना समझौता	म्यांमार		विदेश मंत्रालय
69	संयुक्त आयोग की स्थापना पर भारत और नाइजर के बीच समझौता	नाइजर		विदेश मंत्रालय
70	भारत और नाइजर विदेशी नागरिक नाइजर गणराज्य के बीच परामर्श के लिए प्रोटोकॉल	नाइजर		विदेश मंत्रालय
71	शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग के लिए भारत और नाइजीरिया पर सहयोग में बीच समझौता ज्ञापन	नाइजीरिया		इसरो
72	भारत गणराज्य की सरकार और नाइजीरिया की संघीय गणराज्य सरकार के बीच शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन	नाइजीरिया		इसरो
73	भारत -नॉर्वे के बीच भारत नॉर्वे एकीकृत समुद्र प्रबंधन और अनुसंधान पहल के लिए कार्यद्वारे की स्थापना के लिए आश्व पत्र	नॉर्वे		पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
74	ओमान के साथ राजनयिक / अधिकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते	ओमान		विदेश मंत्रालय
75	भारत गणराज्य के विदेश और पुर्तगाली गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच राजनयिक प्रशिक्षण और सूचना के आदान-प्रदान पर समझौता ज्ञापन	पुर्तगाल		विदेश मंत्रालय

क्र. सं.	शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
76	लोथल (गुजरात) में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में समुद्री गैलरी की स्थापना के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन	पुर्तगाल		पोत परिवहन मंत्रालय
77	भारत और पुर्तगाल की सरकारों के बीच समुद्री परिवहन और बंदरगाह विकास पर सहयोग समझौता	पुर्तगाल		विदेश मंत्रालय
78	भारत और पुर्तगाल की सरकारों के बीच प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर संयुक्त घोषणा	पुर्तगाल		विदेश मंत्रालय
79	इंडियन फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट और पुर्तगाली डिप्लोमैटिक इंस्टीट्यूट के बीच राजनयिक आदान-प्रदान और प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन	पुर्तगाल		विदेश मंत्रालय
80	भारत और पुर्तगाल की सरकारों के बीच ऑडियो-विजुअल सह-उत्पादन पर समझौता	पुर्तगाल		विदेश मंत्रालय
81	पुर्तगाल के आर्थिक और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, एएसएई और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच औद्योगिक और बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	पुर्तगाल		विदेश मंत्रालय
82	इन्वेस्ट इंडिया और स्टार्ट-अप पुर्तगाल के बीच समझौता ज्ञापन	पुर्तगाल		विदेश मंत्रालय
83	भारतीय गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल और सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय के बीच हज मौसम 1441एच (2020जी) सागर के लिए हज मामलों संबंधी व्यवस्था पर समझौता	सऊदी अरब		अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
84	कर के संबंध में सूचना के आदान प्रदान के लिए भारत और समोआ के बीच समझौता	समोआ		वित्त मंत्रालय
85	भारत और सिंप्रा लियोन के बीच राजनयिक और अधिकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता	सेरा लिओन		वित्त मंत्रालय
86	भारत और स्लोवेनिया के बीच संस्कृति, कला, शिक्षा, खेल-कूद और मास मीडिया के क्षेत्र में समझौता	स्लोवेनिया		संस्कृति मंत्रालय
87	भारत और सोलोमन द्वीप के बीच भारत-सोलोमन सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर समझौता	सोलोमन इस्लैंड्स		विदेश मंत्रालय
88	भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 17 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में जेएमसी के 10 वें सत्र का संयुक्त संवाद	दक्षिण अफ्रीका		विदेश मंत्रालय
89	भारत और सूरीनाम के बीच पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर समझौता ज्ञापन	सूरीनाम		आयुष मंत्रालय
90	स्विस संघीय परिषद और भारत सरकार के बीच वायु सेवा समझौते के लिए समझौते को संशोधित करने के लिए प्रोटोकॉल	स्विटजरलैंड		नागरिक उड्डयन मंत्रालय
91	दमिश्क में भारत-सीरिया नेक्स्ट जनरेशन सूचना प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन	सीरिया		नागरिक उड्डयन मंत्रालय
92	भारत और यूएई के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन	संयुक्त अरब अमीरात		पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
93	टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑस्टिन, यूएसए (यूटीए) और इसरो के बीच स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (एसएसए) के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग की एक सामान्य रूपरेखा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन	अमेरीका		इसरो
94	भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदारी केंद्र, भारत के साथ सहयोग पर समझौता ज्ञापन की अवधि को आगे बढ़ाने की व्यवस्था	अमेरीका		परमाणु ऊर्जा विभाग
95	भारत और अमेरिका के बीच समुद्री रक्षा सूचना साझा करने और सहयोग पर तकनीकी व्यवस्था	अमेरीका		रक्षा मंत्रालय
96	पोस्टल शिपमेंट के सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के लिए समझौता	अमेरीका		संचार मंत्रालय

क्र. सं.	शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
97	सहमति पत्र पर "मानसिक स्वास्थ्य" के बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) और स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, अमेरिका सरकार के बीच मानसिक स्वास्थ्यपर समझौता ज्ञापन	अमेरीका		स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
98	अमरीकी ऊर्जा विभाग और भारतीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच सामरिक पेट्रोलियम भंडार पर सहयोग पर समझौता ज्ञापन	अमेरीका		पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
99	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और जनसंख्या परिषद के बीच समझौता ज्ञापन	अमेरीका		ऊर्जा मंत्रालय
100	राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) भारत गणराज्य की सरकार	अमेरीका		सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
101	भारत और अमरीका के बीच बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता	अमेरीका		पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
102	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य विभाग के बीच बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन	अमेरीका		रक्षा मंत्रालय
103	उज्बेकिस्तान गणराज्य के ऊर्जा मंत्रालय के तहत परमाणु ऊर्जा विकास एजेंसी और परमाणु ऊर्जा भागीदारी वैश्विक केंद्र के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन	अमेरीका		वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
104	उज्बेकिस्तान के स्टेट कस्टम कमेटी और और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारत गणराज्य की सरकार के बीच देश की सीमा से जाने वाले माल पर पूर्व सूचना पर ज्ञापन	उज्बेकिस्तान		परमाणु ऊर्जा विभाग
105	राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान, नई दिल्ली और द्वीप समूह वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, वियतनाम के बीच समझौता ज्ञापन	उज्बेकिस्तान		वित्त मंत्रालय
106	भारत के महाकोंसुलावास और पीपल्स कमेटी ऑफ किन गियांग प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए स्थायी जल आपूर्ति के लिए वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		राष्ट्रीय समुद्री प्रतिष्ठान
107	भारत के महाकोंसुलावास और पीपल्स कमेटी ऑफ किन गियांग प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों और द्वीप समूह के लिए सहायक जल कंटेनर की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
108	भारत के महाकोंसुलावास और पीपल्स कमेटी ऑफ बेन तिरि प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए थोई दिनह हेमलेट, चो लेच टाउन, और दिनह बिनह हेमलेट, हो निगहा कम्पून, चो लेच जिले में थोई दिनह सिंचाई निकासी टनल की निर्माण परियोजना	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
109	भारत के महाकोंसुलावास और पीपल्स कमेटी ऑफ हुए तियान गियांग प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए तान फू डोंग जिले, तियान गियांग के लोगों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु बारिश के पानी के जलाशय की निर्माण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
110	भारत के महाकोंसुलावास और पीपल्स कमेटी ऑफ हुए तिन गियांग प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए डोंग थान कम्पून, गो कांग ताई जिला, टीएन जियांग प्रांत के निवासियों को घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय

क्र. सं.	शीर्षक	देश	हस्ताक्षर की तिथि	प्रशासनिक मंत्रालय
111	भारत के महाकोंसुलावास और पीपल्स कमेटी ऑफ हुए गियांग प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए बाढ़ और खारे पानी वाले स्थान में लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए सहायता परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
112	भारत के महाकोंसुलावास और पीपल्स कमेटी ऑफ हुए गियांग प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए चाउ थान जिले, हुए गियांग प्रोविंस में बाढ़ और खारापन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी 4.0 का लागू करने के लिए आधुनिक सिंचाई, जल संरक्षण के साथ सिंचाई मॉडल की निर्माण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
113	भारत के दूतावास और पीपल्स कमेटी ऑफ टयेन क्वांग प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए बिनह एन प्राइमरी स्कूल की टिन टोक शाखा, बिना एन क्म्यून, लेम बिनह जिला, तुयेन क्वांग प्रोविंस में कक्षा की निर्माण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
114	भारत के दूतावास और पीपल्स कमेटी ऑफ थान होआ प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए हेवांग क्यू सेकेंड्री स्कूल, हेवांग क्यू जिला, थान होआ प्रोविंस में विशेष कार्यकलाप सहित परंपरागत हाउस की निर्माण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
115	भारत के दूतावास और पीपल्स कमेटी ऑफ थान होआ प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए हेवांग क्यू सेकेंड्री स्कूल, हेवांग क्यू जिला, थान होआ प्रोविंस में विशेष कार्यकलाप सहित परंपरागत हाउस की निर्माण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
116	भारत के दूतावास और पीपल्स कमेटी ऑफ थान थिन होआ प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए उआन डोंग किंउर ग्रेटेन, क्वांग एन क्म्यून, क्वांग डिन जिला, थवा थिन हुए प्रोविंस में कक्षाओं की निर्माण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
117	भारत के दूतावास और पीपल्स कमेटी ऑफ नगे एन प्रोविंस के बीच सीएलएमवी देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई क्यूआईपी निधि का उपयोग करते हुए मा थान किंगरेथन, मा थान कम्पून, येन थान जिला, नाचे एन प्रोविंस में 6 कक्षाओं के भवन ब्लॉक की निर्माण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
118	वियतनाम समाजवादी गणराज्य के विदेश मंत्रालय और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत के गणतंत्र के बीच समझौता ज्ञापन	वियतनाम		विदेश मंत्रालय
119	आयुष मंत्रालय और डब्ल्यूएचओ के बीच डोनर समझौता	विश्व स्वास्थ्य संगठन		विदेश मंत्रालय
120	जिम्बाब्वे के साथ राजनयिक और अधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौता	जिम्बाब्वे		विदेश मंत्रालय

अनुबंध-IV

2020-2021 में द्विपक्षीय यात्राएं

क्र. सं.	दिनांक	देश
1.	6-10 October 2020	महामहिम डॉ अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह उच्च परिषद के अध्यक्ष की यात्रा
2.	12-14 October 2020	संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व उप विदेश मंत्री महामहिम श्री स्टीफन ई. बीगुन की यात्रा
3.	26-27 October 2020	संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो की यात्रा (2+2)
4.	12-13 December 2020	महामहिम श्री स्टीफन ई. बीगुन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य के पूर्व उप सचिव की यात्रा
5.	14-18 December 2020	डोमिनिक राब सांसद, राज्य के प्रथम सचिव और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के राज्य के सचिव की आधिकारिक यात्रा
6.	14-16 January 2021	प्रदीप कुमार ग्यावली, विदेश मंत्री, नेपाल की आधिकारिक यात्रा

अनुबंध-V

अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक वर्चुअल शिखर सम्मेलन

क्र. सं.	दिनांक	विषय
1.	4 मई 2020	कोविड 19 के लिए गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंस
2.	14 मई 2020	बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस
3.	4 जून 2020	भारत-ऑस्ट्रेलिया लीडर्स आभासी समिट
4.	13 जुलाई 2020	एलफाबेट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुंदर पिचाई के साथ आभासी कॉन्फ्रेंस
5.	15 जुलाई 2020	भारत-यूरोपीय संघ आभासी समिट
6.	20 जुलाई 2020	आईबीएम के सीईओ श्री अरविंद कृष्ण के साथ आभासी कॉन्फ्रेंस
7.	30 जुलाई 2020	मॉरीशस सुप्रीम कोर्ट भवन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन
8.	12 सितंबर 2020	श्री बर्नार्ड लूनी, ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ के साथ आभासी सम्मेलन
9.	26 सितंबर 2020	भारत-श्रीलंका आभासी समिट
10.	28 सितंबर 2020	भारत-डेनमार्क आभासी समिट
11.	06 अक्टूबर 2020	श्री हेनरिक एंडरसन, वेस्टास के सीईओ के साथ आभासी सम्मेलन
12.	19 अक्टूबर 2020	बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ आभासी कॉन्फ्रेंस
13.	05 नवंबर 2020	आभासी वैश्विक निवेशक सम्मेलन
14.	06 नवंबर 2020	भारत-इटली आभासी समिट
15.	09 नवंबर 2020	ऑस्ट्रेलियाई निवेशकों के साथ प्रधानमंत्री का वीडियो सम्मेलन
16.	10 नवंबर 2020	एससीओ शिखर सम्मेलन
17.	11 नवंबर 2020	फ्यूचर निधि, ऑस्ट्रेलिया के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री का वीडियो सम्मेलन
18.	12 नवंबर 2020	श्री लक्ष्मी मित्तल के साथ प्रधानमंत्री की आभासी कॉन्फ्रेंस
19.	12 नवंबर 2020	जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के गवर्नर के साथ प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस
20.	12 नवंबर 2020	17वां आसियान शिखर सम्मेलन
21.	14 नवंबर 2020	15वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन
22.	17 नवंबर 2020	12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
23.	19 नवंबर 2020	भारत-लक्जमबर्ग आभासी समिट
24.	20 नवंबर 2020	भूटान में रुपये कार्ड चरण - II के शुभारंभ के लिए आभासी समारोह
25.	21-22 नवंबर 2020	G20 राष्ट्र आभासी शिखर सम्मेलन
26.	24 नवंबर 2020	कनाडा पेंशन योजना निवेश बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ प्रधानमंत्री का आभासी सम्मेलन
27.	26 नवंबर 2020	कहसे डी डेपोट एट प्लेसमेंट ड्यु क्यूबैक के अध्यक्ष और सीईओ के साथ प्रधानमंत्री का आभासी सम्मेलन
28.	30 नवंबर 2020	एससीओ शिखर सम्मेलन
29.	03 दिसंबर 2020	श्री टी.बी.पेडरसेन, पेंशनडानमार्क के सीईओ के साथ प्रधानमंत्री की आभासी बैठक
30.	11 दिसंबर 2020	भारत-उज्बेकिस्तान आभासी समिट
31.	17 दिसंबर 2020	भारत-बांग्लादेश आभासी समिट
32.	21 दिसंबर 2020	भारत-वियतनाम आभासी समिट
34.	09 जनवरी 2021	16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन

अनुबंध-VI

अनुबंध-VII

01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान विदेशी मिशन प्रमुखों द्वारा प्रत्याह्व-पत्र प्रस्तुति

क्र. सं.	देश	राजदूत/उच्चायुक्त का नाम	प्रत्यय-पत्र प्रस्तुति की तिथि
1.	कोरिया लोकतांत्रिक गणराज्य	महामहिम श्री चोई हुई चोल	21.05.2020
2.	सेनेगल	महामहिम श्री अब्दुल वहाब हैदरा	21.05.2020
3.	लिनिदाद और टोबैगो	महामहिम डॉ रोजर गोपौल	21.05.2020
4.	मॉरीशस	महामहिम श्रीमती संटी बाई हनुमानजी	21.05.2020
5.	ऑस्ट्रेलिया	महामहिम श्री बैरी रॉबर्ट ओ फेरैल	21.05.2020
6.	कोटे डी आइवर	महामहिम एमएन ड्राई एरिक केमिली	21.05.2020
7.	रवांडा	महामहिम सुश्री जैकलिन मुंगिरा	21.05.2020
8.	न्यूजीलैंड	महामहिम श्री डेविड पाइन	08.07.2020
9.	उज़्बेकिस्तान	महामहिम श्री अहतोव दिलशोद खामिडोविच	08.07.2020
10.	सिंगापुर	महामहिम श्री साइमन वॉंग	10.09.2020
11.	स्विट्ज़रलैंड	महामहिम डॉ राल्फ हेकनर	14.10.2020
12.	माल्टा	महामहिम श्री रुबेन गॉसी	14.10.2020
13.	बोत्सवाना	महामहिम श्री गिल्बर्ट शिमाने मंगोले	14.10.2020
14.	हंगरी	महामहिम श्री एंड्रास लैस्ज़लो किरली	20.11.2020
15.	मालदीव	महामहिम हुसैन नित्याज	20.11.2020
16.	चाड	महामहिम श्री अहमद साँगी	20.11.2020
17.	तजाकिस्तान	महामहिम श्री लुकमोन बोबोकालोनजोडा	20.11.2020
18.	पनामा	महामहिम श्रीमती यासिएल एलिस बुरिलो रिवेरा	23.12.2020
19.	एल साल्वाडोर	महामहिम श्री गिलमॉ रुबियो फनेस	20.12.2020
20.	ट्यूनीशिया	महामहिम श्रीमती हयात तालबी ईपी बिएल	07.01.2021
21.	अर्जेंटीना	महामहिम श्री ह्यूगो जेवियर गोबी	26.01.2021
22.	यूनाइटेड किंगडम	महामहिम श्री अलेक्जेंडर एलिस	11.01.2021

2020-21 के दौरान मुख्यालय और विदेशों मिशनों में संवर्ग पदों की संख्या

(वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बजट किए गए पदों, संवर्ग-बाह्य पदों और एमओआईए और पीओई से संबंधित संवर्गित पदों सहित)

क्र. सं.	संवर्ग/पद	मुख्यालय में पद	मिशनों में पद	कुल
1	ग्रेड I	5	28	33
2	ग्रेड II	6	40	46
3	ग्रेड III	38	144	182
4	ग्रेड IV	58	152	210
5	कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड/सीनियर स्केल	117	270	387
6	(i) कनिष्ठ स्केल	10	25	35
	(ii) परिवीक्षार्थी रिजर्व	62		62
	(iii) छुट्टी रिजर्व	15		15
	(iv) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	19		19
	(v) प्रशिक्षण रिजर्व	7		7
	उप कुल I	337	659	996
	आईएफएस (बी)			
7	(i) ग्रेड I	118	125	243
	(ii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	6		6
8	(i) एकीकृत ग्रेड II और III	359	247	606
	(ii) छुट्टी रिजर्व	30		30
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	16		16
	(iv) प्रशिक्षण रिजर्व	25		25
9	(i) ग्रेड IV	214	551	765
	(ii) छुट्टी रिजर्व	60		60
	(iii) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	54		54
10	(i) ग्रेड V/VI	173	84	257
	(ii) छुट्टी रिजर्व	60		60
	(ii) छुट्टी रिजर्व	14		14
11	(i) साइफर कैंडर ग्रेड II	47	47	94
	(ii) छुट्टी रिजर्व	5		5
12	(i) आशुलिपिक संवर्ग	383	556	939
	(ii) छुट्टी रिजर्व	47		47
	(iii) प्रशिक्षण रिजर्व (हिंदी)	10		10
	(iv) प्रतिनियुक्ति रिजर्व	12		12
13	दुभाषिया कैंडर	9	26	35
14	एलएंडटी कैंडर	20	3	23
	उप कुल II	1662	1639	3301
	कुल योग (उपयोग I + II)	1999	2298	4297

05.11.2020 को रिक्तियों का विवरण

समूह क	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
समूह ख	104	26	11	14
समूह ग	267	47	22	45
कुल	198	17	28	56
कुल	533	85	58	101

परिशिष्ट-VIII

अनुबंध-IX

विभिन्न भाषाओं में प्रवीणता प्राप्त आईएफएस अधिकारियों की संख्या

(5 नवंबर 2020 तक)

क्र. सं.	भाषा	अधिकारियों की संख्या
1	अम्हारिक	1
2	अरबी	124
3	बहासा इंडोनेशिया	11
4	बहासा मलय	2
5	बर्मी	9
6	चीनी	92
7	चेक	1
8	फ्रेंच	114
9	जर्मन	39
10	हिब्रू	8
11	इटैलियन	3
12	जापानी	29
13	कजाख	1
14	कोरियाई	8
15	नेपाली	1
16	पश्तो	3
17	फ़ारसी	25
18	पोलिश	1
19	पुर्तगाली	24
20	रूसी	106
21	सिंहली	9
22	स्पैनिश	100
23	स्वाहिली	1
24	तुर्की	7
25	यूक्रेनियाई	1
26	वियतनामी	2
	कुल योग	722

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची (आरपीओ)

क्रमांक संख्या	पासपोर्ट कार्यालय	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1	पीओ अहमदाबाद	गुजरात
2	पीओ अमृतसर	पंजाब
3	पीओ बरेली	उत्तर प्रदेश
4	पीओ बेंगलुरु	कर्नाटक
5	पीओ भोपाल	मध्य प्रदेश
6	पीओ भुवनेश्वर	ओडिशा
7	पीओ चंडीगढ़	चंडीगढ़
8	पीओ चेन्नई	तमिलनाडु
9	पीओ कोचीन	केरल
10	पीओ कोयम्बतूर	तमिलनाडु
11	पीओ देहरादून	उत्तराखंड
12	पीओ दिल्ली	दिल्ली
13	पीओ गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
14	पीओ गोवा	गोवा
15	पीओ गुवाहाटी	असम
16	पीओ हैदराबाद	तेलंगाना
17	पीओ जयपुर	राजस्थान
18	पीओ जालंधर	पंजाब
19	पीओ जम्मू	जम्मू और कश्मीर
20	पीओ कोलकाता	पश्चिम बंगाल
21	पीओ कोझिकोड	केरल
22	पीओ लखनऊ	उत्तर प्रदेश
23	पीओ मदुरै	तमिलनाडु
24	पीओ मुंबई	महाराष्ट्र
25	पीओ नागपुर	महाराष्ट्र
26	पीओ पटना	बिहार
27	पीओ पुणे	महाराष्ट्र
28	पीओ रायपुर	छत्तीसगढ़
29	पीओ रांची	झारखंड
30	पीओ शिमला	हिमाचल प्रदेश
31	पीओ श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर
32	पीओ सूरत	गुजरात
33	पीओ तिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु
34	पीओ त्रिवेंद्रम	केरल
35	पीओ विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
36	पीओ विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश

अनुबंध-X

पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीएसके) की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची

क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएसके की संख्या	पीएसके की अवस्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	4	विजयवाड़ा, तिरुपति, विशाखापत्तनम, भीमावरम
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	ईटानगर
3.	असम*	1	गुवाहाटी
4.	बिहार	2	पटना, दरभंगा
5.	चंडीगढ़ यूटी	1	चंडीगढ़
6.	छत्तीसगढ़	1	रायपुर
7.	दिल्ली एनसीटी ***	3	हेराल्ड हाउस, शालीमार प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस
8.	गोवा	1	पणजी
9.	गुजरात	5	अहमदाबाद I और II, वडोदरा, राजकोट, सूरत
10.	हरियाणा	2	अंबाला, गुड़गांव
11.	हिमाचल प्रदेश	1	शिमला
12.	जम्मू और कश्मीर	2	जम्मू, श्रीनगर
13.	झारखंड	1	रांची
14.	कर्नाटक	5	बैंगलोर I और II, हुबली, मैंगलोर, कालावुरागी
15.	केरल	13	तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम (ग्रामीण), कोल्लम, कोचीन, एर्नाकुलम ग्रामीण, अलापुझा, कोट्टायम, मलप्पुरम, त्रिशूर, कोझीकोड I & II, कन्नूर I और II
16.	मध्य प्रदेश	2	भोपाल, इंदौर
17.	महाराष्ट्र	8	मुंबई I, II और III, पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक, सोलापुर
18.	मणिपुर	1	इंफाल
19.	मेघालय	1	शिलांग
20.	मिजोरम	1	आइजोल
21.	नगालैंड	1	दीमापुर
22.	ओडिशा	1	भुवनेश्वर
23.	पुदुच्चेरी	1	पुदुच्चेरी
24.	पंजाब	5	अमृतसर, लुधियाना, जालंधर- I, जालंधर- II, होशियारपुर
25.	राजस्थान	4	जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर
26.	सिक्किम	1	गंगटोक
27.	तमिलनाडु	8	चेन्नई I, II और III, त्रिचि, तंजावुर, मदुरै, तिरुनेलवेली, कोयंबटूर
28.	तेलंगाना	5	हैदराबाद I, II और III, निजामाबाद, करीमनगर
29.	त्रिपुरा	1	अगरतला
30.	उत्तर प्रदेश	6	लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद
31.	उत्तराखंड	1	देहरादून
32.	पश्चिम बंगाल	3	कोलकाता, बेरहामपुर, सिलीगुड़ी
	कुल		

अनुबंध-XI

डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
1	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान और निकोबार द्वीप	कोलकाता
2	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
3	बापतला	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
4	चित्तौड़	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
5	गुडीवाड़ा	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
6	गुंटूर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
7	हिंदूपुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
8	कडप्पा	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
9	कोदुर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
10	कुरनूल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
11	नंद्याल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
12	नरसरावपेट	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
13	नेल्लोर	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
14	ओंगोल	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
15	अमलापुरम	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
16	एलुरु	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
17	काकीनाडा	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
18	राजमुंदरी	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
19	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
20	विजयनगरम	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
21	येलामंचिली	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम
22	चांगलांग	आंध्र प्रदेश	गुवाहाटी
23	खोंसा	आंध्र प्रदेश	गुवाहाटी
24	बारपेटा	असम	गुवाहाटी
25	धुबरी	असम	गुवाहाटी
26	डिब्रूगढ़	असम	गुवाहाटी
27	गोलपारा	असम	गुवाहाटी
28	गोलाघाट	असम	गुवाहाटी
29	जोरहाट	असम	गुवाहाटी
30	करबीअंगलॉंग	असम	गुवाहाटी
31	करीमगंज	असम	गुवाहाटी
32	कोकराझार	असम	गुवाहाटी
33	मंगलदोई	असम	गुवाहाटी
34	नवगोंग	असम	गुवाहाटी
35	उत्तर लखीमपुर	असम	गुवाहाटी

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
36	सिलचर	असम	गुवाहाटी
37	तेजपुर	असम	गुवाहाटी
38	तिनसुकिया	असम	गुवाहाटी
39	आरा	बिहार	पटना
40	औरंगाबाद	बिहार	पटना
41	बांका	बिहार	पटना
42	बेगूसराय	बिहार	पटना
43	बेतिया	बिहार	पटना
44	भागलपुर	बिहार	पटना
45	बक्सर	बिहार	पटना
46	छपरा	बिहार	पटना
47	डालमिया नगर	बिहार	पटना
48	दलसिंह सराय	बिहार	पटना
49	फोर्बेसगंज	बिहार	पटना
50	गया	बिहार	पटना
51	गोपालगंज	बिहार	पटना
52	हाजीपुर	बिहार	पटना
53	जहानाबाद	बिहार	पटना
54	जमुई	बिहार	पटना
55	कटिहार	बिहार	पटना
56	खगड़िया	बिहार	पटना
57	किशनगंज	बिहार	पटना
58	मधुबनी	बिहार	पटना
59	मनेर	बिहार	पटना
60	मोतिहारी	बिहार	पटना
61	मुंगेर	बिहार	पटना
62	मुजफ्फरपुर	बिहार	पटना
63	नालंदा	बिहार	पटना
64	नवादा	बिहार	पटना
65	पूर्णिया	बिहार	पटना
66	सहरसा	बिहार	पटना
67	समस्तीपुर	बिहार	पटना
68	सासाराम	बिहार	पटना
69	शिवहर	बिहार	पटना
70	सीतामढ़ी	बिहार	पटना
71	सिवान	बिहार	पटना
72	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	रायपुर
73	दुर्ग	छत्तीसगढ़	रायपुर
74	जांजगीर-चंपा	छत्तीसगढ़	रायपुर
75	कोरबा	छत्तीसगढ़	रायपुर

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
76	रायगढ़	छत्तीसगढ़	रायपुर
77	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़	रायपुर
78	सरगुजा	छत्तीसगढ़	रायपुर
79	सिल्वासा	दादर, नगर हवेली	मुंबई
80	दमन	दमन	मुंबई
81	जनकपुरी	दिल्ली	दिल्ली
82	महरीली	दिल्ली	दिल्ली
83	नेहरू प्लेस	दिल्ली	दिल्ली
84	पटपड़गंज	दिल्ली	दिल्ली
85	यमुना विहार	दिल्ली	दिल्ली
86	मढगांव	गोवा	पणजी
87	अमरेली	गुजरात	अहमदाबाद
88	आनंद	गुजरात	अहमदाबाद
89	बारडोली	गुजरात	सूरत
90	भरूच	गुजरात	अहमदाबाद
91	भावनगर	गुजरात	अहमदाबाद
92	भुज	गुजरात	अहमदाबाद
93	छोटा उदयपुर	गुजरात	अहमदाबाद
94	दहोज	गुजरात	अहमदाबाद
95	गांधीनगर	गुजरात	अहमदाबाद
96	गोधरा	गुजरात	अहमदाबाद
97	जामनगर	गुजरात	अहमदाबाद
98	जूनागढ़	गुजरात	अहमदाबाद
99	खेड़ा	गुजरात	अहमदाबाद
100	मेहसाणा	गुजरात	अहमदाबाद
101	नवसारी	गुजरात	सूरत
102	पालनपुर	गुजरात	अहमदाबाद
103	पाटन	गुजरात	अहमदाबाद
104	पोरबंदर	गुजरात	अहमदाबाद
105	राजपिपला	गुजरात	सूरत
106	साबरकांठा	गुजरात	अहमदाबाद
107	सुरेंद्रनगर	गुजरात	अहमदाबाद
108	वलसाड	गुजरात	सूरत
109	वेरावल	गुजरात	अहमदाबाद
110	भिवानी महेंद्रगढ़	हरियाणा	चंडीगढ़
111	फरीदाबाद	हरियाणा	दिल्ली
112	हिसार	हरियाणा	चंडीगढ़
113	कैथल	हरियाणा	चंडीगढ़
114	करनाल	हरियाणा	चंडीगढ़
115	नारनौल	हरियाणा	दिल्ली
116	पानीपत	हरियाणा	चंडीगढ़

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
117	रोहतक	हरियाणा	दिल्ली
118	सिरसा	हरियाणा	चंडीगढ़
119	सोनीपत	हरियाणा	दिल्ली
120	यमुनानगर	हरियाणा	चंडीगढ़
121	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला
122	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	शिमला
123	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	शिमला
124	मंडी	हिमाचल प्रदेश	शिमला
125	पालमपुर	हिमाचल प्रदेश	शिमला
126	ऊना	हिमाचल प्रदेश	शिमला
127	कटुआ	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
128	राजौरी	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
129	उधमपुर	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
130	अनंतनाग	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
131	बारामूला	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
132	लेह	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
133	बोकारो	झारखंड	रांची
134	चाईबाशा	झारखंड	रांची
135	देवघर	झारखंड	रांची
136	धनबाद	झारखंड	रांची
137	दुमका	झारखंड	रांची
138	गिरिडीह	झारखंड	रांची
139	गुमला	झारखंड	रांची
140	हजारीबाग	झारखंड	रांची
141	जमशेदपुर	झारखंड	रांची
142	झुमरी तिलैया	झारखंड	रांची
143	खूंटी	झारखंड	रांची
144	मेदिनीनगर	झारखंड	रांची
145	साहिबगंज	झारखंड	रांची
146	शिमरिया	झारखंड	रांची
147	अंकोला	कर्नाटक	बेंगलुरु
148	बागलकोट	कर्नाटक	बेंगलुरु
149	बेलगावी	कर्नाटक	बेंगलुरु
150	बेल्लारी	कर्नाटक	बेंगलुरु
151	बीदर	कर्नाटक	बेंगलुरु
152	चामराजनगर	कर्नाटक	बेंगलुरु
153	चन्नापटना	कर्नाटक	बेंगलुरु
154	चिकबलपुर	कर्नाटक	बेंगलुरु
155	चिककोडी	कर्नाटक	बेंगलुरु
156	चिन्नदुर्ग	कर्नाटक	बेंगलुरु

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
157	दावणगेरे	कर्नाटक	बेंगलुरु
158	गदग	कर्नाटक	बेंगलुरु
159	हसन	कर्नाटक	बेंगलुरु
160	जलहाली	कर्नाटक	बेंगलुरु
161	कोप्पल	कर्नाटक	बेंगलुरु
162	मदुर	कर्नाटक	बेंगलुरु
163	मैसूरु	कर्नाटक	बेंगलुरु
164	रायचुर	कर्नाटक	बेंगलुरु
165	रॉबर्टसनपेट	कर्नाटक	बेंगलुरु
166	शिवमोगा	कर्नाटक	बेंगलुरु
167	तुमकुरु	कर्नाटक	बेंगलुरु
168	उडुपी	कर्नाटक	बेंगलुरु
169	विजयापुर	कर्नाटक	बेंगलुरु
170	चेगनूर	केरल	कोचीन
171	कट्टापपना	केरल	कोचीन
172	नेनमारा	केरल	कोचीन
173	पलक्कड़	केरल	कोचीन
174	कासरगोड	केरल	कोझीकोड
175	अटांगल	केरल	त्रिवेन्द्रम
176	पथानामथिट्टा	केरल	त्रिवेन्द्रम
177	कावारत्ती	लक्षद्वीप	कोचीन
178	बालाघाट	मध्य प्रदेश	भोपाल
179	बैतूल	मध्य प्रदेश	भोपाल
180	छतरपुर	मध्य प्रदेश	भोपाल
181	छिंदवाड़ा	मध्य प्रदेश	भोपाल
182	दमोह	मध्य प्रदेश	भोपाल
183	देवास	मध्य प्रदेश	भोपाल
184	धार	मध्य प्रदेश	भोपाल
185	ग्वालियर	मध्य प्रदेश	भोपाल
186	होशंगाबाद	मध्य प्रदेश	भोपाल
187	जबलपुर	मध्य प्रदेश	भोपाल
188	रतलाम	मध्य प्रदेश	भोपाल
189	रीवा	मध्य प्रदेश	भोपाल
190	सागर	मध्य प्रदेश	भोपाल
191	सतना	मध्य प्रदेश	भोपाल
192	सिवनी	मध्य प्रदेश	भोपाल
193	टीकमगढ़	मध्य प्रदेश	भोपाल
194	उज्जैन	मध्य प्रदेश	भोपाल
195	विदिशा	मध्य प्रदेश	भोपाल
196	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	मुंबई
197	भिवंडी	महाराष्ट्र	मुंबई

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
198	भुसावल	महाराष्ट्र	मुंबई
199	धुले	महाराष्ट्र	मुंबई
200	जलगांव	महाराष्ट्र	मुंबई
201	राजापुर	महाराष्ट्र	मुंबई
202	सांता क्रुज़	महाराष्ट्र	मुंबई
203	सायन	महाराष्ट्र	मुंबई
204	वाशी	महाराष्ट्र	मुंबई
205	विक्रोली	महाराष्ट्र	मुंबई
206	अहमदनगर	महाराष्ट्र	पुणे
207	बारामती	महाराष्ट्र	पुणे
208	बीड	महाराष्ट्र	पुणे
209	इचलकरंजी	महाराष्ट्र	पुणे
210	जलना	महाराष्ट्र	पुणे
211	कोल्हापुर	महाराष्ट्र	पुणे
212	लातूर	महाराष्ट्र	पुणे
213	माढा	महाराष्ट्र	पुणे
214	नांदेड	महाराष्ट्र	पुणे
215	उस्मानाबाद	महाराष्ट्र	पुणे
216	पंढरपुर	महाराष्ट्र	पुणे
217	परभनी	महाराष्ट्र	पुणे
218	पिंपरीचिंचवाड	महाराष्ट्र	पुणे
219	सांगली	महाराष्ट्र	पुणे
220	सतारा	महाराष्ट्र	पुणे
221	शिरूर	महाराष्ट्र	पुणे
222	श्रीरामपुर	महाराष्ट्र	पुणे
223	अकोला	महाराष्ट्र	नागपुर
224	अमरावती	महाराष्ट्र	नागपुर
225	भंडारा	महाराष्ट्र	नागपुर
226	बुलढाना	महाराष्ट्र	नागपुर
227	चंद्रपुर	महाराष्ट्र	नागपुर
228	गढ़चिरोली	महाराष्ट्र	नागपुर
229	हिंगोली	महाराष्ट्र	नागपुर
230	कटोले	महाराष्ट्र	नागपुर
231	वर्धा	महाराष्ट्र	नागपुर
232	यवतमाल	महाराष्ट्र	नागपुर
233	काचिंग	मणिपुर	गुवाहाटी
234	तुरा	मेघालय	गुवाहाटी
235	अस्का	ओडिशा	भुवनेश्वर
236	बालासोर	ओडिशा	भुवनेश्वर
237	बारगढ़	ओडिशा	भुवनेश्वर
238	बारीपदा	ओडिशा	भुवनेश्वर

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
239	बेरहामपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
240	भद्रक	ओडिशा	भुवनेश्वर
241	भवानीपटना	ओडिशा	भुवनेश्वर
242	बोलंगीर	ओडिशा	भुवनेश्वर
243	कटक	ओडिशा	भुवनेश्वर
244	ढेंकनाल	ओडिशा	भुवनेश्वर
245	जगतसिंहपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
246	जाजपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
247	केंद्रपाड़ा	ओडिशा	भुवनेश्वर
248	क्योंझर	ओडिशा	भुवनेश्वर
249	कोरापुट	ओडिशा	भुवनेश्वर
250	नबरंगपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
251	फूलबनी	ओडिशा	भुवनेश्वर
252	पुरी	ओडिशा	भुवनेश्वर
253	राउरकेला	ओडिशा	भुवनेश्वर
254	संबलपुर	ओडिशा	भुवनेश्वर
255	कराईकल	पुडुचेरी	तिरुचिरापल्ली
256	बसीपत्तन	पंजाब	चंडीगढ़
257	बठिंडा	पंजाब	चंडीगढ़
258	फिरोजपुर	पंजाब	अमृतसर
259	मलेरकोटला	पंजाब	चंडीगढ़
260	मोगा	पंजाब	जालंधर
261	पठानकोट	पंजाब	जालंधर
262	पटियाला	पंजाब	चंडीगढ़
263	फगवाड़ा	पंजाब	जालंधर
264	रोपड़	पंजाब	चंडीगढ़
265	अजमेर	राजस्थान	जयपुर
266	अलवर	राजस्थान	जयपुर
267	बांसवाड़ा	राजस्थान	जयपुर
268	बाड़मेर	राजस्थान	जयपुर
269	भरतपुर	राजस्थान	जयपुर
270	भीलवाड़ा	राजस्थान	जयपुर
271	बीकानेर	राजस्थान	जयपुर
272	चित्तौड़गढ़	राजस्थान	जयपुर
273	चूरू	राजस्थान	जयपुर
274	दौसा	राजस्थान	जयपुर
275	हनुमानगढ़	राजस्थान	जयपुर
276	जैसलमेर	राजस्थान	जयपुर
277	झालावाड़	राजस्थान	जयपुर
278	झुंझुनू	राजस्थान	जयपुर
279	कांकरोली	राजस्थान	जयपुर
280	करौली-धौलपुर	राजस्थान	जयपुर

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
281	कोटा	राजस्थान	जयपुर
282	कोटपूतली	राजस्थान	जयपुर
283	नागौर	राजस्थान	जयपुर
284	पाली	राजस्थान	जयपुर
285	प्रतापगढ़	राजस्थान	जयपुर
286	सवाईमाधोपुर	राजस्थान	जयपुर
287	सिरोही	राजस्थान	जयपुर
288	श्रीगंगानगर	राजस्थान	जयपुर
289	अरणि	तमिलनाडु	चेन्नई
290	चेन्नई जीपीओ	तमिलनाडु	चेन्नई
291	चिदंबरम	तमिलनाडु	चेन्नई
292	कडलूर	तमिलनाडु	चेन्नई
293	धर्मपुरी	तमिलनाडु	चेन्नई
294	कल्लाकुरिची	तमिलनाडु	चेन्नई
295	कांचीपुरम	तमिलनाडु	चेन्नई
296	कृष्णागिरी	तमिलनाडु	चेन्नई
297	रानीपेट	तमिलनाडु	चेन्नई
298	तिरुवल्लूर	तमिलनाडु	चेन्नई
299	तिरुवन्नामलाई	तमिलनाडु	चेन्नई
300	वेल्लोर	तमिलनाडु	चेन्नई
301	विलुप्पुरम	तमिलनाडु	चेन्नई
302	कुन्नूर	तमिलनाडु	कोयम्बट
303	खत्म	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
304	रासीपुरम	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
305	सलेम	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
306	बोडिनेयांकुर	तमिलनाडु	मदुरै
307	देवाकोत्तई	तमिलनाडु	मदुरै
308	कोडाडुरोड	तमिलनाडु	मदुरै
309	नागरकोडल	तमिलनाडु	मदुरै
310	राजपालयम	तमिलनाडु	मदुरै
311	रामतापुरम	तमिलनाडु	मदुरै
312	थुथुकुडी	तमिलनाडु	मदुरै
313	विरुधुनगर	तमिलनाडु	मदुरै
314	करूर	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
315	पेरम्बलुर	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
316	सिरकली	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
317	थिरुथुराडुपोंडी	तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली
318	आदिलाबाद	तेलंगाना	हैदराबाद
319	भोंगीर	तेलंगाना	हैदराबाद
320	कामरेड्डी	तेलंगाना	हैदराबाद
321	खम्मम	तेलंगाना	हैदराबाद
322	महबुबाबाद	तेलंगाना	हैदराबाद

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
323	मंचेरियल	तेलंगाना	हैदराबाद
324	मेडक	तेलंगाना	हैदराबाद
325	मेडचल	तेलंगाना	हैदराबाद
326	महबूबनगर	तेलंगाना	हैदराबाद
327	नलगोंडा	तेलंगाना	हैदराबाद
328	सिद्दीपेट	तेलंगाना	हैदराबाद
329	विकाराबाद	तेलंगाना	हैदराबाद
330	वानप्रार्थी	तेलंगाना	हैदराबाद
331	वारंगल	तेलंगाना	हैदराबाद
332	धरमनगर	त्त्रिपुरा	कोलकाता
333	अमरोहा	उत्तर प्रदेश	बरेली
334	बदायूं	उत्तर प्रदेश	बरेली
335	बिजनौर	उत्तर प्रदेश	बरेली
336	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	बरेली
337	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	बरेली
338	रामपुर	उत्तर प्रदेश	बरेली
339	शाहजहाँपुर	उत्तर प्रदेश	बरेली
340	अचनेरा	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
341	आगरा	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
342	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
343	बागपत	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
344	बुलंदशहर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
345	हाथरस	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
346	मेरठ	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
347	मुजफ्फरनगर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
348	नोएडा	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
349	सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
350	वृंदावन	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद
351	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
352	अंबेडकरनगर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
353	अमेठी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
354	अयोध्या	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
355	आजमगढ़	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
356	बहराइच	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
357	बलिया	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
358	बलरामपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
359	बाँदा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
360	भदोही	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
361	चुनार	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
362	देवरिया	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
363	फर्रुखाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
364	फतेहपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
365	गाजीपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
366	गोंडा	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
367	गोशी (मऊ)	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
368	हमीरपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
369	हरदोई	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
370	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
371	झांसी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
372	खेरी	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
373	महराजगंज	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
374	मिसरिख	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
375	प्रतापगढ़	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
376	रायबरेली	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
377	सिद्धार्थ नगर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
378	सीतापुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
379	सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
380	उन्नाव	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
381	अल्मोड़ा	उत्तराखंड	देहरादून
382	काठगोदाम	उत्तराखंड	देहरादून
383	नैनीताल	उत्तराखंड	देहरादून
384	रुड़की	उत्तराखंड	देहरादून
385	रुद्रपुर	उत्तराखंड	देहरादून
386	श्रीनगर	उत्तराखंड	देहरादून
387	अलीपुरद्वार	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
388	अमता	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
389	आरामबाग	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
390	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
391	अशोक नगर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
392	बेलूरघाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
393	बंगाण	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
394	बांकुरा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
395	बर्धमान	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
396	बैरकपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
397	बशीरहाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
398	बीडॉन स्ट्रीट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
399	बिशुपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
400	बोलपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
401	कैनिंग रोड फेरी घाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
402	चिनसुराह	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
403	कूचबिहार	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
404	दार्जिलिंग	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
405	डायमंड हार्बर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
406	दम दम	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
407	घटल	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
408	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

क्रम संख्या	अवस्थिति	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पासपोर्ट कार्यालय
409	जादवपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
410	जलपाईगुड़ी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
411	झारग्राम	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
412	जियागंज	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
413	काकद्वीप	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
414	कंठी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
415	कटवा	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
416	खड़गपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
417	कृष्णानगर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
418	मखदुमपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
419	उत्तर दिनाजपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
420	पुरुलिया	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
421	रघुनाथगंज	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
422	रामपुरहाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
423	रानाघाट	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
424	सम्सी	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
425	श्रीरामपुर	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
426	तामलुक	पश्चिम बंगाल	कोलकाता



विदेश मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट | 2020-21

यह वार्षिक रिपोर्ट विदेश मंत्रालय के वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है
www.mea.gov.in